



कांग्रेस के सौ वर्ष

मूल्य पचास रुपय (50.00)

संस्करण 19९७, - मन्मथनाथ गुप्त

राजपाल एण्ड स ज, कश्मीरी गेट, दिल्ली 110006 द्वारा प्रकाशित

CONGRESS KE SAU VARSH (History of Indian National Congress)  
by Manmathnath Gupta

# कांग्रेस के सौ वर्ष

सघर्ष और सफलता का इतिहास

मन्मथनाथ गुप्त



राजपाल एण्ड सन्ज



## भूमिका

मैं ममयनाथ गुप्त को जानता हूँ। यह जरूरी नहीं है कि उनकी हर बात से मैं सहमत हूँ। फिर भी उन्होंने यह जो पुस्तक लिखी है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। कांग्रेस की महिमामयी शताब्दी इस वष मनाई जा रही है। उसके सन्दर्भ में श्री ममयनाथ जी की पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी। कांग्रेस का जनता की भावनाओं से अयो-याश्रय सम्बन्ध है। नई पीढ़ी के लिए यह पुस्तक उपयोगी होगी।

7 फरवरी 1983

9, जनपथ, नई दिल्ली

—कमलापति त्रिपाठी

कायकारी अध्यक्ष

श्री भा. कांग्रेस कमेटी



## दो शब्द

राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास का मैं पुराना छात्र हूँ। 1939 में मेरी लिखी हुई पुस्तक 'भारत में क्रांतिचेष्टा का रोमांचकारी इतिहास' प्रकाशित हुई और छपते ही ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर ली गई। पुस्तक का यह नाम मेरा दिया हुआ नहीं था, बल्कि "चाद" का फासी अंक निकालकर यशस्वी हुए रामरखमिह सहगल का दिया हुआ था। असल में उन्होंने इसके प्रथम कई अध्याय अपने मासिक पत्र में छापे थे। लेखमाला समाप्त होने तक धैर्य धारण किए रहना मुझे मुश्किल लगा, इसलिए कि मैं किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकता था और हुआ भी यही— 1939 के सितम्बर में मैं दो युद्ध विरोधी व्याख्यानो के लिए अदर कर दिया गया। पिछली बार 12 साल बाद छूटा था, इस बार सात साल बाद छूटा।

1939 में मेरी एक पुस्तिका भी जब्त हो गई, जिसका नाम था 'क्रान्तिकारी आन्दोलन और राष्ट्रीय विकास'। यह पुस्तिका एक थीसिस के रूप में थी। स्वराज्य (1947) के बाद ये दोनों जब्त पुस्तकें अपटुडेट करके स्वतंत्रता प्राप्ति तक लाकर एक बृहत् पुस्तक बन गई। अब यह सातवें संस्करण में 'क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास' के रूप में है।

पर क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास का एक महत्वपूर्ण और निर्णायक अंश होने पर भी उसमें आन्दोलन का समग्र इतिहास नहीं आ पाया था, अतएव मुझे 1947 में राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास लिखना पड़ा। इसका एक लघु संस्करण भी निकाला गया, ताकि छात्रों के काम आए।

इस क्षेत्र में मेरी रचि पुरानी है। इस सम्बन्ध में मेरे पहले और दूसरे प्रयास के परिणाम ब्रिटिश सरकार ने जब्त करके मुझे जो सम्मान दिया था वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है।

अब दूसरा सम्मान यह मिला कि कांग्रेस के तपे हुए नेता, मेरे प्रथम जेलवास (1929) के तथा काशी विद्यापीठ के वरिष्ठ साथी कमलापति जी ने मेरी इस पुस्तक की भूमिका लिखी।

कहते हैं हाथी के पांव में सबके पांव। भारतीय राजनीति का यह हाथी कांग्रेस है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमारे जंगल में हाथी के अलावा और कोई प्राणी नहीं है। बाघ हैं, जंगल का राजा सिंह है, पानी का राजा घड़ियाल है, बगुले हैं, मरु का पक्षी शुतरमुग है, ईश्वर की तरह घट-घट व्यापी कौए हैं। आलंकारिक भाषा त्याग कर यदि साधारण भाषा अपनाई जाए और कांग्रेस को देश का पर्यायवाची न मानकर एक दल मात्र माना जाए, तो भी जीवित दलों में वह सबसे पुराना पोढ़ा है।<sup>1</sup> कितने दल आए और बाल के



माल में समा गए, पर कांग्रेस जीवित है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि उसे वह गुर मालूम है और वह मंत्र सिद्ध है जिससे द्वारा वह बराबर पतझड़ों को परास्त करके नव यौवन प्राप्त करती है। कांग्रेस बराबर नए विचारों को पचाकर परिपुष्ट हुई है। वह नए विचारों (जैसे समाजवाद) को पचाने में यदि देर करती है तो दूसरे लोग जो समाजवाद की ठेंकेदारी का दम भरते हैं, वही कौन से समाजवाद पर डटे हैं। आज सारे ससार के समाजवादी और साम्यवादी ससदवाद के सुखद दलदल में फस चुके हैं, उनमें बारह कनौ जिया तेरह चूल्हे हैं, निजी जीवन में वे किसी प्रकार दूसरों से श्रेष्ठ नहीं। हृद तो यह है कि वे मार्क्स और लेनिन को नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं तो समझते नहीं। कुछ लोग जो मुख्य दल से फटकर अपने को मार्क्सवादी लेनिनवादी नक्सलवादी कहते हैं वे रूस का साम्राज्य वादी बता रहे हैं। इंदिराजी चुनाव में ये सब घोर दक्षिणपथियो खालिस्तानियों से कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। जनता ने उनको उचित सजा दी। पर इस सजा से वे कुछ सीखे ऐसा नहीं लगता।

कांग्रेस की सबसे बड़ी ऐतिहासिक सेवा रही है देश का एकीकरण। सचार्ई तो यह है कि कांग्रेस के गणन में भगवान भास्कर के भव्य रूप में महात्मा गांधी के उदित होने के पहले ही यह महान काय सिद्ध हो चुका था। जवाहरलाल नेहरू ने 19 जनवरी 1936 को लाड लोथियन को लिखे एक पत्र में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन ने अनिवार्य रूप से देश में एकता पैदा करने में वही सहायता की है। पर उसी पत्र में उन्होंने यह भी लिखा कि अंग्रेजों ने पराधीनता-बोध से उत्पन्न इस प्रक्रिया का विरोध किया, यहाँ तक विरोध किया कि पाकिस्तान बना। खालिस्तान का बीज भी उन्हीं का डाला हुआ है। कथित होमलैंड में आम मुसलमानों की कैमी दुर्गति हुई, कैसे पाकिस्तान टूटा यह सब देखकर भी विदेशी पैसों से कैसे खालिस्तान का आन्दोलन चला, यह हम जानते हैं।

आज अणु बम से सुसज्जित विश्व साम्राज्यवाद के समक्ष एकमात्र प्रश्न यह है— कि भारत की अखंडता बनी रहे। हिटलर पीड़ित यूरोप ने लगभग इन्हीं परिस्थितियों में समुक्त मोर्चे का नारा दिया था। पहले भारत बचे तो सही, फिर हम समाजवाद के लिए लड़ेंगे—वेदाती समाजवाद नहीं, वैज्ञानिक समाजवाद।

मन्मथनाथ गुप्त

## क्रम

कांग्रेस स्थापना की पृष्ठभूमि	11
कांग्रेस का जन्म बंबई अधिवेशन	38
पहली कांग्रेस के बाद	44
आंदोलन युग का आरंभ बंग भंग और अनंतर	72
प्रथम महायुद्ध के दौरान	86
गांधीजी का उदय सत्याग्रह का प्रयोग	95
पूर्ण स्वतंत्रता की मांग	117
प्रांतीय स्वशासन	130
द्वितीय महायुद्ध और कांग्रेस	139
1942-1945 अथवा पुनर्जागरण के वर्ष	151
महायुद्ध का अंत और स्वराज्य	161
स्वराज्य के बाद कांग्रेस सत्ता में	173
सत्तारूढ़ कांग्रेस का नेहरू युग	182
इंदिरा शासन की उपलब्धियाँ	195
शताब्दी वष में राजीव युग का आरंभ	211



## कांग्रेस-स्थापना की पृष्ठभूमि

वृक्ष का इतिहास कहा से शुरू होता है ? जब अकुर आखें खोलकर, अगड़ाई लेकर, सलज्ज दृष्टि से घिराट आकाश को पहली बार देखता है, या कि बीज से, जो ज़मीन के नीचे धरती का रस पीकर एकाएक जगजाहिर होकर अपना झड़ा ऊपर फैलाने की तयारी करता है ?

कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ, पर यह कोई वायकारणहीन आकस्मिक घटना नहीं थी। इसके पीछे वर्षों की साधना, संघर्ष, संग्राम, रक्तपात और साधारण जन के स्वाधीन होने की आकुल छटपटाहट थी। अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को तीन भागों में बाटा था—हिंदू युग, मुस्लिम युग, ब्रिटिश युग—पर इस विभाजन की वास्तविकता यह है कि कथित हिंदू युग में थोड़े से परस्पर सड़नेवाले राजाओं और उनके पिछलग्गुओं का राज्य था। आम जनता सुलसीदास की भाषा में बेरी मात्र थी। कथित मुस्लिम युग में भी परिस्थिति वही रही, सिवा इसके कि शासक अब विदेशी थे, हा उनके वंशज अवश्य भारत में बस गए। मुस्लिम सुलतान भी अपने हिंदू पूर्ववर्तियों की तरह शोषक थे, हा, अब इन सुलतानों के सेवक मानसिंह जैसे कुछ हिंदू भी इन शोषकों में शामिल हो गए। यह इसलिए नहीं कि शासक धर्मनिरपेक्ष थे, बल्कि इसलिए कि वे अपना राज्य स्थायी बनाना चाहते थे। रहा ब्रिटिश युग, उसमें अंग्रेजों और उनके चरण-दातो, धारणों और चपरासियों के चमड़े के सिक्के चलते रहे। आम जनता जहा की तहा रही। महत्वपूर्ण बात यह हुई कि अब उसका धन देश के बाहर जाने लगा।

हजारों वर्षों के हमारे इतिहास में प्रथम बार 1947 के 15 अगस्त को भारत के जनसाधारण के हाथों में राष्ट्र की बागडोर आई। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता प्राप्ति का आवाहन करते हुए 1947 में कहा था—

“आज हम एक आजाद लोग हैं, आजाद मुक्त हैं। मैं आपसे जो बोल रहा हूँ, एक हैसियत, एक सरकारी हैसियत मुझे मिली है, जिसका असली नाम यह होना चाहिए कि मैं हिंदुस्तान की जनता का प्रथम सेवक हूँ। जिस हैसियत में मैं आपसे बोल रहा हूँ, वह हैसियत मुझे किसी बाहरी शक्ति ने नहीं, आपने दी है।”

हैसियत प्राप्ति की यह बात न तो सुघिष्ठिर कह सकते थे, न अशोक, न अकबर। भारत की जनता को प्रथम बार 1947 में एक अहता और मर्यादा मिली, जो पहले के किसी युग में कभी उसे एक दिन के लिए भी नहीं मिली थी। रहा यह कि किन्हीं कारणों से इस अहता और मर्यादा को पूर्ण रूप से विकसित होने का मौका नहीं मिला, यह दूसरी बात है। यथास्थान हम उस पर लौटेंगे।

ऊपर सूत्र रूप में जो कुछ कहा गया, उसके ढांचे में विचार करते हुए जिस सबसे बड़े तथ्य पर हमारी दृष्टि जाकर जम जाती है, वह यह है कांग्रेस का जन्म उन लोगों में एका पैदा करने में सहायक हुआ, जो अब तक विभिन्न भाषाओं, जातियों, धर्मों, उप-

जातियों, श्रेणियों और उपश्रेणियों में बड़े विखरे थे और हरेक अपनी डेढ़ इंच की मस्जिद में अपनी डफली बजा रहा था। श्री पी० वी० बार्णे के अनुसार धर्मशास्त्रों में केवल 172 जातियों का उल्लेख है, पर भदु मनुभारी के अनुसार इन जातियों की संख्या हजारों में पहुँच चुकी थी। यहाँ तक कि मुसलमानों, ईसाइयों, सिक्खों में भी जातिभेद बहुत गहरा था। धर्मों में सज्जो सम्प्रदाय और फिर्के थे, जो एक दूसरे का गला घाटने को उद्यत थे। जब इस्लाम का उदभव भी नहीं हुआ था, उस समय भी जैनियों के विरुद्ध इतना विद्वेष था कि कहा गया कि हस्तिना ताड्यमानोपि न मृच्छेन जनमदिरम' यानी यदि हाथी पीछा कर रहा हो, तो भी जैन मन्दिर में आश्रय न ले। मुसलमानों में शिया, सुन्नी अहमदिया न जाने कितने फिर्के हैं। पाकिस्तान में बानूनन अहमदिया को गैर मुस्लिम और उनकी मसजिदों को अममजिद घोषित किया गया है। सिक्खों में मजहबों सिक्ख हैं, जिनका दर्जा अलग है और अहमदियों की तरह निरकारियों को सिक्ख धर्म के बाहर माना गया है।

मध्य युग में बहुत से हिंदू मुसलमान हो गए, पर जया कि बी० इब्नटसन ने 'पञ्जाब वास्टम' में लिखा है, धर्मपरिवर्तन से जातिपात पर असर नहीं पड़ता था। राजपूत, गुजर, जाट अपनी अपना हिंदू विरादरी के अधिन करीब थे। उच्च वर्णों से आए हुए मुसलमान शरीफ और निम्न वर्णों से आए सांग रजौल कहलाते थे। ईरान और आक्सस नदी के उस पार से आए हुए मुसलमानों को विलायती कहकर उन्हें ईरान की दृष्टि से देखा जाता था। सुन्नी शिया लोगों का रफीजी समझने थे और ईमानदार जुलाहों, कसाईयों, मित्रियों, खानवेगिया (भगियों) को घटिया समझा जाता था। सिक्खों में और यहाँ तक कि ईसाइयों में भी जातिभेद प्रचल है। नानक, कबीर, रामदास, चैतन्य ने जो एक दूसरे को निवट लाने के आन्दोलन चलाए, वे जातिभेद की चट्टान पर टकराकर टूट फूट गए।

भारत में बीस से करीब मुख्य भाषाएँ हैं। एक भाषा होती तो हम में एका भाषाम होता, यह भी शायद एक मिश्रण है, क्योंकि ऐसी स्थिति में अरबों का एक जाति होना चाहिए था। अरबों का तो धर्म भी एक है। ईरान और ईराक आपस में टक्कर ले रहे हैं यद्यपि उनका धर्म मूलतः एक है।

सारी बातों का निचोड़ यह कहा जा सकता है कि भारत एक बहुधर्मी, बहु भाषाभाषी देश है। अंग्रेज इस कमजोरी को अच्छी तरह जानते थे और इसका फायदा उठाकर हमेशा के लिए हम पर राज्य करना चाहते थे। उन्होंने इसका एक दशनशास्त्र बनाया जिसका नाम है White man's burden—इसका अर्थ यह कि श्वेत जातियों पर यह दायित्व था बोझ है कि वे श्वेतोत्तर जातियों पर राज्य करके उन्हें सभ्य बनाते रहें। इस दशन को अब नया नाम देकर सम्पूर्ण श्वेत देश उसे अपने लोगों को 'ग्लोबल रेस्पॉसिबिलिटी' यानी विश्व-दायी जिम्मेदारी बताते हैं।

जब कांग्रेस का जन्म हुआ, उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी सम्प्रदायों, धर्मों, भाषाओं, मतमता-तरो में बड़े लोगों की आवाज़ में एकरूपता लाना। इस एकरूपता के सामने क्या मार्गें हो, उसका लक्ष्य क्या हो, दिशा क्या हो, यह सब धीरे धीरे विकसित हुआ। दिशा के स्पष्टीकरण और आविष्करण के साथ साथ उसे कैसे प्राप्त किया जाए, क्या उपाय किए जाए, आदि उलझन भरे प्रश्न भी उठे।

कांग्रेस से पहले इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए और भी बहुत से व्यक्ति और संस्थाओं ने कार्य किया, पर ये व्यक्ति अकेले थे और संस्थाएँ प्रादेशिक तथा स्थानीय। स्वदेशीय स्तर पर कोई काम नहीं हुआ था।

भारत में उस समय ब्रितानिया की ईस्ट इंडिया कम्पनी का राज्य था। यदि योड़े में कहा जाए तो लार्ड क्लाइव से लेकर जितने भी अंग्रेज शासक हुए, उनका एकमात्र उद्देश्य लूटमार, राज्यविस्तार और भारत का दोहन करने अपने देश के लोगों की उन्नति करना था। मंच कहा जाए तो इंग्लैंड की औद्योगिक 'राति' इसी कारण द्रुत हुई कि भारत से लूटे हुए धन का सहारा उसे मिला, नहीं तो वैज्ञानिक आविष्कार, जैसे स्टीम इंजन का आविष्कार, आदि बातें पुस्तकों के पन्नों में पड़ी पड़ी पीली पड़ जाती। वैज्ञानिक आविष्कार होते गए और पूँजी से उनका पृष्ठपोषण होता गया।

कुछ भारतीय यह जल्द ही पहचान गए कि भारतीयों को अंग्रेजी सीखकर संसार की मुख्य धारा में प्रवेश करना पड़ेगा। ईस्ट इंडिया कम्पनी नहीं चाहती थी कि भारतीय अंग्रेजी की उच्च शिक्षा प्राप्त करें, उनके लिए बलक ही पर्याप्त थे। पर कम्पनी के इस विरोध के बावजूद 1817 की 20 जनवरी को हिंदू रईसों के रथों में बलकत्ता में हिंदू कॉलेज खुल गया। इसमें अंग्रेजी के साथ-साथ संस्कृत पढ़ाने की भी व्यवस्था हुई। इस प्रकार भारतीयों के प्रयत्न में ही अंग्रेजी उच्च शिक्षा की पहली संस्था खुली। यह उस नवजागरण का आरम्भ था जो अनेक रूपों में बढ़ा और पनपा और जिसकी परिणति कांग्रेस की अंग्रेजी द्वारा स्थापना और फिर भारतीयों द्वारा रूप-परिवर्तन में हुई।

### राममोहन राय का उदय

राममोहन राय (1772-1833) भारतीय नवजागरण के पुणेष्ठा कहे जा सकते हैं। वह अंग्रेजी और भारतीय भाषा विद्या, दर्शन तथा धर्म शास्त्रों के ज्ञाता थे। वह बहुत ही उदार विचारों के व्यक्ति थे, और घटनाओं तथा वस्तुओं की भविष्य की दृष्टि से देखने में समर्थ थे। वह जिस युग में पले, उस युग में पश्चिम की उदीयमान एजीवादी सभ्यता और भारतवर्ष की ह्रास शील सामंतवादी धार्मिक सभ्यता में प्रबल संघर्ष हो रहा था। राममोहन ने इन दोनों सभ्यताओं का अच्छी तरह अध्ययन किया था, और उनकी यह राय बन चुकी थी कि भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा अपनानी चाहिए।

राममोहन राय शास्त्रों का अध्ययन करते-करते इस नतीजे पर पहुंचे कि हिंदू धर्म का सार एकेश्वरवाद है, न कि बहुदेव देवी पूजा। उन्होंने 1804 में ही फारसी में 'तहफ़ात उलमुमाहिदीन' नामक एक ग्रंथ लिखा, जिसमें एकेश्वरवाद को पुनः स्थापित किया। कहना न होगा कि उनकी इस चेष्टा से पादरी बहुत नाराज हुए, और मजे की बात यह है कि कई कट्टर हिंदू भी उनसे नाराज हुए। पर वह इससे दबने वाले नहीं थे। 1815 में उन्होंने वेदांत का भाष्य लिखा, और उसमें फिर एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया। उन्नीस साल उन्होंने मानिकतल्ला में आत्मीय सभा नाम से एक सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य वेदांत की आलोचना करना था। यही आत्मीय सभा 1828 में उपासना समाज, ब्राह्म सभा या ब्राह्म समाज में परिणत हो गई।

राममोहन राय केवल दार्शनिक क्षेत्र में ही लोहा लेकर चुप नहीं रहे, उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन किया और 1829 तक इसे सरकार को कानूनन बंद कर देना पड़ा। इस संबंध में राजा राममोहन को पंडितों से बहुत लोहा लेना पड़ा।

राममोहन राय ने शीघ्र ही ब्राह्म समाज की स्थापना की। इसमें सब धर्मों की अच्छी बातों को अपनाया गया। इसमें भूति पूजा पर प्रहार किया और विधवा विवाह को अपनाया। राममोहन दुनिया की हलचलों से परिचित थे, और उनके विषय में बहुत प्रगतिशील दृष्टि रखते थे। कहा जाता है कि आस्ट्रिया द्वारा इटली के रौंदे जाने पर उन्हें बड़ा अफ़सोस था। जिस समय वह इंग्लैंड जा रहे थे, उस समय उन्होंने एक फ़ेंच

जहाज पर फास की क्रांतिकारी पताका देखी। इस पर वह इतने मुग्ध हुए कि उन्होंने उस जहाज को खड़ा करवाया, उस पर चढ़े और चिल्ला-चिल्लाकर फास की जम बोलने लगे। एक विवरण के अनुसार यह घटना केप आव गुड हाप में हुई और इस मौके पर उत्तेजना के कारण उनके पैरों में जो चोट आई, वह अत तक बनी रही। सदन में रहते समय भी उन्होंने अपना देशी पहनावा नहीं छोड़ा। यह बात शायद आज काई बहुत महत्त्व की न जचे, पर उस युग में जब कि लोग अंग्रेजों के साथ का अर्थ ही ईसाई हो जाना तथा शराब पीना समझते थे, यह बहुत बड़ी बात थी। वह 'भारतवर्ष को स्वतंत्र, ब्रिटेन का मित्र तथा एशिया को रोशनी देने वाले' के रूप में देखना चाहते थे।

## पत्रकारिता का विकास

राममोहन ने अपने मत के प्रचार की दृष्टि से समाचार पत्र भी निवाले। इस प्रकार वे बंगला गद्य तथा पत्रकार कला के आदि पिताओं में भी हैं। भारतवर्ष में सबसे पहला गैरसरकारी छापाखाना श्रीरामपुर के बपटिस्ट मिशनरिया ने खोला था और 1780 की 29 जनवरी का जेम्स अगस्टस हिकी ने 'बंगाल गजट' नाम से जो अखबार निकाला, वही भारतवर्ष का प्रथम समाचार पत्र था। 1826 में प्रकाशित 'उदत्त मातङ' हिंदी का पहला पत्र था। इसका प्रकाशक कानपुर के युगलकिशोर शुक्ल थे, जो सदर दीवानी अदालत के एक कर्मचारी थे। पत्र केवल डेढ़ साल चला गया कि लोगो ने इसे नहीं अपनाया। 1830 तक बंगला में तीन दैनिक और तीस अंग्रेजी पत्र थे। पत्रों की स्वाधीनता के सपना का एक निराला ही इतिहास है। हम उसके ग्योरे में नहीं जाएंगे, इतना ही बता दें कि इसमें भी राजा राममोहनराय का नाम अमर रहेंगा। 4 दिसम्बर, 1821 को उन्होंने 'सम्वाद बौमुदी' नाम से एक पत्र निकाला। इस पत्र में वे नियमित रूप से लिखते थे। वे जो कुछ लिखते थे उनका अनुवाद साथ ही साथ जेम्स सिल्क बर्किहम के 'केलकटा जनल' में प्रकाशित होता था। इन्हीं सब कारणों से चिढ़कर भारत सरकार ने 1823 में बर्किहम को भारत से निकालकर इंग्लैंड भेज दिया। बाद में यह सज्जन पार्लियामेंट के मेम्बर हो गए, और वे फिर उही बातों को पार्लियामेंट में कहने लगे जिनके लिए उनको भारत से निकाला गया था।

1823 में ही यह कानून बनाया गया कि कोई भी व्यक्ति बिना इजाजत के न तो छापाखाने का मालिक हो सकता है और न उसको इस्तेमाल ही कर सकता है। कहना न होगा कि इस कानून से छापाखाना तथा पत्र जगत पर कुठाराघात हुआ। वस क्या था, राममोहन राय तथा अन्य पांच प्रमुख व्यक्तियों ने इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दे दी। ये पांच व्यक्ति थे—चंद्रकुमार ठाकुर, द्वारकानाथ ठाकुर, हरिश्चंद्र धोष, गौरीचरण चट्टोपाध्याय और प्रसन्नकुमार ठाकुर। पर बहा इनकी कौन धुनता था? यह दरखास्त *Aeropagatica of the Indian Press* नाम से मशहूर है। 'सम्वाद बौमुदी' के अतिरिक्त राममोहन 12 अप्रैल 1822 से 'मीरतुल अखबार' नाम से एक फारसी अखबार भी निकालने लगे थे। जब उक्त गलाघोट कानून बना तो उन्होंने 4 अप्रैल 1823 को इसके प्रतिवाद में 'मीरतुल अखबार' का प्रकाशन बंद कर दिया।

## रगभेद

राममोहन ने भारतीयों और गैरों में भेदभाव के विरुद्ध भी आंदोलन किया। 1828 में उन्होंने इस नियम के विरुद्ध आंदोलन किया कि हिंदू और मुसलमानों के मुकदमों में ईसाई जूरी हो सकते हैं, पर ईसाइयों के मुकदमों में हिंदू या मुसलमान

जुरी नहीं हो सकेंगे। उन्होंने इस सबध में त्रैफोड को अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में लिखा कि यदि इस प्रकार का भेदभाव जारी रहा, तो वह दिन आ सकता है जब हिंदू और मुसलमान मिलकर इस अवायवपूर्ण कानून के विरुद्ध लड़ेंगे, और उसमें उन्हें कामयाबी हासिल होगी। उन्होंने कुछ कड़ाई के साथ यह लिखा कि भारतवर्ष आयरलैंड नहीं है कि दो बार जगी जहाजों से खोफ खा जाए। यदि भारतवासी आयरिशों का एक-चोथाई साहस भी दिखाएँ, तो देर भले ही लगे, वे अपने दुश्मनों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं।

इस प्रकार राममोहन नवयुग की प्रातिभूति तथा प्रतीक थे। यह आश्चर्य की बात है कि ऐसे मामलों में भी जिनमें अंग्रेजों का कुछ बिगड़ता नहीं था, उन्होंने राममोहन को वर्षों तक टरकाया। सती दाह एक ऐसी कुप्रथा थी जिसके सम्बन्ध में दो राय नहीं हो सकती थी, पर इस सम्बन्ध में भी सरकार ने दीघसूत्रीपन से काम लिया। जब इसका आन्दोलन जोरों से उठाया गया, तो भी लाठ बेलेजली पूछताछ करके ही रह गए। वे समझते थे कि यह प्रथा खराब है, किन्तु वे अपने साम्राज्य का हित इसी में समझते थे कि प्रथा में हस्तक्षेप न किया जाए। बहाना यह था कि सरकार धार्मिक बातों में हस्तक्षेप करके जनता में क्षोभ उत्पन्न करना नहीं चाहती। परन्तु सरकार ने ऐसी सक्ड़ो बातें की जिनसे जनता को क्षोभ हुआ—जैसे यहाँ की बारीगरी का नाश करके हजारों लोगों की रोजी छीन लेना। इसलिए क्षोभ की बात असली नहीं थी। सरकार ऐसे मामलों में क्षाभ उत्पन्न करने से नहीं डरती थी जिनसे उसका काम बनता था।

कुछ अच्छे उदारचित्त अंग्रेज भी थे, जिनमें हिको और बकिंगहम का नाम आ चुका है। डिरोजियो हिंदू कालेज में शिक्षक बनकर आए और उन्होंने भी भारतीयों का साथ दिया। परन्तु डिरोजियो की शिष्य मण्डली और राममोहन द्वारा प्रचारित कार्यक्रम में एक बहुत बड़ा फक यह था कि डिराजियो के शिष्य अपने सुधारों में धर्म का आधार नहीं मानते थे। धर्म को सब कुसकारों का जनक बनाकर उन्होंने धर्म के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा की थी। वे बहुत से ऐसे काम करते थे, उदाहरणार्थ, उन्होंने उसी युग में छुआछूत त्याग दिया था और गो-मांस आदि भक्षण किया था, इत्यादि। पर वह लोगों को ईसाई बनाने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। लोगों को डिरोजियो से इतनी धबकाहट हुई कि हिंदू कालेज कमेटी ने 25 अप्रैल 1831 को उन्हें कालेज से निकाल दिया। इसके बाद डिरोजियो ने पहली जून से 'ईस्ट इंडिया' नाम से एक जम्बवार निकाला। दुर्भाग्य से उसी साल 26 दिसम्बर को उनकी मृत्यु हो गई, नहीं तो इसमें सन्देह नहीं कि वह कालेज के जरिये जो सबा कर रहे थे, अब उसी को अखबार के जरिये व्यापक रूप में जारी रखते। डिराजियो के शिष्यों में नई नवजागृति के नेता हुए। पुराने लोग उनसे जिस प्रकार धबकाते थे, उसकी कोई जरूरत नहीं थी, यह इस बात से साबित है कि डिराजियो की शिष्य मण्डली में केवल कृष्ण मोहन व दोषाध्याय ही ईसाई हुए, बाकी लोगों ने सुधार कार्यों में भाग लिया। कृष्ण मोहन भी बराबर राष्ट्रीय विचार के रहे।

6 अक्टूबर 1831 को ब्रिटिश संसदीय समिति के सामने गवाही देने हुए मेजर जनरल सर लाइनोल स्मिथ ने कहा था—“अंग्रेजी शिक्षा के फलस्वरूप भारतीयों का मन में एक दिन स्वतंत्र होने की भावना जागेगी। उस समय हमें भारतवर्ष छोड़कर चला जाना पड़ेगा।” बाद को भकाले नाम के सुप्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान ने बड़े जोरा के साथ इस बात की सिफारिश की कि भारतवर्ष में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किया जाए। यह सिफारिश करते हुए उन्होंने बहुत सी अप्रासंगिक बातें भी कही, जैसे उन्होंने कहा कि



भारत की सभ्यता तथा संस्कृति दो बौद्धी की है, पर उन्होंने जो सिफारिश की वही इस सम्बन्ध में द्रष्टव्य है न कि उनकी दी हुई गालियाँ तथा सतरानियाँ।

एक तरफ तो 1835 के करीब अंग्रेजी शिक्षा की संगठित चेष्टा हुई, दूसरी तरफ उन्हीं दिनों अर्थात् 1835 में ही 15 सितम्बर को सर चार्ल्स मैटथाफ ने भारतीय छात्रों को स्वतंत्रता दे दी। इसका नतीजा यह हुआ कि देश में स्वतंत्र आलोचना तथा प्रगतिशील विचारों का सूत्रपात हुआ। इन दिनों प्रसन्न कुमार का साप्ताहिक पत्र 'रिफार्मर' खूब चलता था। इस पत्र के जरिए अंग्रेजी शिक्षित वर्ग में प्रगतिशील विचारों का प्रचार हुआ, तथा धीरे धीरे लोग यह महसूस करने लगे कि भारतीयों और गोरों में भेद नहीं होना चाहिए। पर भेद तो था और इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रीय भावना की जड़ में नस्लवाद के तत्त्व थे। यह स्मरण रह कि भारतीय राष्ट्रीयता में, बल्कि सभी औपनिवेशिक देशों की राष्ट्रीयता में, इस तत्त्व को खाने के लिए स्वयं अंग्रेज और दूसरे गोरों ही जिम्मेदार हैं। यदि वे धीरे से ही भारतीयों और गोरों में भेद भाव न करते, तो इस उपादान की उत्पत्ति ही न होती। उनकी आत्मावक्ता के विरुद्ध बचाव के रूप में पदचलित भारतीयों में इस उपादान का उत्पन्न होना आवश्यक और अनिवार्य था।

### आरम्भिक संस्थाएँ

बंगाल में बंगभाषा प्रकाशिका सभा, फिर जमींदार सभा बनी। जमींदार सभा में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब बड़े जमींदार थे। ये लोग पैस खाले होने के नाते अंग्रेजों की बराबरी करना चाहते थे। वे किसानों की भी कुछ उन्नति चाहते थे, क्योंकि किसान समझ होगा तो उनकी भी भलाई होगी।

बाद की जमींदार सभा ने अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाने के लिए यह तय किया कि विलायत में आन्दोलन किया जाए। राममोहन राय का 1833 में ही देहान्त हो चुका था। 1839 की जुलाई में विलियम ऐडम नामक एक अंग्रेज ने अंग्रेजों को भारतीय शिक्षा के बारे में उद्बुद्ध करने के लिए ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी नाम से इंग्लैंड में एक सभा की स्थापना की थी। विलियम ऐडम राममोहन के मित्रों में थे, और वह जब तक इस देश में रहे, भारतीयों पर उनका विशेष स्नेह रहा। जमींदार सभा ने 30 नवम्बर 1839 को यह तय किया कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलायत में जमींदार सभा द्वारा उठाई हुई मांगों के सम्बन्ध में आन्दोलन करे। 1841 में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के मुखपत्र के रूप में 'ब्रिटिश इंडिया एडवोकेट' नामक एक पत्र प्रकाशित होने लगा जिसके सम्पादक हुए विलियम ऐडम। ऐडम को गुलामी प्रथा के विरुद्ध आन्दोलन में प्रसिद्ध जाज टामसन का भी सहयोग प्राप्त हुआ। 17 जुलाई, 1843 को जमींदार सभा की एक बैठक में यह तय हुआ कि जाज टामसन विलायत में सभा के एजेंट हैं। पर जमींदार सभा कुछ ही दिन टिकी।

यह स्वाभाविक भी था क्योंकि देश में जमींदार थे कितने। देश की उदीयमान मध्यवर्ती श्रेणी का जमींदार सभा में कोई स्थान था और न हो सकता था। इसी बीच 'सोसाइटी फॉर एडवोकेटेशन ऑफ जनरल नैलिंग' यानी ज्ञानोपायिका सभा की स्थापना हो चुकी थी। इस सभा के स्थायी सभापति ताराचंद चक्रवर्ती और मंत्री प्यारीचंद मित्र थे। इस सभा के अधिवेशन में इतिहास, साहित्य, राजनीति, सभी विषयों पर व्याख्यान दिए जाते तथा निबन्ध पढ़े जाते थे। सभा के सदस्य कई अखबार भी चलाते थे।

ज्ञानोपाजिका सभा के 8 फरवरी, 1843 वाले अधिवेशन में दक्षिणारजन मुखोपाध्याय ने एक निबन्ध पढ़ा। इस निबन्ध में सरकार की कार्यवाहियों की बहुत कड़ी टीका की गई थी। अधिवेशन हिंदू कालेज के भवन में हो रहा था। कालेज के अध्यक्ष कैप्टन डी० एल० रिचर्डसन भी सभा में उपस्थित थे। जिस समय दक्षिणारजन अपने निबन्ध के उम अंश को पढ़ रहे थे, जिसमें सरकार की टीका की गई थी, रिचर्डसन आपे से बाहर हो गए, और अपना अधिकार जताते हुए बोले कि मैं हिंदू कालेज भवन को राजद्रोहियों के गढ़ में परिणत होने नहीं दे सकता। इस पर सभा के सभापति ताराचंद विगड गए और उन्होंने कहा कि इस समय रिचर्डसन एक निमित्त की तरह यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्हें कोई हक नहीं है कि वे इस तरह की बात कहे। उन्होंने कहा कि यह सभापति का काम है कि वह देखे कि कौन क्या कह रहा है और जो कुछ कह रहा है, ठीक कह रहा है या नहीं। सभापति ने रिचर्डसन से कहा कि आप अपने मतव्य वापस लें, नहीं तो यह मामला कालेज के अधिकारियों, यहाँ तक कि सरकार के सामने पेश किया जाएगा। रिचर्डसन का अपना वक्तव्य वापस लेना पड़ा।

उस युग के लिए यह मामला बहुत बड़ा था। एंग्लो इंडियन अखबार 'इंगलिशमैन' ने इस मामले को बहुत तूल दिया। प्रगतिशील दल का चन्धर्ती गुट करार देकर उसके विरुद्ध हमले किए गए। 'फ्रैंड आफ इंडिया' नामक अखबार ने तो महा तक लिखा कि यदि कोई इस प्रकार का व्याख्यान बटेविया में देता, तो इसके लिए वक्ता को कम-से-कम देश से निकाल दिया जाता। इधर सरकारपरस्त अखबारों ने ऐसा लिखा, उधर राष्ट्रीय अखबार 'बंगाल हरकरा' ने दक्षिणारजन के पूरे निबन्ध को अपने 2 और 3 मार्च के अंक में छाप दिया, और साथ ही यह लिख दिया कि इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं, जिसके कारण रिचर्डसन तथा उसके भाई बन्द इतने विगडे हैं।

पर ज्ञानोपाजिका सभा का वैचारिक दायरा बड़ा होते हुए भी कार्यक्षेत्र छोटा था। यह तय हुआ कि भारतवर्ष के भगल के लिए और भारत में ब्रिटिश सरकार की अनति एवं कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए सब जातियों तथा धर्मों की एक सस्था बनाई जाए और इसका नाम 'बंगाल ब्रिटिश इण्डिया सोसाइटी' हो। सस्था के उद्देश्य के सबंध में तय हुआ कि यहाँ के विषय में सब तरह के तथ्या का संग्रह किया जाए, तथा शांति-पूबक और वैध उपायों से ऐसी कारवाई की जाए, जिसके फलस्वरूप भारत में सभी श्रेणियों की भलाई हो और उनके उचित अधिकार तथा स्वाधों का संरक्षण हो। यह न समझा जाए कि इस सस्था के निर्माता बागी थे। इनके उद्देश्यों में यह साफ कर दिया गया कि सस्था मल्का विक्टोरिया के प्रति श्रद्धा रखकर और उनके शासन तथा कानून को मानकर ही कार्रवाई करेगी।

यह सभा बन गई तो उसके सदस्यों में ज्ञानोपाजिका सभा के बहुत से लोग आए। सच तो यह है कि यह उसी सस्था का दूसरा तथा विस्तृत रूप था। इस सभा के मंत्री भी प्यारीचांद मित्र हुए पर सभापति आज टामसन बनाए गए। पूर्वोल्लिखित ताराचंद इस सभा के असली नेता थे। यद्यपि टामसन इसके सभापति थे, भारत स्थित साधारण अंग्रेज इस सभा की कारवाइयों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। उनका मुख पत्र 'फ्रैंड आफ इण्डिया' बराबर इस सभा पर कड़ी टिप्पणी करता रहता था। टामसन के भारत में रहते ही बंगाल स्पेक्टेटर 20 नवम्बर, 1843 को बंद हो गया। इस पर ताना बसते हुए 'फ्रैंड आफ इण्डिया' ने लिखा कि "इस देश के लोगों के द्वारा कोई अच्छा काम कराना कितना अमम्भव है इसका प्रमाण टामसन इस देश में रहते हुए ही पा गए।"

उक्त सस्या भी अधिक दिन नहीं टिकी। इसके बाद सत्यबोधिनी सभा की स्थापना हुई और उसने 'तत्त्वबोधिनी' पत्रिका निकाली। कबीर रवीन्द्र के पिता देवेन्द्र नाथ ठाकुर इस सस्या के प्रवक्तक थे। इस सभा का उद्देश्य यह था कि दाशनिष्ठ स्तर पर ईसाइयत का विरोध किया जाए। यहाँ हम यह देख लें कि भारतीय राष्ट्रीयता के माथे साय हिन्दू अभ्युत्थान का आंदोलन कदम रखकर चल रहा था, यद्यपि जैसा कि हमने बंगाल ब्रिटिश इण्डिया सोसाइटी के उद्देश्यों में देखा, नारा यह था कि सब जानियो तथा घरों के लोगों की आम भलाई हो।

इस जमाने में हिन्दुओं में केवल विद्रोही सम्प्रदायों के रूप में ही ब्राह्मसमाज, आर्यसमाज आदि की उत्पत्ति हुई ऐसी बात नहीं, बट्टरसनातनी हिन्दुओं में भी सुधार की लहरें जोरों से चल रही थी। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर सम्पूर्ण रूप से बट्टरपथी पण्डित थे। उनके पिता भी पुराने ढंग के पण्डित थे। सारा ज्ञानदान पुराने ढंग का ही था, पर विद्या सागर एक सुधारक के रूप में हमारे सामने आते हैं। उनके प्रयत्नों का फल 26 जुलाई, 1856 को सामने आया जब विधवा विवाह सम्बन्धी कानून बन गया। विद्यासागर ने बहुविवाह को गद्द कराने के लिए भी आंदोलन किया। उन्होंने 25 हजार व्यक्तियों के दस्तखत से एक प्रार्थनापत्र भेजा। पर कुछ नहीं हुआ। स्वतंत्र भारत में ही हिन्दुओं का बहुविवाह बंद हुआ। इसके अतिरिक्त विद्यासागर ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए एक स्कूल भी खोलवा दिया।

## 1857 का महाविद्रोह

दश की विदेशी शासन में मुक्त करने का एक सगंभीर भारतव्यापी प्रयास 1857 में हुआ। वह हमारे स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम अध्याय था। सावरकर ने इस पर एक पूरा ग्रंथ लिखकर साबित किया है कि सामंती उपादान के बावजूद जनता इस विद्रोह के साथ थी। डा० भगवान दास माहौर ने लिखा है "सत्तावनी प्राति कोई सहसा पूट पड़ी और मामाजिक स्थिति से असम्बन्ध एकाकी घटना नहीं है। यह अंग्रेजी राज के विरुद्ध जनता और सिपाहियों के विद्रोह की एक सम्बन्धी परम्परा की विकसित कड़ी है।"

1857 के असफल विद्रोह का 100 साल बाद मूल्यांकन करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने 10 मई 1957 को कहा था—“वह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक नाराजगी का इजहार था और अंग्रेजी हुकूमत को निकालने की कोशिश थी। यह कोशिश किसने की, मिलके की, या अलग अलग की? जहाँ तक अब मालूम होता है, यह कोशिश कोई बहुत मिलके नहीं हुई थी। लेकिन आम जववा इस हिस्से में फँसा हुआ था और जहाँ एक भी चिगारी लगी तो फिर वह आग फैल गई। यानी कोई एक बहुत इतना काम करके यह भुकावला नहीं किया गया था। इस बारे में जो किस्से मालूम हुए हैं, वे भी आपने सुने होंगे कि चपातिया बटी थी। यह एक इशारा था कि लोग तैयार रहें। और भी ऐसे किस्से हैं। लेकिन जहाँ तक मालूम होता है, कोई बड़ा इतना काम करके यह बात नहीं हुई थी, बल्कि एक चिगारी थी जिसका फायदा उठाया गया। यह आम नाराजगी थी, मुख्य लिफ तबको में, ज्यादातर ऊँचे तबको में। राजाओं में जमींदारों में, ताल्लुकेदारों में तो यह नाराजगी थी ही, साथ ही सब कहीं आम लोगों में भी यह नाराजगी जरूर थी। किसी कदर यह बिल्कुल दुरुस्त है कि जो विदेशी राज यहाँ कायम हुआ था, उसके खिलाफ जववा और उसके निकालने की कोशिश की गई इसमें कोई शक नहीं।

“विदेशी राज हिन्दुस्तान में कैसे आया? वह भी बजोब कहाँनी है। वह कोई एकाएक घूमघाम से या बड़ी फतह करके नहीं आया था। वह हल्के हल्के आया। लोगो

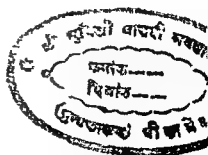
को मालूम भी नहीं हुआ कि कोई विदेशी राज आ रहा है, इस तरह से वह आया। पहले तिजारत के नाम से अंग्रेज यहाँ आए। तिजारत के साथ साथ कुछ और अखिबारात भी उन्होंने हासिल कर लिए। सौ बरस तक वे अपने को हुकूम नहीं कहते थे। वह अपने को मुगल बादशाह के दीवान, या इसी तरह कुछ कहते थे, हालांकि हुकूमत अंग्रेज कर रहे थे। यानी ऊपर एक रंग था और साथ ही पुराने सिलसिले भी चलत जाते थे। इस ढंग से, एक तरह परदे के पीछे से अंग्रेजी साम्राज्य यहाँ कायम हुआ। आखिर में मुगल बादशाह की हुकूमत दिल्ली के लाल किले तक रह गई थी। करीब-करीब समझिए कि वह गिरफ्तार से थे। यह एक परदा सा रहा और आम लोग एक जमाने तक यह समझें भी नहीं कि कोई दूसरी हुकूमत यहाँ कायम हो गई है। खाली यहाँ ही नहीं, बंगाल में भी ऐसा ही हुआ। मिन 1857 के वाक्य से जरा पहले अवध में जब अंग्रेजी ने वहाँ के नवाब को गद्दी से उतारा, तो जाहिर हुआ कि वे अब सीधे तौर से हुकूमत करने वाले हैं। तो इससे एक बड़ा धरका लोगों को पहुँचा और मुल्क में मुहल्लिफ बातें हुईं।

"इसमें तो कोई शक और शुबहा नहीं कि 1857 में जो कुछ हुआ, वह अंग्रेजी हुकूमत या विदेशी हुकूमत के कायम होने के खिलाफ एक जज्बा था, एक बलवा था, एक जग थी। वह बहुत इतजाम करके नहीं शुरू हुई, वह एकाएक इत्फाकन शुरू हो गई। एक जगह हुई, उसका असर दूसरी जगह हुआ लेकिन तभी असर हुआ न, जब एक जज्बा फैला हुआ था?"

हम यहाँ 1857 के विद्रोह के सम्बन्ध में इतना ही कहकर आगे बढ़ते हैं कि 29 मार्च, 1857 को माल पाडे ने क्रांति के लिए निर्दिष्ट तारीख (31 मई) के पहले बरकपुर छावनी में अंग्रेज अफमरो पर गोशिया चला दी। इससे क्रांति शुरू हो गई। मगल पाडे ने अपने का घिरा दगकर अपने का गोली मारने की चेष्टा की, पर असफल रहे। उन्हें 8 अप्रैल, 1857 को फाँसी दी गई। उनकी फाँसी देने के लिए बाहर से ऐसा जल्लाद बुलाया गया जिस पता नहीं था कि वह किसे फाँसी दे रहा है।

क्रांति के नेताओं में थे बाजीराव पणवा के उत्तराधिरारी नाना साहव, फाँसी की विधवा महारानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे, रंगोजी, अजीमुल्ला खा इत्यादि। अंतिम मुगल सम्राट वहादुरशाह जफर न (जिनका राज्य लाल किले के इर्दगिर्द तक सीमित था) इसका औपचारिक नेता होना स्वीकार किया था जो बहादुरी की बात थी। विद्रोह दूर तक हुआ, पर जैसा नेहरू जी ने कहा तैयारी अधूरी थी। लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार होकर भयंकर युद्ध के बाद शहीद हो गई। उन क्रांतिकारियों में अजीमुल्ला के विचार सुनकर हुए थे, जसा कि उनके लिखे भङागीत में प्रकट है। गीत इस प्रकार था—

हम हैं इसके मालिक हिन्दुस्तान हमारा  
पाक वतन है वीम का जनत स भी पारा।  
यह है हमारी मिलियत, हिन्दुस्तान हमारा,  
इसकी रहानियत से रोशन है जग सारा।  
कितना कर्मी कितना नईम सब दुनिया में प्यारा,  
करती है जिसे जरखज गगजमुन की धारा।  
ऊपर बर्फीला पर्वत पहरदार हमारा  
नीच साहिल पे बजता सागर का नक्कारा।  
इसकी खानें उगल गयी हैं सोना हीरा पारा  
इसकी शानोगीबत का दुनिया में जयकारा।



आया फिरयी दूर से ऐसा मन्तर मारा  
 लूटा दोनो हाथो से 'यारा वतन हमारा ।  
 आज शहीदो ने तुमको अहले वतन ललकारा  
 तोडो गुलामी की जजीरें बरसाओ अगारा ।  
 हिंदू, मुस्लिम, सिख हमारा भाई भाई प्यारा  
 यह है आजादी का झंडा इसे सलाम हमारा ।

यह गीत विद्रोह का झंडागीत था, और उस समय के क्रांतिकारी अक्सर 'पयामे आजादी' में छपा था। इस गीत में स्पष्ट है कि 1857 में ही कम-से-कम उनके नेता अजीमुल्ला ऐसे लोग धर्म निरपेक्षता की चोटी पर पहुंच चुके थे।

क्रांतिकारी अजीमुल्ला—अजीमुल्ला ने गोरो के यहां खानसामे का काम करके अंग्रेजी और फेंच का ज्ञान प्राप्त किया था। अपने इसी ज्ञान के कारण भारतीय राजाओं की ओर से प्रतिनिधि बनाकर वह इंग्लैंड भेजे गए थे। वहां कुछ वक्त न देखकर वह और रंगोजी (ये दूसरे राजाओं की तरफ से पैरोकार होकर गए थे) सारे यूरोप का भ्रमण करते रहे। फिर दोनों परिपक्व मन से क्रांति में रुढ़ पड़। उनकी कविता में उनके विचार प्रतिफलित हैं, जो युग की दृष्टि से बहुत प्रगतिशील थे। इकबाल लिखित 'सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा' गीत इसी गीत का परिमार्जित रूप लगता है। छंद भी वही, कई उपमाएं भी वही। अजीमुल्ला के गीत में 'मजहब नहीं सिखाता आपस में बर रखना' का रूप है 'हिंदू, मुस्लिम, सिख हमारा भाई भाई प्यारा।' इसके अलावा इस गीत में गुलामी की जजीरो को तोड़ने की ललकार है जो इकबाल के तराने में नहीं है।

1857 के विद्रोह में हिन्दुओं और मुसलमानों का खून एक साथ बहा और जब फासी की बारी आई, सब लोग (बिना किसी मुकदमे की औपचारिकता के) नीम और दूसरे पेड़ों पर लटकाए गए। 'पयामे आजादी' के सम्पादक मिर्जा बेदारबख्त के बदन पर सूअर की चर्बी मलकर फासी दी गई। यही नहीं, जिस घर से भी 'पयामे आजादी' की कोई प्रति मिली, उसके लोगो को फासी दे दी गई। बाद में हमने गणेशशंकर विद्यार्थी जैसे और भी सम्पादक लेखक पदा किए, जिनका एक पैर सदा जेल के अंदर रहा। मिर्जा बेदारबख्त ऐसे सम्पादकों में अग्रगण्य थे।

1857 का विद्रोह इसके पहले हुए कई प्रकार के विद्रोहों का उबाल बिंदु बनकर भ्रमक उठा था। 1764 में दिल्ली के बादशाह बक्सर की लड़ाई में हारकर 1766 में बंगाल, बिहार उड़ीसा की दीवानी सौंपने पर बाध्य हुए थे। सभी से विद्रोह की आग धुआली, भीतर भीतर घघकती रही। पहाड़ी कबीले भी विद्रोह करते रहे। कोस किसानों ने 1831-32 में विद्रोह किया क्योंकि उनकी जमीन बाहरी सिखों और मुसलमानों को दी गई। 1836 के करीब राजमहल की पहाड़ियों में सत्ताल विद्रोह हुए। यह विद्रोह चक्र विसाई के नेतृत्व में हुआ। वर्षों तक यह वीर लड़ता रहा। 1828 में अहोम राजवंश के गोमधर कोवार ने विद्रोह की घोषणा की। उन्हें सात साल की सजा हुई पर 1830 में फिर विद्रोह हुआ। 1829 में तीरत सिंह के नेतृत्व में खासी विद्रोह हुए। हारे हुए तीरत सिंह से कहा गया कि तुम हमारी अधीनता स्वीकार कर राज्य करो पर उसने उत्तर दिया, 'पराधीन राजा से स्वाधीन व्यक्ति अच्छा।' वह 1834 में प्रवास में मरे। नेपाल के साथ भी लड़ाई हुई। दक्षिण में तिरवाकुर दरबार के साथ झगड़े चले।

1818 में पेशवा की पराजय के बाद रामोशी विद्रोह हुए। 1844 में गढ़करी

विद्रोह हुआ। इसी प्रकार मुसलमानों के कुछ विद्रोह हुए जो वलीउल्ला आदोलन नाम से ज्ञात हैं।

1764 में पहला सिपाही विद्रोह हुआ। 240 व्यक्ति तोपों से बांधकर उठा दिए गए। 1824 में वेल्लोर में एक सिपाही विद्रोह हुआ था।

यहां हमने कुछ ही विद्रोह गिनाए हैं पर ये सारे विद्रोह स्थानीय, सीमित अस्पष्ट उद्देश्ययुक्त विद्रोह थे। इस कारण ये चिनगारिया फूक मारकर बुझा दी गई थी। 1857 का विद्रोह कुचल दिए जाने के बाद कुछ समय के लिए विद्रोह भावना दब गई परन्तु वह नष्ट नहीं हुई और फल्गुनदी की तरह जमीन के भीतर-भीतर बहती रही।

## हिन्दू मेला

1861 में जातीय गौरव सम्पादनी सभा नामसे एक संस्था मेदिनीपुर में स्थापित हुई। श्री राजनारायण वसु ने इसकी स्थापना की थी। यही सभा 6 साल बाद प्रसिद्ध हिन्दू मेला में परिणत हो गई। इस काय में नवगोपाल मिश्र तथा गणेशनाथ ठाकुर ने उन्हें बड़ी मदद दी। 1866 में चैत्र मास के अन्त में पहले-पहल यह मेला हुआ। मेले के अवसर पर ही राष्ट्रीय शिल्पकला की पहली प्रदर्शनी हुई। कसरत, छुरे और तलवार के खेल दिखाए गए। इस अवसर पर 'नेशन' और 'नेशनल' शब्द का बहुत प्रयोग हुआ। मेले के संगठनकर्ताओं के मन पर इटली में चलने वाले राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव था। इन्हीं दिनों जर्मनी का एकीकरण भी हो रहा था। मातृभाषा के प्रति प्रबल अनुराग का भी यही से जन्म होता है। गुड मॉनिंग आदि सम्भाषण की जगह पर 'सुप्रभात' आदि शब्द इस्तेमाल किए जाने लगे। सभा के सदस्यों में जो लोग बातचीत में अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल करते थे, उन्हें प्रत्येक अंग्रेजी शब्द के लिए एक पैसा जुमाना देना पड़ता था।

इस सम्बन्ध में और एक द्रष्टव्य बात यह है कि यद्यपि इसके कर्ताधर्ता सभी बंगाली थे, पर लोग अखिल भारतीय रूप में सोचते थे। हिन्दू मेला के अधिवेशन में सत्येन्द्रनाथ ठाकुर रचित 'गाओ भारतेर जय' जो गाना गाया जाता था, उसमें भी 'भारत' शब्द था न कि 'बंग'।

मुख्य हिन्दू मेले के अतिरिक्त देहाना में भी अपना अपना हिन्दू मेला होने लगा। रवीन्द्रनाथ ने कई अवसरों पर इस मेले में भाग लिया। 1877 के मेले में उन्होंने एक कविता पढ़ी थी। कविता में प्रमुख बात यही है कि इसमें बराबर 'भारत' शब्द आया है न कि 'बंग'।

हिन्दू मेले के लोग दूर भविष्य में स्वतंत्रता की भलक भी देखते थे। इसी अवसर पर स्वदेशी का नाग पहले पहल दिया गया, और यह कहा गया कि लोग स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार करें।

हिन्दू मेले के नेतागण ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन के कड़े आलोचका में थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन में अधिकतर राजा, जमींदार इत्यादि थे, और वह जमींदार सभा बन गई थी। वे कट्टर राजभक्त भी थे। मनमोहन वसु ने एक बार व्यंग्य करते हुए कहा था कि हिन्दू मेले में जो लोग धन देंगे, वे चाहे कितना धन दें पर रायबहादुर राजा नहीं हो सकते। यही कारण था कि हिन्दू मेले में जो दो राजा थे, वे धीरे धीरे खिसक गए। पर हिन्दू मेले के सामने कोई निदिष्ट वायव्य न रहने के कारण वह एक हद तक ही जा सका।

## वहाबी

1857 के विद्रोह की असफलता के बाद भी मुस्लिम वहाबी बराबर छिट-पुट रूप में अपना कार्य करते रहे। पटना इन दिनों उनका प्रधान केन्द्र था। 1871 में उनके नेता अमीर खा को 1818 के रेगुलेशन 3 के अनुसार नजरबंद कर दिया गया। वहाबियों ने इस पर बम्बई के प्रसिद्ध बैरिस्टर मिस्टर ऐनेस्टी को बलकत्ता लाकर इस नजरबंदी के विरुद्ध अपील की और यह कहा कि यदि अमीर खा ने कोई अपराध किया है, तो उसका फसला खुली अदालत में होना चाहिए। मिस्टर ऐनेस्टी ने अपनी पैरवी के दौरान साक्ष्यों के जमाने में जो ज्यादातिया हुई थी, उनका उल्लेख किया। उनका यह बक्तूरा राजनीतिक थी और वहाबियों ने इसे पुस्तिका के रूप में छपवाकर बटवा दिया। 'यायाधीश नारमैन' के मामले में मुकदमा पेश था। मिस्टर ऐनेस्टी की योग्यतापूर्ण वकालत के बावजूद यह मुकदमा खारिज हो गया।

वहाबियों ने इस बात को या ही ग्रहण नहीं किया और अब्दुल्ला नामक वहाबी ने मिस्टर नारमैन पर छूरे से हमला कर दिया। वह उसी रात मर गए। अब्दुल्ला को इस सम्बन्ध में फासी हुई, और गारे उससे इतना नाराज थे कि फासी के बाद उसकी लाश को कब्र देने की बजाय उसे जला दिया। इसी के तुरन्त बाद 1872 की 8 फरवरी को जब लाठ भेयो अण्डमन का दौरा करने गए थे, शेरअली नामक एक वहाबी ने उन्हें मार डाला। यह शेरअली खैबर घाटी का रहने वाला था और मामूली इतिहासों में शेरअली को एक मामूली अपराधी के रूप में दिखाया जाता है, पर वह वहाबी थे और उनका उद्देश्य राजनीतिक था। यह कहा जा सकता है कि भारतवर्ष में 1857 के बाद आतंक बोली डग के आन्दोलन का सूत्रपात अब्दुल्ला और शेरअली ने किया।

## आर्यसमाज

उत्तर भारत में इसी समय स्वामी दयानन्द का उदय हुआ। उन्होंने 1875 में बम्बई के गिरगाव मुहल्ले में आर्यसमाज की स्थापना की। स्वामी जी का सुधार कार्य राममोहन राय, देवे द्रनाथ तथा केशवचन्द्र से भिन्न किस्म का था। पहले तीन सज्जनों का मुंह बहुत कुछ यूरोप की ओर था, पर स्वामी दयानन्द ने यूरोप की ओर पीठ कर रखी थी। राममोहन आदि मानते थे कि सभी धर्मों में सत्य है, वे उन धर्मों के सत्यों पर ही जोर देते थे पर स्वामी जी का मत भिन्न था। वह वैदिक धर्म में ही पूरा सत्य का प्रकाश मानते थे बाकी सब धर्मों को भ्रान्त समझते थे। उनकी लिखी पुस्तक 'सत्याथ प्रकाश' इस बात का प्रमाण है। मुख्यतः वह पुस्तक दूसरे धर्मों के विरोध के उपादान से पुष्ट है और इसमें खण्डन का अंश ही प्रधान है। ईसाई मुस्लिम धर्मों के अतिरिक्त उन्होंने अठारह पुराण, भूतिपूजा शव, शाक्न, चण्णव सम्प्रदाय का भी खंडन किया। उनके अनुसार वेदा का आदेश ही भारत का आदेश था।

आर्यसमाज में यह जो विरोधमूलक उपादान था, यह कोई स्वामी दयानन्द के स्वभाव से उत्पन्न नहीं था, बल्कि इसके गहरे सामाजिक कारण थे। अब तक मुसलमान तथा ईसाई ही अपने धर्म में दूसरों को भर्ती करते थे, पर स्वामी दयानन्द ने हिंदुओं में सुप्त शुद्धि प्रथा को फिर से जलाया जिसके अनुसार अब दूसरे धर्म के लोग भी आर्य समाज में भर्ती किए जान लगे। दूसरे धर्म के लोग भी अब हिंदू हो सकते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि दूसरे धर्म वालों की तरफ से इसका प्रबल विरोध हुआ परन्तु हिंदू समाज में उनका बहुत प्रचार हुआ।

स्वामी दयानंद बहुत व्यावहारिक आदमी थे। उस युग में जसा प्रचार था, वह बड़े-बड़े पंडितों में शास्त्रार्थ करते थे और इस प्रकार अपने मत का प्रचार करते थे। यद्यपि आर्यसमाज का नारा यह था कि 'वेदों के युग में लौट चलो' फिर भी आर्यसमाजियों ने अंग्रेजी शिक्षा से परहेज नहीं किया और यद्यपि आर्यसमाज ने मुस्कूल खुलवाए, उन्होंने कई बड़े कालेज भी स्थापित किए। स्वामी दयानंद ने सारे भारत का पयटन किया। स्वामी जी ने जिन बातों पर विशेष ध्यान दिया, वह था संस्कृत और हिन्दी का प्रचार, वेदों का अध्ययन, हिंदू समूहन, शुद्धि, विधवा विवाह, इत्यादि। पुरातनवादी होते हुए भी उन्होंने सुधार के महत्वपूर्ण कार्य किए।

## अन्य समाजों का कार्य

इसी युग के लगभग रामकृष्ण परमहंस का भी प्रचार हुआ। वे राममोहन या दयानंद की तरह विद्वान नहीं थे, पर वे सबधर्म समन्वय में विश्वास करते थे और इसकी कार्यरूप में बहुत दूर तक ले गए थे। वह बहुत दिनों तक बिल्कुल अलग अलग धर्मों के अनुसार चले और अपनी जगह पर बड़े बड़े सरल दृष्टान्तों से अपने मत का प्रचार करते रहे। बाद में स्वामी विवेकानंद ने इनका पहले भारतवर्ष में और फिर भारत के बाहर भी प्रचार किया।

राममोहन राय के अन्तिम तीन वर्ष मुख्यतः इंग्लैंड में व्यतीत हुए, जहाँ वह अपना राजनैतिक-सामाजिक कार्य करते रहे। 1833 में ब्रिस्टल में उनका देहांत हुआ, उनकी मृत्यु के बाद ब्राह्मण समाज के कई भाग हा गए। कबीर रवींद्र के पितामह द्वारकानाथ ठाकुर सामने आए। महान वक्ता केशवचंद्र सेन बाद का एक सफल धर्मनेता बने।

1867 में केशवचंद्र सेन की यात्रा के परिणामस्वरूप महाराष्ट्र में प्राथमिक समाज का जन्म हुआ, जिसका उद्देश्य था समाज सुधार। बाद में इसमें एम० जी० रानडे और भार० जी० मंडारकर के आ जाने से चार बाद लग गए। 'सुबोध पत्रिका' नाम में एक पत्र निकाला गया और मजदूरों के लिए रात्रि विद्यालय जारी हुआ। पंडिता रमाबाई के द्वारा स्त्रियों के आंदोलन की बल मिला। उन्होंने आर्य महिला समिति की स्थापना की। रानडे लगातार समाज सुधार में लगे रहे। वह प्रचलित जगमिध्यावाद का विरोधी थे। उन्होंने हर बात में अनीति की ओर देखने की निन्दा की। उन्होंने आजस्वी व्यय में पुनर्जन्मवाद का विरोध किया। कहा—'क्या बारह प्रकार के पुत्र और आठ प्रकार के विवाह का पुनर्जन्म करें जिनमें राक्षस विवाह भी है? क्या हम मर्त्य प्रथा को फिर से जीवन करें या फिर नदी में जीवित शिशुओं को तथा आदमियों को फेंके या जगन्नाथ के रथ के नीचे लागा को कुचलना जारी करें?' वह आधुनिकता के पक्षधर थे। हिंदू मुस्लिम मिलन के हामी थे। उन्होंने कहा, अबबर के सारे मुख्य सलाहकार हिंदू थे तथा इसके विपरीत उसकर और गजेब न अपन पैरा पर कुल्हाड़ी मारी।

केशवचंद्र सेन की ही यात्रा से मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई। इसके नेता थे वी० राजगोपालाचार्य, पी० सुब्रायला चेटी और तलंग लखन दायमूर्ति त्रिधनाथ मुदातियर। वेद समाज को के० श्रीधरालू नायडू ने चमका दिया। वह बलवत्ता गए और बहुत सी पुस्तकों के अनुवाद किए, पर 1874 में एक दुष्टता में उनकी मृत्यु हो गई।

इस युग में छोटे मोटे तरीके पर सारे भारतवर्ष में सुधारमूर्त आन्दोलन जारी थे। अधिग्रहण आंदोलन का राजनीतिक आंदोलनों से कोई विशेष सम्बन्ध न होने पर



भी इनका राजनीति पर बहुत भारी प्रभाव पड़ा। 1857 के विद्रोह को इस निंदयता के साथ दबाया गया था कि भारतवासियों की आत्मा विलकुल टट चुकी थी। तिस आगे-काले का भेद, अधिक शोषण, दुर्भिक्ष, फूट, सामाजिक कुप्रथाओं ने भारतीयों को बहुत दुबल कर रखा था। ऐसे समय में इन सुधारकों ने ही भारतीयों का यह वाणी सुनाई कि नहीं, तुम ऊपर उठ सकते हो। किसी ने कहा, तुम्हारा धर्म और सस्कृति औरों के बराबर है, किसी ने कहा, तुम्हारा धर्म और सस्कृति सबसे ऊँची है। विवेकानंद और केशवचंद्र ने विदेशों में जाकर यह प्रमाणित कर लिया कि यहाँ के लोग इतने तुच्छ नहीं हैं, जितना उन्हें समझा जाता है। दुनिया भी उनसे बहुत कुछ सीख सकती है। इसी युग में इंडोलाजी या भारततत्व का जोर हुआ। राममोहन के समसामयिक महाकवि गेटे जैसे व्यक्ति 'शकुंतला' को विश्वसाहित्य की महान कृति बता चुके थे। भारतीय दशन पर शोध जारी थे। सस्कृत भाषा से सब भाषाएँ निकली, यह भी मत चला था। हम धर्म को मानें या न मानें यह मानना पड़ेगा कि इन सुधारकों ने भारतीयों में एक नई जान फूँक दी। पददलित तथा पराधीन भारतवासियों ने इनके मुँह से धर्म के रूप में ही सही, नवीन युग की नई वाणी सुनी। इन लोगों ने अपने अपने ढंग से लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाया। उन लोगों ने अपने अपने युग में बड़ा कार्य किया।

ये लोग हिंदू थे, इसलिए इनकी भाषा हिंदू प्रतीकों से पूर्य थी। परिणामस्वरूप जो राष्ट्रीयता बनी, उसका रूप बहुत कुछ हिंदू ही गया।

### सर सैयद अहमद

अब तक मुसलमानों के कुछ नेता यह विश्वास करते थे कि मुसलमान राज्य फिर से वापस आ सकता है। इसी आशा के कारण वे अंग्रेजी शिक्षा से अलग रहे थे, पर अब मध्यवर्त्ति अंग्रेजी के कुछ मुसलमानों में इस ज्ञान का उभेय हुआ कि हिंदू बहुत आगे बढ़े जा रहे हैं, मुसलमान पिछड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें भी अंग्रेजी शिक्षा अपनानी चाहिए। इस विचार को लेकर बंगाल में नेशनल मोहमेन्ट एसोसिएशन की स्थापना हुई। इन लोगों को बहादुरियों की तरह विद्रोह के माग में विश्वास नहीं था। वे वैध आन्दोलन के पक्षपाती थे।

पर उत्तर भारत में ही इस आन्दोलन ने पूरा जोर पकड़ा और सेनानिबल सरकारी नौकर सर सैयद अहमद खा के नेतृत्व में 1874 की 24 मई को अलीगढ़ कालेज की स्थापना हुई। उनके सलाहकार थे एक अंग्रेज अध्यापक बैंक। वहीं से पढ़े लिखे मुसलमानों का संगठित प्रयास शुरू होता है। ये अलीमुस्ला या बेदारब्रत के माग पर नहीं चले। ये अब्दुल्ला या शेर अली से भी दूर थे।

### अन्य संस्थाएँ

उस युग के नेताओं में सुरेद्रनाथ बनर्जी का स्थान प्रमुख है। वह पहले सिविल सर्विस में थे। एक छोटी तकनीकी गलती के कारण वह उससे निकाले गए। इसके विरुद्ध अपना मुकदमा लड़ने वह इंग्लैंड गए थे। वह अंग्रेजी के बहुत अच्छे वक्ता थे। जन 1875 में इंग्लैंड से लौटने के बाद वह छात्र संगठन के साथ साथ इस कार्य में लगे कि कैसे एक अखिल भारतीय संस्था बने। आनंदमोहन बोस और सुरेद्रनाथ बनर्जी ने मिलकर 26 जुलाई, 1876 को इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। यह एक बहुत ही मजबूत बात है कि इटली के एकीकरण से अनुप्रेरित होकर ही इन लोगों ने अखिल भारतीय आधार पर सोचा कि जो नई संस्था बने, वह अखिल भारतीय आन्दोलन का केन्द्र

हो। मेजिनी के विचारों से अनुप्राणित होकर समुन्नत भारत की धारणा, या कम से कम समूचे भारत की एक राजनीतिक मंच पर लाने की कामना बंगाल के सब नेताओं के मन में समा चुकी थी। तदनुसार इस नई संस्था का नाम 'इण्डियन एसोसियेशन' रखा गया।

इसे सब धर्मों के नागरिकों का सहयोग मिला। रेवरेण्ड के० एन० वैनर्जी के बाद कालीचरण वैनर्जी अपने जमाने के सबसे बड़े भारतीय ईसाई नेता थे। बाद को ये इण्डियन एसोसियेशन के सभापति हुए। इन्होंने इस एसोसियेशन के निर्माण का यह कहकर विरोध किया कि इस प्रकार की एक एसोसियेशन इण्डियन लीग के नाम में कुछ महीने पहले स्थापित हो चुकी है। सुरेन्द्रनाथ ने उनके तर्कों का उत्तर दिया और सभा ने उनकी बात मानकर संस्था को जन्म दिया। इण्डियन लीग ने भी अच्छा काम किया था। 'अमृत बाजार पत्रिका' के शिशिरकुमार घोष, 'रईस एण्ड रैपट' के डॉक्टर शम्भू चन्द्र मुर्जी और मोतीलाल घोष उस संस्था के प्राण थे। पर अब इसे खत्म करके इसके प्रमुख सदस्य इण्डियन एसोसियेशन में शामिल हो गए। संस्था के उद्देश्यों में जनता को सावजनिक आंदोलन में ले जाना प्रमुख था।

### बकिमचन्द्र

इही दिनों बंगाल में बकिमचन्द्र का उदय हुआ। वह डिप्टी मैजिस्ट्रेट थे, और बन्धेमातरम मन्त्र के गायक थे। वह 1872 से 'बग दर्शन' प्रकाशित कर रहे थे, और बराबर पाच साल तक इसे प्रकाशित करते रहे। इस पत्र ने बंगाल के पढ़े लिखे बग में जान फूँक दी और साहित्यिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में बंगाल को सबसे अगली कतार में ला रखने में मदद दी। पर बकिमचन्द्र अपने युग की उपज थे, इसलिए उन्होंने जिस आक्रमणात्मक राष्ट्रीयता का अपने उपन्यासों तथा लेखों में प्रतिपादन किया, उस पर हिन्दुत्व का पुट था। 'आनन्दमठ' नामक उनके उपन्यास में बन्धेमातरम गाना जिस पृष्ठभूमि में आया है, वह कट्टर मुसलमानों को पसन्द नहीं आया। स्मरण रहे कि उसकी रचना 'आनन्द मठ' से कई साल पहले हुई थी और उसे उपन्यास में बाद की पिरोया गया था। बकिम ने कानून से बचने के लिए 'आनन्द मठ' उस रूप में लिखा था। अन्य देशों में भी ऐसा हुआ था—लक्ष्य कोई और था, पर किसी और पर ढालकर बात कही गई।

उस युग में बहुत से भारतीय ईसाई प्रगतिशील थे। बाद के युग में उन्होंने राजनीतिक आंदोलन में अधिक दिलचस्पी नहीं ली, पर उस युग में बहुत से ईसाई प्रगतिशील आंदोलन के साथ रहे। इसका कारण शायद यह हो कि उस जमाने में लोग प्रगतिशीलता के कारण ही ईसाई होने के लिए बाध्य हुए क्योंकि हिन्दू समाज बहुत सकीर्ण था।

सुरेन्द्रनाथ इन दिनों देश भर में व्याख्यान देते हुए घूमने लगे। विशेषकर छात्रों पर उनका बहुत प्रभाव पड़ा। जिन विषयों पर उन्होंने व्याख्यान दिए, उनकी देखने से उस समय की राष्ट्रीयता और भी स्पष्ट होती है। सुरेन्द्रनाथ ने पहला व्याख्यान तो सिख शक्ति के उत्थान पर दिया। दूसरा व्याख्यान श्री चैतन्यदेव विषय पर दिया। इसके बाद कुछ व्याख्यान मेजिनी और नवीन इटली पर दिए। उनके व्याख्यानों के श्रोताओं में नरेन्द्रनाथ दत्त (बाद के स्वामी विवेकानन्द), विपिनचन्द्र पाल आदि थे। विपिनचन्द्र ने अपनी आत्म कथा में इस बात का प्रभावशाली वर्णन किया है कि इस जमाने में इन व्याख्यानों का युवकों के मन पर कैसा प्रभाव पड़ता था। उन्होंने लिखा है

"हम लोगों ने आस्ट्रिया के अधीन इटली के निवासियों तथा अंग्रेजों के अधीन भारतवासियों की अवस्था में बहुत कुछ समता देखी। हमने यह देखा कि कलकत्ते के

बाहर भारतीय और गेरा में यदि किसी प्रकार का मुकदमा उठ खड़ा होता है, तो उसमें भारतीयों को 'याय नहीं मिलना'। एक ही सिविल सर्विस के अंदर भारतीयों और गेरों में जिन प्रकार भेद था, उसमें हमारे दिलों में जलन पैदा होती थी। आसाम के चाय बगीचों के कुलिया की दुदशा उन दिनों दशो अखबारों में कुछ-कुछ निकलने लगी थी। 'अमृत बाजार पत्रिका' में मैजिस्ट्रेटों के जुल्मों की बात अक्सर निकला करती थी। जब इस बातवर्णन में हमने मैजिनों के द्वारा परिचालित स्वतंत्रता सभाम की बात पढ़ी, तो हमारा मन बहवपन से भर गया। हम लोग मैजिनी के लेख और नवीन इटली के आंदोलन का इतिहास पढ़ने लगे। हम लोग धीरे धीरे इटली की स्वतंत्रता के आंदोलन, विशेषकर कारवोनरी सस्था के साथ परिचित हो गए।" (मैजिनी कारवोनरी के साथ सम्बद्ध थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्देश्य से इटली में जो गुप्त समितियाँ बनी थी, उन्हीं को कारवोनरी कहते थे।)

स्वामी विवेकानन्द बड़े भारी अंतर्राष्ट्रीयतावादी थे। उन्होंने कहा था "राज नीति और समाज विज्ञान में भी जो समस्याएँ बीस साल पहले तक राष्ट्रीय समझी जाती थी, अब केवल राष्ट्रीय आधार पर उनका समाधान नहीं हो सकता। अब वे विशाल रूप धारण कर रही हैं। उनका समाधान तभी हो सकता है जब अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि की विस्तृततर पृष्ठभूमि में उनको देखा जाए। यह युग अंतर्राष्ट्रीय संगठनों अंतर्राष्ट्रीय सस्थाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का है, लोग इसी की मांग कर रहे हैं।"

स्वामी जी ने बाद में इन विचारों को और भी विस्तृत रूप दिया, यहाँ तक कि उन्होंने अपने को समाजवादी भी घोषित किया। उन्होंने कहा "मैं इस कारण समाजवादी नहीं हूँ कि मैं समाजवाद को एक सम्पूर्ण पद्धति समझता हूँ बल्कि इसलिए कि कुछ भी रोटी न मिलने में आधी रोटी मिलना अच्छी बात है। दूसरी जो पद्धतियाँ थी, उनको मीका दिया जा चुका है और देखा गया है कि उनमें कसर है। इसलिए इस पर अमन किया जाना चाहिए और किसी कारण से नहीं तो इसलिए कि इसमें नवीनता है।"

उस युग में मैजिनी और गैरीबाल्डी का भारतीय देशभक्तों पर बड़ा असर पड़ा था, यहाँ तक कि कलकत्ता के ठाकुर खानदान के लोग भी गुप्त समिति बनाने लगे। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी आत्मकथा में इस प्रकार की एक गुप्त समिति का उल्लेख किया है।

## इण्डियन एसोसियेशन का कार्य

अब हम फिर इण्डियन एसोसियेशन या भारत सभा के इतिहास पर लौटते हैं। जैसाकि नाम में ही स्पष्ट है इस सभा की अखिल भारतीय दृष्टि से संगठित किया गया था। पंडित ईश्वरचन्द्रविद्यासागर तथा जस्टिस द्वारकानाथ मिश्र बंगाल एसोसियेशन नाम से एक सभा संगठित करना चाहते थे, पर सुरेन्द्रनाथ ने कहा कि नहीं इस सभा को अखिल भारतीय दृष्टिकोण से संगठित करना चाहिए। यों तो इण्डियन लोग भी अखिल भारतीय दृष्टिकोण रखती थी, पर उसका यह विचार कागज पर ही रह गया, और उसे मौका भी कम मिला। इण्डियन एसोसियेशन की शाखाएँ भारत में फैली और सुरेन्द्रनाथ ने जब भी कोई बात उठाई तो सारे भारत का दौरा कर डाला।

मध्यपर्वण मुद्दा—जिन मुद्दों पर भारतीय नवशिक्षित वर्ग चिंतित, दुग्ध तथा उत्तेजित था, उनमें एक प्रधान मुद्दा यह था कि आई सी एस में भारतीय लिए जाए, अधिक सदस्य में लिए जाए भारत में परीक्षा हो इत्यादि।

आंदोलन के पलस्वरूप 1853 में यह तय हुआ था कि सिविल सर्विस के लिए

प्रतियोगिता की जाएगी और उम्मीदवारी की उम्र 23 से कम होगी। उम्मीदवारों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद फौरन नौकरी नहीं दी जाती थी। उन्हें दो साल तक अप्रेंटिस रहना पड़ता था। 1859 में इन नियमों में भी परिवर्तन हुआ। नये नियमों के अनुसार सिविल सर्विस परीक्षार्थी की उम्र घटाकर 22 कर दी गई और अप्रेंटिसी का समय एक साल कर दिया गया। सबसे मजे की बात यह थी कि कहने को तो परीक्षा प्रतियोगितामूलक थी, पर व्यवहार में कुछ ऐसा नियम रखा गया था जिससे गोरों तथा भारतीय परीक्षार्थी में इतना भेद हो जाता था कि किसी भी हाल में भारतीय परीक्षार्थी के लिए गोरों परीक्षार्थी का मुकाबला करना कठिन होता था। गोरों परीक्षार्थी ग्रीक और लैटिन नंबर परीक्षा देते थे और भारतीय परीक्षार्थी संस्कृत या अरबी लेते थे। साधारण बुद्धि की बात तो यही थी कि इन दोनों तरह के विषयों पर एक से उम्बर होते, पर नहीं, संस्कृत और अरबी में केवल 375 नम्बर थे और ग्रीक और लैटिन में 750 नम्बर थे। यह बड़ी अद्भुत व्यवस्था थी।

इस व्यवस्था से पता चलता है कि किस प्रकार ऊपर में बराबरी का दावा होना पर भी भीतर-भीतर के भारतीय मनोभाव से डरते थे, तभी तो यह पैक उतारने लगाए। 1859 में संस्कृत और अरबी का नम्बर बढ़ाकर 500 कर दिया गया परन्तु फिर भी भारतीयों को बहुत असुविधा रही। 250 नम्बर का फल बहुत होता है। आश्चर्य नहीं कि इस बीच जितने भारतीय परीक्षार्थी गए, वे सबके सब असफल रहे, केवल सत्येन्द्रनाथ ठाकुर परीक्षा में कृतकार्य रहे। यद्यपि दस साल में एक श्री ठाकुर ही इस परीक्षा केतरफों को पार कर सके, फिर भी इससे अंग्रेजों में इतनी खलबली मची कि नम्बर घटाकर फिर 375 कर दिये गये।

हम जानते हैं कि बाद की दृष्टि से सिविल सर्विस के इस इतिहास का कोई मूल्य नहीं है, पर साम्राज्यवादी 'याय' के नमूने को दिखलाने तथा यह स्पष्ट करने के लिए कि अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीय क्यों अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध होते जा रहे थे, हमने इसका कुछ धोरा यहाँ दिया है।

इस व्यवहार पर शिक्षित भारतवासियों में जो असंतोष सुलग रहा था उस पर रोकथाम करने के लिए 1870 में कानून बना कि भारत सरकार का चाहिए कि योग्य भारतीयों को सिविल सर्विस के ओहदों पर नियुक्त करे। इस कानून में यह भी कहा गया कि सिविल सर्विस के 1/6 पदों पर भारतीयों को नियुक्त किया जाय, पर यह केवल कामजी सब्ज बाग रहा। इसके विपरीत 1876 की 24 फरवरी को सिविल सर्विस के परीक्षार्थियों की उम्र घटाकर 19 कर दी गई, जिससे भारतीयों की असुविधा बढ़ गई क्योंकि माध्यम अंग्रेजी था और भारतीयों को अंग्रेजी के साथ अंग्रेजी के माध्यम से प्रतियोगिता करनी थी।

सरकार जब चाहती थी कि इन पदों पर भारतीयों की नियुक्ति हो ? इन्हीं दिनों भारत के बड़े साट लिटन ने एक गुप्त गश्ती पत्र में लिखा — भारतीयों की यह मांग कि सिविल सर्विस में उन्हें नियुक्त किया जाय, कभी नहीं मानी जा सकती। इस लिए दो ही रास्ते हैं, एक तो यह कि उनसे साफ साफ कह दिया जाय कि तुम लोगों को इस पद पर नहीं लिया जाएगा और दूसरा यह कि उन्हें धोखा दिया जाय, और सब्ज बाग दिखाया जाए। हम लोगों ने दूसरे माग को ही चुना है। एक तो इंग्लैंड में जाकर भारतीय परीक्षा दें, और परीक्षार्थियों की उम्र बराबर घटे। इन बातों का उद्देश्य यह है कि इस सम्बन्ध में जो वाद किए गए हैं, उन्हें तोड़ा जा रहा है। मैं जो पत्र लिख रहा हूँ वह गुप्त पत्र है, इसलिए इस बात को कहने में हज नहीं कि हमने जिस बात का वादा

किया है काय रूप में उसका पालन नहीं किया है। इस पर कोई यदि हमसे जवाब तन करे तो हम कुछ कह नहीं सकते।”

सुरेन्द्रनाथ के नेतृत्व में बंगाल भर में सभाएँ तो हुई ही, और यह तय हुआ कि समस्त भारतीयों की तरफ से इस सवध में एक स्मरण-पत्र तैयार किया जाय और उसे ब्रिटिश संसद में भेजा जाय।

सुरेन्द्रनाथ ने जनमत तैयार करने के लिए सार भारतवर्ष का दौरा किया, और सब जगह सभाएँ हुई। उन्होंने इस सवध में पंजाब, बंबई, मद्रास आदि प्रान्तों का भ्रमण किया, और वहाँ के जन नेताओं से भेंट की। यह इनाहाबाद में पंडित अयोध्या नाथ, लाहौर में गुरद्वार दयालसिंह मजोठिया, सतनऊ में पंडित विश्वम्भरनाथ, गढ़मूढाबाद के राजा, सुप्रसिद्ध हिंदी कवि भारत-दुर्हरिश्चंद्र, फिरोजगढ़ में हेतु, महादेव गोविंद रानडे, काशीनाथ व्यस्मक तलंग आदि जन नेताओं से मिले, और सबने उनके मन का समर्थन किया।

यह तय हुआ कि स्मरण पत्र लेकर एक भारतीय नत्ता स्वयं इंग्लैंड जाय, और संसद में सामने अपनी मांग पेश करे। तदनुसार भारत सभा ने बैरिस्टर लालमोहन घोष को इस काम के लिए चुना। लालमोहन ने विलायत जाकर बहुत से स्थानों पर व्याख्यान किया। उन दिनों जान ब्राइट ब्रिटिश गणन में चमक रहे थे। उन्हीं के सभा पतित्व में संसद भवन में एक सभा हुई, जिसमें लालमोहन ने इस सवध में भारतीयों की मांग का स्पष्टीकरण किया।

इस व्याख्यान का इतना असर पड़ा कि कहा जाता है कि 24 घण्टे के अन्दर ही लाल सलिसबरी ने 1870 में बनाए हुए नियम को कार्यान्वित करने का यत्न दिया। सिविल सर्विस को तो ज्यों का त्यों रखा गया, अब स्टैच्यूटरी सिविल सर्विस नाम से एक और तथा पहली से घटिया सिविल सर्विस का प्रबंध किया गया। इस सिविल सर्विस में जिन लोगों का लिया जाना था, उनके अधिकार बहुत कम रहे गए। पहले वाली सिविल सर्विस क्विन्टेड सिविल सर्विस कहलायी। इस दूसरी घटिया सिविल सर्विस के लोगों की तनख्वाह पहल की सिविल सर्विस की दो तिहाई थी। इसके अलावा उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त नहीं करना था। इस समय आंदोलन का इतना ही असर हुआ। कहना न हागा कि इससे जनमत सतुष्ट नहीं हो सका। अब भी आंदोलन सम्पूर्ण रूप से आवेदन निवेदन के दायरे में ही था, पर भारतीय जनमत को बड़े पैमाने पर संगठित करने की ओर चेष्टा की गई, वह एक महत्वपूर्ण कदम था।

## 1877 का दरबार

1876 में ब्रिटिश सरकार ने यह तय किया कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्पत्ती घोषित किया जाय। तदनुसार 1877 की पहली जनवरी को दिल्ली में एक बहुत बड़ा शानदार दरबार हुआ, जिसमें महारानी की नयी उपाधि घोषित की गई।

इसी के बाद 14 मार्च, 1878 को वर्नाकुलर प्रेस ऐक्ट के द्वारा अंग्रेजी के अलावा सब भाषाओं के पत्रों पर रोक लगा दी गई। इसका नतीजा यह हुआ कि उस युग के कई प्रसिद्ध बंगला अखबार प्रकाशन बंद कर देने के लिए बाध्य हुए। इस सिलसिले में 'जमत बाजार पत्रिका का नाम विशेष उल्लेखनीय है, क्योंकि उसने करीब करीब रात भर में अपने का एक बंगला पत्र से अंग्रेजी पत्र में परिणत कर दिया, और इस प्रकार इस कानून के शिकारों से बच गया। पत्रकारिता के इतिहास में यह एक अनोखी घटना है।

इसी समय आम्स ऐक्ट यानी अस्त्र कानून पास किया गया, जिसके अनुसार बिना लाइसेंस के बन्दूक, तमचा यहाँ तक कि तलवार रखने की भी मुमानियत हो गई। यह मुमानियत केवल भारतीयों के ही लिए थी।

फैलता हुआ यह असतोष बढ़ते बढ़ते वहाँ तक बढ़ता, पर इस बीच 1880 में इंग्लैंड में चुनाव हुआ, उसमें कजर्वेटिव पार्टी हार गई और ग्लेडस्टन की पार्टी विजयी हुई। इससे पहले ग्लेडस्टन ने अपने स पहल की सरकार की भारतीय नीति की सावजनिक रूप से निंदा की थी। उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस ऐक्ट, यहाँ तक कि आम्स ऐक्ट की भी निंदा की थी। जब उनकी पार्टी की सरकार बनी और लार्ड लिटन पद-त्याग करके चले गए, तो लार्ड रिपन आए। उन्होंने आते ही वर्नाकुलर प्रेस ऐक्ट को रद्द कर दिया। यद्यपि आम्स ऐक्ट जहाँ का तहाँ रहा। उनके सबसे बड़े कार्यों में एक यह है कि उन्होंने स्थानीय स्वायत्त शासन को आरम्भ किया। इससे पहले नगरपालिकाएँ तो कहीं-कहीं बन चुकी थी, पर इन पर जनता नियंत्रण नहीं था। सुरेन्द्रनाथ बहुत दिनों से आन्दोलन कर रहे थे कि नगरपालिकाओं पर जनता का नियंत्रण होना चाहिए। लार्ड रिपन ने इस सबबध में एक कानून बनाया जिससे नगरपालिकाओं और जिला बोर्डों पर जनता का नियंत्रण बहुत कुछ स्वीकार कर लिया गया। लार्ड रिपन ने बाद में किसानों के भी कुछ अधिकार बढ़ा दिए।

## इलबर्ट बिल

नए कानून से किसानों के सबबध में यह तय हो गया कि यदि किसान 12 साल तक लगातार जमीन को जोत चुका हो तो उसका उस पर हक हो गया, और यह भी तय हुआ कि जमींदार लगान पाने की रसीद दें।

व्यक्तिगत दृष्टि से देखने पर लार्ड रिपन ने जिस बात में सबसे बड़ा साहस दिखाया वह था इलबर्ट बिल। अय भेदों के अतिरिक्त अदालतों के सामने भी गोरे और कालों में भेद किया जाता था। यह बात शिक्षित भारतवासियों को यहाँ तक कि भारतीय राजकमचारियों को बहुत अछरती थी। जिस वय सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी ने आई सी एस पास किया था उसी वय श्री रमेशचन्द्र दत्त तथा बिहारीलाल गुप्त ने भी पास किया था। बिहारीलाल गुप्त कलकत्ता में प्रेसीडेन्सी मैजिस्ट्रेट थे। रमेशचन्द्र दत्त राजधानी के बाहर एक जिले के जिला मैजिस्ट्रेट थे। छात्र जीवन के बाद भी रमेश दत्त और बिहारीलाल गुप्त में सम्बन्ध बना हुआ था। रमेशदत्त ने एक बार बातचीत में बिहारीलाल गुप्त से कहा कि मुझे यह हक नहीं है कि मैं किसी गोरे का मुकदमा अपनी अदालत में ले सकूँ, पर मेरे नीचे जो गोरे मैजिस्ट्रेट हैं उनको यह अधिकार है। अवश्य ही यह एक बहुत अजीब परिस्थिति थी।

लार्ड रिपन ने जब इस मामले का अध्ययन किया, तो उन्हें भी यह बात ठीक जची, और उन्होंने कानून सचिव सर कोटनी इलबर्ट का यह हिदायत दी कि आप इस सम्बन्ध में मौजूदा कानून में सुधार कर एक बिल बनावें। यही बिल इलबर्ट बिल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ज्योंही भारत के गोरो को यह बात मालम हुई उन्होंने इस बिल के विरुद्ध प्रबल आन्दोलन शुरू कर दिया। 28 फरवरी 1883 को कलकत्ता के टाउन हाल में बिल के विरोधियों की एक रम्भा हुई, जिसमें भारतीयों को पानी पी पीकर कोसा गया। वक्ताओं ने केवल भारतीयों की ही नहीं, उन गोरो को, जिन्होंने इस बिल में हाथ बटाया था, यहाँ तक कि लार्ड रिपन को भी, हजारों गालियाँ दीं।

मिस्टर बकलैंड ने लिखा है कि "कलकत्ते के कुछ गोरो ने यह पड्यत्र किया था

कि यदि वायसराय इस कानून पर अड़े रहें, तो वे वायसराय भवन के सतरियों को बाह्य में करके वायसराय को गिरफ्तार कर चादपान घाट में एक स्टीमर पर बठा देंगे, और उन्हें कमोन्स अंतरीप भाग से इंग्लैंड भेज देंगे। छोटे साट तथा अन्य जिम्मेदार अपमरों को इस पद्धति का पता था। गोरों ने एक डिफेंस एसोसियेशन यानी आत्मरक्षा समिति भी बनाई थी बाद का चलन जो यूरोपीयन एमोसियेशन बनी, वह इसी का विकसित रूप थी।

गोरों के प्रवल आंदोलन के कारण जिम रूप में कानून का समविदा बना था, उस रूप में वह पाम 7 हो सका। 28 जनवरी, 1883 को इस रूप में कानून पाम हुआ कि देखने का ता प्रत्यक्ष भारतीय हाकिम को यह हक प्राप्त हुआ कि यह अपनी अदालत में किसी गोर के मुकद्दमा की सुनवाई करे पर गोरों मुल्जिम को भी यह अधिकार दिया गया कि वह यह भाग कर कि जूरी में स आधे गोरों हों। चूंकि राजधानी के बाहर जूरी के लिए इतने गोरों मिलना आसना नहीं था इसलिए होता यह था कि मुकद्दमा दूसरे जिले में भेज दिया जाता था या उसी जिले के किसी गोरों हाकिम के इजलास में भेजा जाता था। इन कारणों से स्थिति करीब करीब जहां की तहां रही।

यह सत्य है कि इलवट विन जिम रूप में पास हुआ, उससे भारतीय जनमत की कोई विशेष जीत नहीं हुई पर एक उदीयमान जाति की प्रगति में इस प्रकार का हार भी महत्व रखती है। सच तो यह है कि इस अवसर पर भारतीय जनमत की विजय होती, तो उसमें उनमें मन में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मबंध में कुछ ध्रम पदा हो सकते थे।

यह अक्सर कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीयता में नस्ली उपादान है। अवश्य ही यह बात अच्छी नहीं है। कोई किसी खास नस्ल में पैदा हुआ है, गोरों है या काला है इसी आधार पर उसको भला या बुरा मान लेना गलत है पर साथ ही इतिहास लेखक का यह भी तो काम है कि वह दिखाए कि यदि किसी के साथ कोई विशेष भावना संयुक्त हो गई तो उसका क्या कारण है। सनसन जैसे दुष्ट अंग्रेजों के कारण ही भारतीय राष्ट्रीयता में नस्ली उपादान आए। जिस समय गोरों इलवट बिल के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे उन्होंने सादजनिक मंचों से तथा पत्रों में यह कहा कि भारतीय तो गुलाम जाति है, वे हमेशा गुलाम रहे हैं, उन्हें भला गोरों के बराबर नागरिक अधिकार कैसे दिए जा सकते हैं। ऐसी युक्तियां की जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी वह हुई। ओपनि वैशिक देशों में ब्रिटिश जहां भी एक जाति में दूसरी जाति को पराधीन बनाया है वहां की जातीयता में नस्ली उपादान आ आना विरुद्ध स्वाभाविक है। मैं तो यहां तक कहता हूँ कि यदि नेतृत्व अच्छा हो, और वह अंतिम लक्ष्य यानी मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण के विरोध को न भूलें, तो वह इस उपादान का एक हद तक प्रगतिशील उपयोग भी कर सकता है।

इसी युग में एक और घटना हुई, जिससे जनता में बहुत तहलका मचा। एक मुकद्दमे के सिलसिले में यह प्रश्न उठा कि जिस शालिग्राम शिला पर कसम उठाने की प्रथा अदालतों में है वह पुरानी है अथवा नयी। इस पर कसकता हार्डकोट के मिस्टर जस्टिस नारिस ने हुक्म दिया कि बड़ा बाजार के बटुकनाथ पंडित अपनी शालिग्राम शिला को अदालत में पेश करें, जिससे उसकी शनायत की जा सके। इस पर ब्राह्मों पंडितों ओपिनियन के सम्पादक भुवनमोहन दास ने अपने अखबार के अप्रैल 1883 के एक में टीका करते हुए जज की ज्यान्ती की निन्दा की। उन निन्दा गुरे दनाथ अग्रजी पत्र 'बंगाली' के सम्पादक थे। उन्होंने भी 1883 के 28 अप्रैल के एक में लिखा "इसी

समय हमारे बीच में एक जज साहब मौजूद हैं जा यदि जफरी स्काग आदि के युग की याद नहीं दिलाते, तो कम से कम जब से वे हाई कोर्ट में हैं, तब से उनके इतने कारनामे हो चुके हैं कि लगता है, वह उस मर्यादा की परम्परा को कायम रखने में असमर्थ हैं, जो देश की सभ्य बड़ी अदालत की अब तक विशेषता रही है।”

स्मरण रहे कि भुवन मोहन दाम (देशबन्धु चित्तरजन दास के पिता) तथा सुरेन्द्र नाथ दोनो में से एक भी सनातन धर्मी नहीं थे, वे मूर्ति पूजा विरोधी थे, फिर भी उन्होंने अपने लेखों में केवल जनमत को प्रतिफलित किया था। गौरी के मुखपत्र ‘इंगलिशमैन’ से यह पता चलता है कि उस जमाने में जस्टिस नारिस के हिंदू मूर्ति को अदालत में ले आए जान के कारण भारतीय जनमत बहुत शुद्ध हुआ। ‘इंगलिशमैन’ की इस रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि सनातनी न होते हुए भी भुवन मोहनदास तथा सुरेन्द्रनाथ ने इस विषय पर बयो लिखा था।

### सुरेन्द्रनाथ को सजा

जस्टिस नारिस सुरेन्द्रनाथ की इस टिप्पणी को पी नहीं गए, उन्होंने फट से उन पर अदालत की अमर्याद का मुकदमा चलाया। इस पर पत्र में सपादकीय तौर पर सुरेन्द्रनाथ ने इस विषय पर अफसोस जाहिर किया, फिर भी फुल बेंच के सामने उन पर मुकदमा चला, और उन्हें दो महीने की सखी व द की सजा दी गई। फुल बेंच के जजों में जस्टिस रमेशचन्द्र मित्र ने यह राय दी कि चूंकि ऐसे ही एक मामले में भूतपूर्व जस्टिस पर वामस पीकाफ ने केवल जुर्माना ही किया था, इसलिए अभिव्यक्ति पर जुर्माना किया जाय, पर अधिकांश जजों विशेषकर चीफ जस्टिस सर रिवाड गाय ने सजा देने की ही राय दी।

5 मई, 1883 को सुरेन्द्रनाथ द्वारा अदालत के अपमान का फैसला सुना दिया गया। उस दिन अदालत भवन के सामने छात्रों का एक बड़ा भारी जुलूस आया था। आशुतोष मुखर्जी छात्रों का नेतृत्व कर रहे थे जो बाग में चीफ जस्टिस और कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रधान निर्माता हुए। जुलूस में देशबन्धुदास भी थे। इस अवसर पर एक मजेदार घटना यह हुई कि प्रसिद्ध पहलवान परेशनाथ घोष पुलिस को मदद करने के बहाने पुलिस और छात्रों के बीच म जाकर खड़े हो गए, पर उन्होंने अपने परो को इस तरह से खोल दिया कि उनकी टांगों के नीचे से होकर छात्र हाई कोर्ट के अंदर घुस गए।

सारे भारत, विशेषकर बंगाल में इस घटना से भयकर जाश फैला। श्री आनन्द मोहन बसु ने इंडियन एसोसिएशन की कार्यवाही में लिखा—“इस मौके पर जिस प्रकार अशुभ से शम्भ का उदभव हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इस मामले में सबत्र जितना क्रोध तथा शोभ का उद्रेक हुआ, विभिन्न प्रांतों के लोगों में जिस तरह पारस्परिक प्रीति की भावना बढ़ी, जिस तरह एकता का प्रदर्शन हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ था।”

### अखिल भारतीय संगठन की मांग

जिस समय सुरेन्द्रनाथ जेल में ही थे, लोगों ने यह अनुभव किया कि आन्दोलन को ठग से चलाने के लिए एक राष्ट्रीय कोष की आवश्यकता है। 21 जून, 1883 के ‘ब्राह्मो पब्लिक ओपिनियन’ में इस सम्बन्ध में एक लेख भी निकला। इसके साथ यह आवाज उठाने लगी कि सही मानी में एक अखिल राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए।



सुरेन्द्रनाथ छूटे तो उनको जगह जगह मानपत्र दिए गए, विशेषकर छात्रों ने उनको सिर पर चढ़ा कर स्वागत किया। उन्होंने सैकड़ों सभाओं में भाषण दिया। इन अवसरों पर वह जब भी लोगों से अपने व्याख्यान में पूछते कि तुम में से कौन गरीबाली और मेजिनी होगा, तो इसके उत्तर में सभा के सभी लोग कहते थे—'हम हाँ, हम हाँगे।' किसी बड़े सावजनिक नेता के जेल जाने का यह पहला ही अवसर था, इसलिए सुरेन्द्रनाथ का अभूतपूर्व स्वागत हुआ।

सुरेन्द्रनाथ जेल में निकलकर जोशीली भाषा में लोगों में देश भक्ति का प्रचार तो करत ही रहे, पर साथ ही उन्होंने ठोस काम की ओर भी हाथ बढ़ाया। सुरेन्द्रनाथ के लिए यह एक बहुत प्रशंसा की बात थी, जिसे उनके किसी जीवनी लेखक ने अच्छा तरह समझ नहीं पाया कि इण्डियन एसोसिएशन के होते हुए भी और बंगाल के बाहर भी उसका कुछ प्रचार होने पर भी उन्होंने महसूस किया कि एसोसिएशन से पूरा काम नहीं चल सकता। उन्होंने यह अनुभव किया कि एक बृहत्तर संस्था की आवश्यकता है। और इसीलिए उन्होंने बाहर के नेताओं से पत्र व्यवहार शुरू किया।

यह सही है कि कुछ दूरदर्शी और रघामी नेता हम दिशा में क्रियाशील थे, पर इन नेताओं को असली समयन मिल रहा था जनता की गरीबी से, जो करीब करीब जानमार्ग हो चुकी थी।

भारत की ब्रिटिश लूट किस भयंकर ढंग से की गई, उसका कुछ झोरा यहाँ दिया जाता है। विलियम डिंगबी ने सरकारी आकड़ों में निजी खाती तथा निर्यात पर प्लसा के आधार पर यह हिसाब लगाया कि पलासी युद्ध (1757) से वाटरलू युद्ध (1815) के बीच भारतीय खजानों से 10 करोड़ पाँड बरतानवी बैंका में भेजा गया। इसको आधार माना जाय तो प्रतिवर्ष एक करोड़ बृहत्तर लाख पाँड की लूट होती रही। भारत के मर्त्ये जो खूब लगाए गए, उन्हें देखें तो हसी आती है। कम्पनी ने ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ अपने अधिकार सौंपे, उसका खर्च, चीन और अवीसिनिया के साथ युद्ध में हुए खर्च, लंदन के इंडिया हाउस का सारा खर्च, उन जहाजों के खर्च जो युद्ध में भाग ले और नहीं ले पाए ये सब भारतीय करदाता के मर्त्ये मड़े गए। 1871 में दादा भाई नौरोजी ने लन्दन में कहा कि उस वक्त तक भारत की लूट का परिणाम कम से कम 50 करोड़ पाँड या और वह एक करोड़ बीस लाख पाँड की दर पर जारी थी और बढ़ती जा रही थी। कुछ समय बाद कांग्रेस के संस्थापक ऐलन आक्टेवियस ह्यूम ने (जिन्हें सारी गुप्त सरकारी सूचनाएँ प्राप्त थी) लांड नाथब्रुक को चेतावनी दी कि गरीबी इतनी बढ़ गई है कि लोग जान पर खेल सकते हैं। दादाभाई के अनुसार उस समय औसत भारतीय की दैनिक आमदनी दो पसा थी और उसके पास कुछ चिपड़े और लत्ते थे, पेट नहीं भरता था।

इण्डियन एसोसिएशन के उद्योग से दिसम्बर 1883 में एक राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन तीन दिन तक कलकत्ता के इलवट हाल में हुआ। राज नए नए सभापति होते थे। पहले दिन वृद्ध नेता रामतनु लाहिडी ने सभापतित्व किया। दूसरे दिन काली मोहन दास तथा तीसरे दिन अनन्दाचरण खास्तगीर ने सभापतित्व किया। लोगों के मन में यह विचार था कि बाद को चलकर जो संस्था राष्ट्रीय संसद का रूप लेगी, यह उसी का प्रारूप है। आनंद मोहन बसु ने सभास्थल में यही बात कही। इस अधिवेशन में इस दिना की भारतीय मध्यवर्ति योणी की सब माँगें सामने आ गईं। पहली माँग यह रखी गई कि सिविल सर्विस में भारतीयों को मोरा के साथ बराबरी मिले, दूसरी बात यह तय की गई कि एक राष्ट्रीय फण्ड की स्थापना हो, इनके अतिरिक्त ये माँगें भी थीं कि प्रतिनिधि

मूलक धारासभा बने, शिक्षा विशेषकर शिल्प की शिक्षा दी जाय, 'याय विभाग को पृथक किया जाए, तथा हथियार कानून रद्द कर दिया जाय।

ऐसा मालूम होता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस को अखिल भारतीय रूप से जबानी समर्थन प्राप्त होने पर भी यह राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत कुछ बंगाली मध्यवर्ति नेताओं तक सीमित रही। सुरेन्द्रनाथ को इससे खुशी नहीं हुई। वह मई 1884 में फिर भारत भर का दौरा करने निकले। अब की बार वह उत्तर भारत में सबत्र घूमे। सबत्र उनका स्वागत हुआ। बात यह है कि वह इस बीच बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे और वह बहुत अच्छा बोलने वाले तो थे ही। अब की बार भी उनके भ्रमण का उद्देश्य सिविल सर्विस के सम्बन्ध में भारतीयों के प्रति किए गए अन्यायों का प्रतिवाद था, पर इसके साथ उन्होंने अब की बार अखिल भारतीय राष्ट्रीय संगठन तथा राष्ट्रीय कोप के विषय को भी लोगों के सामने रखा और लोगों को संगठन का महत्व समझाया।

सुरेन्द्रनाथ के इस दौरे का क्या असर हुआ, यह हेनरी काटन लिखित 'यू इंडिया' (1885) से ज्ञात होता है। उसमें मिस्टर काटन ने लिखा—

"शिक्षित समाज ही देश का कण्ठ तथा मस्तिष्क है। इस समय शिक्षित बंगाली ही पेशावर से चटगांव तक लोगों के जनमत का नियंत्रण कर रहे हैं। यद्यपि उत्तर पश्चिम प्रांत के लोग बंगालियों के मुकाबले कम शिक्षित हैं, फिर भी वे शिक्षितों के नेतृत्व को मानने के लिए उसी प्रकार तैयार हैं जैसे बंगाली। 25 साल पहले इसका कोई लक्षण नहीं था। लार्ड लारेस, माटगोमरी, मैक्लायड आदि कभी यह कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि पंजाब पर बंगालियों का कोई प्रभाव पड़ेगा। पर यत वय एक बंगाली नेता जिस समय उत्तर भारत का ध्याव्यान देते हुए दौरा कर रहा था, उस समय वह किसी वीर की दिग्विजय से कम नहीं था। इस समय ढाका से मुल्तान तक सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के नाम में ही युवकों में जोश आ जाता है।"

1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन फिर कलकत्ते में हुआ। अधिवेशन तीन दिन 25, 26, 27 दिसम्बर को होता रहा। अबकी बार यह कांग्रेस कुछ अधिक प्रतिनिधिमूलक थी। इसमें बंगाल के बहुत से स्थानों के अलावा आसाम, इलाहाबाद, बनारस, मेरठ, मुजफ्फरपुर, तिरहुत, बरेली, उड़ीसा आदि से प्रतिनिधि आए थे। दरभंगा के महाराजा तथा बम्बई के बी० एन० मंडलिक भी सभा में उपस्थित थे।

## अन्य प्रान्तों में कार्य

मद्रास में महाजन सभा (स्थापित 1881) नाम से एक संस्था काम कर रही थी, जिसके नेता 'हिन्दू' के परिचालक जी० सुब्रह्मण्य अय्यर थे। पूना की सावजनिक सभा भी 1872 से तरह-तरह के सामाजिक तथा राजनीतिक कार्य कर रही थी। इस संस्था के नेता गणेशदत्त जोशी थे। वह सुरेन्द्रनाथ से मिले थे तथा एक अखिल भारतीय संस्था बनाने के इच्छुक थे। महाराष्ट्र के समाज सुधारक महादेव गोविन्द रानडे इस सभा के नेता थे जो महाराष्ट्र में बहुत जनप्रिय थे। महाराष्ट्र में इन दिनों विष्णुशास्त्री चिपलूणकर तथा नीलकण्ठ जनादन कीतने साहित्य के जरिए प्रचार काय कर रहे थे। विष्णु शास्त्री ने अपन निबन्धों के जरिए महाराष्ट्र में एक नवीन जीवन का संचार किया। इन लोगों ने यह कहा कि "पश्चिम की जो अच्छी वस्तुएँ हैं, उन्हें अवश्य ग्रहण किया जाय पर इस कारण अपनी वस्तुओं का नाश न किया जाय। हम इस समय जिस विपत्ति में पड़े हुए हैं, उससे निकलने के लिए हमारी अपनी ही चीजें काम देगी। इस कारण अपनी भाषा, अपने धर्म, अपने इतिहास तथा अपनी परम्परा की रक्षा की जानी

चाहिए।" नीलकण्ठ जनादन कीतने ने ग्रांट डफ के मराठी इतिहास सम्बन्धी गतियों को दिखलाया। 1874 में विष्णुशास्त्री की निबन्धमाला प्रकाशित हुई। स्मरण रहे कि बकिमचन्द्र का प्रसिद्ध उपन्यास 'आनन्द मठ' इसके बाद 1882 में दिसम्बर में प्रकाशित हुआ था।

बम्बई के नेता इस प्रकार बम्बई में जनवरी 1885 में बम्बई प्रेसीडेंसी एसोसिएशन स्थापित हुई। बाद की जो लोग कांग्रेस के बड़े नेता हुए, उनमें से बड़ध्वी तयबजी फिराजशाह मेहता, दीनशा वाचा इस सस्था के सदस्य थे। इसके पहले बम्बई में 1851 में बम्बई एसोसिएशन नाम से एक सस्था कायम हुई थी। इसके नेताओं में जगन्नाथ शंकर सेठ दादाभाई नौरोजी, मंगलदास नट्यूभाई, नौरोजी करीदूनजी थे। 1850 में राम बालकृष्ण जयकर, दादोबा पाडूरंग तरखड और उनके भाई आत्माराम पाडूरंग ने परमहंस मंडली की स्थापना की, जो ईसाई मत से प्रभावित सवधर्म समन्वय में विश्वास करते थे, पर ये सामने नहीं आए कि लोग उनसे घृणा न करें।

गोपाल हरि देशमुख या 'लोकहितवादी' को महाराष्ट्र का प्रथम समाज सुधारक कहा गया। वह अंग्रेजी शिक्षा की बदौलत बड़े पदों पर रहे, यहाँ तक कि राज्यपाल की परिषद् में पहुँच गए। उन्होंने 'प्रभाकर' पत्रिका में शतपत्रों (सौ पत्र) लिखा, जिनका विषय समाज सुधार था। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें भी लिखीं। एक तरफ उन्होंने भाषवलायन गृह्य सूत्रों पर तथा दूसरी तरफ राजस्थान, गुजरात सौराष्ट्र और श्रीलंका के इतिहास लिखे। वह प्रायः समाज से जुड़े थे, साथ ही पियोसोफिकल आन्दोलन से भी सम्बद्ध थे। वह लोकतन्त्र के प्रतिपादक थे। उनका कहना था कि सरकार या शासन जितना कम हा जनता के लिए उतना ही हितकर है। पिछड़े देश में सरकार पतक और स्पेच्छाचारी तथा सम्म राष्ट्र में वह जनता की सेवक होती है। वह पुरोहितबा, पोगाप य और जातपात के विरोधी थे।

1828 में महात्मा जोतिबा फुले महान सुधारक हुए। उन्होंने सत्यशोधक समाज के द्वारा जनता की सेवा की। 21 साल की उम्र में जबरदस्त विरोध का सामना कर उन्होंने लड़कियों के लिए विद्यालय स्थापित किया। उन्होंने कहा— 'अपनी पुस्तकों की सहायता से हजारों वर्षों से ब्राह्मण जनसाधारण को नीच करार देकर उनका शोच करते रहे।' शिक्षा के द्वारा जनता को इनकी जकड़ से मुक्त करने के लिए 1873 के 24 सितम्बर को सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई। जब महात्माजी ड्यूक आफ यार्क से मिलने गए, तो उन्होंने उन्हें एक लगेटी मेंट में दी जो भारतीय प्रजा की गरीबी का प्रतीक है।

सारे भारतवर्ष में बहुत से उच्च शिक्षित लोग थियोसोफिकल सोसाइटी के सदस्य थे। थियोसोफिस्टों का हर साल कन्वेंशन हुआ करता था। 1884 में मद्रास प्रान्त में इसका जो कन्वेंशन हुआ उसके बाद मद्रास के रावबहादुर रघुनाथ राव के घर पर कुछ विशिष्ट व्यक्ति एकत्र हुए। इन लोगों ने सोचा जिस प्रकार दार्शनिक विचारों पर आलोचना करने के लिए हर साल सभा होती है उसी प्रकार भारत की राजनीतिक समस्याओं पर आलोचना करने के लिए एक अखिल भारतीय सभा क्यों न हुआ करे। इस सम्बन्ध में काम करने के लिए आठ व्यक्तियों की एक कमेटी बना दी गई, जिसमें इंडियन मिस्टर के सम्पादक नरेन्द्रनाथ सेन, जानकीनाथ घोषाल, रघुनाथ राव और बाद की मद्रास के चीफ जस्टिस हुए सुब्रह्मण्य अय्यर थे। जनवरी 1885 में इन लोगों ने भारत भर के नेताओं को पत्र लिखे। इस प्रकार मद्रास में भी लोग इसी दिशा में सोच रहे थे।

## ह्यूम के प्रयत्न

ए० ओ० ह्यूम 1882 तक आई० सी० एस० में थे और इसके बाद इन्होंने पेंशन ले ली थी। 1 मार्च, 1883 को उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातक को सम्बोधित करते हुए एक पत्र लिखा कि विदेशी भारतीयों की मदद कर सकते हैं, पर देश हित के कार्यों में, शासन में तथा अपने अधिकारों को प्राप्त करने में उन्हें खुद आगे बढ़कर काम करना पड़ेगा। यदि 50 शिक्षित भारतीय भी अपने वैयक्तिक स्वार्थों को भूलकर देश सेवा में लग जाएं, तो वे बहुत से सत्कार्य करने में समर्थ हो सकते हैं। और यदि वे इतना भी न कर सकें, तो उन्हें दूसरों का गुताम होकर रहना पड़ेगा।”

ह्यूम के विचार भारतीयों की आकांक्षाओं के प्रति उदार थे। पर जैसा कि उस युग में सभी उदार से उदार गोरे तथा भारतीय भी समझते थे, ह्यूम भी उसी तरह यह समझते थे कि भारत के लिए ब्रिटिश सम्बन्ध अच्छा है क्योंकि ब्रिटेन भारतवासियों को ठीक समय पर स्वतंत्रता दे देगा। वे सचमुच यह समझते थे कि ब्रिटेन भारतवर्ष की भलाई के लिए वहां पर है। इसलिए जब उन्हें मालूम हुआ कि भारतवर्ष बिस्फोटक हालात में है, तो वह कुछ करने के लिए व्याकुल हो उठे। ह्यूम के जीवनी लेखक वेडरबन ने यह साफ लिखा है कि “लाड लिटन के वायसराय युग के अंतिम दिनों में 1878 और 1879 के करीब मिस्टर ह्यूम को इस बात का निश्चय हो गया कि बढ़ते हुए असंतोष का मुकाबला करने के लिए कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। देश के विभिन्न भागों से हितापीयों ने उनकी लिखा कि सरकार को कितना भारी खतरा है।”

कांग्रेस के प्रथम सम्भाषित डब्लू० सी० बोनर्जी ने अपनी पुस्तक ‘भारतीय राजनीति की भूमिका’ में लिखा है—

“बहुत से लोगों को यह बात बिल्कुल नयी मालूम होनी कि कांग्रेस जैसी कि वह बनी है और जैसी कि वह चलती रही है, वह मार्क्सव्स आफ डफरिन की सृष्टि है—उनकी उस समय की सृष्टि जब वे भारत के बड़े लाट थे। 1884 में मिस्टर ए० ओ० ह्यूम के मन में यह विचार आया कि देश के लिए यह बहुत ही अच्छा होगा यदि यहाँ के प्रमुख राजनीतिज्ञ हर साल इकट्ठा होकर सामाजिक विषयों पर विचार विमर्श कर लिया करें तथा आपस में मित्रता का सम्बन्ध स्थापित करें। वह यह नहीं चाहते थे कि इन तर्कों में राजनीति भी जाए। लाड डफरिन ने इस मास में बहुत दिलचस्पी ली, और इस प्रस्ताव पर कुछ दिनों तक विचार करने के बाद उन्होंने मिस्टर ह्यूम को बुलवाकर यह कह दिया कि उनकी योजना बहुत सुन्दर है।

मिस्टर बोनर्जी के इस उद्धरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि मिस्टर ह्यूम भारतीयों के जितने बड़े हमदर्द समझे गए, उनके विचार उतने उदार नहीं थे। वह तो कांग्रेस को सामाजिक विषयों पर विचार विनिमय तक ही सीमित रखना चाहते थे। इसमें बढ़कर इसका और क्या प्रमाण हो सकता है? रहे लाड डफरिन, तो वे भी केवल यही चाहते थे कि पीछे पीछे जो घड़याल हुआ करते हैं, हा सकते हैं या हो रहे हैं उनकी बजाय खुले आम लोग सरकार की जासोचना करें, जिससे एक तो सरकार को मालूम होता रहे कि लोगों का क्या कहना है, दूसरा उससे यह नापा जा सके कि लोगों की भावनाओं की गहराई क्या तक है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जैसे बायलर के फालतू भाग को निकाल देने के लिए सेफ्टी वैल्व हाता है, उगी तरह से ह्यूम और लाड डफरिन कांग्रेस का बनाना चाहते थे। यह कोई कल्पना नहीं है इस बात का प्रमाण उमी युग के कांग्रेस नेताओं के लेखों से ही

मिलते हैं। वेडरबर्न ने इस शब्द का भी इस्तेमाल किया है। वे लिखते हैं—“A safety valve for the escape of great and growing forces, generated by our own action, was urgently needed and no more efficacious safety valve than our Congress movement could possibly be devised” यानी हमारे ही कार्यों से उत्पन्न शक्तियों के परिणामों को रोकने के लिए एक सेफ्टी वाल्व की बड़ी जरूरत थी और कांग्रेस से बढ़कर कोई अन्य सेफ्टी वाल्व नहीं हो सकता था।

कहा जाता है कि 1883 में ही ह्यूम ने अपने विचारों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए इंडियन नेशनल यूनियन नाम से एक संस्था कायम की थी।

### कांग्रेस के संघर्ष में गश्ती चिट्ठी

हम पहले ही बता चुके हैं कि संघर्ष एक अखिल भारतीय संस्था बनाने की दिशा में लोग सोच रहे थे। अब इसके लिए जमीन तैयार हो चुकी थी। मार्च 1885 में इस उद्देश्य से एक सभा हुई, और उसने देश भर में गश्ती चिट्ठी भेजी। इस गश्ती चिट्ठी में यह कहा गया कि “1885 के 25 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक दुर्गा पूजा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होगा। इस काफ़ेस में बंगाल, बम्बई तथा मद्रास प्रेसीडेंसी (उस युग में ब्रिटिश भारत इन्हीं तीन प्रेसीडेंसियों में बंटा हुआ था) के अंग्रेजी जानने वाले तमाम प्रमुख राजनीतिज्ञ भाग ल सकेंगे। पहली काफ़ेस पूना में होगी। यह तय किया गया और पूना की सांख्यिक सभा के चिपलूनकर, जोशी आदि इसकी स्वागत समिति बनाने वाले थे पर काफ़ेस पूना में नहीं हो सकी क्योंकि उन दिनों वहाँ हिंसे का प्रकोप था।

कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में क्या हुआ इस संघर्ष में आलोचना करने से पहले हम इसका उत्तर दें कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में क्यों हुआ। वास्तव में ठीक उसी समय इन्हीं उद्देश्यों को लेकर कलकत्ता में राष्ट्रीय काफ़ेस का अधिवेशन हो रहा था। क्या कारण था कि इधर मिस्टर ह्यूम अपनी असंग खिचड़ी पका रहे थे, और उधर सुरेन्द्रनाथ अपनी डेढ़ इंच की मजिस्ट्रैट अलग बना रहे थे? क्या वे एक नहीं हो सकते थे? किसी भी लेखक ने इस प्रश्न पर सही रोशनी नहीं डाली है। कहा गया है कि सुरेन्द्रनाथ अनर्जी बलकत्ते को ही भारतवर्ष की राष्ट्रीय हलचल का केन्द्र चाहते थे क्योंकि कलकत्ता उन दिनों भारतवर्ष की राजधानी था। पर क्या यही वास्तविक बात थी? हम जब इसकी गहराई में जाते हैं तो मान्य होता है कि बान इससे कहीं ज्यादा गूढ़ थी। मिस्टर ह्यूम नहीं चाहते थे कि कांग्रेस का जन्म एक ऐसे व्यक्ति की छाया में हो जो जेल जा चुका था, तथा जिसके विचार तथा नाम से ही अंग्रेज नाराज होते थे। इसी कारण मिस्टर ह्यूम ने कांग्रेस का अधिवेशन सुरेन्द्रनाथ से बचाकर बम्बई में किया। क्या यह महत्व की बात नहीं है कि जो व्यक्ति उस समय भारतीय राष्ट्रीयता का प्रतीक समझा जाता था, वही कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुआ? अवश्य ही कलकत्ता राष्ट्रीय सम्मेलन के नेताओं के लिए यह प्रशंसा की बात है कि उन्होंने काफ़ेस के तीसरे दिन के अधिवेशन में बम्बई के अधिवेशन को अपनी सहानुभूति का संदेश भेज दिया। प्यारोमोहन मुखोपाध्याय ने राष्ट्रीय काफ़ेस की ओर से बम्बई को यह तार भेजा।

‘कलकत्ता सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधि बम्बई सम्मेलन के प्रति अपनी शुभेच्छा भेजते हैं।

बाद की सुरेन्द्रनाथ दलबल सहित कांग्रेस में शरीक हो गए, और उसके तत्ता

भी हुए, यह भी कांग्रेस तथा सुरेन्द्रनाथ दोनों के लिए प्रशंसा की बात है। यदि इस समय दो समान्तर तथा प्राप्तो के आधार पर स्थापित संस्थाएँ बनती, तो पता नहीं इसका देश की एकता तथा भविष्य की राजनीति पर क्या परिणाम होता।

घटनाएँ जिस प्रकार सुगबुगा रही थी, उसमें एक शून्यता पैदा हो गई थी, जिसे कोई व्यक्ति, चाहे वह कितना भी बड़ा हो, भर नहीं सकता था। कारण यह कि उस समय सार्वजनिक क्षेत्र में तिलक या गांधी की तरह कोई युगपुरुष नहीं था, जो अपने में सब धर्मों, प्रदेशों भाषाओं को समो लेता और सब लोग एक स्वर से उसके लिए कहते *Ecce homo*, अर्थात् यह है वह आदमी जो हमारी नैया को सकटग्रस्त सागर में खेकर उसे पार ले जा सकता है।

1885 में कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ, उसमें मारे भारत से नवजीवन की धिरकन स्पष्ट हुई। भारतीय इतिहास की यह एक विशिष्ट घटना थी। पहली बार राजनैतिक एकता का उद्बोधन किसी देशी या विदेशी राजसक्ति के द्वारा नहीं, बल्कि मातृभूमि की दूरदृष्टि सम्पन्न सत्तानों के द्वारा स्वतः स्फूर्त रूप में हुआ था, जो देश के विभिन्न कोनों से आए हुए थे। ऐसे लोग बम्बई में एकत्र हुए और आपस में मंत्रणा की कि क्या किया जाए। उन्होंने शासकों को माहसपूर्ण चुनौती देते हुए कहा कि "भारत अब विदेशियों के इशारों पर अपने भाग्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, वह अपनी नैया आप खेने में समय और कटिबद्ध है।"

इस मूल्यांकन में सिर्फ एक बात जोड़ने की आवश्यकता है। वह यह कि इन नेताओं की दृष्टि में भारत मध्यवर्ति पड़े लिखे बग तक ही सीमित था। कांग्रेस में महात्मा गांधी के आगमन तक यही दशा रही। कांग्रेस के बाहर जैसे बकिमचन्द्र, विवेकानन्द, रामकृष्ण परमहंस, दयानन्द, किसी न किसी रूप में आम जनता के उत्थान के लिए काय कर रहे थे, वह स्थिति अभी यहाँ नहीं थी। अनेक लेखक अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के शोषण पर लिख रहे थे उस ओर कांग्रेस का ध्यान नहीं था। दीनबन्धु मित्र के नील के खेतहरो के शोषण पर लिखे नाटक का जिक्र यहाँ किया जा सकता है।

18५7 यम के अजीमुल्ला और सम्पानक शहीद वेदार बख्त के बाद दीनबन्धु मित्र को ही प्रगतिशील लेखकों का पितामह कहा जा सकता है। बकिमचन्द्र के 'आनन्द मठ' का नम्बर उसका वाद आता है। 'नीलदण' और 'आनन्दमठ' दोनों जन्त हो गए थे।

यह है वह भूमिजा ज़िम पर कांग्रेस बनी और खड़ी हुई तथा आरम्भ में अंग्रेजों के लिए हतकर होते हुए भी शीघ्र ही भारतीय स्वाधीनता के लिए लड़े जाने वाले सप्राप्त का प्रमुख हथियार बनी। साठ वर्ष का समय बहुत ज्यादा नहीं होता परन्तु लगभग इतने समय में ही वह देश से अंग्रेजों को अंतिम रूप से निकालकर स्वतन्त्र गणतन्त्र स्थापित करने में सफल हुई।

## कांग्रेस का जन्म बंबई अधिवेशन

जैसा हम बता चुके हैं कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूना में होने वाला था, पर वह वहाँ न होकर बम्बई में हुआ। सौभाग्य से श्रीमती एनी बेसेंट ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का एक अच्छा विवरण अपनी पुस्तक 'हाउ इंडिया फाट फार फ्रीडम' में लिखा है।

"पूना में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन नहीं हो सका, क्योंकि ऐन बड़े दिन के पहले वहाँ हैजा फैल गया। कुछ ही लोगों को हैजा हुआ था, पर यह समझा गया कि शायद अब यह महामारी के रूप में फले, इस कारण अब प्रस्तावित कार्यक्रम, जिसका नाम 'कांग्रेस' हो चुका था वहाँ से हटाकर बम्बई में की गई। गोकुलदास तेजपाल सस्कृत कालेज और बोर्डिंग हाउस के मैनेजरों ने अपनी सब सुन्दर इमारतों को कांग्रेस के काम के लिए दे दिया था और 27 दिसम्बर के सवेरे भारतीय राष्ट्र के प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए सब तैयारी पूरी हो चुकी थी। जब हम अपनी दृष्टि इस कांग्रेस में उपस्थित लोगों की ओर डालते हैं, तो हम कितने ही ऐसे लोगों को पाते हैं जो बाद में चल कर भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध के इतिहास में मशहूर हुए। अधिवेशन में भाग ले रहे लोगों में थे—मद्रास के डिप्टी कलेक्टर तथा सुप्रसिद्ध सुधारक दीवान बहादुर आर० रघुनाथ राव, माननीय महादेव गोविन्द रानडे जो उन दिनों विधान परिषद के सचिव तथा पूना के स्माल ब्राज्ज बोट के जज थे और बा० को बम्बई हाईकोर्ट के जज तथा एक बहुत सम्मानित और विश्वस्त नेता हुए, आगरा के साला बजनाथ, जो बाद में चल कर एक बड़े विद्वान तथा लेखक के रूप में प्रसिद्ध हुए, अध्यापक के० सुन्दर रमण और आर० जी० भण्डारकर। प्रतिनिधियों में हम 'ज्ञानप्रकाश', पूना सावजनिक सभा की तिमाही पत्रिका 'मराठा', 'पेसरी', 'नव विभाकर' 'इंडियन मिरर' 'नमीम', 'हिन्दुस्तानी', 'ट्रिब्यून', 'इंडियन यूनियन', 'दि स्पेक्टेटर', 'इन्दुप्रकाश', 'दि हिंदू' तथा 'दि क्रैसेंट' के संपादकों को पाते हैं। बित्तन ही ऐसे नाम आते हैं जो बहुत ही परिचित और सम्मानित हैं। शिमला से मिस्टर ए० ओ० ह्यूम हैं, कलकत्ता से डब्ल्यू० सी० बोनर्जी और नरेन्द्रनाथ सेन हैं पूना से डब्ल्यू० एम० आप्टे और जी० जी० आगरकर हैं, लखनऊ से गंगाप्रसाद वर्मा हैं बंबई से दादाभाई नौरोजी, के० टी० तेलंग, बंबई बारपोरेशन के नेता फिरोजशाह मेहता तथा डी०ई० वाचा हैं, मद्रास में महाजन सभा के सभापति पी० रंगया नायडू, एस० सुब्रह्मण्य अय्यर, पी० आनन्दचामु, जी० सुब्रह्मण्य अय्यर एम०वीर राघवाचारियर, अनन्तपुर से के० विल्ले हैं। ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए आरम्भिक कार्य किया।

"28 दिसम्बर 1885 को 12 बजे गोकुलदास तेजपाल सस्कृत कालेज के हाल में प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में सबसे पहले मिस्टर ए० ओ० ह्यूम, माननीय एस० सुब्रह्मण्य अय्यर तथा माननीय के० टी० तेलंग की

आवाजें सुनाई पड़ी क्योंकि इन्होंने ही कांग्रेस के प्रथम सभापति मिस्टर डब्ल्यू. सी० धोनर्जी के नाम का प्रस्ताव, समर्थन तथा अनुमोदन किया। वह बहुत ही पवित्र तथा ऐतिहासिक मुहूर्त था, जब मातृभूमि के द्वारा इस प्रकार सम्मानित व्यक्तियों की दीर्घ पवित्र मे से प्रथम व्यक्ति ने राष्ट्रीय महासभा के प्रथम अधिवेशन के सभापति का आसन ग्रहण किया।

## कांग्रेस का उद्देश्य

“कांग्रेस के महत्वपूर्ण तथा प्रतिनिधि मूलक चरित्र की ओर ध्यान दिलाने के बाद सभापति ने कांग्रेस के उद्देश्यों का स्पष्टीकरण इन चार रूपों में किया —

- (1) जो लोग देश के विभिन्न भागों में देश के लिए काम कर रहे हैं, उनमें पारस्परिक प्रीति तथा परिचय उत्पन्न करना।
- (2) सब देश प्रेमियों, यानी ऐसे लोगों में जा हमारे देश की प्रेम की दृष्टि से देखते हैं, जाति, धर्म, प्रान्त सम्बन्धी कुसस्वारों को दूर कर सीधा पारस्परिक प्रेम तथा व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित करना और राष्ट्रीय एकता के उन भावों को दब करना, जो हमारे श्रेष्ठ लार्ड रिपन के चिर स्मरणीय राज्य काल में उत्पन्न हुए थे।
- (3) उस समय के महत्वपूर्ण तथा जरूरी प्रश्नों पर भारतीय शिक्षित वर्ग के परिपक्व मत को अच्छी तरह तक वितरक के बाद पता लगाना, और फिर जब यह मालूम हो जाए, तो उसे अधिकार पूर्ण ढंग से लिपिबद्ध करना।
- (4) अगले बारह महीनों में जनता के हित के लिए देश के नेताओं की जो कुछ करना है उसकी रूपरेखा बनाना।”

इस कांग्रेस में 72 प्रतिनिधि थे। जो प्रस्ताव पास हुए, वे इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि करीब करीब गांधी-युग तक कांग्रेस इसी प्रस्तावों के इर्द गिर्द घूमती रही। इस कारण हम इन प्रस्तावों की कुछ ब्योरे में देंगे।

## अध्यक्ष धोनर्जी

परन्तु इसके पहले हम बता दें कि इस अवसर पर जो महानुभाव सभापति चुने गए थे, वह कौन थे। वह कलकत्ता के बहुत बड़े बॉरस्टर थे, और बताया जाता है कि एक जमाना था जब वह गोरा बनने में ही अपनी इतिकर्तव्यता समझते थे। इलवट विल के आन्दोलन के जमाने में उनकी आँखें खुली, और वह समझ गए कि गोरो और भारतीयों में जो खाई है वह कभी पाटी नहीं जा सकती। तब से उनके विचार बदल गए। जब 1884 में लाड रिपन भारतवर्ष से गए, उस समय उनके विदाई समारोह में भी उन्होंने ही नेतृत्व किया था। यहाँ यह भी बता दिया जाए कि जिस समय लाड रिपन भारतवर्ष से गए, उस समय कलकत्ता और बम्बई के बीच सारे स्टेशनो पर लाड रिपन की जय मनाई गई थी। इस विदाई समारोह को देखकर नौकरशाही हैरान रह गई थी, और यह कहा गया था “If it is real what does it mean?” यानी यदि यह वास्तविक है, तो इसका अर्थ क्या है? मिस्टर धोनर्जी ने इस प्रदर्शन में बहुत बड़ा भाग लिया था।

मिस्टर धोनर्जी बहुत ही यथार्थवादी व्यक्ति थे इसमें सन्देह नहीं, क्योंकि उन्होंने सभापति की हैसियत से मुँह खोलते ही यह कहा कि लोग कह सकते हैं कि हम लोग ने



अपना चुनाव आप कर लिया, और हम किसी ने नहीं चना, पर बात ऐसी नहीं है। उन्होंने कहा "इस कांग्रेस के होने की बात साल भर से सभी प्रांतों के लोगों को मालूम है और यद्यपि जायेंते का कोई चुनाव नहीं हुआ, फिर भी जो व्यक्ति यहां प्रतिनिधि होकर आए हैं, वे विभिन्न समस्याओं के द्वारा चुनकर भेजे गए हैं।"

अध्यक्ष ने ब्रिटेन तथा भारत के सम्बन्ध बताते हुए कहा "ब्रिटेन न भारत की भलाई के लिए बहुत कुछ किया है, और इसके लिए सारा दश उसका कृतन है। ब्रिटेन ने भारत को शांति दी रलें दी, और सर्वोपरि उसने पाश्चात्य शिक्षा रूपी महान दान दिया। फिर भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। लोग शिक्षा तथा अन्य तरीके से जितना समझ होते जा रहे हैं, राजनीतिक मामलों में उतनी ही अतदृष्टि बढ़ेगी, और उनमें राजनीतिक प्रगति की उतनी ही इच्छा उत्पन्न होगी।" उन्होंने यह भी कहा कि यदि भारतवासी यह चाहते हैं कि यूरोप में प्रचलित शासन प्रणाली की तरह उनके यहां भी लोकतांत्रिक शासन कायम हो, तो सबसे ब्रिटिश सरकार के प्रति भारतीयों की राजभक्ति में कोई फर्क नहीं आता।

## सम्मेलन के प्रस्ताव

**पहला प्रस्ताव—** हिंदू के संपादक जी० मुबद्दस्य अय्यर ने पहला प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारत पर एक रायल कमीशन बैठाया जाए। उस कमीशन में भारतीय तथा अंग्रेज दोनों हों, और वह इंग्लैंड, और भारत दोनों जगह गवाहियां लेकर तब किसी निणय पर पहुंचे। प्रस्तावक ने अपने व्याख्यान में यह कहा कि 1773, 1793, 1813 और 1853 में भारत की परिस्थिति पर जांच करने के लिए रायल कमीशन की नियुक्ति हुई थी, पर गत 32 सालों से पार्लियामेंट ने कोई सुध नहीं ली। इसके फलस्वरूप स्थानीय सरकार और मौकरशाही बहुत मनमानी कर रही है। वक्ता ने यहां तक कहा कि देश किसी किसी मामले में कम्पनी की अमलदारी से भी पिछड़ चुका है, और जब से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने शासन सूत्र अपने हाथ में लिया है, तब से देश की हालत बिगड़ती ही गई है। इस प्रस्ताव का समर्थन श्री फिरोजशाह मेहता ने किया और अनुमोदन किया नरेन्द्रनाथ सेन ने।

**दूसरे प्रस्ताव के प्रस्तावक एस० एच० बिपलूणकर थे।** इसमें यह मांग की गई कि इण्डिया कौंसिल खतम कर दी जाए। इण्डिया कौंसिल में पेंशनयापता अंग्रेज सिविल सर्विस वाले हाते थे, वे हमेशा दकियानूसी दृष्टिकोण से भारतीय समस्याओं को देखते थे और उसी के अनुसार ब्रिटिश मिनिस्टरों को सलाह दिया करते थे। भारतीय सरकार के मध्ये अबीसीनिया पर अभियान, लंदन में तुर्की मुलतान के स्वागत मिस्र पर अभियान आदि का व्यय बढ़ा गया था, पर इस पर इण्डिया कौंसिल खुश ही थी, मानो ये सब काम भारतीयों की भलाई के लिए हुए थे। पी० आनंदचालू ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और श्री जानकीनाथ घोषाल ने अनुमोदन।

**तीसरे प्रस्ताव में लेजिस्लेटिव कौंसिल की श्रुतियों पर रोशनी डाली गई।** उस युग में लेजिस्लेटिव कौंसिल के सभी सन्त्य नामजद होते थे, इसलिए प्रस्ताव में यह मांग की गई कि सदस्य चुने जाएं कौंसिल के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार हो, उत्तर पश्चिम प्रांत तथा अवध (यू० पी० का यही नाम था) और पंजाब में कौंसिल बनाई जाए और पार्लियामेंट की एक कमेटी हो जो भारतीय लेजिस्लेटिव कौंसिल के अधिकार सदस्यों की तरफ से जो प्रस्ताव आए उन पर विचार करे।

इस प्रस्ताव पर नेताओं के भाषण हुए। बात यह है कि 1831 में जो शासन

सुधार मिले थे, उससे बाद से कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। श्री के० टी० तैलंग ने इस प्रस्ताव को रखते हुए कहा कि हमें नामजदगी नहीं चाहिए, हम चुनाव चाहते हैं। "हमें म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट और लोकल बोर्डों में निर्वाचित सदस्य का अधिकार लाइ रिपन से मिल चुका है। अब हम यह चाहते हैं कि लेजिस्लेटिव कौंसिल के कम से कम आधे सदस्य चुने हुए हों। श्री तैलंग ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा—“भारत मंत्री भारत के तानाशाह मुगल साम्राट है। उनकी खुशी ही कानून है। इस समय भारत में जितनी भी कौंसिलें हैं, उन सबका उद्देश्य यह है कि सरकार की तानाशाही को कानूनी जामा पहनाया जाए।” प्रस्ताव पर कई नेताओं के भाषण हुए। एस० सुब्रह्मण्य अय्यर ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि मैं अपने तजुर्खे से यह बात कहता हूँ कि यद्यपि सरकार बहुत तुच्छ मामलों में गैर सरकारी सदस्यों को कोई कोई छोटी मोटी बात मान लेती है, पर अधिकांश मामलों में उनकी कोई सुनाई नहीं होती। इसका कारण यह है कि भारतीय सदस्य चुने हुए नहीं हैं। श्री दादाभाई नौरोजी ने इस प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि यदि सरकार शासन सुधार दे दे, और साथ ही कौंसिल के सदस्यों को यह अधिकार हो जाए कि वे प्रश्न पूछ सकें, तो सरकार पर लोगों की नागाजगी बहुत कुछ घट जाएगी। लाला मुरलीधर ने कहा कि चुनाव का होना इसलिए आवश्यक है कि बहुत से लोग जो निया मिट्टू बनकर डीम भारतें फिरते हैं, उनकी कलाई खुल जाएगी और यह मालूम हो जाएगा कि कौन लोग राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं। महादेव गोविंद रानडे ने कहा कि भारत मंत्री की कौंसिल में भी चुने हुए सदस्य हों।

चौथे प्रस्ताव में मांग की गई कि ब्रिटेन तथा भारतवर्ष में सिविल सर्विस की परीक्षा एक साथ ली जाए और परीक्षापत्रों की उम्र 19 से बढ़ाकर 23 कर दी जाए। इस प्रस्ताव को दादाभाई नौरोजी ने रखा। पहले ही बताया गया है कि इस विषय को लेकर शिक्षित भारतीयों में बहुत भारी असन्तोष था। हम पहले यह भी बता चुके हैं कि सरकार ने स्टैच्यूटरी सिविल सर्विस नाम से जो सिविल सर्विस कायम की थी, उससे शिक्षितों में असन्तोष घटने की बजाय बढ़ा था। दादाभाई नौरोजी इसी युग में भारत के सम्बन्ध में आर्थिक आलोचना करके लोगों की आंख खोलने में सहायक हो चुके थे। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने यह दिखलाया कि अंग्रेजों की औसत वार्षिक आमदनी 495 रुपये, फ्रांस वालों की 345 रुपये, तुर्की लोगों की 60 रुपये है, पर भारतीयों की वार्षिक आमदनी 27 ही रुपये है, जिनमें से यन्त्र जमींदारों, पूजोपतियों आदि की आय को निकाल दिया जाए, तो आम भारतीयों की सालाना आमदनी 20 रुपया ही होगी। इस हालत में सिविल सर्विस के मोरो की तनख्वाह, पेंशन, भत्ता आदि में करोड़ों रुपये का देश के बाहर चला जाना बहुत ही अवाछनीय है। इसलिए दादाभाई का यह कहना था कि जब समान योग्यता वाले भारतीय मिल सकते हैं, तो सिविल सर्विस में जितने अधिक भारतीय लिए जाए, उतना ही अच्छा है, क्योंकि देश का रुपया देश में ही तो रहेगा।

प्रस्ताव पर बोलते हुए बंगाल से आए 'नव विभाकर' के सम्पादक गिरिजा बाबू ने स्वदेशी की आवाज उठाई। कहना न होगा कि यह व्याख्यान उस युग में बहुत कुछ अप्रासंगिक लगा होगा, फिर भी कांग्रेस के अंदर उठाई हुई स्वदेशी तथा वायकाट की पहली आवाज होने के कारण यह व्याख्यान स्मरणीय है। हम पहले ही देख चुके हैं कि हिंदू मेला में स्वदेशी की आवाज उठाई ही नहीं गई थी, बल्कि उसे व्यवहारिक रूप भी दिया गया था। गिरिजा बाबू ने कहा—“हम गरीब हैं, जो चीजें देश में मिल सकती हैं, उन्हें हम विदेश से अधिक दाम देकर क्यों खरीदें? हम लोग सिविल सर्विस वालों को

तनजवाह तथा पेशान के रूप में जो मोठी रकम देते हैं वह इस देश के बाहर ही खच होनी हैं। हम इनके साथ खच करके यह तजुर्वा हासिल करने हैं कि वह इस देश के बाहर चला जाता है जहाज पर लद कर विदेश चला जाता है, और हमारा ही विरुद्ध वस्तुमान होता है।

पाचवें प्रस्ताव में यह कहा गया कि सेना पर खच घटाया जाए। इस प्रस्ताव की आवश्यकता इसलिए हुई कि इन दिनों भारत सरकार पर रूस का हीरा चढ़ा हुआ था। उन दिनों अंग्रेज राजनीतिज्ञ इस बात को गम्भीरता के साथ समझते थे कि रूस का भार भारत पर हमला करना चाहता है। लाड रिपन ने इमीनिए अफगानिस्तान के साथ एक ऐसा बंदोबस्त किया था कि अफगानिस्तान उधर में हमला करने वाले से पहला मोर्चा ले, पर रूस का हीरा ब्रिटिश सरकार पर इन प्रकार चढ़ा हुआ था कि सरकार का यह प्रस्ताव था कि 20 लाख पौण्ड खच करके दस हजार गोरा और 20 हजार भारतीयों की, कुल 3॥ हजार सेना बढ़ाई जाए।

प्रस्ताव पर बोलते हुए रणैया नायडू ने कहा कि इस समय जो भारतीय सेना है, वह राष्ट्रीय सेना नहीं भाड़े का टट्टू है उनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना को हम पगार शिथिल किया जाए कि वह अपने को भारतीय समझे।

श्री बाबा ने प्रश्नाव का समर्थन करने हुए कहा कि 1856 में भारतीय सेना में 2 54,0०0 लोग थे 885 में घटकर उनकी संख्या 1,89 000 हो गई है, फिर भी पहले जहा 17 कराड रुपय खच होते थे अब वहा 26 करोड रुपय खच हो रहे हैं। श्री बाबा ने इस बीच के इतिहास का विश्लेषण करते हुए कहा कि सरकार ने 1857 के विद्रोह के बाद स यह डग रखा कि भारतीय सेना में भारतीय तो घटाए जाए और गोरो की संख्या बढ़ाई जाए। इस नीति के कारण गोरे सैनिक बढ़ाए गए और उनको चूकि अधिक तनजवाह दी जाती है इसलिए मना घटते हुए भी खच बढ़ा है। श्री बाबा ने यह भी कहा कि 1857 के पहले भारतीय मना भारत में ही काम जाती थी, पर उसके बाद से जहा भी साम्राज्य में जरूरत होती है, वही यह मना भेजी जाती है। भेजी जाए यह गलत नहीं, पर उसका सारा खच भारतीयों पर ब्यो लादा जाए ?

छठा प्रस्ताव भी सैनिक व्यय से सम्बंधित था। इसमें कहा गया था कि यदि सैनिक व्यय बटाना अनिवार्य हो जाए, तो उसका खच विदेशी माल पर टक्स लगाकर तथा लाइसेंसों से रुपये लेकर पूरा किया जाए। प्रस्ताव का आशय यह था कि किसी भी हालत में अब भारतीय सरकार का बोझा बढ़ाया न जाए क्योंकि उसकी हालत भी ही तबाह हो रही है।

सातवें प्रस्ताव में उत्तरी बर्मा को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेने का प्रतिबन्ध किया गया था। लाड डफगिन ने उत्तर बर्मा के राजा यिबो पर इस बहाने से हमला कर दिया था कि यिबो ने फेंच सरकार के साथ कोई गुप्त संधि की है, जो ब्रिटिश स्वार्थों के प्रतिकूल है। कुछ दिनों तक युद्ध होता रहा, पर 1885 के 27 नवम्बर को यिबो ने आत्मसमर्पण कर दिया और राजधानी पर कब्जा कर लिया गया। यहा यह भी बता दें कि जिस समय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था उस समय भी युद्ध हो रहा था और 1886 की जनवरी को बर्मा का बाकी हिस्सा भी साम्राज्य में मिलाया जाने वाला था। इसी कारण यह प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव पर बोलते हुए श्री फिरोजशाह मेहता ने कहा कि यदि अन्त में बर्मा को अधीन किया ही जाना हो, तो उसे भारत के अन्तर्भूत न करने एक श्राउन कालोनी बना दिया जाए। ऐसा प्रस्ताव रखने में श्री मेहता

का उद्देश्य था कि इस गृन्हा वेलज्जत से भारत को छुटकारा मिले, क्योंकि इसकी बदौलत बर्मा का सारा खच, विशेष कर सैनिक खच, भारत को देना पडेगा, और इसमे बर्मा की यह भलाई होगी कि क्राउन बालोनी होने के कारण उसे कुछ शासन सुधार यो ही प्राप्त हो जाएगे ।

आठवें प्रस्ताव मे कहा गया कि जितने भी प्रस्ताव हुए, वे सब देश को विभिन्न सस्थाओ को भेज दिए जाए और उनसे कहा जाए कि इन प्रस्तावो को सामने रखकर उचित कायवाही करें । यह प्रस्ताव भारत के राजनीतिक कायकर्ताओ को एक सूत्र मे बाधने के लिए आवश्यक था ।

नवा प्रस्ताव—इसमे यह कहा गया कि कांग्रेस का अगला अधिवेशन 28 दिसम्बर 1886 को कलकत्ते मे हो ।

### ‘महारानी की जय’ से सभा भग

सब प्रस्तावो के बाद घायवाद आदि हुए जिसमे मिस्टर ह्यूम को विशेष घायवाद दिया गया । कांग्रेस की अपनी रिपोर्ट मे अन्तिम दृश्य का यो वर्णन है— ‘मिस्टर ह्यूम को जो घायवाद आदि दिए गए थे, उहे स्वीकार करने के बाद वे ‘चियर्स’ दिलाने के लिए उठे, क्योंकि यह काम उही के सुपुद किया गया था । उन्होंने कहा कि Better late than never, यानी बेर जायद, दुरस्त आयद के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए मैं प्रस्ताव करता हू कि केवल तीन बार नही, बल्कि तीन का तिगुना, और हो सके तो उसके भी तिगुने ‘चियर्स’ इस महामहिमामयी महारानी विक्टोरिया के लिए दिए जाए जो उन सबको प्रिय हैं, और जिनकी वे सन्तान तुल्य है, और जिनके जूतों के फीतो को खोलने के योग्य वे स्वयं का नही समझन । इसके बाद वक्ता ने जो म तव्य दिए वे स्वतः स्फूर्त जय कारो की आधी मे डूब गए, और लोगो से जो चियस मागे गए थे, वे बार बार दिए गए ।”

इन नेताओ का उद्देश्य चाहे जितना छोटा रहा हो, इतिहास इस बात के लिए हमेशा इनका आभारी रहेगा कि इन लोगो ने एक ऐसी सस्था को जन्म दिया जा बाद मे भारतीय इतिहास का एक युग तक नेतरव करने मे सफल रही । इस कारण इन नेताओ के नाम स्वर्णालि र मे लिखे जाने योग्य हैं । भारत को एक करने और एक रखने मे यह बहुत बडा साधन सिद्ध हुआ ।

कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मे यह तय हुआ था कि कांग्रेस सामाजिक विषयो मे सुधार की चेष्टा करेगी, परन्तु अदरुनी मतभेद के कारण दूसरे अधिवेशन मे निश्चय यह हुआ कि कांग्रेस विशुद्ध राजनीतिक मामलो मे ही आदोलन करेगी तथा सामाजिक मामलो मे हस्तक्षेप नही करेगी ।

कांग्रेस की राजनीतिक वायशक्ति को वायम रखने के लिए यह आवश्यक था कि वह केवल राजनीतिक प्रश्नो तक ही अपने को सीमित रखे । अवश्य ही सामाजिक मामलो मे इम प्रकार तटस्थता मे कुछ अमुविधाए भी थी, क्योंकि मूलतः राजनीतिक प्रगति को सामाजिक प्रगति से अलग करना सम्भव नही था । राजनीति को सामाजिक सुधार से अलग रखने का निणय उस स्थिति को देखते हुए अनिवार्य भले ही रहा हो, पर उसमे कुछ उलझने भी पैदा हुई ।

इस अवसर पर हम यह भी देखें कि जिम रूप मे कांग्रेस शुरू हुई उसमे घम को राजनीति से बिल्कुल अलग रखा गया था । बाद के युग मे कांग्रेस के विप्लव वार-वार यह जो अभियोग लगाया गया कि उसने घम और राजनीति को एक कर दिया, हम देखेंगे कि कांग्रेस के आदि नेता इसके लिए जिम्मेदार नही थे ।

## पहली कांग्रेस के बाद

हमने पहली कांग्रेस का ब्योरा विस्तार से दिया। वह इस कारण कि बाद की लगभग तीन दशक तक जय तक कि महात्मा गांधी ने उसे आपादमस्तक परिवर्तित, परिभाजित करके एक जू सस्या नहीं बना दिया, तब तक वह इसी प्रस्तावों के हृदयि लगभग कोल्हू के बल की तरह घूमती रही। वह इस कारण कि इस बीच कांग्रेस के जो वर्णाधार रह व आवेदन निवदन अधिक में अधिक विलापत तक शिष्टमंडल ले जाकर ब्रिटिश ससद के सामने हल्लागुल्ला ही कर सकत थे। अवश्य ही इसी युग व दौरान एम लोग भी भारत में थे, जो क्रांतिकारी तरीके से सोचत थे। तिलक कांग्रेस में थे, पर क्रांतिकारी सम्पादक और चिन्तक के रूप में उनका एक पर कांग्रेस के बाहर था। इसी बाहरी पर के कारण वह तिलक बने और अंग्रेजों के लिए होवा बन गए जसा कि उस समय के एंग्लो इण्डियन साहित्य में प्रतिफलित था। इस साहित्य में तिलक को एंटी फ्राइस्ट याने ईसा विरोधी के रूप में चित्रित किया गया था।

### क्रान्तिकारी धारा

जो लोग आदालत की इस धारा से अलग रहकर स्वाधीनता के लिए एकान्त में अलख जगा रहे थे, उनमें स दो का नाम उल्लेखनीय है—(1) वामुदय बलवत फडके और (2) रामसिंह कूका। फडके का जन्म कोलावा (महाराष्ट्र) के एक गांव में 4 नवम्बर 1845 को हुआ था। 1857 के महाविद्रोह के समय वह सचेत हुए। 'याममूर्ति' रानडे व दो भाषणों (1872) से वह इतने प्रभावित हुए कि उनसे अब चुप बठना सम्भव नहीं रहा। उनके रोजनामचे से पता चलता है कि वह अंग्रेजी सरकार द्वारा सूद के कारण उत्पन्न भारतीयों की गरीबी से बहुत पीड़ित थे। यह पढ़े लिखे लोगों से निराश थे। उनका लगा कि अतपढ़ जनता ही कुछ कर धर सकती है। उन्होंने जरामयपका समझी जाने वाली रामोक्षी जाति को संगठित किया। धन के लिए डाके डाले। वे एक गिरफ्तारी के लिए सरकार ने इनाम रख दिया। बहुत दिनों तक अंग्रेजों के लिए आतक बने रहने के बाद वह गिरफ्तार हुए तो उन पर दफा 121 (राजद्रोह) 124 (राजद्रोही भाषण) और 395 (डकैती) में मुकदमा चला। 31 अक्टूबर 1880 को फडके आजीवन कालेपानी की सजा भोगत हुए अदन (अरब) जेल से भागे। सत्रह मील भागने के बाद वह गिरफ्तार हुए। फरवरी 1883 में उनका विदेश में देहात हुआ। न किसी ने जाना, न किसी ने आह भरी।

रामसिंह कूका लुधियाना के भणी गांव में पैदा हुए थे। वह महाराज रणजीत सिंह की सेना में थे। अंग्रेजों के बढ़ते साम्राज्य को देखकर वह दुखी होकर गहस्थी छोड़

कर अलग हो गए। वह घम के जरिए देश का उद्धार करना चाहते थे। वह गोरक्ष भी थे। पहले वह कुछ सुलकर, फिर गुप्त रूप में अपने शिष्यों को संगठित करने लगे। गोरक्षा पर जोर के कारण उनके शिष्यों ने कुछ बूचड़ों की हत्या कर दी। सरकार को मौका मिल गया। असली उद्देश्य पीछे रह गया। सरकार ने रामसिंह को पकड़कर 1818 के रेगुलेशन के तहत बर्मा भेज दिया। वहीं उनकी मृत्यु हो गई। उनके बहुत से शिष्य पहले ही तोप से उड़ाए और फाँसी पर चढ़ाए जा चुके थे।

## कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन

कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ते में हुआ। अम्बिकाचरण मजुमदार ने लिखा है कि "यद्यपि कांग्रेस का जन्म बम्बई में हुआ, पर सारी रस्मा के साथ-साथ उसका चरित्रसा साधारण्य की राजधानी कलकत्ते में ही हुआ। अथ सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस में शरीक हुए। इसके बाद में यह बराबर कांग्रेस में शरीक होते रहे, 1917 तक उनका यही क्रम जारी रहा। कांग्रेस तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी दोनों के हक में यह बहुत अच्छा रहा। पंडित मदनमोहन मालवीय पहली बार इस कांग्रेस में आए। अब को बार जो प्रतिनिधि आए, वे कांग्रेस के अंतर्गत विभिन्न सस्थाओं से चुनकर आए। ब्रिटिश इण्डियन एसोसियेशन के सभापति तथा प्रसिद्ध पुरातात्विक डाक्टर राजे द्रलाल मिश्र अधिवेशन की स्वागत समिति के सभापति हुए, और श्री दादाभाई नौरोजी सभापति हुए।

दादाभाई नौरोजी (1825-1917) पारसी पुरोहित परिवार के थे। 1851 में उन्होंने 'रास्त गोफ्तार' नाम का एक पाठिक समाचार पत्र निकाला था। बाद में उन्होंने 1882 में 'वायस आव इंडिया' नाम का मासिक भी निकाला था, जो बाद में मालाबारी के पत्र 'इण्डियन स्पेक्टेटर' के अंतर्भूत हो गया। 1855 में वह व्यापार के सिलसिले में इंग्लैंड गए, 1874 में वडोदा के महाराजा के दीवान बने, पर रेजीडेंट से न पटने के कारण इंग्लैंड वापस चले गए और फिर सावजनिक सेवा में लग गए। 1867 में ही वह लन्दन में इस विषय पर बोल चुके थे कि क्या भारत के लिए ब्रिटिश शासन हितकर है? इसका उत्तर वह ना में दे चुके थे। उनका कहना था ब्रिटिश शासन में गरीबी बढ़ती जा रही है। प्रतिवर्ष 3 या 4 करोड़ पाँड़ की रकम भारत से इंग्लैंड जा रही है। अधिकांश भारतीय भूखों से मर जाते हैं, वे दुर्भिक्ष और रोग के शिकार हैं। ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस का अध्यक्ष पद देना उचित ही था।

इस अधिवेशन में पहली बार एक राष्ट्रीय गीत गाया गया। बमाल के प्रसिद्ध कवि हेमचंद्र ने यह काव्य किया और स्वयं गीत गाया। अभी 'वंदे मातरम' राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृत नहीं था परंतु हेमचंद्र ने जो गीत गाया उसमें उन्होंने 'वंदे मातरम' की कुछ पंक्तियाँ को रस दिया। इससे पता चलता है कि हेमचंद्र नैतिक रूप से समझते थे कि 'वंदे मातरम' गीत ही राष्ट्रीय गीत का स्थान लेने योग्य है।

पहले कांग्रेस का अधिवेशन ब्रिटिश इण्डियन एसोसियेशन के हाल में होने वाला था, क्योंकि समझा गया था कि बम्बई में प्रतिनिधियों की संख्या 72 थी तो यहाँ अधिक से अधिक 172 होगी, पर प्रतिनिधियों की संख्या 426 पहुँच गई, इसलिए टाउन हाल में अधिवेशन करना पड़ा। 27 दिसम्बर के अधिवेशन में स्वयं रवीन्द्रनाथ ने भी एक गीत गाया, जिसमें उन्होंने एक तरह से भारतीयों की एकजुटता पर अपना वक्तव्य दिया, पुरातात्विक डाक्टर राजे द्रलाल मिश्र ने स्वागत समिति की ओर से बोलते हुए कहा

“यह मेरे जीवन का स्वप्न रहा है कि मेरी जाति की बिरारी हुई इजाजत दिला नि एक हो जाए और केवल व्यक्तियों के रूप में जीने के बजाय हम एक जाति के रूप में जीने में समर्थ हो। हम इस सभा में इसी प्रकार की एकता का प्रारम्भ देख रहे हैं। मैं इस कांग्रेस में भारतवर्ष के अधिक सुखवर तथा सुन्दरतर दिवसों को देख रहा हूँ।”

कांग्रेस के अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी ने कांग्रेस के कर्तव्यों का दिग्दर्शन करते हुए कहा कि कांग्रेस केवल ऐसी समस्याओं का लेकर चले, जिनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध सारी जाति से हो और यह सामाजिक सुधार तथा अर्थ वर्गीय प्रश्नों को दूरकर का हाथ में छोड़े।

**अर्थ कानून का विरोध**—इस कांग्रेस में भी प्रतिनिधिमूलक शासन सुधार, सिविल सर्विस में भारतीयों की नियुक्ति, सना का व्यवसाय आदि विषयों पर प्रस्ताव हुए। इस कांग्रेस में हथियार कानून खत्म कर देने के सम्बन्ध में भी भाषण हुआ। अवध के राजा रामपाल सिंह ने इस विषय में जोरदार भाषण दिया। उन्होंने कहा—

“सरकार ने हमारी जो कुछ भलाई की, उसके लिए हम आभारी हैं। पर सरकार से हमारी जो हानि हुई है, और जिसकी कभी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, उसका लिए हम आभारी नहीं हो सकते। हमको दवाने के लिए, हमारे आदर की मुद्राशक्ति को नियमित रूप से विलुप्त करने के लिए, एक योद्धा तथा वीर जाति को मुश्किलों की जाति में परिणत करने के लिए हम सरकार का प्रति आभारी नहीं हो सकते। ईश्वर को धन्यवाद है कि अभी हम लोगों की हालत उतनी नहीं गिर गयी है। भारत में सर्वत्र हममें एक सोच अब भी मौजूद है, जो तलवार चलाना जानते हैं, और खरूरत पड़ने पर देश की रक्षा के लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं।”

**मुसलमानों का अनुपात**—इस कांग्रेस में 38 मुसलमान प्रतिनिधि आए थे जिनमें से बम्बई के प्रसिद्ध व्यापारी रहमतुल्ला सयानी, अवध के राजा अली नवाब तथा बिहार के सफरुद्दीन के नाम उल्लेखनीय हैं। इसमें ज्ञात होता है कि काफी मुसलमान कांग्रेस के पक्ष में थे फिर भी कई प्रमुख लोग जैसे नवाब अब्दुल लतीफ, सैयद अमीर अली तथा उनके अनुयायी इस कांग्रेस में शरीक नहीं हुए।

**गोरे अखबारों के मन्तव्य**—इस कांग्रेस के सम्बन्ध में सरकारी तथा अन्त-सरकारी पत्रों में क्या कहा यह दिलचस्प है। ‘स्टेट्समैन’ ने लिखा “कांग्रेस ऐसे लोगों की सभा है, जिनके लिए हम सब के साथ कह सकते हैं कि सौ साल के हमारे शासन में ऐसे लोग उत्पन्न तो हुए। पर लंदन के ‘टाइम्स’ ने लिखा “यह तो कुछ असंतुष्ट नौकरों चाहने वालों का मजमा था जो पुर्जा के बने हैं, और देश से जिन्हें कोई मतलब नहीं जिनमें अनुकरण करने की काफी शक्ति है पर जो सरकार की वास्तविक समस्याओं को कुछ भी नहीं समझते। ये बात बनाने वाले लोग हैं पर ये सार्वजनिक शान्ति के लिए बहुत गतन्तरनाक ग्राहित हो सकते हैं।”

### कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन

कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन मद्रास में बम्बई के प्रसिद्ध मुस्लिम बरिस्टर वदरुद्दीन तयबजी के सभापतित्व में हुआ। इस बार कांग्रेस में 600 से अधिक प्रतिनिधि आए। जनता में काफी जोश था और आम जनता के लिए पहली बार पदाल का उपयोग हुआ। पदाल तमिल शब्द है और इसका अर्थ ‘मंच’ है, पर यही से यह पदाल शब्द अखिल भारतीय हो गया। बंगाल से 80 प्रतिनिधि एक स्टीमर रिजेंट करके मद्रास आए थे। इस बार के सभापति मुसलमान थे, फिर भी कुछ लोगों ने यह चेष्टा की कि मुसल

मान इसमें शरीक न हो। ऐसे लोगों में नवाब अब्दुल लेतीफ का नाम विशेष उल्लेख योग्य है। इन्होंने बाकीपुर में एक सभा में भाषण देते हुए कहा कि मुसलमान कांग्रेस में शरीक न हो। फिर भी पटना के बार एसोसियेशन से मौलवी सफरुद्दीन, अमीर हदर, तफज्जुल हसन आदि कई मुसलमान चुने गए। बाद की सफरुद्दीन साहब कलकत्ता हाई कोर्ट के जज बने थे।

**म धराराय तथा तैयबजी के मतव्य**—सर टी माधवराव स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने उस युग के नेताओं के दुरंगे विचारों को व्यक्त करते हुए कहा कि “हम विश्वास के साथ अपनी को उस महान जाति तथा महान सरकार के हाथों में सौंप दें जो ईश्वर की कृपा से आज हमारे भाग्य के नियन्ता हैं। हम विश्वास रखें कि हमारा भविष्य उज्ज्वल है।” सभापति ने अन्त विषयों के अलावा यह भी कहा, “भारत में जो विभिन्न सम्प्रदाय हैं, उनके सम्बन्धों में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कांग्रेस सरकार को सुधारने की जो कोशिश कर रही है, हमारे सम्प्रदाय के नेता उससे अलग रहें।”

**कांग्रेस में जनता**—इस अधिवेशन की विशेषता यह थी कि इसमें पड़े-लिखे वर्ग के अतिरिक्त साधारण जनता यहां तक कि मजदूरों ने भी हिस्सा लिया। मद्रास में कांग्रेस को सफल बनाने के लिए जो चढ़ा इकट्ठा किया गया था, उसमें साढ़े पांच हजार रुपये मजदूर और अन्य गरीब लोगों के द्वारा दिए हुए एक आने से लेकर डेढ़ रुपये तक के चन्ने से जमा हुआ था। मद्रासियों को मद्रास में कांग्रेस होने का इतना गव था कि रंगून सिगापुर, माडले आदि से मद्रासियों ने इस कांग्रेस के लिए चढ़ा भेजा था। कोई पांच हजार लोग नेताओं को देखने पडाल के पास इकट्ठे हुए। इस बार के अधिवेशन में तजावर से तीन बढई कांग्रेस में प्रतिनिधि के रूप में आए। इनमें से एक ने कांग्रेस की सभा में भाषण करते हुए बढईयों के दुःख दर्दों का उल्लेख किया।

**अस्त्र कानून के प्रस्ताव पर ह्यूम परेशान**—इस अधिवेशन में भी अस्त्र कानून को हटा लेने के सम्बन्ध में विचार हुआ। विपिनचन्द्र पाल तथा सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने अस्त्र कानून हटा लिए जाने के सम्बन्ध में लम्बे भाषण दिए। नैलोक्यनाथ मिश्र ने सशोधन रखा कि अस्त्र कानून को इस प्रकार सशोधित किया जाय कि स्थानीय तथा नगरपालिका के अधिकारियों से अनुमति लेकर लोग हथियार रख सकें। कहा जाता है कि जिस इस समय प्रस्ताव पर विचार हो रहा था, उस समय मिस्टर ह्यूम बहुत परेशान हो रहे थे, क्योंकि वह डर रहे थे कि वही ऐसे प्रस्ताव पास कर कांग्रेस सरकार की कोप-भाजन न हो जाय। ठीक भी था, जब मिस्टर ह्यूम जैसे लोग यह समझते थे कि ब्रिटेन और भारत का गठबन्धन विरज्जित है, और एक शासित रहेगा और दूसरा उदारचरित शासक, तो उस भारत में अस्त्र कानून बात की कहा आ सकती थी। अस्त्र कानून हटाने की मांग करना ही यह साबित करता था कि मांग करनेवाले किसी हालत में अस्त्र इस्तेमाल करने में विश्वास करते हैं। इस कारण मिस्टर ह्यूम को ये विचार खतरनाक प्रतीत हुए, पर वह इन्हें रोकने में असमर्थ थे।

**गवर्नर की दावत**—कुछ भी हो, अभी कांग्रेस पर सरकार सम्पूर्ण रूप से कुपित नहीं हुई थी। मद्रास के गवर्नर लार्ड कोनरमारा चाहते थे कि वे अधिवेशन में शरीक हो पर लार्ड डफरिन ने सलाह दी कि वे अधिवेशन में जाने की बजाय कांग्रेस के नेताओं को एक घाय पार्टी दें। तदनुसार लार्ड कोनरमारा ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों को एक पुरतकल्लुफ दावत दी। गवर्नर का वैड वज्रता रहा और कांग्रेस के नेता गवर्नर के मेहमान हुए।

गवर्नर के अतिरिक्त मद्रास के गोरे बैरिस्टर नाटन ने भी कांग्रेस प्रतिनिधियों



को दावत दी। वह स्वयं भी कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए। इस प्रकार यह अधिवेशन एक सफल अधिवेशन रहा। इसमें भी उही विषयो पर प्रस्ताव हुए जिन पर पहले अधिवेशनों में हुए थे।

अश्विनीकुमार दत्त का नया तरीका—मद्रास कांग्रेस में पूर्व वंगाल के नेता श्री अश्विनीकुमार दत्त 45 हजार व्यक्तियों के दस्तखत से एक अपील ले आए थे, जिसमें कांग्रेस के नेताओं की शुभकामना करते हुए शासन सुधार की मांग की गई थी। इस प्रकार 45 हजार लोगों के दस्तखत कराना एक नई बात थी। अश्विनीकुमार दत्त ने अपील को पेश करते हुए कहा कि “एक अच्छत मर निकट आया और उसने कहा कि— महाशय, हमारे अपने लोग ही कानून बनाएंगे, यह कितने आनंद की बात है।” इसी प्रकार एक गरीब मुसलमान ने मुझे चार आने पैसे दिए और कहा कि मैं हम अपने लोगों के काम में लगाऊँ। एक दूसरे किसान ने अपने पड़ोसी से कहा कि देखो, जिस हम पचायत चलाते हैं और पचायत के फैसले को मानते हैं, उसी प्रकार हमारे अपने ही आदमी कानून बनाएंगे, तब हम उन्हें क्यों न मानेंगे? महाशय, आप देख रहे हैं कि जनता किस प्रकार हमें सहायता देने के लिए उत्सुक है।”

इस प्रकार मद्रास कांग्रेस में यह सुन्दर शब्द सुनाई पड़ा—जनता। और सो भी 45 हजार के दस्तखत फिर उसमें अछूत भी और मुसलमान भी। जब कांग्रेस के साथ जनता का कुछ मामूली ही सही, सम्बन्ध होने लगा, तो सरकार के कान खड़े हो गए। गौरे अखबार जिनमें उन दिनों इलाहाबाद का ‘पायोनियर’ भी था खुल्लम खुल्ला कांग्रेस पर बौछारें करने लगा। उनको इस समय प्रयुक्त हो रहे शब्द ‘नेशन’ या ‘जाति’ शब्द पर भी आपत्ति थी। कहा तो कलकत्ता में लार्ड डफरिन ने तथा मद्रास में लार्ड कोनरमार ने कांग्रेस नेताओं को दावत दी, पर अब 1888 के प्रारम्भ में ही संयुक्त प्रांत (यू० पी०) के गवर्नर सर आर्चबिशप कालविन ने कांग्रेस के विरुद्ध जेहाद बोल दिया। उन्होंने खिताब देने के लिए बुलाए हुए दरबार में कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा—

“आपको चाहिए कि आप अपना ध्यान अपने कामकाज के उचित दायरे में सीमित रखें न कि बड़ी बड़ी उड़ानों में अपना समय नष्ट करें, जिनको कामकाज में परिणत करने के लिए ऐसी सामूहिक क्रिया तथा व्यवहारिक बुद्धि चाहिए जो लम्बे समय तक सार्वजनिक कार्यों को परिश्रम के साथ करने पर ही उत्पन्न हो सकती है।”

### चतुर्थ अधिवेशन

चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में होना तय हुआ था। कालविन की जब यह मालूम हुआ कि कांग्रेस इलाहाबाद में होने वाली है तो उसने तरह-तरह के अड़ने लगाए। स्वागत समिति कांग्रेस अधिवेशन खजाने बाग में करना चाहती थी, पर सरकार राजी नहीं हुई। इसके बाद यह चेष्टा हुई कि जिले के पास अधिवेशन हो पर सरकार ने यहाँ भी बहाने बनाकर अधिवेशन नहीं होने दिया। तब स्वागत समिति के लोगों ने ‘पायोनियर’ के दफ्तर के पास एक तम्बू गाड़कर अधिवेशन करना चाहा पर इसको यह कह कर टाल दिया गया कि इससे वहाँ के रहने वाली के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। तब स्वागत समिति के पंडित अयाध्यानाय ने कांग्रेस का अधिवेशन अपनी ही एक हवेली में करने का विचार किया। इस पर भी कुछ गड़बड़ी की गई, पर अंत में इसी मकान में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ।

कांग्रेस और अल्पसंख्यक—कांग्रेस की शक्ति बढ़ रही थी, यह इस बात से प्रकट है कि इस बार प्रतिनिधियों की संख्या 1248 रही, जिनमें 221 मुसलमान, 220

ईसाई, ४ सिख, 11 जैन और 7 पारसी थे। इस प्रकार कांग्रेस में आधे के करीब प्रतिनिधि अल्पसंख्यक सम्प्रदायों के थे। सर सैयद अहमद के विरोध करने पर भी अवध से बहुत से मुसलमान आए। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने अपनी पुस्तक 'नेशन इन मेकिंग' में लिखा है कि "हम इस महान राष्ट्रीय कार्य में अपने मुसलमान भाइयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए सब कुछ कर रहे थे। कभी कभी तो हम मुसलमान प्रतिनिधियों को रेल का किराया देकर लाते थे और उन्हें अथ सुविधाएँ देते थे।"

इसी साल जून पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट निकली, तो उसमें एक गुल खिला। कमीशन ने सिफारिश की कि सिविल सर्विस परीक्षा में परीक्षार्थियों की उम्र कम से कम 21 और अधिक में अधिक 23 हो। इसके साथ ही कमीशन ने यह सिफारिश की कि स्टैच्यूटरी रिविज सर्विस उठा दी जाए, और योग्य कर्मचारियों को सरकारी देकर नियुक्त किया जाए। यहाँ तक कि सभी सदस्य एकमत थे पर सिविल सर्विस की परीक्षा एक साथ भारत और इंग्लैंड में हो इस बात पर सब सदस्य एक मत न हो सके।

गोरा ने इसके विरुद्ध वोट दिया यह तो समझ में आता है। वे तो सिविल सर्विस को अपनी बंपोटी बनाना चाहते थे, पर दो मुसलमान सदस्यों ने, जिनमें सर सैयद अहमद भी थे, इस प्रस्ताव का यह कहकर विरोध किया कि भारत में सिविल सर्विस की परीक्षा होने पर हिंदू बाजी मार ले जाएंगे और मुसलमानों को कुछ नहीं मिलेगा। कहना न हाँगा कि यह बहुत ही अजीब तर्क था। इस तर्क का अभिप्राय यह था कि मुसलमान आ नहीं सकते, इसलिए हिंदुओं को भी न आने दिया जाए। सर सैयद अहमद के ये विचार बहुत ही प्रतिन्यायावादी थे और दुर्भाग्य से भारतीय अंग्रेजी शिक्षित मुसलमानों के वे ही नेता हुए। उन्होंने पेद्रियाटिक एसोसियेशन नाम से एक कांग्रेस विरोधी सभा भी स्थापित की।

**सरकार की अकारण घबड़ाहट—**इलाहाबाद कांग्रेस के सभापति मिस्टर जार्ज यूल नामक एक स्काच सज्जन बनाए गए। वे उन दिनों बंगाल चेम्बर्स आफ कामर्स के सभापति थे। आश्चर्य है कि जब इस प्रकार एक जिम्मेदार गोरा कांग्रेस अधिवेशन का सभापतित्व कर रहा था, तो फिर सर कालविन को उसमें होना क्यों दिखाई पड़ा। इस कांग्रेस में लेजिस्लेटिव कौंसिल का सुधार, 'याय विभाग का पथकीकरण, पुलिस विभाग में सुधार, आबकारी में सुधार, एक हजार से अधिक आमदनी पर ही आयकर, शिक्षा के खर्च में वृद्धि, औद्योगिक कमीशन की नियुक्ति तथा नमक कर में कमी पर प्रस्ताव पास हुए।

**साइ डफरिन द्वारा कांग्रेस पर बोझार—**उस यम की विचारधारा यह थी कि विलायत की सरकार और विलायत के अंग्रेज अच्छे हैं, यदि बुरे हैं, तो यहाँ के अंग्रेज, तदनुसार लोग अब यह आवश्यकता अनुभव कर रहे थे कि विलायत में प्रचार काय हो। हूँ तो इस सम्बन्ध में विलायत में आन्दोलन करते ही रहते थे। विलायत में कुछ प्रगतिशील अंग्रेज भारतीयों की हमदर्दी में जब तब कुछ कह दिया करते थे। लार्ड डफरिन जब भारतवर्ष में जाने वाले थे, तो उन्होंने 30 नवम्बर 1888 को सेंट एंड्रूज डिनर के उपलक्ष्य में बोलते हुए कुछ अजीब बातें कही। उन्होंने कहा

"कुछ बुद्धिमान राजभक्त और अच्छे विचार वाले लोग एक बड़ी भारी छलांग इस तरह भरना चाहते हैं कि उनकी इच्छा है कि भारतवर्ष की सरकार में लोकतान्त्रिक ढंगों का प्रयोग किया जाए। वे लोकतान्त्रिक तथा ससदीय ढंग भारत में चाहते हैं जिसे इंग्लैंड ने धीरे धीरे सदियों की तैयारी के बाद मीखा है। वे चाहते हैं कि सरकार लोकतान्त्रिक हो, नौकरशाही उनके अधीन हो और उन्हें राष्ट्र के खजाने पर अधिकार

मिल जाए, और धीरे धीरे ब्रिटिश अधिकारी वग उनमें सामने हाथ जोड़कर सड़ ही। इसका अगला कदम यह है कि देश की रक्षा के लिए सिर्फ भारतीय सेना ही रहे और ब्रिटिश सेना खींची कर दी जाए। मैं उनसे कहूँगा कि भला कोई बुद्धिमान व्यक्ति कभी यहल्पना कर सकता है कि ब्रिटिश सरकार, खुदबीन ने देखे जा सके जो योग्य इस अल्पसंख्या को उम महान तथा विस्तृत साम्राज्य का भाग्य का नियंत्रण करने, जिसने लिग सरकार ईश्वर तथा सम्भ्रता की आस्था में निम्नेदार है।”

लाड डफरिन ने चलते समय कांग्रेस पर जो लात जमाई, उससे एक पूरा नया विवाद उठ खड़ा हुआ। यह व्याख्यान लंदन के 'टाइम्स' में छपा और भारतवर्ष मिस्टर ब्रैडला ने इस विषय पर यूकंसल में एक सभा की। लार्ड डफरिन जिस समय इंग्लैंड पहुँचे, तो ब्रैडला से मिले और उनसे माफी माँगी कि उनका वह अभिप्राय नहीं था। उन्होंने कहा कि हम नहीं समझते कि कांग्रेस राजद्रोही संस्था है।

इही बातोंसे प्रभावित होकर कांग्रेस के नेताओं ने आवश्यकता समझी कि विलायत में प्रचार काय चालू रहे। तदनुसार 27 जुलाई, 1889 को लंदन में कांग्रेस का प्रचार काय करने के लिए ब्रिटिश इण्डिया कमेटी की स्थापना हुई। दादाभाई नौरोजी उन दिनों इंग्लैंड में ही थे। 1886 में वे ब्रिटिश संसद के लिए उम्मीदवार छड़े हुए थे, पर इसमें सफल नहीं हो सके थे। उन्होंने मिस्टर वेडरबन, डब्लू० एस० वेन और विलियम डियरी के साथ ब्रिटिश इण्डिया कमेटी को चलाने का भार लिया। बाद को इसी कमेटी की तरफ से 1890 में 'इण्डिया' नामक मासिक निकलने लगा। यह पत्र जनवरी, 1898 से साप्ताहिक हो गया। असहयोग आन्दोलन के समय जब आत्मबल पर स्वराज्य लेने की बातचीत चली, उस समय 'इण्डिया' का प्रकाशन यह कहकर बंद कर दिया गया कि हमकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें स्वराज्य जीतना है न कि भीख में पाना है।

## कांग्रेस का पाँचवा अधिवेशन

कांग्रेस का पाँचवा अधिवेशन 1889 में फिर बम्बई में हुआ। अब की बार सर विलियम वेडरबन इसके सभापति हुए। सर फिरोजशाह मेहता स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में मजे की बात यह हुई कि यह सन 1889 था और हममें प्रतिनिधि भी 1889 आए थे। बम्बई और सिंध से 821 प्रतिनिधि आए थे, बतमान बंगाल, बिहार, उड़ीसा आसाम से 165, मद्रास से 336, पंजाब से 62, मुघल प्रान्त से 261, मध्य प्रांत और बरार से 214। इनमें मुसलमान प्रतिनिधियों की संख्या 258 थी। 6 स्त्रियाँ भी अधिवेशन में प्रतिनिधि बनकर आई थी। उनके नाम हैं—पड़िता रमाबाई, विद्यागौरी तीलक, रमाबाई रानडे, श्रीमती निक्म, कादम्बिनी गागुली और स्वर्ण कुमारी घोषाल। कादम्बिनी गागुली भारत की प्रथम दो ग्रेजुएट न से थी। इस अधिवेशन में पहली बार गोपालकृष्ण गोखले तथा लोकमान्य तिलक पधारे।

कांग्रेस में चार्ल्स ब्रैडला—इस कांग्रेस की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि चार्ल्स ब्रैडला कांग्रेस के अधिवेशन को देखने के लिए आए थे। ब्रैडला ब्रिटिश संसद के सदस्य थे, और संसद में जब भी भारत का प्रश्न आता था, तभी वह भारत का पक्ष लेते थे, यहाँ तक कि लोग उन्हें 'मेम्बर फॉर इण्डिया' कहने लगे थे। ब्रैडला अनीश्वरवादी थे। अपने निमल चरित्र के कारण लोगों पर उनकी घाक जमी हुई थी। वह बहुत स्वतंत्र विचार के व्यक्ति थे। जब वह संसद के सन्स्य चुने गए, तो उन्हें नियमानुसार यह कहा गया कि ईश्वर का नाम लेकर शपथ ग्रहण करें, पर उन्होंने ऐसा करने में इनकार कर दिया। इसके लिए उन्हें कुछ दिनों तक संसद में बैठन भी नहीं दिया गया, पर अंत में उनके

लिए विशेष नियम बना और उन्हें अपने ही शब्दों में शपथ ग्रहण करने की स्वतन्त्रता दी गई।

**सभापति का भाषण**—सर विलियम वेडरबर्न न ब्रिटिश सरकार की निंदा करते हुए कहा "कम्पनी की अमलदारी में कम्पनी पर जो दखल रहेगी थी, उसके कारण फिर भी भारतीयों की अवस्था अच्छी थी, पर 1858 से जब से सरकार कम्पनी के हाथ से सीधे सम्बाजी के हाथ में गई, तब से भारतीयों के कष्ट और भी बढ़े हैं। कम्पनी को ससद की परवा रहती थी, पर अब सरकार को किसका डर है? उदाहरणस्वरूप, लाड रिपन ने कपि बैंक की स्थापना के लिए एक योजना बनाई थी, भारत सचिव के दफ्तर से इसका समर्थन करने की बजाय इस योजना को खत्म कर दिया। मैं पूछता हूँ कि कपि बैंक के बगैर किसानों की कैस उन्नति हो सकती है? वे तो हमेशा साहूकारों के हाथों में कठपुतले बन रहे हैं। यदि कपि बैंक न हो, तो यह निश्चित है कि किसानों की फसल किसानों के घर में नहीं जाएगी। ज़मीनी को देखिए, वहाँ दो हजार कपि बैंक काम कर रहे हैं।" इस प्रकार किसानों की समस्या किसी न किसी रूप में उठी।

**लोकमाय तिलक और गोखले**—इस कांग्रेस में क्या हुआ, यह बताने के पहले हम यह बता दें कि लोकमाय तिलक तथा गोखले कौन थे। लोकमाय तिलक स्वभाव से एक प्रयत्नशील तथा विद्याप्यसनी थे, पर वह स्वार्थी नहीं थे। वह चाहते थे कि जो शिक्षा उन्हें मिली है, वह देश के अधिक से अधिक लोगों को मिले। उन्होंने 'डेकन एज्यूकेशन सोसाइटी' नाम से एक शिक्षा संस्था तथा एक स्कूल कायम किया था। यह स्कूल बढ़ते बढ़ते फर्ग्युसन कालेज में तबदील हो गया। शिक्षाप्रती होने के अतिरिक्त लोकमाय पत्रकार भी थे। वह सोसाइटी के पत्र 'मराठा' और 'केशरी' में निरन्तर लिखते रहे। वह जो उचित समझते थे वही लिखते थे। उन्होंने 'केशरी' में बम्बई की एक रियासत की समालोचना कर डाली, जिसके कारण उनकी तथा उनके सहयोगी आगरकर को चार महीने की सज़ा हुई। तिलक संस्कृत तथा गणित के प्रकाण्ड विद्वान थे। वह बाद के 'गोता रहस्य' तथा अन्य गवेषणा की पुस्तकें लिख कर अमर हो गए।

गाखले भी डेकन एज्यूकेशन सोसाइटी के सदस्य थे। वह अर्थशास्त्र के पंडित थे। विचारों में वे उदारवादी थे। बाद के पन्ना में हमें तिलक तथा गोखले से अक्सर साक्षात् पड़ेंगे।

**अल्पसंख्यका का प्रश्न**—इस कांग्रेस में भी शामन सुधार की मांग का प्रस्ताव ही मुख्य था। यों तो यह प्रस्ताव पहले की ही तरह था, इसमें कोई विशेषता नहीं थी, पर एक नई बात जरूर थी। वह यह कि प्रस्ताव में कहा गया था कि दस लाख में से एक सदस्य लिया जाय, और पारसी, ईसाई, मुसलमान जो भी अल्पसंख्यक सम्प्रदाय के लोग हों, उनके कम से कम इतने सदस्य लिए जाय कि दस लाख पर एक के हिसाब से उनके सम्प्रदायों की संख्या कम न हो। मि० जाडल नाटन ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। पंडित अमोघानाथने इसका अनुमान किया। मिस्टर ह्यूम की राय में अल्पसंख्यावाली बात की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह बोले "भारतीय तो भारतीय हैं, उनमें अल्प संख्या और बहुसंख्या कौन?" अवध कमुनी हिदायत रसूल ने सशोधन रखा कि यद्यपि हिंदुओं की बहुसंख्या है, पर धारासभा में हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर हो, तब तक वे बैरिस्टर मिस्टर हामिद अली खान ने इस सलाह का यह कहकर विरोध किया कि इस सम्बन्ध में हिंदू और मुसलमानों का कोई प्रश्न नहीं उठता। इस पर संयद बाजिअली ने तर्क में आकर कहा कि धारासभा में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं की संख्या की निगुनी हो। संयद भीरुद्दीन अहमद बलखी ने साम्प्रदायिक मनावृत्तिपुस्तक सरो-

घनो का विरोध करत हुए वहा कि 'हम यहा पर एक सामान्य उद्देश्य लेकर जमा हुए है। ऐसे अवसर पर न तो मुसलमान अपने को मुसलमान कह सकते हैं, न हिंदू अपने को हिंदू कह सकते हैं—यहा तो हम सब सम्प्रदाय जात पात छोडकर मात्र भारतीय ही हैं।' हिदायत रसूल का सशोधन गिर गया। मुसलमानो ने भी इसके विरुद्ध रोड दिया।

स्त्रियों को वोट का प्रस्ताव—शासन सुधार के प्रस्ताव के सिलसिले में कादम्बिनी गांगुली के प्रति द्वारकानाथ गांगुली ने यह सशोधन पेश किया कि स्त्रियां को भी वोट का अधिकार मिले। गांगुली महाशय स्त्रियों के अधिकारों के सम्बन्ध में आगे सन करन के सिलसिले में कष्ट उठा चुके थे। वह 'सलनासुहृद' नामक एक स्त्रियों के अधिकार सम्बन्धी पत्र के सम्पादक भी थे। मिस्टर गांगुली का सशोधन पारित नहीं हुआ, बरिफ उन्हे इसे वापस लेना पडा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि अभी तक इंग्लैंड में भी स्त्रियों को यह अधिकार नहीं मिला था, यद्यपि वहा स्त्रियों की हालत भारतीय स्त्रियों से बड़ी अच्छी थी।

इसी अधिवेशन में यह तय हुआ कि कांग्रेसी नेताओं का एक प्रतिनिधि-मण्डल विलायत भेजा जाय। इस प्रतिनिधि मण्डल में ह्यूम, नार्टन, यूल्, सुरेन्द्र बनर्जी, आर० एन० मुघलकर, फिरोजशाह आदि थे। ये 1890 में विलायत गए और पहले इन्होंने वादाभाई नौरोजी के निर्वाचन क्षेत्र फिसबरी से काम शुरू किया, फिर मण्डल ने विलायत में कई जगह व्याख्यान दिए। चार-पाच महीना घूमकर यह मण्डल विलायत से पुर्तगाल, 1890 के लगभग लौट आया।

पाचवें अधिवेशन के बाद मिस्टर ब्रैडला को एक मानपत्र दिया गया। बहुत से मानपत्र तयार थे, पर यह तय हुआ कि कांग्रेस का मानपत्र ही पढा जाय और बाकी पठित मान लिया जाय।

उ होने कांग्रेस की प्रशंसा की और लोगो से कहा कि "लोग ब्रिटिश संसद के पाठ हजारो लाखो और, हो सके तो करोडो के दस्तखत से अर्जो भेजें।" इस प्रकार मिस्टर ब्रैडला कांग्रेस नेताओं को वे ही भाग बता गए जिनका वह स्वयं अनुसरण कर रहा था। उसमें कोई नई बात नहीं थी। मिस्टर ब्रैडला ने लौटकर संसद में भारत सम्बन्धी एक बिल पेश किया, पर इस बिल के पेश होने से पहले ही 30 जनवरी, 1891 को उनका देहांत हो गया।

इस कांग्रेस में अधिक प्रतिनिधि आए थे, इस कारण प्रतिनिधियों की संख्या नियंत्रित करने के लिए यह तय हुआ कि प्रति दस साल आबादी पर एक प्रतिनिधि आ सकेगा। इस नियम के कारण अगली कांग्रेस में प्रतिनिधियों की संख्या घट गई। कांग्रेस का कोई जमाना था, जब उसमें कुछ लोगो का किसी तरह का जाना ही अच्छा समझा जाता था, पर अब कांग्रेस की ताकत और इज्जत बढ़ चुकी थी। स्वाभाविक रूप से अब प्रतिनिधियों की संख्या के नियमन की जरूरत पड़ी। मिस्टर ह्यूम प्रधान मंत्री रहे और इलाहाबाद के पंडित अयोध्या नाथ उनका सहकारी चुने गए। इनको सलाह देने के लिए बंगाल के उमेश बनर्जी, मद्रास के आनंद चालू और बम्बई के फिरोजशाह मेहता को लेकर एक स्टडींग कौंसिल बनी। इस हम एक तरह से काय समिति का प्रारम्भ कर सकते हैं।

### कांग्रेस का छठा अधिवेशन

1890 में कलकत्ते में श्री फिरोजशाह मेहता की अध्यक्षता में छठा अधिवेशन

सपन हुआ। स्वागत समिति की अध्यक्षता के लिए सर रमेशचन्द्र मित्र को लोगो ने घेरा, अभी अभी वह कलकत्ता हाईकोर्ट की जजी से पेंशन लेकर अलग हुए थे, पर उन्होंने बीमारी के आधार पर यह पद अस्वीकार कर दिया। तब कलकत्ता के प्रसिद्ध बैरिस्टर रत्नमोहन घोष स्वागत समिति के सभापति हुए। इस अधिवेशन के लिए नए नियमों के अनुसार एक हजार प्रतिनिधि चुने गए थे, पर इसमें से केवल 700 अधिवेशन में शरीक हो सके।

सरकारी कर्मचारियों को कांग्रेस में शरीक होने की मनाजिस्त - इस अधिवेशन पर भी सरकार का कोप स्पष्ट था। अधिवेशन के कुछ दिन पहले ही गोरो के अखबारों में खबर निकली, फिर सरकार ने यह विज्ञप्ति निकाली कि कोई भी सरकारी कर्मचारी दशक की हैसियत से भी कांग्रेस के अधिवेशन में शरीक न हो। इससे तहलका मच गया।

कांग्रेस के अधिकारियों ने बंगाल के गवर्नर सर चार्ल्स ईलियट तथा उनके कौंसिलरों के लिए सात काड भेजे थे। ये काड यह कहकर लौटा दिए गए कि गवर्नर महोदय अथवा उनके घर के लोग, इन काडों का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि भारत सरकार ने ऐसी सभाओं में सरकारी नौकरों के जाने की मनाजिस्त कर दी है।

इस पर कांग्रेस के नेताओं में बड़ा जोश फैला, क्योंकि उस युग के कांग्रेसी नेता अपने को यदि देशभक्त समझते थे तो साथ ही साथ राजभक्त भी किसी से पीछे समझते जाने के पक्षपाती नहीं थे। जाज यूल ने इस पर भाषण देते हुए कहा—“क्या हम अच्छे हैं? क्या हम किसी तरह किसी से कम राजभक्त हैं? इसलिए जब ऐसी हिदायतें दी जाती हैं कि कोई सरकारी कर्मचारी हमसे न मिले, तो हम इसे अपना अपमान समझते हैं और इसके उत्तर में हमारा यह कहना है कि इसानियत के गुणों की दृष्टि से हम उनसे किसी प्रकार घटकर नहीं हैं।”

यही उस युग के नेताओं की भावना थी।

इसके उत्तर में बड़े लाट की तरफ से कहा गया कि बंगाल के गवर्नर गंभीर चिटठी का सही मतलब नहीं समझ सके। यह बताया गया कि कांग्रेस आंदोलन बिल्कुल वैध है। भारत सरकार यह मानती है कि कांग्रेस आंदोलन का भारत में वही स्थान है जो यूरोप में अग्रगामी उदारपणियों का है। अवश्य साथ ही दश में बन्तवैटियों का बहुमत है।

लाड डफरिन यहां से विदा होते समय कांग्रेस को लात जमा गए थे, उसका उत्तर देते हुए इस अधिवेशन के सभापति श्री फिरोजशाह मेहता ने कहा—“हम पर यह जो अभियोग लगाया गया था कि हम खुदशोन में देखे जाने योग्य अल्पसंख्यक हैं हम उस अभियोग के नाद भी जी रहें हैं। दूसरा अभियोग लगाया गया है कि हम राग मंत्र छद्म वेशधारी नौकरी चाहने वाले बाधू हैं, हम उससे भी नहीं मरे। हम पर जो बोझारे की गई, गालियां दी गई हमें मूलतः दृष्टि में देखा गया, हम उसके बावजूद जीवित हैं। हम पर राजद्रोही होने का जो अभियोग लगाया गया, हम उसमें भी बर्गी हो चुके हैं।”

इस प्रकार सभापति के भाषण में हम उसी दुरंगी नीति को मूल पाते हैं जो उस युग की एक हद तक अनिवार्यता था।

अल्पसंख्यक सम्प्रदाय और चुनाव - इस कांग्रेस में भी शासन मुद्धार पर प्रस्ताव जाया। पटना में मैगद सफन्दीन ने लाड क्रम तथा लाड मानसबरी के मतव्यों का उत्तर देते हुए कहा कि यह जो कह गया है कि मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और उनको शासन मुद्धार से हानि होगी, इसका कोई अर्थ नहीं है। हम दूर क्या जाए, वस्तुस्थिति को

ही लें। हमारे यहाँ नगरपालिका में 20 सीटें हैं, पर हिंदुओं की बहुसंख्या के होते हुए 13 मुस्लिम सदस्य हैं। बम्बई में हिंदुओं की बहुत अधिक संख्या है, फिर भी पाँच पारसी, तीन गारो, दो हिंदू और दो मुसलमान इसका सदस्य हैं। हमारे देश में अभी तक बहुसंख्या से कोई असुविधा नहीं हुई है इसलिए यह प्रश्न उठाना ही नहीं चाहिए।”

विलायत में कांग्रेस के अधिवेशन का प्रस्ताव—इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव यह भी आया कि 1892 की कांग्रेस विलायत में हो। ब्रिटिश संसद के सदस्य मिस्टर ने इस सम्बन्ध में लोगों से कहा कि हम विलायत के लोगों की तरफ से यह आश्वासन देते हैं कि जब आप विलायत आएं, तो हम आपका ऐसा स्वागत करेंगे कि आप तबीयत ख़ुश हो जाएंगे। पर यह प्रस्ताव माना नहीं गया। स्पष्ट ही सब लोगों के विलायत जाना संभव नहीं था। पर प्रस्ताव का आशय स्पष्ट था।

कुछ अन्य प्रस्ताव—इस कांग्रेस के अन्य प्रस्तावों में नमक कर के विरुद्ध बंगाल के अनिश्चित अन्य स्थानों में इस्तेमाली बंदोबस्त खालू करने के सम्बन्ध में भी प्रस्ताव पास हुए। कांग्रेस ने मादक द्रव्यों पर नियंत्रण के सम्बन्ध पर भी एक प्रस्ताव पास किया।

## कांग्रेस का सातवां अधिवेशन

कांग्रेस का सातवां अधिवेशन नागपुर में मद्रास के आनंद चालू के सभापतित्व में हुआ। छठे अधिवेशन के बाद कहा जाता है कि मिस्टर ह्यूम इंगलड गे थे और उन्होंने इस बात की जी-तोड़ कोशिश की थी कि कांग्रेस का अगला अधिवेशन लंदन में हो। कुछ लोग इस प्रस्ताव को अव्यवहारिक समझते थे पर मिस्टर ह्यूम इस बात पर अग्रसर हुए थे कि उन्होंने लिख भेजा था कि ‘यदि मेरा प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ तो मेरा त्याग पत्र ले लिया जाए।’ जो हो, यह प्रस्ताव कार्यरूप में परिणत नहीं हुआ और नागपुर में कांग्रेस होना तय हुआ। मिस्टर नारायण स्वामी स्वागत समिति के सभापति हुए।

यद्यपि मिस्टर ह्यूम ने कांग्रेस से अलग हो जाने की धमकी दी थी पर वह इन अधिवेशन में आए और उन्होंने कांग्रेस के सून की अपने हाथों में ले लिया। यह समझ में नहीं आता कि वह लंदन में कांग्रेस का अधिवेशन करने के इतने पक्षपाती क्या थे। शायद वह अपने ढंग से यह समझते थे कि लंदन में अधिवेशन होने पर ब्रिटिश सरकार पर अधिक असर पड़ेगा। भारत में आते ही मिस्टर ह्यूम ने कांग्रेस के नेताओं को एक गश्ती चिट्ठी इस आशय की लिखी कि सातवीं कांग्रेस में किसी नए प्रस्ताव की जरूरत नहीं है बल्कि पुराने प्रस्तावों पर नए तरीके से ठप्पा लगाकर काम को आगे बढ़ाया जाए। ऐसी गश्ती चिट्ठी भेजने में उनका आशय कदाचित्त यह था कि ब्रिटिश संसद पर असर डाला जाए कि वे ही प्रस्ताव बराबर आते हैं इसलिए मांग मान ली जाए।

सैनिक व्यय पर प्रस्ताव—इस कांग्रेस में लोकमान्य तिलक ने बड़े हुए सैनिक व्यय के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव रखा, जिसमें उन्होंने यह कहा कि भविष्य में समग्र आश्रितों के नाम पर सैनिक व्यय बढ़ाते जाने का कोई अर्थ नहीं। इसके स्थान पर भारतीय तथा पक्षपात से काम लिया जाता है, उसे दूर किया जाए, युद्ध विद्या सीखने के लिए लोकमान्य का समर्थन करते हुए यह बताया कि भारत सब से गरीब देश है, पर यही का सैनिक व्यय सबसे अधिक है। कांग्रेस नेताओं का इस विषय में शक्ति होना स्वाभाविक था। 1864 से 1885 तक सैनिक व्यय में 5 करोड़ रुपए बढ़े थे, पर 1885 से 1891

तक 54 करोड़ रुपए व्यय बढ़ा। भारत सरकार यह सब हस के ढर से कर रही थी। लोगो को शका थी कि भारत रक्षा के नाम पर सरकार भावी युद्ध की तैयारी कर रही है और वह भी भारतीयों के नाम पर।

**कांग्रेस के अग्र प्रस्ताव**—इस बार के अधिवेशन में जगल कर के विरुद्ध एक प्रस्ताव पास हुआ। पहले वे जमानो में जगलात बहुत कुछ ग्राम संप्रति समझी जाती थी। फिर जगल कर का प्रत्यक्ष फल यह हुआ था कि अनेके मद्रास में ही एक साल के अंदर 3 लाख गायें मर गईं। इस प्रकार कांग्रेस ने यह एक प्रस्ताव ऐसा रखा जिसके सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि वह शहरी मध्यवर्ति वर्ग से सम्बन्धित नहीं था। इसी अधिवेशन में एक प्रस्ताव सरकार की इस चेष्टा के विरुद्ध भी पास हुआ कि सरकार जन शिक्षा के बढ़ाने उच्च शिक्षा को सीमित कर रही है। हम पहले ही दिखा चुके हैं कि तरह तरह का दावा करने पर भी कम्पनी से लेकर ब्रिटिश सरकार तक के कर्मचारी सभी भारतीयों की उच्च शिक्षा के विरोधी थे। सरकार से यह भी अनुरोध किया गया कि शिल्प कला की शिक्षा तथा आम शिक्षा की तरक्की के लिए एक कमीशन बैठाए कि कैसे भारत की उन्नति हो सकती है।

## कांग्रेस का आठवा अधिवेशन

1892 में कांग्रेस का आठवा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। लोग चाहते तो यह थे कि अब की बार दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के सभापतित्व के पद को सुशोभित करें, पर वह पालियामेंट के चुनाव के झगड़े से फुरसत न पा सके, इस कारण उमेशचन्द्र बौनर्जी सभापति बनाए गए। दादाभाई नौरोजी इस बीच ब्रिटिश संसद के सदस्य चुन लिए गए थे, उनको अपने प्रतिद्वंद्वी से तीन वोट ज्यादा मिले थे। उनके प्रतिद्वंद्वी ने अर्जी दी थी कि मनदान पत्रों की फिर से परीक्षा हो। इसी कारण दादाभाई को विलायत में रुकना पड़ा। कुछ भी हो, दादाभाई के चुने जाने पर कांग्रेस के नेताओं में उड़ी खुशी थी और सभापति ने इसको अपने अभिभाषण में व्यक्त किया। इसमें सदेह नहीं कि उन दिनों की दृष्टि में वह एक बहुत ही भारी सम्मान था, साथ ही यह घटना भारतीयों का मनोबल बढ़ानेवाली थी।

**1892 का इंडियन कौंसिल ऐक्ट**—इस बीच 1892 का इंडियन कौंसिल ऐक्ट पारित हो चुका था। इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, फिर भी पुराने कानून से यह कुछ अच्छा था। ब्रडला ने ब्रिटिश संसद के सामने जो कानून रखा था, प्रस्तावक की मंथु के साथ साथ वह खत्म हो चुका था। पर चतुर ब्रिटिश राजनीतिज्ञ यह समझते थे कि भारतीय जनमत को सन्तुष्ट करने के लिए कुछ न कुछ दिखावा करना चाहिए। तदनुसार लाड ब्रास ने एक प्रस्ताव हाउस आफ लाड में रखा था। इस प्रस्ताव में भारतीय सेजिस्ट्रेटिव कौंसिल के सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई। चुनाव का सिद्धांत लागू नहीं हुआ, पर यह कहा गया कि नामजदगी करते समय नगरपालिकाओं और जिला बोर्डों की राय ली जाएगी। इस कानून में प्रत्येक प्रांत की भारतीय कौंसिल में एक गैर सरकारी भारतीय लेने की व्यवस्था थी। प्रांतीय कौंसिलों के भी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। पहले बम्बई और मद्रास में 8 ही सदस्य होते थे, अब इसमें 20 उत्तर पश्चिमी प्रांत में 15 तथा पंजाब में 9 सदस्य कर दिए गए। नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों, चेम्बर आफ कामर्स तथा विश्वविद्यालयों के भी कुछ अधिकार बढ़ा दिए गए। लेजिस्ट्रेटिव कौंसिल में अधिकार भी कुछ बढ़ाए गए, और सदस्यों को यह अधिकार मिला कि वह प्रश्न पूछ सकते हैं। लोकतंत्र की दृष्टि में देखने पर यह विधेयक बिल्कुल निकम्मा



था, क्योंकि न तो इसमें जनता या जनता के किसी हिस्से द्वारा चुनाव ही था, और जो कौंसिलें इस प्रकार बनने वाली थी, उनमें सरकारी सदस्य की ही बहुसंख्या रहनी थी। नार्ड काम का यही विधेयक पारित हुआ।

हाउस आफ कामन्स में भारतीय उपसचिव मिस्टर कजन (बाद को सार्ड कजन) ने यह बिल पेश किया। ब्रैडला द्वारा प्रस्तावित विधेयक के साथ तुलना करने से स्पष्ट होता है कि यह विधेयक कितना प्रतिश्रियावादी था। ब्रैडला का विधेयक भी लोकतांत्रिक दृष्टि से बहुत त्रुटिपूर्ण था, फिर भी उमम यह प्रस्ताव था कि जो कौंसिल बने, चाहे केन्द्रीय या प्रांतीय, उसके आधे सदस्य भारतीयों के द्वारा चुन हुए हों, एक चौथाई सरकार द्वारा नामजद हों, और एक चौथाई सरकारी सदस्य हों।

ऐक्ट पर कांग्रेस का प्रस्ताव — कांग्रेस ने इस विधेयक के सम्बन्ध में प्रस्ताव कर्त्त हुए कहा कि यद्यपि कांग्रेस राजमन्त्रि के साथ इस ऐक्ट को ग्रहण करती है, फिर भी प्रधान मंत्री तथा अन्य लोगों की तरफ से यह जो कहा गया है कि इसका उद्देश्य धारा सभाओं में भारतीयों का वास्तविक प्रतिनिधित्व देना है, सो यह कानून ऐसी कोई बात नहीं करता। फिर भी कांग्रेस यह उम्मीद रखती है कि ऐक्ट के जो नियम बगरह बनाए जा रहे हैं, वे मिस्टर ग्लडस्टोन की घोषणा के अनुसार होंगे और उनसे जनता के प्रति धन्य करने की चेष्टा की जाएगी।

कौंसिल के मेम्बरों को प्रश्न पूछने का जो अधिकार दिया गया था, वह निरपेक्ष इसलिए था कि प्रश्न का जो उत्तर दिया जाता था, वह अंतिम समझा जाता था। न तो उस उत्तर पर कोई बहस हो सकती थी, और न उसकी जांच हो सकती थी। सदस्यों को बजट की आलोचना करने का अधिकार तो मिला था, पर उस पर वोट देने का अधिकार उन्हें नहीं था। इन सब बातों को देखकर विधान बनाने के सम्बन्ध में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की शरारत भरी प्रतिभा की प्रशंसा करनी पड़ती है, पर यह स्मरण रहे कि यह प्रतिभा सगीन के जोरा पर ही काम कर सकी, नहीं तो उस समय के कांग्रेस के नेता, इनसे पीछे नहीं थे। यह बुद्धि की लड़ाई नहीं, बल्कि बुद्धि बनाम सगीन की लड़ाई थी।

## कांग्रेस का नवा अधिवेशन

कांग्रेस का नवा अधिवेशन लाहौर में दादाभाई नौरोजी की सभापतित्व में 1895 में हुआ। सरदार दयालसिंह मजीठिया स्वागत समिति के प्रधान थे। इस बार प्रतिनिधियों की संख्या 866 थी, जिनमें से पंजाब से ही 481 प्रतिनिधि आए थे। दादाभाई नौरोजी के ब्रिटिश संसद में चुने जाने से छात्र समाज उन पर ऐसा खूश था कि घोड़ा हटाकर छात्रों ने ही सभापति की गाड़ी खींची। उनके संसद में चुने जाने से सदस्यों में भारतीयों के सम्बन्ध में एक अच्छा खासा आंदोलन खड़ा हो गया था। दादाभाई नौरोजी लाहौर आने के पहले ही इंडियन संसदीय कमेटी के नाम से एक कमेटी बना चुके थे। इस कमेटी में 154 ब्रिटिश संसद सदस्य शामिल थे। इस कमेटी के आंदोलन के फलस्वरूप बाद को चलकर भारत सचिव के विरोध के बावजूद यह प्रस्ताव पास हो गया कि भारतवर्ष में भी विलायत के साथ साथ सिविल सर्विस की परीक्षा हुआ करे। इसी कमेटी के प्रभाव के कारण इंडिया कौंसिल ऐक्ट का कार्यान्वयन करने के लिए जो नियम तथा उपनियम बने, वे एक हद तक उदार थे, और विश्वविद्यालय, नगरपालिका, चेम्बर आफ कामस जिला बोर्ड कारपोरेशन, जमींदार सभा को यह हक मिल गया कि वे सदस्यता के लिए नाम भेजें। अवश्य सम्बन्धित साट साहब को यह अधिकार रहा कि वे

बाह तो इन सिफारिशों को ठुकराकर अपनी राय के किसी व्यक्ति को कौंसिल में ले लें, पर अक्सर वे ऐसा नहीं करते थे। इस प्रकार परोक्ष रूप से चुनाव का कुछ मामूली धीगणेश हुआ। कलकत्ता कारपोरेशन ने इसी प्रकार सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को कौंसिल में भेजा था।

**दादाभाई का गौरव**—इस कारण दादाभाई नौरोजी का सम्मानित होना बहुत ही स्वाभाविक था। उस समय के अंग्रेजी पढ़े लिखे नेताओं की दृष्टि में ब्रिटिश संसद ही सब अधिकारों को देने वाला कल्पतरु था। जब दादाभाई इसी संसद में पहुँच गए, तो फिर क्या कहना था। उन्होंने इसी का फायदा उठाकर यह संसदीय कमेटी बनाई थी।

**अधिवेशन के अर्थ प्रस्ताव**—इस कांग्रेस में भी शासन सुधार, सार्वजनिक सविस आदि पर प्रस्ताव हुए। लाला साजपतराय ने सरकार की शिक्षा नीति की तीव्र आलोचना करते हुए कहा कि “हमने सरकार को धन-जन तथा सब तरीके से मिल, अबीसिनिया, तथा अफगानिस्तान में मदद दी, इसका हमें यह बदला मिल रहा है कि हमारी शिक्षा घटान की तैयारी है।” इंडियन मेडिकल सविस में भारतीयों को लिए जान के सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव पास हुआ। किसानों के निर्वाचकों को दादाभाई को चुनने के लिए प्रेरणा दिया गया। कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी तथा ‘इंडिया’ नामक पत्र के लिए 60 हजार रुपये की रकम मजूर हुई।

## कांग्रेस का दसवा अधिवेशन

कांग्रेस का दसवा अधिवेशन 1894 में ब्रिटिश संसद के आयरिश सदस्य अल्फ्रेड वेब के सभापतित्व में हुआ। आयरलैंड भी ब्रिटिश बेडियों से छुटकारा चाह रहा था। इस नाते आयरिश भारतीय दोस्ती स्वाभाविक थी। उस युग में लोग एक गीत गाते थे जिसकी एक कड़ी यह थी ‘मिल्ले आयरलैंड दबकर फिर उभरना सीख लो।’ सभापति ने अपने अभिभाषण में यह दिखलाया कि भारत सरकार की धामदनी की एक-बीयाई भारत के बाहर खर्च होती है, फिर भारतवर्ष गरीब क्यों न हो। इस साल भी मामूली तरीके से वे ही प्रस्ताव पास हुए। फिर ब्रिटिश कमेटी के लिए 60 हजार रुपये मजूर हुआ।

**वस्त्रों पर प्रहार**—इस साल कई ऐसी बातें हुईं जिनसे अब यह स्पष्ट होने लगा कि कांग्रेस के पुरानी तरीके के आंदोलन से अब आगे बढ़ना बहुत कठिन है। इस बीच भारतवर्ष में कुछ मिलें खुली थीं। 1860 तक भारतवर्ष में बाहर से यंत्र मगाने पर इम माने में रोक थी कि इस पर भारी टैक्स लगाया जाता था। 1860 में यह टैक्स हटा दिया गया और इस प्रकार भारत के औद्योगिकरण का प्रारम्भ हो गया था।

सबसे पहले तो सन की मिलें खुली, फिर कुछ कपड़े की मिलें भी खुल गईं। इस प्रकार भारतवर्ष में मिलों की इतनी तरक्की होने लगी कि बिलायत के मिल मालिक पचड़ाए। तदनुसार इस साल भारत सरकार की सिफारिश को भी ठुकरा कर ब्रिटिश सरकार ने यहाँ के वस्त्रों पर कर लगाया। इस प्रकार भारतवर्ष को लकाशायर की बलि-वेदी पर चढ़ा दिया गया। कहना न होगा कि इस नियम से उदीयमान भारतीय वस्त्र-सिन्धु को बहुत धक्का पहुँचा, पर ब्रिटिश सरकार को इसकी क्या परवा थी। मजे की बात है कि सरकार की यह भेदभरी नीति 1939-45 के द्वितीय महायुद्ध के दौरान भी कायम रही और सरकार ने युद्ध से सम्बन्ध कई बहुत जरूरी उद्योग धंधों को भी भारत-वर्ष में पनपने की अनुमति नहीं दी।

भारत में परीक्षा से इनकार—ब्रिटिश सरकार ने जो दूसरा अय्याय किया, वह

सिविल सर्विस के सम्बन्ध में था। ब्रिटिश संसद के अधिकांश सदस्यों की यह राय हो चुकी थी कि सिविल सर्विस की परीक्षा भारत तथा इंग्लैंड दोनों जगहों पर हो, पर भारत सचिव ने 19 अप्रैल को भारत सरकार को सूचित किया कि यह प्रस्ताव कार्यान्वित नहीं किया जाएगा। इस सम्बन्ध में यह ध्यान देने योग्य है कि ब्रिटिश सरकार ने इसके पहले भारत सरकार तथा प्रांतीय सरकारों की राय मांगी थी। मद्रास सरकार के अतिरिक्त सभी सरकारों ने इसके विरुद्ध राय दी थी। इस प्रकार जो गान मध्यमवर्ग की प्रधान मांगों में से थी, वह ठुकरा दी गई, और यह भा ब्रिटिश संसद में प्रचार कायम बायजूद।

**मए नेतृत्व की आवश्यकता**—इस पर होना तो यह चाहिए था कि कांग्रेस के नेताओं को अपने आंदोलन के तरीकों पर से विश्वास उठ जाता और वे किसी रईस दिशा में सोचते। स्पष्ट बात यह थी कि एक विषय के सम्बन्ध में आंदोलन परत-करते बसे ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश जनता तक पहुंचा दिया गया, और वहां के बहुत से संसद सदस्यों की अनुकूल राय भी प्राप्त कर ली गई, फिर भी यह नायरूप में न आ सकी और उनकी राय कुंडलान में डाल दी गई। इस पर स्वाभाविक तरीके से नेताओं को आगे सोचना चाहिए था। पर वे आगे सोचने में असमर्थ थे।

**गणपति और शिवाजी उत्सव**—इही दिनों अर्थात् 1894 के करीब लोकमान्य तिलक तथा महाराष्ट्र के नौजवान किसी और ही तरीके से सोच रहे थे। 1891 के करीब लोकमान्य तिलक ने गणपति उत्सव तथा बाद को 1897 में शिवाजी उत्सव का प्रवर्तन किया। इस उत्सव के प्रवर्तक धार्मिक आड़ लेकर जातिबारी विचारों का प्रचार करना चाहते थे। यह साफ था कि इस उत्सव के प्रवर्तक तथा नेता केवल अर्जों में जने प्रा प्रस्तावों में विश्वास नहीं करते थे। दुर्भाग्य से इन उत्सवों को एक धार्मिक और शिवाजी उत्सव के विषय में तो यह कहा जा सकता है कि उसे एक मुसलमान विरोधी रूप प्राप्त हुआ, पर मैं समझता हूँ कि यह रूप बहुत कुछ अनिच्छावृत था। सच तो यह है कि इसके अलावा कोई चारा नहीं था। ये नेता प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ कह नहीं सकते थे, इसलिए वे भूतपूर्व मुसलमान शासकों के विरुद्ध ढाल-ढालकर अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का प्रचार करते थे। हिंदुओं के विरुद्ध मुसलमानों को भड़काने का अंग्रेजों का एक अच्छा मौका मिल गया। लोकमान्य तिलक ने पहले गणपति उत्सव और बाद में शिवाजी उत्सव का प्रवर्तन किया, यह भी अपवृण है। प्रथम उत्सव में धार्मिक आवरण बहुत अधिक था पर शिवाजी उत्सव में यह आवरण कम हो गया, यह शुद्ध राजनीतिक था।

**चाफेकर की हिंदू धर्म संरक्षणी सभा**—इसी समय लगभग श्री दामोदर चाफेकर तथा उनके भाई श्री बालकृष्ण चाफेकर ने 'हिंदू धर्म संरक्षणी सभा' नाम से एक सभा की स्थापना की।

### कांग्रेस का ग्यारहवा अधिवेशन

कांग्रेस का ग्यारहवा अधिवेशन 1895 में पूना में श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। यह एक मजे की बात है कि कांग्रेस के जन्म के पहले भारतीय राज नीतिक गगन पर सुरेन्द्रनाथ ही चमक रहे थे, पर कांग्रेस में शामिल होने के बाद दस साल बीतने पर उन्हें उस सस्था के सभापति होने का मौका मिला। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है बल्कि इसके पीछे कई कारण थे। एक कारण तो यह था कि कांग्रेस के संस्थापक तथा नेता कांग्रेस को एक राजभक्त सस्था के रूप में देखना चाहत थे। अधिक से अधिक गोरो को इस बीच में सभापति बनाने का भी ग्रही उद्देश्य था, पर अब

एक तो उमाना बदल चुका था, और सुरेन्द्रनाथ भी बदल चुके थे। लाकमाय तिलक के नेतृत्व में जिस नौजवान नृत्य का उत्थ हो रहा था, उसके सामने श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की गरमजोशी बहुत कुछ म्लान हो चुकी थी। इस कारण कांग्रेस के जन्म के समय सुरेन्द्रनाथ तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं में जा पायस्य की रेखा थी, वह बहुत कुछ मिट गई थी। इसी कारण सुरेन्द्रनाथ अब सभापति हुए। सुरेन्द्रनाथ ने सभापति की हैमियत से ढाई घण्टे तक भाषण दिया, और इस प्रकार अपनी व्याख्यान शक्ति के यश को नायम रखा।

तत्काल और गोखले इस अधिवेशन के समय उनके पण्डाल में समाज सुधार सम्मेलन में सम्मेलन में लाकमाय तिलक तथा गोपालकृष्ण गोखले भी भाग ले रहे थे। गोखले यह चाहते थे कि समाज सुधार सम्मेलन यही पत्र हो पर निम्न उसके विरुद्ध थे। यह एक ध्यान देने योग्य बात है कि तिलक राजनीति में उग्रवादी थे, पर सामाजिक मामलों में उनका विचार अपरिवर्तनवादी था। उनका इतिहास पर देश भर में प्रवाद चल रहा था कि स्त्रियों की सम्मति की उम्र (age of consent) दस से बढ़ाकर बारह कर दी जाए या नहीं। रानडे तथा बहुत से पुराने नेता बारह साल के पक्ष में थे पर तिलक इसके विरोधी थे और बारह साल के विरुद्ध जो आन्दोलन हुआ, उसका उन्होंने नेतृत्व किया। इस प्रकार हम यहाँ एक बहुत ही अजीब दृश्य देखते हैं कि जो लोग सामाजिक दृष्टि से प्रगतिशील विचार रखते थे, वे राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े हुए तथा दम्बू थे, और जो लोग सामाजिक दृष्टि में अपरिवर्तनवादी थे, वे राजनीतिक दृष्टि में उग्रवादी प्रणाली के पक्षपाती थे। इसका अवश्यमान नतीजा यह हुआ कि दोनों में से एक भी नेतृत्व प्रयोज्य नहीं बन सका। इस दृष्टि से देखने पर कहना होगा कि गांधी जी अपने राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यों में समान रूप से प्रगतिशील विचार लेकर बाद को आए, तथा इसीलिए उनकी विचारधारा का जो सामाजिक तथा नैतिक अनिवार्य रूप से प्राप्त हुई, वह इन नेताओं के विचारों को प्राप्त नहीं हो सका।

बदले हुए सुरेन्द्रनाथ—सभापति के पद से सुरेन्द्रनाथ ने जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने सामान्य समस्याओं पर रोशनी डालते हुए अनुरोध किया कि मैं ब्रिटिश सविच्छा में विश्वास रखता हूँ। इस प्रकार उन्होंने सरकार तथा कांग्रेस नेताओं के निकट यह स्पष्ट कर दिया कि मैं अब क्रान्तिकारी नहीं हूँ।

अधिवेशन के अग्र्य प्रस्ताव—इस कांग्रेस में भी वे ही मामूली प्रस्ताव लाए गए। इन दिनों भारतीय राजस्व का जिस तरह व्यय होता था, इस सम्बन्ध में जांच के लिए एक ब्रिटिश ससैन्य कमेटी बठ चुकी थी। इस कमेटी को सुभाव देते हुए एक प्रस्ताव पारित हुआ। दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों पर ज्यादाती के सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव पारित हुआ। सरकार द्वारा शिक्षा को सीमित करने की नीति पर एक प्रस्ताव पारित हुआ। सिविल सर्विस के सम्बन्ध में प्रस्ताव हुए। रेल के तीसरे दर्जे के मुगाफिकों के दुख-दर्दों के सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव हुआ। अब की बार भी विनायक ने काम करने के लिए 60 हजार की रकम मंजूर हुई। इस कांग्रेस में पंडित मदन मोहन मालवीय के भाषण की बहुत तारीफ की गई।

## कांग्रेस का बारहवा अधिवेशन

कांग्रेस का बारहवा अधिवेशन 1896 में कलकत्ते में मिस्टर रहमनुल्ला सियानी की अध्यक्षता में हुआ। आप बम्बई के अच्छे वकील तथा पुराने कांग्रेसी थे। सभापति ने अपने अभिभाषण में यह प्रमाणित किया कि यह जो कहा जाता है कि मुसलमान कांग्रेस में शामिल नहीं हो, यह बिल्कुल बेवुनियाद है। उन्होंने इस बात की अपील की कि मन में

कोई शक न रखकर मुसलमान कांग्रेस में शरीक हो।

कबीर द्वारा 'वन्दे मातरम्' गान—इस कांग्रेस में कबीर रवीन्द्र ने बड़ा धारण करके 'वन्दे मातरम्' गीत गाया। उनके भाई श्री ज्योतिरिन्द्रनाथ आगरवाला रहे थे, और वह अपनी मस्त आवाज में गा रहे थे। यह पहला अवसर था, जब कांग्रेस के अंदर वन्दे मातरम् गाना गाया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि कबीर सगमरमर के मीनारवासी नहीं थे। बाद की उन्होंने जलियावाला हत्याकांड विरोध में 'सर की उपाधि त्याग दी।

शिक्षा विभाग में भी भेद नीति—अब तक कांग्रेस में सिविल सविस का ही रोना रहता था, और पिछले अधिवेशन में आई० एम० एस० में भारतीयों के लिए जाने का प्रस्ताव किया गया था। पर अब की बार एक नया प्रश्न यह आया कि शिक्षा विभाग में भारतीयों और अंग्रेजों में भ्रष्टाचार व्यवहार किया जाता है। इस प्रस्ताव पर बाले हुए आनंदमोहन बसु ने यह दिसनाया कि 1880 में पहले जहां तक बंगाल का विभाग का प्रश्न है किसी प्रकार की रगभद नीति नहीं थी। पर 1880 में भद्रमूलक नीति का सूत्रपात हुआ और भारतीयों का प्रारम्भिक वेतन पांच गी स घटाकर 330 कर दिया गया, और 1889 में इस और घटाकर 200 कर दिया गया जब कि गोरो का 500 ही रहा। उन्होंने कहा कि भेदमूलक नीति यही पर नहीं रखी। अभी 1896 में जो व्यवस्था हुई है, उसका अनुसार इस विभाग की नौकरियों को अखिल भारतीय और प्रांतीय इन दो भागों में विभक्त किया गया है और तब हुआ है कि अखिल भारतीय और नौकरियों में सिर्फ गोरो ही रहेंगे। वक्ता न बड़े अफसोस के साथ कहा कि विलायत के विषयविद्यालय में शिक्षित होने पर भी भारतीय प्रांतीय सविस में ही लिए जाएंगे और कुछ बालेजा के तो वे प्रिंसिपल भी न हो सकेंगे।

भारत में दुर्भिक्ष पर प्रस्ताव—इन दिनों भारत भर में दुर्भिक्ष फैल रहा था। इस सम्बन्ध में सुरद्रनाथ बनर्जी ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें कहा गया कि देश का इन बहुत अधिक मात्रा में बाहर जा रहा है तथा सिविल और सैनिक विभाग में फिजूल-खर्च हो रही है। देश में कोई उद्योग घटा नहीं है, इसी कारण ये दुर्भिक्ष हुआ करते हैं। 1878 में सरकार ने बार बार होने वाले दुर्भिक्षों के कारणों की जांच करने के लिए एक आयोग बठाया था। उसने 1880 में अपनी रिपोर्ट देते हुए कहा था कि "भारतवर्ष की गरीबी तथा फमल की कमी आदि के समय विपत्ति का दुखद कारण यह है कि सारी जनता खेती पर निर्भर है और दुर्भिक्षों को दूर करने में तब तक कोई विचार सफलता नहीं मिलगी जब तक लोगो के जोर धरें न हों।" दूसरे शब्दों में आयोग ने (स्मरण रहे कि यह सरकारी आयोग था) यह कह दिया कि ब्रिटिश सरकार की नीति के ही कारण यहाँ दुर्भिक्ष पड़ते हैं क्योंकि उसी ने लोगों के दूसरे धंधों को नष्ट किया है।

अब प्रस्ताव—सरकारी चिकित्सा विभाग में गोरों और बालों में भेदभाव है, उसका सम्बन्ध में भी प्रस्ताव आया। दक्षिण अफ्रीका पर भी एक प्रस्ताव हुआ। पर मेजर विल्ल ने इस प्रस्ताव को रखा। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की वित्तनी दुदशा थी, यह इसी से 'यकन होता है कि वहाँ भारतीयों को स्वतंत्रता के साथ चलने फिरे की भी इजाजत नहीं थी काम करना और व्यापार करने की तो बात ही और है। रात में वे घर से नहीं निकल सकते थे और न वे जहाँ चाहे रह सकते थे। वे रेल में किराया देकर भी पहले तथा दूसरे दर्जे में सफर नहीं कर सकते थे। उन्हें होटलों या पार्कों में जाने की इजाजत नहीं थी। भारतीयों पर राह चलते गोरे घूक देते थे तथा उन्हें ट्राम से धकेल देते थे। नेटाल में भी भारतीयों का सम्बन्ध में भेदमूलक कानून पास हुआ था।

कांग्रेस में प्रदर्शनी—इस कांग्रेस के साथ एक प्रदर्शनी भी हुई, जिसमें देशी उत्पादन दिखलाए गए। बाद को ऐसी प्रश्ननिया कांग्रेस अधिवेशनों के लिए अनिवार्य हो गई।

## कांग्रेस का तेरहवा अधिवेशन

कांग्रेस का तेरहवा अधिवेशन 1897 में बरार की राजधानी अमरावती में शकरन नगर (प्रसिद्ध विधिवेत्ता, लेखक, बाद को सर) की अध्यक्षता में हुआ। इस कांग्रेस में 600 प्रतिनिधि आए। कांग्रेस के प्रस्तावों का सरकार पर कुछ भी असर न पड़ता हो, ऐसी बात नहीं थी। बरार कांग्रेस की तरफ से यह जो मांग की जा रही थी कि सरकार अपना खर्च घटाए, सो इस बीच ब्रिटिश ससद ने इस सम्बन्ध में जांच करने के लिए लाड वलबी के सभापतित्व में एक आयोग नियुक्त किया था। इस आयोग में दादाभाई नौरोजी भी थे और इसमें चार भारतीयों की गवाही हुई। बम्बई के श्री वाचा, महाराष्ट्र के गोपालकृष्ण गाखले, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी तथा जी० सुब्रह्मण्य अग्यर ये गवाह थे।

मिस्टर रड की हत्या—इस वर्ष कुछ ऐसी घटनाएँ हुई थी, जिनकी किसी भी प्रकार कांग्रेस या दोलन के अंतर्गत नहीं गिना जा सकता, फिर भी राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में उनका स्थान बहुत ऊँचा है। इस साल की 22 जून का महारानी विक्टोरिया का साठवा राज्याभिषेक त्विस हीरक जयंती के रूप में मनाया जाने वाला था। इसके लिए बड़ी धूमधाम की तयारी थी। उधर देश भर में दुर्भिक्ष फैल रहा था। लोग तड़प-तड़पकर मर रहे थे। ऐसे समय में बम्बई में ताऊन फैल गया। सरकार ने ताऊन का मुकाबला करने के लिए ताऊन कमेटी की स्थापना की। मिस्टर डब्ल्यू सी रैड ताऊन आयुक्त के रूप में तैनात हुए। ताऊन के सिलसिले में ताऊन पीडितों का एक शिविर भी खोला गया। जब किसी के सम्बन्ध में मालूम हो जाता था कि उस ताऊन हुआ है, तो उसे राजी से हो या जबदस्ती, पकड़कर ताऊन शिविर में भरती किया जाता था। कुछ लोग इससे बचने के लिए अपना रोग ही नहीं बताते थे। इस कारण तलाशी बगैरह होती थी। मिस्टर रैड ने इस सम्बन्ध में बहुत सख्ती का बर्ताव किया। तलाशी के इस हक का इस्तेमाल राजद्रोही साहित्य दूढ़ने के लिए किया जान लगा, इस पर जनता में आक्रोश फैला और पहले हम जिन चाफेकर बंधुओं का उल्लेख कर चुके हैं, उ होंने मिस्टर रड पर गोली चलाई। इसी सम्बन्ध में लेफ्टिनेंट आयर्स्ट भी मारे गए। बाद को चाफेकर बंधुओं को फाँसी हुई।

आम धर-पकड़—हत्या 22 जून की रात को हुई, लोकमान्य तिलक 21 जुलाई को गिरफ्तार हुए। 'प्रवाध' के संपादक भी पकड़े गए। इसके अतिरिक्त 'वैभव' के संपादक विश्वनाथ केलकर तथा बलवन्तराव नाटू और रामचन्द्रराव नाटू दो भाई पकड़े गए। तिलक पर यह आरोप लगाया गया कि 12 जून के गणपति उत्सव का उन्होंने केमरी में 15 जून को जो दिवरण निकाला था, वह आपत्तिजनक था। इसके अतिरिक्त लोकमान्य पर यह आरोप भी लगाया गया कि उन्होंने शिवाजी उत्सव के मौके पर अफजल खा की हत्या का समर्थन करने के वहाने अंग्रेजों की हत्या का प्रचार किया। अधिकारों वगैरे का यह कहना था कि इही सब बातों के कारण युवकों का सिर फिर गया।

सजाएँ—अच्छे से अच्छे वकील ने लोकमान्य की पैरवी की, पर उन्हें डेढ़ साल की सजा दे दी गई। नाटू बंधुओं को 1899 तक नज़रबंद रखा गया। उनकी सम्पत्ति भी जब्त कर ली गई। इस प्रकार गण्यमान्य लोग पर प्रहार करने के फलस्वरूप सरकार



अपना रास्ता आप चुन लीजिए।”

॥ ५ प्रस्ताव—राजद्रोह सबंधी कानून के विरुद्ध एक प्रस्ताव पास हुआ। इसके प्रस्तावक जे० मुदालियर ने कहा कि “आज सरकार मे लोगो की सदिच्छा तथा विश्वास के बदले लोगो मे सरकार का अविश्वास ही है। अटक से कटव तक सब लोगो का मन सरकार के तरफ मे रुडवा हो गया है।”

इन दिनों सीफ्रेट प्रेस बमेटी नाम से असबारी पर जा सेंसर बैठाया गया था, उसकी भी निंदा की गई। सरकार इन दिनों नगरपालिकाओं के अधिकार घटाने की भी चेंष्टा कर रही थी, उसके विरुद्ध भी प्रस्ताव पारित हुए। इन्हीं दिनों दक्षिण अफ्रीका, नेटाल और ट्रांसवाल मे भारतीयों के प्रति वहाँ के गोरो का दुर्व्यवहार हृद दर्जें तक पहुँच गया था। महात्मा गांधी इसी युग मे इन अत्याचारों के विरुद्ध वहाँ आंदोलन चला रहे थे। सचाई तो यह है कि गांधीजी दक्षिण अफ्रीका मे अपने नए अस्त्रों की धार की परीक्षा कर रहे और पैना और असरदार बना रहे थे। कांग्रेस ने वहाँ के भारतीयों के साथ हमदर्दी का एक प्रस्ताव भी पास किया।

## कांग्रेस का पन्द्रहवा अधिवेशन

कांग्रेस का पन्द्रहवा अधिवेशन 1899 मे लखनऊ मे श्री रमेशचंद्र दत्त के सभापतित्व मे हुआ। अमरावती मे जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस समय बरार का चीफ कमिश्नर एंटोनी मकडोलन नामक एक गोरा था। यही गोरा इस समय सयुक्त प्रांत का गवर्नर था। अमरावती मे कांग्रेस के होने मे इसने कोई आपत्ति नहीं की थी, पर जब लखनऊ मे कांग्रेस होने लगी, तो इसने उसे शहर भे होने नहीं दिया, शहर से आठ मील दूर देहात मे कांग्रेस हुई। बशीलाल सिंह स्वागत समिति के प्रधान थे।

सभापतिका अभिभाषण—मजे की बात यह थी कि सभापति रमेशचंद्र सरकारी बड़े अफसर होने के साथ ही बगसा भाषा मे ऐसे उपयासों के लेखक थे जो देशभक्ति पून थे। उन्होंने दमन नीति की निंदा करते हुए कहा कि यदि राजद्रोह के नाम पर लोगो को बोलने तथा लिखने से रोका गया, तो उसका नतीजा यह होगा कि राजद्रोह और भी जल्दी फलेगा। रमेशचंद्र ने इस बात का पर्दाफाश किया कि आबादी की वृद्धि के कारण दश मे द्वाभिन्न नहीं होते। उन्होंने साफ शब्दों मे कहा कि भारतीयों को केवल खेती पर निर्भर करना पड़ता है, अत्यधिक टैक्स देने पड़ते हैं तथा इतने भारी सैनिक खर्च का बोझ उठाना पड़ता है कि वे गरीब होते जा रहे हैं।

अधिवेशन मे मुसलमान—इस कांग्रेस मे 300 मुसलमान प्रतिनिधि उपस्थित थे। कांग्रेस के अधिवेशन मे मुसलमान शरीफ न हो इस उद्देश्य से 4 दिसम्बर को लखनऊ मे राजा अमीर हुसैन खा के सभापतित्व मे एक सभा हुई थी। इस पर भी 300 मुसलमान प्रतिनिधि कांग्रेस मे आए, यह ध्यान देने योग्य बात है।

नगरपालिकाओं पर प्रहार—इस बीच कलकत्ता कारपोरेशन के अधिकारी पर जो कुठाराघात हुआ था, उस पर भी एक प्रस्ताव पास हुआ। अब तक कारपोरेशन के जितने सदस्य होते थे, उनमे मे दो तिहाई चुने हुए सदस्य होते थे, पर अब उनकी संख्या घटाकर आधी कर दी गई थी, तिस पर चेयरमैन सरकारी आदमी होता था। इस प्रकार कारपोरेशन मे चुने हुए जादमियों की संख्या कम हो गई थी। बम्बई कारपोरेशन के अधिकारों को घटाने के लिए भी एक विधेयक तयार हो रहा था। इस विषय के प्रस्ताव पर बोलते हुए सुरेंद्रनाथ ने लाड कजन के शासन की निंदा की। साथ ही उन्होंने यह कहा “अपनी शिकायतों को रफा कराने के लिए दो मे से एक उपाय का अवलम्बन



करना पड़ेगा, एक तो सर्वैधानिक और दूसरा जाति। हम लोगो ने अपना रास्ता बन लिया है, सरकार अपना रास्ता चुन ले। क्या सरकार हम लोगो की मदद करना चाहता है या जाति सुलगाना चाहती है? सर्वैधानिकता और जाति, इनके बीच कोई मध्यम मार्ग नहीं है। या तो तुम विधानवाद का पक्ष लोगे या जाति की पताका लेकर हा होगे।”

**सरकार की दमन नीति**—सरकार ने इन बातों की कोई परवा नहीं की और अपनी दमन नीति कायम रखी। सरकार को यह बात भी नापसंद थी कि भारतीयों को बाहरी जगत की कोई खबर मिले, इसलिए सरकार ने टेलीग्राफिक मेसेजेज विन नाम के एक कानून का मसविदा पेश किया, जिसके अनुसार सरकार को यह हक दिया गया कि बाहर से तार द्वारा आए हुए समाचारों पर देख रेख रखे। इस देख रेख का मतलब स्पष्ट था। कांग्रेस ने इस कानून का प्रतिवाद करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इसी दिनों सरकार ने शिक्षा सस्याओं में काम करने वालों पर भी प्रहार किया। यह प्रहार इस रूप में हुआ कि सरकारी सहायता प्राप्त विद्यार्थियों के शिक्षकों तथा अध्यापकों को हुकम दिया गया कि वे शिक्षा विभाग के निदेशों की आज्ञा के बिना किसी भी राजनीति काय में शरीक नहीं हो सकते। कांग्रेस ने इसके विरुद्ध भी प्रस्ताव पारित किए।

**कांग्रेस का पहला विधान**—लखनऊ अधिवेशन के अवसर पर कांग्रेस का पहला विधान बना। यह था—

(1) कांग्रेस का उद्देश्य सर्वविधानवादी तरीके से भारतीय साम्राज्य के लोगों के हिता तथा स्वार्थों की पैरवी करना तथा उन्हें आगे बढ़ाना है। (2) राजनीतिक तथा अन्य सस्याओं के द्वारा सार्वजनिक सभाओं के जरिए प्रतिनिधि चुने जाएंगे। (3) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 45 सदस्य होंगे। इनमें से 40 प्रांतीय कांग्रेस कमेटीयों के द्वारा और यदि किसी प्रांत में प्रांतीय कमेटी न हो, तो उस प्रांत के प्रतिनिधि, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों को चुनेंगे। ये सदस्य एक साल के लिए, एक अधिवेशन से दूसरे अधिवेशन तक के लिए चुने जाएंगे। (4) कमेटी की साल में कम से कम तीन बैठकें होंगी और कमेटी को यह अधिकार होगा कि वह नियम बनाए। (5) प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां प्रांतीय कांग्रेस जिला कमेटीयों का निर्माण करेंगी। (6) इंग्लैंड में एक ब्रिटिश कांग्रेस कमेटी होगी, जिसमें एक सवेतन मंत्री भी होगा। इस कमेटी का खर्च साल में 5 हजार रुपया होगा, जो विगत स्वागत समिति और आने वाली स्वागत समिति में आधा-आधा बंट जाएगा।

### कांग्रेस का सोलहवा अधिवेशन

कांग्रेस का सोलहवा अधिवेशन 1900 में नारायण गणेश चंदावरकर के सभापतित्व में लाहौर में हुआ। जिस समय चंदावरकर कांग्रेस के सभापति बनकर आए कहा जाता है कि उसका ऐन पहले ही उनको बम्बई हाईकोर्ट के जज रूप में अपने नियुक्त होने की बात मालूम हुई। इस कारण उनका भाषण बहुत तरम हुआ। इस कांग्रेस में भी पहली कांग्रेसों के प्रस्तावों की पुनरावृत्ति हुई। मालूम होता है कि इन दिनों भारतीय उद्योग धंधों की बढ़ाने की ओर नेताओं का विशेष ध्यान था। इसलिए लाला लाजपत राय ने इस अधिवेशन में यह प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस और जाति के अलावा कम से कम आधा दिन शिक्षा तथा उद्योग धंधों की आलोचना पर दिया करे। इस उद्देश्य से दो कमेटीयां भी बनीं।

## कांग्रेस का सत्रहवा अधिवेशन

कांग्रेस का सत्रहवा अधिवेशन 1901 में कलकत्ते में सैनिक व्यय आदि अनेक विषयों के विशेषज्ञ दीनशा एदमजी वाचा की अध्यक्षता में हुआ। इस कांग्रेस की सबसे बड़ी विशेषता आज की दृष्टि से यह है कि इसमें महात्मा गांधी, उन दिनों के मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी, उपस्थित थे। 1894 से ही वह अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे और इस क्षेत्र में उन्होंने अपने त्याग, तपस्या और सगठन शक्ति के द्वारा सफलता भी प्राप्त की थी। उस समय कोई नहीं जानता था कि यही मिस्टर गांधी अपने देश का इतना प्यारा होना, जितना कि कभी कोई भारतीय नहीं हुआ कि एक पूरे युग तक देश के सारे कार्यों पर इस नाटे से व्यक्ति की छाप रहेगी और इसी के नेतृत्व में देश को स्वाधीनता प्राप्त होगी।

इस कांग्रेस में भी अथ अधिवेशनों की तरह प्रस्ताव पारित हुए। मिस्टर स्मेल्लि नामक एक निमंत्रित व्यक्ति ने कांग्रेस में भाषण देते हुए लोगों से कहा "आप लोग तरह-तरह के प्रस्तावों में जो मांगें पेश करते हैं, वे बहुत ही मामूली हैं, अधिकारी वगैरह इनकी पूर्ति पर आप लोगों को होमरूल न देकर आपको लक्ष्य से और भी दूर हटा रहे हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि आप लोग भारतवर्ष के होमरूल के लिए हर तरीके से चेष्टा कीजिए, ईश्वर आपकी सहायता करेंगे।" इस प्रकार एक बाहरी आदमी ने भी कांग्रेस को यह उपदेश दे ही दिया कि कांग्रेस होमरूल के लिए लड़े, पर अभी कांग्रेसी नेता इससे बहुत दूर थे। अभी उनको बहुत सी ठीक-ठीक खानी थी।

## कांग्रेस का अठारहवा अधिवेशन

कांग्रेस का अठारहवा अधिवेशन अहमदाबाद शहर में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के सभापतित्व में 1902 में हुआ। कांग्रेस के माथ माथ एक स्वदेशी प्रदर्शनी भी हुई। बडौदा के गायकवाड ने इसका उदघाटन किया। उस बीच लाइ कर्जें भारतीयों की उच्च शिक्षा में बाधा पहुंचाने के लिए जो कुछ कर रहे थे, उनके विरुद्ध सभापति ने अपने अभिभाषण में बहुत बड़े मतव्य व्यक्त किए। इससे अतिरिक्त इस कांग्रेस में बोलते हुए सुरेन्द्रनाथ ने एक नई बात कही। वह बोले "अभी तक स्वतंत्रता का झंडा बुलंद नहीं हुआ। स्वतंत्रता की दबी बड़ी ईर्ष्यापरामय है। वह अपनी भक्त मंडली से बराबर यह चाहती है कि दीर्घकाल तक निरन्तर तपश्चरण किया जाय।" कहीं इसका अर्थ अधिक गहरा न समझा जाए इसलिए उन्होंने यह जोड़ दिया कि "स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से घातक संप्रदाय चलाने के लिए कितना अटूट धर्म, सहनशक्ति तथा स्वायत्त्याग की जरूरत है, यह इतिहास से सीखिए।" इस बार भी सदस्यों की तरह मामूली प्रस्ताव रहे। यह स्पष्ट था कि कांग्रेस का नेतृत्व कुछ करने में असमर्थ है। वह अपने तरीकों के निकम्मेपन को समझते हुए भी उसी मार्ग पर चलने के लिए बाध्य था।

## कांग्रेस का उन्नीसवा अधिवेशन

कांग्रेस का उन्नीसवा अधिवेशन मद्रास में 1903 में श्री लालमोहन घोष के सभापतित्व में हुआ। उन्होंने अपने भाषण में सरकार के प्रतिक्रियावादी कानूनों की भी तीव्र आलोचना की। उन्होंने अपने भाषण वगैरह की भी मूचना दी कि इस प्रकार का एक पड़थ व चले रहा है। इस कांग्रेस में जय प्रस्तावों के अतिरिक्त आफिशियल

सीनेटस ऐक्ट का विरोध किया गया, जिसके अनुसार सरकार की किसी गुप्त बायबाही के सम्बन्ध में जानकारी हासिल करना या देना दंडनीय हो गया।

## कांग्रेस का बीसवा अधिवेशन

कांग्रेस का बीसवा अधिवेशन बम्बई में सर हेनरी काटन के सभापतित्व में 1904 में हुआ। सर हेनरी काटन इसबट बिल के दिनों में ही भारतीय पक्ष से चुने थे। वह 1903 तक आसाम के चीफ कमिश्नर थे। इस पद में उन्होंने यह सिफारिश की थी कि चाय बागान के कुलियों की तनख्वाह बढ़ाई जाय। पर उनका प्रस्ताव इस बार स्वीकृत नहीं हुआ कि चाय बागानों के मालिकों ने लाठ कर्जान को पोट किया। भारतीयों के प्रति सहानुभूति के कारण ही काटन लाठ बगाल के लाठ नहीं हो सके। काटन ने अपने अभिभाषण में 'ए फेडरेशन ऑफ फ्री सेपरेट स्टेट्स, दि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इण्डिया' का नारा दिया। उन्होंने प्रस्तावित बग भग पर बोलते हुए कहा कि यदि हमें बड़े प्रांतों को एक लाठ सभाल नहीं सकता, तो या तो बम्बई और मद्रास की तरह बगाल का शासन सून कौंसिल सहित गवर्नर को दे दिया जाय या बंगलाभाषियों को अलग कर एक प्रांत बनाया जाय। स्मरण रहे, उन दिनों के बगाल में बिहार और उड़ीसा शामिल था। बग भग जिस तरीके से बाँट कर किया गया, उसमें बंगला भाषियों को दो अलग अलग हिस्सों में बाँट दिया गया।

अप्य प्रस्ताव—लाठ कर्जान तो मानो प्रतिनिधितावाद की मूर्ति होकर महा अप्य थे। उन्होंने विश्वविद्यालय ऐक्ट बनाकर विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता छीन ली। उन्होंने खुल्लमखुल्ला प्रस्ताव रखा कि शासन विभाग को अच्छी तरह चलाने के लिए गोरे की अधिक नियुक्ति होनी चाहिए। कांग्रेस ने इसका भी विरोध किया। उन दिनों हजारों से ऊपर तनख्वाह वाले पदों में चौदह फी सदी भारतीय और 500 के पड़ो में सत्रह फी सदी भारतीय थे। तिस पर भी बज्र का यह प्रस्ताव था। लाठ कर्जान में साम्राज्य बढाने के लिए तिब्बत में एक ब्रिटिश मिशन भी भेजा था। एक प्रस्ताव में कांग्रेस ने इसके विरुद्ध टीका की। उस युग के कांग्रेस के नेता इस मिशन के अमली अय को समझते थे, यह इससे प्रमाणित है कि श्री वादिया ने इस प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि तिब्बत के किसान अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत शक्तिशाली शत्रु के विरुद्ध लड़ रहे हैं। स्पष्ट है कि हमारे नेता अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से आर्खें बंद किए हुए नहीं थे। इसी कांग्रेस में यह तय हुआ कि कुछ प्रतिनिधि विलायत जाएं। सात्ता लाजपत राय अमेरिका गए, पर उन्होंने यह कहा कि भारतीय समस्या भारतीय ही हल करेंगे।

## बग-भग और स्वदेशी

बग भग कार्यक्रम में परिणत—बग भग होने वाला है यह बात बहुत दिनों से लोगों को मालूम थी। 1903 तथा 1904 की कांग्रेस में इस योजना के विरुद्ध प्रस्ताव भी पास हुए थे। पर लाठ कर्जान ने इसकी कोई परवाह नहीं की। 20 जुलाई 1905 को बग भग के प्रस्ताव पर भारत सचिव का ठप्पा लग गया। हम पहले ही बता चुके हैं कि बग भग में यह मतलब नहीं कि बंगाल जसा कि वह था, उसे दो टुकड़ा में बाँटा गया। राजशाही, ढाका तथा चटगांव को आसाम कहा गया और बाकी हिस्सा यानी प्रेसीडेन्सी कमिश्नरी, बदवान कमिश्नरी बिहार उड़ीसा और छोटा नागपुर मिलकर बंगाल नाम से प्रांत बना। कहना न होगा कि इस प्रकार का विभाजन बिल्कुल मनमाना था। इसमें

कोई आधार ही नहीं था। इस अवसर पर हिंदू और मुसलमानों का यह कहकर लड़ाई की चेष्टा भी की गई कि इस विभाजन से मुसलमानों को फायदा है क्योंकि पूव वग और आसाम में उन्हीं का बोलबाला रहेगा। पहले दावा के नवाब तथा अन्य कुछ मुसलमानों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई थी, पर बाद में वे इसके पक्ष में हो गए। इस प्रकार स पूव वग और आसाम का नया प्रांत बना, सर वैमफोल्ड फूलर उसके गवर्नर हुए, और कहा जाता है कि उन्होंने कई जगह खुल्लमखुल्ला लोगों से कहा कि हिंदू और मुसलमान उनकी दो बीविया हैं, इनमें से मुसलमान बीवी उनको चाहती है। इस प्रकार की युक्ति भददी होने पर भी उसका आशय स्पष्ट था।

**रबीन्द्रनाथ का रणधौब**—वग-भग के कारण बंगाल में जो जोश फैला, वह अभूतपूर्व था। रबीन्द्रनाथ उन दिनों बकिम चन्द्र के चलाए हुए 'बगदशन' को चला रहे थे। उन्होंने उसमें लिखा—“बाहर की कोई बात हममें फूट पैदा कर हमें परस्पर से अलग कर देगी, इसे हम किसी भी प्रकार नहीं मान सकते। जब बनावटी विच्छेद हमारे बीच में खड़ा होगा, तभी हम सचेतन रूप से यह अनुभव करेंगे कि बंगाल के पूव तथा पश्चिम को चिरकाल में एक ही जाह नवीन अपने बाहुओं में बांध रखा है और एक ही ग्रहपुत्र ने उनके प्रसारित जालिगन को ग्रहण किया है। इसी पूव तथा पश्चिम बंगाल ने हमारे दाहिने तथा बाएँ हिस्से की तरह बंगाल की शिराओं तथा उपशिराओं में रक्त को चलाया है, तथा जनता के दाहिने तथा बाएँ स्तन की तरह हमेशा से बंगाली सत्ता का पालन किया है। प्रतिकूल परिस्थितियों के द्वारा ही हममें ध्वस्त का उदबोधन होगा। आज विधाता की रूद्रमूर्ति में ही हमारा परिचायक है। ब्रह्म को चेतन करने के लिए एकमात्र उपाय है, आघात अपमान तथा अभाव। यह वक्ति आदर या आराम में नहीं, आघात से ही विकसित हो सकती है।”

बाद की महात्मा गांधी ने 'हिंद स्वराज्य या 'इंडियन होम रूल' में लिखा (स्मरण रहे कि गांधीवादी चिंतन में इस पुस्तक का बड़ा महत्व है जो मार्क्सवादी विचारधारा में कम्युनिस्ट घोषणापत्र का है)।—“वास्तविक जागृति तो वग-भग से आई। इसमें लिए हम लाड बज्जिन के प्रति आभारी हैं। वग-भग के समय बंगालियों ने लाड बज्जिन में तक रिया, पर गति की मस्ती में उन्होंने निभी की नहीं सुनी। वग-भग समाप्त होगा, बंगाल फिर एक होगा, पर अंग्रेजों की नाव में जो छेद हो चुका है, वह रहेगा। राष्ट्र बन रहा है। रातारान राष्ट्र नहीं बनते, राष्ट्र के निर्माण में वर्षों लग जाते हैं।” उन्होंने और भी लिखा—“अब तब यह समझा जाता रहा कि शिकायतें दूर कराने के लिए हम राजा के दरबार में जाएं और यदि सुनाई नहीं हुई तो हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं। पर वग-भग से लोग समझ गए कि अर्जों के पीछे शक्ति होनी चाहिए और हम कष्ट भेले। बंगाल से जोश उत्तर में पंजाब में तथा कल्याणुमारी तक पहुंचा।”

**जापान द्वारा रूस की पराजय का असर**—इस प्रकार बंगालियों ने सरकार की इस समस्या को चुपचाप ग्रहण नहीं किया, इसके विरुद्ध प्रचल आन्दोलन किया, रबीन्द्रनाथ की भाषा में 'विधान की रूद्रमूर्ति' का आवाहन किया। इसी दिन जापान ने जारशाही रूस पर जो विजय पाई उसका भी असर पड़े लिखे भारतीयों के मन पर बहुत अधिक हुआ। प्रायः कई शताब्दियों से पूर्वीय देश पादशास्य देशों के हमलों के सामने पीछे हटते चले जा रहे थे, होते होते लोगों के निम्न में यह धारणा बढमूल हो गई थी कि गौर अजेय है। जारशाही पर जापान की यह विजय थी, फिर भी इस घटना ने भारत के राष्ट्रीय चिन्तन के लिये बहुत प्रभाव डाला, इसका कारण यह था कि इससे गौर की अजेयता वाली धारणा खत्म हो गई। सारे पूर्वी देशों के उन्नीयमान राष्ट्रीय

आंदोलनों पर इसका यही असर पड़ा। गोरे भी हराए जा सकते हैं, यह धारणा लोगों में फैल गई और इसने लोगों को बल दिया। पूर्व का लगभग प्रत्येक देश विनी न किशो यूरोपीय शक्ति की साम्राज्यवादी इच्छाओं का शिकार था। उनमें हम प्रकार का उभान उठना स्वाभाविक था।

**बायकाट का नारा**—यत्रतत्र सभाएँ होने लगी, पर कोई यह नहीं बता पाता था कि कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाय। जहाँ तक वहने-मुनने की गुंजाइश थी वहाँ तक ता सभी कुछ किया जा चुका था। कांग्रेस ने ही प्रस्ताव पाम किए थे। सर ह्यूग ब्राउन जैसे सरकार के विश्वासपात्र लोगों ने भी इसके विरुद्ध आवाज उठाई थी, पर कुछ नहीं हुआ था। ऐसे समय में बंगाल में विदेशी वस्तुओं के बायकाट का नारा आया। बस जनता ने इस नारे को उठा लिया। 'बायकाट' शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार हुई कि कैप्टन चार्ल्स कनिंगहम बायकाट, आयरलैण्ड में एक जमींदार बं एजेंट थे। वह किसानों से अधिक लगान मांग रहे थे, इस पर किसानों ने लगान देना तो अस्वीकार कर हा दिया। उनसे हर तरीके से असहयोग किया। यहाँ तक कि उनके नौकर उन्हें छोड़ गए और उन्हें खाद्य भी नहीं मिला। इस समय विदेशी द्रव्यों के सम्बन्ध में यही नारा निया गया। इस नारे के कारण घोर अंधकारपूर्ण मुरग में एक ज्योति सी दिखाई पड़ी।

कृष्णकुमार मिश्र ने नारा दिया—इस नारे को पहले पहल अमरद्वार तरीक से प्रसिद्ध नेता कृष्णकुमार मिश्र ने दिया। उन्होंने अपनी पत्रिका 'सजीवनी' में लिखा कि सब लोग यह प्रतिज्ञा करें—“हम लोग मातृभूमि का पवित्र नाम स्मरण कर स्वदेश के कल्याण के लिए यह प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि आगे से यदि देशी माल मिलेगा, तो हम विदेशी माल कभी नहीं खरीदेंगे, ऐसा करने में यदि हमें कुछ आर्थिक या अन्य तरह की हानि उठानी पड़े, तो भी हम उसे सह्य उठाएंगे। हम लोग केवल खुद ही नहीं करेंगे, बल्कि अपने मित्रों से भी जहाँ तक हा सके यही करवाएंगे। ईश्वर हमारे इस शुभ कार्य में सहायक हो।”

**साहित्यिकों द्वारा नारे का समर्थन**—सारे बंगाल में इस वाणी को अपना लिया। कवी ब्रजवीर तथा अन्य साहित्यकारों ने अपनी कविताओं तथा लेखों के द्वारा इस वाणी का बहुत जोरों के साथ प्रचार किया। कवि रजनीकान्त का मीठा—

भायरे देवा मोटा बापड़

मायाए तुले नेरे भाई,

दीन दुखिनी मा जे तोदोर

तार वेशी आर साध्य नाई।

इत्यादि।

यानी मा के दिए हुए मोटे वस्त्र को सिर बिछाकर ले ला।

तुम्हारी मा गरीब और दुखी है, इससे ज्यादा उनके वश का नहीं है।

उन दिनों बहुत प्रसिद्ध हुआ। सुप्रसिद्ध नाटककार दी० एल० राय ने भी स्वदेशी का नारा दिया। सारे बंगाल की मध्यवर्ति श्रेणी के नेताओं ने स्वदेशी के मर्म को अपनाया।

**स्वदेशी के गहरे कारण**—इन दिनों बायकाट और स्वदेशी का नारा इतना सफल हुआ इसका कारण केवल यही नहीं था कि इस प्रकार जनता का अपने भावों को कायरूप में अनुवाद करने के लिए एक मौका मिल गया, बल्कि इसके और भी सामाजिक आर्थिक गहरे कारण थे। इस समय तक भारतवर्ष में कुछ स्वदेशी मिलें खुल चुकी थी, ब्रिटिश सरकार का इनके प्रति क्या रुख था यह वस्त्र शिल्प पर लगी हुई असुविधा

जनक रोका से ही ज्ञात होता है। इसलिए स्वदेशी मिलो तथा उदीयमान देशो पूजीवाद के अपने पर पर खड़े होने के लिए स्वदेशी का नारा बहुत ही उपयोगी था। विलायती चीजों के मुकाबले में स्वदेशी चीजें मुश्किल से ठहर सकती थी, इसी कारण उन्हें भावना के सहारे की आवश्यकता थी।

**स्वदेशी और मुसलमान**—जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कुछ मुसलमान सरकार के बहुधावे में आ गए पर अन्य बहुत से मुसलमानों ने स्वदेशी का नारा अपनाया। ढाका के नवाब सलीमुल्ला के भाई अकातुल्ला, बरिस्टर अब्दुल रसूल, अब्दुल हलीम गजनवी अब्दुल गफूर मिहोकी, इम्माइल सिराजी, लियाकत हुसैन आदि विशिष्ट मुसलमान नेताओं ने स्वदेशी का नारा अपना लिया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो कारण बताए गए वे मुसलमानों पर उतनी हद तक लागू न होने पर भी यानी जिन मिलों का उदघाटन हो रहा था उनमें मुसलमान पूजीपतियों की अल्पसंख्या होने पर भी वे सामान्य पूजीवाद के प्रभावों से बरी नहीं हो सकते थे। स्वदेशी से मुसलमान जुलाहा को लाभ होने वाला था। फिर इस नारे से मुसलमानों में, सुप्त ही सही, अंग्रेज विद्वेष पुष्ट होता था।

**स्वदेशी के लिए संगठन**—विलायती माल के वायकाट तथा स्वदेशी माल को अपनाने के लिए इस युग में बहुत सी समितियाँ बन गई। ऐसी समितियाँ में चित्तरजन दास (बाद के देशभू दास) के घर में स्थापित स्वदेशी मंडली, मनोरजन गुह ठाकुरता की वस्ति समिति, सुरेशचंद्र ममाजपति का बंदे मातरम् सम्प्रदाय तथा भवानीपुर का सतान सम्प्रदाय वनवत्ता की फोल्ड लण्ड एकेडेमी क्लब, और बरीसाल की स्वदेश बांधव समिति, ममनसिंह की सुहृत् समिति विशेष उल्लेख योग्य हैं।

**राखी बंधन और अरधन**—सरकार की तरफ से यह घोषणा की गई कि 16 अक्टूबर को बग भग कर दिया जाएगा, और उस दिन से दो प्रांत अलग अलग काम करने लगेंगे। गत दो-तीन सालों में बंगाली यह आन्दोलन करते आ रहे थे कि बग भग न हा, पर यह होकर ही रहा। बंगाल का जनमत इस घोषणा से बहुत ही विक्षुब्ध हुआ। रवी द्रनाथ बग भग आन्दोलन के विलकुल सामने की कतार में थे। उन्होंने यह वक्तव्य दिया कि, सरकार बंगलाभाषियों को अलग कर रही है पर हम दिल से अलग नहीं हो सकते। इसी के प्रश्नान के लिए उन्होंने 16 अक्टूबर के दिन राखी बांधने का नारा दिया। राखी एकता का सूचक था। रवी द्रनाथ ने इधर यह नारा दिया और उन दिनों के बंगाली साहित्य के महाग्रन्थी श्री रामे सुंदर त्रिवेदी ने यह नारा दिया कि लोग उस दिन अरधन व्रत करें यानी बंगाल भर में उस दिन किसी के घर में चूल्हा न जले और बच्चा तथा रोगियों के अतिरिक्त कोई खाना न खाए। लोगों को यह प्रस्ताव भी पसंद आया।

**अखंड बगभवन का प्रस्ताव**—इसी तरह सुरे द्रनाथ ने यह प्रस्ताव रखा कि कलकत्ते में परिस के 'होटेल द इनवलिड' के नमून पर एक भवन बने। जिस समय सुरे द्रनाथ परिस गए थे, उस समय उन्होंने देखा था कि होटेल द इनवलिड भवन में भास के प्रत्येक डिपाटमट या जिले की मूर्तियाँ हैं। उन दिना अलमाम लरेन जमनी के अधीन था। इसलिए अलमाम लरेन की मूर्ति तो वहाँ पर थी पर वह ढकी हुई रहती थी, इसी के अनुकरण में सुरे द्रनाथ का यह प्रस्ताव था कि कलकत्ते में जो भवन बने, उसमें बंगाल के प्रत्येक जिले की एक मूर्ति रहे, और जो जिले बंगाल से अलग हैं, उनकी मूर्तियाँ अलमाम लरेन के तरीके पर ढकी हुई रहे। सुरे द्रनाथ का यह प्रस्ताव भी लोगों को पसंद आया।

**बंगाल का नारा** — 16 अक्टूबर को ये तीनों कार्यक्रम पूरे किए गए। आम हड़ताल रही। लोगों के घरों में चल्ते नहीं जले, और सारा बंगाल उस दिन भूखा रहा। अगले सारा बंगाल से यहाँ कुछ भुसलमानों को छोड़कर लिया जा रहा है। उस दिन कई तरह की कायवाही एक साथ हुई। एक तो राखी बांधी गई।

कवींद्र रवींद्रनाथ ने राखी के लिए एक गाना बनाया—

बागलार माटी, बागलार जल,  
बगलार वायु बागलार फल,  
पुण्य होऊक पुण्य होऊक, हे भगवान  
इत्यादि।

यह द्रष्टव्य है कि अब बंगला के कवियों ने भारतवर्ष को छोड़कर फिर बंगाल का नारा दिया। बंगाल के बंकिम और रमेशचंद्र दत्त ने अपना उप यासों तथा डी० एस० राय ने नाटकों में राजस्थान और महाराष्ट्र के मध्ययुगीन वीरों को लेकर अखिल भारतीय देशभक्ति का पाठ पढ़ाया था। फिर भी अब चन्न पीछे को घुमा। क्या?

चन्न पीछे क्यों घुमा?—यह स्वाभाविक ही था क्योंकि बंग भग की आप्त बंगाल पर ही आई थी, और दूसरे प्रांतों के लोगों ने भले ही इसके लिए सहानुभूति दिखाई हो, पर बंगालियों ने उन दिनों जिस भावुकता का अनुभव किया उसे दूसरे प्रांत वाले उस हद तक समझ नहीं सके, उसमें भाग लेने की बात तो दूर रही।

आंदोलन बंग भग से आम निकल गया—यद्यपि हम आंदोलन की उत्पत्ति बंग भग से ही हुई थी, और स्वाभाविक रूप से बंग भग के रह जाते से ही इसका अंत होना चाहिए था, पर यह इनमें से ही समाप्त नहीं होने वाला था, यह 16 अक्टूबर को जो गाने गाए उन्हीं से जात होता था। जाति की सुप्त चेतना एक ठोकर से जागी थी, पर वह उस ठोकर के बहुत आगे जाने वाली थी। इस अवसर के लिए रवींद्रनाथ के उल्लिखित गीत के अतिरिक्त एक और भी गीत गाया गया। हम उस गीत का अनुवाद देते हैं—

“बध्न जितना ही कड़ा होगा, उतना ही वह दूटेगा। हम लोगों का बध्न उतना ही टूट चलेगा। उनकी जाखें जितनी ही लाल पीली होंगी, हम लोगों की आखें उतनी ही खुलेंगी, उतनी ही खुलेंगी। आज तुम्हें कमखीन में जुट पड़ना है, स्वप्न देखने का समय नहीं है। इस समय के जितना ही गजन-तजन करेंगे, हमारी नींद उतनी ही खुलेगी, हमारी नींद उतनी ही खुलेगी।”

यह स्पष्ट है कि यह आंदोलन अपने जन्म के पहले ही दिन बंग भग से कहीं आगे बढ़ चुका था। बंग भग तो चिनगारी थी जिसने जन-आंदोलन को एक विराट अग्निकांड में परिणत कर दिया।

**प्रतिवाद में सभा**—उस दिन कलकत्ते में लोगों ने गया स्नान किया तथा राखी बांधी। उस दिन दोपहर के बाद सुरेन्द्रनाथ के प्रस्ताव के अनुसार अखंड बगभवन की स्थापना के उपलक्ष्य में एक सभा हुई। बड़े नेता आनंदमोहन बसु स्वस्थ बीमार थे। थोड़ा दिमाग वह मर भी गए, पर उस दिन इस सभा का सभापतित्व करने के लिए उन्हें आरामकुर्सी पर बिठाकर ले आया गया। 50 हजार जनता इकट्ठी थी। आनंदमोहन सभास्थल में ता आ गए, पर वह बोल नहीं सके। सुरेन्द्रनाथ ने आनंदमोहन का व्याख्यान लोगों को पढ़कर सुनाया। रवींद्रनाथ सभास्थल पर केवल उपस्थित ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने इस सभा की कायवाही में प्रमुख भाग लिया। उस दिन बंदिमातरम की ध्वनि से आकाश गूँज रहा था और यही से यह नारा स्थाई रूप से राष्ट्रीय नारा हो गया।

उस दिन की घोषणा—उस दिन का सक्त्प कहा जाय या उसे घोषणा कहा जाय, उस बूढ़े आनन्दमोहन बसु ने अपने हाथ से लिखा था। इसे अग्रेजी में बाद के जस्टिस सर आशुतोष चौधरी ने और बंगला में रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने पढ़कर सुनाया। यह घोषणा यो थी—

“चूँकि सावजनिक विरोध को न मानकर ब्रिटिश संसद ने बम-भग करना उचित समझा है, इसलिए हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि बंग भग के कुपरिणामों को नष्ट करने के लिए तथा बंगाल की एकता की रक्षा करने के लिए हम लोग से जो कुछ भी बन पड़ेगा वह करेंगे। ईश्वर हमारी सहायता करें।”

चर्खा और करघा प्रचार—संख्या समय एक और सभा हुई। इसमें एक लाख से अधिक जनता इकट्ठी थी। यह सभा विशेषकर इसलिए बुलायी गई थी कि स्वदेशी वस्त्र तैयार करने के लिए एक कोष खोला जाय। इस सभा में पचास हजार रुपये एकत्र हुए। बाद की यह रकम सत्तर हजार हो गई। इस रकम से कानवालिंस स्ट्रीट पर एक मकान में चर्खा और करघा विद्यालय स्थापित हुआ। इस विद्यालय में कई सौ चर्खे थे। बाद की गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस ने चर्खा की जो याजना रखी है, वह यहाँ पहले से ही मौजूद थी।

देशी उद्योग धर्मों की उन्नति —चर्खा और करघा सफल न रहने पर भी स्वदेशी आन्दोलन के फलस्वरूप भारत के उदीयमान पूँजीवाद को बहुत सहायता मिली। बंग लक्ष्मी मिल, कर्क दर, साबुन, स्टील ट्रक, जूते के कारखाने, बीमा कम्पनिया आदि बहुत से नए उद्योग धर्म खुले।

स्वदेशी और स्त्रियाँ —स्वदेशी के प्रचार में बंगाल की स्त्रियों ने बहुत अच्छा हाथ बटाया। गणेश सुन्दर त्रिवेदी ने ‘बंग लक्ष्मी की व्रत कथा’ में लड़कियों के लिए व्रत की प्रतिष्ठाएँ लिखी—‘माता लक्ष्मी, कृपा करो, वाचन देकर काच नहीं खरीदूंगी। घर का मिलेगा तो बाहर का नहीं पहनूंगी। दूसरे के द्वार पर भीख नहीं मांगूंगी। मोटा वस्त्र पहनूंगी, सान् गहन पहनूंगी, सान् पोशाक होगी। पड़ोसी को खिलाकर खाऊंगी। मोटा अन्न अक्षय हो, मोटा वस्त्र अक्षय हो, घर की लक्ष्मी घर पर रहे, बाहर न जाए।’

सचमुच स्त्रियाँ ने ही स्वदेशी को सफल किया। कवियों ने बहुत से गाने केवल स्त्रियों को ही सम्बोधित करके गाए।



## आन्दोलन युग का आरम्भ वग-भग और अनन्तर

### कांग्रेस का इक्कीसवा अधिवेशन

कांग्रेस का इक्कीसवा अधिवेशन बनारस में 1905 में श्री गोपालकृष्ण गोबिल की अध्यक्षता में हुआ। सभापति ने अपने अभिभाषण में स्वाभाविक रूप से वग भग का उल्लेख किया और कहा, 'वग भग का फलस्वरूप बंगाल में जो विराट जागृति हुई है, उसका हमारा राष्ट्रीय इतिहास में बहुत बड़ा स्थान है। ब्रिटिश शासन में यह पहला है। मौका है जब घर्म और जात पात भूल कर बाहर से किसी की सहायता की परवाह न कर बंगाली अपनी स्वाभाविक वृत्ति से आगे बढ़ रहे हैं।'

श्री गोखले ने अपने अभिभाषण में स्वदेशी के नारे का तो समर्थन दिया, पर बायकाट के नारे के सम्बन्ध में कहा कि इस शब्द के साथ द्वेष तथा हिंसा की भावना रहने के कारण यह ठीक नहीं है।

श्री गोखले ने इस प्रकार मतव्य देने के बाद भी यह कहा कि बंगाल की हालत इतनी खराब हो गई है कि उसमें बायकाट भी सही मालूम होता है।

**वग भग का प्रस्ताव**—सभापति के अभिभाषण के अतिरिक्त वग भग पर एक प्रस्ताव भी रखा गया। श्री सुरेन्द्रनाथ ने यह प्रस्ताव रखा। उन्होंने अपने भाषण में बंगाल में जो जो अत्याचार हो रहे थे, उनका उल्लेख किया। सभा, जुलूस, भजन पाठियों पर रोक, वदेमातरम गाने के लिए मारपीट, बच्चों को सजाए, गुरावों का अत्याचार आदि विषयों का उल्लेख किया। वग भग के कारण बंगाल के छात्र-समाज में बहुत जोरों का आन्दोलन हुआ।

बहुत स छात्रों को स्कूल से निकाल दिया गया था, कुछ लोगों को बेंत मारे गए थे। गरती चिट्ठियों से पबडाने की बजाय कलकत्ते के छात्र समाज ने 'गरती चिट्ठी' विरोधी सभा नाम से अपना संगठन कायम किया। इस सभा की तरफ स बड़े बाजार की विलायती कपड़े की दुकानों पर पिकेटिंग भी हुई। निष्पासित छात्रों को लेकर 9 नवम्बर 1905 को कलकत्ते में एक सभा हुई, जिसमें राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए सुबोधचन्द्र ने एक लाख रुपया दान दिया। इसी प्रकार कई और जमींदारों ने बाद में और भी दान दिए। छात्र-समाज नहीं दबा था।

पंडित मदनमोहन मालवीय ने एक प्रस्ताव में बायकाट का समर्थन करते हुए बहुत ओजस्वी भाषण दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए भारतीया के हाथ में एक यही तरीका है। लाला लाजपत राय ने भी स्वदेशी का समर्थन करते हुए कहा कि देश की गरीबी को दूर करने के लिए यही एक उपाय है।

**विलायत में चुनाव**—वग भग के अलावा कांग्रेस में पहले की तरह बहुत से प्रस्ताव हुए। इस बीच विलायत में चुनाव हुआ था और उसमें उदार नैतिक दल की जीत

हुई थी। इससे भारतीयों को बड़ी आशाएँ थी। जान मार्ले के भारत सचिव हो जान से इस प्रकार की आशाएँ और भी पुष्ट हुई थी। मार्ले बंग भग के पक्षपाती नहीं थे, तो भी उन्होंने कहा कि वह बात तो हो चुकी है। इससे और भी जोश फला, और लोगो ने स्वदेशी व्रत को दृढ़ता के साथ अपनाया।

**बरीसाल सम्मेलन—** 1888 में बंगाल में एक प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन हुआ करता था। यह तय हुआ कि 1906 के 14 और 15 अप्रैल का इस सम्मेलन का अधिवेशन बरीसाल में हो। इस काफ़ेस के सभापति वरिस्टर अब्दुल रसूल चुने गए। बरीसाल की उन दिना हालत यह थी कि वहाँ वदेमातरम का नारा भी गैरकानूनी था। बरीसाल के बहुत से युवक इस दृक्म को न मानकर जेल जा चुके थे, तथा उन पर मार पड़ चुकी थी। सरकार को खतरा था कि इस काफ़ेस के अवसर पर वदेमारम का नारा अवश्य दिया जाएगा। तदनुसार स्वागत समिति से यह वात्ता करा लिया गया कि जब प्रतिनिधि बरीसाल पहुँचें, तो उनके स्वागत में वदेमातरम का नारा न दिया जाय। ऐसा ही हुआ, पर गश्ती चिट्ठी विरोधी सभा के सदस्य इस शत पर इतने नाराज हुए कि उन्होंने स्वागत समिति से सम्बंध रखना उचित नहीं समझा और अलग जाकर ठहर गए। अंत में दोनों दला में समझौता हुआ कि काफ़ेस के पहले दिन प्रतिनिधि मिलकर वदेमातरम का नारा देंगे और राजा बहादुर की हवेली नामक इमारत में जुलूस घना कर सभा स्थल पर जाएंगे।

**जुलूस पर लाठियाँ—** जुलूस में आगे आगे सभापति अब्दुल रसूल तथा उनकी मम पत्नी की गाड़ी थी। इसके पीछे पीछे नेता पैदल चले। सबसे पीछे गश्ती चिट्ठी विरोधी सभा के सदस्य थे, जो वदेमातरम का नारा तो नहीं दे रहे थे, पर वदेमातरम का बज पढ़ने हुए थे। ज्यों ही गश्ती चिट्ठी विरोधी सभा के लाग हवेली से निकले, रवों ही पुलिस ने उन पर लाठियों से हमला कर दिया। अब क्या था, लोग चिल्ला चिल्लाकर वदेमातरम कहने लगे। ऊपर से लाठियाँ पड़ने लगी। बंगल में ही तालाब था, एक तो उसी में गिर पड़ा।

**सुरेन्द्रनाथ पर जुर्माना—** सरकार ने सुरेन्द्रनाथ को 188 रुपया के अंतगत गिरफ्तार कर लिया और 200 रुपया जुर्माना कर दिया। सुरेन्द्रनाथ ने अदालत में एक कुर्सी पर बैठने की चेष्टा की, इस पर अदालत की अमर्यादा करने के अपराध में उन पर और 200 रुपये जुर्माना हुए। वह जुर्माना देकर चले आए।

**अत्याचार की निंदा—** सम्मेलन में पहला आलोच्य विषय पुलिस का अत्याचार था। जो सज्जन तालाब में डूबते डूबते बचे थे, उन्होंने खड़े होकर पुलिस के अत्याचार की कहानी बताई। कई प्रस्तावों में यही जिक्र रहा। सभापति महोदय ने यह साफ कर दिया कि घम अलग-अलग होने पर भी राजनीतिक आदालत में हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब एक हैं। यह द्रष्टव्य है कि सरकार ने सभापति को नहीं पकड़ा और सुरेन्द्रनाथ को पकड़ा, जो उनकी गाड़ी के पीछे पैदल चल रहे थे। ऐसा करने से सरकार का उद्देश्य स्पष्टतः यह था कि एक मुसलमान को गिरफ्तार कर साधारण मुसलमान को तैश न दिलाया जाय। यह नीति बराबर चली।

**पुलिस द्वारा सभा भग—** अगले दिन जब नेता सम्मेलन की कारवाई के लिए पधारे, तो पुलिस सुपरिटेण्डेंट सभा स्थल में आया और मिस्टर रसूल से यह कहा कि या तो वह वादा करें कि सभा में वदेमातरम का नारा नहीं दिया जाएगा, नहीं तो सभा भग करें। नेता इस प्रकार की अपमानजनक शत को मानने के लिए तैयार नहीं हुए परिणाम यह हुआ कि सम्मेलन की कारवाई नहीं हुई और सभा भग कर दी गई।

बंगाल में शिशुजी उत्सव— इस साल बंगाल में बड़ी धूमधाम के साथ शिशुजी उत्सव भी मनाया गया। इस उत्सव के प्रवक्ता लोकमान्य तिलक खापड़ें तथा पत्रों लेकर इस मौके पर बंगाल पधारे। उत्सव के साथ साथ एक स्वदेशी मेला भी लगा। जिस समय लोकमान्य तिलक बंगाल आए, तो बंगालिया ने उनका खूब स्वागत किया, 10 जून को 30 हजार जनता ने लोकमान्य तिलक को लेकर जुलूस निकाला और ज़ावर गंगा स्नान किया। इस मौके पर भवानी पूजा भी हुई। इस प्रकार इस उत्सव में शिशुजी, गंगा स्नान, भवानी पूजा आदि ऐसी कई बातें जुड़ गई। इन्हीं दिनों प्रतापानन्द और सीताराम राय आदि मुगल विरोधी वीरा का उत्सव मनाया गया और उन पर पुस्तक लिखी गई। श्रीमती सत्यादेवी ने वीरपूजा का नारा दिया। अखाड़े तथा छुरा आदि खेलने का भी प्रारम्भ हुआ। स्पष्ट था कि यह आन्दोलन अब धीरे धीरे उग्रतर होना जा रहा था।

'वन्देमातरम्' और अरविन्द — इन्हीं दिनों 'वन्देमातरम्' तथा 'युगान्तर' पत्र प्रकाशित हुए। 'वन्देमातरम्' पत्र का मोटा 'भारतीया' के लिए भारत था। इसके सम्पादक मन्मथ विपिनचन्द्र पाल भी थे। बाद को श्री अरविन्द घोष इस पत्र के निपमित लेखक हुए। उन्होंने 'वन्देमातरम्' में 'यू स्फिरिट' या 'नया माग' घोष के एक लेखमात्रा लिखा, जिसका जनता पर बहुत भारी असर पड़ा। इसके कोई 11 साल पहले ही उन्होंने 'इन्दुप्रकाश' नामक म्यून्सिपल पत्र में कांग्रेस की उन दिनों की नीति की निन्दा करते हुए एक लेख लिखा था और बताया था कि भिक्षापात्र से कुछ होना जाना नहीं है।

युगांतर — 'युगांतर' पत्र बहुत अधिक चला। इसके संपादक स्वामी विवेकानन्द के छोटे भाई भूपद्रनाथ दत्त थे। अन्य लेखकों में अरविन्द घोष, छपेन्द्र व दोषाध्याय आदि थे। उन दिनों आजकल की तरह पत्रों की ग्राहक संख्या हजारों नहीं होनी थी, फिर भी इस पत्र की ग्राहक संख्या 7 हजार थी, और एक एक पत्र को बाँटने लोग पड़ा करते थे। पत्र में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रचार किया जाता था और कहा जाता था कि क्रांतिकारी तरीका से ही देश स्वतंत्र हो सकता है। 'युगान्तर' जनता में इतना प्रिय हो गया था कि छपत ही उसकी कापियां लूट जानी थीं। पत्रकारिता के इतिहास में 'युगांतर' का अमर दान है। रवीन्द्रनाथ भी 'भारत' नामक एक पत्र में स्वदेशी पर जोर दे रहे थे।

राष्ट्रीय शिक्षा परिषद — स्वदेशी आन्दोलन के सिलसिले में अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय शिक्षा की बात भी उठी। विशेषकर यह प्रश्न नेताओं के सामने इस कारण आया कि वन्देमातरम् तथा स्वदेशी आन्दोलन में भाग लेने के कारण बहुत से छात्र अपने विद्यालयों से निकाल लिए गए। कई तो रस्टीकेट कर दिए गए यानी उनके लिए किसी भी स्वीकृत शिक्षा संस्था में भर्ती होने की मुमानियत हो गई। लोगों को आवश्यकता प्रतीत हुई कि एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो। कचोदर रवीन्द्र, गुरुदास बंदोपाध्याय, हीरेन्द्रनाथ दत्त आदि ने इसका बीड़ा उठाया। इन्हीं लोगों ने भीतर भीतर इसके लिए आन्दोलन किया, और जब आन्दोलन कुछ परिपक्व हो गया, तो कलकत्ता के टाउन हाल में एक सभा बुलाई। डाक्टर रासबिहारी घोष इसके सभापति हुए। इसी सभा में नेशनल कोल्लिज आफ एज्युकेशन या राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। श्री सतीशचन्द्र मुखोपाध्याय परिषद के अध्यक्ष बनाए गए। 'दान' नामक पत्र के संपादक तथा डान सोसाइटी के संपादक के रूप में सतीश बाबू पहले ही प्रसिद्ध हो चुके थे।

छात्र समाज पर फुलर का प्रहार असफल — छात्रों पर सरकार का कोप विशेष

रूप से इस कारण हुआ कि उन्हीं के कारण आंदोलन दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा था। पहले ही बताया जा चुका है कि बंगाली छात्रों को आंदोलन से अलग कर देने के लिए तरह-तरह की गश्ती चिट्ठियाँ निकाली गई थी, पर इससे कुछ काम नहीं हुआ।

उन्होंने बलकत्ता विश्वविद्यालय के अधिकारी वग से यह कहा कि विक्टोरिया स्कूल को स्वीकृत विद्यालय की सूची से निकाल दो। विश्वविद्यालय के अधिकारी फुलर की इस बात पर राजी नहीं हुए। लाड मिटो उन दिनों भारत के वायसराय होने के अतिरिक्त बलकत्ता विश्वविद्यालय के चांसलर भी थे। यह मामला उनके निकट फैसले के लिए गया, तो विश्वविद्यालय की ओर से सर आशुतोष ने बड़े लाट से मिलकर यह समझा दिया कि विश्वविद्यालय को ऐसे मामले में नहीं पड़ना चाहिए। यह बात लाड मिटो की समझ में आ गई, और उन्होंने लाट फुलर को लिख भेजा कि इस मामले का ज्ञान दो। फुलर ने लाड मिटो को लिख भेजा कि यदि उसकी मांग मानी नहीं गई, तो वह इस्तीफा दे देगा। अब लाड मिटो क्या करते, उन्होंने मामले की रिपोर्ट भारत सचिव माल्ले को लिख भेजी। माल्ले ने भी बड़े लाट का पक्ष लिया। इस कारण फुलर को इस्तीफा देना पड़ा। इस प्रकार फुलर से बंगाल का पिण्ड छूटा।

**विषय—**देश की बिगड़ती हालत को देखकर ब्रिटिश सरकार से यह प्रस्ताव किया गया था कि भारतीयों को शासन सुधार की एक बिस्त दी जाए। इस मिनमिले में 1906 के अक्टूबर को आगा खा तथा कुछ अन्य मुसलमान वायसराय से मिले, और उनसे कहा कि भविष्य के शासन सुधारों में मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व दिया जाए, साथ ही वास्तविक आवादी से अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। लाड मिटो ने इनकी बातों को ध्यान से सुना और कहा कि मैं आप लोगों की माकूल मांगों को मानूंगा। बाद में जो माल्ले मिटो सुधार दिए गए, उसमें सचमुच आगा खा की ये मांगें मान ली गई। यही से उस विषय का सूत्रपात होता है, जिसने बाद में बहुत ही विषम फल दिए।

**मुस्लिम लीग स्थापित—**9 नवम्बर 1906 के दिन नवाब सलीमुल्ला खा ने प्रतिष्ठित उच्च श्रेणी के लोगों की सलाह से एक गश्ती चिट्ठी भेजी, जिसमें भारत के मुसलमानों की एक राजनीतिक संस्था संगठित करने की ओर ध्यान आकषित किया गया। इसी उद्देश्य को सामने रखकर अखिल भारतीय मुस्लिम एजुकेशनल कांफ्रेंस की सालाना बैठक बुलाने के लिए कहा गया। तदनुसार 30 दिसम्बर 1906 को ढाके में प्रमुख मुसलमानों की एक सभा हुई, और यही नवाब बकारुलमुल्क के सभापतित्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग कायम की गई।

**लीग के उद्देश्य** लीग जिन उद्देश्यों को लेकर स्थापित हुई, वे इस प्रकार थे—

(1) भारतीय मुसलमानों के दिल में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादाराना खयाल उत्पन्न करना, और सरकार की कार्यवाहियों के बारे में उत्पन्न गलतफहमियों को रफा बरना। (2) मुसलमानों के राजनीतिक हकों तथा हितों पर निगरानी रखना, और उनकी आवश्यकताओं तथा इच्छाओं को नज़र में रखकर सरकार के सामने पेश करना। (3) लीग के दूसरे उद्देश्यों को नुकसान पहुंचाए बिना भारत के मुसलमानों में दूसरी जातियों के प्रति सद्भाव रखना।

**लीग और कांग्रेस—**इस प्रकार लीग सरकार के प्रति करीब करीब उसी राज-भक्तिपूर्ण रुख को लेकर चली, जिसे अपनाकर कांग्रेस का जन्म हुआ था, पर एक भारी फक यह था कि लीग इक्कीस साल बाद उस उद्देश्य को लेकर चली, और दूसरा यह कि लीग एक साम्प्रदायिक संस्था बनकर जमी, और उसी रूप में आगे बढ़ी जबकि

कांग्रेस जिन मांगों को भी रखती थी, उन्हें सार भारतीयों की दृष्टि में रखनी थी। व दृष्टि में दृष्टा पर भी लोग के नेता सामन्तवादी थे। वे थे, जबकि कांग्रेस नेवाले पूँजीपति वर्ग तथा पद्धति से सम्बन्धित सामान्य की तरफ से खींचती थी।

वर्ग संग और लीग — लीग का राजनीतिक रुख इससे स्पष्ट हो जाएगा कि प्रस्ताव में वर्ग संग का मुसलमानों के हक में अच्छा बनाया गया और यह कहा गया कि जातिगत अन्ध विरुद्ध आवाज उठा रहा है, वे मुसलमानों को मुक्त करने पहुँचा रहे। मातृभूमि में एक तरह से जन आन्दोलन का सूत्रपात ही वर्ग संग आन्दोलन में होता है। इसका उद्देश्य अनिश्चित रूप से वर्ग संगी बना नहीं थी जो मुसलमानों के विरुद्ध थी, बल्कि लीग ने अपना जीवन का सूत्रपात ही इस आन्दोलन के विरोध से किया। लीग का बराबर यही रवैया रहा। इन्होंने बाद में 1908 में प्रस्ताव पारित किया कि कांग्रेस के वर्ग संग विरोधी प्रस्ताव स्वीकृत होने योग्य नहीं।

भाषिका के पद्धति का प्रारम्भ — 1903 में ही बारीन्द्र कुमार घोष के निम्नलिखित दृष्टिकोण पर गुप्त समितियाँ कायम करने की बात जादू पर बंगाल का दौरा का उन्होंने दृष्टा कि अभी परिस्थिति परिपक्व नहीं हुई है। 1904 में जब वर्ग संग के म. म. बंगाली बहुत क्षुब्ध हो चके थे उस समय बारीन्द्र ने बंगाल का फिर दौरा किया जहाँ हुआ कि जमीन पहल में अधिस्तयार हो चुकी है। उन्होंने इस बार असाढ़ी स्थापना में भाग लिया, साथ ही यह चेष्टा की कि इन असाढ़ी में लीग राजनीति का आलोचना करे। इस प्रकार धीरे धीरे अस्त्र शस्त्र भी एकत्र होने लगे और गुप्त समिति बन गई। बारीन्द्र ने जिस संगठन का निमाण किया, वह जब बाद में जाकर पकड़ा तो अलीपुर पद्धति के नाम से मशहूर हुआ। हम यथासमय इसका उल्लेख करेंगे।

## कांग्रेस का बाईसवा अधिवेशन

कांग्रेस का बाईसवा अधिवेशन बलकम्ता में 1906 में होने वाला था परग और नरम में भीतर ही भीतर संघर्ष चल रहा था। कौन कांग्रेस का सभापति इसे लेकर नरम और गरम दल में मनमुटाव था। गरम दल के नेता लोकमान्य थे। उग्र दल चाहता था कि लोकमान्य तिसक सभापति हों, पर नरम दल इस बात से विरोध करता था। इन दिनों नरम दल के नेता मुरली बनर्जी, गोपाल, भूपेन्द्र बनर्जी थे। सच तो यह है कि कांग्रेस के सभी पुराने नेता अब नरम दल में थे। नरम दल ने देखा कि विवाद अनिवार्य है और सख्या में अधिक होने पर भी कांग्रेस में नरम दल मदद ही रहेगी। इसलिए उन्होंने यह चाल चलनी चाही कि 82 साल के बड़े दादाभाई नौरोजी को सभापति बनाया जाए तो गरम दलवालों का महत्त्व हो जाएगा, और यदि वे इस पर भी चुप नहीं हुए तो उन्हें उन्हीं की मदद होगी। तदनुसार दादाभाई सभापति चुने गए। उन दिनों नियम यह था कि स्वागत समिति सभापति चुननी थी और वह कलकत्ता की थी, जहाँ उन दिनों नरम भी बहुत कुछ नरम हो रहे थे। इसलिए यदि चुनाव होता, तो लोकमान्य तिसक ही चुने जाते। पर इस चाल के कारण गरम दलवाले चुप रह गए।

स्वराज्य के लिए निरुपद्रव आन्दोलन पर जोर — इस कांग्रेस के समय बड़ा जोश था। बीस हजार जनता अधिवेशन देखने आई, और सालह सो से अधिक प्रतिनिधि। दादा को कांग्रेस में दादाजी ने जहिमा तथा शांति का जो नारा दिया, वह भी कांग्रेस के अन्दर विकास की प्रतिक्रिया ने आधार पर उद्भूत हुआ, यह इससे बात साफ़ कि अधिवेशन के सभापति पद से बोलते हुए प्रियतामह दादाभाई ने कहा "आन्दोलन करो,

निरन्तर आदातन करो। लोकतांत्रिक ब्रिटिश जाति आन्दोलन के सामने जितना सिर झुकाती है, उतना किसी बात के सामने नहीं। पर आन्दोलन सब प्रकार के उपद्रवों से वर्जित हो और लोकतांत्रिक हो।" दादाभाई ने अपने अभिभाषण में पहले पहल 'स्वराज्य' शब्द का प्रयोग किया और उसकी व्याख्या करते हुए कहा कि इससे औपनिवेशिक स्वराज्य ही अभीष्ट है।

कांग्रेस के प्रस्ताव — इस कांग्रेस के प्रस्तावों में स्वदेशी युग की पूरी छाप थी, यद्यपि उनकी अंतर्वस्तु पहले के अधिवेशनों के प्रस्तावों से बहुत भिन्न नहीं थी। स्वराज्य अर्थात् औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग करते हुए यह कहा गया कि इसे वाय रूप में परिणत करने के लिए पहले कदम के रूप में फौरन आई० सी० एस० आदि की परीक्षा भारत तथा इंग्लैंड दोनों स्थानों पर हो, कौंसिलों में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़े, स्थानीय स्वायत्त शासन को विस्तृत किया जाए, इत्यादि। एव प्रस्ताव में स्वदेशी को मंजूर किया गया, दूसरे प्रस्ताव में राष्ट्रीय शिक्षा की आवश्यकता बतलाई गई। वायकाट के समय में भी एक प्रस्ताव पारित हुआ।

कांग्रेस के विधान में परिवर्तन — इस अधिवेशन में कांग्रेस के विधान में भी कुछ परिवर्तन हुए। अब तक स्वागत समिति बहुमत में सम्भाषित का चुनाव करती थी, पर अब यह नियम हो गया कि सम्भाषित का चुनाव तीन चौथाई वोटों से होना चाहिए। यदि सम्भाषित का चुनाव इस प्रकार न हो सके, तो अखिल भारतीय स्टैंडिंग कमेटी सम्भाषित का चुनाव करेगी। इस विधान में ही हम भविष्य की आधी की सूचना पा सकते हैं। किसी भी सस्या के विधान में जब परिवर्तन होता है, तो वह किसी कारण से होता है, इस बार क्या कारण था यह स्पष्ट है। नरम दल बाने कांग्रेस को विधान से इस प्रकार बाध रहे थे कि वह उनके हाथ से निकल न जाए।

गरम दल अर्द्ध-रहस्यवादी तथा अर्द्ध धार्मिक — कांग्रेस में इस प्रकार गरम दल तथा नरम दल दो भाग हो जाने से ब्रिटिश सरकार को उड़ा फायदा पहुंचा। उसके लिए अब यह अमान हो गया कि उग्र विचार वालों को न्याय तथा उनका दमन करे। यह न समझा जाए कि उन दिनों के उग्र विचार वाले सब बगहीन समाज के ही उपासक थे। उनमें से अधिकांश तो यह जानते ही नहीं थे कि वे क्या चाहते हैं वे अर्द्ध धार्मिक अर्द्ध रहस्यवादी शब्दावली का प्रयोग करते थे, और वस्तुवाद से दूर थे।

अरबिंद इन दिनों के प्रधान गरम नेताओं में से थे। वह राजनीतिक विषयों को ऐसे धार्मिक शब्दों में कहने थे कि उनका मतलब ही नहीं निकलता था। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना तथा ऐश्वर्य की ईश्वर से उद्भूत एक धर्म करार दिया। वह बोले "राष्ट्रीयता को कोई रोक नहीं सकता क्योंकि ईश्वर ने ही इसे नियंत्रित किया है। केवल राष्ट्रीय काम कर, राष्ट्रीय शिक्षा प्रवर्तित कर या वायकाट का कार्यक्रम अपना कर इस देश का उद्धार संभव नहीं है। स्वदेशी से कुछ आर्थिक लाभ हो सकता है, पर इसकी तड़क भड़क में मूलकर और इसको अपनाने में असली उद्देश्य के नष्ट हो जाने की संभावना बहुत अधिक है। दृश्यमान शक्तियों से स्वदेश की शक्तिया दूसरी तरह की हैं। देशमाता की शक्ति अपनी है। इसकी पुष्टि के लिए न तुम्हारी जरूरत है, न मेरी, दूसरे किसी की आवश्यकता नहीं है।"

विपिनचंद्र के विचार — अरबिंद की तुलना में विपिनचंद्र पाल और तिलक के पर जमीन पर अधिक थे। विपिनचंद्र ने कहा, "कोई किसी को स्वराज्य नहीं दे सकता। यदि आज अंग्रेज मुझमें कहे कि स्वराज्य ले लो, तो मैं उसे ठुकरा दूंगा, क्योंकि जिस चीज को मैं स्वयं उपाजित नहीं कर सकता, उसको मैं लेने का अधिकारी भी नहीं हूँ। हम

अपनी सारी शक्ति को इस तरह में लगाए, जिसमें विरोधी शक्ति को अपने मन पर सब से। विलायती माल के प्रायः आठ भाग सक्रिय विरोध अवस्था (Passive Resistance) तक हमारा अस्त्र है। हम रचनात्मक कार्य भी करेंगे। हम दश भर में गरवारी शासन व्यवस्था की तरह व्यवस्था भी सार दश में प्रतिष्ठित करेंगे।”

यह द्रष्टव्य है कि विपिन बाबू के रसायन में सक्रिय अवस्था तथा गमना सरकार सम्बन्धी विचार भी मौजूद हैं।

तत्काल के विचार—नरम के सम्बन्ध में राजभाष्य तत्काल के विचार और स्पष्ट थे। वह लोकतन्त्र चाहते थे परन्तु सके तो ब्रिटिश शासन के अन्त हो रहता उनका ध्येय था। बाद की लोकभाष्य के विचार उग्रतर हुए, परन्तु तब उस समय का जिक्र रहा है। नरम ललाचा के विचारों के सम्बन्ध में हम पहले ही बातें चुके हैं। गरम नलाचा के विचार अस्पष्ट और शब्दालस समर्थित होने पर भी, उनमें और नरम नलाचा के विचारों में बहुत फरक था।

पञ्जाब में दमन—नरम और गरम दलयाला के इस विरोध से सरकार न पाया उठाया। और उग्र विचार ने पत्रों का दमन तथा नेताओं की गिरफ्तारी शुरू की। पञ्जाब के ‘इंडियन तथा पञ्जाबी नामा पत्रों के सम्पादक और प्रकाशक जेल भेज दिए गए। लाला लाजपत राम पञ्जाब के सर्वप्रधान नेता थे। उन दिनों सरकार ने लगान बढ़ाया था। लालाजी इसके विरुद्ध आन्दोलन कर रहे थे, कम वह 9 मई 1907 को 1818 के रेगुलेशन 3 में नजरबन्द कर माण्डले भेज दिए गए।

बंगाल में दमनचक्र—बंगला ‘युगांतर’ के संपादक भूपेन्द्रनाथ दत्त तथा उनके मुद्रक पकड़े गए। मिस्टर किंग्सफोर्ड की अदालत में मुकदमा था। उन्होंने 20 जुलाई को दत्त को एक साल की तथा मुद्रक को दो साल की सजा दी। संपादक को कम तथा मुद्रक को अधिक सजा देने में सरकार का उद्देश्य यह था कि मुद्रक भड़क जाए तो अखबार छपना मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार भूपेन्द्रनाथ दत्त का सजा देने पर लागू दमन बजाय और भी उभड़े। कलकत्ते की स्त्रियां ने भूपेन्द्र की माता को एक विराट सभा में अभिनन्दित किया।

‘बंदे मातरम और ‘संध्या पर प्रहार—युगांतर के अतिरिक्त ‘बन्धे मातरम और ब्रह्मा घब उपाध्याय के ‘संध्या’ पत्र पर भी प्रहार हुआ। ‘संध्या’ बहुत दिनों से उग्र राष्ट्रीय विचारों का प्रचार कर रहा था। दोनों पत्रों के सम्पादक, अरविन्द तथा ब्रह्मा बाघव उपाध्याय पकड़े गए।

विपिनचन्द्र पाल की सजा और छात्र प्रदर्शन—अरविन्द पर मुकदमा चलाया गया। इस प्रकार बिना कारण दश के एक महान नेता पर मुकदमा चलाने के लिए तत्काल गंवाहा क्षीम फैला। विशेषकर छात्रों ने मुकदमे के फैसले के प्रति अदालत के सामने प्रदर्शन किया। इस पर छात्रों और पुस्तकवालों में कुछ झगडा हो गया। सुधील सेन नामक छात्र इसी सम्बन्ध में पकड़ा गया। मिस्टर किंग्सफोर्ड ने उसे बेंत की सजा दी। विपिनचन्द्र पाल को छह महीने की सजा दी गई।

अरविन्द रिहा, ब्रह्मा घब जेल में मरे—विपिनचन्द्र पाल को तो अरविन्द के मुकदमे में गवाही न देने पर छह महीने की सजा दी गई, पर अरविन्द मुकदमे में 23 सितम्बर को छुट गए। ब्रह्माघव उपाध्याय ने अदालत के सामने यह कह दिया था कि मैं ईश्वर के आदेश पर जिस स्वराज्य आन्दोलन को चला रहा हूँ उसके लिए मैं सरकार के सामने सफाई देने के लिए तैयार नहीं हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि मैं साम्यी हूँ इस कारण कोई भी सरकार मुझे कद नहीं कर सकती। हुआ भी यही वह दवालात में रहते

समय ही मर गए। ब्रह्मवाधव उपाध्याय ने अदालत से असहयोग किया था। ब्रह्मवाधव की सहायत उसी परम्परा में है जिसमें 1857 के युग में 'प्यामे आजादी' के सपादक बेदार बख्त की सुअर की चर्बी मलबर फासी पर चढ़ाया गया था।

**सिडिशस मोटिंग्स ऐक्ट**—इन अत्याचारों से देश में आंदोलन बढ़ा, घटा नहीं। सक्डो स्थानों पर सभाएं होने लगीं, और सरकार की निंदा की जाने लगी। इन सभाओं में विशेष कर मिस्टर क्रिस्फोर्ड की निंदा की जाती थी क्योंकि सभी राजनीतिक मुकदमों में उसी की अदालत में हुए थे। सरकार ने जब देखा कि सभाओं का रोग बढ़ता जा रहा है (तानाशाही सरकार के लिए यह रोग ही था), तो 1 नवम्बर 1901 को 'सिडिशस मोटिंग्स ऐक्ट' (राजद्रोही सभा कानून) नाम से एक कानून बना दिया गया।

बहना न होगा कि यह कानून नहीं, इसके द्वारा कानून का गला घोट्टा गया था। पर यह कोई नई बात नहीं थी। इससे पहले ही भारत सरकार ने एक आर्डिनेंस निकाल कर पूव बंगाल तथा पंजाब की सभाओं पर रोक लगा दी थी, अब इसी को विस्तृत करके यह नया कानून बना, जिसके अनुसार सारे भारत में सभाओं पर रोक लगा दी गई। इस प्रकार गुप्त समितियों के अलावा कोई माग नहीं रहा।

**नागपुर से सूरत**—जो आधी 1906 में प्रपितामह दादाभाई नौरोजी की सभापति बनाकर किसी तरह रोक दी गई थी, 1907 में वह अधिक वेग के साथ दृष्टिगोचर हुई और भी प्रश्न यानी सभापति के चुनाव के इद गिर्द यह भगडा शुरू हुआ। अब की बार भी गरम लोग लोकमान्य को सभापति बनाना चाहते थे, पर नरम दल के नेता इसके विरुद्ध थे। पहले अधिवेशन नागपुर में होने वाला था, यहाँ लोकमान्य को वोट मिल जाते, इस कारण नागपुर में अधिवेशन स्थल बदल कर सूरत में कर दिया गया। सूरत में नरम दल का जोर था।

नरम नेता इस से अस नहीं—इसी दिनों लाला लाजपत राय छूट कर आ गए। लोकमान्य तिलक ने नरम दल वालों पर वही चाल चलनी चाही जो पिछली साल वे उन पर चले थे। उन्होंने लालाजी का नाम यह समझकर पेश कर दिया कि अपनी कद के कारण वह देश में जनप्रिय हो रहे हैं, नरम दल वाले उनका विरोध थोड़े ही करेंगे। पर नरम दल वाले इस चाल में नहीं आए। वह अपनी टेक पर अड़े रहे। वह प्रसिद्ध विधिवेत्ता और दानी डाक्टर रासबिहारी घोष को सभापति बनाना चाहते थे।

## कांग्रेस का तेईसवा अधिवेशन

इसी वातावरण में कांग्रेस का तेईसवा अधिवेशन सूरत में हुआ। सोलह सौ प्रतिनिधि आए थे। नरम लोगों की बहुसंख्या थी, उनकी संख्या करीब 900 थी। इस प्रकार नरम नेताओं को अपने वोटों पर काफी भरोसा था। नरम दल वाले केवल अपना सभापति चुनकर ही सतुष्ट नहीं रहना चाहते थे, वे गत माल के अधिवेशन में बायकाट आदि का समर्थन करते हुए जो प्रस्ताव पास हुए थे, उन्हें भी बदल कर पास कराने पर तुले हुए थे। गरम दल को नरम दल के इन मासूबों का पता लग गया, इसलिए सूरत पहुंच कर गरम दल ने नरम नेताओं से यह कहा कि यदि वे प्रस्तावों को बदलने का अपना मनसूबा त्याग दें, तो वे उनके सभापति को चुन जाने देंगे। नरम नेताओं की तरफ से गोखले ने यह कहा कि खुले अधिवेशन में क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस सम्बन्ध में वह कुछ नहीं कह सकते।

**अधिवेशन में टुल्लड**—इस पर दोनों दलों में समझौता नहीं हो सका, और दोनों तरफ से घमासान युद्ध की तयारी होने लगी। जब अधिवेशन शुरू हुआ, और स्वागत



समिति के सभापति अभिभाषण के बाद अधिवेशन के सभापति का नाम प्रस्तावित करने के लिए उठे, तो हल्लड मच गया। इस पर उस दिन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। यह 27 दिसम्बर की बात है।

कांग्रेस में हल्लड — 28 दिसम्बर का फिर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। लोकमान्य तिलक ने पहले ही इस बात की चेष्टा की थी कि मामला सुलभ जाए। आज भी उ होने यही चेष्टा की। जिस समय सभापति का जुलूस जा रहा था, उस समय लोकमान्य तिलक का एक रुक्का स्वागत समिति के सभापति श्री त्रिभुवनदास भालवी को दिया गया, जिसमें लोकमान्य ने अनुरोध किया था कि अधिवेशन शुरू होत ही उस सभापति का नाम प्रस्तावित तथा समर्थित हो जाए, तो मैं बैठक स्थगित करने का प्रस्ताव रखूंगा। उ होने इसके में लिखा था कि "मैं फाड़ा मिटान के लिए एक रचनात्मक प्रस्ताव रखना चाहूंगा, मुझे मौका दिया जाए।" यदि लोकमान्य को यह मौका दिया जाता तो फाड़ा निपट जाता, कम से कम फिर लोकमान्य संपूर्ण रूप से वैधानिक ढंग से चलने पर नरम दल वालों ने उनके रुक्के को बिलकुल हजम कर लिया। लोकमान्य ने फिर एक और रुक्का भेजकर उहें याद दिलाया कि मुझे बोलने दिया जाए, पर वहां बोल सुनता था। नरम नेता तो कुछ न सुनने पर तुले हुए थे। तब लोकमान्य उठे, और जाकर बोलने लग। पर अधिवेशन के सभापति उहें बोलने न देने पर तुले थे। इस पर भयंकर हल्लड मचा। उमी हल्लड के समय एक मराठा चप्पल मुरे दनाथ को छूता हुआ फीरोज शाह मेहता को लगा। इस पर तो और भी घमासान मच गया। फिर तो कुमिया भी चली, और छडिया भी फेंकी गई। उस दिन का अधिवेशन इस प्रकार भग हो गया।

अलग क्वेश्चन — इसके बाद नरम प्रतिनिधियों ने अपना अलग क्वेश्चन का अधिवेशन किया। मजे की बात है कि लाला लाजपत राय इस क्वेश्चन में शरीक हुए। इस क्वेश्चन ने एक उप समिति नियुक्त की कि कांग्रेस के लक्ष्य तथा विधान के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट पेश करे। बाद को 1908 के 18 तथा 19 अप्रैल को इसी क्वेश्चन का इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ और उपसमिति की रिपोर्ट मंजूर की गई। इस उप समिति ने क्या विधान बनाया इसके बारे में जाने की आवश्यकता नहीं। इतना ही कह देना यथेष्ट होगा कि वैधानिक उपायों से धीरे धीरे औपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त करना कांग्रेस का लक्ष्य बताया गया, और यह साफ कह दिया गया कि जो इस लक्ष्य तथा साधन को स्वीकार करते हैं वे ही कांग्रेस के प्रतिनिधि हो सकते हैं। इसके बाद से कांग्रेस में बहुत सालों तक केवल नरम दल वाला का बोलवाला रहा।

सूरत में कांग्रेस के अधिवेशन के पहले ही पूर्वी बंगाल के अत्याचारी गवर्नर को दो बार मारने की चेष्टा हुई। इसमें एक बार तो गवर्नर की गाड़ी पटरी से उतर गई और वह बाल बाल बचे। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार इस घटाके से पांच फुट चौड़ा और पांच फुट गहरा गड्ढा हो गया था।

मुजफ्फरपुर हत्याकांड — 30 अप्रैल 1908 को मिस्टर किंग्सफोर्ड के घोड़े में मुजफ्फरपुर में श्रीमती केनेडी तथा कुमारी केनेडी मारी गई। अत्याचारी किंग्सफोर्ड की तनाती इन दोनों मुजफ्फरपुर में थी। उसकी मारने के लिए खुदीराम तथा प्रफुल्ल चारी दो युवक कलकत्ता में आए थे। हमला करने के बाद दोनों युवकों में से एक अर्थात् प्रफुल्ल चारी ने आत्महत्या की, और खुदीराम को 1908 के 11 अगस्त को फांसी हुई। उसके कुछ महीने बाद 1908 के 10 नवम्बर को कहेयालाल को फांसी हुई जिन्होंने जेल के अंदर पिस्तौल मगवाकर मुखबिर को मारा था।

अलीपुर घटयक — इसी के बाद 2 जून को पुलिस को मानिकतला में वम के एक

हारखाने का पना लगा। इनके सम्बन्ध में बारी द्र घोष आदि गिरफ्तार हुए। अरविन्द भी इसी सम्बन्ध में गिरफ्तार हुए। नरेन्द्र गोस्वामी मुखबिर हो गया, पर वह जेल में मारा गया। दोनों को फाँसी हो गई। बाकी लोगों पर जो मुकदमा चला, वह अलीपुर पडयत्र के नाम से मशहूर हुआ। सज्जको कालेपानी की सजा हुई। इस मुकदमे में आशुतोष विश्वास मरकरी वकील थे, वे २४ फरवरी सन् १९०९ को मारे गए। सरकार की ओर से जा डी० एस० पी० यह मुकदमा चला रहा था, वह भी बाद को मारा गया।

**चिदम्बरम पिल्लै को काले पानी**—यह न समझा जाए कि केवल क्रांतिकारियों को लम्बी सजाए दी गई। श्री विपिनचन्द्र पाल जिस समय मद्रास का दौरा करने गए थे, उस समय उनकी अनुप्रेरणा से वहाँ एक राष्ट्रीय दल का संगठन हुआ। श्री चिदम्बरम पिल्लै तथा उनके साथी श्री सुब्रह्मण्य शिव इस दल का बहुत अच्छा प्रचार कर रहे थे। बम १२ मार्च १९०८ को वह घर लिए गए और राजद्रोहात्मक-याख्यान के अपराध में चिदम्बरम को आजम तथा सुब्रह्मण्य को दस साल काले पानी की सजा हुई। यह सजा इतनी अधिक थी कि उन दिनों के भारत सचिव मार्ले ने भी इसके विरुद्ध वायसराय लाड मिंटो को लिखा। मार्ले ने लिखा कि मैं चाहता हूँ कि शांति और सुव्यवस्था कायम रहे, परन्तु इस प्रकार की सजाओं से लोग बम के माग की तरफ बढ़ेंगे न कि पीछे हटेंगे।

**बमन का दौरा**—मार्ले ने यह पत्र १४ जुलाई को लिखा था पर इसके पहले ही भारत सरकार ने अपनी कठपुतली धारासभा में ८ जून को ही विस्फोट तथा समाचार पत्र कानून पार कर लिया था। विस्फोटक कानून के अनुसार विस्फोटक रखने की सजा आजम काले पानी तक हो गई, और समाचार पत्र कानून में अखबार बंद तथा प्रेस जन्म किया जा सकता था। इस कानून के पहले ही बहुत से अखबारों पर रोक लगा कर उन्हें बंद कर दिया गया था। ऐसे पत्रों में 'उर्दू ए मुजल्ला' भी था।

**लोकमान्य को ६ साल सजा**—लोकमान्य तिलक ने खुदीराम के विषय को लेकर 'कैसरी' में कई लेख लिखे। इन निबन्धों में उन्होंने आतंकवाद की निंदा की पर साथ ही सरकारी आतंकवाद को भी जारशाही बहकर बुरा भला कहा था। इसी अपराध में वह २४ जून को गिरफ्तार कर लिए गए, और २२ जुलाई को उन्हें छह साल की सख्त सजा और १००० रुपये जुर्माना सुना दिया गया। लोकमान्य ने इस सजा के जवाब में कहा, "जिस पवित्र काय को मिट्टी करने का मैंने प्रयत्न किया है उसके हक में कुछ उठाना अच्छा ही रहेगा। चायद ईश्वर की यही इच्छा है।" इस कठोर उद्गार से देश भर में तहलका मच गया।

**पत्रों पर प्रहार तथा नेता नजरबन्द**—पर इससे उग्रद्वरकने के बजाय घटते ही गए। [१] चिदम्बरम की सरकार ने त्रिनिमल ला में कुछ सशोधन किए। स्पष्टतः इनका उद्देश्य क्रांतिकारियों का दमन था। इन सशोधनों के द्वारा अब सरकार को यह अधिकार हुआ कि वह किसी भी सस्या को केवल सन्देह पर गैर-कानूनी करार दे सकती है। सरकार ने फौरन इस कानून का फाँदा उठाकर जरीसाल की स्वदेश-बाधक समिति, दाका की अनुशीलन समिति, ममनसिंह की सुहृद समिति तथा इस प्रकार की अन्य बहुत-सी समितियाँ को गैर-कानूनी घोषित कर दिया। अकेली अनुशीलन समिति की ही डाके में ५०० छात्राएँ थीं। सरकार इतनी घबड़ाई हुई थी कि मवा समितियों पर भी उसे सन्देह हुआ, और उनकी निगरानी होने लगी। इसके अनिश्चित सरकार ने बंगाल के नौ मुख्य नेताओं को नजरबन्द कर लिया।

**क्रांतिकारियों के जेलों में जनता से**—वगान में इस प्रकार खुली सस्याओं के दमन तथा गताओं का गिरफ्तारी का नीतिगत यत्न हुआ कि गुप्त समितियों का उन्मूलन हुआ तथा

देश क्रान्तिवाद की ओर बढ़ा। बंगाल के क्रान्तिवाद की नींव ऐसी बहुत सी सस्थाओं पर थी, जो खुली तथा कानूनी रहते समय जनता के अदर तक बँठी हुई थी, इसी कारण उन सरकारी दमन से दबाया न जा सका। जिस समय राष्ट्रीय शक्तियों पर इस प्रकार साम्राज्यवाद का प्रहार हो चुका था, और लोकमान्य तिलक, अश्विनीकुमार दत्त आदि नेता सीखचो के अदर बढ़ हो चुके थे, उस समय चाहिए तो यह था कि बची-खची राष्ट्रीय शक्तियाँ संयुक्त मोर्चा बनाकर साम्राज्यवाद का मुकाबला करती, पर ऐसा नहीं हुआ। गरम दल का हाथ आगे बढ़ा हुआ था ही, पर नरम दल के नेता शायद और रुक गए, और वे किसी भी प्रकार एकता के लिए तैयार नहीं थे।

## कांग्रेस का चौबीसवा अधिवेशन

1908 में मद्रास में डाक्टर रासबिहारी घोष के ही सभापतित्व में विभक्त कांग्रेस का 24 वा अधिवेशन हुआ। डाक्टर घोष शायद फिर से सभापति इस कारण बनाए गए कि वह सूरत में डग से सभापतित्व कर ही नहीं पाए थे। डाक्टर घोष ने सरकारी दमन नीति की निंदा की, साथ ही गरम दल की भी निंदा की।

महाराष्ट्र में दमन—सरकार की तरफ से शासन सुधार देने की तयारी थी, पर उधर दमन भी जोरों पर था। 9 जून 1909 को गणेश दामोदर सावरकर को 'तप अभिनव भारत मेला' नामक कविता पुस्तक के कारण आजम काले पानी की सजा दी गई। कविनाओं के कारण इतनी सजा 'सरकार बिलकुल पागल हो रही थी, पर वह कविता पुस्तक तो एक बहाना मान था। सरकार किसी और ही कारण से नाराज थी।

संस्कृत के महान विद्वान श्यामजी कृष्ण वर्मा गडबड देखकर उन्हीं दिनों सन चले गए थे और बहुत दिनों तक चुप रहे। 1905 से वह फिर से इंडिया हामरूल सोसाइटी बनाकर इंग्लैंड में काम करते रहे। वह 'इंडियन सोशियलिजिस्ट' नामक पत्र का संपादन भी करते रहे। वह विशेषकर भारत से पढ़ने के लिए आए हुए छात्रों में काम करते रहे। जब विनायक सावरकर पढ़ने गए, तो वह भी उनका प्रभाव में आए। सावरकर बहुत भारत मेला तथा अभिनव भारत सोसाइटी के पहले से ही सस्थापक थे। सरकार ने इन्हीं सब बातों के लिए गणेश सावरकर पर यह बदला लिया।

धींगरा को फाँसी, विनायक को काला पानी - उधर मदनलाल धींगरा ने 909 की पहली जुलाई को सर वजन वाइली नामक एक अंग्रेज को गाली मार दी। सर वाइली भारतीय छात्रों पर खुफिया का काम करते थे। धींगरा को फाँसी हुई जिसे उ होने बड़ी बहादुरी से ग्रहण किया। विनायक के दल ने नासिक के मजिस्ट्रेट जबरन की भी हत्या की, इस पर विनायक पकड़ कर लंदन से लाए गए, रास्ते में वह जहाज से कूदकर फ्रांस की भूमि में पहुँच गए थे, पर पकड़कर फिर अंग्रेजों के सुपुर्द कर दिए गए। भारत में उन पर मुकदमा चला और उन्हें भी आजम कालापानी दे दिया गया।

## कांग्रेस का पच्चीसवा अधिवेशन

1909 में कांग्रेस का पच्चीसवा अधिवेशन ५० मदनमोहन मालवीय के सभापतित्व में लाहौर में हुआ। इस बार केवल 250 प्रतिनिधि आए। पंडित जी ने शासन सुधार की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह यथेष्ट नहीं है। उ होने अपने भाषण से उपस्थित लोगों पर जादू सा डाल दिया। सैयद हसन इमाम ने साम्प्रदायिक निर्वाचन की निंदा करते हुए कहा कि यह देश के लिए घातक सिद्ध होगा। कांग्रेस ने शासन सुधार

की निन्दा करते हुए चार प्रस्ताव पास किए। इसमें विशेषकर साम्प्रदायिक निर्वाचन तथा मुसलमान वोटरो के साथ अ-वायपूर्ण पक्षपात की निन्दा की गई। साफ कह दिया गया कि सरकार की बहुरूपता होने के कारण यह सारा शासन सुधार तथा उसकी धारा-सभाएं निक्कली हैं। यह तय हुआ कि बग भग के सम्बन्ध में जनता को कितना क्षोभ है, इसको बताने के लिए श्री सुरेन्द्रनाथ तथा भूपेन्द्रनाथ बसु विलायन जाएं और वहां जाकर जनमत जागत करें। कहना न होगा कि देश को जिस बलिष्ठ नेतृत्व की आवश्यकता थी, उसकी पूर्ति नहीं हो सकी। उधर बंगाल में बराबर क्रांतिकारियों का काय जारी रहा। पुलिस भी नए-नए पडयंत्र चलाने लगी।

**माले मि टो शासन सुधार—** इसी साल माले मि टो शासन सुधार कानून दिया गया। इसमें संदेह नहीं कि यह पहला शासन सुधार था, जिसमें चुनाव का सिद्धांत किसी हद तक माना गया था। पर किसी भी क्षेत्र में चुने हुए सदस्यों की संख्या अधिक नहीं थी। भारतीय धारासभा के 68 सदस्यों में 36 सरकारी थे। इसी प्रकार सब प्रांतीय धारासभाओं के सम्बन्ध में नियम बना। वोटर चार हिस्सों में बांटे गए थे—

(1) साधारण, (2) जमींदार, (3) मुसलमान और (4) विशेष स्वायत्त। जमींदार और विशेष स्वायत्त के क्षेत्रों में हिंदू वोटर में फर्क रक्खा गया। यदि एक मुसलमान 750 रुपये मालगुजारी देता, तो वह वोटर हो जाता था, पर एक हिंदू को यह अधिकार तभी मिलता था वह 7000 रुपये देता। इसके अतिरिक्त एक मुसलमान आयकर देते ही वोटर हो जाता था, पर एक हिंदू केवल इतने से ही वोटर नहीं हो सकता था। इस प्रकार हिंदू मुसलमान झगड़े को बढ़ाने का सब तरह से उपाय किया गया। इस सबंध में द्रष्टव्य यह है कि भारत सचिव माले पृथक् निर्वाचन के विरोधी थे, पर भारत की ब्रिटिश नौकरशाही उसके पक्ष में थी। इन्हीं लोगों ने साम्प्रदायिकतावादी पड़े-लिखे मुसलमानों को भड़काया कि वे पृथक् निर्वाचन की मांग पेश करते रहे।

**नेताओं की असमर्थता —** 25 दिसम्बर 1910 को नया शासन सुधार लागू हुआ। इसमें आश्चर्य नहीं कि कांग्रेस के नरम नेताओं ने भी इसे पसंद नहीं किया, पर इसे पसंद न करने पर भी वे और किसी तरीके के सम्बन्ध में सोच नहीं सकते थे। उनके पास बस एक ही अस्त्र था, भिक्षापात्र और वे भिक्षामय के असीम धैर्य से लैस थे।

इसी प्रकार 1911 की 9 फरवरी को नज़रबंद रिहा कर दिए गए, पर साथ ही सरकार ने उसी दिन सवादपत्रों का गला घोटने के लिए एक प्रेस कानून लागू कर दिया। अब छापाखाना खोलने के लिए 500 रुपये से 2000 रुपये तक की जमानत जरूरी हुई। आपत्तिजनक सामग्री छापने पर 1000 रुपये से 10000 रुपये जुर्माना था। फिर छापाखाने की जब्ती की भी व्यवस्था की गई। इस प्रकार यह स्पष्ट कर दिया गया कि शासन सुधार मजाक माना था।

## कांग्रेस का छब्बीसवा अधिवेशन

कांग्रेस का छब्बीसवा अधिवेशन 1910 में इलाहाबाद में सर विलियम वेडर-बन का अध्यक्षता में हुआ। वेडरबन ने चेष्टा की कि गरम तथा नरम दल में संधि हो जाए, पर वह सफल नहीं हुए। इस अधिवेशन में भी माले मि टो सुधार की आलोचना हुई। प्रेस कानून की निन्दा की गई। बाद के इतिहास की दृष्टि से इस कांग्रेस की सबसे बड़ी घटना यह है कि इन्हीं दिनों जिला बोर्ड, नगरपालिका आदि स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्थाओं में भी साम्प्रदायिक निर्वाचन की बातचीत जारी थी, बाद के लीगी नेता मुहम्मद अली जिन्ना ने एन प्रस्ताव में यह बताया कि ऐसा करना घातक होगा।

**दिल्ली दरबार—बग भग रह—**1911 के 12 दिसम्बर को दिल्ली में एक दरबार हुआ। इसमें सम्राट् जाज पचम तथा मन्नाजी मेरी आई थी। सम्राट् ने बग भग का रह कर दिया पर साथ ही राजधानी उलबत्ते से हटाकर दिल्ली में लाने की घोषणा की गई। इस प्रकार बग भग आंदोलन का लक्ष्य तो प्राप्त हो गया, पर इस कारण यह आंदोलन जिसका सूत्रपात इसी बात का लेकर हुआ था नहीं रहा। अब तो वह आंदोलन स्वतंत्रता के लिए आंदोलन में परिणत हो चुका था।

### कांग्रेस का सत्ताईसवा अधिवेशन

1911 में कांग्रेस का सत्ताईसवा अधिवेशन कलकत्ते में हुआ। इस बार मिस्टर रैमजे मन्डोनल्ड सभापति होने वाले थे, पर उनकी पत्नी का देहांत हो गया, इस कारण वह न आ सके। इसलिए लखनऊ के श्री विशन नारायण रं सभापति हुए। दरसाहब ने अपने भाषण में कहा कि अब भारत में बाड़े में सन्तुष्ट हो जाने वाली की जरूरत नहीं है, हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो देश के काम की धुन में अपने को भूल जाए। उन्होंने बहुत धीरे चरने के विरुद्ध चेतावनी देते हुए कहा कि इसमें खतरा यह है कि लोग कायर हो जाएंगे। श्री दर विचारों से मध्यममार्गी थे। इस कांग्रेस में भी यमारीति दमन का प्रतिवाद किया गया, और शासन मुद्धार पर प्रस्ताव पास हुए।

**लाहौर हाडिंग पर बम—**दिल्ली में राजधानी को जिन कारणों से लाया गया था उनमें से एक यह भी था कि राजधानी को बगल से हटाया जाए क्योंकि बंगाल शान्ति कार्यों का बाध था। पर दिल्ली में आए अभी साल भर मुश्किल में गुजरा था कि वहां रोग बहा भी दिखाई पड़ने लगा। 23 दिसम्बर 1912 को लाहौर हाडिंग राजाओं के ठाठ से हाथी पर जुलूस में जा रहे थे कि उन पर बम गिरा। हाडिंग बाल बाल बच गए, पर उनका अंगरक्षक मारा गया। हाडिंग मूर्छित भर हुए। बम फेंकने वाले पकड़े न जा सके। बाद को कुछ सुराग लगा, और दिल्ली पड़्यत्र चला। मास्टर अमीरचन्द, अवधबिहारी, बालमुकुन्द तथा बसन्तकुमार को फांसी हुई, पर इनके नेता रामबिहारी पुलिस का हाथ नहीं लगें और अन्त तक फरार रहे। यम बसन्तकुमार ने फेंका था। रामबिहारी जापान चले गए।

### कांग्रेस का अट्ठाईसवा अधिवेशन

1912 में कांग्रेस का अट्ठाईसवा अधिवेशन श्री आर० एन० मुधोलकर के सभापतित्व में बाकीपुर में हुआ। इस कांग्रेस की स्वागत समिति के अध्यक्ष मजहूरूल हक थे। उन्होंने अपने भाषण में बलकान युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नीति की निन्दा की। उन निन्दा भारतीय मुसलमानों में इस कारण बड़ा सोभ फला हुआ था। इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ था कि हिंदू मुसलमानों में जो वैमनस्य पैदा किया गया था अब धारा उसके विरुद्ध जाने लगी।

**अफ्रीका में सत्याग्रह—**दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों पर जो अत्याचार हो रहे थे, उनकी निन्दा करते हुए कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया। इस बीच श्री गोखले बहा आए थे। उन्होंने अपने निजी तजुर्खे से बतलाया कि वहां भारतीयों की कितनी घोर दुदशा है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय वहां जेल भी जा चुके थे और तरह-तरह की तकलीफें उठा चुके थे।

1912 में लीग—1912 में लीग की बैठक ढाका में हुई। नवाब सलीमुल्ला खा सभापति थे। नवाब साहब ने अपने भाषण में हिंदुओं की शारिशो और सरकार की

बेमुद्वित्तिया का बड़े जोरदार शब्दों में चित्र खींचा। सरकार को बेमुद्वित्त इस कारण कहा गया कि लोग ने बग भग का समर्थन किया था, पर उसमें जिना पूछे ही सरकार ने बग भग रद्द कर दिया।

## कांग्रेस का उनतीसवा अधिवेशन

1913 में कांग्रेस का उनतीसवा अधिवेशन नवाब सैयद मुहम्मद बहादुर की अध्यक्षता में कराची में हुआ। उन्होंने अपने अभिभाषण में हिंदू तथा मुसलमानों को एक होने के लिए कहा, क्योंकि इसीमें सबकी भलाई थी। सीतारमैया ने तो यहां तक लिखा है कि नवाब बहादुर ने इस अवसर पर जो बीज बोये, वे ही बाद को जाकर लखनऊ पैकट में पल्लवित हुए।

गदर पार्टी — ज्ञानिकारी आंदोलन का वह अध्याय बहुत गौरवशाली रहा, जब अमेरिका आदि देशों में अधिक मजदूरों के शोभ और लाभ की दृष्टि से गए हुए, राजनीति में सम्पूर्ण रूप से असम्भवत भारतीय विरोधक पंजाबी सिक्ख और हिंदू एकाएक राजनीति की मुख्य धारा में छलांग लगा गए। यह द्रष्टव्य है कि इन सीधे साधे लोगों ने अमेरिका में गदर पार्टी का निर्माण किया, जिसमें वह बहुत सरल ढंग से धमनिरपक्षता की मजिल तक पहुंच गए। उनमें कोई विद्वान नहीं था, पर वे थे ईमानदार। 1913 में प्रथम महायुद्ध के काल बादल मड़राने लगे थे। इसी समय गदर पार्टी की स्थापना हुई। सोहन सिंह भक्ना, गुरुमुखमित्र, रूद्रसिंह कासीराम आदि दल के नेता थे। लाला हरन्याल ने इसमें भाग लिया। विद्वान और अच्छे वक्ता होने के कारण वह बहुत उपयोगी सिद्ध हुए। गदर पार्टी के 8000 आत्मा भारत में श्रान्ति करने आए थे। उनका प्रयास सफल नहीं हुआ, पर गद्दीदा और बीरो के रूप में वे जो घाती छोड़ गए, वह अनाखी रही।

कोमागाटा मार्ग — बाद को पूर्व एशिया के विख्यात सिख धनी बाबा गुरदित्त सिंह ने कोमागाटा मार्ग नामक एक जहाज को किराये पर ले लिया, और भारतीय सिख तथा मुसलमान यात्रियों को लेकर सीधा कनाडा पहुंचे। यह 23 मई 1914 की बात है। कनाडा की सरकार ने यात्रियों को उतरने नहीं दिया। तब दो महीना कनाडा के समुद्र तट पर पड़े रहने के बाद यह जहाज वापस हुआ, और 19 सितम्बर को बजबज पहुंचा। इस बीच यात्रियों की वायापलट हो चुकी थी। अमेरिका की गदर पार्टी के प्रचार कार्य के कारण जहाज में लोग श्रान्तिकारी हो चुके थे। हर बदरगाह पर कुछ श्रान्तिकारी चपल गए। सब चाहने लगे कि देश में लौटकर श्रान्ति करें। बजबज में जब ये यात्री उतरे तो पुलिस ने उनकी तलाशी लेनी चाही। यात्रियों में कुछ सशस्त्र थे। इस पर लड़ाई हो गई जिसमें कई व्यक्ति मारे गए। बाबा गुरदित्त सिंह तथा 28 अन्य यात्री पुलिस को चरमा देकर भाग गए। बाबाजी सात साल तक फगर रहे और असहयोग के युग में उन्होंने पुलिस को आत्ममर्षण कर दिया।

## प्रथम महायुद्ध के दौरान

यूरोप में सड़ाई के बादल बहुत जल्दी से छा रहे थे। यद्यपि जर्मन पूँजीवाद का क्षेत्र में देर से उतरा था, पर उन्नीसवीं सदी के अंत तक वह सबसे ज्यादा विकसित ब्रिटिश पूँजीवाद के साथ एक कतार में आ चुका था और बीसवीं सदी के प्रारम्भ में यंत्रनिर्माण आदि सबसे उन्नत उद्योग क्षेत्रों में भी ब्रिटिश पूँजीवाद को परास्त कर चुका था। अब वह अपने में इतनी शक्ति का अनुभव कर रहा था कि उसने सीधे महात्मा रक्षणा शुरू कर दिया कि दूसरों की तरह उसके पास भी उपनिवेश होने चाहिए साथ ही वह नौसेना तथा युद्धपोतों के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने लगा। यह तनातना बढ़ गई, और पहली बार 1905 में फिर 1911 में लड़ाई के आसार बने। उस समय इस पर बाध पालिया गया, परंतु जुलाई 1914 में लड़ाई छिड़ ही गई। ऑस्ट्रिया-हंगरी के युवराज फर्डिनेंड का सरायिवो में मारा जाना तो एक उपलक्ष्य मात्र था असली कारण पुराने और गहरे थे।

### कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन

एसी वातावरण में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1914 में मद्रास में श्री भूपेन्द्र नाथ बसु के सभापतित्व में हुआ। उन्होंने पुराने दंग के व्याख्यान में यह कहा कि सरकार को चाहिए कि भारतीयों को औपनिवेशिक स्वराज्य दे। आवश्यक है कि महायुद्ध छिड़ जाने पर भी कांग्रेस के गरम नेताओं ने कोई नया नारा नहीं दिया, यहाँ तक कि उन्हें एकता की जरूरत भी नहीं महसूस हुई।

नेता परिस्थिति के अयोग्य — कांग्रेस के गरम तथा गरम दोनों तरह के नेताओं ने महायुद्ध के छिड़ने से अजीब शयित्य दिखलाया। पुराने वक्ताओं में चाहे जो कुछ हुआ हो, पर इस समय इन दोनों दलों में कोई विशेष फर्क नहीं रह गया था। अब चीजें बहुत कुछ व्यक्तिगत हो चली थी और उनमें कोई तत्व नहीं रहा था। परंतु देश में तथा देश के बाहर देशभक्तों का एक गिरोह था जो समझता था कि इस समय ब्रिटेन मुसीबत में फंसा हुआ है इसलिए इसी समय उस पर हमला बोल दिया जाना चाहिए। ये लोग भारत के नातिकारी थे।

नातिकारियों का कार्यक्रम — प्रस्तुत इतिहास में हम केवल सक्षम में इतना ही बता सकते हैं कि इन नातिकारियों ने किन तरीकों से काम किया। उन्होंने देश भर में गुप्त समितियाँ कायम करने की चेष्टा की, अस्त्र सस्त्रों का संग्रह किया वगैरह के कारखाने खोले, सेना के साथ सम्बंध कायम किया, चंदा तथा इकतियों के द्वारा धन संग्रह किया, विदेशों में जाकर ब्रिटेन के शत्रु राष्ट्रों से सम्बंध कायम किया, नातिकारी साहित्य बाँटा — यानी सभी संभव तरीकों से नाति की तयारी की।

रजनी पामदत्त जैसे व्यक्ति भले ही यह कहे कि इनका प्रयत्न बहुत छोटा था,

पर इसका इतिहास सिड्मिशन कमेटी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। कमे इसी रिपोर्ट से रोलट विधेयक और रोलट विधेयक से असहयोग उत्पन्न हुआ, यह बाद को बताया जाया।

## कांग्रेस का इकत्तीसवा अधिवेशन

1916 में श्री गोखले तथा श्री फीरोजशाह मेहता का देहाल हो गया। इस साल इसी वातावरण में कांग्रेस का इकत्तीसवा अधिवेशन श्री सत्येन्द्रप्रसाद सिंह की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ। अपने व्याख्यान में उन्होंने बतलाया कि भारतवर्ष एक ऐसे रोगी की भाँति है जिसके टूटे हुए अंग प्रत्यग स्प्लिट में बंधे हुए हैं। दूसरे शब्दों में, उन्होंने अभी भारत को स्वराज्य तथा स्वावलम्बन के अयोग्य माना। अवश्य उन्होंने साथ ही में अब्राहम लिंक्न का Government of the people, for the people and by the people—यानी 'जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार' का नारा भी दिया। पर यह शब्द मात्र थे इसमें सदेह नहीं। आश्चर्य नहीं कि श्री सिंह बाद को बिल्कुल निष्क्रिय हो गए। बाद को यह सज्जन लाड बनाकर बिहार उड़ोसा के लाट भी बनाए गए।

**बंबई कांग्रेस के प्रस्ताव**—बंबई कांग्रेस में 2259 प्रतिनिधि आए थे। एक प्रस्ताव में राजभक्ति तथा अर्थ प्रस्तावों में ब्रिटेन के युद्धोद्देश्यों में श्रद्धा प्रकट की गई। ब्रिटेन की नौ सत्ता ने इस बीच जो साहसपूर्ण कार्य किए थे, उनकी सराहना की गई। एक प्रस्ताव में लाड हाडिंग के संबंध में सरकार से यह प्रार्थना की गई कि उनके कार्य सराय होने का समय बढ़ा दिया जाय। कनाडा और दक्षिण अफ्रीका के भारतीय विरोधी कानूनों की निंदा की गई। शासन सुधार की मांग की गई। बीसवें प्रस्ताव में सरकार से कहा गया कि सब प्रांतों में इम्तमरारी बंदोबस्त या कम से कम 10 साल के लिए बंदोबस्त हो।

**लीग और कांग्रेस**—इस बार बम्बई में ही लीग का भी अधिवेशन हुआ था। इससे लीग और कांग्रेस में सदभाव का मौका उत्पन्न हुआ। कांग्रेस के सभापति तथा प्रतिनिधि अपना सद्भाव व्यक्त करने के लिए लीग के अधिवेशन में पहुँचे और वहाँ इनका यथायोग्य स्वागत हुआ। कांग्रेस ने अपने उन्नीसवें प्रस्ताव में शासन-सुधार की मांग करते हुए यह कहा कि मुस्लिम लीग के नेताओं के परामर्श से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एक शासन सुधार की योजना तथा शिक्षात्मक और प्रचारात्मक कार्यक्रम की योजना बनाए। इस बीच लीग ने अपने उद्देश्यों में कुछ परिवर्तन किया था, और अब ब्रिटेन के अधीन आत्मशासन प्राप्त करना उसके उद्देश्यों में शामिल हो गया था, यद्यपि मुसलमानों में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति राजभक्ति का प्रचार अब भी उसके उद्देश्यों में था। यूनो तो इस अधिवेशन में भी कांग्रेस ने पहले ही प्रस्ताव में राजभक्ति व्यक्त की थी। इस प्रकार लीग और कांग्रेस में मेल का रास्ता खुल गया था।

**गांधीजी चुनाव हारे**—इस समय तक गांधीजी भारत जा चुके थे और यहाँ की राजनीति में प्रविष्ट होने के लिए कांग्रेस को ही उन्होंने चुना था। परंतु बाद के इतिहास की दृष्टि से यह एक बहुत ही दिलचस्प घात है कि गांधीजी 1915 की कांग्रेस की विषय निर्धारिणी समिति में चुने नहीं जा सके, इस कारण सभापति श्री सिंह ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके उन्हें इस समिति में नामित किया। इतिहास भी क्या-क्या परिहास करता है इसका यह एक उदाहरण है।

**विधान में परिवर्तन**—इस अधिवेशन में कांग्रेस के विधान में कुछ परिवर्तन



किया गया। जब यह नियम हो गया कि कोई भी संस्था जो दो साल से या उससे अधिक समय की है कांग्रेस के लिए प्रतिनिधि चुन सकती है, बशर्ते वह कांग्रेस के उद्देश्यों को मानती हो। इस परिवर्तन से गरम दल का कांग्रेस में लौटना आसान हो गया। संभव है गोखले तथा फीरोजशाह की मृत्यु से गरम दलवाले अपने को कुछ कमजोर भी पा रहे हों, इस कारण वे कांग्रेस की जिम्मेदारी दूसरों के साथ बंटाने की तैयार हो गए।

**तिलक का कार्यक्रम**—लोकमान्य तिलक समझते थे कि इस समय देश की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल इंग्लैंड भेजा जाय, तो अच्छा रहे। पर वह कांग्रेस के नेताओं को इस अवधि में राजी नहीं कर सके। अभी कांग्रेस में उनका स्थान नहीं था। हाँ, ग्रे विधान के अनुसार अगले साल वह कांग्रेस में जा सकते थे। इस बीच उन्होंने अग्रिम होमरूल लीग का संगठन किया जिसकी बहुत जल्द घूम मच गई। इसका तत्वावधान में तिलक तथा उनका साथिया की विचारधारा का प्रचार होने लगा। यद्यपि लोकमान्य पहले के मुकाबिले में गरम पड़ चुके थे, फिर भी वह जनसम्पर्क में विश्वास करते थे। उनकी राजनीति केवल भिक्षापात्र की नहीं थी, यद्यपि उसमें भिक्षापात्र का पर्याप्त स्थान था।

**श्रीमती बेसेंट**—इस बीच श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राजनीति में आ चली थी। श्रेष्ठ विदुषी होने के अलावा वह ऊँचे दर्जे की वक्ता थी। वह मियोसोफी आन्दोलन की नेत्री थी। काशी के डा० भगवानदास उनके प्रमुख साथी थे। यद्यपि एनी बेसेंट अग्रज थी, पर भारतवर्ष को अपना दश समझती थी। वह चाहती थी कि भारतवर्ष को होमरूल दिया जाय इस उद्देश्य के प्रचार के लिए श्रीमती बेसेंट ने 1914 के 2 जून को ही 'कामनवेल' नाम से एक साप्ताहिक तथा 14 जुलाई से 'यू इंडिया' नामक पत्र प्रकाशित किया। वह चाहती थी कि औपनिवेशिक स्वराज्य के ढाँचे पर भारतवर्ष में होमरूल मिले। उन्होंने भी 1916 के सितम्बर में होमरूल लीग की स्थापना की।

**ब्रिटिश सरकार का प्रहार**—ब्रिटिश सरकार का न तो तिलक का कार्यक्रम पसंद था, न बेसेंट का। स्मरण रहे कि दोनों साम्राज्य के अंतर्गत औपनिवेशिक स्वराज्य के ही समर्थक थे, फिर भी सरकार को ये पसंद इसलिए नहीं थे कि सभाओं तथा लखों के द्वारा ये जनता तक पहुँच रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने लडाई के बहाने 8 मार्च 1915 को 'डिफेंस ऑफ इंडिया ऐक्ट' बना लिया था। इस कानून में 'इंडिया' शब्द फिजूल में ही था। यह कानून साम्राज्यवाद की रक्षा के लिए था, न कि भारत की रक्षा के लिए। मुहम्मद अली शौकत अली, अबुलकलाम आजाद तथा सैकड़ों की तादाद में क्रांतिकारी इस ऐक्ट में नजरबंद हो चुके थे। मुहम्मद अली द्वारा सम्पादित कामरेड पत्र भी बंद कर दिया गया था। अब 26 मई 1916 को श्रीमती बेसेंट द्वारा सम्पादित 'यू इंडिया' से दो हजार की जमानत मांगी गई। इस पर भी जब 'यू इंडिया' ने अपना लहजा नहीं बदला तो 28 अगस्त को यह रकम जस्त कर ली गई। लोकमान्य पर सरकार ने इससे भी भड़ा हमला किया, और उनसे एक माथूली बदमाश की तरह 40 हजार रुपये की जमानत और मुचलका माँगा गया कि वह नकबलन रहेगे। खरियत यह रही कि बम्बई हाईकोर्ट ने इस हुक्म को मसूख कर दिया। स्मरण रहे ये सारी जद्दोजेहद कांग्रेस के बाहर हो रही थी।

**सम्मिलित योजना**—बम्बई कांग्रेस में लीग के साथ मिलकर जिस शासन-सुधार की योजना बनाना तय हुआ था वह 17 नवम्बर 1916 तक बन गई। अक्टूबर महीने में ही इसका खाका बड़े लाट की कौंसिल के 19 चुने हुए सदस्यों के दस्तखत से सरकार के सामने पेश हो चुका था। इसमें यह कहा गया था कि युद्ध के बाद भारतवर्ष को इस आधार पर जिम्मेदार शासन दिया जाय।

## कांग्रेस का वत्तीसवा अधिवेशन

1916 में ससनऊ में कांग्रेस का जो बत्तीसवा अधिवेशन श्री अम्बिकाचरण मजूमदार के सभापतित्व में हुआ, वह बहुत महत्त्वपूर्ण रहा। सूरत में गरम दल तथा नरम दल में जो बिछोह हुआ था, वह अब जाकर मिलन में परिणत हुआ। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात थी कि कांग्रेसी और मुसलमान नेता एक दिखाई दे रहे थे। गांधीजी अब भारतवर्ष में बस गए थे, और इस कांग्रेस में वह मौजूद थे। इस बार भी गांधीजी को विषय निर्धारिणी समिति में जाने में दिक्कत पड़ती, पर लोकमान्य की बुद्धिमानी से वह आ गए। अभी तक गांधीजी दूसरों की दया पर ही कांग्रेस में थे और यह तब जबकि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की वे इतनी सेवा कर चुके थे। इससे उस युग के नेता अच्छी रोशनी में नहीं उभरते।

**कांग्रेस सींग पेंडट**—ससनऊ कांग्रेस की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि कांग्रेस तथा सींग ने एक सम्मिलित योजना तैयार की। इस योजना में पूँयक निर्वाचन को स्वीकार कर मतों को निम्नलिखित रूप से बाँटा गया था।

प्रांत का नाम	मुसलमान
पंजाब	50 फी सदी
संयुक्त प्रान्त	30 " "
बंगाल	40 " "
बिहार	25 " "
मध्यप्रान्त	15 " "
मद्रास	15 " "
बम्बई	33 3 " "
केन्द्रीय कौंसिल	33 3 " "

सब धारासभाओं के लिए यह भाग की गई कि 4/5 सदस्य निर्वाचित हों। हा, यह भाग अवश्य रखी गई कि जहाँ तक हो सके निर्वाचक मंडल विस्तृत हों। यह मान लिया गया था कि केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के अध्यक्ष प्रमथ बड़े लाट तथा वहाँ के स्थानीय लाट होंगे और उनकी कार्यकारिणी समितियों के केवल आधे सदस्य ही वहाँ की धारासभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा चुने हुए होंगे। जिस दृष्टि से भी देखा जाय यह एक बहुत ही नरम भाग थी, पर उस समय की सरकार इतना भी मानने के लिए तैयार नहीं थी।

ससनऊ कांग्रेस में अन्धाय प्रस्तावों के साथ मजूरवर्दी कानूनों के दुष्प्रयोग की निंदा गई और सरकार से सिफारिश की गई कि इंगलंड में जिस प्रकार इन कानूनों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार भारत में भी किया जाय। इस कांग्रेस में अपनी अधीन सस्थाओं को यह हिदायत दी गई कि वे सभायें कर स्वराज्य की मांग के सबंध में जनमत तैयार करें। इस अधिवेशन में 2301 प्रतिनिधि आए।

1917 के प्रारम्भ में ही इन्स्टीट्यूट ऑफ़ नैशनलिटी की नियुक्ति इस कारण हुई थी कि उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति के सबंध में जांच करे, पर इसकी अधिक सख्या ने इसके विपरीत यह लिख दिया कि नहीं, जो है सो ठीक ही है। आयोग के दो भारतीय सदस्यों ने इसके विरुद्ध अपना मत लिखा। आयोग ने सिविल सर्विस की उन्नत घटाकर 19 करने का प्रस्ताव किया।

**माटेगू का झोघ**—इस प्रकार के भेद भाव के कारण होमरूल आन्दोलन खूब प्रचार हुआ। भारतीय इस बात का अनुभव करने लगे कि होमरूल के बगर भू नहीं। 24 जून 1917 का होमरूल लीग के सभापति भूतपूव जस्टिस सर एस० सुब्रह्म ने अमेरिका के राष्ट्रपति विलसन को एक पत्र लिखा जिसमें भारतीयों के लिए होमरूल की मांग की गई। माटेगू साहब उस समय तक भारत सचिव हो चुके थे। उन्होंने पत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि इस प्रकार का पत्र 'disgraceful and improper' अर्थात् लज्जाजनक तथा अनुचित है। इस पर श्री जय्यर ने अपनी 'सर' की उपासना दी।

**होमरूल लीग पर प्रहार**—होमरूल लीग कांग्रेस से कहीं अधिक उग्र सत्तावादी थी। सरकार को यह पसन्द नहीं था कि ये नेता इस प्रकार स्वतन्त्रता के साथ धर्म फिरे। विशेषकर छात्र आन्दोलन में बहुत भाग ले रहे थे। प्रांतीय शिक्षा विभागों गश्ती चिट्ठियाँ निकालकर छात्रों का होमरूल लीग की सभाओं में भाग लेने से रोकना तिलक और विपिनचन्द्र पाल पर यह राक लगी कि वे दिल्ली और पंजाब में न हों। श्रीमती बेसेट भी कई प्रांतों में घुसने से राक दी गई। इन वधनों से नेताओं का प्रभाव और भी बढ़ा। अंत तक ऐसा हुआ कि मद्रास के गवर्नर लार्ड पेटरलंड ने धारामभा की बैठक में श्रीमती बेसेट को बुरा भला कहा। श्रीमती बेसेट इससे दबनेवाली थोड़ी थी। उन्होंने 'यू इंडिया' में लेख पर लेख लिखकर लार्ड पेटरलंड की धिज्जिया उठा दी। अब सरकार क्या करती? 16 जून को श्रीमती बेसेट नजरबंद कर ली गई। इसी के साथ उनके अनुयायी बी० पी० वाडिया और जी० एम० जरखेल भी नजरबंद कर लिए गए।

**धमन से आन्दोलन बढ़ा**—इन तीन नेताओं की गिरफ्तारी से होमरूल आन्दोलन और बढ़ा। पी० के० तेलंग, ए० रंगास्वामी आयरर, सी० पी० रामास्वामी आदि नए नेता सामने आए। श्रीमती बेसेट की गिरफ्तारी से क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई, यह भारत सचिव मिस्टर माटेगू की दायरी से ज्ञान होना है। उन्होंने लिखा है कि श्रीमती बेसेट का गिरफ्तार करने से वही हालत हुई जो शिवजी ने अपनी स्त्री को 52 टक्कों में काटने के बाद अनुभव किया। उन्होंने पाया कि अब एक की बजाय 52 रियायतें हो गई हैं।

**सविनय अवज्ञा की शक्त**—लोकमान्य तिलक ने फौरन श्रीमती बेसेट के मामले को जोरों से उठाया। उन्होंने ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को इस बात के लिए मजबूर किया कि वह सरकार के निकट श्रीमती बेसेट आदि की रिहाई की मांग करे। यह आन्दोलन यहां तक जोर पकड़ गया कि जिम्मेदार लोगों में सविनय अवज्ञा की बात चलने लगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जुलाई अधिवेशन में भी यह बात चली और प्रांतीय कांग्रेस कमेटियाँ तथा मुस्लिम लीग की कौंसिल को यह हिदायत दी गई कि वे इस सम्बन्ध में छह हफ्तों के अंदर रिपोर्ट दें। बाद की कई प्रांतीय कमेटियों ने इसकी सिफारिश भी की। लोकमान्य ने यह भी प्रस्ताव रखा कि श्रीमती बेसेट आगामी कांग्रेस की सभानेत्री हो। आन्दोलन के फलस्वरूप श्रीमती बेसेट छूट भी गई। पहले नरम दल के लोग श्रीमती बेसेट का सभानेत्री बनाना नहीं चाहते थे, यहां तक कि कलकत्ते में दो स्वयंसेवक समितियाँ भी बनाई गई थीं, पर जनमत के सामने नरम दल की कुछ नहीं चली।

**माटेगू की धोपणा**—सरकार ने इस बीच दो काम किए। एक तो श्रीमती बेसेट को छोड़ दिया, और दूसरा, अगस्त में एक धोपणा की। 20 अगस्त को भारत

सचिव मिस्टर माटेगू ने निम्नलिखित घोषणा की

“सम्राट की, ब्रिटिश सरकार की और भारत सरकार की राय भी यही है कि शासन काय के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का अधिकाधिक सहयोग हो तथा समस्त शासन मूलक संस्थाओं का क्रमिक विकास हो, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत भारत में जिम्मेदार सरकार का विकास हो सके। इन दोनों सरकारों ने तय किया है जहां तक तक संभव हो, शीघ्र इस दिशा में अच्छा कदम उठाया जाय।”

पामदत्त ने ‘इंडिया टुडे’ में लिखा कि यह घोषणा श्रुति के फलस्वरूप हुई, जो एक मजेदार बात है। सच तो यह है कि भारतीय अभी इसके बारे में जानते भी नहीं थे। फिर, अभी तो समाजवादी क्रांति हुई भी नहीं थी। हा, फरवरी क्रांति हो चुकी थी।

श्रीमती बेसेंट ने परिवर्तन—वर्द्ध प्रान्तों से सविनय अवज्ञा का समर्थन आया। परन्तु स्वयं श्रीमती बेसेंट ने, जिनसे लोग यह आशा लगाए हुए थे कि वे छूटकर कोई जोरदार कार्यक्रम रखेंगी, सविनय अवज्ञा के प्रस्ताव का विरोध किया। कुछ महीनों की जबरबंदी ने ही उन्हें बदल दिया था। सच तो यह है, और जैसा कि माटेगू की डायरी से भी ज्ञात होता है, वह किसी प्रकार की प्रतिज्ञा करके छूटी थी। इसके बाद से वह बराबर नरम पड़ती चली गई। फिर भी श्रीमती बेसेंट ने पहले जो कुछ किया, उसके कारण ही उनका नाम भारत के इतिहास में स्वर्णशरीरों में लिखा रहेगा। पर उन्होंने जिस भारी काम को उठाया था, वह उसके योग्य साबित न हो सकी।

चम्पारन में गांधीजी का उदय—इधर श्रीमती बेसेंट का सूर्यास्त हो रहा था, उधर चम्पारन में गांधीजी नील की खेती करने वाले किसानों की तकलीफों को लेकर लड़ते हुए गगन पर उभर चुके थे। एक नए सूर्य का उदय हो रहा था। पहले नील उत्पन्न करना किसानों के लिए बिल्कुल लाभदायक नहीं था, पर किसान इस लिए गोरे प्लटरों द्वारा मजबूर किए जाते थे। अब जब से वैज्ञानिक तरीके से नील उत्पन्न होने लगा था, नील का उत्पादन प्लटरों के लिए भी लाभदायक नहीं रह गया था। पर प्लटर इन हानि को उठाने के लिए तैयार नहीं थे। वे किसी न किसी तरह सारी हानि का बोझ किसानों पर डालना चाहते थे। इसके लिए वे जबरदस्ती किसानों से झूठे बाड लिखवाते थे। सरकार इन्हें मदद दे रही थी। पूरी नादिरशाही चल रही थी।

गांधीजी ने इन्हीं किसानों के काय को उठा लिया था। वह अप्रैल 1917 में मोतिहारी पहुँचकर खोज करने लगे कि किसानों की क्या तकलीफें हैं, तो सरकार ने उन पर दफा 144 लगाकर यह हुक्म दिया कि वे फौरन जिला छोड़कर चले जाएं। उन्होंने ऐसा करने से इकार किया। यही तभी, उन्होंने महायुद्ध के लिए अंग्रेजों की मदद करने के लिए प्राप्त अवकाश ‘कैंसर ए हिंद’ मंडल भी लौटा दिया। आदालत बढ़ने पर सरकार ने उनके विरुद्ध दफा 144 का मुकदमा लौटा लिया। इसके बाद उन्होंने बीस हजार किसानों के बयान लेकर उनकी मांग सरकार के सामने रखी। सरकार एक आयोग बैठाने पर मजबूर हुई, और अन्त तक किसानों की बहुत सी मांगें मान ली गईं।

इस प्रकार गांधीजी भारतीय राजनीति में पहले पहल सताए हुए किसानों के मित्र के रूप में आए। यह आगमन अनोखा था। गांधीजी ने जन संपर्क के इसी तरीके को भारतीय राजनीति में वृहत्तर क्षेत्र के लिए प्रयोग करना चाहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और लीग ने शासन सुधार की जो योजना बनाई है, उसे केवल अंग्रेजी तक सीमित न रखकर देशी भाषाओं में अनुवाद कर जनता तक पहुँचाया जाय। तदनुसार 1917 के अन्त तक दस लाख लोगों के दस्तखत से यह प्रस्ताव रखा गया।

## कांग्रेस का तैतीसवा अधिवेशन

1917 में कलकत्ता में कांग्रेस का तैतीसवा अधिवेशन श्रीमती बसन्त की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन में 4967 प्रतिनिधि आए। इस कांग्रेस में भी राजभक्ति का प्रस्ताव हुआ। नया प्रस्ताव अर्थात् कांग्रेसियों की तरह थे। कांग्रेस ने माटेगू घोषणा का स्वागत किया, पर यह कहा कि 'कब तक' भारतीयों को पूरी जिम्मेदारी दी जाय। यह उना दिया जाय। कांग्रेस ने कहा कि पहले रुढ़ि के रूप में फौरन कांग्रेस और लाल ने मिलकर जो योजना बनाई है उसे कार्यान्वित किया जाय। एक प्रस्ताव में आधुनिक पथक प्राप्ति बनाने की मांग की गई। इस कांग्रेस की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस अधिवेशन में भंडे का प्रश्न उठा। इसमें पहले ही होमरूल लीग ने तिरंगा का अंगण था। तिरंगे का विचार फ्रांस की राज्यशास्त्र से आया था। महान् क्रांतिकारिणी मित्रा जी कामा 1907 में स्टुटगार्ट अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में तिरंगा झंडा पहना चुकी थी। कलकत्ता के नातिकारियों में तिरंगा प्रचलित था। कांग्रेस ने प्रस्तावित किया था कि होमरूल लीग के तिरंगा झंडा की जाच के लिए एक कमटी बने, और दो कमटी बन भी गई, पर इस कमटी को कभी बटन नहीं हुई और होमरूल लीग का झंडा ही कांग्रेस का झंडा हो गया। हा, यान् को इसमें चला जाड़ा गया, और केसरिया की जालाल रंग कर लिया गया।

**नरम दल डेढ़ इंच की मस्जिद**—1917 की कांग्रेस अन्तिम कांग्रेस थी, जिसमें नरम दल बान मौजूद थे। बाद की अर्थात् कमकत्ता कांग्रेस के तुरन्त बाद नरम दल बाने अलग हो गए और उन्होंने 'नेशनल लिबरल लीग' कायम कर ली। मजे की बात यह है कि नरम दल वाले न यह जो अलग संस्था कायम की, यह मिस्टर माटेगू के भन्वाने पर की थी। माटेगू भडकात या नहीं भडकाते, ये लोग एक कांग्रेस में रह नहीं सकते थे क्योंकि कांग्रेस अब धीरे धीरे जनता की संग्रामकारी संस्था में परिणत होती जा रही थी। नरम दल वाले यह समझते थे कि वे केवल 'यास्यानो शिष्टमंडली आदि' द्वारा इतिहास की सृष्टि कर रहे हैं। वे वंचारे ब्रिटिश कूटनीति की चाल में आ गए।

**श्रीमती बेसेंट का सूय डूबा**—श्रीमती बसन्त कांग्रेस की प्रथम प्रधान थी जिन्होंने यह दावा किया कि अधिवेशन का मभापनि सार भर प्रधान होता है, और इन्होंने इस दावे का नायरूप में इस अवसर पर परिणित किया कि वह दश भर में बराबर दीवसी रही। परन्तु वह समय के साथ बदल मिलकर आगे नहीं बढ़ सकी। वह कुछ दूर आगे बढ़कर पीछे हटने लगी जसा कि पट्टाभि मोतारमया ने लिखा है 1918 के सितम्बर की विशेष कांग्रेस में बेसेंट का ही प्रभाव अधिक था, पर 1918 के दिसम्बर में वह हतप्रभ हो चुकी थी।

## कांग्रेस का विशेष अधिवेशन

29 अगस्त 1918 का कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बम्बई में हुसैन इमाम साहब के सभापतित्व में हुआ। इसमें 3845 प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस कांग्रेस के सत्र में यह न्याय था कि आपस का वैमनस्य बढ़ेगा क्योंकि शासन सुधार के प्रस्तावों के सत्र में लोगों के मत भिन्न थे। पर अधिवेशन में ऐसी कोई बात दृष्टिगोचर नहीं हुई। इस कांग्रेस ने शासन सुधार के सरकारी प्रस्ताव को अनावश्यक और निराशाजनक करार दिया। इस समय तक रोलट कमटी की रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी थी। कांग्रेस ने इसकी निंदा की।

**रोलट कमेटी** — यह कमेटी 10 दिसम्बर 1917 को भारत सरकार ने एस०ए०टी० रोलट के सभापतित्व में भारत में नातिकारी आंदोलन की जांच के लिए बंठाई गई थी। रोलट कमेटी ने एक बृहद रिपोर्ट पेश की। इसकी रिपोर्ट में वे सभी बातें आ गई जो पुलिस को मालूम थी। इस कमेटी ने भारतीयों की रही सही स्वतंत्रता पर पानी फेरकर जारशाही चलानी चाही। इसे पता नहीं था कि रूस में इन्हीं जारशाही खत्म की जा रही थी। यद्यपि कुछ लोग भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को प्रकोष्ठों में बंटा देना और दिखाना चाहते हैं, पर इस कमेटी के माननीय सदस्यों ने लोकमान्य तिलक तथा चाफेकर, विपिनचंद्र पाल और खुदीराम को एक ही साठी से हाका है, हमेशा उनको एक ही दृष्टि से देखा है, और उनके लिए एक ही दवा तजवीज की है। उन्होंने नातिकारियों तथा सविधानवादियों दोनों को एक-दूसरे का पूरक समझा है।

**रोलट रिपोर्ट**—इस कमेटी की सिफारिशों के अनुसार जिस किसी व्यक्ति को जब चाह नजरबंद और गिरफ्तार किया जा सकता था, जिसे किसी की तलाशी ली जा सकती थी, जिस किसी से जमानत मांगी जा सकती थी। संक्षेप में, यह सैनिक कानून का ही एक रूप था। भारत रक्षा कानून तो था ही, जिसके तहत पर सरकार ने 1600 व्यक्ति नजरबंद किए थे, फिर इसके सम्बंध में एक तसल्ली यह थी कि यह कानून युद्ध कालीन था, पर रोलट रिपोर्ट तो शांतकाल में प्रयोग में आनेवाली थी। स्मरण रहे, अभी केवल रिपोर्ट ही प्रकाशित हुई थी, पर लिफाफा देकर मजबूत भापा जा सकता था और कहा जा सकता था कि इस रिपोर्ट पर विधेयक कैंसा रहेगा।

## कांग्रेस का चौतीसवा अधिवेशन

1918 में दिल्ली में पंडित मदनमोहन मालवीय के सभापतित्व में कांग्रेस का चौतीसवा अधिवेशन हुआ। अधिवेशन के पहले ही महायुद्ध का अंत हो चुका था। इस सत्र में एक लाख भारतीय सैनिक मारे गए और भारत का 1000 करोड़ खर्च बठाया। सत्र के खतम होने पर भारतीय नेता यह समझने लगे कि अब सरकार भारत के साथ किए गए वायदों को पूरा करेगी। इस कांग्रेस में 4865 प्रतिनिधि आए। इस कांग्रेस में भी राजभक्ति का प्रस्ताव हुआ तथा युद्ध की सफल समाप्ति पर सरकार को बधाई दी गई।

युद्धकाल में मिश्रपक्ष के नेताओं ने यह वायदा किया था कि युद्धांत होने पर प्रगतिशील जातियों को आत्मनिर्णय या अधिकार दिया जाएगा। कांग्रेस ने तदनुसार यह भाग की कि भारतीयों को प्रगतिशील जाति मानकर उन्हें आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाय। कांग्रेस ने दाहिने कांफ्रेंस के लिए लोकमान्य तिलक, गांधीजी और मिस्टर हसन को चुना। इस कांग्रेस में प्रिंस आर्चबिशप के भारत आने का स्वागत किया गया।

यहां एक बात यह बता दी जाए कि नातिकारियों ने महायुद्ध के चरित्र को समझकर यह तय किया था कि साम्राज्यवादों के आपसी युद्ध का फायदा उठाकर अपने मुनित युद्ध को सफल बनाया जाय। इसी उद्देश्य से बर्लिन से कलिफोर्निया तक जहां भी जाया, नातिकारियों ने जुट गया। बनारस, मनपुरी, लाहौर में गिरफ्तारियां हुईं। विशेषतः नातिकारी छावनीयों में काम कर रहे थे। उन्होंने जमनों की मदद ली। पिगले मेरठ छावनी में ही पकड़े गए। उन्हें फांसी हुई थी। लाहौर से लेकर माण्डले तक जहां भी पड़्यत्र चला, नातिकारियों पर यह अभियोग था कि उन्होंने पड़्यत्र किए। मनपुरी के अभियुक्तों पर कई ढाकों के आरोप लगाए गए थे। इनके नेता पंडित गेंदालाल दीक्षित थे।

**मुसलमान नातिकारी**—नातिकारी आंदोलन में मुसलमानों ने भी हाथ बंटाया,

महायुद्ध में तुर्की ब्रिटेन के शत्रुपक्ष में था, इस कारण भारतीय मुसलमान इस युद्ध में अंग्रेजों के बहुत भक्त तथा अनुगत नहीं थे। यों तो कई तरह के सरकार विरोधी कार्यों में मुसलमान शरीक रहे पर रेशमी चिट्ठियों का पढ़यन इय्य सम्बन्ध विशेष उल्लेखनीय है। सन 1916 में सरकार को पता लगा कि भारतवर्ष के मुसलमान सरकार को उलटने के लिए एक विराट पढ़यन कर रहे हैं। 1915 के अगस्त में मौन ओबेदुल्ला सिंधी फतहमुहम्मद और मुहम्मदअली के साथ सरहद पार कर गए। ओबेदुल्ला पहले सिक्ख थे, फिर मुसलमान होकर देवबंद में मौलवी हो गए थे। य ओबेदुल्ला ने यह सोचा कि क्यों न फिर से मुस्लिम राज्य कायम किया जाय। बहुत साग उनके प्रभाव में आ गए। यहां तक कि देवबंद के सबसे बड़े अध्यापक मौलाना मुहम्मद हुसैन भी उनके प्रभाव में आ गए। इस काय के लिए बाहर जाकर मुस्लिम सुलतानों की मदद प्राप्त करना उचित समझा गया। तदनुसार मुहम्मद हुसैन और ओबेदुल्ला गैर अलग अलग भारत के बाहर पहुंचे। ओबेदुल्ला बाहर जाने वाले भारतीय मुसलमानों को प्रचार करते रहे। वह मुस्लिम राष्ट्रों का भड़काते रहे कि वे भारत पर हमला करें, पर इन राष्ट्रों ने उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं ली।

जमनी में क्रांति के पुजारी सितम्बर 1914 में एक नौजवान तमिल ने, जिनका नाम चम्पकरमण पिल्लै था और जो जुरिख में अंतर्राष्ट्रीय प्रो इंडिया कमेटी के सभापति थे जुरिख के जमन काँसल को लिखा कि हम जमनी में ब्रिटिश विरोधी साहित्य के प्रकाशन की अनुमति चाहते हैं। अक्टूबर 1914 में वह जुरिख छोड़कर बर्लिन चले गए जहां वे जमन परराष्ट्र दफ्तर की देखरेख में काम करने लगे। उन्होंने वहां पर जमन जेनरल स्टाफ से मिलकर इंडियन नेशनल पार्टी नाम से एक दल स्थापित किया। इसके सदस्यों में 'गदर पत्रिका के सस्थापक लाला हरदयाल, तारकनाथ दास, बरकतुल्ला चन्द्र चक्रवर्ती तथा हरम्बलाल गुप्त भी थे। आखिरी दो अर्थात् चक्रवर्ती और गुप्त सनफोर्सिस्को के जमन भारतीय पढ़यन में अभियुक्त थे। यह कहानी बड़ी लम्बी है।

## गांधीजी का उदय : सत्याग्रह का प्रयोग

हम देख चुके हैं कि गांधीजी कुछ समय पूर्व द० अफ्रीका से भारत आ गए थे और कांग्रेस के माध्यम से राजनीति में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहे थे। उनका सम्पान आंदोलन बहुत सफल रहा था। अब वह समय आया जब देश ने उनको पहचाना और प्रायः सन उनका नेतृत्व स्वीकार किया। हम देखेंगे कि उन्होंने न केवल कांग्रेस का चरित्र बल्कि काय पद्धति भी आमूल परिवर्तित कर दी।

**रोलट बिल—**1919 की फरवरी में रोलट बिल का रूप रंग सामने आ गया। इसमें भारतीयों की रही-सही नागरिक स्वाधीनता बिलकुल खत्म कर दी गई थी। इस बिल के दो भाग थे। एक भाग तो सामयिक महत्व का था जो, भारत रक्षा कानून के खत्म हो जाने से सरकार की जो क्षति छिन जाती थी, उसकी पूर्ति करता था। दूसरा भाग स्थायी था, तथा प्रचलित फौजदारी कानून में ऐसे परिवर्तन करता था जिनसे जनता का हक घटकर नहीं बल्कि घराबर रह जाता था और पुलिस की ताकत बढ़ जाती थी। देश भर में इन बिलों के विरुद्ध प्रबल आंदोलन हुआ, पर सरकार के कानों में जू नहीं रेंगी और उसके रक्त से ज्ञान हुआ कि यह बिल ऐक्ट बनकर रहेगा।

**आज्ञा भंग—**वहा तो लोगों को सड़ाई की सफल समाप्ति पर बड़ी बड़ी आशाएं थी, और वहा यह तोहफा मिला। हम बता चुके हैं कि लोकमाय तिलक ने युद्ध के शुरू होते ही युद्ध में सहायता का नारा दिया था। महात्मा गांधी ने भी यही नारा दिया था। बुझर युद्ध में भी उन्होंने ब्रिटिश सरकार को मदद दी थी। यह मदद केवल नैतिक नहीं थी, वह सक्रिय रूप से रंगरूट भर्ती कराने में लगने ही वाले थे कि युद्ध समाप्ति की घोषणा हो गई। केवल तिलक और गांधी ही नहीं, उस युग की समूची कांग्रेस युद्ध में मित्र पक्ष की विजय चाहती थी। केवल आतिकारी दूसरे मार्ग को अपनाए हुए थे।

**गांधीजी युगपुरुष—**अब जो रोलट बिल आया, तो लोग अपने को बहुत असहाय अनुभव करने लगे। पुराने नेता यहां तक कि लोकमाय तिलक भी कुछ राह नहीं सुझा सके। ऐसे समय एक व्यक्ति था जो नहीं घबड़ाया। उसने अपने सामने एक मार्ग की रेखा दे दी। दूसरे नेताओं की तरह उसने अपने को असहाय नहीं पाया। उन्होंने 1 मार्च की घोषणा की कि यदि यह बिल ऐक्ट में परिणत हो गया, तो हम सत्याग्रह आंदोलन शुरू करेंगे। यह व्यक्ति थे गांधीजी, उन्होंने इस उद्देश्य से जनमत संगठित करने के लिए सारे देश का दौरा किया।

**अब नेता असमंजस में—**इस प्रकार कांग्रेस के अंदर जो घारा तीन साल पहले जारी हुई थी, और जिसे शासन-सुधार का पत्थर अटकाकर बंद कर दिया गया था, अब फिर जारी हो गई। गांधीजी की यह धमकी भारतीय राजनीति में नई बात थी। सरकार ने तथा भारतीय नेताओं ने इसे गंभीरता के साथ लिया। नरम दल वाले नेताओं ने इस पर अपनी शकाएं जाहिर की। श्रीमती बेसेंट ने, जो अब तक उग्रवादिनी समझी जाती



थी, इस प्रस्ताव के विरुद्ध आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि सत्याग्रह छेड़ना ऐसी गिनियों को मुक्त करना होगा जिनकी बुराई की ताकत किसी को मालूम नहीं है।

**कानून भंग की प्रतिज्ञा**—पर गांधीजी पीछे नहीं हटे। उन्हें विश्वास था कि हम रोलट बिल को वापस कराने में सफल होंगे। 16 मार्च को यह विधेयक बन गया। उन दिन गांधीजी ने एक प्रतिज्ञा पत्र छपवाया जिसमें दस्तखत करने वाले को यह प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी—“चूँकि मैं इन बिलों का विरोधी हूँ और उनको अय्यायपूर्ण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का घातक तथा मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात करने वाला समझता हूँ इसलिए यदि ये बिल कानून बन गए, तो मैं इस कानून का तब तक मनाबन करूँगा, जब तक कि वह न खारिज हो जाए। साथ ही मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं सत्य तथा अहिंसा का पालन करूँगा।”

**दिल्ली में उपद्रव**—जब कानून बन गया, तो यह तय हुआ कि इसके विरोध में 30 मार्च को भारतव्यापी हड़ताल हो और उस दिन लोग उपवास और प्राणना करें। यहाँ दृष्टान्त है कि यह दिवस धार्मिक व्रत के रूप में मनाया जाना वाला था बाद का यह तारीख 30 मार्च से 6 अप्रैल कर दी गई, पर दिल्ली में इसकी सूचना नहीं पहुँची एक पूरा कार्यक्रम के अनुसार जुलूस निकला और हड़ताल हुई। गोलियाँ चलीं। जुलूस का नेतृत्व स्वामी श्रद्धानंद कर रहे थे। कुछ गोरे सिपाहियों ने उनकी धमकाया कि गोली मार देंगे, इस पर उन्होंने अपना सीना खोलकर तान लिया जिससे गोरे भौंप गए। दिल्ली स्टेशन पर झगडा हो गया जिसमें आठमी मारे गए और बीसिया घायल हो गए।

**सफल आम हड़ताल**—6 अप्रैल को सारे देश में हड़ताल रही। जो दृश्य अब उपस्थित हुआ वसा पहले कभी देखने में नहीं आया था। हिंदुओं और मुसलमानों में सद्भाव के अपूर्व दृश्य दिखाई पड़े। इन दिनों मुसलमानों का दिल भी सरकार से खटका हो चुका था। वे अनुभव कर रहे थे कि लड़ाई में हार जाने के कारण खलीफतुल इस्लाम की दुर्गति होगी। हिंदुओं ने भी इस कारण मुसलमानों से सहानुभूति दिखाई। इस प्रकार मेल का आधार घम होने पर भी नारा था घम खतरे में।

**अमतसर 10 अप्रैल**—अमतसर में अगली कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था पर सर ओ' डायर इस पर तुल्य हुए थे कि पंजाब को खतरे से बाहर रखा जाय, क्योंकि पंजाब सैनिक जातियों का घर था। यहाँ राजनीतिक आंदोलन का फलना खतरे से खाली नहीं था।

10 अप्रैल को सबेरे अमतसर कांग्रेस के संगठनकर्त्ता डाक्टर किचलू और डा० सत्यपाल अमतसर जिला मैजिस्ट्रेट के बगले पर बुलाए गए और वहीं से वे न मालूम कहा भेज दिए गए। यह खबर बात की बात में फल गई और बड़ी भीड़ आप से आप इकट्ठी होकर यह पूछने के लिए मैजिस्ट्रेट की ओर बढ़ी कि ‘वे कहाँ हैं?’ पर भीड़ को बगले की तरफ जाने नहीं दिया गया। जनता ने लौटते समय नेशनल बैंक में आग लगा दी और उसमें गोरे मैनेजर को मार डाला। कुल पाँच अंग्रेज जान से मारे गए।

**गांधीजी को पंजाब निकालना**—डा० सत्यपाल तथा स्वामी श्रद्धानंद के निमंत्रण पर गांधीजी 8 अप्रैल को दिल्ली रवाना हो चुके थे। पर रास्ता में उनको यह हुक्म दिया गया कि आप पंजाब में प्रवेश न करें। गांधीजी ने इस आदेश को मानने में इनकार किया और वह पलवल स्टेशन से स्पेशल ट्रेन द्वारा 10 अप्रैल को बम्बई वापस कर दिए गए।

**जलियावाला बाग का हत्याकाण्ड**—सबसे रोमाचकारी घटना तो अमतसर में हुई। डा० सत्यपाल और किचलू की निरपत्तारी पर वहाँ आम हड़ताल हुई। 11 अप्रैल को शहर की परिस्थिति ऐसी खराब हो गई कि फौज बुला ली गई। 12 को सभाओं पर

रोक लगाई गई, पर किमी को पता न लगा। 13 को हिंदुओं का नया साल धुरु होता था। उस दिन शाम के समय अमृतसर के जलियावाला बाग में सभा हुई। जलियावाला बाग चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ एक पतला-सा रास्ता है जिसमें होकर एक गाड़ी नहीं जा सकती। जिस समय यह स्थान भौड़ से खचाखच भर रहा था, और व्याख्यान हो रहा था, जनरल डायर सेना की एक टुकड़ी के साथ यहाँ आए, और लोगों पर बिना किसी चेतावनी के गोलिया चलाना शुरू कर दिया। अब जनता भागती भी तो कैसे भागती! सेना उसी पतले प्रवेश पथ को लक्ष्य करके गोली चला रही थी। सरकारी हिसाब से भी 379 आदमी मारे गए, पर वास्तव में लगभग 1000 आदमी मारे गए थे। कई हजार जखमी होकर रात भर वहीं पड़े रहे। उन्हें किसी प्रकार न तो मदद दी गई, न देने दी गई।

**डायरशाही का जमाना—**जनरल डायर की 'वीरता' यही पर खतम नहीं हुई। वह तो बिद्रोही पंजाबियों को एक सबक सिखाना चाहते थे। उन्होंने शहर की बिजली और पानी काट दिया। राहगीरों को पकड़कर रास्ते पर छाती के बल चलने को मजबूर किया गया। दो आदमियों से अधिक के लिए एक साथ चलने की मनाही कर दी गई। लोगों को बिना किसी अपराध के खुली सड़क पर बेंत लगाए गए, रेलों में तीसरे दर्जे का टिकट बंद कर दिया गया। साइकिलें छीन ली गईं। शहर में जगह जगह बेंत लगाने की टिकटी लगा दी गई। फौजी अदासता में लोगों को मनमानी सजा दी गई। 51 आदमियों को तो फासी ही दे दी गई। सर भाइकल ओ' डायर को जब जनरल डायर के इन अत्याचारों की बात मालूम हुई, तो उन्होंने उनके काले कारनामों का समर्थन करते हुए एक तार भेज दिया।

**कबीर का प्रतिवाद—**कबीर रबीन्द्र ने प्रतिपादित स्वरूप अपनी 'सर उपाधि त्याग दी। ऐसा करते हुए उन्होंने एक पत्र लिखा जो शांतिनिकेतन के रबीन्द्र सदन में सुरक्षित है। पत्र यों है—

"पंजाब सरकार ने कुछ स्थानीय उपद्रवों को शान्त करने के लिए जिन भयंकर उपायों का अवलम्बन किया, उससे हमारे मानस नेत्रों के सम्मुख निष्ठुर घड़के के साथ भारत में ब्रिटिश प्रजा के रूप में हमारी असह्य स्थिति स्पष्ट हो गई है। अमाने लोगों पर जिस प्रकार से बिना किसी अनुपात सजा बोली गई और उसे जिन तरीकों से कार्यान्वित किया गया, उसे देखकर हम इस निश्चित मत पर पहुँच चुके हैं कि सम्पूर्ण सरकारों के इतिहास में उसकी कोई तुलना नहीं है, अवश्य ही प्राचीन तथा आधुनिक काल में उसके कुछ अपवाद पाए जाते हैं। यह दुर्व्यवहार ऐसे लोगों पर किया गया है, जो नर हत्या के अत्यन्त भयंकर कुशल समर्थन वाली एक शक्ति के द्वारा अशक्त और साधन हीन बना दिए गए हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें बहुत जोर के साथ यह बता देना चाहिए कि इसके लिए किसी प्रकार का राजनीतिक मसलहत्त का बहाना नहीं किया जा सकता, नैतिक समर्थन की बात तो दूर रही। पंजाब में हमारे भाइयों का जिस तरह अपमान हुआ है, और उन पर जो कष्ट पड़े हैं, उनकी कुछ कुछ कथा कठरुद्ध नीरवता के जरिये भारत के कोने-कोने में पहुँच चुकी है और हमारे देश के लोगों के हृदय में इसके फलस्वरूप क्रोध की जो सार्वदेशिक ज्वाला भड़की है, हमारे शासकों ने उसकी अवज्ञा की है। समभव है, वे अपने को बर्छाई दे रहे हों क्योंकि वे समझते होंगे कि इस तरह उन्होंने बड़ा हितकर सबक दिया है। अधिकांश एंग्लो इंडियन अखबारों ने इस हान्यहीनता की प्रशंसा की है, और इनमें से कुछ तो उस पाशविक हृद तक चले गए हैं कि उन्होंने हमारी यत्रणाया की हसी उड़ाई है और इसमें गंभीर अधिकारीवर्ग की ओर से

किसी प्रकार से अंधा नहीं पहुँचाई गई क्योंकि यह भी कष्ट पानेवाले लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे मुखपत्रों पर बराबर निंदयता के साथ व्यवहार करते रहे हैं और कष्ट की किसी भी अभिव्यक्ति का विरोध करते रहे हैं। यह जानकर दुःख होता है कि हमारी अपीलों का कोई नतीजा नहीं हुआ और हमारी सरकार में राजनीतिज्ञता के पवित्र मिशन पर प्रतिशोध का अंधा पर्दा पड़ा हुआ है। यदि यह सरकार चाहती तो उसमें जितनी पशु शक्ति और नस्ल परम्परा है, वह उसी अनुपात से महान हो सकती थी। इस स्थिति में अपने देश के लिए जो सबसे कम कुछ कर सकता हूँ, वह यह है कि हम अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को स्वर दें, जो इस समय आतंक की यंत्रणा से अभिभूत होकर चण्णी साधे हुए हैं। अब वह समय आ गया है, जब अपमान को देखते हुए सम्मान के क्षण हमारी लज्जा को और भी गहरी बना देते हैं और जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, मैं यह चाहता हूँ कि सब तरह की सम्मानसूचक विशेषताओं से वंचित होकर मैं उन देशवासियों के साथ जाकर लड़ा हो जाऊँ, जो अपनी व्यक्तिगत तुच्छता के कारण ऐसे अपमानों के शिकार होते हैं जो मनुष्यों के लिए अनुचित हैं। यही वे कारण हैं जिनकी वजह से मैं इस बात के लिए मजबूर हुआ हूँ कि उपयुक्त सम्मान के साथ महामहिम से यह निवेदन करूँ कि आप मुझे नाइट की उपाधि से सुविधा दें, जिसे मैंने तब आपके पूर्ववर्ती महान सम्राट के हाथों ग्रहण किया था, जिनके हृदय की महानता को मैं अब भी प्रशंसा के साथ देखता हूँ।

**काशमकश—**20 तथा 21 अप्रैल को पंजाब की घटनाओं पर जांच की मांग तथा गांधीजी तथा अन्य नेताओं के पंजाब प्रवेश पर रोक की निंदा करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक की ओर से विट्ठलभाई पटेल तथा नरसिंह चिन्तामणि केलकर इंग्लैंड भेजे गए कि जाकर आम अंग्रेजों को परिस्थिति की भयावहता से परिचित करा दें। भारत सरकार ने 21 अप्रैल को एक आर्बिट्रल निकाश, जिसके द्वारा पंजाब सरकार को यह अधिकार दिया गया कि 30 मार्च के बाद किए गए किसी भी अपराध का फौजी अदालत में फैसला हो सके। घटनाएँ बहुत द्रव गति से चल रही थी।

**कांग्रेस अधिवेशन का स्थान बही रहा—**19 तथा 20 जुलाई को अ० मा० कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, और पंजाब की परिस्थिति खराब होने पर भी अमृतसर में ही अगली कांग्रेस का होना निश्चित रहा।

**श्रीमती बेसेंट से झूठ—**इन दिनों बहुत से नेता भारत के प्रतिनिधि बनकर इंग्लैंड गए थे। कांग्रेस के प्रतिनिधियों को इस कारण दिक्कत पड़ी कि श्रीमती बेसेंट उनके विरुद्ध प्रचार कर रही थी। श्रीमती बेसेंट का यह रुख बहुत अजीब रहा। पहले तो उन्होंने इस प्रकार के कुछ मत व्यक्त किए कि रोलट बिल में ऐसी कानूनी बात है जिससे वास्तविक रूप से निर्दोष नागरिक को बुरा लगे। उन्होंने यह भी कहा कि जिस समय जनता उत्तेजित हो जाती है और फौज पर दला चौराहा मारने लगती है, उस समय यह दया की बात है कि सिपाहियों से कहा जाए कि वे कुछ गोलियाँ चला दें। विलायत में श्रीमती बेसेंट ने जो कुछ किया, उससे उनकी और भी भद्दा हुई। यदि वह गुप्त वादा करके रिहा हुई थी तो राजनीति से अलग हो जाती और थियोसोफी तथा धर्म का ही काम करती, पर वह राजनीति में टांग भी अड़ाना चाहती थी। हद तो उस दिन हुई जब 15 अक्टूबर 1919 को लंदन में मिस्टर लसबरी की अध्यक्षता में सभा हुई। इस सभा में भारतीयों के आत्मनिर्णय की मांग के समर्थन में प्रस्ताव पेश हुआ तो जहाँ अन्य भारतीय नेता यह कह रहे थे कि भारतवर्ष को पूरी जिम्मेदारी दी जाए, श्रीमती बेसेंट

ने वहा माटेगू के प्रस्तावित शासन सुधार की तारीफ के पुल बांध दिए। इस पर श्री विट्ठलभाई पटेल को कहना पड़ा कि आप भारतीय मत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही हैं। श्री खापडें ने इस पर उन्हें 'पूतना' की उपाधि ही दे डाली।

**हत्याकांड पर जांच—**पंजाब के हत्याकांड को लेकर इतने प्रबल आंदोलन का सूत्रपात हुआ कि सरकार ने अक्टूबर में हटर कमेटी नाम से एक जांच आयोग बैठाया। चित्तरंजन दास कांग्रेस की तरफ से इसके सामने पेश हुए पर कुछ ऐसी दिक्कतें पेश आई कि कांग्रेस ने कहा कि माशाल ला बंदियों को गवाहों के रूप में पेश किया जाए, पर हटर कमेटी इस पर राजी नहीं हुई। इसके बाद कांग्रेस ने अपनी अलग जांच कमेटी बठाई। गांधीजी, मोतीलाल नेहरू, सी० आर० दास, फजलुल हक, तथा अब्बास तैयबजी इसके सदस्य हुए, और वे० सन्तानम हुए इसके मंत्री। यथासमय दोनों जांच कमेटियों की रिपोर्ट निकली। सीपा पोती करने पर भी हटर आयोग के सामने जनरल डायर ने जो कुछ कहा था वही यह प्रमाणित करने के लिए मयेष्ट था कि हत्याकांड पहले से मोचा हुआ था। उस समय तक भारत में ऐसा हत्याकांड नहीं हुआ था—'उस समय तक' इस कारण लिखा कि इसके बाद 1942 में कई हत्याकांड हुए।

**शासन सुधार का स्वरूप—**इसी युग में साम्राज्यवाद की सुपरिचित एक तरफ गरम तथा दूसरी तरफ गरम नीति के अनुसार शासन सुधार का काम भी चालू था। 23 दिसम्बर 1919 को ब्रिटिश संसद का शासन सुधार सम्बंधी ऐक्ट भी पास हो गया। इस प्रस्ताव के द्वारा डायर्की या द्वैध शासन का सूत्रपात हुआ। इस पद्धति का नाम द्वैध-शासन इसलिए दिया गया कि स्थानीय स्वायत्त शासन, शिक्षा स्वास्थ्य चुने हुए सदस्यों में से बनाए गए मंत्रियों के हाथों में रहनेवाला था, तथा राजस्व, पुलिस और कानून पहले की तरह सरकार के हाथों में रहने वाला था। कहना न होगा कि यह कोई होमरूल नहीं था। जो विषय मंत्रियों के हाथों में दिए भी गए थे, वे इस कारण व्यर्थ थे कि किसी भी योजना को कार्यान्वित करने के लिए धन की जरूरत पड़ती, और राजस्व का सारा विभाग सरकार के हाथों में था।

भारत की करोड़ों जनता में केवल 53 लाख व्यक्तियों को प्रांतीय धारासभाओं का वोट बनाना था। फिर भी पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार मिला था। स्त्रियों को वोट का अधिकार नहीं दिया गया, पर प्रांतीय धारासभाओं को यह अधिकार दिया गया कि वे चाहें तो अपने प्रांत की स्त्रियों को वोट का अधिकार दें। धारासभाओं में पहली बार निर्वाचित सदस्यों का बहुमत हो गया, पर कौंसिल ऑफ स्टेट में वोटों की संख्या मात्र 18 हजार होने के कारण इसका कोई अर्थ नहीं रहा।

सदस्यों को बजट पर आलोचना का अधिकार रहा, पर सैनिक खर्च, सिविल सर्विस आदि की सनख्वाह, भत्ता, गिजों पर खर्च आदि पर उनको वोट देने का कोई अधिकार नहीं मिला। जिन विषयों पर वोट का अधिकार दिया भी गया, सरकार उन विषयों में बहुमत को मानने के लिए मजबूर नहीं थी।

**कुछ कैदी छूटे—**शासन सुधार कानून बनते ही माशाल लों के कैदी तथा कुछ अन्य राजनीतिक कैदी छूटे। क्रांतिकारी कैदियों में बहुत थोड़े ही छूटे। साबरकर छूटे, बनारस पंडित के शचींद्रनाथ सायान बिना शर्त छूटे, पर मैनपुरी पंडित के लोग शर्त के साथ ही छूटे। कांग्रेस के नेता इस शासन-सुधार से सतुष्ट नहीं थे, वे इससे कहीं अधिक की उम्मीद कर रहे थे।

**शासन सुधार पर लोकमाय—**लोकमाय सर विले टाइन चिरोल के विरुद्ध मान हानि के मुकद्दमे में इंग्लैंड गए थे, पर वह जमतसंग कांग्रेस के पहले वापस आ गए।

इंग्लैंड में रहते समय उन्होंने सुधार-योजना के सम्बन्ध में यह वक्तव्य दिया था कि जितना मिला है, हम उसे ले लेंगे, और बाकी के लिए लड़ेंगे। पर भारत आते ही शायद लोकमत तथा मित्रों का प्रभाव पड़ा, कि वह पलट गए। फिर भी जब एक्ट पास हुआ, तो उन्होंने ब्रिटिश मन्त्रिमंडल को बधाइया और भेजी और 'रेस्पांसिव को-ऑपरेशन' अर्थात् जिस हद तक रियायत उस हद तक सहयोग का नारा दिया। इसके लिए लोकमत को दोष देना उचित न होगा क्योंकि उनके सामने कोई और रास्ता नहीं था।

## अमृतसर कांग्रेस 1919

इसी वातावरण में अमृतसर की कांग्रेस पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1919 में हुई। इस कांग्रेस में मतों का संचय रहा। देशबन्धु दास ने कांग्रेस का मुख्य प्रस्ताव इन शब्दों में रखा (1) कांग्रेस अपनी उस घोषणा को पुनरावृत्ति करती है कि भारतवर्ष पूर्ण स्वराज्य के उपयुक्त है और इसके विरुद्ध कहीं गई बातों का प्रतिपादन करती है, (2) कांग्रेस दिल्ली में स्वीकृत प्रस्ताव का समर्थन करती है, और समझती है कि सुधार की योजना अपर्याप्त, असतोषजनक तथा निराशाप्रद है, (3) ब्रिटिश संसद को चाहिए कि भारतवर्ष को आत्मनिर्णय के सिद्धांतों के अनुसार पूर्ण स्वराज्य देने के लिए जल्दी कदम उठाए।

गांधीजी का सशोधन—गांधीजी ने इस प्रस्ताव में आए हुए निराशाप्रद शब्दों के स्थान पर यह परा जोड़ने का सशोधन रखा "ब्रिटिश संसद द्वारा पूर्ण स्वराज्य प्रवर्तित शान्त तक कांग्रेस राज भक्ति पूर्ण तरीके से सम्राट की घोषणा में व्यक्त इन भावुकतापूर्ण शब्दों का स्वागत करती है—'हमारी प्रजा तथा कमचारियों में एक सामान्य उद्देश्य से काम करने से एक नवयुग का प्रभात हो', और यह विश्वास करती है कि जनता तथा कमचारी इस प्रकार सहयोग से शासन सुधार को कार्यान्वित करेंगे कि जल्द ही जल्द पूर्ण जिम्मेदार सरकार कायम हो। यह कांग्रेस इस सम्बन्ध में श्रीमान् माटो को धन्यवाद देती है।"

महामुद्र और तुर्की—1914-18 के महामुद्र में तुर्की बर्तानिया और फ्रांस के विरुद्ध लड़ा था। इससे भारत की मुस्लिम जनता में अंग्रेजों के विरुद्ध यथेष्ट असंतोष था। कहीं इस असंतोष का कोई दुष्परिणाम न हो इसलिए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लार्ड जॉर्ज न भारत के मुसलमानों को यह वादा किया था कि हम किसी भी हालत में तुर्की पर कब्जा नहीं करेंगे। सरकार ने इधर तो यह वादा किया, उधर तुर्की के अधीन अरब जाति में अपने दूत भेजकर विद्रोह की ज्वाला भड़काई। इस काम के लिए अंग्रेजों ने बहुत योग्य आदमियों को भेजा और पानी की तरह पसा बहाया। अंग्रेज अपनी मोहता में इस कारण सफल हुए कि तुर्की के अधीन मुस्लिम देशों में बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं थी, और ये जातियाँ स्वतंत्र होना चाहती थी। भारतीय पक्ष लिखे मुसलमान इन बातों से बेखबर थे। उनकी यह मान रही कि लड़ाई में हारने पर भी तुर्क साम्राज्य जिस का तत्ता बना रहे।

अजीब माग—इसके साथ ही यह भी सही है कि अंग्रेजों ने युद्धकाल में अरब में जो पड़यंत्र किया था, वह अरब जातियों की स्वतंत्रता के लिए नहीं था। उसका उद्देश्य तो तुर्की सरकार को कमजोर करना तथा पेट्रोल प्राप्त करना था। किसी भी हाव में एक घम होने के कारण यह उद्घोष करना कि शाम, इराक, फिलिस्तीन आदि के लोग हजारों घण तुर्कों के गुलाम बने रहें, यह बहुत अदभुत बात थी।

**19 मार्च की हड़ताल**—तय हुआ कि 19 मार्च को देश के सारे मुसलमान उपवास रहें और ईश्वर से प्रार्थना करें। ऐसे समय गांधीजी आगे आए, और उन्होंने कहा कि यदि तुर्की के साथ मुल्ह भारतवर्ष के मुसलमानों की भावना के अनुसार नहीं होती, तो मैं असहयोग आन्दोलन चलाऊंगा। मौलाना शीकत अली ने 19 मार्च को सत्र पास किए जाने के लिए एक प्रस्ताव बनाया कि यदि मुल्ह की शर्तें भारत के मुसलमानों को नासबद हूँ, तो हम मुसलमान इसके लिए मजबूर हो जाएंगे कि ब्रिटिश सिंहासन से अपना राजभक्तिपूर्ण सम्बंध तोड़ दें। उस समय आम जनता में यह भावना इतने ज़बदस्त तरीके से फैल रही थी कि अंग्रेज सरकार को डर हुआ कि वही सरकारी अफसर भी इस आन्दोलन में न बहने लगे। इसलिए उन्होंने एक हुक्मनामा निकाला जिसके अनुसार 19 मार्च के प्रदर्शनों में सरकारी नौकरों को भाग लेने से मना कर दिया गया।

**महारमाजी का वक्तव्य**—महात्माजी ने इस पर एक सम्बन्ध बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा "मुसलमानों की भावनाओं को कुचलने के लिए जो कोशिश की जा रही है, उसको हम मान नहीं सकते, और जो लोग सरकारी समझौता, उपाधि पाए हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि इसके विरोध में उन्हें त्याग दें और सरकार में जितने लोग नौकरी पर हैं, वे भी उस त्याग दें।" इस प्रकार गांधीजी ने खिलाफत के प्रश्न पर शब्द मुस्लिम भावनाओं पर मरहम रखना चाहा।

**लोकमान्य और खिलाफत**—लोकमान्य तिलक अभी तक जीवित थे। उन्होंने भी यही वक्तव्य दिया कि "हमारा दल खिलाफत के प्रश्न का वही समाधान चाहता है जो मुस्लिम विश्वास तथा कुरान के अनुसार हो।" लोकमान्य भी पढ़े लिखे मुसलमानों को खुश करना चाहते थे।

**जवाहर के साथ आए, भाटे के साथ गए**—यह जरूर है कि गांधीजी खिलाफत की कुंजी से ही उन दिनों भारतीय मुसलमानों के हृदय में घुसने में समर्थ हुए, पर इसका अंतिम परिणाम यह हुआ कि ज्यों ही तुर्की के सुयोग्य नेता कमाल पाशा के हाथों से खिलाफत समाप्त हो गई, खलीफा स्विटजरलैंड भाग गए, त्यों ही कुछ के सिवा सारे के सारे मुसलमान जो जवाहर के साथ आए थे, भाटे के साथ चले गए। पाकिस्तान के बीज को इससे पृष्ठि ही मिली। कुछ मुसलमान कांग्रेस में जरूर टिक गए, पर वे मुल्ह हुए साग थे, खिलाफत आन्दोलन उठाया जाता या न उठाया जाता, वे राष्ट्रीय आन्दोलन में अवश्य आते।

**मुहम्मद अली जनात मौलाना आजाद**—इस बीच मौलाना मुहम्मद अली ने जोग में आकर यह कह दिया कि यदि अफगानिस्तान हिंदुस्तान पर हमला करे, तो भारतीय मुसलमान अफगानिस्तान का साथ देंगे। कहना न होगा कि यह उचित बहुत गुमराहकृन्त थी और सर्व इस्लामी मनोवृत्तिको सूचित करती थी। इस बयान से हिंदुओं के मन में सदह का उदय हुआ। खरियत यह हुई कि मौलाना अबुलकलाम ने एक दूसरा वक्तव्य देकर परिस्थिति सम्हाल ली। उन्होंने कहा कि यदि हिंदुस्तान स्वतंत्र हो, और उसमें ऐसी शासन पद्धति हो जिसमें मुसलमानों को और हिंदुओं को बराबर हक मिल जाए, तो इस्लाम की शरियत का यह हुक्म है कि मुसलमान अपने मुल्क की हिफाजत करें, चाहे स्वयं खलीफा ने ही उस मुल्क पर हमला किया हो।

**असहयोग की तैयारी**—2 जून को इलाहाबाद में सब दला के नेताओं के सामने असहयोग का प्रश्न रखा गया। इस कांग्रेस में असहयोग का प्रस्ताव पास हो गया और एक कमेटी बनाई गई जिसके सदस्य गांधीजी तथा मुसलमान नेता हुए। इस कमेटी को यह भार सौंपा गया कि वह असहयोग का कार्यक्रम बनाए। इस कमेटी ने जो कार्यक्रम

बनाया, उसमें बालेज स्कूल तथा अदानता के बायकट का नारा भी दिया गया।

**लोकमाय का महाप्रयाण**—तीनमाय तिलक ने भी असहयोग व प्रस्ताव का समयन किया था। एक अगस्त की रात का एक बज कर 45 मिनट पर वह चल बस। मानो इस प्रकार उन्होंने गांधीजी के बंधो पर भारत का नेतृत्व छोड़ दिया। पहली अगस्त का बाजान्ता असहयोग होने वाला था, जोर एक अगस्त को ही लोकमाय का देहांत हुआ।

**मुराजरी**—इस बीच कुछ मुसलमान हिजरत करके अफगानिस्तान जाने लगे। मुस्लिम शास्त्रों में ऐसी व्यवस्था है कि जब कोई राजा अयायी हो, तो उसमें राज्य का छोड़कर चला जाना चाहिए। सिध में ही पहले पहल इस आंदोलन का सूत्रपात हुआ, पर धीरे धीरे यह आंदोलन फैला, और 18,060 मुसलमानों ने अफगानिस्तान की राह ली। अफगानिस्तान में इस हिजरत करने वालों का स्वागत नहीं किया। इसके विपरीत उनमें से कुछ गिरफ्तार कर लिए गए, और उन्हें तरह-तरह की तकलीफें दी गईं। हिजरत करने वाले यह समझते थे कि ये जहां इस्लामी मुल्क में पहुंच गए कि उनका वरतपाक से स्वागत होगा, पर इसके विपरीत उनमें से बहुत से ब्रिटिश गुप्तचर समझ गए। अफगानिस्तान से अपनी आबाणी ही नहीं संपरती थी, वह बाहर के लोगों को कैसे रखता? इस हिजरत से फिर भी कुछ फायदा हुए। जो लोग इस धोखे में थे कि शास्त्रों में चाहे जो लिखा हो, पर प्रत्येक मुल्क का आदमी अपने ही आदमी को चाहता है और धमभाई होने के कुछ विशेष फायदे नहीं हैं। उन्हें यह भी पता हो गया कि बाहर के मुसलमानों को यहां के मुसलमानों से सहानुभूति नहीं है। कुछ हिजरती मुसलमान तो भटककर रूस चले गए, वहां उन पर यह पभाव पड़ा कि वे कट्टर मुसलमान होने के बजाय धर्म विरोधी समाजवादी हाकर लौटे।

पहली अगस्त को असहयोग घोषित कर दिया गया। इसका पहला असर यह हुआ कि ब्रिटिश युवराज भारत आने वाले थे, सो उन्होंने अनिश्चित काल के लिए अपनी यात्रा स्थगित कर दी। उनकी जगह पर ड्यूक ऑफ कनाट का आना निश्चित हुआ।

## कांग्रेस का विशेष अधिवेशन

असहयोग का इस तरह से प्रारंभ ता हो चुका था, पर सोचा गया कि इस प्रश्न का कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन के सामने रखा जाय। तदनुसार 4 सितम्बर 1920 को कलकत्ते में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ। लाला लाजपत राय सभापति हुए। लालाजी महायुद्ध छिड़ने के साथ अमेरिका चले गए थे बाद को वह नहा आ पाए। अमेरिका में वह इंडिया ब्यूरो स्थापित कर तथा 'यंग इंडिया' पत्र प्रकाशित कर भारत का प्रचार काय कर रहे थे। वह 20 फरवरी को भारत लौटे, फिर 'बंदे मातरम' पत्र चलाने लगे।

**मुख्य प्रस्ताव**—इस कांग्रेस का मुख्य प्रस्ताव यो था

'चूंकि खिलाफत के मामले में भारतीय तथा ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मुसलमानों के साथ अपने कृतव्य का पालन न करने वादाखिलाफी की है इसलिए प्रत्येक अमुसलमान का यह कृतव्य है कि अपने मुसलमान भाई की मदद करें। चूंकि भारत सरकार तथा संसद की सरकार ने पंजाब की निहत्थी जनता के साथ जिन अफसरो ने अयायपूर्ण बर्ताव किया, उन्हें सजा देने में तत्परता नहीं दिखाई और इस तरह यह प्रमाणित कर दिया कि पंजाब के मामले में सरकार पाय करना नहीं चाहती, जोर न उनमें कोई पश्चात्ताप की भावना ही है चूंकि अस्तोष के इन दोनों कारणों का दूर किए

बिना भारत में कोई शांति नहीं हो सकती, इसलिए भारत के आत्म-सम्मान का तकाजा यह है कि भारत के लोग अब अहिंसात्मक असहयोग का मार्ग ग्रहण करें।”

**कायक्रम—** इस प्रस्ताव में कहा गया कि (1) सब उपाधिया, ऑनरेरी पद तथा स्थानीय स्वायत्त शासन की सस्याओं से नामजद किए हुए सदस्य इस्तीफा दें, (2) सरकार के दरबारों तथा राजभक्ति प्रकट करने के लिए बुलाई गई सभाओं में भाग न लिया जाय, (3) लड़कों को धीरे धीरे सरकारी तथा सरकार की सहायता प्राप्त शिक्षा-सस्याओं से निकाल लिया जाय, राष्ट्रीय विद्यालय खोले जाए तथा उनमें लड़के भर्ती किए जाए, (4) ब्रिटिश अदालतों का वकील तथा मुकदमे वाले धीरे-धीरे बायकाट कर दें, और आपसी झगड़ों के लिए अपनी अदालत जारी की जाय, (5) फौज और कुली और तथा अन्य सरकारी कार्यों में नियुक्त लोग ईराक जाने से इनकार कर दें, (6) नये शासन सुधार के अनुसार जो कौंसिलें बनी हैं, उनमें न तो वोटर लोग वोट देकर किसी को भेजें, और न कोई उनके लिए खड़ा हो, (7) विदेशी माल का बायकाट किया जाए।

**धर्म का प्रचार—** इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि चूंकि भारत की मिलें अभी इतना कपड़ा नहीं बना सकती जिससे राष्ट्र की जरूरत पूरी हो, और आगे बहुत दिनों तक भी ये शायद ऐसा न कर सकें, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि चर्खा चलाना शुरू किया जाए।

**गांधीजी का क्रांतिकारित्व—** महात्माजी ने यह प्रस्ताव रखा था। यह द्रष्टव्य है कि गांधीजी ने पहले पहल चर्खों को मिल प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि पूरक रूप में रखा था। मित्र मालिक इस कार्यक्रम से क्यों नहीं घबड़ाए यह स्पष्ट है। इस अवसर पर हम कुछ ठहराए यह देख लें कि महात्माजी ने जो कार्यक्रम इस अवसर पर देश के सामने पेश किया, उसकी प्रत्येक बात (यहां तक कि चर्खा भी) पहले के आंदोलनों में थी।

## नागपुर कांग्रेस 1920

अगली कांग्रेस नागपुर में 1920 में श्रीविजय राघवाचार्य के सभापतित्व में हुई। श्री जमनालाल बजाज इस बार स्वागताध्यक्ष थे। इसी कांग्रेस में असहयोग के सबंध में अंतिम फसला होना वाला था। इस कांग्रेस में 14 हजार प्रतिनिधि उपस्थित थे। यह अधिवेशन कई दृष्टियों से बहुत ही महत्वपूर्ण था। गांधीजी का असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ, पर बंगाल तथा महाराष्ट्र की ओर से इसका विरोध हुआ। अकेले देशबन्धुदास 250 प्रतिनिधि लेकर नागपुर आए थे। पर उन्होंने गांधीजी का विरोध नहीं किया। इस अधिवेशन में कांग्रेस का नया विधान बना। अ०भा० कांग्रेस कमेटी का नए ढंग में निर्माण हुआ। कार्य समिति बनी। गांधीजी ने बतलाया कि कांग्रेस का उद्देश्य सब प्रकार के वैध तथा शान्तिपूर्ण उपायों से भारत के लोगों द्वारा स्वराज्य की प्राप्ति है। कुछ लोगों ने जो इस नए ढंग से घबरा रहे थे, उद्देश्य पर बहुत बारीक बहस छेड़ दी। जिन्ना इसी के वाक्य से कांग्रेस से अलग हो गए। इससे प्रमाणित हो गया कि वह जन आंदोलन से विचलित थे। उनकी हृदयहीनता थी।

**गांधी युग का आरंभ—** ड्यूब आफ कनाट के स्वागत के बायकाट का प्रस्ताव पास हो गया। मुसलमानों को इमराने घयबाद दिया गया कि उन्होंने गो-वध बंद करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। इसी कांग्रेस से गांधी-युग का सूत्रपात हुआ, ऐसा कहा जा सकता है। इस युग में जैसा कि बाद में हम देखेंगे, कई बार अपने माधियों के सामने उन्हें गच्चा खाना पड़ा, और एकाधिक बार तो कांग्रेस से अलग भी हो जाना पड़ा, पर



अन्त में उही की जीत रही।

**अथ काय—**जनवरी में श्री जमनालाल बजाज ने तिलक स्वराज्य फंड में एक लाख रुपए दिए। देशबन्धुदास को इस बात का भार सौंपा गया कि वह मजदूरों का संगठन करें। मि० एल० आर० तैयबजी का आर्थिक वायकाट कमेटी का सयाजक बनाया गया। तिलक स्वराज्य फंड के लिए एक करोड़ रुपए की भाग की गई। गावा और गृह में जोर का प्रचार काय शुरू हुआ। मकड़ों सभाएं होने लगी। अभी तक राजनीतिक कार्यकर्त्ता गावों में नहीं जाते थे, पर अब गावा में भी राजनीति पहुंची। चर्खे चलने लगे।

**आन्दोलन जोरों पर—** घर पकड़ होती रही। कांग्रेस काय समिति ने 30 अप्रैल के अपने अधिवेशन में यह राय दी कि गिरफ्तार असहयोगी अदालत से सहयोग न करें। हा, वह एक बयान दे सकता है। जमानत, मुचलका देने की भी मनाही कर दी गई। जुलाई के अन्त में अ० भा० कांग्रेस कमेटी की बैठक में मालूम हुआ कि चन्ना एक करोड़ से 15 लाख अधिक मिला। पर सदस्य एक करोड़ की जगह 50 लाख हुए और 20 लाख बरखे चल रहे हैं। तब हुआ कि पहली अगस्त में कोई भी कांग्रेस जन विरोधी वस्त्र नहीं पहनेगा। बम्बई के मित्र मालिकों से कहा गया कि मजदूरों का पेट न काट्ट हुए मिला के कपड़े को सस्ता कर दें। विलायती कपड़े के व्यापारियों से कहा गया कि वे नया माल न मगावें, और जो माल है उसे विदेशों में खपा दें।

**मौलाना मुहम्मद अली—** आन्दोलन दिन दूना रात चौगुना बढ़ता गया। सरकार ने जब इस आन्दोलन का बढ़ते देखा, तो दमन चक्र शुरू हो गया। संयुक्त प्रांत (उत्तर प्रदेश) और बंगाल में कांग्रेस तथा खिलाफत के वालंटियर दल को गर कानूनी करार दिया गया। कराची में 8 जुलाई 1921 को खिलाफत कांफ्रेंस के शवसर पर मौलाना मुहम्मद अली ने एक तगड़ा व्याख्यान दिया। इस कांफ्रेंस में यह प्रस्ताव पारित हुआ था कि कोई फौज में शरीक न हो। इस सम्बन्ध में कई अदमियों को मज्जा हुई। जिस समय गांधीजी को मालूम हुआ कि मुहम्मद अली आदि पर एक व्याख्यान तथा प्रस्ताव के संबन्ध में मुकदमा चल रहा है वह त्रिचनापल्ली में थे। तब गांधीजी ने स्वयं एक सत्र में उसी व्याख्यान को सुनाया और कांग्रेस कमेटियों से भी कहा कि वे इस व्याख्यान को देश के कोने कोने में दुहरावें। पर इस सम्बन्ध में न तो वह खुद और न और कोई गिरफ्तार हुआ।

**ब्रिटिश युवराज का वायकाट—** 12 नवम्बर को युवराज भारतवर्ष पधार। असल में युवराज नई असेम्बली का उद्घाटन करने वाले थे पर जैसा कि हम बता चुके हैं, अगस्त, 1920 में भारत का राजनीतिक वातावरण ऐसा था कि ब्रिटिश सरकार ने उनका न भेजकर ड्यूक आफ कनाट को भेजा था। कांग्रेस ने पहले ही तय किया था कि युवराज का वायकाट किया जाएगा। तदनुसार युवराज का वायकाट किया गया और साथ ही विलायती कपड़े जलाए गए। जिस दिन युवराज बम्बई पहुंचे, उस दिन बड़ जोरों का सरकार विरोधी दंगा हुआ, और यह दंगा तीन चार दिन तक चलता रहा। गांधीजी और सरोजिनी देवी भीड़ में घुसकर लोगों को समझाते रहे पर दंगा कठिनाता से बंद हुआ। लोग अंग्रेजी राज्य का खातमा करके ही दंग लेना चाहते थे। बहुत से आदमी जान से मारे गए। गांधीजी ने इन सबका प्रायश्चित्त करने के लिए 7 दिन का उपवास रखा। यदि गांधीजी इस प्रकार इन दंगा का न रोकते तो पता नहीं पानी कहा जाकर सकता। इन दिनों जो आन्दोलन हो रहा था उसकी पृष्ठभूमि में प्रबल आर्थिक कारण थे।

**समझौते की आशा—** इही दिनों पंडित भदनमोहन मालवीय ने सरकार और कांग्रेस समझौते की चेष्टा की।

## अहमदाबाद कांग्रेस 1921

यथासमय अहमदाबाद कांग्रेस दिसम्बर 1921 में हुई। पर इस समय इस बार के निर्वाचित सभापति देशबन्धु दास तथा 30,00 अ य लोग जेल में थे। हकीम अजमल खा सभापति हुए। आंदोलन व प्रधान मैनपति अभी जेल के बाहर थे। यह बात आपात दृष्टि से आश्चर्यजनक होने पर भी असली बात यो है कि सरकार डरती थी कि गांधीजी की गिरफ्तारी से न मालूम कौसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए। अहमदाबाद कांग्रेस के पहले तक कुर्सी तथा बेंच आदि का इस्तेमाल होता था, पर अबकी बार यह सब हटा दिया गया था। कांग्रेस अब जनता में आ चुकी थी। अंग्रेजी की जगह हिंदुस्तानी का प्रयोग हुआ, और अब कांग्रेस में खट्टर ही लट्टर दिखाई देने लगी।

पूण स्वतन्त्रता का प्रस्ताव गिरा—असहयोग पूरे जोर पर था। अहमदाबाद कांग्रेस की सबसे बड़ी घटना यह है कि कवि हमरत मुहानी ने कांग्रेस के लक्ष्य की 'विशेषता के प्रभाव से सम्पूर्ण रूप से मुक्त पूण स्वतन्त्रता' के रूप में परिभाषा करनी चाही, पर गांधीजी ने इसका विरोध किया। मुहानी का प्रस्ताव गिर गया। इस कांग्रेस में गांधीजी पहली बार कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के सर्वाधिनायक (डिप्टेटर) चुने गए।

बारदोली में तयारी—उधर गांधीजी खगानबंदी के लिए तैयारी कर रहे थे। इस लिए बारदोली चुना गया। वहां के लोगों पर गांधीजी का विशेष प्रभाव था। गांधीजी गुले हुए थे, उन्होंने पहली फरवरी को साठ साहब का यह सूचना भी दे दी कि बारदोली में खगानबंदी शुरू होगी। बल्लभभाई पटेल और उनके बड़े भाई विठ्ठलभाई पटेल बारदोली तथा गुजरात के सबसे बड़े नेता थे।

चौरीचौरा से आंदोलन का अंत—आंदोलन देश भर में तेजी में चल रहा था। उसी सिलसिले में 5 फरवरी को चौरीचौरा में निहत्थे गांववालों का एक जुलूस निकल रहा था, पुलिस ने इसमें बाधा पहुंचाई। पुलिस ने गोनिया चलाई और तब तक चलाई जब तक उनकी गोनिया खत्म नहीं हो गई। दो हिंदू और एक मुसलमान मारे गए। तब पुलिसवाले भागकर बचने पहुंचे। इस पर जनता ने बचने में आग लगा दी। इसमें 22 पुलिसवाले जलकर मर गए। इससे गांधीजी पर इतना असर हुआ कि उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और हिदायत दी कि आगे कोई भी ऐसा कार्यक्रम न चलाया जाए जिसमें गिरफ्तारी की गुंजाइश हो। अब देश के सामने केवल रचनात्मक कार्यक्रम रहा।

जेल में बंद नेता कुपित—असहयोग वापस लिए जाने का लोगों पर बुरा असर पड़ा। सुभाष बाबू ने अपनी पुस्तक 'भारतीय सग्राम' में इसके विषय में यह लिखा है कि ऐसे समय जब कि जनता का जोश सर्वोच्च बिंदु पर पहुंच चुका था, पीछे लौटने का नारा राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। महात्माजी के सभी मुख्य शिष्य चित्ररजन दास, मोतीलाल नेहरू, लाजपतराय सभी दुःख हुए। मैं उन दिनों देशबन्धु के साथ जेल में था, इस दुःख से उनका बुरा हाल हुआ। नेताओं ने गांधीजी के पास शोधपूर्ण पत्र भी लिखे, पर गांधीजी ने इन सब सदेशों को यह कहकर टाल दिया कि जो लोग जेल में हैं, वे नागरिक रूप से मरे हुए हैं, उनका किसी बात में बोलने का कोई अधिकार नहीं।

रचनात्मक कार्यक्रम—गांधीजी ने असहयोग के सग्रामात्मक भाग को स्पष्टित कर देने के बाद यह तय किया कि अब रचनात्मक कार्यक्रम लेकर चला जाए। रचनात्मक कार्यक्रम के सम्बन्ध में गांधीजी की धारणा भी बराबर विकसित होती रही है, इस कारण

यह बताया दिया जाय कि इस समय हमसे सरका गया मतलब था। इस समय रचनात्मक कार्यक्रम में उतका मतलब था - (1) रक्षा तथा रक्षा प्रचार, (2) अष्टनीदार, (3) राष्ट्रीय गिणन मस्याआ की स्थापना, (4) कांग्रेस में सदस्या की भर्ती तथा (5) जन पचायतो की स्थापना। 24 तथा 25 फरवरी, 1922 का निम्नी म अ० भा० काडन कमेटी का जा अधिवेशन हुआ उसमें यही सार कार्यक्रम स्वीकृत हुआ।

गांधीजी गिरफ्तार - यद्यपि गांधीजी का आदानन वापस ले लिया था, फिर भी सरकार मोता पाते हो उनको गिरफ्तार करना चाहती थी। जब जानकारी परिशिर्षि समाप्त हो गई, और देा ग फिर निद्रा-मी छाने लगी, और सरकार न यह ममक विरा कि जब उह गिरफ्तार करने में कोई सतरा नहीं है तब 13 मार्च को गांधीजी गिरफ्तार कर लिए गए। वहा तो उनकी गिरफ्तारी पर प्राति का भय था, पर अब एक उगनी का नहीं उठी।

मुकदमा और सजा—उन पर दवा 124 अनिक मुकदमा चलता, और 'पु इडिया' में प्रकाशित तीन लेखा के सम्बन्ध में Tampering with Loyalty, Puzzle and its solution, Shaking the manes मुकदमा चलता। उन्हें छह सन की सजा दी गई। गांधीजी ने सार आदोलन, विरोध और चोरीचोरा को जिम्मगारा जत ऊपर ले ली। गांधीजी न उदारतापूर्वक आदानन वापस ले लिया, पर सरकार ने राय नतिक न दिया को नहीं छोडा, इसमें विपरीत और लोग भी गिरफ्तार होते गए। गांधीजी हिमा में विश्वास नहीं करते थे पर ब्रिटिश सरकार केवल उनी में विश्वास करती थी।

मुस्लिम लीग की घुरी हालत—इस बीच में लीग की क्या हालत थी इस भी हम संक्षेप में देख लें। लीग की 1921 घानी बैठक का लीग के जीवन की सतर मशन दिया था। यह इजलास मोलाना फजलुल हसन के सभापतित्व में अहमदाबाद में हुआ था और पहले के सालों की तरह इस बैठक में कांग्रेस के बाहर मौजूद सभी बड़े नेता यान महात्माजी, विजयराघवाचार्य पटेल, हकीम अजमल खा उसमें गए थे। देश में, विषय पर मुमलमानों में भी बड़ा जोश था, पर लीग में कम लोग मरे पडे थे, वे असहयोग प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थे। सभी क्रियाशील मुसलमान उन दिनों तिलाफ्त का फंस में थे। लीग में असहयोग का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था, इस कारण लीग लोमा की नजरा में गिर गई। लीगी नेता इस्लाम के नार पर भी खडे नहीं हो सके। वे घर बडे रहे। लीग का सितारा इस समय ऐसा डबा कि 19-2 में इसकी कोई बैठक ही नहीं हुई। 1923 के मार्च का लीग की बैठक संखनऊ में गुलाम मुहम्मद मरगिरी की अध्यक्षता में बुलाई गई पर कोरम पूरा न होने की वजह से सभा विरजित कर दी गई। इस प्रकार सग्राम के युग में लीग का बुरा हाल रहा। बाद की भी जब सग्राम हुआ, लीग डुबकी लगा गई।

## गया कांग्रेस 1922

कांग्रेस का अगला अधिवेशन गया में 1922 में देखवधु दास के सभापतित्व में हुआ। श्री दास ने कमाल पाशा के नेतृत्व में उदीयमान स्वतंत्र तुर्की राष्ट्र का अभिादन किया, और एशियाई सघ का नारा दिया। उन्होंने बदली हुई स्थिति में बदली हुई कम पद्धति का नारा दिया। वह धारासभाआ के बायकाट के पक्ष में कभी नहीं थे, अब उन्होंने खुलकर इसका नारा दिया। पर राजगोपालाचारी के नेतृत्व में अधिकांश प्रतिनिधियों ने कांग्रेस के पहले कार्यक्रम पर डटे रहने का नारा दिया। कांग्रेस में दो दल हो गए, एक

परिवर्तनवादी, दूसरा अपरिवर्तनवादी। अपरिवर्तनवादियों की ही बहुसंख्या रही, इसलिए श्री दास न इस्तीफा दे दिया, गांधीजी की गिरफ्तारी के साथ ही सविनय अवज्ञा सवधी परिस्थिति की जाच के लिए एक कमटी नियुक्त हुई थी, इस कमेटी के मददगार भी मतभेद हो गया था। हकीम अजमल खा, मातीलाल नेहरू तथा विट्ठलभाई पटेल ने देशबन्धु के पक्ष में और डा० असारी, रानगापालाचारी तथा आयगर न इसक विरुद्ध राय दी। पर श्री दास न जब इस्तीफा दे दिया और मोतीलाल नेहरू न स्वराज्य पार्टी के निर्माण की घोषणा कर दी, तो परिस्थिति बदल गई। सुभाष बाबू न लिखा है कि गया कांग्रेस से अपरिवर्तनवादी जीत कर गए, पर उनके मन में गुशी नहा थी और स्वराज्य हार कर गए, पर वे लड़कर जीतने के लिए कटिबद्ध थे।

इसका सघष — हुआ भी यही। 1923 के मध्य भाग तक स्वराज्यी ५० भा० का० कमेटी में बहुसंख्या में हो गए, इस कारण काय समिति को इस्तीफा देना पड़ा। पर स्वराज्यी भी कायसमिति बनाने के लिए तैयार नहीं थे, इस कारण कुछ मध्यमपथी काय समिति बनाकर चलने लगे। सब प्रांता में दो दलों में भगड़ा चलन लगा यहाँ तक कि बंगाल में एक माय दो कांग्रेस कमेटियाँ चलती रही। इन्हीं बातों के कारण भित्तम्बर, 1923 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया।

खिलाफत का अंत और उसका प्रभाव ——उधर यूरोप में कमालपाशा ने तुर्की की स्वतंत्रता के लिए जोड़ा छेड़ी थी, वह सफल हो गई और 1923 की जुलाई में तुर्की राष्ट्र एक सच्चमुच्च स्वतंत्र राष्ट्र हो गया, यान उस पर से विदेशिया का प्रभाव नष्ट हो गया। तुर्की मुलतान भाग गए और तुर्की राष्ट्र गणतान्त्रिक हो गया। पहले कमालपाशा न खलीफा नियुक्त किया था, पर बाद को उसे कतई खतम कर दिया। इस प्रकार खिलाफत का अंत हो गया। कमालपाशा ने अरबी लिपि हटाकर तुर्की भाषा की लिपि रोमन कर दी। उन्होंने कहा कि तुर्की नागरिक मात्र मसजिद के अंदर मुसलमान हैं।

## दिल्ली का विशेष अधिवेशन

दिल्ली के विशेष अधिवेशन में कौंसिल प्रवेश के लिए उस माग में विश्वास करने वाला को स्तत्र कर दिया गया। अब तो स्वराज्य पार्टी काकायदा चुनाव की तैयारी करने लगी। भित्तम्बर तक चुनाव हो गया और स्वराज्य पार्टी की अच्छी जीत रही। हम सगे हाथों यह देख लें कि कभी बंगाल के 'बिताज के बादशाह' मुरेद्रनाथ (जो पहल ही 'सर' हो चुके थे) अब चुनाव में स्वराज्य पार्टी के विरुद्ध लड़े हुए तो उन दिनों के एक मामूली व्यक्ति विधान सभा के विरुद्ध हार गए। नगरपालिकाएँ पहले के बनिस्तरन स्वतंत्र हो गई और उन्हें गैर सरकारी चेयरमैन चुनने का अधिकार मिला।

स्वराज्य पार्टी का दान — पंडित मोतीलाल स्वराज्य पार्टी को ओर से केन्द्रीय धारा सभा में गए, और उन्होंने शुरू से ही बड़ी योग्यता तथा निर्भीकता प्रदर्शित की। स्वराज्य पार्टी के नेतृत्व में पहले ही राष्ट्रीय माग पर एक प्रस्ताव पेश हुआ जिसका जय यह था कि फौरन औपनिवेशिक स्वराज्य के ढाँचे पर शासन विधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाए। सरकार ने इस पर सर अलेक्जेंडर मूडीमैन के सभापतित्व में एक कमेटी बनाई, पर इसका कोई नतीजा नहीं निकला। इस प्रकार स्वराज्य पार्टी के कारण देश में एक तरह का जोश बना रहा, जो केवल रचनात्मक कार्यक्रम से कभी सम्भव नहीं था। उन दिनों स्वराज्य पार्टी और अपरिवर्तनवादियों में जो झगड़े चले, वे बाद की मुला दिए गए क्योंकि बाद को सारी कांग्रेस ही स्वराज्य पार्टी हो गई। बाद को कांग्रेस एक साल सत्याग्रह करती, तो नौ साल स्वराज्य-पार्टी बनी रहती। इस दृष्टि से देखने पर

श्री दाम के तान को उतना महत्व नहीं दिया गया, जितना दिया जाना चाहिए। बापू का गांधीवादा का जो रूप बना, उसमें दासवाद आ गया। दास जीवित नहीं रहे, इस कारण इतिहास में उन्हें पूरा श्रेय नहीं मिला।

## कोकनद-कांग्रेस 1923

1923 व ली कांग्रेस कोकनद में मौलाना मुहम्मद अली के सभापतित्व में हुई। इसमें भी कोसिल प्रवेश का ममयन किया गया। मौलाना मुहम्मद अली ने कोसिल प्रवेश के पक्ष में राय दी।

**गांधीजी और स्वराजी**—गांधीजी जेल से छूटे तो देश में स्वराज्य पार्टी का रोव बैठ चुका था। इस पर, जैसा कि सुभाष बाबू ने निम्ना है, "उन्होंने अनिवार्य रूप से सामने फिर झुका दिया या हास्य है कि उन्होंने यह समझा हो कि बदली हुई हालात में नीति बदलनी चाहिए।" कुछ भी हो, वे स्वराजी नता श्री दास और प० मातीन से मिले और इनमें एक तरह का समझौता हो गया। वह समझौता जिस गांधी दान पकट कहा गया इस आशय का था कि महात्माजी खट्टर प्रचार में लगें, और राजनैतिक कार्य स्वराजियों के हाथों में रहें जिसमें गांधीजी स्वराज्य पार्टी या कांग्रेस के हस्तक्षेप के बगैर अपना काम कर सकें। गांधीजी को अधिकार दिया गया कि वे 'चर्खा सभ' नामक स्वतंत्र सभा का संगठन करें। सुभाष बाबू ने यह भी साफ लिखा है कि 'स्वराज्य पार्टी' के लोगों के मन में गांधीजी के लिए बहुत इज्जत होने के बावजूद यह पार्टी इतनी मजबूत थी कि इसने गांधीजी का इच्छापूर्वक राजनीति से बैठ जाने के लिए मजबूर किया, और उन्हें करीब करीब 1928 यानी कलकत्ता कांग्रेस तक बैठ ही रहना पड़ा।"

**फिर क्रांतिकारी संगठन**—जब तक असहयोग आन्दोलन चला, भारतीय क्रांतिकारी चुप थे। अब बिखरे हुए क्रांतिकारी दल फिर से संगठित होने लगे। कुछ पुराने क्रांतिकारी नेता पस्त हो चुके थे, उनकी जगह नए नेता आए। कुछ पुराने नेता भी संगठन करने लगे पर सफल सफल नहीं। उत्तर भारत में शचीन्द्रनाथ सायान तथा बंगाल में अनुशीलन समिति आदि संगठन करने लगे।

**गोपीमोहन शाहा**—हम इस आन्दोलन के व्योरे में नहीं जाएंगे। 3 अगस्त, 1923 को जब कुछ क्रांतिकारियों ने शारंगरी टोला पोस्ट ऑफिस पर हमला कर दिया, तो पता लगा कि क्रांतिकारी आन्दोलन सिर उठा रहा है। इस प्रकार की कुछ और घटनाएँ हुईं। 1924 की जनवरी को गोपीमोहन शाहा ने जब बुध्यात पुलिस साहब टैगट के घोड़े में एक अग्रेज सीदागर अर्नेम डे को मार डाला, तो बड़ी सनसनी फैली। उसी साल बंगाल में सिराजगंज में मौलाना अकरम खा के सभापतित्व में प्रादेशिक राजनैतिक कांग्रेस का शहीद की देशभक्ति तथा साहस की प्रशंसा की गई। गांधीजी ने इस प्रस्ताव की बहुत कड़े शब्दों में निंदा की। देशबन्धु ने उसका उत्तर दिया जिस पर बात बढ गई। जून में अहमदाबाद में जब अ० भा० कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई तो महात्माजी ने सिराजगंज वाले प्रस्ताव के विरुद्ध एक प्रस्ताव रखा। देशबन्धु ने इस पर एक सशोधन रखा, पर गांधीजी कुछ वोटों में जीत गए।

**कोहाट का दगा**—इसी साल नई जगह हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। कोहाट में सितम्बर का दगा उठा मयकर रहा। कोहाट के दंगे की जांच करने के लिए गोकुल अली और गांधीजी की एक कमेटी बनी, पर वे एकमत नहीं हो सके। गोकुल अली इस राय पर पहुँचे कि दोष हिंदुओं का है, जबकि तथ्य यह था कि हिंदू सड़कों की तादाद में मारे

गए थे। यही से अली भाई साम्प्रदायिकता की ओर जाने लगे। गांधीजी ने कोहाट के दगे पर दिल्ली में मोलाना मुहम्मद अली के घर में 21 दिन का उपवास शुरू किया। इसी लक्ष्य में एक एकता का फ़र्म भी हुई, पर दगे नहीं रहे।

बंगाल आर्डिनेंस - बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन संगठित हो रहा था। मध्य-वित्त नौजवान धडाधड नातिकारी दल में शामिल होत चले जा रहे थे पर प्रचलित कानून के अ तगत सरकार इन सभी को पकड़न में असमर्थ थी। शारगरीटोला डाकखाने की लूट के मामले पर सरकार ने एक पड्यत्र चलाना चाहा था, पर यह मुकदमा छूट गया। तब रेगुलेशन 3 का प्रयोग हुआ। अप्रैल 1924 में मिस्टर ब्रूस की हत्या का प्रयत्न किया गया, फिर फरीदपुर में बम निकला। दो एक क्रांतिकारी पिस्तौल सहित गिरफ्तार हुए। शचीन्द्र सा माल लिखित 'रिवालयूननरी' पत्र सारे भारत में पढ़ने ही बट चुका था। 18 अक्टूबर को मयूकन प्रा त में लोटते हुए योगेशचन्द्र चटर्जी हावडा स्टेशन पर गिरफ्तार हो गए। उनके पास कुछ कागजात मिले, जिनसे सरकार को यह पता लगा कि बंगाल के बाहर कम से कम 23 स्थानों में क्रांतिकारी संगठन हो चुका है। बस, 25 अक्टूबर 1924 को बंगाल आर्डिनेंस जारी कर दिया गया। यह रोलट ऐक्ट का सगा भाई था।

दमन का प्रतिवाद—इस आर्डिनेंस में सुभाष बाबू, जो उन दिना कलकत्ता कापोरेशन के एक्जीक्यूटिव आफिसर थे, तथा बंगाल स्वराज्य पार्टी के अध्यक्ष नेता गिरफ्तार हो गए। इस आर्डिनेंस के द्वारा बंगाल के सब प्रगतिशीलों पर हमला किया गया। बम्बई में इसी दमन का प्रतिवाद करने के लिए तथा स्वराज्य का एक मसबिदा बनाने के लिए 21 तथा 22 नवम्बर को एक सबदल सम्मेलन बुलाया गया।

## बेलगाव कांग्रेस 1924

दिसम्बर 1924 में महात्मा गांधी के सभापतित्व में बेलगाव में कांग्रेस हुई। गांधीजी ने अपने भाषण में सम्पूर्ण रूप से हिंसा और त्याग पर जोर दिया। उन्होंने, मतभेद के बावजूद, स्वराजियों और असहयोग में आस्था रखने वालों के कांग्रेस के अंदर सहअस्तित्व का प्रोत्साहन दिया। साथ ही लिबरलों को कांग्रेस में लौट आने की यह कहकर सलाह दी कि जब मर्यादा नहीं हो रहा है, तो आप लौट जाए। गांधीजी ने अपने 'यादगार' का अंत बदेमातरम से किया। बेलगाव में रचनात्मक कार्यक्रम पर जोर दिया गया।

कानपुर पड्यत्र - 1924 का विवरण समाप्त करने के पहले कानपुर पड्यत्र का उल्लेख करना उचित होगा। 1917 की क्रांति के कारण रूस में समाजवादी राष्ट्र स्थापित हुआ था। समाजवादी रूप में उसी समय से क्रांतिकारियों के लिए रूस तीर्थ स्थान बन गया था। समाजवादियों का उद्देश्य केवल एक देश में समाजवाद स्थापित करना नहीं है। सच तो यह है कि किसी एक देश में तब तक केवल एक सीमा तक ही समाजवाद स्थापित हो सकता है जब तक सब देशों में समाजवाद स्थापित न हो जाए। फिर समाजवाद का उद्देश्य जखिल मानव जाति में शांति का अंत है। नरेन्द्र भट्टाचार्य उफ एम० एन० राय पुराने क्रांतिकारी थे। वह अस्त्र शस्त्र के सिलसिले में बटविया भेजे गए थे, पर उधर ही जब उन्हें पता लगा कि भारत में दमन हो रहा है तो वह घूम घूम कर रूस पहुंचे। वहां में उन्होंने भारत में पत्र आदि भेजकर समाजवादी संगठन स्थापित करने की चेष्टा की। उनके चलाए संगठन में सौ के करीब लोग आए। कानपुर पड्यत्र में श्री डागे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी की चार चार साल की

सजा हुई।

दास की मृत्यु—16 जून 1925 को श्री दास का देहांत हुआ। उनकी मृत्यु ने स्वराज्य पार्टी को विधाय नुकसान पहुंचा। फिर भी 21 और 22 सितम्बर को कांग्रेस कांग्रेस कमेटी की बैठक में स्वराज्य पार्टी की ही जीत रही।

कांग्रेस और नगरपालिका—इस बीच गांधीजी के छूटने पर जो वास्तविकता के साथ सूरत का 'वखेता' लग गया था, वह जाता रहा। चार आना के पास दो अब यह माना गया। कट्टर अपरिवर्तनवादी सन, चरखे में ही व्यस्त रहे, ऐसा नहीं हुआ बल्कि इन तार नगरपालिका के चुनावों में उन लोगों ने भाग लिया, और स्वस्थ संस्थाओं पर कांग्रेस का कब्जा हो गया।

पदलोपपत्ता सत्या विगठन—परन्तु स्वराज्य दल के कुछ लोगों में पदलोपपत्ता की जोर मार रही थी। व्यर्थ के विरोध से उन्हें कुछ फायदा नहीं लग रहा था। मध्यप्रान्त की कौंसिल में एक स्वराज्यी सभासद ने पार्टी की पीठ के पीछे एकाएक गवर्नर की कार्य समिति में मददगार ग्रहण कर ली। पं० मोतीलाल ने इसका विरोध किया और बताया कि कुछ समय में कुछ लोग इसी ओर झुक रहे हैं, यह इसी का नतीजा है। केवल, जयकर, मुझे भी स्वराज्य दल की कौंसिल से अलग हो गए।

## कानपुर कांग्रेस 1925

1925 में कानपुर में श्रीमती सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। श्रीमती नायडू अंग्रेजी की कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध थी। वर्षों से वे गांधीजी की शिष्या थी। उन्होंने हिंदू मुस्लिम बमनस्य पर दुःख प्रगट करते हुए मुनक्त मानो से कहा कि वे देश की बात अधिक साचें न कि शाम, ईराक, अरब और मिस्र की। उन्होंने भाषण का अन्त तमसो म ज्योतिर्गमय' के अंग्रेजी अनुवाद से किया। कानपुर कांग्रेस में बहुत से प्रस्ताव पास हुए। हम पहले ही बता चुके हैं कि इस समय तक देश में निर्जीवता आ चुकी थी। स्वराज्य पार्टी का जोर घट रहा था। इस कांग्रेस में यह प्रस्ताव पास हुआ कि सरकार फरवरी तक भारतीयों की कम से कम भाग को मान ले नहीं तो स्वराज्य पार्टी धारासभाओं से निकल आएगी।

बिखरने की प्रक्रिया—स्वराज्य पार्टी में कुछ लोग थे जो विरोध का कार्यक्रम पसंद नहीं करते थे। ऐसे लोगों ने देश के अन्य तत्वों के साथ मिलकर एक नया पार्टी बनाई जिसका नाम 'इंडियन नेशनल पार्टी' रखा गया। कहीं ये लोग बहुत दूर नहीं जाए, इस कारण गांधीजी ने 21 अप्रैल को साबरमती में एक कांग्रेस बुलाई, जिसमें एक सम्मेलन हुआ। पर यह सम्मेलन टिक न सका। जो लोग बिना देखे सुन विधानसभा में कूदना चाहते थे, और उसे सफल बनाने के लिए दबाव की राजनीति भी नहीं करना चाहते थे, वे कब तक कांग्रेस में टिकते? इनका तो सही स्थान लिबरल फंडेशन था, और हुआ भी यही। ऐसे लोग अन्त तक हिंदू महासभा में चले गए।

इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी—कुछ मध्यमस्थ थे, जैसे लालाजी और पंडित मदनमोहन मालवीय। 1926 के नवम्बर में जब आम चुनाव होने को हुआ तो लालाजी स्वराज्य पार्टी से अलग हो गए और मालवीय जी के साथ मिलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बनाई। इस बार चुनाव में बहुत अच्छे नतीजे नहीं रहे।

## गुवाहाटी कांग्रेस 1926

ऐसी स्थिति में 1926 में श्री श्रीनिवास आयंगर के सभापतित्व में गुवाहाटी में

कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस साल बराबर हिंदू मुस्लिम दंगे होते रहे। ऐन कांग्रेस अधिवेशन के पहले स्वामी श्रद्धानंद अब्दुरशीद नामक मुसलमान आतनायी के हाथों मारे गए। स्वामीजी कुछ दिनों से शुद्धि आंदोलन चला रहे थे। स्वामी श्रद्धानंद की मृत्यु के कारण गुवाटोटी कांग्रेस में सभापति का हाथी पर जुलूम निकलने वाला था, वह रोक दिया गया।

नत्माजी ने स्वामी श्रद्धानंद सम्बंधी प्रस्ताव रखा और मुहम्मद अली ने उसका समर्थन किया। केनिया में भारतीयों पर दिन ब दिन अत्याचार की जा बढ़ि हो रही थी, उसकी निंदा की गई। नजरबंदों की रिहाई की मांग की गई। इस कांग्रेस में भी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव आया। सच तो यह है कि अहमदाबाद से बराबर यह प्रस्ताव आ रहा था। गांधीजी ने इसका विरोध किया, और प्रस्ताव गिर गया। कहना न होगा कि व कांग्रेस का अधिवेशन पहले की तरह याने गांधी से पूर्व युग की तरह नीरस हो चला था। सीतारमैया ने भी इस बात को स्वीकार करते हुए लिखा है, "अब (1926) तब कांग्रेस का इतिहास शुभेच्छापूर्ण प्रस्तावों की तथा कौंसिलों में मतभेद की झंझट से बहानी हो चली थी।" अब इसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता थी।

ब्रिटिश सरकार ने घोषित किया कि शासन विधान की जांच के लिए एक कमीशन बड़ेगा। यह खबर इतनी महत्वपूर्ण समझी गई कि गांधीजी, जो उन दिनों मंगलौर में थे, उड़ दिल्ही बुलाकर यह खबर दी गई। 8 नवम्बर को साइमन के नेतृत्व में कमीशन आने का ऐलान हो गया।

**इस बीच मुस्लिम लीग—** इस बीच मुस्लिम लीग के इतिहास को यहां देखें। हम यह तो पहले ही बता आए हैं कि सन 1921, 22 तथा '23 में लीग का जीवन खतरे में रहा। 1924 की मई में लीग के पुनरुज्जीवन के लिए लहौर में उन मुसलमानों की एक सभा हुई जिन्होंने खिलाफत तथा स्वतंत्रता के सग्राम में कोई भाग नहीं लिया था, जो घर बंदे रहे, तथा हजारों की तादाद में जो मुसलमान जेल गए थे, उनसे अलग रहे। इस सभा के सभापति हमारे पूर्व परिचित मिस्टर जिना थे। इस प्रकार लीग की गांडी फिर से चन निकली, पर इसके अधिवेशनों में कोई खास बात नहीं होती थी।

**लीग के दो टुकड़े—**दिसम्बर 1927 में सर मुहम्मद याकूब के सभापतित्व में लीग का अधिवेशन कलकत्ते में हुआ, जिसमें साइमन कमीशन के बायकाट का प्रस्ताव पास हुआ। तब हुआ कि कांग्रेस के साथ मिलकर एक विधान बनाया जाय जिसमें मुसलमानों के हकों की रक्षा हो और सिंध अलहदा हो जाय। इसी वष पक्क और सम्मिलित चुनाव के प्रश्न पर मुस्लिम लीग में विरोध हो गया था। शफकी लीग और जिना लीग नाम से इसमें दो टुकड़े हो गए थे। 'सारे जहाँ से अच्छा' के कवि सर मुहम्मद इकबाल और सर शफी ने पृथक् निर्वाचन का पक्ष लिया, और मि० जिना तथा अली भाइया ने कुछ शर्तों के साथ सम्मिलित चुनाव का पक्ष लिया। परिणाम यह हुआ कि दिसम्बर 1927 में एक ही तारीख में लीग के दो अधिवेशन हुए — शफी लीग का लाहौर में और जिना लीग का कलकत्ते में। इन दोनों टुकड़ों में कैसे मेल हुआ यह हम बाद में लिखेंगे।

## मद्रास कांग्रेस 1927

1927 में डाक्टर असारी के सभापतित्व में मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। डा० असारी बहुत उदार चरित्र के व्यक्ति थे। वह 1912 में बलकान युद्ध में मेडिकल मिशन के साथ तुर्की गए थे। मद्रास कांग्रेस में साइमन कमीशन के बायकाट का प्रस्ताव पास



हुआ। यह तय हुआ कि जिस दिन कमीशन भारतवर्ष की भूमि पर पर रहे, उमनि सार देश में प्रदर्शन हो। इस अधिवेशन में बाबूरी के शहीदों की फासी पर उनक प्रति वारा के साथ सहानुभूति प्रकट की गई और उन्हें फासी देने की निंदा की गई।

बाबूरी पडयंत्र - संसद में बतला दिया जाय कि बाबूरी पडयंत्र क्या था जिसके शहीदों के लिए कांग्रेस को प्रस्ताव करना पड़ा। हम बतला चुके हैं कि असहयोग आंदोलन बंद कर दिए जान व बाद क्रांतिकारी फिर संगठन करने लग। शचीन्दा सायल और रामप्रसाद बिस्मिल उत्तर भारत में गतिविधि हुए। उद्देश्य की पूर्ति के लिए दल की ओर से क्रांतिकारी पच्चे बांटे गए, अस्त्र शस्त्र इकट्ठे किए गए और धन के लिए डाके भी डाले गए।

इस दल की ओर से लखनऊ के पाम बाबूरी स्टेशन से कुछ फासले पर बाउन पैसंजर को रोक कर उसका खजाना लूट लिया गया। इस सिलसिले में बाद में गिरफ्तारियां हुई और पडयंत्र चला। इस मुकदमे में मरवार के कोई 15 लाख रुपये खर्च हुए। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, राजेन्द्र लाहिड़ी, रोशनसिंह तथा अशफाबुल्ला खां को फासी हुई, अन्य अभियुक्तों को काले पानी से लेकर चार साल तक की सजा हुई। देश में इन सजाओं पर बहुत जोश फैला। केन्द्रीय असम्बली के चुने हुए सदस्यों की आर से फासी की सजा रद्द करने के लिए दरदरास्त भी भेजी गई। राजेन्द्र लाहिड़ी को 17 दिसम्बर तक, बाकी तीन व्यक्तियों को 19 दिसम्बर सन् 1927 को फासी पर चढ़ा दिया गया। प्रांतीय विधानमण्डल में बचे हुए बंदिआ से विशेष व्यवहार का प्रस्ताव पारित हुआ, पर हुआ कुछ भी नहीं।

साइमन कमीशन पर क्षोभ—साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई में उतरा। उस दिन सारे देश में हड़ताल की गई। जहां जहां कमीशन गया, वहां-वहां उसका स्वागत 'साइमन लौट जाओ' के नारों से किया गया। मद्रास की जस्टिस पार्टी तथा कुछ मुस्लिम मस्थाआ के अतिरिक्त सबने इसका वायकाट किया। जिस समय यह कमीशन लखनऊ पहुंचा, तो उसके वायकाट के संबंध में पंडित जवाहरलाल तथा गोविन्द वल्लभ पंत को भी चोटें आईं। पटना में कमीशन का वायकाट हुआ। सरकार कुछ भाइ आदमियों को गांवों से फुसलाकर ले आई थी पर वे लोग आते ही प्रदर्शनकारियों में शामिल हो गए। इसी प्रकार सब स्थानों पर हुआ। लाहौर में 30 अक्टूबर को तो कुछ हुआ वह ऐतिहासिक इसलिए हो गया कि उसके साथ लाला लाजपत राय की मृत्यु तथा भगतसिंह का नाम जुड़ गया। लाहौर में लालाजी के नेतृत्व में कमीशन का वायकाट हुआ। लालाजी पर पुलिस की लाठी पड़ी। इसी चोट के बाद उन्होंने जो विस्तर पकड़ा तो फिर वे उठे नहीं और 17 नवम्बर को वीरगति प्राप्त कर गए। बाद में क्रांतिकारी दल ने इसका बदला लेने के लिए भगतसिंह चन्द्रशेखर आजाद तथा राजगुरु को भद्र कर लाहौर के पुलिस सुपरिन्टेंडेंट मिस्टर सट्स को 15 दिसम्बर को चार बजे गोलीया स मरवा दिया।

क्रांतिकारी दल ने अपने तरीके से साइमन कमीशन के बहिष्कार की चेष्टा की। काशी से मनमोहन गुप्त, माकडेंय तथा हरेन्द्र बहुत शक्तिशाली बम लेकर इसलिए रवाना हुए थे कि साइमन कमीशन को उड़ा दें परन्तु चलती गाड़ी में बम फट गया। माकडेंय स्वयं शहीद हो गए और बाकी दो व्यक्ति मनमोहन और हरेन्द्र को गिरफ्तार कर सजा दी गई।

नेहरू रिपोर्ट—मद्रास कांग्रेस में यह प्रस्ताव हुआ था कि एक तरफ तो साइमन कमीशन का वायकाट हो, और दूसरी तरफ देश के लोग एक विधान बनाएं। तदनुसार

दिल्ली में एक सवदल सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन की ओर स 19 मई को पंडित मोतीलाल नेहरू के सभापतित्व में एक कमेटी बना दी गई जिस पर यह भार सौंपा गया कि वह भारत के लिए एक विधान बनाए। यह कमेटी नेहरू कमेटी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कमेटी में अध्यक्ष ने अतिरिक्त सर तेजबहादुर सप्रू, सर अली इमाम, श्री अण, सयद कुरशी, सुभाषचंद्र बोस और जी० आर० प्रधान थे। इन लोगों ने बड़े परिश्रम से औपनिवेशिक स्वराज्य के आधार पर एक विधान बनाया, पर किसी किसी मामले में, जसा मजिस्ट्रेट तथा वैदेशिक मामलों में, कमेटी ने जो सिफारिशें की, वे औपनिवेशिक स्वराज्य से भी कम थी। यह विधान बनाने का ऊपरी उद्देश्य चाहे कुछ भी बताया जाय, पर असली उद्देश्य ब्रिटिश सरकार पर यह प्रभाव डालना था और यह दिखाना था कि हम कम में भी सन्तुष्ट होने के लिए तैयार हैं, यद्यपि कि हमें वे चीजें दे दी जाए।

**इंडिपेंडेन्स लीग**—सवदल सम्मेलन ने नेहरू कमेटी की बनाई हुई रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस के अंदर इस समय तक कुछ ऐसे लोगो का उदभव हो चुका था जो औपनिवेशिक स्वराज्य को अपना ध्येय मानने के लिए तैयार नहीं थे। इन लोगों के नेता जवाहरलाल तथा सुभाषचंद्र बोस थे। कांग्रेस के अंदर पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पाम कराने में असमर्थ रहकर इन लोगों ने इंडिपेंडेन्स लीग बना ली। ये लोग बराबर प्रत्येक प्रश्न पर इसी दृष्टिकोण से विचार करते थे, और करीब करीब एक पार्टी की तरह काम करते थे। ऐसे लोगो को नेहरू रिपोर्ट स्वीकार नहीं हो सकती थी। फिर भी इन लोगों ने इसे इस रूप में स्वीकार किया कि इसके आगे उन्हें आन्दोलन का अधिकार रहेगा।

## कलकत्ता कांग्रेस 1928

1928 में कांग्रेस का अधिवेशन पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कलकत्ते में हुआ। इस मौके पर सुभाषचंद्र बोस स्वयंसेवको के प्रधान सेनापति थे। अभी तक साइमन कमीशन भारतवर्ष का दौरा कर रहा था और सबत्र उसका विरोध हो रहा था। गोरे तथा अधगोरे अक्सर इस बायकाट में इतने खौलताए हुए थे कि उन लोगों ने अपने पत्रों में भारतीय राष्ट्रियता के सिर को कुचल देने का नारा दिया। पंडित मोतीलाल ने अपने भाषण में बायकाट की गफलता का बर्णन किया। बड़े मासिक शब्दों में उन्होंने साइमन आयोग के बायकाट में छात्रों की प्रशंसा की। उन्होंने यह भी कहा कि अपनी सामाजिक बुराइयों के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं।

**महात्माजी फिर सामने**—बहुत दिनों में महात्मा गांधी ने कांग्रेस में सक्रिय भाग नहीं लिया था। इस बार वह सामने आए और उन्होंने नेहरू कमेटी की स्वीकृति सबंधी प्रस्ताव पेश किया। विषय निर्धारणी कमेटी में इस विषय पर बड़ी चर्चा चल रही, क्योंकि इंडिपेंडेन्स लीग के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष बाबू ने इस पर सशोधन पेश किया। अंत में गांधीजी को इस प्रस्ताव में कुछ परिवर्तन करना पड़ा। बाद को जब यह प्रस्ताव उठाया गया तो सुभाष बाबू ने इस पर एक सशोधन प्रस्तुत किया जिसका समर्थन जवाहरलाल नेहरू ने किया। सीतारमैया ने लिखा है कि 'सुभाष बाबू तथा जवाहरलाल दोनों समझते थे, इसलिए गांधीजी बहुत बिगड़ गए और उन्होंने इन लोगों को डाटते हुए कहा तुम लोग जिस तरह मुसलमान अन्त्याह का नाम लेते हैं, और हिंदू कृष्ण तथा राम का, उसी तरह स्वतंत्रता-स्वतंत्रता रट रहे हो। पर इससे कुछ न होगा यदि इसके पीछे सम्मान न हो। यदि तुम लोग अपने बचन पर डटे नहीं रह सकते तो स्वतंत्रता कहा से आएगी। स्वतंत्रता इससे कठिन वस्तु

की बनी है, बातों के जमा-खर्च से स्वतंत्रता नहीं आ जाती।”

एक साल की मुहलत—इस कांग्रेस में यह भी प्रस्ताव पास हुआ कि यदि ब्रिटिश संसद 31 दिसम्बर 1929 तक संवदल सम्मेलन की मांग को पूर्ण रूप से मान ले तब ठीक है, पर यदि इसके पहले या इस तारीख तक मांग न मानी जाय तो कांग्रेस अहिंसात्मक असहयोग, टैक्स बंदी तथा अन्य उपायों का प्रयोग करेगी। अगले साल के लिए कांग्रेस में लोगों से रचनात्मक वायव्यम अपनाने की अपील की गई। देशी रिवासों को चेतावनी दी गई कि वे अपना जनविरोधी रवैया बदलें।

कांग्रेस दुविधा में—यह स्पष्ट था कि अब कांग्रेस विधानवादी कार्यो में असफलता से ऊब चुकी थी। प्रत्येक प्रातः से क्रांतिकारी आवाजें आ रही थीं। स्व. कांग्रेस में ही स्वतंत्रता सपना वाली का जोर बढ़ता जा रहा था। अब औपनिवेशिक स्वराज्य के द्वारा नौजवानों को साथ रखना असंभव था। कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पास किया था, उसका आशय स्पष्ट था। अब देश में लड़ाई का वातावरण उत्पन्न हो रहा था और लड़ाई को रोकना असंभव था। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का भी भारत पर असर हो रहा था।

ब्रिटेन से आशा—साइमन कमीशन 14 अप्रैल को भारत में अपना काम समाप्त कर चुका था। मई में इंग्लैंड में आम चुनाव होने वाला था। हम यह सोचें आगे बढ़कर यह बता दें कि इस चुनाव में लेबर पार्टी को अधिक सीटें मिलीं, पर इतनी नहीं कि वह स्वयं सरकार बना सके। कुछ भी हो लेबर पार्टी ने दूसरे लोगों से मिलकर सरकार बना ली और रैमसे मैकडोनाल्ड प्रधान मंत्री तथा वेजवुड बेन भारत सचिव बनाए गए। रैमसे मैकडोनाल्ड भारत पर एक पुस्तक लिख चुके थे, तथा जसा कि हम बता चुके हैं, वह कांग्रेस के एक अधिवेशन के सम्भाषित भी बनाए जाते थे। इसलिए उनके पदारूढ होते ही देश में एक आशा की लहर दौड़ गई। पर अभी भारतीयों को यह सीखना बाकी था कि जहां तब साम्राज्य सम्बन्धी नीति थी—ब्रिटेन की सब पार्टियां एक ही तरीके से सोचती थी।

मजदूर संगठन—आगे की घटनाओं के वर्णन करने के पहले हम कुछ पीछे मुड़ कर यह देख लें कि इस बीच अर्थ शक्तियां क्या कर रही थी। हम पहले ही/कानपुर पड़यन के वर्णन में यह बता चुके हैं कि इस के समाजवादी भारत में अपनी शाखा काम करने के लिए उत्सुक थे। दुनिया के सब देशों में कम्युनिस्ट पार्टियां स्थापित हो रही थीं। भारत में मजदूर आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा था। यह एक बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि भारत में मजदूरों को संगठित करने में भी गांधीजी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उ होने सन 1917 में ही अहमदाबाद में मजदूर संघ की स्थापना की थी।

मजदूरों की कमिक वृद्धि—1921 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना बम्बई में हुई थी। उस समय तक मजदूरों की संख्या बहुत हो चुकी थी। आंकड़ों में हैं

साल	कारखानों की संख्या	औसत मजदूर
1894	815	349810
1902	1533	541634
1914	2936	950973
1918	3436	1122922
1922	5144	1361002

साल	कारखानों की संख्या	औसत मजदूर
1926	7251	1518391
1930	8148	1528302

**कम्युनिस्ट पार्टी**—या तो अहमदाबाद कांग्रेस से ही एम० एन० राय लिखित कोई न कोई पर्चा गुप्त रूप से कांग्रेस अधिवेशनों में बटा करता था, और वाकायदा कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में मानी जाने पर भी 1928 में वे सक्रिय हुए और मजदूरों में काम करने लगे।

**मजदूर और साइमन कमीशन**—ट्रेड यूनियन कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में देशबन्धु दाम उसके सभापति हुए, फिर 1927 के दिसम्बर में इसका जो अधिवेशन हुआ, वही से इसका महत्व शुरू होता है। इस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार, चीन की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों के साथ सहानुभूति तथा वहां पर भारतीय फौज भेजने की निंदा के प्रस्ताव पास किए गए। जिस समय साइमन कमीशन बम्बई में उतरा उस समय उसके बायकाट के नारे लगाते हुए काले झंडे लिए मजदूरों का एक विराट जुलूस निकला था। 1928 भारतीय मजदूरों के इतिहास में मजदूर पूंजीपति संधप के लिए स्मरणीय है। 16 अप्रैल को हड़ताल शुरू हुई। 23 अप्रैल को परशुराम यादव नामक एक मजदूर गोली से मारा गया। 1928 की हड़ताल से वग युद्ध की बुनियाद मजबूत हुई।

**मेरठ पडयत्र**—ब्रिटिश सरकार को मजदूर आंदोलन यो ही अखर रहा था। इनने में ट्रेड यूनियन कांग्रेस का भरिया अधिवेशन हुआ जिसमें यह तय हुआ कि उसका सम्बन्ध 'लीग एगेस्ट इम्पिरियलिज्म' से कर दिया जाए। 20 मार्च 1929 को ये लोग जिहोने बम्बई और बंगाल की हड़तालों में प्रमुख भाग लिया था, गिरफ्तार कर लिए गए। यही बाद को मेरठ पडयत्र नाम से मशहूर हुआ। इस पडयत्र में भी एम० एन० राय पर अभियोग था, पर वह पकड़े न जा सके। बाद को जब वह चोरी से भारतवर्ष आए, तब उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चला। इस पडयत्र में सजा पाने वालों में डागें, मुजफ्फर अहमद तथा शीकत उस्मानी का नाम विशेष उल्लेखनीय है।

**काकोरी पडयत्र** के बाद क्रांतिकारी दल का नेतृत्व चन्द्रशेखर आजाद तथा भगतसिंह पर पड़ा। इन लोगों के हाथों में क्रांतिकारी आंदोलन, मौजवान भारत सभा के माध्यम से करीब करीब एक जन-आंदोलन के रूप में परिणत हो गया। पंजाब में बहुत दिनों तक यह आय किसी संस्था से भी अधिक मजबूत बना रहा। सरदार भगतसिंह केवल इसी कारण प्रसिद्ध नहीं हुए कि उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक मुह्त में सब काम किए बल्कि वह एक बहुत बड़े संगठनकर्त्ता तथा सिद्धान्तवादी भी थे। काकोरी युग में क्रांतिकारी समिति का नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन था, इन लोगों ने इसका नाम बदल कर सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसियेशन रख दिया। इस प्रकार इन्होंने लक्ष्य के रूप में समाजवाद पर जोर दिया।

**असेम्बली में पडाका**—भारत में साम्यवाद का प्रचार रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार पब्लिक मेपटी बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास करना चाहती थी। इन दोनों का उद्देश्य मजदूर आंदोलन का दमन था। इन बिलों के विरुद्ध बहुत जोर था। अध्यक्ष विट्ठलभाई पटेल इस पर अपना निणय देने वाले थे। सब लोगों की आँखें उन्हीं की ओर लगी हुई थीं। ऐसे समय में एवाएक असेम्बली भवन में दशकों की गैलरी से दो वम

गिरे। सर जाज सूस्टर तथा सर वमनजी दलाल आदि कुछ व्यक्तियों को हल्की चोट आई। बम फेंकने वाले दो नवयुवक थे, सरदार भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त।

यती ब्रनाथ दास पहले ही हम सैंडर्स हत्याकाण्ड का उल्लेख कर चुके हैं। इही सब घटनाओं को लेकर लाहौर पडयत्र चला। इस समय की घटनाओं में लाहौर तथा मेरठ पडयत्र का एक बहुत ही प्रमुख स्थान है। लाहौर के यती ब्रनाथ दास ने अपने साथियों के साथ राजनैतिक कैदियों के लिए विशेष व्यवहार की मांग करते हुए अनशन किया, और 62 दिन अनशन कर वह 13 सितम्बर का शहीद हो गए। इहा दिना बर्मा के फूंगी विजय ने 164 दिन अनशन के बाद प्राण त्याग दिया। यती ब्रनाथ लाहौर में मरे, पर अर्ध रात पर कलकत्ता भेजी गई। प्रत्येक स्टेशन पर अपार भीड़ रही। कलकत्ता में उनकी अर्धों के साथ 6 लाख व्यक्ति शमशान तक गए।

इरविन का सज्ज बाग — महात्मा गांधी बराबर देश का दौरा करते रहे। इस बीच में लाड इरविन छुट्टी में इंग्लैंड गए हुए थे। वह 16 अक्टूबर को लौट आए और 31 अक्टूबर को उन्होंने घोषणा की कि भारत के लिए एक शासन विधान बनाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य से एक गोलमेज कांफ्रेंस बुलाई जाएगी। लाड इरविन का यह बयान पूरा सज्ज बाग था और एक हद तक नेतागण इस पर रीढ़ भी गए, पर साथ ही उन्होंने यह मांग पेश की कि कुछ बातों में जो अस्पष्टता है उसे दूर किया जाए। विशेष रूप से यह पूछा गया कि सरकार गोलमेज स्वराज्य का विधान बनाने के लिए ही बुला रही है या नहीं। जब कांग्रेस कार्यसमिति की तरफ से इस प्रकार का बयान दिया गया, तो सुभाष बाबू ने उससे इस्तीफा दे दिया।

जले पर नमक — नेताओं ने जिन बातों के सम्बन्ध में गारटी मांगी, उस सम्बन्ध में सरकार की ओर से कोई विशेष बात नहीं बही गई। इसके विपरीत ब्रिटिश संसद में उसी वेजवुड बेन ने, जो भारत के मित्र रूप में एक बार कांग्रेस में बोले थे, संसद में कहा कि भारतीय व्यावहारिक रूप से औपनिवेशिक स्वराज्य तो पा ही चुके हैं। उनका यह कहना था कि राजसंघ में भारतीय सदस्य हैं, साम्राज्य सम्मेलन में भारतीय सम्मेल्य हैं फिर औपनिवेशिक स्वराज्य में कमी क्या रही? वेजवुड बेन के इस छल के सम्बन्ध में बात कराने के लिए बड़े लाट लाड इरविन तथा महात्माजी, मोतीलाल नेहरू जिना, पंडित मालवीय तथा विट्ठल भाई पटेल का मिलना तय हुआ।

वायसराय की गाड़ी पर बम — लाड इरविन वहीं बाहर गए थे और नेताओं से बातचीत करने के लिए दिल्ली लौट रहे थे। उधर कई दिन पहले से क्रांतिकारी बाय सराय की टोह में रेल लाइन के नीचे बम लगाए प्रतीक्षा कर रहे थे। जब वायसराय की गाड़ी बमों के ऊपर आई तो बटन दबा दिया गया और बड़े जोर का धड़ाका हुआ। थोड़ी देर हुई यानी कुछ सैंकेण्ड की इसलिए वायसराय का डिव्वा न उखड़कर उसमें तीमरा डिव्वा उड़ गया। इस कार्य में चंद्रशेखर आजाद तथा यशपाल का प्रमुख भाग रहा।

कोई गारटी नहीं — वायसराय नेताओं को इस तरह का कोई गारटी नहीं दे सके कि जा गोलमेज बुलाई जाएगी उससे औपनिवेशिक स्वराज्य दिया ही जाएगा। इस प्रकार यह प्रमाणित हो गया कि लाड इरविन ने 31 अक्टूबर को जो घोषणा की थी, वह केवल भारतीयों को भ्रमजाल में डालकर निष्क्रिय कर देने के लिए थी। एक अनुमान यह भी है कि श्रमिक सरकार कुछ करना चाहती थी, पर वायसराय की 31 अक्टूबर वाली घोषणा से सगद में इतना कोहराम मचा कि श्रमिक दल को पीछे हट जाना पडा।

## पूर्ण स्वतन्त्रता की माग

1929 की लाहौर कांग्रेस से कांग्रेस में पूर्ण स्वतन्त्रता की माग का युग आरम्भ हुआ। यह बात महत्वपूर्ण है कि यह कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई और वे ही 1947 में अंग्रेजों के जाने के बाद देश के पहले प्रधान मंत्री बने।

### लाहौर कांग्रेस 1929

पंडित जी जब से यूरोप से लौटे तब से बराबर पूर्ण स्वतन्त्रता और समाजवाद का नारा दे रहे थे। ऐसे समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू को सभापति का आसन देना पुराने नेताओं के लिए बहुत ही बुद्धिमत्ता की बात थी क्योंकि लाहौर में विचारों का प्रबल संपर्क होने वाला था। कलकत्ता कांग्रेस में ब्रिटिश सरकार को जो स्मरणपत्र दिया गया था, उसके उत्तर में उन्होंने सब्ज बाग दिखाया, और जब इस सब्ज बाग की जांच की गई तो पता लगा कि वह एक मरोचिया भाग है। नौजवान दल उत्तेजित था। लाहौर तथा मेरठ पड़्यत्रा के कारण लोगों का जोश उबाल बिंदु तक पहुँच रहा था। आम जनता में जवाहरलाल और सुभाष बाबू इनके नेता थे।

कांग्रेस के अंदर जवाहरलाल का सिंहनाद—जवाहरलाल ने अपने अध्यक्षीय अभिभाषण में अपने को प्रजातन्त्रवादी तथा समाजवादी घोषित किया। उन्होंने कहा कि मुझे राजाओं में कोई विश्वास नहीं। उन्होंने रणनीति के तौर पर अहिंसा की प्रशंसा की। उन्होंने यह साफ कर दिया कि उनके निकट स्वतन्त्रता का अर्थ ब्रिटिश सम्बन्ध से बिल्कुल अलग हो जाता है।

संग्राम का प्रारम्भ—अधिवेशन में लाट साहब की गाड़ी पर आक्रमण की बड़े शक्ती में निंदा की गई। मद्रास कांग्रेस में ही पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रस्ताव पास हो गया था, पर यह प्रस्ताव निरर्थक था। यह कलकत्ते में नेहरू रिपोर्ट की स्वीकृति तथा इस बीच होने वाली अन्त्य घटनाओं से साबित हो गया था। अतएव कलकत्ता कांग्रेस के निश्चय के अनुसार एक साल की मियाद बीत जाने पर 31 दिसम्बर को रात के 12 बजे काँग्रेस पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रस्ताव पास कर दिया गया। अब यह कह दिया गया कि नेहरू रिपोर्ट की पूर्ति से भी भारत सतुष्ट नहीं हो सकता, असेम्बली तथा कौंसिल के सदस्यों को यह हिदायत दी गई कि वे धारासभाओं की सदस्यता से इस्तीफा दे दें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को यह अधिकार दिया गया कि वह पूर्ण स्वतन्त्रता को ध्येय मानकर आन्दोलन शुरू कर दे। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि वह जब और जहाँ चाहे करबंदी तथा सत्याग्रह का आन्दोलन चलाए।

सुभाष बाबू की नई पार्टी—लाहौर कांग्रेस ने एक तरह से कांग्रेस तथा देश में नए सिरे से जान फूँक दी। सुभाष ने इस अवसर पर श्रीनिवास आयरर से मिलकर कांग्रेस डिमोक्रैटिक पार्टी नाम से एक दल की स्थापना की चेष्टा की। इस बार पंडित

जवाहरलाल उनके साथ नहीं थे। वह कांग्रेस के सभापति थे। यह पार्टी पनप नहीं सकी और पटा हाते ही गर गई क्योंकि उनके बाद इस के सम्प्रदाय में कुछ सुनाई नहीं पड़ा। अवश्य इसके कुछ ही दिनों बाद वह गिरफ्तार हो गए फिर पार्टी कौन चलाता?

स्वतंत्रता दिवस—लाहौर कांग्रेस के बाद से प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना लगा, तथा स्वतंत्रता सम्बन्धी प्रतिज्ञा पत्र पढ़ा जाना लगा। इस प्रतिज्ञा पत्र में यह कहा जाता था कि भारतीयों का स्वतंत्रता प्राप्त करने का अविच्छेद अधिकार है क्योंकि ब्रिटिश शासन से भारतवर्ष का आर्थिक, राष्ट्रीय, नैतिक तथा सामाजिक पतन हुआ।

देश में जोश—26 जनवरी 1930 को सारे भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस जिन जोश के साथ मनाया गया, उससे यह स्पष्ट हो गया कि देश में कितना प्रबल जोश है। 25 जनवरी को वायसराय ने धारासभा के सम्मुख जा भाषण दिया था उससे यह सात हो गया था कि सरकार कुछ सना देना नहीं चाहती। इस कारण स्वतंत्रता दिवस और भी जोरा से मनाया गया।

गांधीजी की ग्यारह शर्तें—महात्मा गांधी ने सरकार की सत्ता की परीक्षा करने के लिए 11 शर्तें रखी—

(1) सम्पूर्ण मादक द्रव्य निषेध, (2) एक रुपया एवं शिलिंग चार पैसे का बराबर हो (3) लगान कम से कम आधा कर दिया जाए और इस धारासभा के अधीन कर दिया जाए (4) नमक कर उठा लिया जाए, (5) युद्ध सम्बन्धी व्यय प्रारम्भिक तौर पर आधा कर दिया जाए (6) लगान की कमी को देखते हुए बड़ी-बड़ी नौकरियों के वेतन कम से कम किए जाए (7) विदेशी कपड़ा के आयात पर निषेधात्मक कर करके कानून बनाया जाए (8) भारतीय सन्तुष्ट तट को केवल भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित में सजा मिली है, उनके अतिरिक्त अन्य सब राजनैतिक कैंदियों को छोड़ दिया जाए या मामूली कानूनी द्रिब्यूननों में उनका मुकदमा चलाया जाए। सब राजनैतिक मुकदमे वापस ले लिए जाए। धारा 124 अलिफ तथा 1818 के रेगुलेशन 3 को रद्द कर दिया जाए। भारत के बाहर जो दश निकाला पाए हुए लोग हैं उन्हें लौटने दिया जाए, (10) खुफिया पुलिस का महकमा तोड़ दिया जाए, अथवा उस जनता के अधिकार मरवा जाए, (11) सबको आत्म रक्षाय हथियार रखने का साइसेंस मिले, और जनता का उस पर अधिकार हो।

ब्रिटिश सरकार तैयार नहीं—कहना न होगा कि सरकार ने इन शर्तों को मजूर नहीं किया। फरवरी तक कांग्रेस की ओर से धारासभा में गए सब सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। इस बीच घर पकड़ भी शुरू हो गई। सुभाष तथा उनके ग्यारह माथी 23 जनवरी को गिरफ्तार कर लिए गए।

कैंदियों का वर्गीकरण—हम पहले ही बता चुके हैं कि यतीन्द्रनाथ दास राजपूजाब में जेल कमेटी बठी। लाहौर के आतंककारी कैंदियों ने समझा कि वही कमेटी बना पड़यंत्र के दण्डिता की तरह सरकार द्वारा उल्लू न बनाए जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह सोचा कि यतीन्द्रनाथ दास का त्याग व्यर्थ न जाए। इसलिए उन्होंने यतीन्द्रनाथ दास को मांगा को लेकर अनशन कर दिया। साम्राज्यवाद के विरुद्ध जेलों के अंदर संग्राम में इस अनशन का विशेष महत्त्व है। इस अनशन में तीन काकोरी कैंदियों ने भी बरेली जेल

म भाग लिया, और वे भगतसिंह आदि के बाद तक याने तब तक डटे रहे जब तक उनका वर्गीकरण नहीं किया गया। कांग्रेस कार्यसमिति ने अपने 14, 15, 16 फरवरी के अधिवेशन में इस पर भी एक प्रस्ताव पास किया। सरकार ने 19 फरवरी को एक विज्ञप्ति निकालकर जेल में ए.पी.सी. श्रेणियों की सृष्टि की। इससे यतीन्द्रनाथ की मार्ग पूरी नहीं हुई, पर कुछ प्रगति अवश्य, इस अर्थ में हुई कि गोरो बालो का भेद दूर हुआ। सरकार ने इस वर्गीकरण में राजनैतिक या अराजनैतिक कोई बात नहीं रखी, उसने हैसियत के आधार पर यह वर्गीकरण किया।

**डांडी यात्रा — 14, 15 और 16 अप्रैल को साबरमती में कांग्रेस कार्यसमिति की एक बैठक हुई। इसमें गांधीजी ने घोषणा की कि वह नमक सत्याग्रह से काम शुरू करेंगे। महात्माजी ने 2 मार्च को इस आशय का एक पत्र साह्यद्वारा को लिखा था। 12 मार्च से गांधीजी ने 79 आश्रमवासियों के साथ डांडी यात्रा शुरू की। पहले ही से देशी तथा विदेशी अस्त्रधारों के सवाददाता वहाँ मौजूद थे, और यह यात्रा बड़े नाटकीय ढंग से चलती रही। कार्यक्रम यह था कि समुद्र किनारे पहुँचकर वे समुद्र के जल से नमक बनाएँ। डांडी पहुँचने के रास्ते में जितने भी पड़ाव आएँ, गांधीजी सबका व्याख्यान देते गए। हजारों की भीड़ उनके व्याख्यान को सुनने के लिए एकत्र होती थी।**

**नमक सत्याग्रह पर दमन — 5 अप्रैल को गांधीजी डांडी पहुँचे। फिर उन्होंने वहाँ पर कार्यक्रम के अनुसार नमक कानून तोड़ा। गांधीजी ने कार्यक्रम इस प्रकार रखा था कि 6 अप्रैल से ही राष्ट्रीय सप्ताह भी पड़ता था। स्मरण रहे कि यह राष्ट्रीय सप्ताह जलियावाला बाग की स्मृति में मनाया जाता था। गांधीजी ने तय किया था कि 5 अप्रैल को मैं कानून तोड़कर नमक बनाऊँगा और 6 अप्रैल से देश में सावजनिक रूप से नमक बनाना शुरू हो जाएगा। या तो सरकारी प्रयत्नाओं ने यह कहा था कि जिस तरह मैं गांधीजी नमक बनाने को कहते हैं, उसमें खर्च अधिक पड़ेगा, पर जब सावजनिक रूप से नमक बनाना शुरू हो गया, तब सरकार के कानून खड़े हो गए और दमन का दौर शुरू हो गया। नमक बनाने में सत्याग्रहियों का उद्देश्य आर्थिक न होकर राजनैतिक था। गांधीजी के बहुत से अनुयायियों ने भी नमक सत्याग्रह का नाम सुनकर नाव भी सिकोड़ी थी, पर वे यह नहीं जानते थे कि गांधीजी की नाटकीय बुद्धि बहुत जवदस्त थी, और यह वह जानते थे कि किस प्रकार जनता के मन पर प्रभाव पैदा किया जाता है।**

**गिरफ्तार न होने पर अग्न्युपाय — गांधीजी सोचते थे कि डांडी में नमक बनाते ही वह गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उनके तरीके में गिरफ्तार होना ही सफलता का प्रारम्भ था, इसलिए जब वह डांडी में गिरफ्तार न हो सके, तो उन्होंने दूसरा कार्यक्रम बनाया। घरसना में सरकारी नमक का गोदाम था। गांधीजी ने तय किया कि इस गोदाम पर घावा बोलकर सरकारी नमक पर कब्जा कर लिया जाए। कहा गया कि जिस प्रकार पानी और हवा पर सबका अधिकार है, उसी प्रकार नमक पर सबका अधिकार है। यदि सरकार ने नमक इकट्ठा कर रखा है तो यह अत्याचार है। यह घावा अहिंसात्मक था।**

**गांधीजी गिरफ्तार — गांधीजी ने घरसना पर घावा बोलने के पहले वायसरॉय को पत्र लिखा। अब सरकार के लिए चुप रहना असंभव हो गया क्योंकि यद्यपि सैद्धान्तिक रूप से कांग्रेस अब भी अहिंसा पर ही डटी थी, पर घरसना पर घाव से स्थिति बिगड़ने का डर था। अब सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करना तय किया, और 5 मई को दिन के 1 बजेकर 10 मिनट पर वह गिरफ्तार कर लिए गए।**

**नमक गोदामों पर हमला — गांधीजी की गिरफ्तारी से आंदोलन को बहुत**



उत्तेजना मिली। भारत भर में जोर की हड़ताल हुई। गांधीजी के बाप घरसना पर धावा करने के लिए बड़ नेता तैयबजी चुने गए। वह भी गिरफ्तार हो गए। इनके बाप श्रीमती नायडू सामने आई। वह भी गिरफ्तार हो गई। फिर तो आम तरीक स घरसना पर स्वयंसेवकों का धावा होना लगा। सरकार की तरफ से लाठी चार्ज की नीति बरती जाने लगी। घरसना की तरह नमक के अंग गोदामों पर भी हमले हुए और कहीं-कहीं तो स्वयंसेवक नमक लेकर भागने में समर्थ भी हुए।

**आंदोलन का विस्तृत रूप** - गांधीजी की गिरफ्तारी के बाद इलाहाबाद में कायसमिति की बैठक हुई। इसमें यह तय हुआ कि नमक सत्याग्रह तो जारी रखा ही जाए, साथ ही सत्याग्रह के क्षेत्र का विस्तृत किया जाए, कायसमिति ने निश्चय किया कि विदेशी वस्त्र का पूर्ण बायकाट किया जाए, जो स्टॉक मौजूद है, उसे बेचा न जाए और रुपड़ों के जो आडर विदेशों में दिए गए हैं उन्हें मसूख कर दिया जाए। कमरे में तय किया कि जिन स्थानों में जमोनों का रैयतवाड़ी बंदोबस्त है जमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में वहां चौकीदारी टैक्स न दिया जाए। कायसमिति ने राय दी कि जंगल कानून तोड़ा जा सकता है तथा और भी जो इस प्रकार के बँक, बीमा, जहाज तथा अन्य कम्पनियों के बायकाट का भी नारा दिया। इस बीच साइडरविन ने एक आर्डिनेंस से प्रेस की स्वतंत्रता करीब करीब खत्म कर दी। इसके प्रति बाद में कई अखबारों ने प्रकाशन बंद कर दिया। कायसमिति ने इनकी सराहना करत हुए अन्य अखबारों से भी ऐसा करने के लिए कहा।

**सफल बायकाट तथा धावे** - इन दिनों विदेशी वस्त्र का बायकाट इतना जारी रहे हुआ कि दूकानों में माल पड़ा पड़ा सड़ता रहा। प्रत्येक शहर और गांव में नमक सत्याग्रह हुआ। नमक के किसी किसी कारखाने पर 15 हजार लोगो ने एक साथ हमला किया। बडाला में ऐसा ही हुआ। कर्नाटक में शन्नीकट्टा में दस से पंद्रह हजार लोगो ने एक-एक बार में एक साथ हमला किया और हजारों मन नमक उठा कर ल गए।

**दमन का ताता** - सरकार ने इन बातों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अखबार तथा कायकर्त्ताओं का दमन और गिरफ्तारी जारी रही। 131 अखबारों से दो लाख चालीस हजार की जमानत ली गई। धीरे धीरे कांग्रेस कमेटीया भी गर कानूना करार दी जाने लगी और जून में अन्त में कांग्रेस में कांग्रेस की कायसमिति भी गर कानूनी करार दे दी गई, और मोतीलाल नेहरू भी गिरफ्तार हो गए।

**अपकर अत्याचार** - यह संभव नहीं कि गिरफ्तारियों के ब्योरे दिए जाए। गिरफ्तारी, गोली चलाना तथा लाठी चार्ज आम बात हो गई। पेशावर में पठाना ने इस समय विशेष बहादुरी दिखलाई। इसका सारा श्रेय खान-बख्शों को है। खान अब्दुलगफ्फार खां बहुत पुराने जनसेवक थे। 1911 में उन्होंने एक संस्था कायम की थी जिसका नाम अंगान यूथ लीग था। 1928 से उन्होंने खुदाई खिदमतगार आंदोलन प्रारम्भ किया। 1930 से यह मस्या कांग्रेस के अंतर्गत सम्मिलित हो गई। इस समय उन्होंने जबदस्ती पकड़ कर माफीनाम पर अंगूठा नमवाया जाता था फिर वह सबको मांस, न रज वामुरी। खान अब्दुलगफ्फार खां के घर में आग लगा दी गई। उनके भाई डाक्टर खान साहब का मकान जमींदोज कर दिया। अरवाब अब्दुल गफ्फार को बँत लगाए गए। लोगो के कपड़े उतारकर सावजनिक स्थानों में नंगा किया गया। पेशावर की

घटनाएँ खुद में एक कहानी हैं। पेशावर में अंग्रेजी राज्य कई दिनों के लिए रात में सा हो गया था। सेना भी प्रभावित हुई। गढ़वालियों ने चन्दनसिंह गढ़वाली के नेतृत्व में जनता पर गाली चलाने में इत्तफाक कर दिया। इस प्रकार चन्दनसिंह ने अहिंसा की वह पराकाष्ठा दिखाई जिसके कारण सैनिक कानून के अनुसार उन्हें गाली मारी जा सकती थी।

शोलापुर में भी अपनी सरकार हो गई थी।

लगानवदी का जोर—लगानवदी आंदोलन का विशेषकर गुजरात, कर्नाटक, सयुक्त प्रांत और बंगाल में जोर रहा। गुजरात के हजारों लोग लगानवदी के वाद जादर बंगाल में बस गए। बंगाल के मेदिनीपुर के काथी नामक स्थान के लोगो ने विशेष बहादुरी दिखाई।

चटगाव शस्त्रागार काण्ड—इस बीच क्रांतिकारी भी अपना काम कर रहे थे। गांधीजी 5 अप्रैल को डांडी पहुंचे। 18 अप्रैल को चटगाव के करीब 74 नौजवानों ने सूप सेन के नेतृत्व में एक साथ पुलिस लाइन तथा टेलीफोन एक्सचेंज पर आक्रमण कर दिया। य चार टुकड़ियों में बंटे हुए थे। सरकार ने तोप से भी काम लेंना शुरू कर दिया। तब क्रांतिकारी भागकर जलालाबाद पहाड़ी पर चढ़ गए। अतः इस लड़ाई में क्रांतिकारी हार गए। उनमें से 19 तो जलालाबाद की पहाड़ी पर ही शहीद हो गए। इन प्रकार क्रांतिकारियों ने इस ऐतिहासिक अवसर पर एक आदेश रखना चाहा। चटगाव वालों का उद्देश्य यह था कि लोग उनके उदाहरणों की अपनाकर शास्त्रों पर कब्जा करें। इन्हीं दिनों अथ क्रांतिकारी घटनाएँ भी हुई जिनका पथक वणन यहां नहीं किया जा सकता है। सूप सेन अंत में पकड़े गए और उन्हें फांसी हुई।

संप्र जयकर वार्ता—जुलाई 1930 में सर तेज बहादुर संप्र और एम० आर० जयकर ने सरकार और कांग्रेस के बीच एक वार्ता चलाई। इस संबंध में वे जेल में नेताओं से भी मिले पर इसका कोई विशेष नतीजा नहीं निकला।

कथित गोलमेज—सरकार ने 12 नवम्बर 1930 को लन्दन में गोलमेज की बैठक बुलाई। इस बैठक में राजाओं की तरफ से 16, ब्रिटिश भारत से 58 तथा विलायत से 13 प्रतिनिधि शामिल किए गए। इसमें कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं था और जो लोग प्रतिनिधि बनाए गए, वे सरकार द्वारा नामजद थे। इस सम्मेलन में उपस्थित भारतीयों में श्रीनिवास शास्त्री तथा जिन्ना प्रमुख थे। ब्रिटेन के प्रधान मंत्री मिस्टर मक्डोनाल्ड ने गोलमेज बातें शुरू कीं। थोड़े ही दिनों में सबने यह समझ लिया कि सम्मेलन में कोई समस्या हल नहीं होगी।

नेतागण रिहा—25 जनवरी 1931 को वायसराय ने एक दस्तावेज प्रकाशित किया जिसके अनुसार 1930 की पहली जनवरी से जितने लोग कांग्रेसमिति के मेंबर हुए थे, उनका रिहा कर दिया गया। मोतीलाल जी बीमागी के कारण पहले ही छूट चुके थे। माथ ही कांग्रेस कायममिति पर से सब तरह की रोक उठा ली गई। एक तरफ तो सत्याग्रह जारी रहा, और दूसरी तरफ गिरफ्तारियां जारी रहीं। कांग्रेसमिति के मौलिक तथा वाद के सब सदस्य 31 जनवरी को इलाहाबाद में एकत्र हो चुके थे। पर इस बीच लंदन से श्रीनिवास शास्त्री तथा श्री संप्र ने तार भेजा था कि अभी कोई फैसला न लिया जाय। आलापना होती रही, पर कोई निणय प्रकाशित नहीं किया गया। इस बीच 6 फरवरी 1931 को मोतीलाल नेहरू का देहांत हो गया। देश का एक महान त्यागी नेता उठ गया।

इस बीच लंदन से संप्र तथा शास्त्री लौट आए। उनके द्वारा यह तथ्य हुआ कि महात्माजी 17 फरवरी को लाड इरविन से मिलें। ऐसा लगता था कि अब कुछ

होकर रहेगा।

**चंद्रशेखर आजाद**—इही दिनों आतिथारियों के महान नेता चंद्रशेखर आजाद जवाहरलाल नेहरू से मिले। जवाहरलाल ने इसका विवरण अपनी आत्मकथा में लिखा है। वे 27 फरवरी को इलाहाबाद के एक पाक में पुलिस द्वारा घेर लिए गए और गोलियाँ का जवाब गोलियों से देते हुए सहोद हो गए।

**गांधी इरविन पेंकट**—गांधीजी तथा वायसराय में सुदीर्घ बातचीत के बाद 5 मार्च को एक समझौता हुआ। यह समझौता गांधी इरविन पेंकट नाम से प्रसिद्ध है। यह संधि बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए संक्षेप में यहाँ दी जा रही है।

(1) गांधीजी और वायसराय के बीच बातचीत के बाद एक अस्थाई संधि हुई है, इसलिए सत्याग्रह स्थगित कर दिया जाय, और सरकार की ओर से भी तदनुकूल कार्रवाई की जाय। (2) शासनविधान के प्रश्नों पर आगे विचार होगा, किंतु उसके सम्बन्ध में मुख्य बातें इस प्रकार तय की गईं (क) शासन का स्वरूप फेडरेशन का होगा (ख) केन्द्र में उत्तरदायित्व रहेगा, (ग) विदेश नीति, रक्षा नीति आदि भारत के हित की दृष्टि से रखी जाएगी। (3) गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रतिनिधि लिए जाएँगे। (4) संधि का सम्बन्ध सत्याग्रह आन्दोलन से भी है। (5) सत्याग्रह आन्दोलन बाल्यविक रूप में बदल कर दिया जाएगा। (6) विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का राजनैतिक रूप हटा लिया जाएगा। भविष्य में ऐसा बहिष्कार केवल आर्थिक उन्नति के लिए किया जाएगा। (7) शराब और विलायती वस्तुओं पर धरना कानूनी हद के अन्दर रहेगा। (8) पुलिस के अत्याचारों की जांच के लिए गांधीजी ने अपना आग्रह वापस ले लिया। केवल सरकार का ध्यान उस आर आकर्षित किया गया। (9) दमन बंद किया जाएगा। (10) आन्दोलन वापस ले लिए जाएँगे, सिवाय आन्दोलन से न। सन 1831 के जो आतंकवादी आन्दोलन के विरुद्ध हैं, और इन्हें रद्द न किया जाएगा। (11) सत्याग्रह आन्दोलन के सिलसिले में सत्याग्रहों को गैरकानूनी करार देने के लिए जो गान्धी जारी किए गए हैं वे वापस ले लिए जाएँगे। (12) मुकदमे उठा लिए जाएँगे। (13) सत्याग्रह आन्दोलन के कड़ी छाड़ दिए जाएँगे, किन्तु हिंसात्मक अपराधों के कड़ी नहीं छोड़े जाएँगे। (14) जुमनि माफ होगी, किन्तु बमूलशुदा जुमनि लौटाए नहीं जाएँगे। (15) अतिरिक्त पुलिस के लिए लगाया हुआ टक्स बंद होगा। (16) जम की हुई जामनाद वापस होगी। (17) 1930 के न आन्दोलन के मुताबिक राजा की हुई जामनाद वापस कर दी जाएगी। (18) सरकार जिला अफसरों को हिदायत देगी कि अगर किसी जगह लगान गैर कानूनी तौर पर बमूल हुआ है तो उसकी जांच हो। (19) जो नीवरिया स्थायी रूप से भर गई हैं वे न मिल सकेंगी, दोष सब फिर से मिल जाएगा। (20) यदि कांग्रेस गतों का यथोचित पालन नहीं करेगी, तो सरकार उचित कार्रवाई करेगी।

**पेंकट पर विचार**—यदि गढ़वाई के साथ देखा जाय तो गांधी इरविन समझौता सिर्फ इसी माने में एक बड़ी जीत थी कि सरकार ने जिस सस्या को बल तक गैरकानूनी करार दे रखा था, उसी के नेता के साथ उसे झुककर समझौता करना पड़ा। कांग्रेस ने लिखा है कि कांग्रेस इस पेंकट में किसी बात को मनवाने से यहाँ तक कि आमकानून हटवाने में भी समर्थ नहीं रही। अहिंसा की प्रतिमूर्ति चंदन सिंह गढ़वाली की रिहाई के लिए भी किसी ने नहीं कहा।

इस समय आंग्लन बहुत तेजी से ऊपर की ओर जा रहा था और विलकुल श्रानिकारी परिस्थिति हो रही थी। गायवाट इतना मफल हुआ था कि विलायत के कारखाना में रोना मच गया था। आंदोलन घट रहा हो एमी बात नहीं थी बल्कि वह और उग्र होता जा रहा था। कई स्थानों पर तो समानान्तर सरकार कायम हो गई थी। जनता ने लड़ाई को अपने हाथ में ले लिया था। एमी हालत में यह समझौता हुआ। अवश्य ही ब्रिटिश सरकार ने तभी समझौता किया, जब वह अपनी परिस्थिति को सतर्ताक पान मगी।

## कराची अधिवेशन 1930

इही परिस्थितियों में माच के अंत में कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल के सभापतित्व में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। जवाहरलाल नेहरू पर समझौता सबधी प्रस्ताव रखने का भार डाला गया। उन्होंने लिखा है कि इस प्रस्ताव को 'मैंने मानसिक संघर्ष तथा बेचनी में भी रखना स्वीकार किया।' सुभाष बायू ने राष्ट्रीय एकता दिखाने के लिए इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। इस प्रकार गांधी जी की पूरी विजय रही। कुछ मुकदमों ने अवश्य भगतसिंह की फांसी पर उनकी काने झुंटे दिखाए।

कानपुर का दंगा और विद्यार्थीजी की शहादत—जिस दिन भगतसिंह का फांसी हूँ, उस दिन कानपुर की हालत बहुत खतरनाक थी। यही हालत बहुत से स्थानों की थी। पर यही श्रानिकारी परिस्थिति कांग्रेस की भयंकर मारकाट में परिणत हो गई। सत्ता हत्याएं हुई। इस सम्बंध में हिंदू मुस्लिम एकता के अर्थ उपासक, श्रानिका-रिया के विरमित्र सभापक - बंसरी गणेश शंकर विद्यार्थी, जो पिछले दिन कई सौ मुसलमानों को बचा चुके थे, मुसलमानों के ही हाथों 25 मार्च को मारे गए। नाशों के ढेर से उनकी फूनी हुई लाश हाथ पर गुदे हुए नाम से पहचानी गई। कांग्रेस अधिवेशन में इसकी खबर पहुंची। उनके हत्या तथा भगतसिंह की फांसी से कराची में मातम छा गया।

भगतसिंह पर प्रस्ताव—इस अधिवेशन में समझौते का प्रस्ताव तो मुख्य था ही, पर भगतसिंह तथा उनके साथियों पर रखे गए प्रस्ताव को लेकर काफी झुंटे हुए। प्रश्न था कि प्रस्ताव के साथ ये शब्द रहें कि न रहें 'कांग्रेस किसी भी रूप में राजनैतिक बल प्रयोग से अपने को अलग रखती है तथा उसे नापसंद करती है।' अधिवेशन में प्रस्ताव इही शब्दों के साथ पास हुआ, पर कांग्रेस स्वयंसेवकों की कॉफ्रेंस में यह प्रस्ताव इन शब्दों को निकालकर पारित किया गया।

॥ ५ प्रस्ताव - कांग्रेस ने अर्थ अनक विषयों पर प्रस्ताव पास किए जिनमें सत्याग्रहियों को अभिनंदित किया गया, साम्प्रदायिक दंगों की निंदा की गई शराबबंदी की प्रशंसा की गई, लंदन प्रचार का समर्थन किया गया, शराब तथा विलायती कपड़ा की दुकानों पर शांतिपूर्ण पिकेटिंग की सिफारिश की गई सरहदों प्रांत के लोगों को आश्वासन दिया गया कि जो भी शासन सुधार होगा वह वहां भी लागू होगा। बर्मा का भारत से अलग हो जाना का हक स्वीकृत हुआ, पर सरकार उसे अलग करा रही है इस बात की निंदा की गई, क्योंकि यह बताया गया कि ऐसा करने में सरकार का उद्देश्य बर्मा को हड़पना है न कि उसकी भलाई करना।

मौलिक अधिकार के प्रस्ताव—कराची कांग्रेस में मौलिक अधिकारों पर भी एक प्रस्ताव पास हुआ। प्रस्ताव की कुछ खूबियां ये थी किसी को खिनाय नहीं दिया जाएगा, मृत्युण्ड नहीं रहेगा, लगान घटाने का वायदा किया गया, तब हुआ कि किसी सरकारी नौकर का पांच सौ रूपयों से अधिक तनखावा नहीं मिलेगी, बिदशी वस्तु तथा

विदेशी सूत को देश से निकालने का वायदा किया गया, कहा गया कि प्रधान उद्योग-धंधा पर खाना रेलों मार्गों जहाज तथा यातायात के अत्यन्त आवश्यक साधना पर पड़ का कब्जा रहेगा, किसानों की बर्जदारी घटाने तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मूल्सारी पर नियन्त्रण करने का वादा किया गया, तथा सब नागरिकों को सैनिक शिक्षा देने का वादा किया गया।

**जिज उत्पन्न**—कराची अधिवेशन के बाद ही कांग्रेस वाला को यह बात होने लगा कि गांधी इरविन समझौते का पालन कांग्रेस की तरफ से तो हो रहा है पर सरकार की तरफ से उसका पालन नहीं हो रहा है। लाड इरविन 18 अप्रैल को ही भारत छोड़ कर चले गए, और उनकी जगह लाड विनिंग्डन वायमराय होकर आए। लाड विनिंग्डन मानों कांग्रेस को कुचलने को ही आए थे। परिस्थिति इतनी बिगड़ गई कि गांधीजी ने कार्यसमिति की राय लिए बिना गोलमेज में जाना अस्वीकार कर दिया। इसके बाद गांधीजी के साथ सरकार की फिर बातचीत हुई। गांधीजी लाड साहब से मिले और चूंकि बड़े लाट ब्राह्मोली के मामले में जांच करने पर राजी हो गए इसलिए वे जून-जून 29 अगस्त को विलायत के लिए रवाना हुए। सीनारमैया ने लिखा है कि यद्यपि गांधी जी विलायत के लिए रवाना हो गए थे, पर वह निराश ही गए।

**गोलमेज की भबड़**—गोलमेज में जो लोग गए थे वे सरकार द्वारा नामजद थे। इन लोगों की राय एक दूसरे में मिलती नहीं थी, फिर तृतीय पक्ष भी बराबर भत्कावा रहता था। इसलिए सब मामलों में सारे सत्तार के सामने काफी भद्द रही और प्रत्येक विषय में अन्तिम निर्णय सरकार पर छोड़ा जाता रहा। गांधीजी ने भरमक् कोणिंग से कि सरकार की तरफ से कोई निश्चित आश्वासन मिले, पर वे सफल नहीं हुए। यह सारा सम्मेलन, जसा कि सरकार चाहती थी एक तमाशे में परिणीत हो गया। राष्ट्रीय माग की आलोचना तो कम रही, अधिकतर आलोचना इसी बात पर रही कि अल्प सङ्घकों का प्रश्न कैसे सुलझाया जाय और इस प्रश्न को सुलझाने की जिनती कोशिश की गई वह उतना ही उलझना गया।

**ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल परिवर्तन**—इसी बीच विश्वव्यापी मन्दी के कारण ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल का पतन हो गया और सयुक्त मन्त्रिमण्डल बना। मिस्टर मकडोनाल्ड प्रधान मन्त्री बने, पर वह नाम मात्र के लिए थे। सर सैमुएल होर भारत सचिव बने।

**भारत में दमन**—चाहे यह मन्त्रिमण्डल के परिवर्तन के कारण हो, चाहे इस कारण कि सरकार इस बीच कांग्रेस से लड़ाई की सब तैयारी कर चुकी थी गांधीजी ने लौटते ही भारतवर्ष में दमन की स्थिति पाई। गांधीजी 1 दिसम्बर को गोलमेज बैठक से विदा लेकर 28 दिसम्बर 1931 को भारतवर्ष पहुँचे।

**क्रांतिकारियों के साथ**—इस बीच भारतवर्ष में जो घटनाएँ हुई थी, उनका संक्षेप में दिग्दर्शन कराया जाता है। क्रांतिकारियों ने अपना आन्दोलन पूरे उत्साह से जारी रखा था। 25 अगस्त को ही कलकत्ते में मिस्टर टेगट पर फिर हमला हुआ। 29 अगस्त का ढाका में पुलिस इसपेक्टर जनरल सामेन पर विनयकृष्ण बोस ने गोली चलाई, वे दो दिन बाद मर गए। छोटे मोटे कितन ही हमले हुए। 8 दिसम्बर 1930 को कलकत्ते की रायटर्स विल्डिंग में जेल विभाग के इसपेक्टर जनरल मिस्टर सिमसन पर गोली चलाई गई और वे वहीं ढेर हो गए।

सयुक्त प्रांत की हलचलें जिस समय गांधीजी भारतवर्ष लौटकर आए, उस समय, विशेषकर सयुक्त प्रांत के किसानों की हालत बहुत खराब हो गई थी। कांग्रेस के समझाने पर किसानों ने भरसक लगान अदा किया पर एक बिंदु ऐसा आ गया, जहाँ से

बागे वे लगान देने में असमर्थ थे।

**सीमा प्रात में बमन—**सीमा प्रात में भी हालत बहुत विचित्र हो रही थी। सरकार को यह अटार रटा था कि पठानों में कांग्रेस का प्रचार हो रहा है। एक लाख साल कुर्तीवाले तैयार थे। खान अब्दुसगफ्फार खा को सीमा प्रात के चीफ कमिश्नर के दरबार में बुलाया गया। उ होन वहा जाने स इन्तार कर दिया। इस पर गांधीजी के लौटने के कुछ ही दिन पहले खान अब्दु गिरफ्तार कर लिए गए। इस प्रकार सीमाप्रात में कांग्रेस और सरकार की संधि सत्तम हो गई।

**बाते बादल—**गांधीजी जब भारतवर्ष पहुँचे, तो जवाहरलाल नेहरू और शेर बानी उन्हें परिस्थिति समझाने के उद्देश्य से बम्बई जा रहे थे। रास्ते में ही दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। इन परिस्थितियों में गांधीजी ने आते ही लाड विलिंग्डन को लिखा कि 'मैं आपसे मिलना चाहता हूँ' इसका उत्तर यह आया कि सरकार द्वारा बंगाल सयुक्त प्रांत तथा सीमा प्रात में जो आड़िनेस जारी किए गए हैं, उनके संबंध में वह गांधीजी से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं। गांधीजी ने फिर 1 जनवरी को तार दिया कि वे इसी बातों के संबंध में लाड विलिंग्डन से बातचीत करना चाहते हैं। इसी बीच कांग्रेस कांग्रेसमिति भी एक परिणाम पर पहुँच चुकी थी। सच तो यह है कि इंग्लैंड से लौटते ही गांधीजी को बंबई में कांग्रेसमिति तैयार मिली थी। गांधीजी ने अब यह लिखा कि यदि वह लाल गांधीजी से बिना शर्त के मिलना अस्वीकार करेंगे, तो इसका मतलब यह लगाया जाएगा कि गांधी इरविन पैक्ट टूट गया। दूसरी तारीख को इसका भी उत्तर आ गया। उसमें कहा गया कि लाट साहब उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं हैं। 3 तारीख का गांधीजी ने फिर तार दिया, और अब उसका कोई उत्तर नहीं मिला।

**फिर बमन शुरू—**ब्रिटिश सरकार किमा भी प्रकार के समझौते के लिए तैयार नहीं थी। जिस कारण से भी हो सरकार ने यह तय कर लिया था कि आन्दोलन को कुचन देना है। इस बीच जनता का जोश भी घट गया था। 4 जनवरी को महात्मा गांधी तथा सरकार पटेल गिरफ्तार हो गए। सुभाष बंगाल लौटते हुए गिरफ्तार हो गए। लार्ड इरविन ने एक एक करके आड़िनेस जारी किए थे, पर इस बार एक साथ कई आड़िनेस जारी कर दिए गए। कांग्रेस इस प्रचंड तथा अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थी। पहले चार महान में ही 8 लाख गिरफ्तारियां हुईं। अप्रैल 1933 में जो कांग्रेस का नाममात्र का अधिवेशन हुआ उसके अनुसार उस समय तक 1 लाख 20 हजार गिरफ्तारियां हो चुकी थी। मंत्र कांग्रेस कमेटियां, राष्ट्रीय विद्यालय, यहाँ तक कि जिन मकानों में ये सत्याग्रही, उन पर भी बन्ना कर लिया गया था। मारपीट की तो कोई सीमा ही नहीं थी। गिरफ्तारियों से ज्यादा मारपीट हुई। क्रांतिकारियों ने भी इन दिनों खूब खलकरी खेल खेली। विशेषकर बंगाल में बहुत-सी घटनाएँ हुईं। सरकार ने भी हजारों बंगाली युवकों को नजरबंद कर लिया।

## दिल्ली की गैरकानूनी कांग्रेस 1931

1931 के अप्रैल में दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन होना वाला था। सरकार चाहता था कि यह अधिवेशन हो सके, पर हर प्रांत से कुछ न कुछ प्रतिनिधि रवाना हो चुके थे, और उनमें से कई दिल्ली पहुँच भी गए थे। सेठ रणछोडदास अमृतलाल ने सभापति का काम किया क्योंकि मनोनीत सभापति पंडित मदनमोहन मालवीय रास्ते में गिरफ्तार कर लिए गए थे। अधिवेशन में पूण स्वतन्त्रता को फिर कांग्रेस का ध्येय बताया गया, सत्याग्रह का समर्थन किया गया, महात्मा गांधी के नेतृत्व

किया था, उसके लिए जनता को बढ़ाई दी गई।

**साम्प्रदायिक बंटवारा और गांधीजी का अनशन**—इस बीच सरकार ने गांधीजी का तमाशा जारी रखा था। जिस समय गांधीजी गोलमेज में गए हुए थे, उसी समय उनकी इसका आभास मिल गया था कि माले मिटो शासन सुधार से जिस साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति का प्रवर्तन किया गया था, वही भेद-नीति सर्वत्र तथा असवण हिंदुओं में भी बरती जाने वाली है। उसी समय उन्होंने यह घोषणा कर दी थी कि यदि इसी प्रकार हिंदू समाज को विखंडित करने की कोशिश की गई, तो वे प्राणों की बाज्रा लगा कर भी इसका विरोध करेंगे। गांधीजी ने जेल से ही 11 मार्च को सरकार को लिखा कि मैं अपने निश्चय पर दृढ़ हूँ। 17 अगस्त को प्रधान मंत्री मिस्टर मैकडोनाल्ड ने अपने कृपयात साम्प्रदायिक बंटवारा घोषित किया। इसमें गांधीजी ने जिस बात का विरोध किया था वही बात थी, यानी कथित अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचन था, और यह स्वरूप में था कि यदि गांधीजी इसका विरोध करने लगे तो गठनफहमी की गुजाइश थी। अखंडता को अनुपात से अधिक सीटें दी गई थी, और साधारण सीटों में भी प्रतिभागिता का हवा दिया गया था। गांधीजी ने 18 अगस्त को ही पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि यदि इसे बदला नहीं गया तो मैं 20 सितम्बर से आमरण अनशन करूंगा।

**पूना पक्ष**—12 सितम्बर को सरकार ने गांधीजी के निश्चय की बात साबर्जनिक रूप से घोषित कर दी। पंडित मदनमोहन मालवीय के कहने पर फौरन पूना में एक कांफ्रेंस बुलाई गई, जिसमें अछूतों के नेता डा० भीमराव अम्बेडकर और कथित उच्च वर्ण के नेता मौजूद थे। 24 तारीख तक नेता एक निणय पर पहुंचे। गांधीजी ने इस निणय को सतोपजनक समझा। 26 सितम्बर को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने इस निणय को मान लिया और उसी दिन बंबई रबींद्र के सामने गांधीजी ने अनशन व्रत समाप्त कर दिया। नई व्यवस्था के अनुसार यह तय हुआ कि पहले कथित अछूत चार व्यक्तियों का नामजद करेंगे, इस नामजदगी में अछूत ही भाग ले सकेंगे, इसके बाद कथित उच्च जाति और अछूत द्वा चार में से एक का चुनेंगे।

**'हरिजन' पत्रिका**—महात्माजी ने इस व्यवस्था को मनवाने के बाद सरकार से यह अधिकार मांगा कि उन्हें हरिजन बाय के सबध में जेल में सुविधा दी जाए। 7 नवम्बर तक उनकी यह मांग मान ली गई और वह 'हरिजन' पत्रिका निकालने लगे।

## कलकत्ता का चौराहा अधिवेशन 1933

अप्रैल 1933 में कलकत्ते में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस बार भी मनोनाथ सभापति पंडित मदनमोहन मालवीय थे पर वह रास्ते में ही पकड़ लिए गए, इस कारण चौराहा और घमटल्ला के चौराहे पर खली जगह में अधिवेशन हुआ। श्रीमती सेतगुप्ता सभापति बनीं और जल्दी जल्दी अधिवेशन का कार्य आरम्भ किया गया। बाइस सी प्रतिनिधि देश भर से रवाना हुए थे, जिनमें हजार के करीब अधिवेशन में पहुंच भी गए। पुलिस पहुंच गई और प्रतिनिधियों पर भीषण लाठी चार्ज हुआ। परंतु इसमें पहले ही अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का ध्येय फिर से स्वीकृत हो चुका था। सत्याग्रह आंदोलन को मजबूत बनाना निश्चित हुआ था, विदेशी वस्त्र बायकाट के लिए देशवासियों से कहा गया था, हाल में प्रकाशित श्वेतपत्र से लोगों को आगाह किया गया था, ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए विधान पर अविश्वास प्रकट किया गया था, गांधीजी की अनाज की सफलता के लिए बढ़ाई दी गई थी, स्वराज्य का अर्थ क्या है इस सबध में कराची के मौलिक अधिकार सबध प्रस्ताव पर आस्था प्रकट की गई थी।

**श्वेत पत्र**—ब्रिटिश सरकार ने 17 फरवरी 1933 को एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया था। इसमें शासन सुधार सम्बन्धी जो प्रस्ताव पेश किए गए, वे देश के नरम पण्डितों को भी पसन्द नहीं आए थे। इसी पर कांग्रेस में प्रस्ताव हुआ था।

**गांधीजी का अनशन और रिहाई**—महात्मा गांधी ने पहली मई को यरवदा जेल में घोषणा की कि वे 8 तारीख से 21 दिन का उपवास करेंगे। इस उपवास का उद्देश्य हरिजन व सबंध में जनता की कतव्य बुद्धि को जाग्रत करना घोषित किया गया। साथ ही यह आत्म शुद्धि के लिए भी था। इसके फलस्वरूप गांधीजी 8 तारीख को ही रिहा कर दिए गए।

**विट्ठलभाई और सुभाष का वक्तव्य**—गांधीजी ने जेल से बराबर हरिजनों के सबंध में लिखा। वह एक राजनैतिक सग्राम के नेता थे, और इसी रूप में जेल गए थे, इस कारण लोग उनसे राजनैतिक विचारों की आशा करते थे। इन दिनों विट्ठलभाई पटेल तथा सुभाष विजया में इलाज करा रहे थे। सुभाष और पटेल ने गांधीजी के विरुद्ध एक संयुक्त वक्तव्य दिया क्योंकि गांधीजी ने छूटते ही 6 सप्ताह के लिए आंदोलन स्थगित कर दिया था। वक्तव्य में पटेल तथा बोस ने कहा, “गांधीजी ने तो सत्याग्रह स्थगित कर दिया, यह एक तरह से इस बात की स्वीकृति है कि वे नेतृत्व के अयोग्य हैं। हम लोग इस निश्चित मत पर पहुंच चुके हैं कि एक राजनैतिक नेता के रूप में गांधी जी विफल रहे हैं। समय आ गया है कि कांग्रेस को एक नए सिद्धांत पर संगठित किया जाए। इसके लिए एक नए तरीके तथा एक नए नेता का उदभव आवश्यक है।”

**सग्राम स्थगित**—यद्यपि आंदोलन 6 सप्ताह के लिए ही स्थगित किया गया था। पर यह एक तरह से आंदोलन का अन्त था। गांधीजी ने 29 मई को अपना अनशन सफलता के साथ समाप्त किया। 12 जुलाई को स्थानांतरण सभापति श्री अणे ने पूना में नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया जिसमें यह तय हुआ कि अब देश के लिए सावजनिक सत्याग्रह उपयुक्त नहीं है, परंतु कुछ चुने हुए लोग सत्याग्रह कर सकते हैं। अधिवेशन में कांग्रेस जना के द्वारा गुप्त तरीकों के इस्तेमाल की निन्दा की गई। इसके साथ ही स्थानांतरण सभापति ने सब कांग्रेस संगठनों तथा युद्ध समितियों को रद्द घोषित कर दिया। जब युद्ध ही नहीं रहा तो युद्ध समिति कैसी?

**गांधीजी की हलचलें**—इसके बाद गांधीजी ने फिर सांड विलिंग्डन से बातचीत करने का प्रयत्न किया, पर सांड विलिंग्डन इसके लिए तैयार नहीं हुए। तब गांधीजी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की तैयारी की। सबसे पहले उन्होंने सावरमती आश्रम को भग कर लिया, और आश्रमवासियों से कहा कि वे सब कुछ होम कर व्यक्तिगत सत्याग्रह में कूद पड़ें। उन्होंने आश्रम का सामान आदि हरिजन संध तथा ऐसी अयसस्थाओं के हवाले कर दिया। वह मय रास नामक गांव के लिए रवाना होने वाले थे, पर उसके पहले ही वह तथा उनके 34 साथी गिरफ्तार कर लिए गए। उनको 4 अगस्त को छोड़ दिया गया और यह हुक्म दिया गया कि वे यरवदा जेल छोड़कर पूना जाकर रहे। इस पर गांधीजी राजी नहीं हुए, और उनको एक साल की सजा दे दी गई। इस बार फिर गांधीजी ने जेल में रहते समय हरिजन आंदोलन का अधिकार मांगा। उन्होंने 20 अगस्त को अनशन शुरू किया, और 23 को वह फिर छोड़ दिए गए।

**हरिजन कार्य**—30 अगस्त को जवाहरलाल छूटे, और गांधीजी से मिले। आगे क्या करना चाहिए इस विषय पर विचार करने के बाद वे हरिजन आंदोलन के सबंध में देश का दौरा करने लगे। गांधीजी ने जब से जेल में हरिजन आंदोलन उठाया था, तब से देश के बहुत से प्रसिद्ध मंदिर हरिजनों के लिए खुल गए थे। किन्तु सनातनियों की



और मे उनका बहुत विरोध भी हुआ था। इस दौरे में गांधीजी पर एक बार पटाखे से हमला भी किया गया, फिर भी गांधीजी कई प्रसिद्ध मंदिरों को छुलवाने में समर्थ रहे।

**बिहार में भूकम्प और ५० नेहरू की सजा**—इन कार्यक्रमों में यह साल निकल गया, और 16 जनवरी को बिहार में भयंकर भूडोल आया। इस भूडोल का 30 हजार वग मील से अधिक पर असर हुआ, और कम से कम 20 हजार व्यक्ति मरे। सारा देश बिहार की मदद के लिए दौड़ पड़ा। महात्माजी तथा राजेन्द्र बाबू तो मौजूद थे ही। गांधीजी ने एक दयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि छुआछूत के पाप की भगवान ने बिहार भूकम्प के रूप में सजा दी है। इस पर कवी द्र रवी ने कहा कि इस प्रकार ईश्वर की इच्छा की मनचाही व्याख्या करना गलत है।

बिहार के भूकम्प के जमाने में ही जवाहरलाल नेहरू गए और वहाँ उन्होंने प्रांतिकारियों की और साथ ही साथ सरकार के आतंकवाद की भी निन्हा की। इस कारण उन्हें दो साल की सजा हुई।

**फिर स्वराज्य पार्टी**—जब से पूना काफ़ेस हुई थी, तभी से कुछ नेता यह सोच रहे थे कि अब सत्याग्रह का पर्व समाप्त हो चुका, अब स्वराज्य पार्टी के तग पर कुछ काम करना चाहिए। इस काफ़ेस में यह भी तय किया गया कि आगामी निर्वाचन में भाग लिया जाए।

**सत्याग्रह स्थगित**—इसी महीने पटना में 18 तथा 19 मई को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। अभी तक कमेटी सरकारतुनी करार नहीं दी थी। बैठक में गांधीजी की सलाह मानकर सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया, और जिन लोगों ने स्वराज्य पार्टी बनानी चाही थी, मुख्यतः उनको लेकर पार्लियामेंटरी बोर्ड बन दिया गया। इस प्रकार स्वराज्य पार्टी की प्रवृत्ति को कांग्रेस ने अपने अधीन एक बाँट बनाकर स्वीकार कर लिया।

**कांग्रेस समाजवादी दल का जन्म**—गांधीजी ने जिस प्रकार से आंदोलन को चलाया था, उससे कुछ ऐसे कांग्रेसजनों में बहुत अधिक असंतोष उत्पन्न हुआ, जो जलोढ़ रहकर समाजवादी साहित्य पढ़ चुके थे। उन्होंने यह नतीजा निकाला कि गांधीजी के नेतृत्व दल को स्वतंत्रता के माँग पर ले जाने में असमर्थ है। इसी कारण कांग्रेस समाजवादी दल का जन्म हुआ। सुप्रसिद्ध विद्वान आचार्य नरेंद्रदेव के सभापतित्व में 17 मई को पटना में ऐसे लोगों की एक सभा हुई जिसमें यह तय हुआ कि गांधीवादी हमारी समस्या का समाधान करने में असमर्थ हैं, अतएव समाजवाद के आधार पर एक दल बनाया जाए। बिहार में सबसे पहले इस दल की बैठक हुई, इसका कारण यह था कि बिहार इस काम में अग्रणी था। आचार्य नरेंद्रदेव के अतिरिक्त बाबू सम्पूर्णानंद, जयप्रकाश नारायण तथा अन्य बहुत से लोग इस दल के जन्म में शरीक थे। पर इनमें से बहुत से बाद को विभिन्न कारणों से दल से ही नहीं समाजवादो विचारधारा से भी अलग होते गए।

**स्वाभाविक था कि कांग्रेस के अंदर से जो समाजवादी धारा निकली वह अलग संगठित हुई।** कांग्रेस समाजवादी शब्द के पहले लगा हुआ 'कांग्रेस' शब्द यह प्रगट करता था कि कांग्रेस का सदस्य ही इसका सदस्य हो सकता है, कि यह कांग्रेस के अंतर्गत एक दल है। बाद में 1947 में इस दल ने अपने नाम से 'कांग्रेस' शब्द निकाल दिया। दल के नेताओं के अनुसार यह जन्म इसलिए निकाल दिया गया जिससे कांग्रेस के बाहर के लोग भी इसमें शरीक हो सकें। यह बंदम भी कांग्रेस के प्रति अविश्वासमूलक ही था।

**कुछ राजनैतिक कैंदी छूटे**—जब कांग्रेस की ओर से बिना शर्त सत्याग्रह वापस

ले लिया गया, तब सरकार ने 22 जून तक कांग्रेस की कमेटियो को कानूनी वरार दे दिया। कुछ राजनीतिक कैदी भी छोड़े गए, पर सब नहीं। आतिकारी कैदी तो छूटे ही नहीं, साथ ही बहुत से सत्याग्रही कैदियों को भी पूरी बंद काटनी पड़ी। बहुत से ऐसे कैदी तो 1934 के अंत तक जेल में पड़े रहे। शर्तों के साथ तो आंदोलन बंद किया नहीं गया था।

## कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन 1934

27 तथा 28 अक्टूबर, 1934 को बम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में हुआ। कांग्रेस के नेताओं में राजेन्द्र बाबू महात्माजी के अनुरोध होने के साथ ही नीरव त्यागी भी थे। राजेन्द्र बाबू ने अपने भाषण में अहिंसा का गुण गाते किया और विपन्नता के दशन का प्रतिपादन किया। वह बोले, "हम एक बार असफल हो सकते हैं, दो बार असफल हो सकते हैं, पर किसी न किसी दिन हम अवश्य सफल होंगे।" उन्होंने कहा कि सत्याग्रह में कई बार सामयिक रूप में हार हो सकती है, पर इसमें पराजय है ही नहीं।

कांग्रेस का नया विधान—इस अधिवेशन में एक नया विधान बना, जिसके अनुसार कांग्रेस प्रतिनिधियों की संख्या दो हजार कर दी गई। सभापति को यह अधिकार मिला कि वह कार्यसमिति के सदस्यों को नामजद करें।

महात्माजी कांग्रेस से अलग—महात्माजी ने ही एक तरह से कांग्रेस की इस कारवाई की संचालित किया, फिर भी वह यहीं से कांग्रेस की चार आने की सदस्यता से अलग हो गए। इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि मुझमें तथा बहुत से कांग्रेसियों में बहुत अधिक मतभेद है और यह मतभेद निरंतर बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अहिंसा में एक पालिसी के तौर पर विश्वास करते हैं। ऐसी हालत में उनके लिए कांग्रेस में रहना संभव नहीं है। उन्होंने यह सब कहा अवश्य, पर तब यह है कि इसने बाद भी वह बराबर कांग्रेस के सर्वेसर्वा बने रहे क्योंकि उनके बिना कांग्रेस की रूपना असंभव थी। इसके बाद भी उनकी शक्ति बढ़ती रही, घटी नहीं।

9440  
—  
4487

## प्रान्तीय स्वशासन

**इंडिया ऐक्ट 1935**—गोलमेज की जो सचिद्वी पक रही थी, उसके फलस्वरूप बने प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संयुक्त संसदीय कमेटी बनाई। इस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, उसके विरुद्ध प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस कायसमिति ने 1 फरवरी का दिन निश्चित किया। पर इसका कोई परिणाम नहीं निकला, और 23 जुलाई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट 1935 के रूप में इस योजना पर ब्रिटिश संसद ने दस्तखत हो गए।

कहना न होगा कि इस ऐक्ट में स्वराज्य की भाग नहीं मानी गई थी, पर इतने सदेह नहीं कि यह मांटग्यू-चेम्सफोर्ड शासन सुधारों पर अगला क़दम था। इसमें राज्य का 4/5 भाग सुरक्षित रखा गया। सेना, परराष्ट्र तथा वादरिया का विभाग बड़े साठ के हाथों में रहा। रेलवे बोर्ड रेल का सब बातों के लिए उत्तरदायी माना गया। केन्द्र में धारासभाओं के निर्माण की बात हुई, उनमें रियासतों के सदस्यों की मख्या दो तिहाई रखी गई। इसका उद्देश्य यह था कि ये धारासभाएं पालतू रहे।

**ऐक्ट की सफ़सील**— ब्रिटिश भारत को 1। प्रांतों में बांटा गया। जदन और बमरा अब तक भारत के अंश थे, अब वे पंथक कर दिए गए। मद्रास बर्बई बंगाल, संयुक्त प्रदेश, बिहार और अजम में दो दो धारासभाएं कर दी गई जब कि इंग्लैंड में भी हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स के लोहा देने की कम से कम उसकी शक्ति घटाने की बात चल रही थी। इस बार शासन-सुधार में सरकारी नामजदगी का तरीका समाप्त कर दिया गया। आंध्रक संयुक्त दल की मंत्रिमण्डल बनाने का अधिकार मिला। पर गवर्नर के विशेषाधिकार इतने थे कि वह जम चाहे स्वयं शासन हाथ में ले सकता था। इस बार लगभग 14 वीं सदी लीगो की वोट का अधिकार दिया गया। इस ऐक्ट का सबसे आपत्तिजनक भाग साम्प्रदायिक बंटवारा था। गोरों को, विशेषकर बंगाल में, मंत्रिमण्डल बनाने एवं बिगाने के अधिकार दे दिए गए। यह बंटवारा बिलकुल मनमाना था, और इसका उद्देश्य हिंदू तथा मुसलमानों को आपस में जहाना था।

**साम्प्रदायिक नियम से सभी नाखुश**—खिलाफत आन्दोलन व युग में मुसलमानों की मध्यवर्ति श्रेणी ने (जो बड़ी हद तक मुसलमानों के मत का नियम करनेवाली थी) राष्ट्रीय विचार के हिंदुओं का साथ दिया था पर हम देख चुके हैं कि इसके बाद से ही धारा दूसरी तरफ बहने लगी थी। 'सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा' के बन्दि और अब 'चीनो अरब हमारा' के लेखक सर मुहम्मद इब्नबाल के सम्पादित तब दिसम्बर 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था, जिसमें पहले पहल पाकिस्तान की योजना रखी गई। बाद के युग में यह नारा एक भयंकर युद्धभोप के रूप में तथा भ्रातघात के हथियार के रूप में इस्तेमाल होनेवाला था। गोलमेज में जो मुसलमान गए, वे किसी ढंग के समझौते पर राजी थे, पर उन्हें भड़का दिया गया और उनके फलस्वरूप

सारी दुनिया के पत्र जगत के सामने जो जग हसाई हुई, वह एक स्मरणीय बात है। घूत साम्राज्यवाद ने यह जग-हसाई विशेषकर इस कारण कराई कि सत्याग्रह आंदोलन के कारण जो अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव उत्पन्न हुआ था, उस पर पानी फिर जाए।

मजे की बात यह है कि साम्प्रदायिक निर्णय से मुसलमान भी खुश न हो सके। उन्हें प्रातो की कुल 160 की करीब सीटों में पौने पाच सौ सीटें दी गई, फिर भी वह समझते थे कि उनके साथ आया हुआ है। बंगाल में मुसलमानों की आबादी 51 फीसदी थी, पर उन्हें 47½ फीसदी सीटें दी गईं, और उहे सम्पूर्ण रूप से भारी पर निर्भर रखा गया। पंजाब में इनकी संख्या 55 फीसदी थी, मगर उन्हें 49 फीसदी सीटें दी गईं थी। मुस्लिम-लीग का जिन्ना युग 1934 से शुरू होता है। 4 मार्च 1934 को लीग का एक जलसा फिर देहली में हुआ, जिसमें बैरिस्टर अब्दुल अजीज सभापति पद से अलग हो गए, और जिन्ना मुस्लिम लीग के स्थायी सभापति नियुक्त हुए।

### कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन अप्रैल, 1936

1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। इसकी नीबत ही नहीं आई। कांग्रेस चुनाव लड़ने में ही सारी शक्ति लगा दी। 1936 में 12, 13, 14 अप्रैल को कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू के सभापतित्व में हुआ। उन्होंने अपने भाषण में जो कुछ कहा, वह बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसमें उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के विश्लेषण के बाद कहा, "मैं इस सम्बन्ध में निश्चित हूँ कि ससार की तथा भारत की समस्याओं का समाधान केवल समाजवाद से ही हो सकता है। यह स्मरण रहे कि मैं इस शब्द का प्रयोग अस्पष्ट मानवतावादी ढंग से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उसका प्रयोग बानिभ आर्थिक रूप में कर रहा हूँ। समाजवाद न केवल एक आर्थिक सिद्धान्त है बल्कि इससे बढ़कर जीवन का एक दर्शन है और उस रूप में भी मैं उसकी तरफ आकृष्ट होता हूँ।" उन्होंने आगे कहा, "यदि भविष्य आशाजनक है तो यह बहुत कुछ सोवियत रूस के कारण और उसने जो कुछ किया है उसके कारण है, और यदि विश्व में हम बीच कोई संकट न आए, तो यह नई सभ्यता और दशों में फैलेगी और इस प्रकार पृथिवी द्वारा युद्धों और सघर्षों का अन्त हो सकेगा।"

लखनऊ कांग्रेस के फाय—इस अधिवेशन में यह मांग की गई कि भारतीयों का शासन विधान भारतीय ही बना सकते हैं अतएव शीघ्र में 'नीघ भारतीयों का विधान सम्मेलन' बुलाया जाए। यह तय हुआ कि अगले चुनाव में हिस्सा लिया जाए। इसके लिए एक पारियामेन्टरी बोर्ड बना दिया गया। अधिवेशन में इस प्रश्न पर भी परामर्श बहस रही कि चुनाव लड़ने के बाद मंत्रिमण्डल ग्रहण किया जाएगा या नहीं। बहरहाल, यह प्रश्न स्थगित रखा गया।

इस समय तक अंग्रेजीनियाम पर फामिस्ट इटली द्वारा हमला शुरू हो गया था। कांग्रेस में इसकी गहानुभूति में भी एक प्रस्ताव पास किया। इसी कांग्रेस में जनमन्थक कमरा भी उनी। मुभाप इस कांग्रेस में इस कारण भाग न ले सके कि वह बहुत ज़िना तक विज्ञान में रूचि के बाद ज्यो ही प्रवर्द्ध लोटे, 1818 के रेगुलेशन 3 के अन्तर्गत गिरफ्तार हो गए।

लिनलिपियों का आगमन—इसी महीने माड बिलिगडन का वायसराय समाप्त हो गया और उनकी जगह लार्ड लिनलिपिया भारत के वायसराय बनकर आए। लार्ड लिनलिपिया भारत में बिनाकून अपरिचित थे, ऐसी बात नहीं। वह कुछ दिन पहले भारत में नव माण कृषि आयाग के अध्ययन होकर यहाँ आए थे। यह आयाग भारत की किसान

जनता की त्रय शक्ति बढ़वाने के उपाय सोचने के लिए आया था। इसके अतिरिक्त वह उस संयुक्त पार्लियामेन्टरी कमेटी के भी सभापति थे क्योंकि तभी विलायती माल बहाल हो सकता था। इटिया ऐक्ट 1935 का जन्म इसी कमेटी से हुआ था। लाड विलिंग्डन का शासन काल दमन युग था। अब लिनलिपगो ने आकर चिकनी-चुपड़ी बातें शुरू कर दीं।

**चुनाव घोषणा तथा चुनाव की तैयारी** - कांग्रेस ने सामने सबसे बड़ा काम चुनाव लड़ना था। इस सबंध में कांग्रेस की ओर से चुनाव घोषणा बनाने के लिए 22 और 23 अगस्त को बम्बई शहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ। यहाँ जो चुनाव घोषणा बनी, उसमें और बातों के अलावा यह वादा किया गया कि मजदूरों को कम से कम मजदूरी तय करना तथा किसानों को हर तरीके से मुक्त करना कांग्रेस का ध्येय है। इन दिनों देश में इस विषय पर बड़ी बहस चल रही थी कि मंत्रि पद ग्रहण करना चाहिए या नहीं। प्रश्न को आगे के लिए टाल दिया गया। पंडित भदनमोहन मालवीय का दल अलग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था, उससे भी कांग्रेस का सम्बन्ध हो गया। इस प्रकार अपनी सब शक्तियों को एकत्र कर कांग्रेस चुनाव सत्राम में उतरने के लिए तैयार हो गई।

### फैजपुर अधिवेशन दिसम्बर, 1936

कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1936 के 27 तथा 28 दिसम्बर को महाराष्ट्र के फैजपुर नामक एक गांव में हुआ। गांधीजी ने ही यह सलाह दी थी कि कांग्रेस का अगला अधिवेशन गांवों में होना चाहिए, जिससे कि गांवों की जनता को कांग्रेस के साथ प्रत्यक्ष सम्पर्क में आने का मौका मिले। अहमदाबाद कांग्रेस के बाद कांग्रेस ने यह नया कदम उठाया था। हम पहले ही बता चुके हैं कि अहमदाबाद कांग्रेस में मेज-कुर्सी हटा दी गई थी, और गांवों में अधिवेशन शुरू किया। अवश्य इस नये कदम के साथ ही एक बड़ी समस्या का भी उदय हुआ। वह समस्या यह थी कि कांग्रेस में आने वाली लाखों जनता के खाने पीने, रहने का प्रबंध कैसे किया जाए। अवश्य इससे उस इलाके के देहातियों को आर्थिक तथा अन्य सब तरीके से फायदा रहने लगा, पर बाहर के साखी लोगों की अमुबिधा की तुलना में यह कहा तक लाभ रहा, यह विचारणीय है।

**अधिवेशन का काय**—इस अधिवेशन के सभापति फिर जवाहरलाल हुए। पंडितजी ने अपनी स्वभावसिद्ध विद्वता के साथ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की आलाचना करते हुए संसार में फासिस्टवाद के खतरे की ओर लोगों की दृष्टि आकर्षित की। उन्होंने फिर लोगों को यह समझाया कि समाजवाद ही भारत की गरीबी की समस्या को हल करने में समर्थ है। पर साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि समाजवाद स्थापित होने के लिए यह आवश्यक है कि पहले स्वतंत्रता हो। उन्होंने कहा कि सारे विश्व में समाजवाद और फासिस्टवाद में संघर्ष चल रहा है। इस अधिवेशन में भी मंत्रि पद लिया जाय कि नहीं, इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया गया। यह तय हुआ कि चुनाव के बाद चुने हुए सदस्यों का एक कन्वेंशन बुलाया जाएगा, जिसमें यह प्रश्न तय किया जाएगा।

**चुनाव**—1937 की फरवरी में प्रान्तों में चुनाव हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने इस चुनाव के सबंध में जिस अथक रूप से देश का दौरा किया, उससे उनका एक के बाद एक, दो बार कांग्रेस का सभापति चुना जाना समर्थित हो गया। किसी भी एक नेता को इस चुनाव के जीतने में इतना ध्येय नहीं है, जितना उन्हें है। कांग्रेस जनों ने इन सालों में जिस प्रकार से जेल, लाठी, मार, जुर्माना सहन किया था, उससे कांग्रेसी जनता में परि

चिन और प्रिय हो चुके थे। जो लोग गांधीजी द्वारा प्रतिपादित जेल जाकर हृदय परिवर्तन की हसी उड़ाते हैं, उन्हें भी यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि इस जेल जाने के कार्यक्रम के कारण ही कांग्रेसी जनता में प्रिय हो गए, और कांग्रेस का नाम घर घर पहुंच गया। दूसरों को कोई जानकारी ही नहीं था।

**कांग्रेस की जीत—**चुनाव में कांग्रेस विजयी हुई। कांग्रेस को मद्रास में 215 सीटों में से 159 अर्थात् 74 फी सदी बिहार में कुल 152 सीटों में से 98 अर्थात् 65 फी सदी, बंगाल में कुल 250 सीटों में से 56 सीट अर्थात् 22 फी सदी, मध्य प्रदेश और बरार में 112 सीटों में से 72 याने 62.5 फीसदी, बम्बई में कुल 175 सीटों में से 86 याने 49 फी सदी, संयुक्त प्रांत में 228 सीटों में से 134 याने 59 फी सदी, पंजाब में 125 सीटों में से 18 याने 10.5 फी सदी, सीमाप्रान्त में कुल 50 सीटों में से 19 याने 38 फी सदी, सिंध में 60 सीटों में से 7 याने 11.7 फी सदी, असम में कुल 108 सीटों में से 33 याने 31 फी सदी, उड़ीसा में कुल 60 सीटों में से 38 याने 60 फी सदी सीटें कांग्रेस को मिलीं।

**चुनाव में लोग हारी—**मुस्लिम लोग ने भी चुनाव में पूरी तैयारी के साथ हिस्सा लिया था, पर उसे कोई विशेष सफलता नहीं मिली, यह निम्नलिखित सूची से ही गत होता है।

प्रांत	कुल मुस्लिम सीटें	लोग को मिलीं
मद्रास	28	10
बम्बई	29	20
बंगाल	117	39
संयुक्त प्रांत	64	27
पंजाब	84	1
बिहार	39	0
मध्य प्रान्त	14	0
असम	34	9
सीमाप्रान्त	36	0
उड़ीसा	4	0
सिंध	33	3

**लोग का दावा खोखला—**इस प्रकार लोग का चुनाव में चोपाई से भी कम मुस्लिम सीटें प्राप्त हुईं। पंजाब में मिर्जापुर हयात था, सिंध में अल्तावशा, बंगाल में कलकत्ता हब के मतदाताओं का नाम बरन वाली यूनियनलिस्ट, अल्तावशा का दल तथा कपूर प्रजा पार्टी के कारण लोग को इस प्रकार नीचा देखना पड़ा। यहना न हागा कि इस जमाने में लोग मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था होने का दावा नहीं कर सकती थी, फिर भी लोग ने बहुत नता पीछे हटनेवाले नहीं थे। जिना ने इही जिना घन खतरनाक नारा फिर उठाया जिसमें उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में सांस्कृतिक नदी होना चाहिए। उन्होंने 'मैनचेस्टर गार्जियन' में प्रकाशित एक लेख में कहा कि एक माथारण भ्रष्ट है कि यह समझना बठिन नहीं है कि भारतवर्ष में पश्चिम में सम्मानित मोरतत्र का गिद्वान क्या लागू नहीं हो सकता।

**मंत्रिमण्डल तथा दल—**चुनाव के पश्चात्परूप कांग्रेस 6 प्रांतों में अर्थात् बम्बई, बिहार, मद्रास, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा, मध्य प्रांत में मंत्रिमण्डल बनाकर गयी।

पंजाब, बंगाल, सिंध अर्थात् जिन प्रान्तों में मुस्लिम सीटें अधिक थीं, उनमें लीप नहीं भी मंत्रिमण्डल नहीं बना सकती थी पर सिकंदर हयात खा, फजलुल हक तथा अल्ताफुल्लाह इन प्रांतों में मंत्रिमण्डल बना सकते थे और उन्होंने बाद में मंत्रिमण्डल बना भी लिए।

**मंत्रिमण्डल बनाने की शर्त**—कांग्रेस अब भी मंत्रिमण्डल बनाएगी या नहीं, इस सम्बन्ध में किसी निणय पर नहीं पहुंच सकी थी। 17 तथा 18 मार्च 1937 को इस सम्बन्ध में निणय करने के लिए दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ। इस बार यह तय हुआ कि यदि प्रांत के गवर्नर यह वादा करें कि वे वोटों या विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे, तभी कांग्रेस मंत्रिमण्डल बनाएगी। यह भी तय हुआ कि लाठ साहब को यह वादा सावजनिक रूप में करना पड़ेगा।

**घायसराय द्वारा आश्वासन**—पहली अपील से नए विधान के अनुसार काम होने वाला था। पर कांग्रेस ने जो शर्त रखी, उसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए सरकार ने अल्प सख्या वाले दलों को मंत्रिमण्डल बनाने के लिए बुलाया, और मंत्रिमण्डल बन गए। पर विधान के अनुसार 11 में से 6 प्रांतों में मंत्रिमण्डल न बनने के कारण विधान के व्यर्थ होने की नौबत आ गई। इसलिए सरकार की ओर से कांग्रेस से बातचीत चली। 21 जून को लाठ लिनलिथगो ने यह घोषणा की कि कानून के अनुसार शासन कार्य में मंत्रिमण्डल की ही अधिकार प्राप्त है। बहुत कम मामलों में गवर्नर अपनी राय से काम कर सकते हैं, और जब वह ऐसे काम करें तो मंत्रिमण्डल को यह अधिकार होगा कि वह यह साफ कर दे कि अमुक काम उनका किया हुआ नहीं है। इस समय तक कांग्रेस के अंदर मंत्रिमण्डल ग्रहण करने वालों की सख्या अधिक हो चुकी थी। 7 जुलाई को कायसमिति ने इस आश्वासन को यथेष्ट समझ कर मंत्रिमण्डल कायम करने का आदेश दे दिया।

**तनख्वाह पाच सौ**—कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों ने मंत्रिपद ग्रहण करते ही कराचा के प्रस्ताव में यह जो कहा गया था कि अधिक से अधिक तनख्वाह पांच सौ हों, उसे काय रूप में परिणित कर दिया। इसके अनुसार मंत्रियों की तनख्वाह पांच सौ और भत्ता 250 रुपए तय हुआ।

**क्रांतिकारी कैदी रिहा और उनका स्वागत**—कांग्रेस ने अपनी चुनाव घोषणा में वादा किया था कि सभी राजनीतिक कैदी रिहा कर दिए जाएंगे। इसी वाद के अनुसार संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी मंत्रिमण्डल ने काकोरी कैदियों को, जो गत 12 साल से जेलों में बंद थे, रिहा कर दिया। छठने पर काकोरी कैदियों का देश में बड़ा शानदार स्वागत हुआ। कानपुर तथा लखनऊ की नगरपालिकाओं ने उन्हें मानपत्र दिए तथा लासों की भीड़ ने इन लोगों की बाणी सुनी। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, रायवादी, समाजवादी सभी स्वागत में शरीक थे।

**गांधीजी द्वारा स्वागत की निंदा**—उस अभूतपूर्व स्वागत से सरकार बहुत घबरा गई, और गांधीजी ने एक वक्तव्य देते हुए इस सबंध में किए गए सारे सावजनिक प्रदर्शनों को अशोभनीय करार दिया।

उही दिनों अण्डमान के राजनैतिक कैदी अनशन कर रहे थे। सारे देश में उनके लिए बड़ा जोश था। गांधीजी ने इसमें हाथ बटाया।

**किसान सम्बंधी कानून**—कांग्रेस मंत्रिमण्डलों ने पद ग्रहण करते ही किसानों की भलाई के कानून के कार्य को उठाया, पर जिस तेजी से उन्होंने इस काम को उठाया, उस तेजी से यह आगे नहीं बढ़ सका।

क्रांतिकारी कैदियों के सम्बन्ध में जिन्हें—संयुक्त प्रान्त तथा बिहार के सभी राजनैतिक कदी अभी तक छोड़े नहीं गए थे। कुछ क्रांतिकारी कदियों की रिहाई के संबंध में सरकार ने अड़गल लगा दिया। उधर देश में इनकी रिहाई के लिए बराबर मांग की जा रही थी। कांग्रेस मंत्रिमण्डल उन्हें छोड़ना चाहते थे, पर गवर्नर इसमें रोक अटका रहे थे। फरवरी 1938 तक यह एक शासकीय संकट के रूप में परिणत हो गया और बिहार तथा संयुक्त प्रान्त के मंत्रिमण्डलों ने गवर्नर के इस हस्तक्षेप के विरुद्ध मंत्रिमण्डलों से इस्तीफा दे दिया। यह स्मरण रह कि बीच में 3 सितम्बर 1937 को सीमा प्रान्त के गैर कांग्रेसी मंत्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास हो चुका था, और वहां भी कांग्रेसी मंत्रिमण्डल कायम हो गया था। इसलिए जिस समय बिहार तथा संयुक्त प्रान्त के मंत्रिमण्डलों ने इस्तीफा दिया, उसी समय यह साफ कर दिया गया कि क्या तो दो ही मंत्रिमण्डल न इस्तीफे दिए हैं पर आगे बाकी पांच कांग्रेसी मंत्रिमण्डल भी इस्तीफे दे देंगे। इसी हालात में हरिपुरा कांग्रेस हुई। इसके वृत्त के पहले हम यह देखें कि इस बीच और कौन सी घटनाएँ हुई।

कांग्रेस की वैदेशिक नीति— कांग्रेस ने जिस समय मंत्रिमण्डल ग्रहण किया, उस समय अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति बहुत तजी से बिगड़ने लगी थी। इस साल जुलाई के महीने में जापान ने चीन पर हमला कर दिया था। उधर अवीसीनिया और स्पेन में सशई जारी थी ही। भारतीयों की सहानुभूति प्रत्येक क्षेत्र में प्रगतिशील शक्तियों के साथ थी। 29, 30, 31 अक्टूबर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था, उसमें जापानी हमले की निंदा की गई। इस प्रकार कांग्रेस की आखें बराबर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की ओर लगी रही।

लीग के साथ समझौते की चेष्टा — इस बीच की घटनाओं में एक खास बात यह भी है कि लीग के साथ समझौते की चेष्टा की गई। कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल इस संबंध में जिन्ना से मिले, पर कोई नतीजा नहीं निकला। हम पहले ही लिखा चुके हैं कि इस समय तक मुस्लिम लीग में भी लीग को एक चौपाई सीटें नहीं मिली थी। ऐसी हालत में फजलुल हक मिर्जापुर हयात, अल्लावुल्लाह आदि मुसलमानों के वास्तविक नेताओं से न मिलकर जिन्ना से मिलना कहा तक उचित हुआ, और कहा तक इसी गलती के कारण मुस्लिम लीग की बढोतरी हुई, यह विचारणीय है।

## हरिपुरा अधिवेशन 1937

कांग्रेस का अगला अधिवेशन बारनोली के हरिपुरा गांव में 19 फरवरी से सुभाषचन्द्र बोस के सभापतित्व में शुरू हुआ। सुभाष कुछ दिन पहले ही जेल से छूटे थे। उन्होंने अपने भाषण में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर प्रकाश डालते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि लड़ाई का खतरा करीब है। उद्घाटन विशेषण 1935 के एक्ट में उल्लिखित सघ शासन की निंदा की। कांग्रेस ने भी सघ शासन की इस योजना के विरुद्ध एक प्रस्ताव पास किया।

क्रांतिकारी कदी छूटे—दो मंत्रिमण्डलों के इस्तीफा देने में सरकार को झुकना पड़ा और हरिपुरा के बाद कांग्रेस ने इन प्रान्तों में फिर मंत्रिमण्डल ग्रहण कर लिया और जिन राजनैतिक कैदियों के संबंध में झगडा था, वे रिहा कर दिए गए। इस प्रकार कांग्रेसी प्रान्तों के सब क्रांतिकारी कैदी छूट गए।

नेशनल प्लानिंग कमेटी—सुप्रसिद्ध योजना कमेटी (National Planning Committee) कायम हुई। इस कमेटी का उद्देश्य यह था कि प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान



तथा संगठन के द्वारा आगे बढ़ा जाए। स्पष्ट कहा जाए, तो यह कमेटी गांधीजी द्वारा कल्पित ग्रामो की आत्मनिर्भरता नीति से भारत को ऊपर उठाकर एक आधुनिक औद्योगिक देश में परिणत करना चाहती थी। जवाहरलाल नेहरू इस कमेटी के वक्ता हुए। कांग्रेस सरकारों के अतिरिक्त बंगाल, पंजाब, सिंध की सरकारों ने तथा हैदराबाद, मैसूर, बड़ोदा, तिरुवावुर, भोपाल आदि रियासतों ने इस कमेटी में भाग लिया। कांग्रेस को सब तरह के विद्वानों तथा विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त था। बहुत हितकर भावों का संग्रह किया गया। कमेटी का उद्देश्य भारत का शीघ्रातिशीघ्र औद्योगीकरण ही नहीं, सब क्षेत्रों में उन्नति करना था यह इसके विभागों के नाम में ही व्यक्त होता है। विभागों के नाम इस प्रकार थे—(1) कृषि, (2) उद्योग (3) विभिन्न मन्त्रदायों की सत्ता तथा उनके पारस्परिक सम्बन्ध का निष्पत्ति (4) यातायात तथा यानगाहन व साधना की उन्नति, (5) व्यापार और राजस्व, (6) लोक कल्याण, और (7) शिक्षा। यह मात्र काम एक कमेटी नहीं कर सकती थी, इसलिए विशेषज्ञों की उत्तम-अवत 27 उपसमितियाँ बना दी गई। कमेटी ने अपने सामन जो उद्देश्य रखे, वे राष्ट्रीय निर्माण की दृष्टि से प्रगतिशील थे।

असम में भी कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल - असम में भी कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल काम में लगाया गया। इस प्रकार 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल बन गए। इन मन्त्रिमण्डलों ने जिन तरीकों से काम किया, उनके चार हिस्सों में बांटकर दिखाया गया है। कांग्रेस का उद्देश्य था—(1) लगान तथा मालगुजारी घटाना, (2) किसानों को जमीन पर अधिकतर अधिकार देना, (3) उस कब्जदारी से बचाना, और (4) मजदूरों की उन्नति करना। कांग्रेस ने इनकी तरफ बल दे दिया। कांग्रेस के प्रधान नेता गांधीजी थे, इसलिए कुछ बातें उनके विशेष विचारों के अनुसार करने की कोशिश की गई। गांधीजी शराब पीने के पक्ष में थे। तदनुसार मन्त्रिमण्डलों ने इस सम्बन्ध में काम शुरू किया। कुछ इलाकों में शराब बिक्री, बनाना बंद कर दिया गया। इसी प्रकार गांधीजी की शिक्षा सम्बन्धी वर्गा योजना का काम में लागे की कोशिश की गई। मद्रास के मन्त्रिमण्डल ने अछूतों और तथा हिंदी प्रचार के क्षेत्र में काम किया। संयुक्त प्रांत के मन्त्रिमण्डल ने ग्राम-सुधार की योजना बनाई। इसमें कोई संदेह नहीं कि कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने इंडिया ऐक्ट 1935 तथा कांग्रेस की वर्गीय योजना के बावजूद अनेक सुधारात्मक कार्य किए। मन्त्रिमण्डल के जमाने में मजदूरों की कई हड़तालें हुईं।

यूरोप में फासीवाद - अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति क्रमशः बिगड़ती चली जा रही थी। हिटलर एक दुर्दैव की तरह यूरोप के राजनैतिक गणन में तपने लगा था। 1914-18 के युद्ध के बाद फ्रांस तथा ब्रिटेन के पूँजीपतियों ने जर्मन पूँजीवाद को उठने न देने के लिए तैयार एक के सभी व्यवस्था कर ली थी। याने वहाँ के पूँजीवाद का नष्ट करने के अलावा सब कुछ किया गया था। वे ऐसा क्यों करते, जब वे खुद ही पूँजीवादी थे? जर्मन पूँजीवादी जीवित और सबल था और उसने साथ वहाँ प्रचुर परिमाण में कोयला, लोहा, बिजली तथा विज्ञान भी था। साथ ही एक ऐसा समाजवादी आन्दोलन था, जो यद्यपि इतना मजबूत नहीं था कि सरकार पर कब्जा कर ले, पर इतना मजबूत अवश्य था कि पूँजीपतियों के शासन को खतरे में डाल दे। साथ ही अंग्रेजों साम्राज्यवाद की शह थी। तो फिर फासीवाद के उदय में क्या बरकरार हो सकती थी? इन परिस्थितियों में इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फासीवाद का उदय हुआ। इधर जर्मनी में हिटलर एक के बाद एक आत्ममर्णात्मक बल उठाता जा रहा था। उसने 1938 के मितम्बर में चेकोस्लावकिया का सूडेटन प्रांत माँगा और यह उसे दे भी दिया गया।

परिस्थिति पर सुभाष बाबू—अब लड़ाई क बादल तिलकुल सिर पर थे। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि ऐसे समय में केन्द्र में भी भारतीयों के साथ कुछ समझौता हो जाए, और 1935 के इंडिया ऐक्ट के सध वाले हिस्से को कुछ उलट फेर के साथ भारतीय ग्रहण कर लें। सुभाष ने इसकी परवा नहीं की, और अपने पत्थक व्याख्यान में कड़े शब्दों में सध योजना की निंदा की। उन्होंने यहां तक कहा कि यदि कांग्रेस सध योजना ग्रहण करे, तो वह अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे और इसके विरुद्ध सग्राम करेंगे।

## त्रिपुरी कांग्रेस 1939

इसी समय अगली कांग्रेस के सभापति का चुनाव हुआ। चुनाव में सुभाष जीत गए। गांधीजी अब तक चुप थे, पर अब उन्होंने कहा कि पट्टाभि की हार मेरी हार है। पर सुभाष तो चुने जा चुके थे। इन्हीं परिस्थितियों में 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस का अधिवेशन 10, 11, 12 मार्च को हुआ। जब त्रिपुरी में कांग्रेस होने वाली थी, उस समय सुभाष बहुत बीमार थे (इसलिए मोलाना अबुलकलाम ने सभापतित्व किया) और दूसरे, उन्हीं दिनों गांधीजी राजकोट के सम्बन्ध में अनशन कर रहे थे। इन दिनों बोसवादी तथा गांधीवादियों का सम्बन्ध इतना खराब हो गया कि गांधीवादी कहते थे कि बोस बीमार नहीं हैं लोगो की सहानुभूति पाने के लिए भवकड भारकर पड़े हैं। दूसरी तरफ लोगो ने यह कहा कि इस समय गांधीजी के अनशन का उद्देश्य अपनी तरफ कांग्रेसजनों की सहानुभूति खींचकर सुभाष को नीचा दिखाना है।

पत प्रस्ताव— पहले यह भय था कि त्रिपुरी में अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाएगा पर यह प्रस्ताव नहीं आया। इसकी जगह पत प्रस्ताव रखा गया, जिसमें अध्यक्ष से कहा गया कि आप महात्माजी की अनुमति से अपनी कायसमिति बनाएं। कांग्रेस समाजवादी दल इस प्रस्ताव पर असह्य हट गया। इसी को सुभाष के प्रशंसक त्रिपुरी का विश्वासघात कहते हैं। पत प्रस्ताव पास हो गया।

सुभाष का इस्तीफा और फारवर्ड ब्लॉक का सगठन—झगडा बढ़ता ही गया और सुभाष कायसमिति न बना सके। पहले की कायसमिति के सदस्यों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। अब सुभाष के लिए परिस्थिति विकट हो गई। अन्त में उन्हें इस्तीफा दे देना पड़ा, और राजेन्द्र बाबू कांग्रेस के सभापति बनाए गए। इसी समय सुभाष ने फारवर्ड ब्लॉक नाम से नई सस्या का सगठन किया। इसका उद्देश्य पहले एक ब्लॉक वर्गानु वर्गपक्ष के समूक्त मोर्चे के रूप में रहना था, पर वर्गपक्षी दलों ने जब सहयोग नहीं किया, तो मोर्चों की जगह धीरे धीरे यह एक दल में परिणत हो गया। जिस समय फारवर्ड ब्लॉक बना था, उसमें और गांधीवादी दल में सिवा इसके कोई विशेष संध्यातिव्यतिरेक नहीं था कि फारवर्ड ब्लॉक तेज चाल में विश्वास करता था, गांधी गुट को नंतरव से हटाना चाहता था, और समझौते के विरुद्ध था।

कुछ आपत्तिजनक प्रस्ताव—1939 के जून में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कुछ ऐसे प्रस्ताव पास किए जिनसे यह समझा गया कि कांग्रेस के अंदर के वर्गपक्षी दलों की स्वतंत्रता पर आघात हुआ है। ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से या बहुत बड़े सम्मति से पास नहीं हुए थे। एक प्रस्ताव में यह हिदायत थी कि प्रांतीय कांग्रेस कमेटी स अनुमति प्राप्त किए बगर कोई कांग्रेसजन सत्याग्रह नहीं कर सकता। समझा गया कि इस प्रस्ताव से किसान तथा मजदूर सभाओं की स्वतंत्रता छिन गई थी। दूसरे प्रस्ताव में कांग्रेस मंत्रिमण्डल की प्रांतीय कांग्रेस कमेटी से स्वतंत्र करके अखिल भारतीय पार्लियामेण्टरी सर्व-कमेटी के, जिसके प्रधान सरदार पटेल थे, अधीन कर दिया गया। इन दिनों कुछ प्रांतीय

में वामपक्षियों का कांग्रेस में जोर था।

**प्रस्तावों का विरोध**—इन प्रस्तावों के विरुद्ध क्या किया जाए इसका निर्णय करने के लिए सब मतस्थानीय वामपक्षियों की एक सभा लेफ्ट वसालिजेशन कमेटी के नाम से हुई, जिसमें तय हुआ कि 9 जुलाई को अखिल भारतीय रूप से इन प्रस्तावों का विरोध किया जाए। तदनुसार उस तारीख को सावजनिक सभाओं का ऐलान हुआ। आचार्य कृपलानी तथा डॉक्टर राजेन्द्रप्रसाद ने धमकी दी कि यदि सूचना के अनुसार सभा की गई, तो अनुशासन की वारंवाई की जाएगी। यद्यपि एम० एन० राय इस कमेटी में शामिल थे, पर धमकी पावर बहुत बाल्यक्रम से ऐन भीके पर खिसक गए। और भी बहुत से वामपक्षी कान्नी बाट गए। इसलिए यह वामपक्षी कमेटी टाय-टाय फिक्स हो गई।

**अनुशासन की वारंवाई**—9 जुलाई की सभाएं कुछ हद तक सफल रही। भारत के एक कोने में लेकर दूसरे कोने तक सभाएं हुईं। एम० एन० राय के अतिरिक्त सब वामपक्षियों ने इन सभाओं में भाग लिया। इस प्रदर्शन के कार्यक्रम कायसमिति का अगली बैठक में सुभाष पर अनुशासन की वारंवाई की गई और उन्हें सब पदों से निवारित कर चार आने का सदस्य भर रहने दिया गया। उनके अलावा और जिन कांग्रेसियों ने 9 जुलाई की सभा में भाग लिया था, उन पर अनुशासन की वारंवाई करने का भार प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों पर छोड़ दिया गया। उस समय सुभाष बंगाल कांग्रेस कमेटी के सभापति थे, किंतु इस प्रस्ताव के बाद वे सभापति नहीं रह सकते थे। इस कारण वे अपने अलग हो गए।

**बंगाल में गड़बड़**—बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने दूसरा सभापति चना अस्वीकार किया पर सुभाष बाबू के बीच में पड़ने से उन्हीं के द्वारा नामजद श्री राजेन्द्र चन्द्र देव चुने गए। रामगढ़ के पहले बंगाल में कांग्रेस का कोई चुनाव न हो सका, और बंगाल, रामगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव में भाग न ले सका। वहां कुछ कांग्रेसी नेता तथा करीब आधे एम० एन० ए० एड होंक कमेटी की तरफ हो गए पर जनता सम्पूर्ण रूप से उनके विरुद्ध थी, इतनी कि एड होंक कमेटी के लोग एक भी सावजनिक सभा नहीं कर सकते थे। इस प्रकार बंगाल में बराबर दो कांग्रेस कमेटियां काम करती रही और जब नेतागण 1942 के बाद छूटे, तभी उनका मिलन हुआ।

**वामपक्षी एकता की चेष्टा**—सुभाष ने उस युग में वामपक्षी शक्तियों को एकत्र करने की बहुत बड़ी चेष्टा की थी। वह चेष्टा सफल नहीं हुई, पर इस बात को भलाया नहीं जा सकता कि इस दिशा में उन्होंने एक बड़ा कदम रखा था।

## द्वितीय महायुद्ध और कांग्रेस

**हिटलर को बड़ाया—**हम पहले चेकोस्लावाकिया व बल्गियन द्वारा हिटलर की दानव को तुष्ट करने की चेष्टा का उल्लेख कर चुके हैं। म्यूनिख पकट में यह आशा थी कि इनने स हिटलर मान जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि यूरोप में तड़ाई छिड़ने की स्थिति आ गई। रूस के नेता इस बात को जानते थे, और वे चाहते थे कि रूस और पश्चिमी लोकतंत्रों में समझौता हो जाए, जिससे हिटलर का विराध किया जा सके पर अंग्रेज राजनीतिज्ञ इन इस आशा से टालते रहे कि हिटलर रूस पर हमला करेगा। इसी धारणा के बशवर्ती हाकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने जर्मनी के फासिस्टवाद को बढ़ाया था। हिटलर ने इटली तथा जापान के फासिस्ट राष्ट्रां के साथ एक त्रिमंडान विरोधी पकट कर रखा था, जिसके कारण उनके मन में यह सुनहली आशा थी।

**इसी जर्मन पकट—**इन आशाओं को व्यर्थ करने तथा तत्काल अपनी रक्षा करने के लिए सावियत रूस ने फासिस्ट जर्मनी के साथ 23 अगस्त 1939 को अनाक्रमण संधि कर ली। स्मरण रहे कि सोवियत रूस पश्चिमी लोकतंत्रों के भाष जो मर्घ करना चाहता था, वह केवल अनाक्रमण संधि नहीं थी, बल्कि उस संधि में यह शर्त रखी जाने वाली थी कि यदि एक पर आक्रमण हो, तो दूसरा उसकी रक्षा के लिए आ जाए। पर, पश्चिमी लोकतंत्रों ने इसे मंजूर नहीं किया था। तब रूस को जर्मनी से पकट करना पड़ा।

**भारत सरकार भी लड़ाई में कड़ी—**जो हो इसी के बाद हिटलर ने पोलैण्ड पर हमला कर लिया। ब्रिटेन तथा फ्रांस पोलैण्ड की रक्षा के लिए बचनबद्ध थे इसलिए यही से महायुद्ध छिड़ गया। ब्रिटेन के लड़ाई में कूदते ही भारत सरकार ने भी युद्ध घोषणा कर दी। इस मामले में भारत की ब्रिटिश सरकार ने न तो केन्द्रीय धारासभा की राय ली, और न प्रांत के मंत्रिमण्डल की ही राय ली। सरकार इतने ही से सतुष्ट नहीं रही, बल्कि उसने अब प्रांत की कांग्रेस सरकारों के सिर के ऊपर से काम करना शुरू किया।

**कांग्रेस का रुख—**कांग्रेस कार्यसमिति ने अगस्त 1939 के प्रारम्भ में ही अर्थात् लड़ाई छिड़ने के तीन सप्ताह पहले ही यह प्रस्ताव पास किया था कि “कांग्रेस लोकतंत्र तथा स्वतंत्रता के पक्ष में है। कांग्रेस ने बार-बार यूरोप, अफ्रीका तथा एशिया के सूदूर-पूरुब में फासिस्ट आक्रमण तथा चेकोस्लोवाकिया और स्पेन में ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा लोकतंत्र के साथ विश्वासघात किए जाने की निंदा की है। ब्रिटिश सरकार की भूत-काल की नीति तथा इस समय के रवैये से यह ज्ञात होता है कि यह सरकार लोकतंत्र तथा स्वतंत्रता की पक्षपाती नहीं है, और यह किसी भी समय इन आदर्शों की तिलाजलि दे सकती है। ऐसी हालत में भारतवर्ष ऐसी सरकार के साथ न तो सहयोग कर सकता है। और न वह लोकतान्त्रिक स्वतंत्रता के लिए अपना धन-जन दे सकता है जबकि इस बात का सतर्क है कि इन आदर्शों के साथ विश्वासघात किया जाएगा और जब कि उस स्वयं भी लोकतान्त्रिक स्वतंत्रता नहीं मिली है।” कांग्रेस कार्यसमिति ने सरकार की नीति के

विरोध में केन्द्रीय घासभा के कांग्रेसी सदस्यों की हिदायत दी, कि वे अगले अधिवेशन में उपस्थित न हों।

**सरकार द्वारा स्वतंत्रता सकोच**—त्रिपुरी कांग्रेस में ही सुभाष बाबू ने अपने भाषण में यह कहा था कि लड़ाई नजदीक आ ही रही है इसलिए यह मौका हाथ से जाने न दिया जाए, और 6 महीने की मुहलत देकर सरकार के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी जाए। अन्य वामपन्थियों ने भी इसी आशय की बातें कही थीं। जिस समय महायुद्ध छिड़ा, पंडित जवाहरलाल नेहरू चुगचुंग में थे। वह फौरन वापिस बुल आ गए। इस बीच भारत सरकार ने न केवल भारत की तरफ से लड़ाई छेड़ दी, बल्कि उन्होंने कुछ आड़िनेस भी लया दिष्ट, जिनसे प्रांतीय मन्त्रिमण्डल के अधिकार बहुत कुछ छिन गए। ब्रिटिश मसद ने भी फौज 1935 के पैक्ट को सुधारते बलियाँ बिगाड़त हुए एक सशोधन पास कर दिया जिससे प्रांतीय स्वायत्त शासन एक मज्जाक बन गया था।

**कांग्रेस दल के साथ सहायता पर संयार**—14 सितम्बर को कांग्रेस कायसमिति की बैठक में भाग लेने के लिए जिना को भी निमन्त्रण दिया गया था, पर वह नहीं आए। कायसमिति ने फासिस्टवाद और नात्सीवाद की निन्दा की, पर साथ ही वायसराय तथा ब्रिटिश सरकार ने जो कुछ किया था उससे प्रति भी विरोध जाहिर किया। कांग्रेस ने सहयोग देना स्वीकार किया, पर कहा कि सहयोग इन मानों में ही हो सकता है। जबदस्ती सहयोग प्राप्त करना गलत है। कहा गया कि कांग्रेस लोकतन्त्र तथा स्वतंत्रता के पक्ष में है, पर भारतवर्ष एक ऐसे युद्ध में सहयोग नहीं दे सकता जिसका उद्देश्य तो लोकतन्त्र तथा स्वतंत्रता बताया जा रहा है, परन्तु स्वयं भारतवर्ष में ही जो कुछ मामूली नागरिक स्वतंत्रता थी वह भी छिन ली गई है। यह कहा गया कि यदि युद्ध का उद्देश्य साम्राज्यवादी स्वार्थों, उपनिवेशों, स्थिर स्वार्थों की रक्षा है, तो भारत को ऐसे युद्ध से कोई मतलब नहीं हो सकता। राजवाड़ों के शासकों की ओर से जो यह ऐलान किया था कि वे लोकतन्त्र तथा स्वतंत्रता की ओर से लड़ेंगे, कायसमिति ने इसकी समालोचना करते हुए कहा कि पहले वे अपनी रियासतों में तो लोकतन्त्र तथा स्वतंत्रता स्थापित करें, फिर घड़-घटकर दूसरी बातें करें। कायसमिति ने बार-बार यह बात साफ कर दी कि वह ब्रिटेन को सहायता देने के लिए तैयार है, पर बिना शर्त नहीं।

**मन्त्रिमण्डलों का इस्तीफा**—ब्रिटिश सरकार ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। उधर 8 प्रांता में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों की हालत बुरी होती जा रही थी। गवर्नरों और मन्त्रियों में खीचातानी बढ़ रही थी। 22 अक्टूबर को कांग्रेस कायसमिति ने मन्त्रिमण्डलों को पद त्याग करने की हिदायत दी, और नवम्बर में ही एक एक करके मन्त्रिमण्डलों ने इस्तीफा दे दिया।

**दमनचक्र गुरु**—मन्त्रिमण्डल का इस्तीफा देना था कि दमनचक्र बहुत जोर से शुरू हो गया। पञ्जाब की जहंगर पार्टी तथा मयूकन प्रांत की यूथ लीग लड़ाई छिड़ने के बाद से ही युद्ध विरोधी प्रचार काय कर रही थी। चारों तरफ इन लोगों की तथा अन्य लोगों की गिण्टारिया गुरु हो गई। अहरारों ने इस समय सबसे अधिक बहादुरी दिखलाई। स्मरण रहे कि अहरार मुस्लिम प्रधान सस्था थी।

## रामगढ़ कांग्रेस 1940

कांग्रेस ने अब भी यह फैसला नहीं किया कि लड़ाई के विरुद्ध कुछ किया जाए। इसी अवस्था में 1940 के 19-20 मार्च को मौलाना अबुल कलाम आझाद की अध्यक्षता में बिहार के रामगढ़ नामक स्थान में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। यह कांग्रेस इस

कारण बहुत ही एतिहासिक रही कि इनमें बाद वई सालों तक कांग्रेस के अधिवेशन की कोई नीबत ही नहीं आई। अध्यक्ष ने बड़ी योग्यता के साथ कांग्रेस की मांग का स्पष्टीकरण किया, और यह बताया कि कांग्रेस साम्राज्यवादी तथा फासिस्ट तरीकों के विरुद्ध है और उसे बहुत ही खुशी होगी यदि वह आजाद होकर फासिस्टवाद के विरुद्ध लड़ सके। मौलाना ने अपने भाषण में हिन्दू और मुसलमानों में सद्भाव के लिए भी विशेष अपील की। उन्होंने कहा, "एक हजार वर्षों के संयुक्त जीवा से हम एक जाति में परिणत हो चुके हैं।"

**रामगढ़ के निश्चय**— इस कांग्रेस में युद्ध समस्या पर यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि कांग्रेस समझती है कि ब्रिटिश सरकार इस युद्ध का किसी महान उद्देश्य की सिद्धि के लिए नहीं, बल्कि साम्राज्य की रक्षा के लिए कर रही है। कांग्रेस ने घोषणा की कि पूर्ण स्वतंत्रता के अलावा भारतीय किसी बात पर राजी नहीं हो सकते। कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में साफ यह दिया कि भारतवर्ष का विधान भारतीयों का विधान सम्मेलन ही बना सकता है। उसने भारतवर्ष को विखंडित करने के प्रयास का विरोध किया।

**समझौता विरोधी सम्मेलन**— रामगढ़ कांग्रेस के अवसर पर सुभाषचंद्र बोस ने वहां एक समझौता विरोधी सम्मेलन किया। यह सम्मेलन बहुत ही सफल रहा, और इसमें समझौतामूलक नीति का विरोध किया गया। स्वामी सहजानंद इसके प्रमुख व्यक्तित्व थे। जयप्रकाश इसमें आगे बोले पर वह नहीं आए, उल्टे राहुल सांकृत्यायन को भी तार दे दिया कि आप न आए।

**फारवाड ब्लाक का सग्राम**— इस अवसर पर फारवाड ब्लाक ने यह तय किया कि 6 अप्रैल से स्वतंत्रता सग्राम छेड़ दिया जाए। बाद को सचमुच 6 अप्रैल को कुछ स्थानों में सत्याग्रह के ढंग की बातें हुई। मजे की बात यह है कि बंगाल में जहां सुभाष सच मौजूद थे कुछ नहीं हुआ। सुभाष बारपोरेवाले के चुनाव में व्यस्त रहे, पर उत्तर भारत के कुछ स्थानों विशेषकर इलाहाबाद में कोतवाली, जेल इत्यादि स्थानों पर कड़ा चढ़ाने का आंदोलन चला, और इसमें करीब एक सौ व्यक्ति गिरफ्तार हुए। ग्रुप सींग ने यह आंदोलन चलाया। अतः यह कहा जा सकता है कि सुभाष द्वारा चलाया हुआ यह आंदोलन सच्चा की दृष्टि से सोलहो आने असफल रहा। इस आंदोलन में दूसरे किन्हीं वामपक्षी दल ने भाग नहीं लिया। हा, कम्यूनिस्ट पार्टी ने युद्ध विरोधी पर्चेबाजी जारी रखी। बारपोरेवाले से छुट्टी पाने के बाद सुभाष ने हासवेल मानुमट तोड़ने का आंदोलन चलाया, पर फजलुल हक ने चालाकी से मूर्ति ही रात को हटवा ली, इस कारण कई सी व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन ठप्प हो गया।

**आर० एस० पी० का जन्म**— रामगढ़ में ही अनुशीलन समिति के नेताओं की एक अखिल भारतीय बैठक हुई। अनुशीलन समिति बंगाल की तपी हुई प्रातिकारी पार्टी थी। इस अधिवेशन में पार्टी का नाम भारतीय क्रांतिकारी समाजवादी दल या आर० एस० पी० आदि रखा गया।

**जून 1940 का सहयोग प्रस्ताव**— सरकार का दमन चक्र जोरों के साथ चलने लगा। कांग्रेस के कुछ नेता सहयोग के लिए लालायित हो रहे थे। राजगोपालाचारी इस प्रवृत्ति के प्रमुख नेता थे। इन्हीं के नेतृत्व में जून 1940 में कांग्रेस कार्यसमिति ने यह कहा कि अभी सरकार इतना करे कि आदर्श रूप से पूर्ण स्वतंत्रता को मान ले पर कार्य रूप में 1935 के इण्डिया ऐक्ट के अंदर ही केन्द्र में विभिन्न दलों की राष्ट्रीय सरकार बनाई जाए। वायसराय रहे, पर शक्ति इस सरकार के हाथ में रहे, तो कांग्रेस सरकार को लड़ाई चलाने में मदद देगी। महात्माजी ने इस प्रस्ताव का इस कारण विरोध किया

कि उनका कहना था कि इस प्रकार युद्धोद्योग में शिरवत में अहिंसा की नीति टूट जाती है। पर कांग्रेस के इस नरम प्रस्ताव पर भी सरकार राजी नहीं हुई।

मौलाना आजाद उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इस कारण उन्होंने यद् से उत्पन्न कांग्रेस के चोटी के नेताओं में अदर-अदर क्या लहरें प्रति लहरें उठी, उसका जो वणन दिया, उसे कुछ व्योरे के साथ हम उनकी आत्मकथा से उद्धृत कर रहे हैं। वह लिखते हैं “कांग्रेस के इतिहास में यह बहुत ही काटे का समय था, पर इससे भी अधिक खतरनाक यह बात थी कि हम लोगों में इस सबंध में मतभेद थे। मैं कांग्रेस का प्रधान था, और मैं चाहता था कि भारत को लोकतन्त्र के शिविर में ले जाऊँ, बशर्त कि वह स्वतन्त्र कर दिया जाए। लोकतन्त्र एक ऐसा मध्य था जिस पर भारतीय बहुत स्पष्ट भावनाएँ रखते थे। पर लोकतन्त्री शिविर के साथ हो जाने के भाग में एक ही रोड़ा था और वह था भारत की गुलामी। गांधीजी के लिए यह बात ऐसी नहीं थी। गांधीजी के लिए प्रश्न शांतिवाद का था न कि भारत की स्वतन्त्रता का। मैं इस पर स्पष्ट रूप से घोषणा कर ही कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शांतिवादी संगठन नहीं है, बल्कि भारत की स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए बनाई सस्था है। इसलिए मेरे अनुसार गांधीजी ने जो प्रश्न उठाया था, वह अप्रासंगिक था, पर गांधीजी ने अपनी राय नहीं बदली। उनका दृढ़ विश्वास यह था कि किसी भी हालत में भारत को सड़ाई में भाग नहीं लेना चाहिए।’

पर गांधीजी की यह बात सबको मान्य नहीं थी। इस पर कांग्रेस कायसमिति में मतभेद हो गया। मौलाना आजाद लिखते हैं “प्रारम्भिक सोपानों में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजगोपालाचारी तथा स्याम अब्दुल गफ्फार खाँ मेरे साथ थे। राजेन्द्र प्रसाद आचार्य कृपलानी और शंकरराव देव पूर्ण रूप से गांधीजी के साथ थे। गांधीजी के साथ साथ उनका यह कहना था कि यदि यह मान लिया गया कि स्वतन्त्र भारत युद्ध में भाग ले सकता है तो स्वराज्य के लिए भारत के शांतिमय सग्राम का आधार खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ मैं यह महसूस करता था कि स्वतन्त्रता के लिए आतंरिक संग्राम तथा आक्रमण के विरुद्ध बाहरी संग्राम में फँक है। स्वतन्त्रता के लिए संग्राम करना एक बात थी और देश स्वतन्त्र हो जाने पर युद्ध करना दूसरी बात थी। मरा यह कहना था कि इन दो तर्कों को मिलाया नहीं चाहिए।’

मौलाना के निकट अहिंसा केवल संग्राम का एक तरीका मात्र था। वह उससे हर हालत में बंधे रहने पर विश्वास नहीं करते थे और जैसा कि उन्होंने अपने सस्मरण के प्रथम अध्याय में दिखाया है वह पहले एक नातिकारी थे और नातिकारियों के साथ ही उनके राजनीतिक जीवन का सूत्रपात हुआ था।

मौलाना आजाद के सस्मरणों से पता चलता है कि किस प्रकार युद्ध के प्रभाव के कारण कायसमिति के नेता अपने विचार विकसित करते चले गए। वह लिखते हैं ‘युद्ध के प्रति अपने रुख के सबंध में कायसमिति के सदस्य लड़खड़ाते रहे। उनमें से कोई भी इस बात को भूल नहीं सकता था कि गांधीजी सैद्धांतिक रूप से युद्ध में किसी भी तरह भाग लेने के विरोधी थे और न वे यही भूल सकते थे कि भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम उन्हीं के नेतृत्व में वर्तमान आकार प्राप्त कर सका था। पहली बार एक मौलिक प्रश्न पर वे उनसे मतभेद रख रहे थे और उन्हें अकेला छोड़ रहे थे। साधन के रूप में अहिंसा में दृढ़ विश्वास से उनके निष्कर्ष पर असर आने लगा। पूना की सभा के एक महीने के अंदर सरदार पटेल ने अपनी राय बदल दी और उन्होंने गांधीजी का रुख ग्रहण कर लिया। दूसरे सदस्य भी ढावाढोल रहे। जुलाई 1940 में डा० राजेन्द्र प्रसाद

तथा कायसमिति के कुछ सदस्यों ने मुझे लिखा कि वे युद्ध के सबंध में गांधीजी के विचारों में दृढ़ता के साथ विश्वास रखते हैं और वे चाहते हैं कि कांग्रेस उस पर बनी रहे। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे विचार भिन्न हैं और पूना में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मेरा ही समर्थन लिया था। इसलिए उनके मन में यह संदेह उठ खड़ा हुआ था कि उन्हें 'कायसमिति' में इसलिए नामजद किया गया था कि राष्ट्रपति की (उन दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष का राष्ट्रपति कहते थे) महायता करें, पर चूंकि एक मौलिक प्रश्न पर उनकी मतभेद था तो उनका लिए इस्तीफा देने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया था। उन्होंने इस विषय पर गहराई के साथ विचार किया था और हमें किसी तरह सुझाव मन डालने के लिए वह तब तक कायसमिति के सदस्य बने रहने को तैयार थे, जब तक कि उनके मतभेद का कोई तात्कालिक व्यवहारिक असर नहीं होता। पर यदि ब्रिटिश सरकार ने मेरी बातों को स्वीकार कर लिया और युद्ध में भाग लेना एक सशर्त प्रश्न हो गया, तो उनका सामने इसका सिवा कोई चारा नहीं रहगा कि वे पदत्याग करें। उन्होंने यह भी लिखा कि यदि मैं इस स्थिति में सहमत होऊँ तो वे कायसमिति के सदस्य बने रहने को तैयार हैं, नहीं तो इस पत्र को त्यागपत्र के रूप में लिया जाए। इस पत्र को पढ़कर मुझे बहुत धक्का सा लगा क्योंकि इस पर जवाहरलाल नेहरू, रामगोपालाचारी, आसफ अली और सैयद महमूद के अलावा सभी सदस्यों के हस्ताक्षर थे—यहां तक कि अब्दुल गफ्फार खान ने, जो पहले मेरे बहुत बड़े समर्थक थे, अब अपनी राय बदल दी थी। मुझे अपने साथियों से इस प्रकार के किसी पत्र की आशा नहीं थी। मैंने फौरन लिख दिया कि मैं पूर्ण रूप से उनके दृष्टिकोण को समझता हूँ और उनकी स्थिति को मानता हूँ।"

गांधीजी अपनी राय पर बने रहे, यहाँ तक कि जब वह साठ लिनलिथगो से मिले तो उन्होंने कहा कि ब्रिटन के लोगों को अस्त्र सत्यास लेना चाहिए और उन्हें साम्राज्यवादी शक्ति से हिटलर का विरोध करना चाहिए। इस पर साठ लिनलिथगो उत्तरका गए। जब गांधीजी जाने लगे, तो जसा कि वह हमेशा करते थे, घण्टी बजाकर बगन की सीढ़ियों के साथ मंच पर देते थे जो उन्हें मोटर पर बिठाने आता था, पर इस अवसर पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब गांधीजी मौलाना से मिले, तो उन्होंने भद्रता से इस बात का जिक्र किया, तो मौलाना ने कहा कि आपका सुझाव बहुत ही अद्भुत था और वाइसराय जरूर इससे हक्के बक्के रह गए होंगे। इस पर गांधीजी खूब हस।

कुछ आगे जाकर बताया गया कि जब मौलाना 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह वाली कदम स छूटे तो उन्होंने फौरन ही बारदोसी में, जहाँ गांधीजी ठहरे हुए थे, कायसमिति की बैठक बुलाई। वहाँ उन्होंने यह अनुभव किया कि गांधीजी और उनमें मतभेद और बढ़ चुका है। वह लिखते हैं "मैं फौरन ही गांधीजी से मिलने गया और ऐसा मालूम हुआ कि हम लोगों में मतभेद बहुत बढ़ गया है। पहले केवल सिद्धांत संबंधी मतभेद था पर अब वह स्थिति को जिस तरह देखते थे और मैं जिस तरह देखता था, उसमें आधारभूत भिन्नता थी। गांधीजी अब दृढ़ता के साथ यह समझते थे कि ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्र मानने के लिए तैयार और इच्छुक थी बशर्ते कि भारत यह प्रयास में पूरी सहायता दे। उनका यह ख्याल था कि यद्यपि ब्रिटिश सरकार प्रमुख रूप से अश्विनीवादी थी और मिस्टर चर्चिल उसके प्रधान मंत्री थे, फिर भी युद्ध अब इस मजिद में पहुँच चुका था कि ब्रिटिश सरकार को भारत की स्वतंत्रता सहयोग के मूल्य के रूप में माननी ही पड़ेगी। पर इस सबंध में मेरे विचार बिल्कुल भिन्न थे। मेरा विचार यह था कि ब्रिटिश सरकार ईमानदारी के साथ हमारा सहयोग चाहती थी, पर



वह भारत की स्वतन्त्रता स्वीकार करने के लिए अभी तैयार नहीं थी।”

इस सम्मरण में मौलाना आज़ाद ने जहाँ गांधीजी के साथ अपने मतभेद स्पष्ट रूप से दिखलाए हैं, वहाँ यह भी दिखलाया है कि गांधीजी ने इस बात की अद्भुत प्रतिष्ठा की कि वे दो विरोधी मतों को एक प्रस्ताव में दरशा कर दोनों को सुझा सकते थे। यही बात बाद का कायसमिति में जो प्रस्ताव रखा गया, उसमें देखी गई।

मौलाना आज़ाद ने यह भी दिखलाया है कि सुभाषचन्द्र बोस 26 जनवरी, 1941 के पहले ही भारत से सटक गए थे और इसका गांधीजी पर बड़ा प्रभाव पड़ा था। मौलाना आज़ाद लिखते हैं “गांधीजी स्पष्ट शब्दों में युद्ध व परिणाम के सबंध में कुछ कहते नहीं थे, पर उनके साथ बातचीत करते हुए हमें ऐसा मालूम हुआ कि वह धीरे धीरे मित्र पक्ष की विजय के सम्बन्ध में सन्दिग्ध हो चले थे। मैंने यह भी देखा कि सुभाष बोस के जमनी भाग जाने का उन पर भारी प्रभाव पड़ा था। पहले वह सुभाष दावू के बहुत से कार्यों को पसंद नहीं करते थे, पर अब मैंने देखा कि उनकी राय बदल चुका है। उनके कुछ मतभेदों से मेरा यह मत बना होगा कि सुभाष बोस ने भारत से भागने में जो साहस तथा साधन-सम्पन्नता दिखलाई थी, उसकी वह प्रशंसा करते थे। सुभाष बोस के प्रति प्रशंसा भावना के कारण उनके अनजान में ही युद्ध स्थिति के सबंध में उनका विचारों पर रंग चढ़ने लगा था।”

मौलाना आज़ाद ने तो यहाँ तक लिखा है कि यह प्रशंसा भावना भी एक कारण था कि जब भारत में त्रिप्स मिशन आया तो उस पर एक घबराहट पड़ी रही।

पहले हम देख चुके हैं कि किस प्रकार युद्ध स्थिति के सबंध में महारमाजी के विचार बदले। पर आगे चलकर उनके विचार और किस तरीके से बदले, इस पर मौलाना आज़ाद लिखते हैं “जन 1942 में मैं वर्षा गांधीजी से मिलने गया और उनके साथ लगभग पाँच दिन रहा। उनके साथ जो बातचीत होती थी, उससे मैं यह समझ गया कि युद्ध के प्रारम्भ में उन्होंने जो रुख लिया था, उससे वह बहुत दूर चले गए थे। बात यह है कि इन दिनों जापानी सेना जीत पर जीत प्राप्त कर रही थी और भारत सरकार भी यह समझती थी कि जापानी डायमण्ड हावर की तरफ से कलकत्ता पर हमला करेंगे और उस हालत में भारत सरकार ने यह भी तय किया था कि किस प्रकार स पीछे हटा जाएगा। एक गुप्त गश्ती चिट्ठी प्रधान अधिकारियों को भेजी गई थी कि किस प्रकार वे कलकत्ता, हावड़ा और चौबीस परगना धीरे धीरे छोड़ दें और कौन सा रास्ता पकड़कर चले। रास्ते में कई जगह जापानियों के विरुद्ध प्रतिरोध होने वाला था। उस योजना के अनुसार पहला प्रतिरोध पद्मा नदी पर, दूसरा आसनसोल, तीसरा इलाहाबाद पर होने वाला था। यह भी तय हो चुका था कि जापानी हमले की हालत में घर फूट नीति अपनाई जाए। यह भी तय था कि जमशेदपुर के इस्पात करखाने को नष्ट कर दिया जाए।”

इस स्थिति में गांधीजी का क्या मत रहा, इस पर मौलाना लिखते हैं “मुझे आश्चर्य हुआ कि गांधीजी मुझसे मतभेद रखते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि जापानी सेना भारत में आए तो वह हमारे शत्रु के रूप में नहीं, बल्कि ब्रिटेन के शत्रु के रूप में आएगी। उनका कहना था कि यदि अंग्रेज फौरन भारत छोड़ जाए तो उनका विश्वास है कि जापान भारत पर आक्रमण नहीं करेगा। मैं उनके हर मत को नहीं मान सका और सम्झी बहसों के बावजूद हम किसी राय पर नहीं पहुँच सके। मैंने देखा कि सरदार पटेल के भी विचार वही हैं जो गांधीजी के हैं और शायद उन्होंने ही गांधीजी पर यह प्रभाव डाला था।”

गांधीजी पर नई रोशनी—मौलाना ने बहुत सी बातें ऐसी लिखी हैं जिनसे

गांधीजी के नेतृत्व पर कांग्रेसी नई राशनी पड़ती है। पर 1942 के आन्दोलन के सवध में उन्होंने निम्ना है "गांधीजी यह सोच रहे थे कि इस मोर्चे पर कोई न कोई आन्दोलन चलाया जाए, पर मैंने जब यह पूछा कि प्रतिरोध का कार्यक्रम क्या है तो उनके पास कोई स्पष्ट विचार नहीं था। एतन्मात्र जान जो उन्होंने रखी, वह यह थी कि इस बार लोग खड़े हो जायेंगे। उह चाहिए कि वे गिरफ्तारी का प्रतिरोध करें और उसी गिरफ्तारी स्वीकार करें जो आंग्लिक शासन में हमारे लिए बाध्य हो जाए।"

कायसमिति के अध्यक्ष मन्सूरी से अधिकांश के मन में भी इस आन्दोलन के सवध में कोई स्पष्ट विचार नहीं था। मोलाना ने लिखा है 'वे बहुत कम मोर्चे पर किसी बात पर विचार करते थे और किसी भी हानत में वे गांधीजी के निर्णय के सामने अपने निज का प्रयास नहीं करते थे। इस रूप में उनके माय नभ करना लगभग व्यर्थ था। इसी कारण जानकीत के बाद जो कुछ वह कह गये, वह यह था कि हमें गांधीजी पर पराविश्वास रखना चाहिए। उनका कहना था कि यदि हम उन पर विश्वास रखें तो वह कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। उन्होंने इस सवध में 1930 के नमक सत्याग्रह आन्दोलन का उदाहरण दिया, कि जब वह गुरु हुआ था तो कोई भी नहीं जानता था कि गांधीजी सत्कार स्वयं उस आन्दोलन को चुनकर समझती थी। परन्तु नमक सत्याग्रह आन्दोलन को बहुत बड़ी सफलता मिली और सरकार का सर्व मानस पर राजी होना पड़ा। सरकार पटेल और उनके साथियों का कहना था कि इस बार भी गांधीजी का उसी प्रकार सफलता मिलेगी। मैं मानता हूँ कि इस प्रकार की तब प्रणाली से मुझे सतीत नही होता था।'

जवर्दस्त परतु क्षणिक मतभेद—इस मौके पर मोलाना और गांधीजी में बहुत बड़ा मतभेद हो गया जिसका स्मरण में इस प्रकार उल्लेख किया गया है "5 जुलाई को हमारी बातचीत शुरू हुई और कई दिन तक चलती रही। इससे पहले कई अवसरों पर इस विषय के सवध में मुझ से गांधीजी का मतभेद हो चुका था। पर इससे पहले हमारा मतभेद इतना पूरा नहीं हुआ था। यह उस समय सीमा तक पहुँच गया जब उन्होंने मुझे इस आशय का एक पत्र भेजा कि मेरा मत उनसे इतना भिन्न है कि हम एक साथ काम नहीं कर सकते और यदि कांग्रेस चाहती है कि गांधीजी आन्दोलन का नेतृत्व करें तो मुझे कांग्रेस का अध्यक्ष पद त्याग देना चाहिए और कायसमिति से भी अलग हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यही बात जवाहरलाल भी करें। मैंने फौरन ही जवाहरलाल को बुलाया और उह गांधीजी का पत्र दिखाया। सरदार पटेल भी आ गए और वे उह पत्र पढ़ा तो उह भी वही धक्का मार लगा। वह फौरन गांधीजी के पास गए और उन्होंने उनके इस हल का जवर्दस्त विरोध किया। पटेल ने यह बताया कि यदि आजाद अध्यक्ष पद से अलग हो जाते हैं और जवाहरलाल और मैं कायसमिति में इस्तीफा दे देना हूँ तो देश पर उनका प्रभाव बहुत बुरा पड़ेगा। उस हालत में न केवल जनता का बहिष्कार होगा बल्कि कांग्रेस की भी जड़ें हिल जाएगी। गांधीजी ने यह पत्र मुझे 7 जुलाई को भेजा था, पर दोपहर के समय उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने एक लम्बा भाषण दिया जिसका सार यह था कि उन्होंने सवेरे जल्दबाजी में वह पत्र लिखा था। अब उन्होंने उस विषय पर और भी सोचा है और वह उस पत्र को लौटाना चाहते हैं। मुझे उनकी बात माननी पड़ी। जब 3 बजे कायसमिति की बैठक हुई तो पहली बार जो गांधीजी ने कही, वह यह थी कि एक अनुत्पन्न पापी मोलाना के पास लौट आया है।"

इसके बाद किस तरह आन्दोलन चला और सब नेता गिरफ्तार हुए, गांधीजी अलग रखे गए, परतु बाकी नेता अहमदनगर गढ़ में रखे गए, इन बातों को हम देखेंगे। इन्हीं

दिना मौलाना की पत्नी और बहन का देहान्त हुआ जिसका बड़ा गार्मिक वर्णन सम्मरण में बहुत थोड़े में किया गया है। इसके बाद गांधीजी एकाएक छोड़ दिए गए क्योंकि अनशन से वह बहुत कमजोर हो चुके थे। मौलाना ने लिखा है कि गांधीजी ने यह समझा कि छूटने का कारण यह था कि ब्रिटिश नीति में कुछ तबदीली हुई है पर बाद की घटनाओं ने यह दिखला दिया कि वह गलती पर थे। इसके बाद मौलाना लिखते हैं कि गांधीजी ने इस अवसर पर जो सरकार से बातचीत करने की चेष्टा की, वह भी गलत थी।

मेहरू और मौलाना सही साबित—मौलाना लिखते हैं “जब मैं 1957 में यह लिख रहा हूँ और पहली घटनाओं पर दृष्टिपात कर रहा हूँ तो मैं एक बात यहाँ बिना कहे नहीं रह सकता कि उनके घनिष्ठ अनुयायियों में हिंसा बनाम अहिंसा के मामले में बहुत आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए थे। सरदार पटेल, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद आचार्य कृपलानी, डॉ० प्रफुल्ल घोष कायसमिति से उस समय इस्तीफा देना चाहते थे जबकि कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पास किया था कि यह उस हालत में युद्ध में योगदान करेगी यदि ब्रिटेन भारत को स्वतंत्र कर दे। उस समय उन्होंने मुझे यह लिखा था कि उनके लिए अहिंसा एक धर्म था जो भारतीय स्वतंत्रता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। पर जब भारत 1947 में स्वतंत्र हो गया तो उनमें से एक ने भी यह नहीं कहा कि भारतीय सेना तितर बितर कर देनी चाहिए। इसके विपरीत उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय सेना भी हिंदुस्तान पाकिस्तान में बांट दी जाए और भारत सत्ता के तात्कालिक नियंत्रण में रख दी जाए। स्मरण रहे कि उन दिनों के कमाण्डर इन चीफ ने जो यह प्रस्ताव किया था, उसके यह बिलकुल खिलाफ था। कमाण्डर इन चीफ ने सुझाव दिया था कि तीन मास तक यह संयुक्त सेना या एक संयुक्त ब्रह्मण हो, पर वह इस पर राजी नहीं हुए थे। यदि अहिंसा सचमुच उनका धर्म था तो वह उस सरकार में जिम्मेदारी का पद कैसे ग्रहण कर सकते थे, जो सेना पर 100 करोड़ से ऊपर खर्च करती है। सच तो यह है कि इनमें से कुछ सेना पर खर्च बढ़ाना न कि घटाना चाहते थे और इस समय यह खर्च लगभग 200 करोड़ है। कायसमिति में जवाहरलाल ही एक मात्र व्यक्ति थे जिनका मुझसे पूरा रूप से मत मिलता था। मैं समझता हूँ कि घटनाओं ने उनकी और मेरी स्थिति को ही बस पहुँचाया।”

उस समय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना आज़ाद के ये सम्मरण बहुमूल्य हैं और हम भीतरी भाँकी मिलती है।

मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का नारा— कांग्रेस तो यह सब कर रही थी। उधर मुस्लिम लीग अपनी खिचड़ी अलग पका रही थी। हम पहले ही कह चुके हैं कि कवि मुहम्मद इकबाल किस प्रकार सबइस्लामवादी हो चुके थे। पर यह परिवर्तन आकस्मिक नहीं था। 1930 में इनाहाबाद में हुई मुस्लिम लीग की बैठक में अध्यक्षीय भाषण में वह कह चुके थे “मैं चाहता हूँ कि पंजाब उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत सिंध बलूचिस्तान एक राष्ट्र में सम्मिलित हो। ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर या उसके बाहर आत्मशासन और उत्तर पश्चिम भारत का एक ठोस मुस्लिम राष्ट्र मुझे ऐसा लगता है, मुसलमानों का अंतिम भाग्य है कम से कम उत्तर पश्चिम भारत का।”

बीज तो इसके पहले से मौजूद था। 1940 की मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को अपना ध्येय करार दिया। उसे अंग्रेजी साम्राज्यवाद से लड़ना महत्वपूर्ण नहीं लगा जसा कि इन शब्दों से—“ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर या बाहर” जाहिर है।

व्यक्तिगत सत्याग्रह—अंत में कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। कहना

न होगा कि लड़ने का यह कोई बेअसर तरीका नहीं था। इस सत्याग्रह में चुने हुए कांग्रेस जन "इस लड़ाई में मदद देना हुराम है" कहकर या कहने की चेष्टा करते हुए गिरफ्तार होते थे। आंदोलन के संचालकों के अनुसार यह आंदोलन प्रतीकवादी था। नेहरू जी प्रथम वैयक्तिक सत्याग्रही होने वाले थे पर वह सत्याग्रह बिना किए गिरफ्तार हो गए और सत्याग्रह करने के पहले ही एक व्याख्यान के कारण वह जेल पहुँच गए। आचार्य विनोबा भावे प्रथम वैयक्तिक सत्याग्रही हुए।

फिर भी एकदम व्यर्थ नहीं—यह नहीं कहा जा सकता कि वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन बिल्कुल व्यर्थ था। कोई भी सग्राम एकदम व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह प्रतीकवादी ही क्यों न हो। न कुछ करने से प्रतीकवादी सग्राम ही अच्छा था। अब ऐसी हानत पहुँच गई थी कि युद्ध के विरुद्ध उठाई हुई उगली भी हितकर थी। जब वैयक्तिक सत्याग्रह के पक्षस्वरूप भारत के जगत प्रसिद्ध व्यक्ति तथा कल के प्रांतीय मंत्री और मध्य मंत्री गिरफ्तार होने लगे, तो इससे सत्कार के सामने यह बात साफ होती गई कि भारत के वास्तविक प्रतिनिधि लड़ाई के साथ नहीं हैं।

सरकार पर असर नहीं—जहाँ तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सबध है, उसने इस आन्दोलन की कुछ परवाह नहीं की। सरकारी दमन जारी रहा। 1941 में सत्याग्रही कदिया की सत्याग्रह बहुत बड़ गई। समुक्त प्रांत में सबसे अधिक लोगों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया। और प्रांतों में तो वैयक्तिक सत्याग्रह सचमुच वैयक्तिक रहा, पर समुक्त प्रांत में यह जन आंदोलन में परिणत हो गया। अब प्रांतों में जब सत्याग्रह करने पर ही गिरफ्तारी नहीं हुई, तो लागू सत्याग्रह करते करते दिल्ली की ओर चले।

रस पर आक्रमण और कम्युनिस्ट—22 जून को हिटलर ने यूरोप जीतने के बाद रस पर हमला कर दिया। स्मरण रहे कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के सब लोग जेलों में पहुँच चुके थे। देवली कैप में अनेक कम्युनिस्ट नजरबंद थे। वे अभी तक युद्ध निराशी थे। सब तो यह है कि दिसम्बर 1941 तक, जब तक कि इंग्लैंड की कम्युनिस्ट पार्टी से हिदायत नहीं आई कि अब युद्ध का समर्थन करना है क्योंकि यह 'जन युद्ध है,' तब तक वे युद्ध विरोधी ही रहे। इसके बाद वे एकाएक युद्ध के पक्षपाती हो गए। अब उनके निकट युद्ध का चरित्र बदल गया। उसके बाद के युद्धोद्योग में मदद देने लगे, और 'जन युद्ध' के सिद्धान्त का प्रचार करने लगे। रायवादी तथा एम० एन० राय तो पहले ही जन मोर्चे से अलग हो गए थे, और सरकार के साथ काम कर रहे थे। उनका कहना था कि युद्ध फासिज्म विरोधी है। इसी कारण वह कांग्रेस से निकाल भी दिए गए थे।

जापानी आक्रमण और कांग्रेस—7 दिसम्बर, 1941 को जापान भी युद्ध में बढ़ पड़ा और उसने बात की बात में अमेरिका का पल हावर ले लिया। धीरे धीरे उसने दक्षिण पूर्वी एशिया के सब देशों को भी हड़प लिया। 30 दिसम्बर 1941 को कार्यमिति ने सरकार की तरफ बहुत तपक् से हाथ बढ़ाया। इस सम्बन्ध में अपनी सच्चाई लिखाने के लिए कार्यसमिति ने भाषीजी की नेतृत्व से भुक्ति दी। जापानी आक्रमण का फायदा उठाने के बजाय कांग्रेस सरकार के साथ सहयोग करने को तैयार थी। और इस सम्बन्ध में उसकी इच्छा ऐसी ईमानदारीपूर्ण थी कि अपने नेता को भी बला करने से नहीं झिझकी।

सुभाष फरार—इस साल की घटनाओं को समाप्त करने के पहले यह बता दिया जाए कि इस साल के प्रारम्भ में 1941 की 26 जनवरी के दिन सुभाष अपने बलकत्ते के मकान से गायब पाए गए। वह कुछ दिन पहले अनशन के कारण मेडिकल

प्राउड पर रिहा हुए थे। सुभाष की इस फरारी के ऐतिहासिक परिणाम क्या हुए, इसका हम बाद का वर्णन करेंगे।

**क्रिप्स प्रस्ताव**—यूय में युद्ध की हालत बहुत जल्दी खराब होती जा रही थी। यद्यपि सरकार अब तक कांग्रेस के सब अनुरोधों का ठहराती रही थी, पर माच को रगुन जापानियों के बच्चे म चले जान से ऐसी परिस्थिति आ गई कि ब्रिटिश सरकार युद्धोद्योग में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए तैयार हो गई। तदनुसार 11 माच को क्रिप्स मिशन की घोषणा हुई और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स 23 माच 1942 को ब्रुस प्रस्ताव लेकर नयी दिल्ली आय। क्रिप्स प्रस्तावों का आशय यह था कि भारतवर्ष एक यूनिशन या संयुक्त राष्ट्र बने। प्रस्ताव में कहा गया था कि युद्ध खत्म होने के बाद ही भारतवर्ष को जिम्मेदार सरकार दी जाएगी। योजना में लोग को भी, जिसने अब तक पाकिस्तान की अपना उद्देश्य घोषित कर दिया था, खुश करने की कोशिश की गई थी। इसमें प्राप्ता तथा रियासता को यह स्वतंत्रता दी गई थी कि वे संयुक्तराष्ट्र में जब चाहें सभी शामिल हों।

गांधीजी ने इस प्रस्ताव को 'दिवालिया बक' पर बाद की तारीख लगा हुआ चक' घोषित किया। क्रिप्स प्रस्ताव के समय बयवितक मर्याद यह था। आशय की बात है कि इसी युग में कांग्रेस समाजवादी दल ने शायद कांग्रेस का अनुकरण कर अपन का युद्ध के प्रति निष्पक्ष घोषित किया था। क्रिप्स मिशन के बारे में मजिदार बात यह है कि पहले क्रिप्स कुछ देना चाहते थे पर एकाएक उनको विलायत से कोई हिदायत आ गई—शायद जीत की संभावना पक्की हो गई थी— और वह फिर बड़े पड़ गए।

**कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा स्पष्टीकरण**—क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता के कारण अब कांग्रेस के सामने इसके सिवा कोई चारा नहीं रहा कि लड़ाई छोड़े। वार्ता का मग करते हुए मौलाना अबुलकलाम आजाद ने यह साफ कह दिया कि ऐसा मालूम होता है कि सरकार भारतवर्ष की ठीक ठीक रक्षा नहीं करना चाहती, उसे बस इसी बात की फिक्र है कि साम्राज्य कायम रहे। इसी दिन सुभाष जापानी अधिभूत देशों से रेडियो पर भाषण दे रहे थे। मग यही चाहते थे कि घालेबाज अंग्रेजों को कोई मन्दन का जाम।

**फौज में भर्ती जारी**—अवश्य इसके साथ ही यह भी बता दिया जाए कि हजारों की तादाद में लोग सरकारी फौज तथा अन्य युद्ध सम्बन्धी नौकरियों में भर्ती हो रहे थे। एक दश जिसमें आधे पेट भर खाने को नहीं पाते हैं, उसमें जैसे एक तरफ साम्राज्यवादी युद्ध का विरोध अनिवार्य था उसी तरह इस प्रकार भर्ती भी अनिवार्य थी। भर्तियों की सफलता के कारण यह समझना कि जनता में ब्रिटिश विरोध कम था, गलत होगा।

**अगले सप्ताह पर गांधीजी**—गांधीजी ने 1942 की 19 जुलाई को अगले सप्ताह का खाका खींचते हुए कहा, 'इस बार मैं मागकर जेल नहीं जाने वाला हूँ। इस सप्ताह में मागकर जेल जाना नहीं है। मागकर जेल जाना बहुत ही नरम चीज होगी। अवश्य अब तक हमने माग कर जेल जाने का व्यापार कर रखा था। अब की बार मेरा डराला यह है कि चीज को जहाँ तक हो सके शीघ्र तथा छोटा किया जाए।' इसी परिस्थिति में बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ।

**अगस्त प्रस्ताव**—इसी अधिवेशन में बहुत सोच विचार के बाद अ० भा० का० कमेटी में वह प्रस्ताव पास हुआ, जो कांग्रेस के इतिहास में 'अगस्त प्रस्ताव' नाम से मशहूर हुआ। प्रस्ताव का सार यह है

"अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने रूसी और चीनी मोर्चों पर स्थिति के विगड़ने को निराशा के साथ देखा है, और वह रूसियों और चीनियों की उम बौरता की प्रशंसा करती है जो उन्होंने अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा में प्रदर्शित की है। जो लोग स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और आक्रमण के शिकार व्यक्तियों से सहानुभूति रखते हैं, उन सबका उत्तरा नित्य प्रति बढ़ता जा रहा है। यह उस नीति की जांच पड़ताल अनिवार्य कर देता है, जिसके बिना राष्ट्र गोप्य है। इस नीति का आधार स्वतन्त्रता उतना नहीं है, जितना कि साम्राज्यवादी परम्पराओं और प्रणालियों का नाश करना है। साम्राज्य की अधिकांश में रचना सामान्य मता की शक्ति बढ़ाने के बजाय एक भार और नाप बढ गया है। आधुनिक साम्राज्यवाद की मर्यादित श्रद्धाभूमि भारत इस प्रश्न की कमेटी बन गया है क्योंकि भारत की स्वतन्त्रता में ही ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों की परीक्षा होगी। इस प्रकार इस दश में ब्रिटिश शासन के अंत हान पर युद्ध का भविष्य और स्वतन्त्रता तथा लाक्षणिक की सफलता निर्भर है। आज के खतरे को देखते हुए भारत की स्वतन्त्र कर देना और ब्रिटिश आधिपत्य को समाप्त कर देने की आवश्यकता है। भविष्य के लिए किसी प्रकार की प्रतिज्ञाओं से परिस्थिति में सुधार नहीं हो सकता। इसलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी भारत में ब्रिटिश शासन का हटा लेने की मांग को दोहराती है। भारत की स्वतन्त्रता की घोषणा हो जाना पर एक अस्थायी सरकार स्थापित कर दी जाएगी, और स्वतन्त्र भारत मित्र राष्ट्रों का मित्र बन जाएगा। अस्थायी सरकार दश के मुख्य दलों और वर्गों के सहयोग से बनाई जा सकती है। अब किसी बात को आधार मानकर सत्तार की समस्याएँ सुलझाई नहीं जा सकती। कमेटी का मत है कि सत्तार की भावी शान्ति, सुरक्षा और व्यवस्थित उन्नति के लिए एक विश्व संधि बन। इस प्रकार का विश्व संधि स्थापित हो जाने पर समस्त देशों में निःशस्त्रीकरण हो सकेगा तथा सेनाओं की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ब्रिटिश सरकार की प्रतिश्रिया तथा भ्रमपूर्ण आलाचनाओं में स्पष्ट हो गया है कि भारतीय स्वतन्त्रता की मांग का भी विरोध किया जा रहा है, यद्यपि यह वर्तमान खतरे का सामना करने के लिए और अपनी रक्षा तथा इस आवश्यक घड़ी में चीन और रूस की सहायता कर सकने के लिए की गई है। चीन और रूस स्वतन्त्रता की बड़ी मूल्यवान् निधि हैं और उनकी रक्षा हमारी चाहिए। इसलिए कमेटी इस बात के लिए बड़ी उत्सुक है कि उसमें किसी प्रकार की बाधा न पड़े, और मित्र राष्ट्रों की आत्मरक्षा करने की शक्ति में कोई विघ्न न हो। कांग्रेसमिति ने ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों से ईमानदारी के साथ जो अपील की थी, उसका अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी फिर ब्रिटेन तथा मित्र राष्ट्रों से अपील करना चाहती है। भारत की स्वतन्त्रता के अविच्छेद्य अधिकार का समर्थन करने के उद्देश्य से कमेटी अहिंसात्मक प्रणाली से और अधिकांश से अधिक विस्तृत पमाने पर एक विशाल संग्राम आरम्भ करने की स्वीकृति देती है जिससे दश गत 22 वर्षों के शांतिपूर्ण संग्राम में सचित समस्त अहिंसात्मक शक्ति का प्रयोग कर सके। भारतीयों को याद रखना चाहिए कि अहिंसा इस आन्दोलन का आधार है। अतः अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यह त्रिकुल स्पष्ट कर देना चाहती है कि संग्राम के द्वारा वह कांग्रेस के लिए ही सत्ता प्राप्त करना नहीं चाहती, सत्ता पर समस्त भारतीयों का अधिकार होगा।"

करो या मरो — यह प्रस्ताव 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव के नाम से है

कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल ने इसे पेश किया और सरदार पटेल ने किया। प्रस्ताव का स्पष्टीकरण करते हुए नेहरू ने साफ साफ यह दिशानिर्देश नहीं है। यह तो एक निमन्त्रण है। इसके द्वारा हमने बताया

है। हमने सहयोग का हाथ आगे बढ़ाया है। पर इसने पीछे एक साफ इशारा भी है— कि यदि कुछ बातें नहीं हूँ तो परिणाम क्या हो सकता है। यह स्वतंत्र भारत के सहयोग का दावतनामा है। किसी दूसरी शक्त पर हमारा सहयोग प्राप्त नहीं हो सकता। उमक भलावा हमारा प्रस्ताव बमल सघष तथा लछाई का वादा करता है।”

महात्माजी ने इस अवसर पर भाषण देते हुए ‘करो या मरो’ का नारा दिया, जो चिनगारी साबित हुआ, जिससे सारे देश में तुमुल अग्निकाण्ड मच गया। सहयोग के लिए हाथ बहुत ज्यादा बढ़ाया गया था, तीन साल तक प्रतीक्षा के बाद सग्राम का नारा आया।

## 1942—1945 उथल-पुथल के वर्ग

अगस्त आति का आरम्भ—मुप्रसिद्ध अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त को रात में पास हुआ, और उसी रात अर्थात् अंग्रेजी हिसाब के अनुसार कुछ घण्टी बाद 9 अगस्त को बम्बई में एकत्रित सब नेता गिरफ्तार कर लिए गए। नेताओं की गिरफ्तारी से देश में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई। यह कोई नहीं सोचता था कि इतनी जल्दी सरकार हमला बोल देगी। सरकार ने अपने दयाल से ठीक ही किया था, पर कांग्रेस के नेता इसके लिए पूर्णतः तैयार नहीं थे। अगले दिन अर्थात् 9 तारीख को गांधीजी ने प्रत्येक प्रातः से कुछ खास कार्यक्रमों को बुलाया था जिसमें वे अपना कार्यक्रम बताने वाले थे, पर उसका मौका ही नहीं आया।

स्पष्ट कार्यक्रम नहीं—नतीजा यह हुआ कि देश को ठीक-ठीक कार्यक्रम नहीं दिया जा सका। फिर भी कुछ बातें हुआ में थी, और देश ने उन पर अमल किया। सबसे पहली बात तो कानून भंग कर जुलूस निकालना वगैरह देश के सामने था ही। इसके अतिरिक्त कुछ जिम्मेदार कांग्रेसियों ने तोड़ फोड़ के सम्बन्ध में जो हिदायतें दी थी, वे भी इस सम्बन्ध में आगे के आन्दोलन को एक दिशा देने में समर्थ हुई। यह ऐतिहासिक बात है, और इसमें इन्कार करने का कोई कारण नहीं है कि जिम्मेदार कांग्रेसियों ने तोड़ फोड़ के सम्बन्ध में हिदायतें दी थी।

आंध्र की गश्ती चिट्ठी—ऐसी हिदायतों में आंध्र की गश्ती चिट्ठी है, जिसमें कांग्रेसजनों से तार काटने की निषेधाज्ञा की गई थी। सरकार ने इस गश्ती चिट्ठी को पकड़ लिया था, और इसका हवाला देकर यह प्रमाणित करने की चेष्टा की गई कि अव्यवस्थित भीड़ नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता रेल और तार में हस्तक्षेप और तोड़ फोड़ के लिए जिम्मेदार थे। इस विषय पर सरकारी प्रस्ताव यों था—“कौन्सिल सहित गवर्नर जनरल को इस बात का पता रहा है कि कुछ दिनों से कांग्रेसजनों ने बराबर सरकारानुनी और कुछ क्षेत्रों में हिंसात्मक कारवाइयाँ की हैं। ऐसी कारवाइयों में रेल, तार, यातायात तथा समाचार के साधनों में तोड़ फाड़, हड़तालों की तैयारी, सरकारी फौजों का बरगलाना तथा युद्ध की तैयारियों में विशेषकर भरती में बाधा देना था।”

तोड़ फोड़ के लिए कौन जिम्मेदार—भारत सचिव एमरी ने नेताओं की गिरफ्तारी का समयन करते हुए एक भाषण दिया, जिसमें बताया गया कि कांग्रेस तोड़ फोड़ मूलक काम करना तय कर चुकी है।

बहुत से लोगो को तो इसी भाषण से ज्ञात हुआ कि कांग्रेस का ऐसा कार्यक्रम है। इस प्रकार से जस भी जो कार्यक्रम लोगो को मालूम हो सका उस कार्यक्रम को चलाने के लिए चेन्दा भी किया गया। कही वही पर तो प्लास वगैरह भी बाटे गए। यह कहना सत्य का अपलाप होगा कि ऐसा केवल वामपंथियों ने ही किया था उन लोगो ने किया जो राजनैतिक काम में बल प्रयोग में विश्वास रखते हैं। वामपंथियों में अधिकांश तो



पहन ही घर लिए गए थे, यदि वे बाहर हाते ता शायद तोड़ फोड़ ही करते, पर उनमें से बहुत थोड़े बाहर रह गए थे। इस आंदोलन में हिंसात्मक या बर्षित हिंसात्मक जा भी काय हुए, उनमें बड़े खूबे वामपक्षी तथा दक्षिणपक्षी सभी कांग्रेसियां न हिंसा लिया।

**जनता की श्रांतिकारी बुद्धि**—पर इस आंदोलन में सबसे अधिक भाग नेताओं का नहीं जनता का ही रहा। जनता ने सरकार की चुनौती का स्वीकार कर लिया। जनता ने इस आंदोलन के दौरान नई-नई तकनीक की सृष्टि की। वही गाली का सामना करने के लिए लोग सीना तान देते या लट जाते, तो वही पीछे हटकर फिर रात को हमला करते। बड़े बड़े श्रांतिकारी जिन कामों को करने में यह नहीं समझ पाते कि कैसे किया जाए उन सब विशेषज्ञतापूर्ण कामों को, जैसे तार काटना, इन्जन तोड़ना, धान पर कब्जा करना आदि को जनता ने अपनी बुद्धि से किया।

**जनता पर नेहरू**—जवाहरलाल ने बाद को एक व्याख्यान में कहा था 'यदि 9 अगस्त को ही सब नेता गिरफ्तार हो गए थे, फिर भी जनता ने सरकार की चुनौती स्वीकार कर ली और साहसपूर्ण तरीके से तुर्की-युर्की जवाब दिया। नेताओं का गिरफ्तारी पर क्रोध तथा आवेश में जनता ने बहादुरी के साथ बमबाजी, मशीनगन के गोले तथा लाठियां बर्दाश्त की। उनके हृदयों पर स्वतंत्रता के लिए जो अमिट प्रतीक घटक रही थी, वह साहसी तथा वीरतापूर्ण कृत्यों में प्रत्यक्षित हुई।'।

**कांग्रेस में कम्युनिस्ट**—जब फासिस्टवाद के उद्भव के कारण रूस ने संयुक्त मोर्चा का नारा दिया था, तब से कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कांग्रेस में काम करने लगे और यह मानना पड़ेगा कि उन्होंने अच्छा काम किया। सन् 34 में कम्युनिस्ट पार्टी गिरफ्तारी करार दी गई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस समाजवादी दल का अपना मंच बनाया और कई जगह तो कांग्रेस समाजवादी दल के सभी लोग भीतर भीतर कम्युनिस्ट थे। ऐसा नहीं कि यह उन्होंने छिप कर ही किया, कांग्रेस समाजवादी नेता इसको जानते थे, पर उन्होंने इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस समाजवादी दल ने इन प्रकार कम्युनिस्ट पार्टी को खुला मंच देकर उसे जीवित रखा। अस्तु, कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के अंदर काम करती रही। 1941 में जून में जब जर्मनी ने रूस पर हमला कर दिया उस समय भी वे अपने साम्राज्यवाद विरोधी रक्त पर डटे रहे। इन दिनों जेलों में वे बराबर कहते रह कि नहीं, हम अभी अपना रक्त नहीं बर्लेंगे। पर बाद को जमा कि हम इंगित कर चुके हैं जब कम्युनिस्ट इंटरनशनल से हिदायत आ गई, तभी उन्होंने 'जन युद्ध' का नारा दिया और बयान देकर जेलों से छूट। जब 1942 में कांग्रेस ने लड़ाई छेड़ दी, तो उन्होंने इसका विरोध किया।

**पूव आ डोलनों से भिन्न**—इसमें सदेह नहीं कि अधिकांश स्थानों का जनता ने हत्या तोड़ फोड़ आदि में भाग नहीं लिया, पर उन लोगों ने तो किसी काम में भी भाग नहीं लिया। इसमें सदेह नहीं कि यह आन्दोलन गुण रूप में 1921, 1930, 1931 तथा 1940 के आंदोलनों से भिन्न था। इस आंदोलन के दौरान जो वीर तथा शहीद सामने आए उनके कृत्यों में ही इस बात का अनुमादन हो सकता है।

**बलिया की घटनाएं**—जिस बलिया की बहुत रयाति हुई उसकी घटनाएं ये हैं—9 अगस्त की शाम को गांधीजी तथा अ य नेताओं की गिरफ्तारी की खबर बलिया पहुंची। 10 अगस्त को शहर में पूर्ण हड़ताल रही। 11 अगस्त को छात्रों ने एक तुलम निकालकर कातवाली की आग जाना चाहा पर सिटी मजिस्ट्रेट ने उन्हें चेतावनी दी कि वे ऐसा न करें। छात्रों ने इस चेतावनी का मानन से इकार किया, इस पर उन पर लाठी चार्ज हुआ और कई लोगों को मृत्यु चोटें आईं। उसी रात को छात्रों के घरों की

तलाशिया हुई और 40 छात्र गिरफ्तार कर लिए गए।

12 तथा 13 अगस्त को सब तार कट गए, स्टेशन जला दिए गए और सरकारी सम्पत्ति नष्ट कर दी गई। 14 अगस्त को उलिया जिला सारी दुनिया से कट चुका था। 15 अगस्त को सरकारी इमारतों पर हमले हुए, तगर पोस्ट आफिस लूट लिया गया और जिला काफ्रेस कमेट्री का नष्टनर, जिस पर 10 अगस्त से पुलिस का कब्जा था, जनता के अधिकार में आ गया। 16 अगस्त को पुलिस न शहर में मनमाने तौर पर गोलियाँ चलाई, जिसमें नौ शहीद हुए और अनेक घायल हुए। 10 अगस्त को गसडा तहमील के थाने तथा खजाने पर जनता ने हमला कर दिया। पुलिस न यहाँ फिर गोलियाँ चलाई, जिनमें बहाई कई खेत रहे। 18 अगस्त का जनता ने बामडीह तहमील के खजाने को लूट लिया तथा वहाँ के थाने में आग लगा दी। जनता ने बैरिया थान पर भी हमला कर दिया। इस पर पुलिस साढ़े चार घण्टे तक गोनियाँ चलाती रही। 19 मरे तथा कई घायल हुए।

सारे जिले पर जनता का कब्जा हो गया था।

19 अगस्त को यह प्रस्ताव पास किया गया कि बलिया शहर पर हमला किया जाय, जिला मजिस्ट्रेट का पकड़ लिया जाय, तथा जेल पर हमला करके काफ़स नेताओं को छोड़ा लिया जाय। पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने चौतू पाड़े को, जो उन दिनों जेल में बंद थे, जेल से मुक्त कर उनके हाथों में जातसमर्पण कर दिया।

डिंडोरा पीट कर अब बलिया की स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी गई और तीन दिन तक बलिया में जनता का राज्य रहा।

22 अगस्त को सेना आ गई और जनता के साथ कई बार डट कर लड़ाई करने के बाद बलिया पर फिर अधिकार कर लिया गया। 1 मितम्बर को बलिया के इंचार्ज कमर ने लाट साहब को एक तार भेजा जिसमें कहा गया कि बलिया पर फिर से अधिकार कर लिया गया है।

मेदिनीपुर की क्रांति—मेदिनीपुर में भी जनता ने पहले तो जुलूस निकाला, फिर जब उसका साथ छोड़ छोड़ हुई, तो दूसरे ढंग अखिनयार किए। सूत्ताहाट्टा थाना के इंचार्ज न जुलूस वालों से सितर बितर होने को कहा पर जनता ने उस गिरफ्तार कर लिया और पुलिसवालों को गोली न चलाने का भीका देकर उनके हथियार छीन लिए। शक्तिकारी जनता इलाके भर में फैल गई। कुछ सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई। रास्ते बन कर दिए गए, तार काट दिए गए। विद्युत बाहिनी ने सारा इत्तजाम अपने हाथों में लिया।

क्रांति का दमन—यदि हम और विवरण दें, तो वह स्वयं ही एव ग्रन्थ हो जाएगा। जो घटनाएँ बलिया तथा मेदिनीपुर में हुई, वे कुछ परिवर्तित रूप में सनारा आदि स्थानों में भी हुई। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले, बिहार बंगाल का मेदिनीपुर, असम, बम्बई शहर अहमदाबाद तथा सत्तारा इस आंदोलन में सबसे आगे रहे।

■ महीने तक के आकड़े—उस समय के सरकारी आकड़े यों हैं

पुलिस तथा फौज की गोलियों से मरे	940 व्यक्ति
पुलिस तथा फौज की गोलियों से घायल	1630 "
गोलियाँ चली	538 बार
गिरफ्तारी	60000 व्यक्ति
नजरबंद	18000 "

फौज बुलाई गई	60 बार
हवाई जहाज से बम गिराए गए	6 स्थानों में
दिसम्बर तक बरबाद स्टेशन	318
गिराई हुई गाड़ी	59
तोड़-फोड़ द्वारा रेल की क्षति	रुपए 18,00,000
मोटर कारियों की क्षति	रुपए 9,00,000
स्टेशनों की इमारतों की क्षति	रुपए 6,50,000
डाकखाने जिन पर हमले हुए	954
टेलीफोन तथा तार काटे	12000 जगह

इसके अतिरिक्त और भी हानि हुई जिसकी सही तौर पर दिखाया नहीं गया है। इन आकड़ा में बहुत कमी है। किसी भी आकड़े से परिस्थिति की भयकरता का अनुमान नहीं हो सकता। 1942 की क्रांति 1857 से वहीं अधिक व्यापक और भयकर थी। यह जन क्रांति थी।

नजरबंदी से गांधीजी का पत्र—गांधीजी नजरबंद हो गए, पर वह आगला प्रासाद के अखबारों के जरिए से देश की घटनाओं पर निगरानी रखते रहे। 14 अगस्त से ही उन्होंने लार्ड लिनलियगो से पत्र-व्यवहार शुरू कर दिया। 14 अगस्त के पत्र में उन्होंने लिखा कि भारत सरकार को कम से कम तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक मैं जन आंदोलन शुरू न करता। मैंने सावजनिक रूप से यह कहा था कि निर्दिष्ट कायपद्धति ग्रहण करने के लिए मैं आपको पत्र लिखूंगा। गांधीजी ने इस पत्र में यह साफ बताया कि उस पत्र व्यवहार से जो नये मामले निकलते, उन पर फिर पत्र व्यवहार हो सकता था। उन्होंने यह भी लिखा कि कांग्रेस ने यह आंदोलन अत्यंत मित्रतापूर्ण उद्देश्य से शुरू किया है। 23 सितम्बर को गांधीजी ने फिर लिखा कि "इसके विरुद्ध जो कुछ कहा गया है, मेरा यही कहना है कि कांग्रेस की नीति सम्पूर्ण रूप से अहिंसात्मक है। ऐसा मालूम हाता है कि सब नेताओं की गिरफ्तारी के कारण जनता को इतना रोष आया कि उसका आत्म संयम नष्ट हो गया।" सरकार ने इस पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया।

सरकार के सदेह पर गांधीजी क्षुब्ध—गांधीजी ने 1942 के अंतिम दिन वायसराय को एक पत्र लिखा कि सरकार के मन में मेरी अहिंसा पर जो सदेह है, उससे मैं बहुत क्षुब्ध हूँ। उन्होंने यह भी लिखा कि ऐसे मौके पर सत्याग्रही के लिए एक ही तरीका है, वह उपवास के द्वारा शरीर को कष्ट दे।

अनशन की घोषणा—हम इस पत्र व्यवहार के ब्योरे में जाने की आवश्यकता नहीं है। इस पत्र व्यवहार ने फलस्वरूप एक तरफ गांधीजी अपनी बात कहते रहे, दूसरी तरफ सरकार अपनी बात कहती रही, और अंत में गांधीजी ने यह लिख भेजा कि 9 फरवरी से मैं अहिंसा के सम्बंध में अपने विश्वास को प्रगट करने के लिए अनशन करूंगा। इसके उत्तर में इस बार वायसराय ने नहीं बल्कि भारत सरकार के एडीशनल सेक्रेटरी टाटेनहम ने लिखा कि भारत सरकार को बहुत अफसोस है कि आप 21 दिन का अनशन करने जा रहे हैं और भारत सरकार ने यह तय किया है कि आप अनशन के दौरान में बाहर जा सकते हैं।

बंगाल में दुर्भिक्ष—1942 के 16 अक्टूबर को बंगाल के दक्षिणी जिलों, विशेष कर मेदिनीपुर और चौबीस परगने में, इतना प्रबल सूफान आया कि हजारों लोग बेघर

बार हो गए, और खेत नष्ट हो गए। पर इसके कारण मेदिनीपुर वाला पर, 1942 के आंदोलन में भाग लेने के कारण जो भयंकर अत्याचार हो रहे थे, उनमें कोई कमी नहीं आई। इसका परिणाम यह हुआ कि वहां दुर्भिक्ष शुरू हो गया। मेदिनीपुर में तो बहुत कुछ प्राकृतिक कारणों से दुर्भिक्ष का सूत्रपात हुआ था पर 1943 में सारा बंगाल एक भयंकर दुर्भिक्ष के पंजे में फँस गया, यह प्राकृतिक कारणों में नहीं बल्कि सरकार की अव्यवस्था तथा अत्याचार के कारणों से था।

1942 का प्रतिशोध—यह कहा गया है कि बंगाल में 1913 का जो दुर्भिक्ष पड़ा, वह 1942 में बंगाल में जो प्रातिकारी काय हुआ थे उनके प्रतिशोध में डाला गया था। मनुष्यों को तालने पर प्रतीत होता है कि इसमें सत्य का एक उड़ा अंश है। कम से कम इतना तो बिल्कुल सत्य है कि सरकार की सैनिक तथा असैनिक नीति के कारण यह दुर्भिक्ष पड़ा, यदि सरकार चाहती तो इसे रोक सकती थी।

सरकार द्वारा जबरदस्ती 'डिनायल' की नीति - लड़ाई में शत्रु पक्ष के हाथ पैरों के साधन न लग जाए इस कारण युद्ध में शत्रु सेना के सामने पीछे हटते हुए जितनी भी चीजें लड़ाई के लिए उपयोगी हो सकती हैं, उनको नष्ट कर दिया जाता है। इसी को 'स्काफ़ अण्ड पालिसी' कहते हैं, याने शत्रु सेना जब आगे बढ़ती है तो उसे केवल जली मिट्टी मिलती है। 15 फरवरी, 1942 को ही सिंगापुर जापानियों के हाथों में चला गया था। और जापानी सेना तेजी के साथ भारत की ओर आगे बढ़ती चली आ रही थी। जापानी भारत के करीब आ गए थे। ब्रिटिश सरकार की सिट्टी पिट्टी गुम हो रही थी। इसी के परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार की तरफ से जली मिट्टी नीति का नारा दिया गया, याने भारतीयों से कहा गया कि तुम लोग इस बात के लिए तैयार हो जाओ कि जापानियों की आहुति पाते ही अपनी सारी सम्पत्ति को अग्नि देवता के हवाले कर दो। इस सम्बन्ध में रूस तथा अन्य देशों की बात और थी। वे समझते थे कि यह लड़ाई उनकी है, इस कारण वे बिना किसी हिचकिचाहट के जली मिट्टी की नीति का अनुसरण करते थे। परन्तु भारतीय इस युद्ध को अपना नहीं समझते थे, इसी कारण उनमें जली मिट्टी नीति का स्वागत नहीं हुआ। स्वयं महात्मा जी ने इस नीति को हिंसामूलक कह कर इसका विरोध किया। परन्तु ब्रिटिश सरकार जापानियों से इतनी डरी हुई थी कि उसने इसका नाम बदलकर 'डिनायल' की नीति कर दिया, और चूंकि जनता तैयार नहीं थी, इसलिए उसने जबरदस्ती असम तथा बंगाल के लोगों की नावें, साइकिलें आदि यातायात के सब साधन छीन लिए। उन्हें डर था कि जापानी इनका उपयोग करेंगे।

नावों के अभाव से दुर्भिक्ष—लोगों के पास नावें बिल्कुल नहीं रह गई थीं। नौकरशाही को यह समझना चाहिए था कि बंगाल में मछली पकड़ना खेती के हो बराबर महत्वपूर्ण रोजगार है, और यह काम तभी ढंग से हो सकता है जब नावें हों। इसलिए नावें छीनकर जनता से उनकी रोटी का सबसे बड़ा साधन छीन लिया गया था। पहले रोज सैकड़ों मनुष्य मछली पकड़ी जाती थी, और उससे सैकड़ों आदमी पलते थे। इसलिए इस काय के बंद हो जाने से भी दुर्भिक्ष को बल मिला।

दुर्भिक्ष के अन्य कारण—युद्ध के कारण लाखों आदमी बर्मा तथा अरakan से आकर बंगाल में इकट्ठे हो गए थे। इस प्रकार उनका बोझ भी बंगाल ही पर था। बंगाल के औद्योगिक केंद्रों में बाहर से आए लाखों आदमी बस गए थे। बर्मा से चावल आना बंद हो गया था। बंगाल में यंत्र-तंत्र बीसियों हवाई जहाजों बन जाने के कारण खेती की जमीन में कमी हो गई थी। फिर जापान से मोर्चा लेने के लिए इस समय बड़ी-बड़ी

सेनाएँ बगाल में हटी हुई थी। यह भी दुर्भिक्ष का एक कारण था। शत्रु आए तो उस घान बगैरह न मिले, इसलिए बहुत से जिला में घान तिलकुल हटा दिया गया था।

**लडाई के कारण दुर्भिक्ष**—इस प्रकार यह दुर्भिक्ष सम्पूर्ण रूप से लडाई के कारण था। मजे की बात यह है कि ऐसे समय में भी सरकार ने इस डर से कि वहाँ आगे दुर्भिक्ष की हालत और खराब न हो और फिर फौज को भूखी मरने की गीबत न आए, एक तरफ तो जल्दी जल्दी जो कुछ भी घान आदि मिला उस खरीद लिया, और दूसरी तरफ बाहर घान भेजा जाना भी जारी रखा।

**नजीमुद्दीन मन्त्रिमण्डल में दुर्भिक्ष और बड़ा**—एक समय कोई भी मन्त्रिमण्डल होता, वह शायद ही कुछ कर पाता, क्योंकि सरकार अन्य मन्त्रिमण्डल के सिर पर से सब काम कर रही थी। फिर भी यदि जनप्रिय मन्त्रिमण्डल होता, तो परिस्थिति को सम्हालता—जैसे कुछ समय बाद अन्तरबालीन सरकार ने 1946-47 के बराबर मिर पर आए दुर्भिक्ष को सम्हाल लिया। 29 मार्च 1943 का बगाल में फजलुल हक का मन्त्रिमण्डल सरकार ने निशाल बाहर किया, और इसके स्थान पर सर नजीमुद्दीन का मन्त्रिमण्डल बना। नजीमुद्दीन तिलकुल सरकारी पिटतू था। इसके अतिरिक्त इस मन्त्रिमण्डल ने इस्फहानी आदि कुछ पूँजीपतिवादी बगाल सरकार की तरफ से खाद्य द्रव्यों का एकाधिकार भी दे दिया, और इन लोगों ने दुर्भिक्ष में अपने को मालामाल कर लिया।

**लीगी मन्त्रिमण्डल ने मुसलमान मारे**—यद्यपि इस दुर्भिक्ष से मुख्यतः मुसलमान पूँजीपति ही मालामाल हुए क्योंकि मन्त्रिमण्डल ने उन्हीं को जागे बड़ाया, पर स्वयं दुर्भिक्ष में जो लोग मरे, उनमें मुसलमानों की ही ज्यादा संख्या थी। इस प्रकार लीगी मन्त्रिमण्डल की गलत नीति के कारण हिन्दुओं की तुलना में मुसलमान अधिक मरे। इसमें यह बात साफ हो जाती है कि लीगी मन्त्रिमण्डल आम मुसलमानों के लिए बाढ़ जितना भी दम भरे, पर वह वास्तव में लीगी पूँजीवाजियों तथा नवाबों की ही मरथा थी।

**सुभाष जमनी में**—हम पहले ही बता चुके हैं कि सुभाष अपने घर से गायब हो गए थे। कुछ लोगों ने कहा कि ये गायब सच्यामी हो गए हैं। बड़े बड़े लेख लिखे गए, और अन्त में यह पता लगा कि वे वास्तु में रास्ते भारतवर्ष से निरत गए थे और काबुल में कुछ दिन रहने के बाद जमनी पहुँच गए थे।

**रासबिहारी के कार्य**—इस लडाई के पहले से ही सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस के नतत्व में जापान में भारत का स्वतन्त्रता के लिए आन्दोलन करने वाला एक संस्था काम कर रही थी। इस संस्था का उद्देश्य २० पू० एशिया के भारतीयों को स्वतन्त्रता के लिए संगठित करना तथा विश्व में भी तृतीय स्वतन्त्रता के लिए लाक्षणिक उत्पन्न करना था। जिस समय 1937 में चीन पर जापान ने हमला किया था, उस समय रासबिहारी ने इस हमले का यह बहुरर समयन किया था कि चीन पर दूसरे विश्वयुद्ध का राजा है इसमें अच्छा है कि जापान का बर्खा हो जाए। जहाँ तक भारत का सम्बन्ध था वे अपने जीवन की अन्तिम घड़ी तक उनकी स्वतन्त्रता चाहते थे और वे यह समझते थे कि भौका पड़ने पर जापान भारत में स्वतन्त्रता प्राप्त करने में मदद देगा। इसी धारणा से वे बराबर काम करते रहे।

**आजाद हिन्द फौज**—पहले महायुद्ध में यह चेष्टा हुई थी कि लडाई में जा भारतीय सिपाही कर्त होकर जमनी पहुँच जाते थे, या जमनी के हाथ में पड़ जाते थे उनकी लेकर प्रथम आजाद हिन्द फौज का संगठन हुआ था। इस बार जून 1942 में जापानी मलाया पहुँच गए और बहुत से भारतीय सिपाही उनके हाथों कद हो गए, तब फिर इनको संगठित करने का प्रयत्न हुआ। मेजर फूजीवारा ने वादा किया कि भारतीयों को

स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सहायता दी जाएगी। इस पर 9 और 10 मार्च को निगापुर में मलाया के देशभक्त भारतीयों की एक सभा हुई। रासबिहारी ने इसको और मज्जित रूप देने के लिए टोकियो में मार्च के अंतिम सप्ताह में जापानी अधिकृत दशों के भारतीयों की एक सभा बुलाई। यह सभा उसी के सभापतित्व में हुई, और इंडिया इंडिपेंडेंस लीग जोरों के साथ काम करने लगी। स्मरण रहे कि यद्यपि जापानी भूमि पर तथा जापान की दक्ष रेखा में यह सभा हुई, फिर भी यह स्पष्ट कर दिया गया कि लीग का उद्देश्य भारत में स्वतंत्रता स्थापित करना है, और इस स्वतंत्रता में किसी भी विदेशी शासन का प्रभाव न रह सकेगा। सभा में यह भी घोषित कर दिया गया कि "भारतीय नायका के अधीन केवल आजाद हिंद सेना के द्वारा भारत पर सैनिक अभियान होगा। इंडिपेंडेंस लीग एक कार्य समिति बनाएगी, जिसे यह अधिकार होगा कि वह आवश्यकता के अनुसार जापान में स्थल सैनिक, जल सैनिक, तथा वायु सैनिक सहायता लें।" यह भी तय हुआ कि भारत का भावी विधान बनाने का एकमात्र अधिकार भारत के प्रतिनिधियों को ही होगा।

आजाद हिंद फौज और जापान सरकार में सनातनी—पहली आजाद हिंद फौज का संगठन कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में हुआ। कैप्टन मोहनसिंह ने इस फौज का संगठन इंडिपेंडेंस लीग की तरफ से किया। प्रारम्भ से ही लीग ने अपनी नीति स्वतंत्र रखी। जापानी नेता चाहते थे कि यह सस्था तथा इसके द्वारा संगठित फौज उनका हाथ की कठपुतली हाकर रहे, पर ऐसा नहीं हो सका। नतीजा यह हुआ कि 1942 के दिसम्बर में जापान तथा आजाद हिंद फौज के बनल एस० एन० मिल जापानियों के हाथ गिरपतार हो गए। इंडिपेंडेंस लीग ने इसका प्रतिवाद करने के लिए यह तय किया कि जब जापानियों को मनमानी हो करना है, तो वे जो चाहे सो करें, लीग की आवश्यकता नहीं है। कायसमिति ने इस्तीफा दे दिया। रासबिहारी को अभी तक जापान पर विश्वास था, इसलिए लीग की कायसमिति ने कहा कि वे खदे टोकियो जाएं, और वहां से जापान सरकार द्वारा सब बातों का स्पष्टीकरण करवाएं।

सुभाष के भाने से नया जोश—जापानियों ने भी इस बात की चेष्टा की कि लीगी नेताओं को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरा मज्जित कायम किया जाए। इस प्रकार लीग और जापानी सरकार में गड़बड़ी चलती रही। अब सुभाष के महान् व्यक्तित्व के कारण जापान अधिकृत देश के भारतीयों में एक नई उमंग पैदा हुई। 4 जुलाई को पूर्वी एशिया के भारतीयों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें सुभाष ब्राह्मण सवसम्मति से अध्यक्ष चुन गए, और आजाद हिंद फौज नए जोश के साथ बनने लगी। डाक्टर लक्ष्मीनाथन के नेतृत्व में स्त्रिया की भी आजाद हिंद फौज बन गई और इसका नाम भासी की रानी ब्रिगेड रखा गया।

सुभाष का मंत्रिमण्डल—21 अक्टूबर, 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना की गई। सुभाष ब्राह्मण इसके मन्त्रीधनायक, फौजी तथा वैदेशिक मंत्री और प्रधान मन्त्री पद पर हुए। श्री एस० ए० अय्यर प्रचार मंत्री हुए, कैप्टन डा० लक्ष्मी महिला विभाग की मंत्री हुई। लेफ्टिनेंट कर्नल श्री ए० सी० चटर्जी अर्थ मंत्री हुए, और लेफ्टिनेंट कर्नल अजीज अहमद, लेफ्टिनेंट कर्नल एन० एस० भगत कर्नल जे० भासन लेफ्टिनेंट कर्नल गुलजारा सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल एम० जेट० बियानी, लेफ्टिनेंट कर्नल ए० पी० लोकनायक, लेफ्टिनेंट कर्नल ईमान कादिर, लेफ्टिनेंट कर्नल शाहनवाज सेना के प्रतिनिधि हुए, श्री जान दमोहन सहाय विशिष्ट सेक्रेटरी हुए। श्री रासबिहारी वसु प्रधान सलाहकार हुए। इनके अतिरिक्त मन्त्री करीम गनी, देवनाथ दास, डी० एस० सा, ए०

जेलिया, जे० थिनी, और सरदार ईशर सिंह सलाहवार और श्री ए० एन० सरदार वानूनी सलाहकार हुए। जब रून जापानियों के बच्चे में आ गया तो 1944 की 7 जनवरी को आजाद हिन्द फौज का प्रधान दफ्तर उठकर रगून चला गया। इस फौज में करीब 50 हजार मैनिक थे।

**आजाद हिंद फौज पीछे हटी** — मान के मध्य भाग में यह फौज बर्मा की सीमा को पार कर भारत भूमि पर पहुँची, और पहली बार भारत की स्वतंत्र भूमि पर स्वतंत्र तिरंगा फहराया। कई कारणों से इनका आगे बढ़ना सम्भव नहीं हुआ, और इन्हें पीछे हटना पड़ा। इसके बाद जापान की हार शुरू हो गई, और बराबर आजाद हिन्द फौज को भी पीछे हटना पड़ा। 23 अप्रैल, 1945 को जापानियों को रगून छोड़कर जाना पड़ा।

**नेहरू तथ्यों से प्रभावित** — जिन दिनों आजाद हिंद फौज के सम्बन्ध में कुछ बातें नहीं थी, उन दिनों यह समझा जाता था कि आजाद हिंद फौज जापानियों के हाथ की कठपुतली है। इसी धारणा के वसवर्ती होकर जवाहरलाल ने 1944 में छूटने के बाद भी यह कहा था कि यदि आजाद हिंद फौज भारत में आए तो मैं उसने विशुद्ध लड़न वाला प्रथम व्यक्ति होऊंगा। पर जब उन्हें यह बात हो गया कि उन्होंने जो समझा था वह गलत है, तो उन्होंने आजाद हिंद फौज को बढ़ाया, 'जय हिंद' को भारत के घर पर में पहुँचा दिया और फौज के बंदियों का छुड़ाने में कोई बसर नहीं रखी। यह उनके मन दिमाग का घातक तो है ही, साथ ही आजाद हिंद फौज के लिए बहुत प्रशंसा की बात है।

**कम्युनिस्ट तथ्य से दूर** — भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने आजाद हिन्द फौज को 'पाँचवाँ दस्ता' यानी जासूस घोषित किया और अपने अखबारों में सुभाष को टोका का कुत्ता बनाकर कार्टून निकाला।

**नई फार्मिडारा** — आजाद हिंद फौज केवल भारतीय स्वतंत्रता की एक गौरवमय चेष्टा ही नहीं थी बल्कि इसने बाद की भारतीय राजनीति पर कुछ बहुत गहरे प्रभाव भी डाले। इसने भारत में एक नवीन प्रातिहारि धारा को जन्म दिया। जनता में आजाद हिंद फौज की प्रशंसा के कारण ब्रिटिश भारतीय फौज में जिन भयंकर विस्फोटों का सूत्रपात हुआ, और बराबर होता रहा, उनके कारण ब्रिटिश साम्राज्यवाद का भारत से पैर उखड़ने में बहुत सहायता मिली। सरकार को फौज में विश्वास नहीं रहा, इसी कारण उसे बाद की अपने आप भारत छोड़ने की एक तारीख तय करनी पड़ी। आजाद हिंद फौज ने साम्प्रदायिक एकता का महान आदेश उपस्थित किया।

**एटलांटिक अधिकार पत्र** — 1943 के अंत तक यह लगने लगा था कि महायुद्ध में विजय अंग्रेजों की ही रहनी। इटली में सेनापतियों ने विद्रोह कर दिया और इटली ने आत्ममर्दण कर दिया। जर्मनी का भी दम फूलने लगा था परंतु जापान मजबूत था। इसी सत्र एटलांटिक महासागर में एक स्थान पर मिलकर चर्चिल और रूजवेल्ट ने एक अधिकार पत्र बनाया जिसमें परतंत्र जातियों के लिए स्वतंत्रता का वादा किया गया था। इस अधिकार पत्र के कारण परतंत्र जातियों, विशेषकर भारतीयों में खुशी की लहर दौड़ गई, पर चर्चिल ने जल्द ही ब्रिटिश समक्ष स्पष्ट कर दिया कि भारतीयों पर यह अधिकार पत्र लागू नहीं होता, यह केवल उन जातियों पर लागू होता है जो युद्ध के दौरान पराधीन हो चुकी हैं। कहना न होगा कि इनसे भारतीयों की विशेष ठेस नहीं लगी क्योंकि वे जानते थे कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के इरादे काले हैं। बाद की पता लगा कि एटलांटिक अधिकार पत्र नामक कोई योजना थी ही नहीं। यह महज एक गप्प थी

या कह लीजिए लड़ाई जीतने का कौशल था।

भारतीयों की तरफ से बराबर यह भाग हो रही थी कि कांग्रेसी नेता छोड़े जाए, परन्तु भारत सचिव एमरी की तरफ से यह घोषणा होती रही कि जब तक अगस्त प्रस्ताव वापिस नहीं लिया जाता, तब तक उनके छूटने का कोई प्रश्न नहीं उठता। गीताजी याद हुआ कि दोनों पक्ष जहाँ के तहाँ रहे, और ज़िज बनी रही।

**रस्तूरवा का देहात**—22 फरवरी 1944 का महात्मा गांधीजी सुयाग्य सह-धर्मिणी राष्ट्रमाता कस्तूरबा गांधी का देहात हो गया। सरकार उन्हें छोड़ने के लिए तयार थी, परन्तु उन्होंने पति के पास रहकर मरना ही श्रेयस्कर समझा।

**गांधी बवेल पत्र व्यवहार**—इसके बाद गांधीजी और लाड बवेल में कुछ पत्र व्यवहार हुए, जिनमें राजनैतिक विषयों पर भी आलोचना हुई। इस आलोचना के फलस्वरूप ऐसा लगा कि वातावरण कुछ सुधर रहा है। दोनों तरफ से कुछ ऐसी बातचीत हुई जिसमें यह मालूम पड़ा कि समझौते की गुंजाइश है। गांधीजी ने 9 अप्रैल, 1944 के पत्र में लाड बवेल का लिखा “आपके पत्र का मन्तव्य यह है कि कांग्रेस शासन में सहयोग रहे, और यदि ऐसा न कर सके तो भविष्य के लिए योजना बनाने में हाथ बटावे। मेरी राय में इसके लिए यह जरूरी है कि दोनों दलों में समता और पारस्परिक विश्वास हो। पर यहाँ तो समता का अभाव है और पग पग पर हम यह दखते हैं कि सरकार कांग्रेस पर अविश्वास रखती है। इस सबके माथ इस तथ्य को भी जोड़ लीजिए कि कांग्रेसजनों में यह विश्वास नहीं है कि ब्रिटिश सरकार भारत की गलती को मोचने में समर्थ है। विश्वास का यह अभाव भारत में बहुत मानो तब ब्रिटेन का जो रबैया देखा उसी के कारण उत्पन्न हुआ है। क्या इस बात के लिए समय नहीं आ गया ‘क आप भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के जरिए भारत की जनता से बातचीत करें, न कि उनसे जो ही सहयोग करेंगे। यही बातें अगस्त प्रस्ताव में अतिनिहित थी।

‘उन प्रस्ताव में जो भाग की गई थी, उसकी पृष्ठभूमि में हिंसा नहीं बल्कि आत्म-बलिदान था। जिस किसी ने भी, चाहे वह कांग्रेसजन हो या और कोई, आचरण में इन नियमों के विरुद्ध कार्य किया, उसे अपने कार्य के लिए कांग्रेस के नाम के इस्तेमाल का अधिकार नहीं था। पर मैं देख रहा हूँ कि जैसे लाड सिलिलियंगो अगस्त प्रस्ताव से बोलते थे वैसे ही आप इस प्रस्ताव से शकित हैं। मैंने इस सम्बन्ध में अपना मत परिश्रित नहीं किया है। आप जो यह कहते हैं कि अगस्त प्रस्ताव का असर यह हुआ कि मुद्रोद्योग में बाधा पहुँची, सो मैं इसे समझने में असमर्थ हूँ। कांग्रेसजनों का एकाएक गिरफ्तार करने के फलस्वरूप जो परिस्थिति उत्पन्न हुई, उसकी जिम्मेदारी संपूर्ण रूप से सरकार पर है। आपका इस सम्बन्ध में यह कहना है कि आपको भारत की रक्षा कर सकने में हमारी मामूली पर अविश्वास था और इसलिए आपने हमारी इस कथित सामरिक दुर्गति से फायदा उठाना चाहा।’

**गांधीजी मुक्त तोड़-फोड़ की निंदा**—इस प्रकार गांधीजी और लाड बवेल में पत्र-व्यवहार हो रहा था कि इसी बीच गांधीजी बीमार हो गए, जिसमें फलस्वरूप सरकार ने उन्हें 6 मई को रिहा कर दिया। इसके पहले श्रीमती सरोजिनी नायडू भी छुट चुकी थी। गांधीजी ने छूटने के बाद कड़े शब्दों में 1942 की श्रांति की निंदा की। इसमें पहले श्रीमती सरोजिनी नायडू ने यह बयान दिया था कि “कांग्रेस ने कोई आंदोलन शुरू नहीं किया, आंदोलन इस कारण शुरू हुआ कि लोग लश् में आ गए थे। कांग्रेस किसी ऐसे कार्य का समर्थन नहीं करती, जो अहिंसा के विरुद्ध पड़ता है।”

गांधीजी ने भी छिपकर काम करने की निंदा की। उन्होंने पंचगनी से 28



जुलाई को एक वयान देते हुए कहा कि "अक्सर लोग मुझमें पूछा करते हैं कि मैं छिपकर काम करने का समर्थन करता हूँ या नहीं। इनमें तोड़ फोड़ तथा गैर कानूनी साहित्य का प्रकाशन भी है। मुझे बताया गया है कि कुछ कायकर्ताओं के फरार हुए बिना कुछ किया ही नहीं जा सकता था। कुछ लोगों ने यह भी मुझसे कहा है कि इस प्रकार सम्पत्ति नाश को, जिसमें यातायात तथा समाचारों के आदान प्रदान के साधनों का विनाश भी है, अहिंसा में समझा जाना चाहिए बशर्तें इसमें किसी का खून न हो। मुझे यह भी बताया गया है कि दूसरी जातियों ने बल्कि इससे कहीं ज्यादा ऐसा किया है। मेरा कहना है कि जहाँ तक मुझे मालूम है, किसी जाति ने सचेत रूप से स्वाधीनता प्राप्ति के साधन के रूप में सत्य और अहिंसा का उपयोग नहीं किया है। उस मानदण्ड से नापकर मैं बिना किसी हिचकिचाहट के यह कहता हूँ कि अहिंसा में ऐसे कार्यों का स्थान नहीं होना चाहिए। तोड़ फोड़ और सम्पत्ति का विनाश हिंसा ही है तथापि यह दिखलाया जा सकता है कि इन कार्यों से जनता में कुछ जोश फैला—पर मुझे इसमें सन्देह नहीं कि ऐसे कार्यों से कुछ मिलकर आन्दोलन को नुकसान ही हुआ।"

**नौकरशाही पर अच्छा असर—**स्मरण रहे कि अभी तक महायुद्ध चल रहा था, इसलिए गांधीजी के इन वयानों का नतीजा नौकरशाही पर अच्छा ही हुआ होगा, और उस बहुत कुछ अभ्यासन ही मिला होगा। फिर भी सरकार ने कोई बिगड़ इस नहीं लिया। सरकार आदालत को दवा चुकी थी, अब उसे बाहे की परवाह थी?

**नजरबंदी से ही लोग से समझौते की चेष्टा—**गांधीजी बैठे रहने वाले व्यक्ति नहीं थे। ज्यों ही वे कुछ अच्छे हुए, उन्होंने चेष्टा की कि मुस्लिम लीग से समझौता हो जाए। 1943 की मई में ही, जब वे नजरबंद थे, उन्होंने अखबारों में पढ़ा था कि जिन्ना ने कहा है कि यदि गांधीजी हिंदू मुस्लिम समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वह मुझसे पत्र-व्यवहार करें। इस पर अमल करते हुए गांधीजी ने 1943 की 4 मई को जिन्ना को एक पत्र लिखा, जिसमें उनसे यह कहा कि क्यों न मैं और आप मिलकर इस समस्या का ऐसा समाधान निकालें जो सबका भाग्य हो। गांधीजी ने यह पत्र नजरबंदी की हालत में लिखा था, इसलिए यह पत्र केवल सरकार के ही जरिए जा सकता था। भारत सरकार ने इस पत्र को जिन्ना के पास भेजने से इन्कार कर एक विज्ञप्ति प्रकाशित की। जिन्ना को भी यह समाचार दे दिया गया कि ऐसा एक पत्र रोक लिया गया है। छोटी सी बात होते हुए भी इस सम्बन्ध में यह बता दिया जाए कि जिन्ना ने इससे पहले यह भी डींग मारी थी कि उनके नाम भेजा हुआ पत्र रुक नहीं सकता। पर जब इस प्रकार एक असत्य निर्दोष पत्र रुक गया, तो वह चुप्पी साध गए। जिन्ना की नीति में सरकार से मुद्द करना था ही नहीं।

**वार्ता का परिणाम नहीं—**अब जब गांधीजी छूटे, तो उन्होंने उसी वार्ता के सूत्र को फिर से उठा लिया। गांधीजी कई रोज जा-जाकर जिन्ना के घर पर मिलते रहे और घण्टा उनसे बातचीत की पर नतीजा कुछ नहीं निकला, क्योंकि जिन्ना अपनी पाकिस्तान की मांग पर डटे रहे। बल्कि पहले से बड़वापन और अविश्न बढ़ा। स्थिति यह है कि गांधीजी ने जिस प्रकार यह बातचीत चलाई, उससे जिन्ना की साख पहले से अधिक बढ़ी।

**कस्तूरबा ट्रस्ट—**गांधीजी के छूटते ही कुछ लोगो ने यह विचार व्यक्त किया कि उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी के नाम पर एक ट्रस्ट कायम किया जाए जिसका उद्देश्य स्त्रियों की उन्नति करना हो। बात की बात में सवा करोड़ रुपये जमा हो गए। महात्मा जी ने एक ट्रस्टी मण्डल बनाकर सारा धन उसके हाथ में दे दिया। इस कोष की तरफ से देश में चारों तरफ स्त्रियों की उन्नति के लिए सस्थाएँ खोली गईं। इस ट्रस्ट की देख रेख में स्त्रियों में नाय की जो योजना बनी, उसका आधार ग्रामीणों का स्वालम्बन है।

## महायुद्ध का अन्त और स्वराज्य

जमनी की हार—1945 के घुस् में अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति साफ होने लगी। हम ने हिटलरी सेना को एडेडते एडेडत जमनी तक पहुँचा दिया। इधर जब चर्चिल ने देखा कि हम आगे बढ़ता चला जा रहा है, और वह जहाँ जहाँ बढ़ रहा है वहाँ वहाँ समाजवाद को स्थापना हो रही है, तो जल्दी से दूसरा मोर्चा कायम कर दिया। इस प्रकार हम भगड़े का सूत्रपात हुआ जो अब तक चालू है—सत्तार दो भागों में बंट गया।

शिमला काफ़ेस—जून 1945 में कायममिति के याकी सदस्य भी छोड़ दिए गए। इसके बाद ही कांग्रेस और सरकार में बातचीत चली, जो शिमला काफ़ेस के नाम से मशहूर है। इस काफ़ेस में जो बातचीत होने वाली थी उसके सम्बन्ध में लाड वैवेल ने कहा कि किसी एक सम्प्रदाय के विरोध से अधिवेशन भग नहीं किया जाएगा। परन्तु जिला माहुर ने जिद पकड़ी कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि है और उन्होंने कांग्रेस द्वारा किसी मुसलमान के भेजे जाने का विरोध किया। जिला इम जित पर डटे रहे और शिमला काफ़ेस रातम हो गई। लाड वैवेल ने गांधी जी के तरीके पर इन काफ़ेस की अमफलता का बोझ अपने ऊपर ले लिया। परिणाम यह हुआ कि जित जया की त्या कायम रही। जिना के कारण सरकार को फिर एक बार यह कहना पड़ा कि आपसी भगड़ा के कारण वह अधिकार नहीं दे सकती, वरना वह तो तैयार थी।

चुनाव की तैयारी महायुद्ध के बाद इंग्लैंड में श्रमिक सरकार बनने पर बड़े साटने एलान किया कि धारासभाया के जिस चुनाव को लडाई के कारण स्थगित रखा गया था, वह अब कराया जाएगा। जिस लहजे में चुनाव का एलान किया गया उससे यह भी कुछ भनक आई कि चुनाव के नतीजे को देखकर सरकार अपने कतन्य का निणय करेगी। कांग्रेस तथा लीग ने चुनाव की जोरदार तैयारी शुरू की।

आजाद हिंद फौज की प्रतिभिया —इही दिनों आजाद हिंद फौज की घटनाएँ विश्वस्त रूप से मालूम होने लगी और फौज के प्रमुख नेता शाहनवाज, सहगल तथा डिलन पर लाल किले में मुकद्दमा चलने को हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन बहानों के विषय को उठा लिया, और इतने जोर का आंदोलन किया कि एक बार भारत भर में जयहिन्द और आजाद हिंद फौज के अलावा और कुछ सुनाई नहीं दता था। प्रत्येक चुनाव सभा में आजाद हिंद फौज का उल्लेख किया जाने लगा, और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी गई, मानो आजाद हिंद फौज की रिहाई और चुनाव दोनों एक ही बात हैं। दश में बहुत ज्यादा जोश फैला, यहाँ तक कि यह जोश सेना में भी व्याप्त हो गया। मना कि जोश का कारण सरकार को आज्ञा हिंद फौज के इन तीन अफसरों को रिहा कर देना पड़ा, और शेष के साथ नरमी का व्यवहार करना पड़ा। सरकार ने खुली अदालत

मे आजाद हिंद फौजियों पर मुकदमा इस कारण चलाया कि लोगों को नसोहत दी जाए पर जन आंदोलन के कारण सरकार को लेने के देने पड़ गए। जब फौज पर भरोसा नहीं रहा, तब एक तरह से यही से साम्राज्यवाद का बिस्तर गोल होने लगा।

**श्रमिक सरकार का आगमन**—1945 की जुलाई में ब्रिटेन में चुनाव हुआ। श्रमिक दल नहीं चाहता था कि फौरन चुनाव हो, पर प्रतिक्रिया की प्रतिभूति मदमाते चर्चिन ने सोचा कि जमनी पर हमारे ही नेतृत्व में विजय प्राप्त हुई है, इस कारण चुनाव में भी विजय हमारी ही रहेगी। उन्होंने जल्दी से चुनाव करवा दिया, और चुनाव के लिए समाजवाद बनाम पूंजीवाद को विषय बनाकर समाजवाद के विरुद्ध प्रचार किया। वह स्वयं तो चुने गए पर उनकी पार्टी हार गई। मिस्टर ऐटली के नेतृत्व में श्रमिक सरकार की स्थापना हुई।

**जापान भी पराजित**—जब तक सोवियत रूस ने जापान के विरुद्ध युद्ध घोषणा नहीं की थी, पर 1945 के 8 अगस्त को उसने भी जापान के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया और लाल सेना को मंचूरिया के अंदर भेज दिया। यद्यपि इसमें और अणु बम के इस्तेमाल में कोई सम्बन्ध नहीं था, पर इसी दिन अमेरिका ने हिरोशिमा पर अणु बम डाल दिया और यह नगर बिल्कुल ध्वस्त हो गया। इस घटना के तुरन्त बाद नागासाकी पर भी अणु बम डाल दिया गया। यह शहर भी बात की बात में नष्ट हो गया। इस पर जापान ने हथियार डाल दिए और 2 सितम्बर को हार मानते हुए संधि पर दस्तखत कर दिए। इस प्रकार द्वितीय महायुद्ध अंतिम रूप से समाप्त हो गया।

**आम चुनाव**—1945 के अंत में सब धारासभाओं का चुनाव हुआ। इन चुनावों में हिन्दू सीटों से कांग्रेस तथा मुस्लिम सीटों से मुस्लिम लीग विजयी हुई। दोनों के मुकाबले में खड़ी शेष सभी संस्थाएँ बिल्कुल हार गईं। कम्युनिस्ट पार्टी ने भी कुछ उम्मीदवार खड़े किए थे, पर एकाध के अलावा वे भी सभी क्षेत्रों में हार गए।

**1942 पर कांग्रेस**—इन तिनो आजाद हिंद फौज के वीरों की बहुत जबरन आवभगत तथा प्रशंसा हो रही थी। साथ ही 1942 के शहीदों तथा वीरों की भी प्रशंसा हो रही थी। दिसम्बर में कायसमिति ने अहिंसा पर फिर से प्रस्ताव पास किया और यह बतला दिया कि 1942 के तथा आजाद हिंद फौज के वीरों की प्रशंसा करते हुए भी अहिंसा की नीति पहले की तरह कायम है। कलकत्ते में कायसमिति ने अपनी बैठक में यह प्रस्ताव पास किया “1942 के अगस्त में मुख्य कांग्रेसियों की गिरफ्तारी के बाद नेतृत्वहीन जनता ने धागडोर अपने हाथों में ले ली और स्वतः स्फूर्त रूप से काम किया। यदि जनता को बहुत सी वीरता तथा कुर्बानी के कार्यों के लिए श्रेय प्राप्त है तो दूसरी तरफ उमने ऐसा भी काय किए जो अहिंसा के अन्तर नहीं आ सकते। इसलिए कायसमिति के लिए यह जरूरी हो गया है कि मक्के पथ प्रश्नन के लिए वह यह साफ कर दे कि अहिंसा के अंदर सावजनिक सम्पत्ति को जलाना, तारों का काटना, गाड़ियों को पटरी से उतारना तथा आतंक फैलाना नहीं आने। कायसमिति का यह निश्चिन्त मत है कि 1920 की कांग्रेस में अहिंसा सम्बन्धी जो प्रस्ताव पास हुआ था, और जिसकी समय समय पर व्याख्या होती रही और जिसके अनुसार इन वर्षों में काय हुआ था उसी के कारण भारत का सिर ऊंचा हुआ है।”

**आजाद हिंद फौज पर कांग्रेस**—कायसमिति ने आजाद हिंद फौज के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव पास किया “कांग्रेस इस पर गव करते हुए भी कि विदेशों में अभूतपूर्व परिस्थितियों में श्री मुभाषचंद्र बोस ने जिस आजाद हिंद फौज का संगठन किया, उसके लोगों ने कुर्बानी, अनुशासन, देशभक्ति, बहादुरी तथा अपनी सद्भावनाओं का प्रदर्शन किया,

तथा यह मानने हुए भी कि कांग्रेस के लिए यह उचित तथा ठीक है, जिन फौजियों पर मुकामा चल रहा है, उनकी पैरवी की जाए, और इस फौज के ऐसे लोगों को जिनको मर्ग की जरूरत है मदद की जाए। कांग्रेसियों को यह नहीं भूलना चाहिए कि इन लोगों की पैरवी करने तथा इन लोगों को मदद देने का यह अर्थ नहीं है कि कांग्रेस किसी तरह स्वराज्य प्राप्त करने की अपनी अहिंसा सम्बन्धी नीति से विचलित हो गई है। इस प्रकार कांग्रेस ने 1942 तथा आजाद हिंद फौज के सम्बन्ध में अपने वक्तव्य को स्पष्ट कर दिया। यह वही पुरानी नीति थी।

**‘एक दल, एक नेता’ का नारा**—जब से कांग्रेस के नेता छूटे, कुछ विशिष्ट नेता जिन सुपुत्र प्रान्त में कृष्णदत्त पालीवास तथा बम्बई में पाटिल, शंकरराव देव, महात्मा कि नरहर पटेल ने भी ‘एक दल, एक नेता’ का नारा दिया। 1942 तथा उसके बाद कम्युनिस्टों ने जो रवैया अखिनयार किया था, उससे कांग्रेस के अंदर इस नारे का उठना सामाजिक हो गया था। पर साथ ही साथ कुछ लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे केवल कम्युनिस्ट पार्टी ही नहीं बल्कि किसी भी पार्टी को कांग्रेस में रहने देना नहीं चाहते। इस पर बहुत जोर की बहस छिड़ी। दोनों तरफ से तर्क लिए गए। इसी समय कम्युनिस्ट शासन से निकाल तो दिए ही गए, पर साथ ही कांग्रेस के विधान को इस तरीके से शान्ति से वापस ले लिया कि जिससे उसमें कोई अड़तल न रह सके। बाद को कांग्रेस ने एक विधान समिति बनाकर यह टेढ़ा प्रश्न उसके सुपुट कर दिया।

**नवम्बर प्रदर्शन के कारण अहिंसा सम्बन्धी प्रस्ताव**—कांग्रेस ने अहिंसा का जो शब्द लिया उसकी विशेषकर इसलिये जरूरत पड़ी थी कि नवम्बर में कलकत्ते में छात्रों का एक प्रदर्शन हुआ था जिसने बिलकुल नातिवारी ढंग अखितयार करके एक बार फिर 1942 के दृश्य दिखला दिए थे। इस अवसर पर छात्रों पर गोली चली, पर वे पीछे नहीं हटे। फलतः छात्रों ने बहुत सी सैनिक लाशों को जला दिया, और तोड़ फोड़ के ब्रह्म काय किए। इस प्रदर्शन से सरकार बिलकुल विकर्तव्यविमूढ़ हो गई।

**फरवरी का नौसैनिक विद्रोह**—फरवरी 1946 में बम्बई में भारतीय नौसेना के नौजवानों ने एकाएक विद्रोह कर लिया। तलवार नामक एक जहाज में नौसेना को शिशा दी जानी थी। इसी जहाज से विद्रोह फैला। 11 फरवरी को गौर अफसर कमांडर किंग ने नौबिद्या शिष्याओं को ‘कुत्ते का बच्चा’ तथा ‘कुली का बच्चा’ कहकर गालियां दीं। उसी गालियां तो हमेशा से दी जाती थी, और भारतीय नौसैनिक उस बर्दाश भी कर लते थे, पर आजाद हिंद फौज का प्रभाव बढ़ने के कारण लोगों में ज्यादा बोल था। इस कारण इस पर लोग बहुत नाराज हुए। जिन लोगों को गाली दी गई थी उन्होंने अर्जी वर्ग रह भेजी, पर इसका कोई असर नहीं हुआ। 18 फरवरी को उन्हें बहुत रद्दी नाश्ता मिला, इस पर ‘तलवार’ के ग्यारह सौ नौसैनिकों ने हड़ताल कर दी। इस पर कमांडर किंग ने उन्हें धमकाया, पर इसका कोई असर नहीं हुआ। दोपहर के बाद नौसैनिकों ने एक सभा की, जिसमें उन्होंने अपनी मांग तय की। इन मांगों में उनकी निम्नी मांगें—अच्छा खाना, कमांडर किंग के विरुद्ध वायवाही गोरे और भारतीय सैनिकों की बराबर तनकाह आदि मांगें तो रखी ही, साथ ही सब राजनतिक कैदियां तथा आजाद हिंद फौजियों की रिहाई की मांग की और कहा कि सारी भारतीय फौज हिंसा से वापिस बुलाई जाए। इस प्रकार उन्होंने अपनी राजनतिक बुद्धि का परिचय दिया। 19 फरवरी तक सारी भारतीय नौसेना में हड़ताल फैल गई। 20 हजार नौसैनिक तथा 20 बड़े जहाज और 100 के करीब छोटे जहाजों के लोग हड़ताल में शामिल हो गए। कई जगह जहाजों पर तिरंगा, लोगी हरा तथा लाल झण्डे लगा दिए गए और

जहाजों पर विद्रोहियों का अधिकार हो गया।

कराची से सिंगापुर तक भारतीय नौसैनिकों में यह हड़ताल फैल गई। एक दिन बाद हड़तालियों ने बम्बई की सड़कों पर क्रांतिकारी नारों के साथ जुलूस निकाला। एडमिरल राने विद्रोहियों से बातचीत करने आए और मार्गें भी लिख ले गए पर उन्होंने जाते ही 309 नौसैनिकों को गिरफ्तार कर लिया। 21 तथा 22 फरवरी का स्थिति भयानक हो गई और सशस्त्र युद्ध की नौबत आ गई। कराची में भी सशस्त्र युद्ध हुआ। गोरो ने नौसैनिकों को गोलियों से भून दिया। फिर भी हड़ताल चलती रही। अन्त में सरदार पटेल ने स्वयं आकर आत्मसमर्पण कर देने को कहा, तभी विद्रोह शान्त हुआ। सरदार ने आश्वासन दिया कि विद्रोहियों को कोई सजा नहीं दी जाएगी, पर बाद को बहुत से विद्रोही नौसैनिकों को बहुत कड़ी सजाए दी गई और हजारों निकाल भी दिए गए।

**फरवरी प्रदर्शन**—फरवरी में आजाद हिंद फौज के रशीद की सजा का विरुद्ध बम्बई, कलकत्ता तथा अन्य स्थानों में प्रदर्शन हुआ। सारिया आदि जलाई गई जिसने फिर एक बार कलकत्ता में नवम्बर प्रदर्शन की बात ताजी हो गई। इस अवसर पर सींग तथा कांग्रेस की जो एकता देखने में आई, वह अभूतपूर्व थी। लगा कि देश की परिस्थिति बहुत ही क्रांतिकारी है, लोग जैसी प्रतिक्रियावादी सस्था को भी क्रांति का साथ देना पड़ा। सरकार के लिए सबसे खतरनाक बात यह थी कि भारतीय सेना में भी अशान्ति फैल गई थी और सेना राजनैतिक नारे देने लगी थी। 18 फरवरी को नौसैनिक विद्रोह शुरू हुआ और 19 को ऐटली की तरफ से घोषणा हुई कि कैबिनेट मिशन भारत जा रहा है।

**संसदीय मिशन तथा कैबिनेट मिशन**—शिमला काफ़ेस में तो सरकार नहीं झकी थी, पर अब परिस्थिति को सम्हालने के उद्देश्य से एक के बाद एक संसदीय मिशन तथा कैबिनेट मिशन भारतवर्ष में आए और समझौते की वार्ता चलाई। संसदीय मिशन जे जमीन की जांच कर गई, और फिर कैबिनेट मिशन प्रस्ताव लेकर मई 1946 में आया। मिशन के नेता के रूप में सर स्टैफ़ोर्ड क्रिप्स आए थे। भारतीय नेताओं के सामने इस मिशन ने जो प्रस्ताव रखा, उसका सार यह था—(1) भारतवर्ष की एक यूनियन बने, जिसमें ब्रिटिश भारत तथा रियासतें हो, यूनियन के हाथों में बदेशिक विभाग, आरम्भ, परिवहन और समाचार आदान प्रदान के कार्य हो और इसे यह अधिकार हो कि इन कार्यों के लिए धन को उगाह सके। (2) यूनियन की एक धारासभा तथा कार्याकारी विभाग हो, जो ब्रिटिश भारत तथा रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा बने हों। किसी विषय में यदि कोई बड़ा साम्प्रदायिक मामला धारासभा में उठे तो उसके फलते फलने के लिए उपस्थित प्रतिनिधियों की बहुमत्या तथा दो बड़े सम्प्रदायों की मत की जरूरत होगी। (3) यूनियन के विषयों के अतिरिक्त सारे विषय प्रांता के हाथों में रहेंगे। (4) यूनियन को जो शक्तियाँ दी जाएं उनके अतिरिक्त बाकी सभी शक्तियाँ रियासतों के हाथों में होंगी। (5) प्रांत इस बात के लिए स्वतंत्र होंगे कि वे धारासभाओं तथा कार्याकारी विभाग के साथ ग्रुप बनाएं, और प्रत्येक ग्रुप को इस बात का अधिकार होगा कि वह एक साथ जिन प्रांतीय विषयों को चाहे ले सके। (6) यूनियन तथा यूपी के विधान में ऐसी व्यवस्था हो कि वे धारासभा की बहुमत्या से शुरू में हर दस साल बाद विधान के पुनर्विवेचन की मांग रखें।

इही सूत्री के इंदु गिर्द नेताओं तथा मिशन में बातचीत हुई।

**कायसमिति का प्रस्ताव**—24 मई को कांग्रेस कायसमिति ने एक बहुत लम्बा प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि मिशन ने जो चित्र पेश किया है और जिस पर उन्होंने अन्तर्कालीन सरकार में भाग लेने के लिए कहा है, वह स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस

कायसमिति का उद्देश्य तथा लक्ष्य यह है कि भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त की जाय, सीमित अधिकार होने पर भी केन्द्र में शक्तिशाली सरकार स्थापित की जाय, प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दी जाय, केन्द्र तथा देश के अन्य भागों में लोकतांत्रिक व्यवस्था हो। प्रत्येक व्यक्ति को सुविधा देने तथा उसका विकास करने के लिए उसके मौलिक अधिकार स्वीकार किए जाएं तथा प्रत्येक सम्प्रदाय को बहत्तर ढाँचे के अंदर रहकर अपनी इच्छा नुसार जीवन चलाने के लिए बराबर सुविधा दी जाय। कार्यसमिति को दुख है कि लक्ष्य के साथ ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों का सामंजस्य नहीं है।

कायसमिति ने कहा कि यदि सरकार सचमुच अंतर्कालीन सरकार को स्वराज्य की पहली सीढ़ी बनाना चाहती, तो उसके प्रस्ताव कुछ और ही होते। कायसमिति ने यह भी कहा कि संविधान सम्मेलन ही भारतवर्ष के विधान का निर्माण कर सकता है और सरकार यदि ईमानदार है, तो उसे अंतर्कालीन सरकार को पूरी जिम्मेदारी देनी चाहिए।

बातचीत भंग - इसके बाद बड़े लाट लाड वेल काग्रेस तथा लोग से इस विषय पर बात करने लगे कि वे अंतर्कालीन सरकार में सहयोग करें और इस बीच संविधान सम्मेलन का चुनाव आदि हो जो अंतिम विधान का निर्माण करे। बड़े लाट ने चेष्टा की कि कांग्रेस और लोग अंतर्कालीन सरकार में बराबर सीटें लें, पर इस पर कांग्रेस राजी नही हो सकी और बातचीत भंग हो गई। फिर भी अनौपचारिक बातचीत चलती रही और नए नए प्रस्ताव किए जाते रहे।

26 जून को कांग्रेस कायसमिति ने अपने प्रस्ताव में कहा कि प्रस्तावित अन्तर्कालीन सरकार के हाथों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वह स्वतंत्र राष्ट्र के तुल्य हो और फिर वही स्वतंत्र राष्ट्र में परिणत हो सके। कहा गया कि किसी प्रकार की अंतर्कालीन या अल्पकालीन प्रकाश की सरकार बनाने में कांग्रेस अपना राष्ट्रीय अधिकार नहीं छोड़ सकती। कायसमिति ने कहा कि "अंतर्कालीन सरकार के हाथ में शक्ति तथा अधिकार होना चाहिए। यह जिम्मेदार हो, भले ही कानूनन सम्पूर्ण रूप से स्वतंत्र न हो, पर व्यवहारिक रूप से अवश्य स्वतंत्र हो। ऐसी सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी रहेगी न कि और किसी के प्रति। कांग्रेस कोई अ-यायपूर्ण समझ नहीं मान सकती और न यह स्वीकार कर सकती है कि किसी साम्प्रदायिक दल को यह अधिकार दे दिया जाए कि वह जिस बात को चाहे रह कर दे। इस कारण समिति 16 जून के बयान के अनुसार अंतर्कालीन सरकार में भाग नहीं ले सकती।"

समिति ने संविधान सम्मेलन में भाग लेकर भारत का संविधान बनाना स्वीकार किया, पर साथ ही यह कहा कि इस बीच प्रतिनिधि स्थानीय जिम्मेदार सरकार की स्थापना होनी चाहिए क्योंकि गैरजिम्मेदार सरकार के रहते हुए न तो दुर्भिक्ष पर ही रोक पाम हो सकती और न संविधान सम्मेलन का कार्य हो सकता है। कायसमिति ने संविधान सम्मेलन के सम्बन्ध में भी यह कहा कि भारतीयों के वोटों से संविधान सम्मेलन का निर्माण होना चाहिए संविधान सम्मेलन के अधिकार पर कोई रोक टोक न हो, और संविधान सम्मेलन विभक्त भारत नहीं बल्कि संयुक्त भारत के संविधान की रचना करे।

संविधान सम्मेलन का निर्वाचन—संविधान सम्मेलन का निर्वाचन जल्दी ही चुनाव में हो गया। यह संविधान सम्मेलन सावजनिक वोट पर नहीं, बल्कि धारासभाओं के सदस्यों के द्वारा चुना गया। चुनाव में पहले की तरह एक सीमाप्राप्त के अलावा सब वर्गों से मुसलमान सीटों से लीगी और हिंदू सीटों से कांग्रेसी आण। लोग ने चुनाव में

तो हिस्सा लिया, पर बाद का वह दिया कि सविधान सम्मेलन में हिस्सा नहीं लगी। यहाँ से सविधान सम्मेलन के सफल होने में सदेह हो गया।

**अन्तर्कालीन सरकार में कांग्रेस**—कुछ बातचीत के फलस्वरूप कांग्रेस ने अन्तर्कालीन सरकार में भाग लेना मंजूर कर लिया और 2 सितम्बर, 1946 को जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने अन्तर्कालीन सरकार में भाग लेना शुरू किया। इस दिन सारे देश में कांग्रेसियाँ न खुशी मनाई और चूँकि लीगी इसमें शरीक नहीं हुए, सारे भारत के मुसलमानों ने हड़ताल मनाई तथा काले भेदे दिखाए। अन्तर्कालीन सरकार में कांग्रेस की शिरकत के कारण ही इस बार भारत बंगाल दुमिठा के बहुतरासकरण से बच गया।

**बाद की लीग भी शामिल**—लीग ने बाद में जब देखा कि अन्तर्कालीन सरकार में जाने से अड़गल लगाने की नीति अधिक सफल हो सकेगी, तब लीग के नेताओं ने बड़ लाट के साथ बातचीत के दिखावे के बाद अन्तर्कालीन सरकार में भाग लेना स्वीकार कर लिया।

## मेरठ कांग्रेस 1946

1940 की रामगढ़ कांग्रेस के बाद नवम्बर 1946 में मेरठ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। आचार्य कृपलानी इस अधिवेशन के सभापति बनाए गए। रामगढ़ से लेकर 1946 तक अबुलकलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, इससे बाद नेहरू सामने आए और मौलाना आजाद की जगह कांग्रेस के प्रवक्ता हुए। ऐसा क्यों और कैसे हुआ इस सम्बन्ध में स्पष्ट कुछ पता नहीं, पर उन दिनों एक अपवाद यह था कि जिना को बार-बार कांग्रेस के सभापति या अध्यक्ष से मिलना पड़ता था और जिना ने मौलाना की स्वीकार नहीं किया था। इस पर चुनाव हुआ और नियमानुसार प्रांतीय कांग्रेसों से सिफारिशें मांगी गईं। अधिकांश प्रांतों ने सरदार पटेल का नाम भेजा, दो ने राजेन्द्र बाबू का नाम दिया, और किसी भी प्रांत से नेहरू का नाम नहीं आया। आचार्य कृपलानी ने पत्रकार दुर्गादास से कहा मैं जानता था कि महारामजी जवाहरलाल को चाहते थे, इसलिए मैंने स्वयं नेहरू का नाम यह कहकर रखा कि कुछ दिल्ली वाले नेहरू को चाहते हैं।”

पर अन्तर्कालीन सरकार में जाने के बाद उनका दल प्रवक्ता रहना अनुचित समझा गया। यह अधिवेशन बहुत ही सफल होता, परंतु अगस्त में लीग ने ‘डायरेक्ट एक्शन’ नाम से जिस असम्य आंदोलन का सूत्रपात किया था, उसके कारण आवश्यक बहुत गंदी हो गई थी। ऐन मौक़े पर गठमुक्तेश्वर में कुछ बसेड़ा भी हो गया। इसके अतिरिक्त दुमिठा की हालत के कारण यह अधिवेशन शानदार न हो सका। आचार्य कृपलानी ने अपने व्याख्यान में यह स्पष्ट किया कि इस बीच जो दमन हुआ उसके बावजूद कांग्रेस पहले से कहीं अधिक गतिशील हुई है। मेरठ अधिवेशन का सबसे सनसनीपूण क्षण वह था जब नेहरूजी ने यह बताया कि अन्तर्कालीन सरकार में बायसराय और लीग के पड़पत्र के कारण ऐसी परिस्थिति हो गई है कि किसी भी समय कांग्रेस को उससे निवृत्त कर संग्राम का सूत्रपात करना पड़ सकता है। अधिवेशन में कांग्रेस के विधान के सम्बन्ध में एक समिति भी बना दी गई।

**नेहरू तथा जिना की विलायत यात्रा**—लीग ने अन्तर्कालीन सरकार का बायकाट कर रखा था। लीग और कांग्रेस में कोई समझौता हो सकता है या नहीं जिससे लीग 9 दिसम्बर से शुरू होने वाले सविधान सम्मेलन में भाग ले सके, यह जानने के लिए मि०

एटली न जवाहरलाल नेहरू तथा जिन्ना को विलायत बुलाया। पहले तो नेहरू ने कहा कि जिन्ना व्यर्थ है क्योंकि लोग ने 15 मई की घोषणा का स्वीकार कर लिया है अर्थात् संविधान सम्मेलन में भाग लेने की शक्त को मानकर ही अंतर्जालीन सरकार में हिस्सा लेना शुरू किया है—इसलिए बेकार की बातचीत से कोई फायदा नहीं है। 26 नवम्बर को नेहरू ने लाइ बेबल को लिखा कि लंदन जाने का अर्थ ही यह है कि फिर सारी बात पर चर्चा की जाए। नेहरू ने कहा कि वह इसके लिए तैयार नहीं हैं। फिर 1 दिसम्बर से संविधान सम्मेलन की बैठक होना जा रही है। यदि उस वक्त तक वापस न आ सके, तो संविधान सम्मेलन स्थगित कर दिया जाएगा, और इस पर तरह तरह के खतरनाक प्रचार होगा, जिसमें बहुत नुकसान होगा। प्रधान मंत्री ने इस पर यह लिखा कि 9 दिसम्बर से संविधान सम्मेलन का अध्ययन हो, यही उद्देश्य लेकर चर्चा होने जा रही है। इसलिए क्विंट मिशन की योजना को त्याग देने अर्थात् संविधान सम्मेलन के अधिवेशन को स्थगित करने का कोई प्रश्न नहीं है। प्रधान मंत्री ने लिखा कि क्विंट मिशन योजना को बनाना या स्थगित करना लक्ष्य नहीं है, बरिक् उससे सफल बनाना ही लक्ष्य है। फिर भी जवाहरलाल ने जान से इन्कार किया। परंतु जब एटली ने फिर अनुरोध किया और यह बात किया कि 9 दिसम्बर के पहले ही वह लौट आये, तब वह राजी हुए।

अब नेहरू राजी हो गए तो जिन्ना राजी नहीं हुए। जिन्ना ने कहा कि पश्चित नेहरू का जो आश्वासन दिए गए हैं, यदि वे सही हैं तो उनके जाने का कोई अर्थ नहीं होगा। इस पर प्रधान मंत्री ने लिखा कि किसी भी दृष्टिकोण से देखें तो चर्चा में कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। इस पर जिन्ना भी जान के लिए राजी हो गए। परंतु लंदन में हुए इस चर्चा का कोई नतीजा नहीं निकला और नेहरू तथा जिन्ना दोनों जैसे गए थे वैसे ही लौट आए। पहले बार्थोस में कुछ ऐसी राय हुई कि विवादग्रस्त विषय फेडरल स्तर पर सुपुर्द कर दिए जाए और बाद की कांग्रेस ने यह इरादा छोड़ दिया।

संविधान सम्मेलन—9 दिसम्बर की यथारिति संविधान सम्मेलन की कार्यवाही शुरू हुई। प्रसिद्ध विद्वान श्री सच्चिदानंद सिल्ला अधिक उग्र होने के नाते इस अधिवेशन के अध्यक्ष बन और उन्हीं की अध्यक्षता में स्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेन्द्र प्रसाद का चनाव हुआ। नेहरू जी ने पहले ही पत्रों को वक्तव्य देते हुए कह दिया था कि संविधान सम्मेलन सर्वप्रभु संस्था है। सम्मेलन के कुल सदस्यों की संख्या 385 थी। इनमें सीधे कांग्रेस तथा कांग्रेस के द्वारा नामजद 207 सदस्य थे। 14 अन्य सदस्यों के कांग्रेस के साथ काम करने की उम्मीद थी। इन 385 सीटों में रियासतों की 93 सीटें नहीं जोड़ी गई। संविधान सम्मेलन ने स्थायी अध्यक्ष चुनने के बाद उप समितियों का निर्माण किया और उनका कार्य चलने लगा। 13 सितम्बर को नेहरू ने प्रस्ताव रखा कि भारतवर्ष एक गणराज्य तथा प्रभुतासंपन्न राष्ट्र बनेगा।

6 दिसम्बर की घोषणा—9 दिसम्बर में संविधान सम्मेलन का अधिवेशन शुरू होना था, पर 6 दिसम्बर को ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि प्रांतों के युपिंग को मानकर ही सम्मेलन कार्य कर सकता है। कहना न होगा कि यह प्रस्ताव संविधान सम्मेलन की प्रभुता पर हस्तक्षेप था। अभी संविधान सम्मेलन ने कुछ काम नहीं किया था जिस पर ऊपर से यह हुक्मनामा आया, यह कोई अच्छा लक्षण नहीं था। पर कांग्रेस कार्यमिति ने यह सोचकर कि सरकार कहा तक जाती है यह देखा जाए, इस घोषणा को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस के नेता शायद सोचते थे कि कुछ प्रांतों को न सही, परंतु बाकी प्रांतों को ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता देती है या नहीं, यह देखा जाए। स्मरण रहे, इस घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने 16 मई की घोषणा के विरुद्ध मतव्य दिया



था। उस घोषणा में कहा गया था कि किसी भी अल्पसंख्यक सम्प्रदाय को यह अधिकार न होगा कि वह किसी जगह के वस्त्र में बाधा पहुंचाए, पर इस घोषणा में यह कहा गया कि सरकार इस बात के लिए तैयार नहीं है कि किसी भी अनिच्छुक अंग पर सविधान सम्मेलन के फैसले को लागू किया जाए। यद्यपि कांग्रेस ने 6 दिसम्बर की घोषणा को मान लिया, फिर भी जिना तथा उनकी पार्टी ने सम्मेलन में भाग लेने से इंकार कर दिया। कांग्रेस ने फिर भी इस आशा से कि शायद लीग को सुबुद्धि आ जाए नेहरू वाले प्रस्ताव को बिना पारित किए ही, 23 दिसम्बर को कुछ आरम्भिक कारवाई करने के बाद, अधिवेशन को स्थगित कर दिया। असम के नेताओं ने कांग्रेस कायसमिति के बावजूद यह तय किया कि वे ब्रिगिंग में शरीक नहीं होंगे।

**कलकत्ता हत्याकांड** अगस्त 1946 से लीग ने बंगाल में जो कायपद्धति चलाई थी, उसके कारण बंगाल के हिंदुओं की हालत बहुत खराब हो गई थी। 16 अगस्त को जिन दिन लीग का वर्यित 'डायरक्ट एक्शन' दिवस शुरू हुआ, उस दिन लीगियों ने भयंकर रूप से हिंदुओं की हत्या करने का कार्यक्रम उठाया। यही नहीं, लीगी सरकार ने पुलिस को भी लोगों की मदद के लिए नहीं आने दिया। नतीजा यह हुआ कि कलकत्ता में हिंदू दूरी तरह मारे गए और तीन दिन बाद जब हिंदू भी अपने प्रथम विस्मय से जागकर आत्मरक्षा के लिए उठ खड़े हुए, तो पुलिस ने हस्तक्षेप शुरू किया।

**नोआखाली और बिहार के दंगे**—इसन बाद लीग ने नोआखाली में संगठित तरीके से हिंदुओं का नाश आरम्भ किया। इस बार लीगियों ने स्त्रियों को भगाना तथा लोगों को जबदस्ती मुसलमान बनाना भी शुरू किया। पुलिस न सताए हुए लोगों का बिल्कुल मदद नहीं की बल्कि अपराधियों की मदद की। लोगों में इतना भय फैला कि वे गांव और घर छोड़कर भागने लगे। गांधीजी का लीग ने जाकर नोआखाली की खबरें बताई, तो वह भारी संकट सहकर नोआखाली पहुंचे और जनवरी में उन्होंने गांव गांव का दौरा करना शुरू किया। उनका उद्देश्य हिन्दू-मुस्लिम में लड़ाई करना था। बंगाल के लीग द्वारा आरम्भ किए दंगों की प्रतिनित्या स्वरूप बिहार में बहुत भयंकर दंगे हुए, जिनमें मुसलमान बहुसंख्या में मारे गए। दंगा बंगाल और बिहार दोनों में हुआ पर बिहार में सरकार ने दंगाइयों को दबाया और मुसलमानों की रक्षा की। उगाल में सरकार ने दंगों में प्रत्यक्ष भाग लिया और फिर दंगा खत्म होने के बाद न अपराधियों को पकड़ा और न भगाई हुई औरतों का पता लगाने में मदद दी। इन भगाई हुई स्त्रियों में से हिंदू स्त्रियों के बसरा तक ले जाए जान की गारंटी का मिली। गांधीजी नोआखाली के बाद अन्य दंगापीड़ित क्षेत्रों का दौरा करने लगे, पर तु उनमें नोआखाली से भी ठीक फरक ही रहा फिर भयंकर अत्याचार शुरू हो गया।

**फिर बग भग का नारा**—बंगाल की लीगी सरकार की साम्प्रदायिक नीति तथा खुन्नम खल्ला मुसलमान दंगाइयों और अपराधियों के साथ पक्षपात करने के कारण बंगाल के हिंदुओं तथा राष्ट्रीय विचार के लोगों में यह धारणा जार पक गई कि लीगी सरकार के अधीन रहना दुर्भाग्य ही होगा। इस कारण जा बंगाली हिंदू कभी बग भग के विरुद्ध अपना शांतिपूर्ण देकर लड़े थे अतः इस बात के लिए मजबूर हुए कि बग भग का नारा दें। ऐसे लोगों ने यह नारा दिया कि बंगाल के पश्चिमी जिले जिनमें हिंदुओं की बहुसंख्या है एक प्रांत के रूप में संगठित किए जाए। यह आंदोलन दिन व दिन जार पकता गया। अंत में बंगाल की प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने भी इस नारे का समर्थन किया। मजे की बात यह है कि जब यह आंदोलन जोर पकड़ने लगा, तो लीग के नेता बृहत्तर बंगाल का नारा देने लगे और कहने लगे कि बंगाली जाति के एक बन रहने में ही भलाई है। य लीग भूल

कि इनक सिद्धांत क अनुसार बगाली जाति का तो कोई अर्थ ही नहीं होता क्योंकि ब्रिटिश तो मुस्लिम और हिंदू दो ही हैं। ये सोच यह भी भूल गए कि उनके लिए तो एक ही शब्द है, पाकिस्तान, और बृहत्तर बंगाल का कोई अर्थ नहीं होता।

एशिया सम्मेलन—माच, 1947 में मुख्यतः जवाहरलाल नेहरू के प्रयत्नों से एशिया में अखिल एशिया सम्मेलन बुलाया गया। एशिया के प्रत्येक देश ने इस सम्मेलन में अपना प्रतिनिधि मण्डल भेजा तथा भारत की सब पार्टियाँ ने इसके साथ पूरा सहयोग दिया। केवल भारतीय मुस्लिम लीग ने इसका वायकाट किया। इस प्रकार अखिल एशिया सम्मेलन का वायकाट कर लीग के नेताओं ने सारे एशिया के प्रतिनिधियों के सामने यह स्पष्ट कर दिया कि उनके विचार बहुत ही मकील हैं। उन्होंने इस सम्मेलन पर यह दोष लगाया कि यह एक विशेष पार्टी अर्थात् कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, इसलिए वह इसमें शरीक नहीं हो सकते। यह द्रष्टव्य है कि इस सम्मेलन में बाहर से कोई प्रतिनिधि आए उनमें बहुत से धुसलमान थे। इसमें 30 देशों से 230 प्रतिनिधि आए। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए नेहरूजी ने कहा कि यूरोप तथा अमेरिका के जल शरीरों में यह शका प्रकट की गई है कि यह सम्मेलन गोरी जातियों के विरुद्ध है, जो गलत है। हम एक दुनिया के आदर्श के लिए काम करेंगे।

एशिया सम्मेलन के कार्य—सम्मेलन में किसी देश की आन्तरिक राजनीति पर कोई आलोचना नहीं की गई। ऐसा इसलिए किया गया कि वही किसी समस्या पर अपनी भगड़ा उठ खड़ा न हो। श्रीमती सरोजिनी नायडू इस सम्मेलन की सभानेत्री थी। सम्मेलन में इंडोनेशिया के नातिकारी नेता डाक्टर शहरयार सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। अवश्य अन्य देशों से जो प्रतिनिधि आए थे, वे भी अपने अपने देश के बड़े नेता थे। सम्मेलन के फलस्वरूप एशियाई देशों में मित्रतापूर्ण वातावरण उत्पन्न हुआ। इस सम्मेलन से 'एशिया छोड़ो' का साम्राज्यवाद विरोधी नारा भी निकला।

जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा—इस सम्मेलन के पहले ही 27 जनवरी, 1947 को मिस्टर ऐटली ने यह घोषणा की थी कि जून 1948 तक ब्रिटिश सरकार भारत छोड़ देगी। इस घोषणा में मिस्टर ऐटली ने कहा "अनेक वर्षों से एशिया की एक के बाद एक सरकार भारत में स्वायत्त शासन प्रतिष्ठित करने की चेष्टा कर रही हैं। इस नीति का अनुसरण करने के कारण भारतीयों में क्रमशः जिम्मेदारी बढ़ती गई है और आज यह हालत पहुँच चुकी है कि शासन व्यवस्था तथा भारतीय शासन सभा भारतीय कमचारियों पर बहुत कुछ निर्भर है। शासन सुधार के क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि ब्रिटिश संसद ने 1919 और 1935 में भारतीयों को यथेष्ट अधिकार दिए।" इस प्रकार शासन सुधार का इतिहास देने के बाद घोषणा में कहा गया कि जून 1948 के पहले जिम्मेदार भारतीयों के हाथों में सत्ता सौंप देने का सरकार निश्चित कर चुकी है। जो सरकार भारतीयों के समर्थन से बनेगी, और जो सरकार वाय का सिद्धांत के अनुसार भारत का शासन कर सकेगी, और शांति स्थापित कर सकेगी, ब्रिटिश सरकार उसके हाथों में जिम्मेदारी देने के लिए उत्सुक है। अगले साल तक इस प्रकार जिम्मेदारी को लेने के लिए सब दलों को भ्रमड़े मिलाकर एक हो जाना चाहिए। समूह रूप से प्रतिनिधिमूलक संविधान सम्मेलन जिस विधान की रचना करेगा, ब्रिटिश सरकार अपनी संसद में उसे समर्थन देगी। यदि इस बीच ऐसा संविधान नहीं बन पाया, तो ब्रिटिश सरकार किसी के हाथों भारतीय केंद्रीय सरकार की ताकत दे, इसे बाद का सोचा जाएगा। जून 1948 तक शायद पूरी शासन शक्ति दे पाना संभव न हो, इसलिए हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। अर्सेनिक शासन व्यवस्था कुशल हो और भारत

देश की रक्षा ढग स की जाए, इसका आयोजन बहुत जरूरी है। देशी रियासतों के सबध में घोषणा में कहा गया कि ब्रिटिश सरकार सावभौम शक्ति की हैमियत से जो शक्ति रखती है तथा उनके साथ उसके जो सबध है, उन्हें पूरे तरीके से शक्ति हस्तांतरित करने से पहले ब्रिटिश सरकार नहीं छोड़ेगी। भारत में ब्रिटेन के व्यापारिक तथा औद्योगिक स्वार्थों की भी रक्षा करने की बात कही गई।

**घोषणा का असर**—इस घोषणा के पहले अंतर्कालीन सरकार में लीग तथा कांग्रेस का सबध इतना बड़बुदा हुआ था कि कांग्रेस के नेता यह खुलआम घमकी देने लगे थे कि या तो लीग 16 मई 1946 की घोषणा मानकर संविधान सम्मेलन में भाग ले या वह अंतर्कालीन सरकार छोड़कर चली जाए, परंतु इस घोषणा से यह परिस्थिति बदल गयी।

**पंजाब में दंगा**—एंग्लो की घोषणा के बाद ही पंजाब में यूनिवर्सिट मंत्रिमण्डल के नेता खिजर हयात खा ने यह कहकर इस्तीफा दे दिया कि इस घोषणा से परिस्थिति इतनी बदल गई है कि अब उनका मुख्यमंत्री रहना उचित नहीं लगता। पता नहीं कि यह बात पहले से तय थी या नहीं मंत्रिमण्डल के इस्तीफा देते ही लीग की तरफ से भय कर साम्प्रदायिक दंगे शुरू हो गए, और हजारों निरीह लोग मारे जाने लगे। लीग की असेम्बली पार्टी मंत्रिमण्डल बनाने में असमर्थ रही। दंगों के कारण पंजाब के सिक्ख तथा हिंदुओं ने भी पंजाब के विभाजन का नारा दिया और कांग्रेस कायसमिति ने उसे स्वीकार भी कर लिया। हिंदू मुस्लिम दंगे कराने लीग ने 'मुस्लिम नेशन' के लिए अलग होमलैंड की अपनी मांग पूरा करा ली।

**स्वराज्य**—साथ ही देश का विभाजन—एक तरह से 3 जून, 1947 को ही भारतवर्ष को स्वराज्य प्राप्त हो गया। युग युग की सदी हुईं जमीर खनखनाकर गिर पड़ी। इससे देश में अपार हर्ष की गहराई हुई। परंतु साथ ही देश का जो दो हिस्से पाकिस्तान और हिंदुस्तान में विभाजन हुआ। इससे देश की सारी समझदार जनता, विशेषकर राष्ट्रीयतावादी तथा समाजवादी हिस्सा बहुत दुखी हुआ। कुछ समाजवादी तो अखण्ड हिंदुस्तान के नारे में विश्वास रखते थे परंतु अधिकांश जातियों के आत्म निणय में, यहां तक कि अलग राष्ट्र बनाने की हद तक आत्म निणय में, विश्वास करते थे। परंतु वे भी भारतवर्ष के धार्मिक विभाजन के विरुद्ध थे। वे समझते थे कि धार्मिक विभाजन का समाजवाद में कोई स्थान नहीं है। आवश्यक की बात है कि अपने को समाजवाद का एक मात्र ठेकेदार समझने वाली कम्युनिस्ट पार्टी की इस सबध में नीति दुर्लभ ही रही। कम्युनिस्ट पार्टी ऐसे गोलमोल शब्दों में अपनी नीति व्यक्त करती रही कि विरुद्ध मतों के सम्मिश्रणों को उसके सबध में परस्पर विरोधी धारणाएँ उत्पन्न होती रही। फिर इस सबध में भी उसकी नीति बराबर बदलती भी रही।

कांग्रेस के नेताओं ने देश के धार्मिक विभाजन को यह समझकर ग्रहण किया कि इससे कम से कम जापसी भगंडे का अंत हो जाएगा। तीन जून को दिल्ली से इसी कार्य के लिए विशेष रूप से भेजे गए वायसराय लार्ड माउंटबेटन ने ब्राडकास्ट किया जिसमें उन्होंने भारतवर्ष का औपनिवेशिक पद प्राप्त होना और उसका दो राष्ट्रों में विभाजित होना घोषित किया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषित किया कि कांग्रेस इस घोषणा को यह समझकर स्वीकार करती है कि इस प्रकार शायद बिछड़े हुए हिस्सों के जुड़ने में शीघ्रता हो। पटेल भी इसी राय पर पहुंच चुके थे।

उन दिनों के कम्युनिस्ट नेता—याद रहे, उस समय कम्युनिस्ट पार्टी एक ही थी और टुकड़ों टुकड़े नहीं हो पाई थी। श्री विपिनचंद्र द्वारा सम्पादित पुस्तक 'दि

इंग्लैंड लेफ्ट' के अनुसार कम्युनिस्ट पार्टी के मंत्री श्री पी० सी० जाशी ने दंडे गव के साथ निम्न "केवल हमारी पार्टी ने कांग्रेस-लीग एकता के लिए चपटा की। हमने जेहादी बोम कांप्रेसजनों में पाकिस्तान की मांग को और लीगियों में कांग्रेस मांग का जनप्रिय बनाया।" कहा न होगा कि यह प्रचार हास्यास्पद था। परंतु दूसरे कम्युनिस्ट नेता रावी की तरह धून नहीं थे। कभी-कभी उनके मुह से सत्य निकल ही पड़ता था। प्रमुख कम्युनिस्ट नेता अधिकारी ने कहा "यदि हम यह कहते हैं कि लीग का प्रभाव प्रतिक्रिया से और साम्प्रदायिक था, तो उमरा अथ यह है कि मुस्लिम जनता कभी साम्राज्यवाद विरोधी जनता तक पहुंची ही नहीं।" कम्युनिस्ट नेताओं ने इस सवध में बराबर जो दूसरी बातें की, उनमें उनका मानसिक दिवालियापन तथा साथ ही वर्तमान प्रकट होती है। यही कारण है कि जाकर हमने केवल एक दो नमूने ही पेश किए हैं जिनसे नेहरू का यह वक्तव्य प्रमाणित होता है कि "कम्युनिस्ट जिना की भाषा के संपूर्ण समर्थक हैं।" दूसरी गलतियाँ इस कारण होती हैं कि भारतीय कम्युनिस्टों ने लेनिनवादी सोशलिज्म का आत्मनिर्णय (स्वातंत्र्य) न जिससे विस्तार किया) सिद्धांत को जबरदस्ती पाकिस्तान मांगने वाले कट्टर मुसलमानों पर लागू कर दिया, जबकि वास्तव में इस कम्युनिस्ट सिद्धांत में धार्मिक आधार पर जाति की स्वीकृति नहीं है। अवश्य कम्युनिस्ट गुजरात और लखनऊ तो भी पाकिस्तान रक्त नहीं जाता, ऐसा मानते हुए भी यह कहा जा सकता है कि कम्युनिस्टों की गलत स्थापनाओं के कारण बहुत से मुसलमान जा शायद गुमराह न होते, गुमराह होत चले गए। वे प्रगतिशील भी बने रहें और पाकिस्तानी भी। इन पाकिस्तान और भारत दोनों का गहरी हानि पहुंची। यदि को जा घटनाएँ हुईं, सभी रोशनी में यह जानना दिलचस्प होगा कि कम्युनिस्ट उस समय अकानियों की भाषा पंजाब की भाषा के विरुद्ध थे। कोई पूछे कि क्यों? यदि आत्मनिर्णय सिद्धांत पर मुसलमानों पर लागू हो सकता है, तो वह उसी तक से सिक्खा पर भी लागू हो जाता है।

**पंजाब सिद्धांत**—दुर्गादास ने लिखा है "अंतिम विश्लेषण में कांग्रेस के नेता या अथ सभी दल कुल मिलाकर इतना थक चुके थे कि आगे सग्राम चलाने को तैयार हो गए। कुछ यह भी डर था कि ब्रिटेन के अगले चुनाव में श्रमिक दल जा पाए या न आए।" इस 'पंजाब सिद्धांत' का समर्थन एक अंग्रेजी लेखक लिजानाड मास्ले ने भी अपनी पुस्तक 'लास्ट डेज आफ दि राज' में किया है, पर साथ ही उसने यह भी कहा है "नेहरू और पटेल माउंटबेटन द्वारा लटकाए हुए गान्धी से प्रलुब्ध नहीं थे।

लीग तथा उसके नेताओं को जो जरा भी जानता था, वह कभी यह आशा नहीं रखता था कि जिस रूप में पाकिस्तान मिला, उस रूप में वह किसी भी प्रकार उनको रक्षित कर सकता था। जिस सत्ता ने नाआखाली तथा कलकत्ता में सगठित तरीके से बू विनाश तथा उनकी स्त्रियों का भगाने का कार्यक्रम चलाया था, उनसे यह आशा तो कि वह शक्ति हाथ में आ जाने पर साधु हो जाएंगे तथा लाकतांत्रिक तरीके में न के दुराशा मात्र थी।

**जुनागढ़ कश्मीर**—जुनागढ़ तथा कश्मीर की घटनाओं और पूर्वी बंगाल द्वारा उन और पश्चिमी बंगाल की भूमि पर चढ़ाई से यह स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान का जना भगडे घटाने में सहायक न हाकर भगडों का पैमाना बढ़ाने में सहायक हुआ। जो पहले बहुत कुछ दंगों के रूप तक सीमित रह सकते थे जब उनके युद्ध में परिणत हो की समाप्ति उत्पन्न हो गई। कश्मीर पर हुए हमले के सवध में यह अच्छी तरह विदित हो चुका है कि इस हमले में पाकिस्तान का हाथ था। पाकिस्तान इन आक्रमण

कारियों को खाना पीना, अरन शस्त्र, सभी कुछ दे रहा था। इस आश्रमण का मामला समुक्त राष्ट्र सभ के सामने पेश हुआ पर उसने पक्षपात से काम लिया।

फिर पाकिस्तान बनने के दौरान पश्चिमी पंजाब के अगणित हिन्दू तथा सिख मारे गए तथा जो बचे उन्हें वहाँ से खदेड़ दिया गया। जवाब में पूर्वी पंजाब के मुसलमानों के साथ भी ऐसा ही किया गया, जिसका नतीजा एक तो यह हुआ कि बड़वापन बढ़ा और भारतीय सभ के लिए एक ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो गया कि सारा धन इसी में खर्च होने लगा। राष्ट्र निर्माण की किसी योजना को कार्यान्वित करने की कोई गुंजायमानता नहीं रही क्योंकि बिना धन के किसी योजना को कार्यान्वित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

स्वतंत्रता का आवाहन— भारत के प्रथम प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के स्वतंत्रता का आवाहन बरत हुए आकाशवाणी से कहा “आज एक नुम और मुबारक दिन है। जो स्वप्न हमने बरसों से देखा था, वह कुछ हमारी आँखों के सामने आ गया। चीजें हमारे बच्चे में आई हैं। निल हमारा खुश होता है कि एक मजिल पर हम पहुँचे। यह हम जानते हैं कि हमारा सफर खतम नहीं हुआ अभी बहुत मजिलें बाकी हैं, लेकिन, फिर भी, एक बड़ी मजिल हमने पार की और यह बात तय हो गई कि हिन्दुस्तान के ऊपर कोई गैर हुकूमत अब नहीं रहेगी। हमारा मुल्क आजाद हुआ, गियासी तौर पर एक बोझा जा बाहरी हुकूमत का था वह हटा। लेकिन आजादी भी अजीब-अजीब जिम्मेदारियाँ लाती है और बोझें लाती है। अब उन जिम्मेदारियाँ का सामना हमें करना है और एक आजाद नैसियत से हम आगे बढ़ना है और अपने बड़े-बड़े सवालों को हल करना है। सवाल बहुत बड़े हैं। सवाल हमारी सागी ब्राता का उद्धार करने के हैं, हमें गरीबी को दूर करना है बीमारी को दूर करना है, अनपढ़पन को दूर करना है और आप जानते हैं, कितनी और मुसीबतें हैं जिनको हमें दूर करना है। आजादी महज एक सियासी चीज नहीं है। आजादी तभी एक ठीक पोशाक पहनती है, जब उससे जनता को फायदा हो। आजकन हमारे सामने ये आर्थिक सवाल बहुत सारे हैं बहुत काफी जमा हुए हैं, जो हमारी गुलामी के जमाने के हैं। बहुत कुछ पिछनी लड़ाई की वजह से पिछनी बड़ी लड़ाई जो दुनिया में हुई और उसके बाद जो हालात दुनिया में हुए हैं, उसकी वजह से ये सवाल जमा हैं। खान की कमी है कपड़े की कमी है और ज़रूरी चीजों की कमी है और ऊपर से चीजों के दाम बढ़ते जाते हैं जिससे जनता की मुसीबतें बढ़ रही हैं।’

## स्वराज्य के बाद कांग्रेस सत्ता में

स्वराज्य के बाद कांग्रेस की स्थिति स्वाभाविक रूप से बदल गई। किसी भी दृष्टि से वह दिन अच्छा होने से माथ ही घुरा भी होता है जब उसका लक्ष्य पूरा हो जाता है क्योंकि उसके बाद उसके अस्तित्व का कारण (Raison d'être) समाप्त हो जाता है। ब्रजकिशन चांदीवाला और ले दुलकर के अनुसार महात्मा गांधी ने कांग्रेस को समाप्त कर लोक सेवक सघ बनाने की एक योजना बनाई थी, जो कायसमिति की भांति बैठक में पेश की जाती। परन्तु इसी बीच महात्माजी एक धर्माघ हिंदू के हाथों मारे गए, और यह योजना एक दस्तावेज मात्र रह गई। हा, यह पूरी योजना गांधीजी की गृहादत के करीब दो सप्ताह बाद उनके पत्र 'हरिजन' (15 2 48) में छपी।

लोकसेवक सघ — इस परिपत्र में महात्माजी ने कहा था “कांग्रेस अपने वर्तमान रूप और आकार यानी प्रचार के माध्यम और सप्तदीय यंत्र के तौर पर अपनी दशमिता खो चुकी है। भारत को अभी अपने शहरा और कस्बों से अलग सात लाख गांधी के लिए सामाजिक, नैतिक और आर्थिक आजादी प्राप्त करनी है।”

इस योजना के अनुसार पांच बालिग पुरुष और स्त्रिया की मूल पचायती इकाई बनाई जानी। इस प्रकार की पचायतें पिरामिड के ढंग पर ऊपर उठती चली जाती। प्रत्येक पचायती के लिए खानी पहनना तथा धूपपान से बचना जरूरी होता। सघ के बलापन में स्वयं शासित संस्थाएँ होती—

(1) चर्चा सघ, (2) ग्रामीण सघ, (3) हिंदुस्तानी तालीम सघ, (4) हरिजन सेवक सघ तथा (5) गोसेवा सघ।

देश के निर्माण की यह अच्छी योजना थी और यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता तो दलबंदी से बहुत सीमा तक बचा जा सकता था। परन्तु तथ्य यह है कि कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस के विलीनीकरण की आवश्यकता नहीं समझी। इस सम्बंध में मनो रंजन बाट गट्ट है कि गांधीजी ने 27 जनवरी को ‘कांग्रेस की स्थिति’ शीर्षक से एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को मरने नहीं दिया जा सकता। वह सभी मरगी जब राष्ट्र मरेगा। प्रतीत होता है कि महात्माजी स्वयं अभी दुराहे पर खड़े थे, किन्तु निश्चय पर नहीं पहुँचे थे।

पाकिस्तान की रचना — पाकिस्तान ज़िम्मेदार बनना, वह बताया जा चुका है। वह मुसलमानों के होमलैंड या वतन के रूप में सामने आया, परन्तु लगभग चार करोड़ मुसलमान फिर भी भारत में रह गए। इस प्रकार पाकिस्तान का बनना इन मुसलमानों के साथ धोखा ही हुआ। यह भी नहीं कहा जा सकता कि जो चनाबरोड़ मुसलमान भारत में रह गए उनमें से सभी भारत के प्रति प्रेम करने के कारण ही वहाँ रहे। उनके भाग लिए गए वोट इसका प्रमाण है। इनके अनावा, लोग कोई भी नई बात, विशेषकर परिवार छोड़कर एक्लम नई जगह जाकर बसना, पसंद नहीं करते। इस प्रकार की कई

वार्ते इसने अंदर थी। आजादी के पहले भारत के मुसलमान किसी भी तरह से, बहानों में आकर ही सही मुस्लिम लीग को अपन लगभग सारा वोट दे देते थे, परंतु दस्ता जाए तो असलियत कुछ और ही थी। यी राष्ट्रीय आंदोलन में कुछ मुसलमान बहुत ईमानदारी के साथ थे, पर इनमें से एक आघ मुसलमान ही इस योग्य था कि वह मुसलमान वोटों से किसी धारामभा में चुना जा सके। हाफिज मोहम्मद इब्राहीम आदि कुछ कांग्रेसी मुसलमान ही इतना ज़बदबा रखते थे कि वह अपने हल्ले से मुस्लिम वोटों पर चने जा सकें। जो चार करोड़ मुसलमान भारत में रह गए, व एक प्रकार से बड़ी अजीब स्थिति में पड़ गए। यद्यपि उनमें से बहुतों ने, जमा कि मुस्लिम लीग को उनके बाट देने से ज्ञात होता है, मुस्लिम हामसण्ड के सपने देखे थे, पर जब स्वप्न सामने आया तो वे प्रमाद या आलस्य से पीछे हट गए।

**कश्मीर युद्ध** — कश्मीर में राजा महदू था, जो स्वराज्य के साथ स्वयं स्वयं होने का सपना देख रहा था। परंतु जब पाकिस्तान ने उस पर हमला कर दिया, तो उसने भारत की मदद मांगी और कश्मीर बानूनी रूप से भारत का अंग बन गया यद्यपि वह एक मुस्लिम प्रधान प्रांत था। उस समय के कश्मीरी नेता राष्ट्रीयवादी थे। वे राजा के साथ इस शर्त पर मिल गए कि कश्मीर में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार बनेगी। कश्मीर युद्ध में पाकिस्तान को मुहंजी खानी पड़ी और यदि नेतागण उस समय और थोड़ी हिम्मत दिखाते, तो युद्ध विराम रेखा का टूटा नहीं रहता, पूरा कश्मीर ही भारत में मिल जाता।

यहां देखने की बात यह है कि पाकिस्तान के नेता कश्मीर को तो हड़पना चाहते थे, पर उन्होंने चार करोड़ मुसलमानों से यह नहीं कहा कि तुम यहां आ जाओ। उन्हें मुस्लिम जनता से कोई प्रेम नहीं था, उन्हें तो साम्राज्य चाहिए था।

केवल कांग्रेस के नेता ही नहीं सभी लोगों ने पाकिस्तान के जन्म को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार किया। कई बुद्धिमान लोग यह भी सोचते थे कि देश का जन्म चाहे किसी भी तरह हुआ हो, पर हकूमत की भूल पूरी हो जाने पर नायब सारा भगडा निबट जाएगा। पर इस उम्मीद पर पहली बार पानी तब फिर गया, जब पाकिस्तान बनने के साथ ही वहां भयंकर मारकाट हुई और हिंदुओं का मार भगया गया। हा, पूर्वी पाकिस्तान में काफी हिंसा रह गई।

कश्मीर का भारत में होना पाकिस्तान के मुद्दे पर एक थप्पड़ की तरह रहा। यो यहां बताया जाये कि आर्थिक दृष्टि में कश्मीर का भारत में होना कोई फायदा नहीं सौदा नहीं था। करोड़ों रुपये उस पर खर्च हुए और जरावर हाते रहे हैं। पाकिस्तान के लिए भी वह आर्थिक फायदे का सौदा नहीं होता, कम से कम बहन माना तक नहीं। फिर भी पाकिस्तान कश्मीर का लोभ लिए तड़पता रहा। क्यों? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जिस अवैधानिक बुनियाद पर बना उस पर भारत में कश्मीर रहने से आच आती है जबकि भारत के धर्मनिरपेक्षता की बुनियाद पर निर्मित होने के कारण उसमें कश्मीर रहने से उसे बल मिलता है। यह बात यहां अवश्य कह देनी चाहिए कि भारत केवल मुद्दे से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं रहा बल्कि वह सब तरह से अपन यहां धर्मनिरपेक्षता का बल पट्टावा रहा। जहां पाकिस्तान में यह नियम है कि कोई भी घर मुसलमान पाकिस्तान का राष्ट्रपति नहीं हो सकता भारत में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। सच तो यह है कि भारत में बड़े से बड़े ओहदों पर अहिंदू हमेशा रहें हैं।

**पहला पाक हमला** — किन परिस्थितियों में पाकिस्तान और भारत का यह पहला युद्ध छिड़ा, जाइय यह देखें। गांधीजी अभी हमारे बीच थे और उन्होंने इस युद्ध

को आशीर्वाद दिया था। आचार्य कृपलानी ने लिखा है "अक्सर यह पूछा जाता है कि अहिंसा कौन पुजारी गांधीजी ने कश्मीर में फौज भेजने का समयन किया, सो बात यह है कि गांधी एक अहिंसावादी सरकार को परामर्श नहीं दे रहे थे, बल्कि एक ऐसी सरकार को सलाह दे रहे थे जो बंध स्वयं की रक्षा के लिए फौज रखती थी।" भारत किसी भी हालत में किसी देश से युद्ध नहीं करना चाहता था और लोगों में यह धारणा बन गई थी कि भारत किसी भी हालत में युद्ध नहीं करेगा। बाद में शायद अयूब के मन में भी यही धारणा बठ गई।

**स्वराज्य के बाद गांधी** — पाकिस्तान द्वारा आक्रमण के पहले ही वातावरण काफी खराब था। यह अजीब बात है कि चार करोड़ मुसलमान भारत में थे, कम से कम उनका स्वागत को देखकर पाकिस्तान को भारत पर हमला नहीं करना चाहिए था। पर स्वराज्य के बाद देश भर में साम्प्रदायिक मारकाट चानू हुई, तो गांधीजी को बहुत दुःख हुआ। 15 अगस्त, 1947 के बाद उन्होंने सिर्फ एक ही काम पर ध्यान दिया था — हिंदुओं और मुसलमानों में वैमनस्य दूर करना। उन्होंने उस अधिकांश वातावरण में यह संदेश दिया — "मेरे धर्म की कोई भौगोलिक रेखाएं नहीं हैं। यदि इसमें मेरा विश्वास सच्चा है तो भारत के प्रति मेरा ज़रा प्रेम है, वह भौगोलिक सीमाओं में आगे जाने वाला साबित होगा। मेरा जीवन तो इस लिए अर्पित है कि मैं अहिंसा धर्म के द्वारा भारत की सेवा करूँ।"

**स्वराज्य के बाद शांति यात्रा** — वह हिंदुओं और मुसलमानों में प्रेम भावना उत्पन्न करने के लिए विहार गए जो आखिली गए अपने शिष्यों को लाहौर और जहा लहा भवा। जब गांधीजी की हत्या हुई उस समय श्रीमती सुशीला नैयर लाहौर में काम कर रही थी। उस समय लाहौर पाकिस्तान का भाग बन चुका था तथा हिंदुओं और मुसलमानों में बहुत वैमनस्य था।

**गांधीजी का अनशन** — जब गांधीजी ने देखा कि वाता वा किसी पर अगर नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि सरकार में भी कुछ लोग ऐसे हैं, जो उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं तो उन्होंने अनशन का आश्रय लिया। कुछ लोग यह समझते थे कि अनशन सरकार बल्लभ भाई पटेल के विरुद्ध है, जो गलत मंत्री थे। इस संबंध में गांधीजी ने यह कहा 'सरदार अपने क्षेत्र में बहुत बड़े हैं और बड़े योग्य प्रशासक हैं। यह सच है कि सरकार ने मेरे अधीन राजनैतिक शिक्षा का आरंभ करने की नम्रता दिखाई, परंतु जसा कि उन्होंने मुझे बताया, ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि उन दिनों भारत में जिस प्रकार का मादक जीवन प्रचलित था और जिस प्रकार की राजनीति चलती थी, उसमें वे भाग नहीं ले सकते थे। जब उनके हाथ में शक्ति आई, तो उन्होंने देखा कि वह अहिंसा के तरीकों का सफलता के साथ कार्यवाही नहीं कर सकते। पहले वह इसी अहिंसा से बहुत भारी सफलता प्राप्त करते थे, यह दूसरी बात है। रही मेरी बात, मैंने यह आश्वासन दिया है कि मैंने तथा मेरे साथ के लोगों ने जिसे अहिंसा का नाम रखा था, वह अपनी वस्तु नहीं थी, बल्कि वह उसकी एक क्षीण प्रतिमा थी, जिसका नाम 'सविनय अवज्ञा' था। स्वाभाविक रूप से 'सविनय अवज्ञा' शासकों के लिए किसी मतलब की नहीं है।"

उन्हीं बाद उन्होंने कहा "जैसा कि मैंने बहुत ही साफ शब्दों में कहा है, मेरा उद्देश्य भारत में रहने वाले मुस्लिम अल्पसंख्यकों के पक्ष में है और इसलिए यह आवश्यक रूप से भारत के हिंदुओं और सिखों और पाकिस्तान के मुसलमानों के विरुद्ध है। इसी प्रकार यह पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए है जिस तरह कि यह भारत के



मुसलमान अल्पसंख्यकों के लिए है।”

**पचपन करोड़ का मामला**—भारत सरकार ने इस अनशन पर एक विज्ञापित प्रकाशित करते हुए कहा कि सरकार जहां तक संभव है, राष्ट्रीय कल्याण को ध्यान में रखते हुए ऐसे सब कारणों को दूर करने के लिए उत्सुक है जिनसे साम्प्रदायिक घमनस्प्य पैदा होते हैं। गांधीजी के अनशन के तीसरे दिन भारत सरकार ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपये देने का निश्चय कर लिया।

55 करोड़ का यह मामला क्या था इस सम्बन्ध में थोड़ी सी बातें बता दें कि जरूरत है। जिस समय भारत का विभाजन हुआ था, विभाजन को कार्यान्वित करने के लिए एक विभाजन परिपद का निर्माण हुआ था। कुल नगद धन 375 करोड़ रुपये था, जिसमें से पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरण के तिन 20 करोड़ रुपये दे दिए गए। यह रकम पूरी नहीं थी और बाढ़ का हिसाब बित्ताब के बाद यह नियम होना था कि पाकिस्तान को कुल बित्तों की रकम देनी चाहिए। अतः नतीजतन यह तय हुआ कि 55 करोड़ रुपये दिए जान चाहिए। यह नियम दोनों पक्षा के प्रतिनिधियों की राय से नवम्बर के अन्तिम सप्ताह में हुआ। उन्ही तिनो बरगौर पर पाकिस्तान का हमला चल रहा था। इसके अलावा कुछ ऐसे मामले भी थे जिनके अंतर्गत पाकिस्तान से भारत को धन राशि मिलनी थी। पाकिस्तान इन रकमा को देने में आनाकानी कर रहा था। इसलिए भारत सरकार ने यह तय किया कि जब तक सारे मामलों पर अन्तिम फैसला न हो जाए और बरगौर का मामला सुलझ न जाए, तब तक पाकिस्तान को कोई रकम नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने यह कभी नहीं कहा कि वे देय धन राशि देने से इन्कार करते हैं, परन्तु वे तब तक चुप बने रहे जब तक कि 55 करोड़ रुपये वाला नियम लिखित रूप में नहीं आ गया। यही नहीं, इसमें तुरन्त बाढ़ उठाने यह कहना शुरू किया कि 55 करोड़ रुपये तो भारत का धन ही हैं, बाकी मामलों फिर देख जाएंगे। इसके पक्षस्वरूप भारत सरकार ने 55 करोड़ वाली धन राशि का भुगतान स्थगित कर दिया। इस पर पाकिस्तान के वित्तमंत्री ने इस आक्रमण करने के बराबर बताया। पण्डित नेहरू ने एक सावजनिक बयान देते हुए कहा ‘ऐसी परिस्थितियाँ मध्य रात्रि के दूधरे रात्रि की धन राशि का भुगतान रद्द कर देना है परन्तु हमने उस अर्थ में किसी प्रकार भी भुगतान बन्द नहीं किया है। जो कुछ हमने कहा, उसका मतलब यह है कि हम उस समयोठे को मानते हैं पर सब बातों को मिलाकर एक पूरा समयोत्तर होना चाहिए और हम उसे पूर्ण तरीके से मानेंगे।’

**ममता का नतीजा**—6 जनवरी 1948 का गांधीजी ने इस प्रश्न पर साइमन कमेटी के सदस्यों की और साइमन कमेटी ने कहा कि यदि भारत सरकार ने 55 करोड़ की रकम का भुगतान स्थगित कर दिया, तो यह भारत सरकार का पहला असम्मानजनक काम होगा। इस सम्बन्ध में पाकिस्तान तथा भारत में भिन्न भिन्न रायें रहीं, परन्तु गांधीजी ने यही राय कायम की कि पाकिस्तान चाहें जो कुछ करें हम 55 करोड़ रुपये दे देंगे। भारत सरकार ने अब तक दूसरा दरा दिया था, परन्तु गांधीजी के अनशन के तीसरे दिन 55 करोड़ रुपये का भुगतान पाकिस्तान का कर दिया गया।

**भारत सरकार की उदारता**—बहुत ही जल्दी ही गांधीजी की यह उदारता ऐतिहासिक भी, क्योंकि उन्होंने जबल अपना मत जनता के सामने रखा और नेहरू सरकार को मजबूर कर दिया कि वह इस सम्बन्ध में पूरी उदारता में काम लें। उन्होंने सरकार के उदार नियम का अभिनय करते हुए एक बयान दिया जिसमें उन्होंने

वहा 'किमी भी जिम्मेदार सरकार के लिए एक निश्चित और इच्छाकृत नीति को बदल सकना आसान नहीं है। फिर भी हमारे मंत्रिमण्डल ने, जो हर तरीके से जिम्मेदार है, बहुत ही सोच समझ और साथ ही निश्चिन्त संकल्प को बदल दिया है। मैं जानता हूँ कि समार की सारा जातियाँ इस काय का स्वागत करेंगी और मैं यह कहूँगा कि हमारा मंत्रिमण्डल ने यह काय करके बहुत ही श्रेष्ठ आचरण का परिचय दिया है।"

मुस्लिमतोषण नहीं, आत्मतोषण — गांधीजी ने यह भी स्पष्ट किया कि इसे मुस्लिमतोषण न कहा जाए, बल्कि यह आत्मतोषण है। उ होने कहा कि एक बहुत बड़ी जनता का प्रतिनिधि मंत्रिमण्डल कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकता, जिससे कि वह विचारहीन जनता की वाटवादी से भटक जाए। जबकि चारों तरफ पागलपन का वातावरण है, क्या यह जरूरी नहीं कि हमारे प्रतिनिधि अपने दिमाग ठीक रखें और राष्ट्र की न्याय को घटान से टकराकर टूटने से बचाए।"

प्राथना सभाओं में हुल्लड़ — इसी प्रकार जब मितम्बर, 1947 में दिल्ली या उनके आस पास बिहार में भगड़े हुए, तो महात्माजी ने मुसलमानों को बचाने की चेष्टा की। इन सारी बातों के फलस्वरूप हिंदुओं में एक बग ऐसा उत्पन्न हुआ गया, जिसने हर कदम पर गांधीजी का विरोध करना शुरू किया, यहाँ तक कि उनकी प्राथना सभाओं में भी लोग उन से बुरी तरह पश आने लगे। कई बार तो सर्वधर्ममूलक प्राथना बंद ही कर लेनी पड़ी। उनकी प्राथना की विलोपना यह होती थी कि उसमें कुरान में आपत्तें, ईगई गीत, वैद की भ्रूचाएँ आदि सभी पड़ी जाती थी। लोग और तो सब कुछ सह लेते थे, पर कुरान की आयतों पर भगड़ा करते थे।

गांधीजी की हत्या — इन परिस्थितियों में एक घमांस के हाथों महात्माजी की हत्या होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पहले ही गांधीजी पर बम से एक हमला हो चुका था। तेइलकर के अनुसार "30 जनवरी की शाम को चार बजे सरदार पटेल गांधीजी से मिले और उनके साथ एक घंटा रहे। हाल के उपवास तथा अन्य कारणों से सरदार पटेल और जवाहरलाल ने जो मतभेद हुए थे, उससे वह चिंतित थे। वह चाहते थे कि दोनों नेता कंधे से कंधा मिलाकर चलें। संध्या समय की प्राथना के बाद नेहरू और आजाद उनमें मिलने वाले थे। पांच बजे गांधीजी ने घड़ी निकाली और सरदार से बोले — 'प्राथना का समय हो गया।' वह पांच बजकर दस मिनट पर अपने कमरे से निकले और टहलते हुए पास के मैदान की प्राथना सभा की ओर गए। उनकी पीठिया मनु और आभा उनके बगल में थी। वह उन दोनों का सहारा लेकर चल रहे थे। दोनों तरफ सड़े लोगों के बीच होते हुए वह प्राथना सभा की ओर जा रहे थे। अब वह पीठियों के कंधे पर से हाथ हटाकर लोगों के नमस्कार का उत्तर दे रहे थे। एकाएक भीड़ में एक हिंदू नाथुराम गोडसे भीड़ को कुहनी मारकर चीरता हुआ आया। मनु ने समझा कि वह गांधीजी के चरण छूना चाहता है, इसलिए उसने उसको रोका, और पीछे करना चाहा। पर गोडसे ने मनु का हाथ झटककर छुड़ा लिया फिर हाथ जोड़कर, मानो चरण स्पर्श के लिए आतुर हो, एक के बाद एक सात गोलियों वाली पिस्तोल से तीन गोलियाँ चलाइ। सभी गोलियाँ गांधीजी के दाहिने सीने पर लगीं। दो गोलीयाँ शरीर छूँकर निकल गईं, तीसरी फँफड़े में घुस गई। पहली गोली लगते ही उनके चलते हुए पैर रुक गए। नमस्कार में उठे हाथ धीरे धीरे थिथिल होकर नीचे आ गए। अब भी वह परो पर सड़े थे, परन्तु इसके बाद जब दूसरी और तीसरी गोली दनदनाई, तो वह गिर पड़े। उनके मुँह से निकला 'हूँ राम'। चेहरा पक पड़ गया। श्वेत वस्त्र पर सान घबरे आ गए। लोगों ने उन्हें उठाया और भीतर ले जाकर उस गद्दे पर रख दिया

जहाँ बैठकर वह काम करते थे। फौरन उनकी मृत्यु हो गई।”

**हत्याओं का वक्तव्य** — ११ नवम्बर 1948 को 'यायमूर्ति आत्माचरण' ने लाल किले के अन्दर बंद नाथूराम विनायक गोडसे से नियमानुसार कहा—“तुम सारी गवाही सुन चुके हो तुम्हें कुछ कहना है?”

इस पर गोडसे ने एक लिखित बयान पढ़ना चाहा। इस्तगास की आपत्ति पर भी गोडसे को बयान पढ़ने की अनुमति मिल गई। गोडसे उत्तेजित नहीं था, यद्यपि इस बीच इस हत्या की सारे ससार में बहुत निन्दा हो चुकी थी। उसने कहा कि यद्यपि सारे लोगो ने मेरी निन्दा की है, पर मुझे निश्चय है कि इतिहास दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा।

पुणे के पत्र 'हिंदू राष्ट्र' के सम्पादक नाथूराम विनायक गोडसे के अतिरिक्त सात और व्यक्ति इस घणित पदपत्र में शरीक थे—नारायण भाटे विष्णु करवरे, शंकर किस्तीया, दिगम्बर बडग, मदनलाल पट्टवा, गोपाल गोडसे और दत्तात्रेय परचुर।

**बहुत साल बाद** — मई 1983 के 'सोसायटी' पत्र के एक खोजी लेखक मधु बेल्लुरी के अनुसार उस समय तब गांधी हत्या मुकदमे के मदनलाल पट्टवा, गोपाल गोडसे और दत्तात्रेय परचुरे जीवित थे। मदनलाल का कहना था कि उनके पिता काश्मीरी लाल कांग्रेसी थे, फिर भी वह विभाजन के दंगों के दौरान बहुत मारे पीटे गए थे और अस्पताल में पड़े थे। पिता को उस रूप में देखकर ही वह मुसलमानों पर हमला करने लगा। उसने कहा कि ग्वालियर में इस प्रकार के कामों के लिए अच्छा मौका था। उसका तो यहाँ तक कहना था कि बड़े बड़े नेता उसकी महायत्ना कर रहे थे।

**मुहराबर्दी को भी मारना था** — मदनलाल के अनुसार जब महात्मा जी द्वारा अनशन करके पाकिस्तान को पकड़न करोड़ दिनाने की खबर आई तब उनकी हत्या का कार्यक्रम जोर पकड़ने लगा। नाथूराम गोडसे, उसका भाई गोपाल गोडसे करकरे किशतया योजना बनाने लगे। उस पत्रकार मधु ने कहा “हम मुहराबर्दी और गांधी को मारना चाहते थे नेहरू को नहीं। महाना सरकारी प्रचार था कि हम नेहरू का मारना चाहते हैं। तीन दिन तब तिल्ली क मेरिना होटल में जलपनाए चतनी रही। मदनलाल को (जो उस समय 20 वर्ष का युवक था) मराठी ब्राह्मण इम योग्य न थे समझत थे कि उस पर पूरा विश्वास किया जाए। उसमें कहा गया कि तुम्हारा काम यह होगा कि बम फेंको, जिसके धड़ारे से भगदड़ मच जाए। लोगों का ध्यान जब धड़ावे की तरफ जाएगा, तब हम गांधी पर हमला करेंगे।

**हत्या का पहला कार्यक्रम** पढ़ने कार्यक्रम में नाथूराम और भाटे केवल परिदृश्य ही। गोपान पढ़ने बम फेंकना और फिर करकरे भीड़ में एक और बम फेंकना। उस योजना में बडग महात्मा गांधी पर गोली चवानवाला था। 20 जनवरी 1948 को यह सब होना था। घडाका तो हुआ, पर श्रम योग अपना निश्चित कार्य न कर सके। मदनलाल पकड़ लिया गया। उसने अनुसार पुलिस ने उसके मनद्वार में मिच डाली, उसे बफ की गिटनी पर प्रत्या, ऊपर से सिर पर चीनी का रंग डाला ताकि चीटिया रेंगे। उसे कम्यन उठाकर रेल के स्टेशन तथा मावजनिक् स्थानों पर घुमाया गया। मदनलाल ने सब से साथ कहा “मैंने स्टेशन पर गोडसे और करकरे को बम्बई की गाडी में चढ़ते देखा, पर उन्हें पहचाना नहीं।”

**हत्या से खोजी** — दस दिन बाद जब महात्मा जी हत्या की खबर मदनलाल को मिली तो उसका कहना था उस खुली हुई थी। वह 16 मान जेल में रहकर 1964 के 14 अक्टूबर को छूट चुका था। पत्रकार मधु मदनलाल के साथ एटनबरो की किम

गांधी देखने गया था। फिल्म देखते हुए मदनलाल ने एक दीवार देखकर उत्तेजित स्वर में कहा—“मैंने वहाँ बम रखा था।” फिल्म के गोडसे को देखकर उसने कहा—“यह गोडसे नहीं सगता। गोडसे ने तो खाकी कमीज पहन रखी थी।” मदनलाल को यह भी गिनायत थी कि फिल्म में गांधी की गलतियाँ जैसे खिलाफत की पैरवी (जब कमाल ब्रानुक ने खलीफा की परम्परा को एक झटके में खतम कर लिया) इविन के साथ समझौता (जिसमें वह ‘उल्लू’ बने) नहीं दिखाई। इसके अलावा प्राथना सभा में बहुत कम लोग दिखाए गए जबकि वास्तविक प्राथना सभा में हजारों लोग थे।

पत्रकार मधु गोपाल गोडसे से मिले। गोपाल द्वितीय महायुद्ध में भाग ले चुका था। लौटकर वह पुणे के किरकी आडनेस कारखाने के बाहर काम में लग गया। प्रथम हत्या प्रयास में वह घटनास्थल पर था। पत्रकार मधु को लगा कि गोपाल में अब भी पुराना पागलपन मौजूद है। वह बोला—“मैं मानता हूँ गांधी महापुरुष थे। उन्होंने कई शान सिद्ध किए। पर वह इन सिद्धियों के कारण नहीं, बल्कि जनता को धोखा देने के लिए मारे गए। उन्होंने उपवास की जबदस्ती से पाकिस्तान को 55 करोड़ दिलाए। विम समय देश का विभाजन हुआ, उस समय उन्होंने अनशन क्या नहीं किया? क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि मैरी लाश पर ही पाकिस्तान बन सकता है?”

गोपाल ने कहा कि सब देशों ने गांधी की भस्म अपनी नदी में फेंके जाने की अनुमति दी, पर मुस्लिम होमलैंड पाकिस्तान ने भारतीय राजदूत श्री प्रकाश को सिंधु नदी में भस्म नहीं डालने दी, जबकि महात्मा जी पाकिस्तान के लिए ही मरे। गोपाल के अनुसार ‘हे राम’ भी कांग्रेसियों की जालमाजी है।

गोपाल के अनुसार नाथूराम ने अपनी राख सिंधु नदी में ही क्यों डलवानी चाही, —क्योंकि वही एक नदी है जो पवित्र बची है।” यह नाथूराम न फासी के दिन कहा था।

एक से अधिक अर्थों में ऐतिहासिक — महात्मा गांधी की हत्या एक से अधिक अर्थों में ऐतिहासिक है। गणेशशंकर विद्यार्थी मुस्लिम धर्मा धो के हाथों मारे गए थे जबकि महात्मा एक हिंदू के हाथों मारे गए। यह भी एक संयोग है कि वर्मा के महान नेता आग सान भी इसी प्रकार मारे गए थे। जिं ता पाकिस्तान बनते समय कैंगर के शिकार थे। भारत के नेताओं को इस रोग की घात मालूम नहीं थी, पर ब्रिटिश गुप्तचर विभाग को मालूम थी। मरु जल्दी हा गई और उसमें पाकिस्तान के राजनीतिज्ञों का हाथ बताया जाता है। लिआकत अली खा की भी हत्या ही हुई। फिर जिसने हत्या की थी, उसकी भी हत्या कर दी गई। इस प्रकार यह हत्या रहस्य ही रह गई। और इस हत्या के बाद से पाकिस्तान में सैनिक शासन हो गया।

गांधी युग — महात्मा जी ने कांग्रेस को आमूलचूल परिवर्तित कर उसे एक सशस्त्री सभा बना दिया था। यह सही है कि कांग्रेस के आंदर कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि गांधीजी को उससे अलग हो जाना पड़ा, परंतु मनाकर उनको लौटाया भी जाता रहा क्योंकि कांग्रेस में अगर किसी के पाम जनता के मन की चामी थी तो यह उही पाम थी। गांधीजी के विरुद्ध पहला विद्रोह तब हुआ, जब असहयोग आंदोलन अचानक बंद कर लिए जाने के बाद चितरजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज्य पार्टी का उद्घाटन हुआ। कांग्रेसी नेताओं की यह दूरदर्शिता रही कि स्वराज्य दल कांग्रेस का एक विभाग बना दिया गया। इसके बाद सुभाष का विद्रोह हुआ, उसका अन्त के कांग्रेस से निकलने में हुआ। द्वितीय महायुद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार से प्रश्न पर कांग्रेस और महात्मा जी में मतभेद हुए, जिससे महात्मा जी कुछ अ

पर इसका भी मत 1944 में 'करो या मरो' का नारा देकर सशाम छिड़ते ही हो गया, इसलिए यह कहना सच्चा उचित है कि कांग्रेस का यह साग युग गांधी युग था। अवश्य ही इस दौरान कांग्रेस के अंदर कांग्रेस समाजवादी जैसे दल का उदय और बाहर प्राति कारी विस्फोट होते रहे जिनके मील के पत्थर हैं, काकोरी, लाहौर, मेरठ पडयंत्र और आजाद हिन्द फौज।

देश में कांग्रेस का बोलबाला—स्वराज्य के बाद देश में कांग्रेस का रूप बदल गया। वह अब आंदोलनकारियों का समुक्त मोर्चा न रहकर शासनाखंड दल हो गया। महात्मा गांधी यद्यपि स्वयं साल भर में उठ गए, परन्तु इसका कांग्रेस सत्था पर विशेष असर नहीं पड़ा। 1947 से प्रायः आज पयन्त देश में कांग्रेस का ही शासन चला आ रहा है। बीच में दो-तीन वर्ष के लिए कांग्रेस गद्दी से अलग रही, पर उस दौरान भी जनता पार्टी के जो लोग शासनाखंड रहे, उनमें से कुछ को छोड़कर शेष सभी जैसे मोरारजी देसाई चरणसिंह आदि सब कांग्रेसी ही थे। यहाँ भी यह बात महत्वपूर्ण है कि इनमें करीब-करीब सभी कांग्रेस से अलग होने पर भी गांधीजी के ही शिष्य होने का दावा करते रहे। भारतीय जनता पार्टी जैसे दक्षिणपणियों ने भी गांधीवादी कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया। देखा जाए तो जो लोग स्वराज्य के बाद ही कांग्रेस विरोधी दल बनाकर सामने आए, वे सब भी भूतपूर्व कांग्रेसी ही थे। कम्युनिस्ट नेता नम्बुदरीपाद भी भूतपूर्व कांग्रेसी थे।

सब कहा जाए तो गांधीवाद अब तक जीवित है और बहुत सारे लोग यह भी मानते हैं कि सच्चे मानों में गांधी की आवश्यकता आज भी है। अनेक देशों में उनके सिद्धांतों तथा कार्यक्रमों को अपनाकर राजनीतिक सदाइया सड़ने का प्रयास किया गया है, जो बहुत कुछ सफल भी रहा है। फिर भी यह मानना होगा कि स्वयं गांधीजी के न रहने से मानों कांग्रेस की आत्मा ही नष्ट हो गई और उन्हीं के अनुयायियों द्वारा बहुत सी गलतियाँ भी की जाने लगीं। कहा जा सकता है कि गांधीजी जीवित होते तो उन्हें माफ नहीं करते। इस सम्बन्ध में अग्रणी पत्रकार दुर्गादास ने तभी लिखा था '30 जनवरी 1948 को गांधी युग का अंत हो गया और एक ऐसी शून्यता पग हो गई, जो कभी नहीं भरने की। गांधी वह ब्रह्मान थे, वह आत्मिक शक्ति थे, जिस पर कांग्रेस स्थिर थी और जनता पर उसका दबदबा कायम था।'

निरे कांग्रेसी बनाम पदधारी कांग्रेसी—स्वराज्य के बाद कांग्रेस या कांग्रेसी शासनाखंड हुए और इसका परिणाम यह हुआ कि पदधारी और पदहीन कांग्रेसियों के दो भेद हो गए। पदहीनों में कुछ कांग्रेस में जलम हो गए और उन्होंने अपनी सत्थाएँ बना लीं। जो कांग्रेस में रहकर भी पद पा सके उनका महत्व उन कांग्रेसियों के मुकाबले में घट गया जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, सामान्य विधायक या किसी निगम आदि के अध्यक्ष बने। यह स्वाभाविक होते हुए भी ठीक नहीं था क्योंकि इसके अर्थ अनेक दुष्परिणाम हुए। वैसे यह शुरुआत पहले ही हो गई थी जब स्वराज्य के पहले कांग्रेसी अध्यक्ष कृपलानी ने इस कारण अध्यक्ष पद में इस्तीफा दे दिया था कि सरकार में बैठे कांग्रेसी नेता उन्हें महत्वपूर्ण मंत्रियों में भी नहीं बुलाते थे। इसके बाद पुरुषोत्तम दास टंडन को भी कांग्रेसी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि कृपलानी के अनुसार नेहरू के साथ उनकी नहीं बनी। ये दोनों इस्तीफे विचारधारागत नहीं थे जसा कि सुभाष का इस्तीफा था।

जब कही सशामकारी दल सत्ताखंड हो जाता है, तो प्रायः ऐसा ही होता है। सुभाषदास जी ने कहा है 'प्रभुता पाय काहि मद नाही'। परन्तु यह अटल नियम भी नहीं

है कि सत्ता प्राप्त होत ही पतन हो ही जाए। आधुनिक बाल में हम देखते हैं—लेनिन को भी मित्र का सत्तारूढ़ होने पर किसी अर्थ में भी पतन नहीं हुआ। स्वयं महात्मा गांधी गद्दी पर नहीं बैठे, और यदि वे जीवित रहते तो भी नहीं बैठते। वास्तव में वे जब तक सत्तारूढ़ नेहरू और पटेल पर महाशक्ति और अकुश के रूप में रहे। उनकी हत्या का कारण हुई कि वह अपनी घमनिरपेक्षता को इस हद तक ले गए कि लोग उन्हें गलत समझने लगे।

दुसरी रंग—यहां हम दश की एक दुसरी रंग पर पहुंच जाते हैं। कांग्रेस शुरू में, यहाँ तक कि जब उसमें जो हज़ूर और खरखवाह किस्म के लोगो का बोलबाला था, ब्राम्हणों का बहुत महत्त्व देती थी। गांधी से पहले ब्रम्हदीन तैयबजी 1887 में, मुहम्मद रहीमतुल्ला सयाफी 1886 में, नवाब सैयद मुहम्मद बहादुर 1913 में और हुसैन इमाम 1918 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर चुके थे। दादाभाई नौरोजी ने 1906 में तथा ऐनी बेसेन्ट ने 1917 में इस आसन की शोभा बढ़ाई थी। जब गांधी यहाँ आया तब कांग्रेस की गद्दी पर हकीम अजमल खा 1921 में, मुहम्मद अली 1923 में, एम० ए० असारी 1927 में बैठ चुके थे। आज़ाद 1940 से स्वतंत्रता प्राप्ति तक फिर बराबर अध्यक्ष रहे। यह चुनौती बार-बार दी जाती रही, कि आखिरी दशक को छोड़कर कांग्रेस के अंदर लीग से अधिक मुस्लिम सदस्य रहे। (यद्यपि लीग ने कभी अपने मन्सूमा की मदद नहीं बताई)। 1937 के प्रांतीय शासन के युग में लीग सिकंदर हुसैन और फाजुल हक के प्रांतीय दलों के सामने नहीं ठहर पाई और अपनी दाल पत्ती न दलबंद जिन्ना इंग्लैंड में बसने चले गए परंतु फिर भी लीग को महत्त्व दिया जाता रहा।

## सत्तारूढ कांग्रेस का नेहरू युग

स्वतंत्र भारत की पहली सरकार के नेता श्री नेहरू थे। छह महीने के भीतर ही महात्मा गांधी नहीं रहे, और सरदार पटेल भी लगभग तीन वर्ष तक ही उनका साथ दे सके। इसलिए स्वतंत्र देश के नवनिर्माण का प्रायः पूरा ही दायित्व नेहरू जी पर आ पड़ा। यह बहुत कठिन समय था परन्तु उन्होंने बड़े परिश्रम तथा योग्यता से राष्ट्र के भावी विकास के लिए आवश्यक सभी बातों की आधारशिलाए रख दी। उनके मार्गदर्शन में संविधान बना, योजना आयोग ने काम आरम्भ किया, महत्वपूर्ण उद्योग खड़े किए गए, विविध क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए संस्थाएँ स्थापित की गईं, समाजवादी ढाँचे को विकास का लक्ष्य स्वीकृत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उन्होंने गुट निरपेक्ष आन्दोलन की जबरदस्त धुरिआन की। सनह वर्ष तक वे इन सब कार्यों का संचालन करते रहे।

**संविधान सभा—** भारत के लिए एक यायपूर्ण संविधान बनाने की माँग या लक्ष्य बहुत पुराना कहा जा सकता है। क्रांतिकारियों ने इस विषय पर जो चिन्तन किया, वह 1923 में रचिन हिन्दुस्तान प्रजातांत्रिक संघ के संविधान में प्रतिफलित था। इसमें बताया गया था कि फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ हिन्दुनाइटेड स्टेट्स ऑफ इण्डिया' यानी भारत के संयुक्त राष्ट्रों का प्रजातांत्रिक संघ स्थापित करना हमारा लक्ष्य है। सरदार भगतसिंह ने इसमें 'समाजवादी' शब्द जोड़कर इसे पूर्णता तक पहुँचा दिया था।

कांग्रेस का अन्दर भी संविधान सभा की माँग बहुत प्रबल थी। 1934 की कांग्रेस कार्यसमिति के एक प्रस्ताव में यह कहा गया 'सरकारी स्वतंत्रता का एकमात्र स्थापना जनक विकल्प यह है कि वालिंग सावजनिक मताधिकार या जहाँ तक हो सके, उनका आस पाम के ढग से चुनी हुई संविधान सभा होनी चाहिए। यह हो सकता है कि महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक क्षेत्र अपने लोग के मत में अपने प्रतिनिधि चुनें।' उसके बाद 1937 में फैजपुर कांग्रेस, 1938 में हरिपुरा कांग्रेस, और 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस में यह माँग दुहराई जानी रही। 1945 के शिमला सम्मेलन में भी कांग्रेस ने यही माँग की थी।

धर्मनिरपेक्ष परम्परा को कायम रखते हुए स्वतंत्र भारत में डॉ० जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति बने और हिदायतुल्ला पहलू यायाधीश तथा फिर उपराष्ट्रपति रहे। यह पुस्तक लिखते समय जानी जलमिह राष्ट्रपति हैं। संविधान सभा ने 9 दिसम्बर 1946 को अपना काम शुरू किया था। मुस्लिम लीग ने इसका बायकाट यह कहकर किया कि लीग तो अलग राष्ट्र चाहती है। कई माला तक संविधान सभा समझ के रूप में रही यानी उस दृष्टि से भारत की यह पहली सभा भी रही। इसीने 14 अगस्त की मध्यरात्रि में ब्रिटिश सरकार से शक्ति ग्रहण की। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, उसके बनने में करीब दो साल लगे। 1949 की 26 नवम्बर

संविधान का प्रारूप तैयार होकर पारित हो चुका था। 1952 में नए संविधान के अनुसार चुनाव हुए।

**संविधान में सब धर्मों की समानता—**1950 को जो संविधान लागू हुआ, उसमें सब धर्मों के मानने वालों को समान अधिकार दिए गए। पाकिस्तान के साथ तुलना करने पर पता चलेगा कि वहाँ एक तो अधिकांश समय सैनिक शासन रहा, दूसरे भूटो के जमाने (1971-1977) जब एक संविधान कुछ हद तक चला, उसमें भी गैर-मुसलमानों के लिए राष्ट्रपति आदि बनने का कोई अधिकार नहीं था। हिंदुओं, ईसाइयों या पारसियों का तो यह अधिकार दिया ही नहीं गया, अहमदियों को भी 1974 में एक कानून के द्वारा मुसलमान मानने से इंकार कर दिया गया। अहमदिया कुरान और हजरत मुहम्मद में आस्था रखते हैं, परंतु वह यह नहीं मानते कि हजरत अंतिम पैगम्बर हैं। वे मिर्जा गुलाम अहमद को मानते हैं और उन्हें 'खलीफतुल मसीह' कहते हैं। पाकिस्तान में अहमदियों के विरुद्ध आंदोलन आरम्भ से ही चल रहा है। 1953 में अहमदियों के विरुद्ध दंगे हुए और ख्वाजा नाजिमुद्दीन को सैनिक कानून लागू करके रण राकना पड़ा था। तब से बराबर अहमदियों का दमन जारी है। बहुत से अहमदिया पाकिस्तान से भागकर पारसार्थी हो गए। वहाँ यायभूति मुनीर की अध्यक्षता में इस विषय की मीमांसा के लिए एक आयोग बनाया गया। उन्होंने उपसंहार में कहा कि कबीर बात यह है कि कुछ मुस्लाओ के अनुसार जो असली मुसलमान हैं, वही दूसरे मुस्लाओं के अनुसार काफिर हैं।

**भारतीय संविधान में स्थिया—**भारतीय संविधान में स्त्रियों को भी हर क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार दिया गया। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि कई यूरोपीय देशों में भी स्त्रियों का मतदान का अधिकार भारत के बाद मिला। पाकिस्तान में न तो मतदान है, न स्त्रियों को विवाह, तलाक, पर्दा, गवाही के मामले में कोई अधिकार प्राप्त है।

**योजना आयोग—**पराधीन भारत में ही कांग्रेस के नेताओं का ध्यान योजना बनाकर उन्नति करने की ओर गया था। कांग्रेस ने 1938 में नेहरूजी की अध्यक्षता में (उन समय सुभाष कांग्रेस के अध्यक्ष थे) एक योजना समिति बनाई थी। उसकी काफी शक्ति रिपोर्ट निकली थी जो कई जिल्लों में छपी। दुर्भाग्य यह रहा कि प्रतिवेदन तैयार हो गए पर इसी बीच नेता जेल पहुँच गए। नेहरूजी ने 1 मई, 1940 में कहा था स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राष्ट्र हमारा लक्ष्य है—ऐसा राष्ट्र जिसमें राजनैतिक, आर्थिक स्वतंत्रता होगी। योजना का क्षेत्र उत्पादन वितरण, उपभोग, विनियोग, व्यापार, आय, सामाजिक सहायता तथा उन अन्य राष्ट्रीय क्रियाकलापों तक विस्तृत होगा जो परस्पर एक-दूसरे का प्रभावित करते हैं। योजना का उद्देश्य सारी जनता के भौतिक और सांस्कृतिक मानवता का उन्नयन है।"

स्वराज्य के बाद सरकार ने ज्यों ही विभाजन की दुखद भारवाट से छुट्टी पाई, योजना का क्रम चालू हो गया। 1948 में सरकार की औद्योगिक नीति की घोषणा करते हुए कहा गया कि युद्धोद्योग, अणु ऊर्जा, रेल, कोयला, लोहा-इस्पात, हवाई जहाज उद्योग तथा क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में सरकार का लगभग एकाधिकार रहेगा।

अप्रैल 1950 में कांग्रेस अध्यक्ष की पुकार पर प्रदेश कांग्रेस कमेटियों तथा मुख्य निकायों का जो सम्मेलन हुआ, वह योजना सम्मेलन कहलाया और यह अधिवेशन गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में हुआ। यही से भारतीय योजना आयोग की नींव पड़ी। 1951-52 के प्रथम आम चुनाव के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने अपनी योजनात्मक आर्थिक



नीति का पुनरालोचन किया। यह स्पष्ट कर दिया गया कि निजी उद्योग रहण परन्तु उर्ध्व सामाजिक क्षेत्र व साथ तालमेल रखकर चलना पड़ेगा।

शीघ्र ही पहली पंचवर्षीय योजना (1951-55) देश के सामन आई, परन्तु वह बाद की योजनाओं की तुलना में बहुत छोटी थी। योजना की एक तिहाई रकम खेती में इस कारण लगाई गई कि विदेशों से खाद्य का आयात रोका जाए। परिवहन और संचार में 23 प्रतिशत व्यय किया गया। पहली योजना काल में राष्ट्रीय आय 18 प्रतिशत बढ़ी। यह और बढ़ती यदि इसी बीच आबादी 6 प्रतिशत न बढ़ जाती। आबादी की वृद्धि को रोकने के लिए दूसरी योजना में जोरा के साथ परिवार नियोजन की व्यवस्था की गई, जो बाद की योजनाओं में बढ़ती गई। आबादी में वृद्धि हमारी उन्नति में सबसे अधिक बाधक है।

देशी राज्यों वाला बखेड़ा—यहां हम यह बना दें कि 1947 में जब भारत को स्वाधीनता मिली तो दो टुकड़ों में बांटने के अतिरिक्त विदेशी शासक हमारे लिए दो समस्याएँ और छोड़ गए थे। भारत में सफ़रमग चौधई इनाके ऐसे थे जिनमें देशी राजाओं का शासन था। इन राजाओं के साथ अंग्रेजों के सन्धिपत्र थे, जिनकी विशेष शर्तों के अनुसार वे अंग्रेजी शासन के अधीन थे। ये देशी राज्य आकार और जनसंख्या की दृष्टि से एक गांव से लेकर पूरे प्रांत जैसे हैनराबाद निरुवाकर आदि तक थे। यदि अंग्रेज चाहते, तो कह सकते थे कि भारत सरकार हमारी उत्तराधिकारी होने के नाते सर्वोपरि है परन्तु उन्होंने ऐसे व्यक्तियों लिए जिनके अस्पष्ट वातावरण में राजाओं और नवाबों को यह गलतफहमी हो गई कि वे चाहे तो स्वतंत्र रहे और चाहे तो भारत या पाकिस्तान किसी में भी शामिल हो जाए।

हम बता चुके हैं कि कश्मीर का हिन्दू राजा इसी धारणा के कारण स्वतंत्र राजा बनने का स्वप्न देख रहा था कि पाकिस्तान ने उस पर हमला कर दिया। तब उसने भारत की मदद मांगी। भारत ने यह मुद्दा सुनी, पर इस बात पर कि वहां जनता का पानी जनता की प्रतिनिधि नेशनल काँग्रेस और उनके नेता शेख अब्दुल्ला का शासन हो। राजा को यह मानना पड़ा और अन्त तक गद्दी भी छोड़नी पड़ी। स्मरण रखने की बात है कि भारत ने मुस्लिम प्रजा का पक्ष लिया न कि हिन्दू राजा का।

प्रजामण्डल—अब देशी राज्यों का विलय तरह तरह के पैंचों के अधीन हुआ। सबसे बड़ा पैंच था प्रजामण्डला का। कांग्रेस ने देशी राज्यों के आन्दोलन को अपने में अलग रखा था परन्तु उनमें सक्त्र प्रजा आन्दोलन प्रवल था। कई जगह प्रजामण्डल इतने शक्तिशाली थे कि वे चाहते तो बिना बाहरी मदद के अपने राजा या नवाब को आसमान दिखा सकते थे। अंग्रेजों के तमाम में राजा या नवाब की सहायता के लिए ब्रिटिश भारत से फौज आ सकती थी, परन्तु अब स्वराज्य के बाद स्थिति बदल गई थी। कांग्रेस के नेता सरदार पटेल इस बात को समझते थे। जब उड़ीसा के राजा विलय के विपक्ष में कुछ बोलने हरे कृष्ण महताब और सरदार पटेल ने भट्ट कह दिया—'यदि आप हमारे प्रस्ताव को नहीं मानते तो हम आपके राज्य में कानून और व्यवस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते आप जानें और आपका काम जाने।' नतीजा यह हुआ कि राजा साहब जल्दी राह पर आ गए।

देशी राज्यों के प्रजामण्डल कांग्रेस से अलग होत हुए भी एक हद तक उनसे अभिन्न भी थे। जवाहरलाल नेहरू ने 15 फरवरी 1939 को 'अखिल भारतीय प्रजा मण्डल सम्मेलन' के लुधियाना अधिवेशन में कहा था "कुछ लोगों ने देशी राज्यों में चलने वाले आन्दोलन के प्रति कांग्रेस के रक्त की समय-समय पर आलाचना की है और हस्तक्षेप

और बहुमतपक्ष के विषय में गर्मागर्मी हुई है। इस समय घम आलोचना और तब वित्तक प्रकाश की बात बनकर अब निरर्थक हो चुके हैं। फिर भी संक्षेप में दशरी राज्या के प्रति शासन की नीति के विकास पर दृष्टिपात वाछनीय है। इस नीति की सारी अभिव्यक्तियों से या समस्या के कुछ पहलुओं पर ही जोर देना मैंने पसंद नहीं किया। परंतु मैं निश्चित है कि मौलिक नीति परिस्थितियों को देखते हुए सही रही और बाद की होने वाली रचनाओं से उसका अनुमोदन हुआ है। शक्ति या आमूलचूल परिवर्तन के नदय के लिए शक्यपद्धति अपनाई जाए, उसे वास्तविकता तथा उस समय की परिस्थिति में सम्पन्न कर चलना पड़ेगा। डीगमूलक, जवानों जमाखर्च या लनतरानी प्रधान सारगर्भहीन श्माव, जिनका उस समय की परिस्थिति से कोई सामंजस्य नहीं है, शक्तिवागी परिवर्तन उत्पन्न नहीं कर सकते। न इसके लिए कृत्रिम रूप से स्थितियां पैदा की जा सकती हैं और न जन आंदोलन ही चालू किए जा सकते हैं जब तब कि जनता तैयार न हो। साथ ही इस तथ्य से परिचित है और जानती है कि देशी राज्यों की जनता अभी तैयार नहीं है। यह देशी राज्यों के बाहर सन्नामों में अपनी शक्ति लगाती रही, यह समझकर कि इन उपायों से देशी राज्यों की जनता को अपने लिए सघर्ष करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।"

कांग्रेस की नीति का मथन करते हुए और स्पष्टता के साथ नेहरू ने कहा 'देशी राज्यों में चलने वाले आंदोलन के सम्बन्ध में कांग्रेस की नीति के विकास में हिंदु का प्रस्ताव एक मील का पथर रहा और उसमें हमारी कार्यपद्धति का सुलासा किया गया। जिस स्वतंत्रता के लिए हम लड़ रहे थे, भारत की एकरता और अखंडता तथा अपरिहाय अग रही और हम यह चाहते रहे कि बाकी भारत को जिस हद तक परमनिक, सामाजिक और आर्थिक आजादी मिले, देशी राज्यों की जनता को भी उस एकर आजादी प्राप्त हो। इस मामले में कोई समझौता संभव नहीं है।

दुर्गन्ध का कहना है कि कांग्रेस से देशी राज्यों को अभी छेड़ना गरी चाहती थी। राज्यों में अलवर और भरतपुर थे। महात्माजी की हत्या की जांच करते हुए यह पता लगा कि हत्या वाली पिस्तील अलवर के महाराजा के शस्त्रागार से आई थी और अलवर में भी गोलियां चलाने का अभ्यास किया गया था। उस समय एन० बी० खरे अलवर के मुख्य मंत्री थे। महात्माजी ने उन्हें मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्रित्व में नियुक्त किया था, इसलिए खरे महात्माजी से चिढ़े हुए थे। इन्हीं दिनों अलवर के विदोष प्रशासक ने एक रिपोर्ट यह भेजी कि अलवर और भरतपुर भारत सरकार का सत्ता उलटने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो बात सबसे ज्यादा उनके खिलाफ गई और जिसमें नेहरू बहुत शक्ति हुए, वह यह थी कि ये राजा अपनी मेव मुस्लिम प्रजा को राज्यों में भगा रहे थे। नेहरू के कारण माउंटबटन को झुकना पड़ा। राजाओं ने फिर भी पडयंत्र करना चाहा, परन्तु सरकार को सब खबर मिलती रही और उनकी एक् नहीं चली।

राजप्रमुख — भारत सरकार की ओर से कुछ मुख्य देशी राजाओं को राजप्रमुख का पद दिया गया, जिससे उन्हें ऐसा लगा कि उनकी आकांक्षा पूरी हुई और वे भारत में शामिल हो गए।

हैदराबाद—हैदराबाद का किस्सा कश्मीर की तरह था। कश्मीर में प्रजा मुख्यतः मुसलमान थी और राजा हिंदू था, यहां निजाम मुसलमान था और प्रजा हिंदू। माउंटबटन 29 जून 1948 को भारत से चले गए और सी० राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने। निजाम से कहा गया था कि तुम सीधे मे दूसरे राजा नवाबों की तरह भारत में अन्तर्भुक्त हो जाओ, परन्तु वह पाकिस्तानी मनाइति के

सलाहकारों से घिरा हुआ था।

सरदार पटेल ने अपने खास आदमी के ० एम० भू-शी का भारत सरकार के प्रति निधि के रूप में हैदराबाद भेजा। भू-शी ने रिपोर्ट दी कि प्रजा तयार है, उस हथियार मिल जाए तो अभी निजाम औंधे मुंह गिरा दिखाई देगा। पर सरदार ने सलाह नहीं मानी। उनका कहना था कि यदि जबदस्ती ही करनी है तो सरकार करगी।

**पुलिस एक्शन**—कुछ दिनों बाद भारत सरकार को यह खबर मिली कि निजाम पुतगाली सरकार से गोवा खरीदने की बातचीत चला रहा है ताकि समुद्र का रास्ता खुल जाय, जिसमें पाकिस्तान के साथ सीधा सम्पर्क स्थापित हो सके। यह भी पता लगा कि निजाम ने पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपये उधार दिए हैं ताकि जिन्ना उसका साथ दे। इस पर नेहरू और पटेल ने मिर्जापुराद छावनी में फौज भेज दी। फौज के हैदराबाद में घूमने पर 'पुलिस एक्शन' सम्पूर्ण हो गया। इससे पहले दो बार 'पुलिस एक्शन' रद्द किया गया था। तीसरी बार भी निजाम के अनुरोध पर गवर्नर जनरल नेहरू से कहकर उसे रद्दवा रहे थे कि उन्हें बताया गया कि काम तो हो चुका। नेहरू ने 10 सितम्बर को इसकी घोषणा की। 17 सितम्बर को निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस बीच पाकिस्तान में हैदराबाद 'आक्रमण' पर संयुक्त राष्ट्र में शिकायत उठाई। सोवियत संघ, यूक्रेन और चीन निष्पक्ष रहे। 19 सितम्बर को नेहरू ने घोषणा की कि हैदराबाद राज्य के भविष्य का निर्णय वहाँ की जनता की इच्छा के अनुसार होगा। जिन्ना को क्रमशः हैदराबाद और जूनागढ़ सभ्य हार खानी पड़ी। यह स्पष्ट है कि जिन्ना किसी सिद्धान्त का पालन नहीं था। वह हिंदू प्रधान इलाकों को भी हड़पना चाह रहा था।

## आवडी कांग्रेस 1955

पहली योजना काल में 1955 की जनवरी को कांग्रेस का आवडी अधिवेशन हुआ, जो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि उसमें पहले पहल समाजवादी ढांचे को लक्ष्य के रूप में स्वीकृति दी गई। इस समय तक भारत के फ्रांस शासित इलाके भी भारत में आ चुके थे। अध्यक्ष डेवर ने इसका उल्लेख करते हुए बताया कि फ्रांस तो मान गया है परंतु पुतगाली अभी तक अड़ हैं। डेवर ने कहा 'पुतगाली शासन में पिछते और सम्मान करने अपने भाइयों और बहनों का हम पूरा नैतिक समर्थन भेजते हैं। हम पुतगाली संस्कृति के विराधी नहीं, परंतु भारत की स्वाधीनता का अर्थ है भारत के चपे चपे जमोनों की स्वाधीनता।

डेवर के भाषण में स्त्रियों की उन्नति पर विशेष रूप से बल दिया गया। कहा गया कि स्त्रियों की द्रुत उन्नति के बिना देश की आधी शक्ति अपाहिज रहेगी।

**समाजवादी ढांचा और समाजवाद**—इस अधिवेशन में समाजवादी ढांचे की कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। श्री नेहरू 1929 की कांग्रेस में ही अपने को समाजवादी और प्रजातन्त्रवादी घोषित कर चुके थे। 'समाजवादी ढांचा और 'समाजवाद' एक है या भिन्न, इस विषय पर नेहरू ने अप्रैल 1956 में कहा 'कुछ लोग समाजवादी ढांचा और समाजवाद में बारीक फर्क बताते हैं, पर दोनों एक हैं।'

असल में देना जाए तो लाहौर कांग्रेस से ही कांग्रेस के अंदर समाजवादी विचार धुंधलाते रहे थे, खुलकर भद्रक उठने का मौका अब आजादी मिलने के बाद आवडी में आया।

नेहरू ने समाजवादी ढांचे वाले प्रस्ताव की व्याख्या करते हुए कहा 'स्वतंत्रता

हम के किसी भी सोपान में हमारी दृष्टि राजनैतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं रही, बावज़ूब स्वतंत्रता की अतर्गत वस्तु में वृद्धि होती रही। सदा आर्थिक पहलू पर हमारी शकलें लगी रही। हम किमान, मजदूर, दलितों और बच्चों के विषय में सोचते रहे। हमने अवसर यह कहा कि हम ऐसा समाजवादी ढांचा चाहते हैं, जो भारतीय प्रतिभा के अनुकूल हो। हम कल्याणकारी राज्य चाहते हैं। कल्याणकारी राज्य के बिना समाजवादी ढांचा अकल्पनीय है। हम कठिन परिश्रम से ही समाजवाद प्राप्त कर सकते हैं, न कि प्रस्ताव या सरकारी हुक्मनामे से। हम अधिक से अधिक उत्पादन करें और ठीक से नायपूण ढंग से वितरण करें। हमारी आर्थिक नीति का उद्देश्य होगा—प्रचुरता।”

## कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1956

1956 में अमृतसर में यू० एन० डेबर की अध्यक्षता में कांग्रेस का 61वां अधिवेशन हुआ। इस बीच यानी आवडी और अमृतसर के बीच दो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए

(क) इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया को सावजनिक व्यवस्था में लाकर स्टेट बैंक आफ इण्डिया का गठन।

(ख) जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण।

स्वामाधिकार रूप से अमृतसर कांग्रेस ने इन कदमों का स्वागत किया। इसमें फिर से समाजवादी ढांचे पर जोर दिया गया।

## इंदौर अधिवेशन 1957

जनवरी 1957 में इंदौर में अधिवेशन हुआ और इसके अध्यक्ष भी श्री नेहरू ही रहे। इस अधिवेशन में कांग्रेस के सविधान में जहां केवल सहकारितामूलक कामनवेल्थ का, वहां उसमें ‘समाजवादी’ शब्द जोड़ दिया गया।

श्री नेहरू ने इस अवसर पर कहा “मैं समाजवाद का एक बुद्धिशील, गतिशील धारणा के रूप में लेता हूँ, जो प्रस्तरीभूत अवल अटल न हो, जो मानव जीवन तथा देश की उपलब्धियों के साथ तालमेल रखे।”

## गुवाहाटी कांग्रेस 1957

कांग्रेस का 63वां अधिवेशन गुवाहाटी में हुआ। इसमें भूमि सुधार पद्धति पर विशेष जोर दिया गया और कहा गया जहां संभव हो, खेतिहरों की सम्मति से सहकारी खेती का प्रवर्तन किया जाए।

## नागपुर कांग्रेस 1958

नागपुर में इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस का 64वां अधिवेशन हुआ। जिसमें नियोजन पर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया गया। इसमें कहा गया

1. सावजनिक उद्योग तथा सरकारी व्यापार को बढ़ावा दिया जाए ताकि सब श्रेणियों के लिए अधिक साधन प्राप्त हों।

2. आयात पर कड़ाई से नियंत्रण किया जाए ताकि अनावश्यक आयात न हो और विदेशी मुद्रा की वृद्धि हो।

- 3 जीवन बीमा मित्रा पूजा एकत्र करने में लगी हुई सस्याओं को प्रोत्साहन दिया जाए।
  - 4 उत्पादन का ढाँचा ऐसा हो कि लोगों की आवश्यक जरूरतों की पूर्ति हो।
  - 5 मजदूरी और वेतन का किए हुए काम तथा उत्पादन से अधिकाधिक सम्बन्ध हो। निजी क्षेत्र में मुनाफे पर नियंत्रण हो।
  - 6 जरूरत के अनावा बड़ी और व्ययसाध्य इमारतों का निर्माण तभी किया जाए, जब योजना के लिए अपरिहाय हो। इन इमारतों में विलासिता वजित रहे। सावजनिक इमारतें सीधीसादी हो।
  - 7 मूल्यवृद्धि न हो, पर खेती की उपज का लागत के अनुसार दाम दिया जाए। खेती के क्षेत्र में उत्पादकों का प्रोत्साहन मिले।
- नागपुर में सरकार द्वारा अनाज की आड़ों और व्यापार का समयन किया गया।

## बगलौर अधिवेशन 1960

1960 में बगलौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। यहाँ यह दृष्टव्य है आजादी मिलने के बाद कांग्रेस अधिवेशनों का महत्व घट गया।

इसके बाद तीसरे आम चुनाव का समय आ गया, परन्तु आगे बढ़ने में पहले हम इस बीच घटी उस घटना का देख लें जिसमें स्वतंत्रता में जो थोड़ी कमी थी, वह भी पूरी हो गई।

**गोवा राजा—** भारतीय स्वतंत्रता युद्ध के इतिहास में गोवा का स्थान बहुत अद्भुत और जलज है। जब भारत 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्र हुआ, तो भारत के वे कुछ हिस्से स्वतंत्र होने से रह गए जो अंग्रेजों के साम्राज्य में नहीं थे। इन स्थानों में फ्रांस के अधीन चंदननगर और पांडिचेरी और पुर्तगालियों के अधीन गोवा, दमन और दिव थे। फ्रांस तो थोड़े ही वर्षों में स्थिति को समझ गया और उसके उपनिवेश भारतीय स्वतंत्रता के भागीदार और सहभोजता हो गए। परन्तु पुर्तगाली नहीं माने। उनके द्वारा शासित भूखंड 19 दिसम्बर, 1961 को तभी स्वतंत्र हो सका जब भारत ने उस पर आकायदा अपनी फौज चढ़ा दी।

गोवा में प्रबल क्रांतिकारी (आजाद गाम-तक) तथा अहिंसात्मक दोनों प्रकार के आंदोलन चालू होने पर भी उनका असर पुर्तगाली सेना पर नहीं पड़ा, न पड़ सकता था, क्योंकि वह एक विदेशी सेना थी जिसका वहाँ की जनता से कोई रक्त सम्बन्ध नहीं था।

इस रक्तगत सम्बन्ध का विकसित न होने देने में पुर्तगाली साम्राज्यवाद के दो रूप थे—

(1) गोवा के लोगों को जबदस्ती ईसाई बनाना ताकि ईसाई बन जाने पर वे अपने लोगों से कट जाएँ और विदेशियों को अपना समोत्र तथा प्रभु मानें। इसको विराष्ट्रीकरण (डिनेशनलाइजेशन) की प्रक्रिया बताया गया।

(2) पुर्तगाली मना को स्थानीय जनता में अलग रखा जाए और उन्हें धारणा निलाई जाए कि यहाँ के लोग हीन हैं। इसके अलावा पुर्तगाल से समय समय पर नई सेना मगाकर पुरानी सेना को दश भेज देना जारी रखा जाए।

विदेशी हमलावर बार-बार इस कारण सफल होते रहे कि वे नई तकनीक के अस्त्रों से सुसज्जित होकर आए, उनका संगठन श्रेष्ठतर था तथा वे एक मजबूत गुटबंदी

(ग्यागतर धार्मिक) स मतबाने थे। वे आए तो लूटमार से प्रलब्ध होकर, पर कहा यह जाना रहा कि धर्म का प्रचार करना है। पुर्तगाली अब तक इस धार्मिक उमात् स मत थे, जबकि मुस्लिम सामन्तो का धार्मिक उमाद विनासिता के कारण बहुत पहले ही मरिद पड चुका था। इनकी तुलना मे हिंदू 'बाग्ह कनोजिया तरह चूल्हे की नीति से मदा सचालिन रहे है।

गोवा के ईसाई देशभक्तों और स्वातन्त्र्य सैनिकों द्वारा प्रस्तुत वहां के इमादकरण का वक्ता त सचमुच बहुत ही अदभुत है। अंग्रेजों ने भी बड़े बड़े जुल्म उनके धर्म का प्रचार किया, विगपकर पिछड़े क्षेत्रों में परंतु उनके अधीन भूमि का विस्तार बहुत अधिक रहने के कारण यह जुल्म उतना जघन हो सका, जितना गोवा में हुआ। फिर भी गोवा में चार सौ वर्षों के अत्याचार के बावजूद सिर्फ 3॥ फीसदी लोग ही ईसाई हुए। मुसलमान दो प्रतिशत बच रहे हिंदू 60 प्रतिशत हैं।

दो शोध पुस्तकें—एक प्रसिद्ध ईसाई देशभक्त ने अंग्रेजों में एक, बल्कि दो पस्तिकाएँ, निम्नी जिनने नाम थे 'पोचुगीज इंडिया' और 'डिनशनलान्जिंग आब गोवस'। ये पुस्तकें पुर्तगाल में प्रकाशित नहीं हो सकती थीं, इसलिए बम्बई में प्रकाशित हुईं। पुर्तगाली सरकार ने इस प्रकाशन पर भारत की अंग्रेज सरकार को आपत्ति करते हुए पत्र लिखा और चार चार मीसरे भाई के नाते पुस्तक-प्रकाशक पर भारत रक्षा कानून के अनुसार मुकदमा चला। मुकदमे का फमला पहली अदालत में सरकार की इच्छा के अनुसार हुआ, परंतु बम्बई हाई कोर्ट ने उस समय एम० सी० चागला 'यायाधीश' थे। उन्होंने प्रकाशन का समर्थन करते हुए पहली अदालत के फैसले को इस आधार पर रद्द कर दिया कि जिन तथ्यों को मानकर ये पुस्तकें लिखी गईं वे अवाटय हैं। इस प्रकार ये पुस्तकें जन्म न की जा सकी और अब एक ही जिल्द में उपलब्ध हैं।

इन पुस्तकों ने लेखक टी० पी० कुहा ने केवल गोवा के स्वातन्त्र्य योद्धा थे, बल्कि विद्वान भी थे। उन्होंने पुर्तगाली (गोवा की राजधानी) में माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की फिर वह पांडोचेरी में उच्च शिक्षा के लिए गए और वहां स्नातक हो गए। इसके बाद वह फ्रांस में और उच्च शिक्षा के लिए चले गए। 14 वर्ष फ्रांस में रहकर 1926 में गोवा लौटे। फिर वह गोवा के स्वातन्त्र्य संग्राम में जुट गए। वहां उन्होंने गोंग यूथ लीग (युवासंघ) की स्थापना की। भारतीय स्वतन्त्रता के ऐन पहले 18 जून, 1946 को जब राममनोहर लोहिया ने गोवा स्वतन्त्र करने की मांग को बुलंद किया, वहां साहब पर इसी अपराध में सगीनो से काँका गया, जिसके चिह्न वह अपनी कब्र के दिनों तक ले गए। उन्हें अंगुआदा दुग में बंदी बनाकर रखा गया, जहां सफाई देशभक्त रहे।

1946 की 24 जुलाई को कुहा का सचिव अदालत के द्वारा 8 साल की सजा सुनाई गई और उन्हें पुर्तगाल जेल भेजा गया। वह 1950 की आम माफी में छूटे, पर उन्हें लिस्बन में ही रहने को कहा गया। पर दो साल बाद वह वहां से भागकर पेरिस पहुँचे। वह अपने भाई के साथ, जो एक भारत विद्या विशारद थे, कई साल रहे, फिर वह 4 मितम्बर, 1953 को भारत लौटे। वहीं में कोकणी भाषा में 'आजाद गोवम' प्रकाशित करते रहे। स्वास्थ्य गिर चुका था, भाग्य स्वतन्त्र होने पर भी गोवा परतत्र था, फिर भी वह लड़ाई जारी रखते रहे। 19५४ के 26 सितम्बर को उनका देहांत हुआ और उनकी बम्बई के स्काटलैंड क्विस्तान में समाधि दी गई।

पुर्तगाली, अंग्रेजों के मुकाबल अधिक घमांघ थे अतएव उनके शासन में हजारों मुसलमानों और हिंदुओं का जबरन ईसाई बनाया गया।

पुर्तगालियों ने लगभग चार सौ साल खूब लूट मार की। नय गिरजे ~~अंग्रेजों~~ के

बावजूद वे अपने ही धार्मिक मानदण्डों से भी बनई धार्मिक नहीं थे। वे सब दुश्चरित्र और लम्पट थे। वे धर्म का इस्तेमाल करके अपने शोषण को चिरस्थायी बनाना और मौज उड़ाना चाहते थे।

श्री कुहा लिखते हैं "पुतगाली एक तरफ सूट मार करने और दूसरी तरफ धर्म प्रचार करत थे। इसके लिए उन्हें पोष की मनद प्राप्त थी और वे सारी लड़ाइयाँ ईसाइयाँ के चिह्न क्रॉस और तलवार के तहत लड़ते थे। वे भारत में हिंदू धर्म का अस्तित्व नकारते हुए यह गमभीर चलत थे कि यहाँ सब ईसाई हैं। प्रारम्भ में उनकी धार्मिक घृणा की ताप का मुह मुस्लिमों की तरफ था क्योंकि वे ही उनके प्रतिद्वंद्वी थे। उन दिनों कुछ इन गिन नस्लारियन ईसाई यहाँ थे, जो बाग का केंथोलिक बन गए। पर पुतगालिया के दिमाग पर यह जुनून सवार था कि भारत के सब लोग ईसाई ही हैं और इसी पामल पन से परिगलित होकर वास्काडिगामा ने वालीकट कएर हिंदू मंदिर को ईसाई गिरजा समझा था और उसके अंदर प्रनिष्ठित बात्तो की मूर्ति को मरियम समझकर उसे अघ्य चढ़ाया था। पुतगालिया द्वारा सबसे पहले कुछ वंश्याएँ ईसाई बनाई गई। मुन्ना वेन्साओ को प्रचुर उपहार देकर और धमका कर ईसाई बनाने का उद्देश्य यह था कि पुतगाली सैनिक हराम करने से बचाए जाए। गोवा में अनबुर्क न अपने सैनिकों की शांति, तुर्की अफमरा की छीनी हुई वीवियो और बटिया से कराई। ये तुर्की अभय देकर जहाज पर सपरिवार बुलाए गए थे। परन्तु पहुँचने पर पुष्टियों को तलवार के घाट उतारकर उनकी बीवियाँ और बटियों का सैनिकों के सुपुत्र कर दिया गया।"

मन जेवियेर ऐसे लोग भी अमाचारों के बावजूद ईसाई धर्मप्रचार में सफल नहीं हुए। इसलिए उन्होंने बराबर पुतगाली सम्राट को यह लिखा कि आप अपने गोवा नियत कमचारियों का यह आदेश देते रहें कि उनका तभी सफल प्रशासक माना जाएगा जब वे धर्म का झण्डा फहराने में अपनी पटुता दिखाएँ। पादरी, जनता पर असर जुनूस करते थे। वे धर्म प्रचार के नाम पर शान और शक्ति की खिंदगी बिताते रहे। वे कामुक और लोभी थे। अपनी पाश्चात्तिक वस्तुओं की चरिताय करने के लिए वे भारतीयों पर खलकर अत्याचार करते थे, यहाँ तक कि ईसाई बनाए गए लोगों को भी नहीं बख्शते थे। 1410 में पुतगाली में प्रजातन्त्र कायम होने के साथ साथ देश के अंदर गिरजा और राष्ट्र का अलगभाव हुआ गया, पर पुतगाली र भारतीय साम्राज्य में पादरियों की दुष्टता और मन मानी जारी रही।

1926 में पुतगाली में फामिस्ट अधिनामकवाद का बोलबाला हुआ। पुतगाली में सब तरह की स्वाधीनता नष्ट हो गई। सारी राजनीतिक पार्टियाँ निषिद्ध हो गई। अल्ल धारों का कण्ठरोध किया गया। गोवा की भाषा तकली है। गोवा के बाहर भी 7000 लोग मौन नए यह भाषा प्रचलित है। भाषा विज्ञान के विद्वान इस भाषा को गोमंतकी कहते हैं। पर मराठी भाषी नम मराठी की एक बारी मानते हैं। गोवा पर चार क्षताब्दी शासन में पुतगालिया ने काकणी का खूब चढ़ाया और फिर भी पुतगाली शासन काल में तो या तीन प्रतिशत लोग ही पुतगाली का गान प्राप्त कर सके। पुतगाली शासन में शराब का खूब प्रचार प्रसार हुआ। पुतगाली शासन में सबसे अधिक यानी 20 प्रतिशत राजस्व शराब से जाता था। गोवा क्षेत्र में शराब के बड़े कारखाने हैं।

पुतगालियों ने 1510 के पहले भोके में ही हर मुसलमान को मारकर सारी मस्जिदें तोड़ दी थी। एक ही दिन में एक जगह 6000 मुसलमान मार दिए गए थे। मुसलमानों पर उम विनोद अत्याचार का कारण यह था कि वे शायक जाति के समझ जाते थे। मस्जिदों की सम्पत्तियाँ गिरजा की गोप व रक्षक का बजाया गया। हिंदुओं की

बाते आई तो घर के अंदर भी बीतन निषिद्ध करार दिया गया, तुलसी का पेड़ उगाना, घोती या चोली पहनना भी जुम बना दिया गया।

जब भारत स्वतंत्र हो गया, तो गोवावासी बहुत विचलित हुए, पर वे सबसे अधिक विचलित तब हुए जब फ्रांसीसियों ने अपने भारतीय उपनिवेशों को भी स्वतंत्र करके इन को सौंप दिया।

**हातम्य सप्राप्त**—पुतगाली यह प्रचार करके दुनिया की आंखों में धूल भोکنे लगे कि फ्रांसीसी उपनिवेशों में गोवा का मामला भिन्न इस कारण है कि गोवावासियों में 70 फीसदी जनता पुतगाली रक्त की है। परंतु गोवा के स्वातंत्र्य आंदोलन की विशेषता यह था कि न केवल इसमें ईसाई पूरी तरह शामिल थे, बल्कि वे बराबर गोवा को भारत का अविच्छेद अंग मानकर चल रहे थे। गोवा के स्वातंत्र्य योद्धाओं का वे द्रबम्बई था, वहां में उनकी घन और प्रचार सम्बन्धी सहायता प्राप्त होती रहती थी। गोवा से फरार लोग बम्बई में बैठकर आंदोलन को बल पहुंचाते थे। वही पूरा साहित्य छपता और वारी से गोवा भेजा जाता। 10 नवम्बर, 1954 को मुक्त गोवा की एक घोषणा में पुतगाली साम्राज्यवादियों को यह चेतावनी दी गई कि वे फ्रांसीसियों की तरह बिना रक्तपात के गोवा त्याग दें। इस घोषणा के अंत में यह कहा गया कि पाण्डिचेरी तथा चन्दन नगर में जिस काम का गुभारम्भ हुआ, उसकी पूर्णाहुति गोवा की स्वतंत्रता से हो।

यहां यह बता दें कि भारत के प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू को जब भी गोवा पर प्रश्न किया जाता, तो वह जो भी कहते, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखकर कहते। उससे गोवावासियों को निराशा होती थी। गोवा पर भारत सरकार बहुत देर में किमी ठोस निर्णय पर पहुंची।

**दादरा, नगर हवेली स्वतंत्र**—1954 में गोवा के कांग्रेसी भी समझ गए कि क्वल प्रस्तावों से कुछ नहीं होगा। पीटर अल्वारिस के नेतृत्व में फिर से ज़ोरो के साथ संगठन चालू हुआ। एक नई समिति बनी जिसके अध्यक्ष पुडलिक गायताडे बने। पुतगाली पब्लिस को पता लगा और पुडलिक गायताडे को पकड़कर पुतगाल की जेल में भेज दिया गया। गोवा के स्वातंत्र्य योद्धा बम्बई और गोवा के बीच दौड़ने लगे। बम्बई में 'आजाद गोवा' का दफ्तर खुले आम कायम कर रहा था। तय हुआ कि दादरा तथा नगर हवेली को पहले चरण में मुक्त किया जाए। पर प्रश्न था कि क्या बम्बई के सर्वेसर्वा मोरारजी देसाई इसे स्वीकार करेंगे? उनसे क्रांतिकारी बात करने लगे। बड़ी कठिनाई से मोरारजी तयार हुए, तब 1954 में 22 जुलाई को दादरा नगर हवेली को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। बम्बई के गरम दलीय नेताओं के सहयोग से यह सम्भव हुआ।

**गोवा मुक्त**—पर यह तो प्रतीकात्मक विजय थी। आजाद गोमातक (नेता विश्वनाथ सावे दे) और गोवा लिबरेशन आर्मी (नेता शिवाजी देसाई) ये दो क्रांतिकारी दल बराबर कायम कर रहे थे, पर कोई भी क्रांति या मुक्तिपथ तब तक सफल नहीं हो सकता, जब तक कि सेना को मिला न लिया जाए। यह शर्त यहां पूरी नहीं हो सकती थी, क्योंकि सेना पुतगाली थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो गोवा की मुक्ति बहुत कठिन थी। अंतर्राष्ट्रीय जनमत से कुछ आशा करना मूलतः था, क्योंकि उस पर साम्राज्यवादियों का बकाया था। फिर भी दादरा नगर हवेली की स्वाधीनता के बाद हवा ऐसी बनती चला गई कि भारत सरकार ने 19 दिसम्बर, 1961 को गोवा के भीतर अपनी फौज भेजनी पड़ी और करीब करीब बिना रक्तपात के गोवा आजाद कर दिया गया। अगुआदा यह में जो छोटे मोटे स्वातंत्र्य योद्धा बन्द थे वे मुक्त कर दिए गए, परन्तु कई महत्वपूर्ण



व्यक्ति पुतगाल की जेलों में पड़े थे, वे नहीं छोड़े गए। व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय जनमत गोवा के हमले पर खूब शोर मचाता रहा, परंतु इन चर्चों के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा। बहुत बाद में वे पुतगाल की जेलों से सजा की अवधि पूरी करने के बाद रिहा किए गए।

**गोवा अधिग्रहण की निंदा** - अनेक देशों और पाकिस्तान में इस घटना की यह कहकर निंदा की गई कि भारत विस्तारवादी और साम्राज्यवादी है और वह गांधी के आदर्शों से गिर चुका है। पुतगाल को भड़काया गया कि वह अपना बड़ा भेजकर फिर से गोवा पर अधिकार जमा ले। परंतु पुतगाल ने यह बेवकूफी नहीं की। किसी सम्प्रदाय ने यह नहीं कहा कि इस विषय पर गोवा वालों की भी राय ली जाए।

**चीनी आक्रमण** गोवा का आजाद कराने के बाद सबसे बड़ी घटना चीनी आक्रमण है, जो 1962 के 19 अक्टूबर को एकाएक बिना मेघ के वज्रपात की तरह घटित हुआ क्योंकि देश में तुरावर वर्षा से 'चीनी हिंदी भाई भाई' का नारा गूज रहा था।

भारत और चीन में सैकड़ों वर्षों की दोस्ती और आदान प्रदान रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चीन के नेता सुन यातमेन की जीवनी उसी चाय से भारत में पढ़ी जाती थी, जसे इटली के मजिनी, गैरीबाल्डी, और आयरलैंड के डिकेलेरा डानब्रिन की जीवनी पढ़ी जाती थी। जब 1949 में चीन में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में क्रांति हुई, तब से भारत की परम्परागत दोस्ती और प्रबल हो गई, चीन भी पूरी तरह ईमानदार रहा। इनका एक प्रमाण यह है कि एक बार जब नेपाल के प्रधानमंत्री तनखाप्रसाद आचार्य ने सरकारी भोज में नेपाल चीन की दोस्ती का नारा दिया तो माओ ने जो उस भोज में उपस्थित थे, वहनव्य को सुधारते हुए कहा—'नेपाल चीन भारत की दोस्ती।' प्रसिद्ध पत्रकार दुर्गादास ने अपनी पुस्तक 'इण्डिया फ्रॉम कजुन टु नेहरू ऐज्ड आफ्टर' में इस घटना का उल्लेख किया है।

दोनों देशों में तब कुछ ठीक चलता रहा। हा, सीमा पर कुछ आलोचना होती रही। नेहरू चाहते थे कि चीन मैकमोहन रेखा का मान्यता दे, पर चाउ एन लाई बंदते में अक्साई चिन का इलाका चाहते थे। नेहरू को इनमें विशेष आपत्ति नहीं थी क्योंकि, जैसा कि उन्होंने कहा, उस इलाके में घास की एक पत्ती भी नहीं उगती। परंतु जाने कसे इसकी भतक विरोधी पक्ष के कानों में पहुंच गई। वस मसंद में बाबेला मच गया कि देश को बेचा जा रहा है। नतीजा यह हुआ कि चीन और भारत की बातचीत में ज़िद पैदा हो गई।

परंतु किसी को भारत पर चीनी आक्रमण का भय नहीं था। इसलिए जब आक्रमण हुआ, वह आकस्मिक लगा। भारत इसके लिए तैयार नहीं था, न मानविक रूप से, न सैनिक रूप से। नतीजा यह हुआ कि चीन भारत में घुस आया। पर वह बहुत आगे न बढ़कर लौट गया। क्यों लौटा, इस पर बहुतों का कहना है कि चीन भी इसमें ज्यादा के लिए तैयार नहीं था।

जो हो, चीन के इस काय से भारत की जगहमर्द हुई और लोग इनने नाराज हुए कि नेहरू को रक्षामंत्री मेनन को मंत्रिमण्डल से निचालना पड़ा। मेनन योग्य पर जिद्दी व्यक्ति थे। इसके बाद सुरक्षा उद्योग का जो सिलसिला चला, उसका परिणाम यह हुआ कि तीन वर्ष बाद 1965 में जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो भारत सामना करने के लिए तैयार था। इस दृष्टि से देखा जाय तो चीनी आक्रमण ने हम सैनिक रूप से जयाकार हमारा कल्याण ही किया।

कहा "किसी भी जिम्मेदार सरकार के लिए एक निश्चित और इच्छाकृत नीति को बदल सकना आसान नहीं है। फिर भी हमारे मंत्रिमण्डल ने, जो हर तरीके से जिम्मेदार है, बहुत ही सोच समझ और साथ ही निश्चित सत्य को बदल दिया है। मैं जानता हूँ कि सभार की सारी जातियाँ इस कार्य का स्वागत करेंगी और मैं यह कहूँगा कि हमारे मंत्रिमण्डल ने यह कार्य करके बहुत ही श्रेष्ठ आचरण का परिचय दिया है।"

**मुस्लिमतोषण नहीं, आत्मतोषण**—गांधीजी ने यह भी स्पष्ट किया कि इसे मुस्लिमतोषण न कहा जाए, बल्कि यह आत्मतोषण है। उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी जनता का प्रतिनिधि मंत्रिमण्डल कभी ऐसा बदम नहीं उठा सकता, जिससे कि वह विचारहीन जनता की बाह्यादृष्टि में भटक जाए। जबकि चारों तरफ पागलपन का वातावरण है क्या यह जरूरी नहीं कि हमारे प्रतिनिधि अपने दिमाग ठीक रखें और राष्ट्र की न्याय की चट्टान से टकराकर टूटने से बचाव।"

**प्राथना सभाओं में हस्तक्षेप**—इसी प्रकार जब मितम्बर, 1947 में दिल्ली में उनके आस-पास बिहार में भगड़े हुए, तो महात्माजी ने मुसलमानों को बचाने की चेष्टा की। इन सारी बातों के फलस्वरूप हिंदुओं में एक बड़ा ऐसा उत्पन्न हो गया, जिसने हर स्तर पर गांधीजी का विरोध करना शुरू किया, यहाँ तक कि उनकी प्राथना सभाओं में भी लोग उनसे घुरी तरह पेश आने लगे। कई बार तो सवधमूलक प्राथना बंद ही कर देनी पड़ी। उनकी प्रार्थना की विशेषता यह होती थी कि उसमें कुरान से आयतें, ईसाई गीत, वेद की ऋचाएँ आदि सभी पड़ी जाती थी। सांग और सों सब कुछ सह लेते थे, पर कुरान की आयतों पर झगड़ा करते थे।

**गांधीजी की हत्या**—इन परिस्थितियों में एक घमांच के हाथ महात्माजी की हत्या होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पहले ही गांधीजी पर बम से एक हमला हो चुका था। तत्काल के अनुसार "30 जनवरी की शाम को चार बजे सरदार पटेल गांधीजी से मिले और उनके साथ एक घंटा रहे। हान के उपवास तथा अन्य कारणों से सरदार पटेल और जवाहरलाल ने जो मतभेद हुए थे, उससे वह चिन्तित थे। वह चाहते थे कि दोनों नेता कंधे से कंधा मिलाकर चलें। संध्या समय की प्रार्थना के बाद नेहरू और आजाद उनमें मिलने वाले थे। पाँच बजे गांधीजी ने घड़ी निकाली और सरदार ने बोले—'प्राथना का समय हो गया।' वह पाँच बजकर दस मिनट पर अपने कमरे में निकले और टहलते हुए पास के मैदान की प्राथना सभा की ओर गए। उनकी पोतियाँ मनु और आभा उनके बगल में थी। वह उन दोनों का सहारा लेकर चल रहे थे। दाना तरफ खड़े लोगों के बीच होते हुए वह प्राथना सभा की ओर जा रहे थे। अब वह पोतियों के कंधे पर से हाथ हटाकर लोगों के नमस्कार का उत्तर दे रहे थे। एकाएक भीड़ में एक हिंदू नाथुराम गोडसे भीड़ को कुहनी मारकर चीरता हुआ आया। मनु ने समझा कि वह गांधीजी के चरण छूना चाहता है, इसलिए उसने उसकी रोका, और पीछे करना चाहा। पर गोडसे ने मनु का हाथ झटककर छुड़ा लिया, फिर हाथ जोड़कर, मानो चरण स्पर्श के लिए आतुर हो, एक के बाद एक सात गोलियों वाली पिस्तौल से तीन गोलियाँ चलाइ। सभी गोलीयाँ गांधीजी के दाहिने सीने पर लगीं। दो गोलियाँ शरीर छेँकर निकल गईं, तीसरी फेफड़े में घुस गई। पहली गोली लगते ही उनके चलते हुए पर रुक गए। नमस्कार में उठे हाथ धीरे धीरे थिथिल होकर नीचे आ गए। अब भी वह पैरों पर खड़े थे, परन्तु इसके बाद जब दूसरी और तीसरी गोली टनटनाई, तो वह गिर पड़े। उनके मुँह से निकला 'हे राम'। चेहरा फव पड़ गया। श्वेत वस्त्र पर सात घन्टों का गए। लोगों ने उन्हें उठाया और भीतर ले जाकर उस गद्दे पर रख दिया।

जहा बठकर वह काम करते थे । फौरन उनकी मृत्यु हो गई ।”

**हत्याओं का वक्तव्य** — 8 नवम्बर 1948 को ‘यायभूति आत्माचरण ने लाल किले के अंदर बंद नाथूराम विनायक गोडसे से नियमानुसार कहा—“तुम सारी गवाही सुन चुके हो तुम्हे कुछ कहना है ?”

इस पर गोडसे ने एक लिखित बयान पढ़ना चाहा । इस्तगसे की आपत्ति पर भी गोडसे को बयान पढ़ने की अनुमति मिल गई । गोडसे उत्तेजित नहीं था, यद्यपि इस बीच इस हत्या की सारे ससार में बहुत निंदा हो चुकी थी । उसने कहा कि यद्यपि सारे लोगो ने मेरी निंदा की है, पर मुझे निश्चय है कि इतिहास दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा ।

पुणे के पत्र ‘हिंदू राष्ट्र’ के सम्पादक नाथूराम विनायक गोडसे के अतिरिक्त सात और व्यक्ति इस घणित पंडमंत्र में शरीक थे— नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, शंकर किस्तया, दिगम्बर बडगे, मदनलाल पहवा, गोपाल गोडसे और दत्तात्रेय परचुरे ।

**बहुत साल बाद** — मई 1983 के ‘सीसायटी’ पत्र के एक खोजी लेखक मधु बेल्लुरी के अनुसार उस समय तक गांधी हत्या मुकदमे के मदनलाल पहवा, गोपाल गोडसे और दत्तात्रेय परचुरे जीवित थे । मदनलाल का कहना था कि उसके पिता काश्मीरी लाल काग्रैसी थे, फिर भी वह विभाजन के दंगों के दौरान बहुत मारे पीटे गए थे और अस्पताल में पड़े थे । पिता को उस रूप में देखकर ही वह मुमलमानों पर हमला करने लगा । उसने कहा कि ग्वालियर में इस प्रकार के कामों के लिए अच्छा मौका था । उसका तो महा तक कहना था कि बड़े बड़े नेता उसकी महायता कर रहे थे ।

**सुहरावर्दी को भी मारना था** — मदनलाल के अनुसार जब महात्मा जी द्वारा अनशन करके पाकिस्तान को पचपन करोड़ दिनांश की खबर आई, तब उनकी हत्या का कार्यक्रम जोर पकड़ने लगा । नाथूराम गोडसे, उसका भाई गोपाल गोडसे, करकरे, किस्तया योजना बनाने लगे । उसने पत्रकार मधु में कहा “हम सुहरावर्दी और गांधी को मारना चाहते थे, नेहरू को नहीं । यह तो सरकारी प्रचार था कि हम नेहरू को मारना चाहते हैं ।” तीन दिन तक दिल्ली के मेरिना होटल में जलनाए चलती रही । मदनलाल को (जो उस समय 20 वर्ष का युवक था) मराठी ब्राह्मण इस योग्य नहीं समझते थे कि उस पर पूरा विश्वास किया जाए । उसमें कहा गया कि तुम्हारा काम यह होगा कि बम फेंका, जिसके धडाके से भगदड़ मच जाए । लोगों का ध्यान जब धडाके की तरफ जाएगा, तब हम गांधी पर हमला करेंगे ।

**हत्या का पहला कार्यक्रम** — पहले कार्यक्रम में नाथूराम और आप्टे फवल परिदशन होत । गांधीन पढ़ने बम फेंकना और फिर करकरे भीड़ से एक और बम फेंकता । उस योजना में बडग महात्मा गांधी पर गोली चरानवाला था । 20 जनवरी 1948 को यह सब होना था । घडाका तो हुआ, पर अर्य नाग अपना निश्चित काय न कर सके । मदनलाल पकड़ लिया गया । उसने अनुसार पुलिस ने उसके मन्डार में मिच डाली, उसे वफा की गिटनी पर बठाया, ऊपर से सिर पर चीनी का रस डाला ताकि चीटिया रेंगे । उसे कम्बन उडाकर रेल के स्टेशन तथा मावजनिक स्थान पर धुमाया गया । मदनलाल ने गव के साथ कहा “मैंने स्टेशन पर गाडसे और करकरे को बम्बर्दी की गाडी में चढते देखा, पर उन्हें पहचाना नहीं ।

**हत्या से खशी** — दम निन वान जब महात्मा की हत्या की गवर मदनलाल को मिनी गा उगवा क्त्ता था उा खुशी हुई थी । वह 16 मान जेल में रहकर 1964 के 14 अक्टूबर को छूट चुका था । पत्रकार मधु मदनलाल के साथ एटेनबरो की फिल्म

गांधी' देखने गया था। फिल्म देखते हुए मदनलाल ने एक दीवार देखकर उत्तेजित स्वर में कहा—“मैंने वहाँ बम रखा था।” फिल्म के गोडसे को देखकर उसने कहा—“यह गोडे नहीं सगता। गोडसे ने तो खाकी कमीज पहन रखी थी।” मदनलाल को यह भी सिखाया था कि फिल्म में गांधी की गलतियाँ जैसे खिलापत की परी (जब कमाल बानु ने खलीफा की परम्परा को एक भटके में खतम कर दिया) इविन के साथ सम-भौता (जिसमें वह ‘उल्लू’ बने) नहीं लिखाई। इसके अलावा प्रार्थना सभा में बहुत कम लोग दिखाए गए जबकि वास्तविक प्रार्थना सभा में हजारों लोग थे।

पत्रकार मधु गोपाल गोडसे से मिले। गोपाल द्वितीय महायुद्ध में भाग ले चुका था। सोचकर वह पुणे के किरवी आडनेस कारखाने के बाहर काम में लग गया। प्रथम हफ्ता प्रयाग में वह घटनास्थल पर था। पत्रकार मधु को लगा कि गोपाल में अब भी पुराना पागलपन मौजूद है। वह बोला—“मैं मानता हूँ, गांधी महापुरुष थे। उन्होंने कई गलतियाँ कीं। पर वह इन सिद्धियों के कारण नहीं, बल्कि जनता को धोखा देने के लिए मारे गए। उन्होंने उपवास की खदबस्ती में पाकिस्तान को 55 करोड़ दिलाए। किस समय देश का विभाजन हुआ, उस समय उन्होंने जनशत्रु कया नहीं किया? क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि मेरी जान पर ही पाकिस्तान बन सकता है?”

गोपाल ने कहा कि मरा देशों ने गांधी की मरम अपनी नदी में फेंके जाने की अनुमति दी, पर मुस्लिम हमले में पाकिस्तान ने भारतीय राजदूत श्री प्रकाश को सिंधु नदी में मरम नहीं डाला, जबकि महात्मा जो पाकिस्तान के लिए ही मरे। गोपाल के अनुसार हे राम भी पाक्रेसियों की जालसाजी है।

गोपाल के अनुसार नाथूराम ने अपनी राख सिंधु नदी में ही क्यों डलवानी चाही, —“क्याकि वही एक नदी है जो पवित्र बची है।” यह नाथूराम ने फासी के दिन कहा था।

एक से अधिक अर्थों में ऐतिहासिक — महात्मा गांधी की हत्या एक से अधिक अर्थों में ऐतिहासिक है। गणेशशंकर विद्यार्थी मुस्लिम धर्मांधा के हाथों मार गए थे, जबकि महात्मा एक हिंदू के हाथों मार गए। यह भी एक सयोग है कि धर्मांधे महान नेता आग बान भी इसी प्रकार मार गए थे। जिन्हा पाकिस्तान बनते समय बस्तर के शिकार थे। भारत का नेता आ का इस रोम की बात मालूम नहीं थी, पर ब्रिटिश गुप्तचर विभाग को मालूम थी। मरु जल्दी हा गई और उसमें पाकिस्तान के राजनीतिज्ञों का हाथ बताया जाता है। लिखाकत अली खा की भी हत्या ही हुई। फिर जिसने हत्या की थी, उसकी भी हत्या कर दी गई। इस प्रकार यह हत्या रहस्य ही रह गई। और इस हत्या के बाद से पाकिस्तान में सनिक शासन हो गया।

गांधी युग — महात्मा जी ने कांग्रेस को आमूलचल परिवर्तित कर उसे एक सगामी सत्ता बना दिया था। यह सही है कि कांग्रेस के अंदर कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि गांधीजी को उससे अलग हो जाना पड़ा, परंतु मनावर उनको लोटाया भी जाता रहा क्योंकि कांग्रेस में अगर किसी के पाम जनता के मन की चाभी थी, तो यह उही का नाम था। गांधीजी के विरुद्ध पहला विद्रोह तब हुआ, जब अमहयोग आ दोलन अचानक बंद कर दिए जाने के बाद चितरजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज्य पार्टी का उदय हुआ। कांग्रेसी नेताओं की यह दूरदर्शिता रही कि स्वराज्य दल कांग्रेस का एक विभाग बना दिया गया। इसके बाद सुभाष का विद्रोह हुआ, उसका अंत सुभाष के कांग्रेस से निकलने में हुआ। द्वितीय महायुद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार से सहयोग के प्रश्न पर कांग्रेस और महात्मा जी में मतभेद हुए, जिससे महात्मा जी कुछ अलग हो गए।

पर इसका भी अंत 1944 में 'करो या मरो' का नारा देकर सपना छिड़ते ही हो गया, इसलिए यह कहना सच्चा उचित है कि कांग्रेस का यह साग युग गांधी युग था। अवश्य ही इस दौरान कांग्रेस के अंदर कांग्रेस समाजवादी जैसे दल का उदय और बाहर प्रातिकारी विस्फोट होते रहे जिनके भील के पत्थर हैं, बाकोरी, लाहौर, मेरठ प्रह्व व और आजाद हिंद फौज।

देश में कांग्रेस का बीसवाला—स्वराज्य के बाद देश में कांग्रेस का रूप बन गया। वह अब आन्दोलनकारियों का संयुक्त मोर्चा न रहकर शासनाह्व दल हो गया। महात्मा गांधी यद्यपि स्वयं साल भर में उठ गए, परन्तु इसका कांग्रेस सत्ता पर विशेष असर नहीं पड़ा। 1947 से प्रायः आज पर्यंत देश में कांग्रेस का ही शासन चला आ रहा है। बीच में दो-तीन वर्षों के लिए कांग्रेस गद्दी से अलग रही, पर उस दौरान भी जनता पार्टी के जो लोग शासनाह्व रहे, उनमें से कुछ को छोड़कर शेष सभी जैतें मोरारजी देसाई, चरणसिंह आदि सब कांग्रेसी ही थे। यहां भी यह बात महत्वपूर्ण है कि इनमें करीब-करीब सभी कांग्रेस से अलग होने पर भी गांधीजी के ही सिध्य होने का दावा करते रहे। भारतीय जनता पार्टी जैसे दक्षिणपंथियों ने भी गांधीवादी कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया। देखा जाए तो जो लोग स्वराज्य के बाद ही कांग्रेस विराधी दल बनाकर सामने आए, वे सब भी भूतपूर्व कांग्रेसी ही थे। कम्युनिस्ट नेता नम्बुदरीपाद भी भूतपूर्व कांग्रेसी थे।

सब कहा जाए तो गांधीवाद अब तक जीवित है और बहुत से लोग यह भी मानते हैं कि सच्चे मानों में गांधी की आवश्यकता आज भी है। अनेक देशों में उनके सिद्धांतों तथा कार्यक्रमों को अपनाकर राजनीतिक लड़ाइयां लड़ने का प्रयास किया गया है जो बहुत कुछ सफल भी रहा है। फिर भी यह मानना होगा कि स्वयं गांधीजी के न रहने से मानों कांग्रेस की आत्मा ही नष्ट हो गई और उही क अनुयायियों द्वारा बहुत सी गलतियां भी की जाने लगी। कहा जा सकता है कि गांधीजी जीवित होते तो उन्हें माफ नहीं करते। इस सम्बन्ध में अग्रणी पत्रकार दुर्गादास ने तभी लिखा था '30 जनवरी 1948 को गांधी युग का अंत हो गया और एक ऐसी युगता पग हो गई, जो कभी नहीं भरने की। गांधी वह कमान थे वह आत्मिक शक्ति थे, जिस पर कांग्रेस स्थिर थी और जनता पर उसका दबदबा कायम था।'

निरं कांग्रेसी बनाम पदधारी कांग्रेसी—स्वराज्य के बाद कांग्रेस या कांग्रेसी शासनाह्व हुए और इसका परिणाम यह हुआ कि पदधारी और पदहीन कांग्रेसियों के दो भेद हो गए। पदहीनों में कुछ कांग्रेस में अलग हो गए और उन्होंने अपनी संस्थाएं बना लीं। जो कांग्रेस में रहकर भी पद नहीं पा सके, उनका महत्व उन कांग्रेसियों के मुकाबले में घट गया जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, मामूली विधायक या किसी निगम आदि के अध्यक्ष बने। यह स्वाभाविक होते हुए भी ठीक नहीं था क्योंकि इसके अर्थ अनेक दुष्परिणाम हुए। वैसे यह शुरुआत पहले ही हो गई थी जब स्वराज्य के पहले कांग्रेस अध्यक्ष कृपलानी ने इस कारण अध्यक्ष पद में इस्तीफा दे दिया था कि सरकार में बैठ कांग्रेसी नेता उन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालयों में भी नहीं बुलाते थे। इसका बाद पुरुषोत्तम दास टंडन को भी कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि कृपलानी के अनुसार नेहरू के साथ उनकी नहीं बनी। ये दोनों इस्तीफे विचारधाराने नहीं थे जसा कि सुभाष का इस्तीफा था।

जब कहीं मणामकारी दल सत्ताह्व हो जाता है, तो प्रायः ऐसा ही होता है। तुलसीदास जी ने कहा है 'प्रभुता पाय काहि मद नाही'। परंतु यह अटल नियम भी नहीं

है कि सत्ता प्राप्त होते ही पतन हो ही जाए। आधुनिक काल में हम देखते हैं—लेनिन की ही चीं मिह का सत्तारूढ़ होने पर किसी अर्थ में भी पतन नहीं हुआ। स्वयं महात्मा गांधी गद्दा पर नहीं बैठे, और यदि वे जीवित रहते तो भी नहीं बैठते। वास्तव में वे जब तक रहे सत्तारूढ़ नेहरू और पटेल पर महाशक्ति और अकुश के रूप में रहे। उनकी हत्या इस कारण हुई कि वह अपनी धमनिरपेक्षता को इस हद तक ले गए कि लोग उन्हें गलत समझने लगे।

दुखती रंग —यहां हम देश की एक दुखती रंग पर पहुंच जाते हैं। कांग्रेस शुरू से ही, यहां तक कि जब उसमें जी हजूर और खरखाह किस्म के लोगों का बोलबाला था, बलमन्त्रिका का बहुत महत्त्व देती थी। गांधी से पहले बंदरूदीन तयबजी 1887 में, इम्मद रहीमतुल्ला सयाफी 1886 में, नवाब सैयद मुहम्मद बहादुर 1913 में और इन इमाम 1918 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर चुके थे। दादाभाई नौरोजी ने 1906 में तथा एनी बेसेन्ट ने 1917 में इस आसन की शोभा बढ़ाई थी। जब गांधी पग आया तब कांग्रेस की गद्दी पर हबीम अजमल खा 1921 में, मुहम्मद अली 1923 में, एम० ए० अमारी 1927 में बैठ चुके थे। आजाद 1940 से स्वतंत्रता प्राप्ति तक फिर बराबर अध्यक्ष रहे। यह चुनौती बार-बार दी जाती रही, कि आखिरी दशक को छोड़कर कांग्रेस का अंदर लीग से अधिक मुस्लिम सदस्य रहे। (यद्यपि लीग ने कभी अपने सन्ध्या की सध्या नहीं बढ़ाई)। 1937 के प्रांतीय शासन के युग में लीग सिक्कंदर ह्यात और फजलुल हक के प्रांतीय दलों के सामने नहीं ठहर पाई और अपनी दाल गलती में दखल कर जिना इंग्लैंड में बसने चले गए, परंतु फिर भी लीग को महत्त्व दिया जाता रहा।

## सत्तारूढ कांग्रेस का नेहरू युग

स्वतंत्र भारत की पहली सरकार ने नेता श्री नेहरू से। यह महीने ४ भीतर ही महारमा गांधी नहीं रहे और मरदार पटेल भी स्वयंभग तीन वर्ष तक ही उनका साथ दे सके। इसलिए स्वतंत्र देश के नवनिर्माण का प्रायः पूरा ही दायित्व नेहरू जी पर आ पड़ा। यह बहुत बड़िन समय था परन्तु उन्होंने बड़े परिश्रम तथा योग्यता से राष्ट्र के भावी विकास के लिए आवश्यक सभी बातों की आधारशिलाए रख दी। उनका माग दशन में संविधान बना, योजना आयोग ने कार्य आरम्भ किया, महत्वपूर्ण उद्योग सँभल लिए गए, विविध क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए गम्भीर स्थापित की गई, समाजशास्त्री डॉक्टरों विकास का लक्ष्य स्वीकृत किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उन्होंने गुट निरपेक्ष आगे लाने की जबरदस्त धुरान की। मगर यह सब वे इन सब कार्यों का संचालन करते रहे।

संविधान सभा— भारत के लिए एक वायपूर्ण संविधान बनाने की मांग या लक्ष्य बहुत पुराना कहा जा सकता है। प्रातिवारियों ने इस विषय पर जो ध्यान दिया, वह 1923 में रचित हिंदुस्तान प्रजातान्त्रिक संघ के संविधान में प्रतिफलित था। इसमें बनाया गया था कि 'फेडरल रिपब्लिक ऑफ हिन्दुस्तान स्टेट्स ऑफ इण्डिया' यानी भारत के गणतन्त्र राष्ट्रों का प्रजातान्त्रिक संघ स्थापित करना हमारा लक्ष्य है। मरदार भगवति ने इसमें 'समाजशास्त्री' नाम जोड़कर इसे पूरना तक पहुँचा दिया था।

कांग्रेस के अन्दर भी संविधान सभा की मांग बहुत प्रचल थी। 1934 की कांग्रेस कार्यसमिति के एक प्रस्ताव में यह कहा गया "मरदारी श्रमों का एकमात्र माग जनक विकास यह है कि बालिक सावजनिक मताधिकार या जहाँ तक हो सके, उनका आम नाम के हक में चुनी हुई संविधान सभा होनी चाहिए। यह हो सकता है कि मरदार पूरा अन्वगम्य करन अपने नाम के मन में अपा प्रतिनिधि चुने।" इसके बाद 1937 में फैजपुर कांग्रेस, 1938 में त्रिपुरा कांग्रेस, और 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस में यह मांग दुहराई जाती रही। 1945 के सिमला सम्मेलन में भी कांग्रेस ने नयी मांग की थी।

धमनिरपेक्ष परम्परा की वायव्य रगत हक स्वतंत्र भारत में डॉ० आरिफ़ खान, परम्पदीन अनी अहमद भारत के राष्ट्रपति बन और सिमला में पान ग्यायाधीन तथा फिर उपराष्ट्रपति रहे। यह पुनः सिमला समय जानी 'अपान' राष्ट्रपति है। संविधान सभा ने 9 नवम्बर 1946 को अपना कार्य शुरू किया था। मुस्लिम लीग ने इसका कार्य बाट यह कहकर किया कि लीग तो अलग राष्ट्र चाहती है। कई मामलों में संविधान सभा लक्ष्य के करीब रही यानी उस दृष्टि में भारत की यह पहली सभा भी रही। इसी 14 अगस्त की मध्यरात्रि में ब्रिटिश सरकार ने जलिन छद्म की। 26 अक्टूबर 1950 को जो संविधान लागू हुआ, उसमें बनने में करीब दो साल लगे। 1949 की 26 नवम्बर

को संविधान का प्रारूप तैयार होकर पारित हो चुका था। 1952 में नए संविधान के अनुसार चुनाव हुए।

**संविधान में सब धर्मों की समानता**—1950 को जो संविधान लागू हुआ, उसमें धर्मों के मानने वाला को समान अधिकार दिए गए। पाकिस्तान के साथ तुलना करने पर पता चलेगा कि वहां एक तो अधिकांश समय सैनिक शासन रहा, दूसरे भूटो के जमाने में (1971-1977) जब एक संविधान कुछ हद तक चला, उसमें भी गैर-मुसलमानों के लिए राष्ट्रपति आदि बनने का कोई अधिकार नहीं था। हिन्दूओं, ईसाइयों या पारसियों का तो यह अधिकार दिया ही नहीं गया, अहमदियों को भी 1974 में एक कानून के द्वारा मुसलमान मानने से इंकार कर दिया गया। अहमदिया कुरान और हज्ज-त मुद्रमन्त में आस्था रखते हैं, परन्तु वह यह नहीं मानते कि हज़रत अन्तिम पैगम्बर हैं। वे मिर्जा गुलाम अहमद का मानते हैं और उन्हें 'खलीफ़तुल मसीह' कहते हैं। पाकिस्तान में अहमदियों के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ से ही चल रहा है। 1953 में अहमदिया के विरुद्ध दण्ड हुए और सन्नाजा नाज़िमुद्दीन को सैनिक कानून लागू करके दण्डांकन पड़ा था। तब से बराबर अहमदियों का दमन जारी है। बहुत से अहमदिया पाकिस्तान से भागकर ग़रुषार्थी हो गए। वहां मायमूर्ति मुनीर की अध्यक्षता में इस विषय की मीमांसा के लिए एक आयोग बैठाया गया। उन्होंने उपसंहार में कहा कि बर्ताने बात यह है कि कुछ मुल्ताओं के अनुसार जो असली मुसलमान हैं, वही दूसरे मुल्ताओं के अनुसार काफ़िर हैं।

**भारतीय संविधान में स्त्रियाँ**—भारतीय संविधान में स्त्रियों को भी हर क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार दिया गया। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि कई यूरोपीय देशों में भी स्त्रियों को मतदान का अधिकार भारत के बाद मिला। पाकिस्तान में न तो मतदान है, न स्त्रियों को विवाह, तलाक़, पर्दा, गवाही के मामले में कोई अधिकार प्राप्त है।

**योजना आयोग**—पराधीन भारत में ही कांग्रेस के नेताओं का ध्यान योजना बनाने की ओर गया था। कांग्रेस ने 1938 में नेहरूजी की अध्यक्षता में (यह समय सुभाष कांग्रेस के अध्यक्ष थे) एक योजना समिति बनाई थी। उसकी काफ़ी शक्ति रिपोर्ट निकली थी, जो कई जिल्दों में छपी। दुर्भाग्य यह रहा कि प्रतिवेदन तैयार हो गए पर इसी बीच नेता जेल पहुँच गए। नेहरूजी ने 1 मई 1940 में कहा था 'स्वतंत्र और लोकतान्त्रिक राष्ट्र हमारा लक्ष्य है—ऐसा राष्ट्र जिसमें राजनैतिक, आर्थिक स्वतंत्रता होगी। योजना का क्षेत्र उत्पादन वितरण, उपभोग, विनियोग, व्यापार, आय, सामाजिक सेवाएँ तथा उन अन्य राष्ट्रीय क्रियाकलापों तक विस्तृत होगा जो परस्पर एक दूसरे का प्रभावित करते हैं। योजना का उद्देश्य सारी जनता के भौतिक और सांस्कृतिक मानवता का उन्नयन है।'

स्वतंत्रता के बाद सरकार ने ज़्यादा ही विभाजन की दुखद मारकाट में छुट्टी पाई, योजना का क्रम चालू हो गया। 1948 में सरकार की औद्योगिक नीति की घोषणा करते हुए कहा गया कि युद्धोद्योग, अणु ऊर्जा, रेल, कायला, लोहा इस्पात, हवाई जहाज उद्योग तथा खनिज क्षेत्रों में सरकार का लगभग एकाधिकार रहेगा।

अप्रैल 1950 में कांग्रेस अध्यक्ष की पुकार पर प्रदेश कांग्रेस कमेटियों तथा मुख्य शक्तियों का जो सम्मेलन हुआ, वह योजना सम्मेलन कहलाया और यह अधिवेशन गोविंद वल्लभ पंत का अध्यक्षता में हुआ। यही से भारतीय योजना आयोग की नींव पड़ी। 1952 के प्रथम आम चुनाव के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने अपनी योजनात्मक आर्थिक



नीति का पुनर्लेख किया। यह स्पष्ट कर दिया गया कि निजी उद्योग रहेगे परन्तु उन्हें सावजनिक क्षेत्र के साथ तालमेल रखकर चलना पड़ेगा।

शीघ्र ही पहली पंचवर्षीय योजना (1951-55) देश के सामने आई, परन्तु वह बाद की योजनाओं की तुलना में बहुत छोटी थी। योजना की एक तिहाई रकम खेती में इस कारण लगाई गई कि विदेशों से खाद्य का आयात रोका जाए। परिवहन और संचार में 23 प्रतिशत व्यय किया गया। पहली योजना काल में राष्ट्रीय आय 18 प्रतिशत बढ़ी। यह और बढ़ती यदि इसी बीच आबादी 6 प्रतिशत न बढ़ जाती। आबादी की वृद्धि को रोकने के लिए दूसरी योजना में जोरा के साथ परिवार नियोजन की व्यवस्था की गई, जो बाद की योजनाओं में बढ़ती गई। आबादी में वृद्धि हमारी उन्नति में सबसे अधिक बाधक है।

**देशी राज्यों वाला बल्लेबा—**यहां हम यह बता दें कि 1947 में जब भारत को स्वाधीनता मिली, तो दो टुकड़ों में बांटने के अतिरिक्त विदेशी शासक हमारे लिए दो समस्याएँ और छोड़ गए थे। भारत में लगभग चौमाई इलाके ऐसे थे, जिनमें दसवीं राजाओं का शासन था। इन राजाओं के साथ अंग्रेजों के संधिपत्र थे, जिनकी विशेष शर्तों के अनुसार वे अंग्रेजों के अधीन थे। ये देशी राज्य आकार और जनसंख्या की दृष्टि से एक गांव से लेकर पूरे प्रांत जैसे हैदराबाद, निरुवाकर आदि तक थे। यदि अंग्रेज चाहते, तो कह सकते थे कि भारत सरकार हमारी उत्तराधिकारी होने के नाते सर्वोपरि है, परन्तु उन्होंने ऐसे बल्लेबा के लिए जिनके अस्पष्ट बानावरण में राजाओं और नवाबों को यह गलतफहमी हो गई कि वे चाहें तो स्वतंत्र रहें और चाहें तो भारत या पाकिस्तान किसी में भी शामिल हो जाए।

हम बता चुके हैं कि कश्मीर का हिन्दू राजा इसी धारणा के कारण स्वतंत्र राजा बनने का स्वप्न देख रहा था कि पाकिस्तान ने उस पर हमला कर दिया। तब उसने भारत की मदद मांगी। भारत ने यह गुहार सुनी, पर इस बात पर कि वहां जनता का धार्मिक जनता की प्रतिनिधि नेशनल काँग्रेस और उनके नेता नेहरू का शासन हो। राजा को यह मानना पड़ा और अन्त तक यही भी छोड़नी पड़ी। स्मरण रखने की बात है कि भारत ने मुस्लिम प्रजा का पक्ष लिया न कि हिंदू राजा का।

**प्रजामण्डल—**अब देशी राज्यों का विलय तरह-तरह के पैंचों के अधीन हुआ। सबसे बड़ा पैंच था प्रजामण्डल का। कांग्रेस ने देशी राज्यों के आंदोलन को अपने से अलग रखा था परन्तु उनमें सबत्र प्रजा आंदोलन प्रबल था। कई जगह प्रजामण्डल इतने शक्तिशाली थे कि वे चाहते तो बिना बाहरी मदद के अपने राजा या नवाब को आसमान दिखा सकते थे। अंग्रेजों के जमाने में राजा या नवाब की सहायता के लिए ब्रिटिश भारत से फौज आ सकती थी, परन्तु अब स्वराज्य के बाद स्थिति बदल गई थी। कांग्रेस के नेता सरदार पटेल इस बात को समझते थे। जब उन्नीसवें राजा विलय के विपक्ष में कुछ बोले, हने कृष्ण महताब और सरदार पटेल ने भट्ट कह दिया—“यदि आप हमारे प्रस्ताव को नहीं मानते तो हम आपके राज्य में कानून और व्यवस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, आप जानें और आपका काम जानें।” नतीजा यह हुआ कि राजा साहब जल्दी राह पर आ गए।

देशी राज्यों के प्रजामण्डल कांग्रेस से अलग होत हुए भी एक हद तक उससे अभिन्न भी थे। जवाहरलाल नेहरू ने 15 फरवरी 1939 को ‘अखिल भारतीय प्रजामण्डल सम्मेलन’ के लक्ष्मियाना अधिवेशन में कहा था “कुछ लोगों ने देशी राज्यों में चलने वाले आंदोलन के प्रति कांग्रेस के रुख की समय-समय पर आलाचना की है और हस्तक्षेप

और अहस्तप क विषय में गर्मागर्मी हुई है। इस समय मैं मे आलोचना और तक श्रितक प्रश्न की बात बनकर अब निरपेक्ष हो चुके हैं। फिर भी संक्षेप में देशी राज्या का प्रति शासन की नीति के विकास पर दृष्टिपात वाछनीय है। इस नीति की सारी अभिव्यक्तियों को समझना कुछ पहलुओं पर ही जोर देना मैंने पसंद नहीं किया। परंतु मैं निश्चित कि मौलिक नीति परिस्थितियों को देखते हुए मही रही और बाद का होन वाली स्थिति से उसका अनुमोदन हुआ है। श्रान्ति या आमूलचूल परिवर्तन के लक्ष्य के लिए शासनपद्धति अपनाई जाए, उसे वास्तविकता तथा उस समय की परिस्थिति में सम्पन्न कर चयना पड़गा। डीममूलक, जवानी जमाखच या लनतरानी प्रधान सारगभहीन ज्ञान, जिसका उस समय की परिस्थिति से कोई सामंजस्य नहीं है, शानिकारी परिवर्तन उत्पन्न नहीं कर सकते। न इसके लिए कृत्रिम रूप से स्थितियां पदा की जा सकती हैं और न जन आन्दोलन ही चालू किए जा सकते हैं, जब तक कि जनता तयार न हो। शासन इस तथ्य में परिचित है और जानती है कि देशी राज्यों की जनता अभी तैयार नहीं है। यह देशी राज्यों के बाहर सपना में अपनी शक्ति लगाती रही, यह समझकर कि इसी उपाय से देशी राज्यों की जनता को अपने लिए मघप करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।"

कांग्रेस की नीति का मथन करते हुए और स्पष्टता के साथ नेहरू ने कहा 'देशी राज्यों में चलने वाले आंदोलन के सम्प्रदाय में कांग्रेस की नीति के विकास में निम्न का प्रस्ताव एक मील का पर्यय रहा और उसमें हमारी कार्यपद्धति का सुलासा शक्ति प्राप्त गया। जिस स्वतंत्रता के लिए हम लड़ रहे थे, भारत की एकता और अखंडता का अवरिहाय अग रही और हम यह चाहत रहे कि बाकी भारत को जिस हद तक शान्ति सामाजिक और आर्थिक आजादी मिले, देशी राज्यों की जनता को भी उस शक्ति आजादी प्राप्त हो। इस मामले में कोई समझौता संभव नहीं है।"

दुर्गादास का कहना है कि कांग्रेस देशी राज्यों को अभी छोड़ना नहीं चाहती थी। स राज्या में अलवर और भरतपुर थे। महात्माजी की हत्या की जांच करते हुए यह सा गया कि हत्या वाली पिस्तौल अलवर के महाराजा के शस्त्रागार से आई थी और अलवर में ही गोशिया चलाने का अभ्यास किया गया था। उस समय एन० बी० खरे अलवर के मुख्य मंत्री थे। महात्माजी ने उन्हें मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्रित्व में निवाला था, शक्ति खरे महाराजाजी से बिछे हुए थे। इही दिनी अलवर के विदेश प्रशासन ने एक रिपोर्ट यह भेजी कि अलवर और भरतपुर भारत सरकार का तटता उलटने का शयन कर रहे हैं। जो बात सबसे ज्यादा उनके खिलाफ गई और जिससे नेहरू बहुत दुःख हुए, वह यह थी कि य राजा अपनी भेव मुस्लिम प्रजा को राज्यों से भगा रहे थे। नेहरू के कारण माउंट बटन को झुकना पड़ा। राजाओं ने फिर भी पड़पत्र करना चाहा, परन्तु सरकार को सब खबर मिलती रही और उनकी एक नहीं चली।

राजप्रमुख — भारत सरकार की ओर से कुछ मुख्य देशी राजाओं को राजप्रमुख शक्ति प्रिया गया, जिससे उन्हें ऐसा लगा कि उनकी आकांक्षा पूरी हुई और वे भारत में शान्ति हो गए।

हैदराबाद — हैदराबाद का निम्सा कश्मीर की तरह था। कश्मीर में प्रजा मुख्यतः मुसलमान थी और राजा हिंदू था, यहां निजाम मुसलमान था और प्रजा हिंदू। माउंट बटन 29 जून 1948 का भारत से चले गए और सी० राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बन। निजाम से कहा गया था कि तुम सीधे से दूसरे राजा राजाओं की तरह भारत में अन्तर्मुक्त हो जाओ, परंतु वह पाकिस्तानी मनावृत्ति के

सलाहकारों से घिरा हुआ था।

सरदार पटेल ने अपने खास आदमी के० एम० भूशी का भारत सरकार व प्रतिनिधि के रूप में हैदराबाद भेजा। भूशी ने रिपोर्ट दी कि प्रजा तयार है, उसे हथियार मिल जाए तो अभी निजाम आँधे मुह गिरा लिखाई देगा। पर सरदार न सलाह नहीं मानी। उनका कहना था कि यदि जबदस्ती ही करनी है तो सरकार करेगी।

**पुलिस एक्शन**—कुछ दिनों बाद भारत सरकार को यह खबर मिली कि निजाम पुतगाली सरकार से गोवा खरीदने की बातचीत चला रहा है ताकि समुद्र का रास्ता खुल जाए, जिससे पाकिस्तान के साथ सीधा सम्पर्क स्थापित हो सके। यह भी पता लगा कि निजाम ने पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपये उधार दिए हैं ताकि जिन्ना उसका साथ दे। इस पर नेहरू और पटेल ने मिकंदराबाद छावनी में फौज भेज दी। फौज के हैदराबाद में घुसने पर 'पुलिस एक्शन' सम्पूर्ण हो गया। इससे पहले दो बार 'पुलिस एक्शन' स्थगित किया गया था। तीसरी बार भी निजाम के अनुरोध पर गवर्नर जनरल नेहरू से कहकर उसे रकवा रहे थे कि उन्हें बताया गया कि काम तो हो चुका। नेहरू ने 10 सितम्बर को इसकी घोषणा की, 17 सितम्बर को निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस बीच पाकिस्तान ने हैदराबाद 'आक्रमण' पर संयुक्त राष्ट्र में शिकायत उठाई। सोवियत संघ, यूनेस्को और चीन निष्पक्ष रहे। 19 सितम्बर को नेहरू ने घोषणा की कि हैदराबाद राज्य के भविष्य का निर्णय वहाँ की जनता की इच्छा के अनुसार होगा। जिन्ना को कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ सबत्र हार खानी पड़ी। यह स्पष्ट है कि जिन्ना किसी सिद्धांत का पाबंद नहीं था। वह हिंदू प्रधान इलाकों को भी हड़पना चाह रहा था।

## आवडी कांग्रेस 1955

पहली योजना-बाल म 1955 की जनवरी को कांग्रेस का आवडी अधिवेशन हुआ, जो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि उसमें पहले पहल समाजवादी ढांचे को लक्ष्य के रूप में स्वीकृति दी गई। इस समय तक भारत के फ्रांस नासित इलाक़ भी भारत में आ चुके थे। अध्यक्ष डेबर ने इसका उल्लेख करते हुए बताया कि फ्रांस तो मान गया है परन्तु पुतगाली अभी तक अड़ हैं। डेबर ने कहा "पुतगाली शासन में विसर्त और संप्राम करते अपने भाइयों और बहनों को हम पूरा नतिक समर्थन प्रेरित हैं। हम पुतगाली सत्कृति के विरोधी नहीं, परन्तु भारत की स्वाधीनता का अर्थ है भारत के अपने अपने जमीन की स्वाधीनता।"

डेबर के भाषण में स्त्रियों की उन्नति पर विशेष रूप से बल दिया गया। कहा गया कि स्त्रियों की द्रुत उन्नति के बिना देश की आधी शक्ति अप्राप्ति रहेगी।

**समाजवादी ढांचा और समाजवाद**—इस अधिवेशन में समाजवादी ढांचे को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। श्री नेहरू 1929 की कांग्रेस में ही अपने को समाजवादी और प्रजातन्त्रवादी घोषित कर चुके थे। 'समाजवादी ढांचा और 'समाजवाद' एक है या भिन्न, इस विषय पर नेहरू ने अप्रैल 1956 में कहा "कुछ लोग समाजवादी ढांचा और समाजवाद में बारीक फर्क बताते हैं पर दोनों एक हैं।"

जसल में देखा जाए तो लाहौर कांग्रेस से ही कांग्रेस के अंदर समाजवादी विचार धुंधलाते रहे थे खुलकर भ्रमक उठने का मौका अब समाजवादी मिलने के बाद आवडी में आया।

नेहरू ने समाजवादी ढांचे वाले प्रस्ताव की व्याख्या करते हुए कहा 'स्वतंत्रता

सशम के किसी भी सोपान में हमारी दृष्टि राजनैतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं रही, बराबर स्वतंत्रता की अतृप्त वस्तु में वृद्धि होती रही। सदा आर्थिक पहलू पर हमारी आँखें लगी रही। हम किसान, मजदूर, दलितों और वंचितों के विषय में सोचते रहे। हमने अक्सर यह कहा कि हम ऐसा समाजवादी ढांचा चाहते हैं, जो भारतीय प्रतिभा के अनुकूल हो। हम कल्याणकारी राज्य चाहते हैं। कल्याणकारी राज्य के बिना समाजवादी ढांचा अकल्पनीय है। हम कठिन परिश्रम से ही समाजवाद प्राप्त कर सकते हैं, न कि प्रस्ताव या सरकारी हुक्मनामे से। हम अधिक से अधिक उत्पादन करें और ठीक से न्यायपूर्ण ढंग से वितरण करें। हमारी आर्थिक नीति का उद्देश्य होगा—प्रचुरता।”

## कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1956

1956 में अमृतसर में यू० एन० डेबर की अध्यक्षता में कांग्रेस का 61वां अधिवेशन हुआ। इस बीच यानी आठवीं और अमृतसर के बीच दो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए

(क) इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया को सावजनिक व्यवस्था में लाकर स्टेट बैंक आफ इण्डिया का गठन।

(ख) जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण।

स्वाभाविक रूप से अमृतसर कांग्रेस ने इन कदमों का स्वागत किया। इसमें फिर से समाजवादी ढांचे पर जोर दिया गया।

## इंदौर अधिवेशन 1957

जनवरी 1957 में इंदौर में अधिवेशन हुआ और इसके अध्यक्ष भी श्री डेबर ही रहे। इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में जहाँ केवल 'सहकारितामूलक कामनवेल्थ' था, वहाँ उसमें 'समाजवादी' शब्द जोड़ दिया गया।

श्री नेहरू ने इस अवसर पर कहा “मैं समाजवाद को एक दृढ़शील, गतिशील धारणा के रूप में लेता हूँ, जो प्रतरीभूत अचस अटल न हो, जो मानव जीवन तथा देश की उपनधिषियों के साथ तालमेल रखे।”

## गुवाहाटी कांग्रेस 1957

कांग्रेस का 63वां अधिवेशन गुवाहाटी में हुआ। इसमें भूमि सुधार पद्धति पर विशेष जोर दिया गया और कहा गया जहाँ समर्थ हो, खेतिहरों की सम्मति से सहकारी खेती का प्रवर्तन किया जाए।

## नागपुर कांग्रेस 1958

नागपुर में इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस का 64वां अधिवेशन हुआ। जिसमें नियोजन पर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया गया। इसमें कहा गया

1. सावजनिक उद्योग तथा सरकारी व्यापार को बढ़ावा दिया जाए ताकि सावजनिक क्षेत्रों के लिए अधिक साधन प्राप्त हों।

2. आयात पर कड़ाई से नियंत्रण किया जाए ताकि अनावश्यक आयात न हो और विदेशी मुद्रा को बचत हो।

दावजूद वे अपने ही धार्मिक मानदण्डों से भी कनई धार्मिक नहीं थे। वे सब दुश्चरित्र और लम्पट थे। वे धर्म का इस्तेमान करके अपने शोषण को चिरस्थायी बनाना और मौज उड़ाना चाहते थे।

श्री कुहा लिखते हैं "पुतगाली एक तरफ लूट-भार करत और दूसरी तरफ धर्म प्रचार करते थे। इसके लिए उन्हें पोष की सनद प्राप्त थी और वे सारी लड़ाइयाँ ईसाइया के चिह्न कास और तलवार के तहत लड़ते थे। वे भारत में हिंदू धर्म का अस्तित्व नकारते हुए यह ममझकर चलते थे कि यहाँ सब ईसाई हैं। प्रारम्भ में उनकी धार्मिक घणा की तोप का मुह मुस्लिमों की तरफ था क्योंकि वे ही उनके प्रतिद्वंद्वी थे। उन दिनों कुछ इन गिने नस्तोरियन ईसाई यहाँ थे, जो बाप को कैथोलिक बन गए। पर पुतगालियों के दिमाग पर यह जुनून सवार था कि भारत के सब लोग ईसाई ही हैं और इसी पागल पन से परिचालित होकर बास्काडिगामा न बालीकट के एक हिंदू मंदिर को ईसाई गिर्जा समझा था और उसके अंदर प्रतिष्ठित वाली की मूर्ति को भरियम समझकर उसे अघ्य चढ़ाया था। पुतगालियों द्वारा सबसे पहले कुछ वेश्याएँ ईसाई बनाई गई। सुंदरा वेश्याओं को प्रचुर उपहार देकर और धर्मका बर ईसाई बनाने का उद्देश्य यह था कि पुतगाली सैनिक हुराम करने से बचाए जाए। गोवा में अलबुकर्क ने अपने सैनिकों की शान्ति, तुर्की अफसरों की छीनी हुई बीवियाँ और बेटियाँ से कराई। ये तुर्की अभय देकर जहाज पर सपरिवार बुलाए गए थे। परंतु पहुँचने पर पुरुषों को तलवार के धात उतारकर उनकी बीवियाँ और बेटियों का सैनिकों के सुपुंर कर लिया गया।"

मत जेवियर ऐसे लोग भी अत्याचारों के दावजूद ईसाई धर्मप्रचार में सफल नहीं हुए। इसलिए उन्होंने तुरावर पुतगाली सम्राट को यह लिखा कि आप अपने गोवा स्थित कमचारियों का यह आदेश देते रहें कि उनको तभी मफल प्रशासक माना जाएगा जब वे धर्म का झण्डा फहराने में अपनी पट्टा दिखाएँ। पान्नी जनता पर अनग जुल्म करते थे। वे धर्म प्रचार के नाम पर शान शोक्त ही जिंदगी बिताते रहे। वे कामुक और लोभी थे। अपनी पासबिक बतियों को चरितार्थ करने के लिए वे भारतीयों पर खलक अत्याचार करने थे, यहाँ तक कि ईसाई बनाए गए लोगों का भी नहीं बर्खास्त था। 1910 में पुतगाल में प्रजातन्त्र कायम होने के साथ साथ देश के अंदर गिरजा और राष्ट्र का अलगाव हुआ गया, पर पुतगाल के भारतीय साम्राज्य में पादरियों की दुष्टता और मन मानी जारी रही।

1926 में पुतगाल में फामिस्ट अधिनायकवाद का बोलबाला हुआ। पुतगाल में सब तरह की स्वाधीनता नष्ट हो गई। मारी राजनीतिक पार्लिया निषिद्ध हुआ। अल वारों का कण्ठारा किया गया। गोवा की भाषा नाकणी है। गोवा के बाहर भी 7000 बग मीन तक यह भाषा प्रचलित है। भाषा विज्ञान व विद्वान इस भाषा को गोमंतकी कहते हैं। पर मराठी भाषी इस मराठी की एक बोली भाषा मानते हैं। गाँवा पर चार शताब्दी शासन में पुतगालियों ने नाकणी का खूब दबाया और फिर भी पुतगाली शासन काल में मा मा तीन प्रतिशत लोग ही पुतगाली का ज्ञान प्राप्त कर सके। पुतगाली शासन में शराब का खूब प्रचार प्रसार हुआ। पुतगाली शासन में सबसे अधिक यानी 20 प्रतिशत राजस्व शराब से आता था। गाँवा में शराब के कई कारखाने हैं।

पुतगालियों ने 1510 के पहले भोवे में ही हर मुसलमान को मारकर मारी मस्जिदें तोड़ दी थी। एक ही दिन में एक जगह 6000 मुसलमान मार लिए गए थे। मुसलमानों पर इस विरोध अत्याचार का कारण यह था कि वे शामक जाति व ममझ जात थे। मस्जिदों की सम्पत्तियाँ गिरजा का मोष कर धर्म का ढका बजाया गया। हिंदुओं की

बारी आई तो घर के अंदर भी कीतन निषिद्ध करार दिया गया, तुलसी का पेड़ उगाना, घोती या चोली पहनना भी जुम बना दिया गया।

जब भारत स्वतंत्र हो गया, तो गोवावासी बहुत विचलित हुए, पर वे सबसे अधिक विचलित तब हुए जब फ्रांसीसियों ने अपने भारतीय उपनिवेशों को भी स्वतंत्र करके उन को सौंप दिया।

**स्वातन्त्र्य सप्राप्त**—पुतगाली यह प्रचार करके दुनिया की आंखों में धूल भोक्ने लगे कि फ्रांसीसी उपनिवेशों से गोवा का मामला भी न इस कारण है कि गोवावागमिया में 70 फीसदी जनता पुर्तगाली रक्त की है। परंतु गोवा के स्वातन्त्र्य आंदोलन की विशेषता यह थी कि न केवल इसमें ईसाई पूरी तरह शामिल थे, बल्कि वे बराबर गोवा को भारत का अविच्छेद अंग मानकर चल रहे थे। गोवा के स्वातन्त्र्य योद्धाओं का वे ब्रम्हर्षि था, जहां से उनको धन और प्रचार सम्बन्धी सहायता प्राप्त होती रहती थी। गोवा सरकार लोग ब्रम्हर्षि मठकर आंदोलन को बल पहुंचाते थे। वही पूरा साहित्य छपता और चोरी से गोवा भेजा जाता। 10 नवम्बर, 1954 को मुक्त गोवा की एक घोषणा में पुतगाली साम्राज्यवादियों को यह चेनावनी दी गई कि वे फ्रांसीसियों की तरह बिना रक्तपात के गोवा त्याग दें। इस घोषणा के अंत में यह कहा गया कि पाण्डिचेरी तथा चंदन नगर में जिस काय का गुभारम्भ हुआ, उसकी पूर्णाहुति गोवा की स्वतन्त्रता से हो।

यहां यह बता दें कि भारत के प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू को जब भी गोवा पर प्रश्न किया जाता, तो वह जो भी कहते, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखकर कहते। उससे गोवावासियों को निराशा होती थी। गोवा पर भारत सरकार बहुत देर में किमी ठोस निगम पर पहुंची।

**दादरा, नगर हवेली स्वतंत्र**—1954 में गोवा के कांग्रेसी भी समझ गए कि केवल प्रस्तावों से कुछ नहीं होगा। पीटर अल्वारिस के नेतृत्व में फिर से जोरों के साथ संगठन चालू हुआ। एक नई समिति बनी जिसके अध्यक्ष पुडलिक गायतोडे बने। पुतगाली पुलिस को पता लगा और पुडलिक गायतोडे को पकड़कर पुतगाल की जेल में भेज दिया गया। गोवा के स्वातन्त्र्य योद्धा ब्रम्हर्षि और गोवा के बीच दौड़ने लगे। ब्रम्हर्षि ने 'आजाद गोवा' का दफ्तर खुले आम काय कर रहा था। तब हुआ कि दादरा तथा नगर हवेली को पहले चरण में मुक्त किया जाए। पर प्रश्न था कि क्या ब्रम्हर्षि के सर्वोच्च मोरारजी देसाई इसे स्वीकार करेंगे? उनसे आतिशय बात करने लगे। वही कठिनाई से मोरारजी तयार हुए, तब 1954 में 22 जुलाई को दादरा नगर हवेली को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। ब्रम्हर्षि के घर में दलीय नेताओं के सहयोग से यह सम्भव हुआ।

**गोवा मुक्त**—पर यह तो प्रतीकात्मक विजय थी। आजाद गोमंतक (नेता विश्वनाथ लावेदे) और गोवा लिबरेशन आर्मी (नेता शिवाजी देसाई) ये दो आतिशय दल बराबर काय कर रहे थे, पर कोई भी आतिशय या मुक्तिपथ तब तक सफल नहीं हो सकता, जब तक कि सेना को मिला न लिया जाए। यह शर्त यहां पूरी नहीं हो सकती थी, क्योंकि सेना पुतगाली थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो गोवा की मुक्ति बहुत कठिन थी। अंतर्राष्ट्रीय जनमत से कुछ आशा करना गलत था, क्योंकि उस पर साम्राज्यवादियों का कब्जा था। फिर भी दादरा नगर हवेली की स्वाधीनता के बाद हवा ऐसी बनती चली गई कि भारत सरकार ने 19 दिसम्बर, 1961 को गोवा के भीतर अपनी फौज भेजनी पड़ी और करीब-करीब बिना रक्तपात के गोवा आजाद कर दिया गया। अगुआदा पड़ म जो छोटे मोटे स्वातन्त्र्य योद्धा बाद में वे मुक्त कर दिए गए, परन्तु कई महत्वपूर्ण

व्यक्ति पुतगाल की जेलों में पड़े थे, वे नहीं छोड़े गए। व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय जनमत गोवा के हमले पर खूब शोर मचाता रहा, परन्तु इन कदमों के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा। बहुत बाद में वे पुतगाल की जेलों से सजा की अवधि पूरी करने के बाद रिहा किए गए।

**गोवा अधिग्रहण की निंदा** - अनेक देशों और पाकिस्तान में इस घटना की यह कहकर निंदा की गई कि भारत विस्तारवादी और साम्राज्यवादी है और वह गांधी के आदर्शों से गिर चुका है। पुतगाल को भड़काया गया कि वह अपना बड़ा भेजकर फिर से गोवा पर अधिकार जमा ले। परन्तु पुतगाल ने यह बकबूफी नहीं की। किसी समय देश ने यह नहीं कहा कि इस विषय पर गोवा वाला को भी राय ली जाए।

**चीनी आक्रमण** गोवा को आजाद कराने के बाद सबसे बड़ी घटना चीनी आक्रमण है, जो 1962 के 19 अक्टूबर को एकाएक बिना मेघ के वृष्टपात की तरह घटित हुआ क्योंकि देश में तुरावर वर्षा में 'चीनी हिन्दी भाई भाई' का नारा गूँज रहा था।

भारत और चीन में सैकड़ों वर्षों की दोस्ती और आदान प्रदान रहा है। स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान चीन के नेता सुन यातमेन की जीवनी उसी चाव से भारत में पढ़ी जाती थी, जैसे इटली के मैजिनी, गैरीबाल्डी, और आयरलैंड के डिक विलेरा डानब्रिन की जीवनी पढ़ी जाती थी। जब 1949 में चीन में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में क्रान्ति हुई, तब से भारत की परम्परागत दोस्ती और प्रबल हो गई चीन भी पूरी तरह ईमानदार रहा। इसका एक प्रमाण यह है कि एक बार जब नेपाल के प्रधानमंत्री तनसाप्रसाद आचार्य ने सरकारी भोज में नेपाल चीन की दोस्ती का नारा दिया तो माओ ने जो उस भोज में उपस्थित थे, वक्तव्य को सुधारते हुए कहा—'नेपाल चीन भारत की दोस्ती।' प्रसिद्ध पत्रकार दुर्गादास ने अपनी पुस्तक 'इण्डिया क्राम कजन टू नेहरू ऐण्ड आपटर' में इस घटना का उल्लेख किया है।

दोनों देशों में सब कुछ ठीक चलता रहा। हा, सीमांत पर कुछ आलोचना होती रही। नेहरू चाहते थे कि चीन मैकमोहन रेखा को मान्यता दे, पर बाऊ एन लाई बदले में अक्सर चीन का इलाका चाहते थे। नेहरू को इनमें विशेष आपत्ति नहीं थी क्योंकि, जैसा कि उन्होंने कहा, उस इलाके में घास की एक पत्ती भी नहीं उगती। परन्तु जान कसे इसकी भनक विरोधी पक्ष के कानों में पहुंच गई। इस मसदे में बावेला मच गया कि देश को बेचा जा रहा है। नतीजा यह हुआ कि चीन और भारत की बातचीत में खिद पदा हो गई।

परन्तु किसी को भारत पर चीनी आक्रमण का भय नहीं था। इसलिए जब आक्रमण हुआ, वह आकस्मिक लगा। भारत इसके लिए तैयार नहीं था, न मानसिक रूप से, न सैनिक रूप से। नतीजा यह हुआ कि चीन भारत में घुस आया। पर वह बहुत आगे न बढ़कर लौट गया। क्यों लौटा, इस पर बहुतों का कहना है कि चीन भी इससे ज्यादा के लिए तैयार नहीं था।

जो हो चीन के इस काय से भारत की जयहमाई हुई और लोग इनने नाराज हुए कि नेहरू को रक्षामंत्री मेनन को मंत्रिमण्डल से निवालेना पड़ा। मेनन योग्य पर जिद्दी व्यक्ति थे। इसके बाद सुरक्षा उद्योग का जो सिलसिला चला, उसका परिणाम यह हुआ कि तीन वर्ष बाद 1965 में जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो भारत सामना करने के लिए तैयार था। इस दृष्टि से देखा जाय तो चीनी आक्रमण ने हमें सैनिक रूप से जगाकर हमारा कल्याण ही किया।





तथा संविधान के नियामक सिद्धांतों की याद दिलाते हुए समाजवादी लक्ष्य की ओर भुवनेश्वर में विशेष ध्यान दिलाया गया। कामराज ने आशा प्रकट की कि वर्ग संघर्ष के बिना भी हम समाजवाद प्राप्त कर सकते हैं।

भुवनेश्वर में जो प्रस्ताव पारित हुए, उनमें और बातों के अलावा सावजनिक सेवाओं में लगे हुए लोगों की मनोवृत्ति बदलने की बात भी कही गई। यह महसूस किया जा रहा था कि नीकरशाही अड़मनाजी कर रही है।

जवाहरलाल नेहरू का देहांत—1962 के माघ में ही नेहरू का स्वास्थ्य खराब होने लगा था, पर कोई गंभीर बात नहीं थी। चीनी आक्रमण का उनके मन और स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ा था। मना करने पर भी वे भुवनेश्वर कांग्रेस में गए और 27 मई, 1964 को वही उनका देहान्त हो गया। श्री नेहरू 17 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। जब से सरदार पटेल का देहांत हुआ था, तब से वही शासन तथा कांग्रेस संस्था में सर्वोपरि थे।

नेहरू की वाणी—नेहरूजी ने 1949 में, जब भारत का विधान तैयार हो रहा था, लाल किले से कहा था "मुझे हिन्दुस्तान में प्यार है। मुझे भारत के भविष्य में भरोसा है कि आइंदा इसकी शक्ति बढ़ेगी और शक्ति खाली इस तरह से नहीं बढ़ेगी कि वह एक फौजी शक्ति हो। ठीक है, एक बड़े देश की फौजी शक्ति भी होनी चाहिए लेकिन असल ताकत होती है उसकी काम करने की शक्ति, उसकी मेहनत करने की शक्ति। अगर हम इस देश की गरीबी का दूर करेंगे तो बानूनों से नहीं, और गुल मर्चा के नहीं, शिक्षाएँ करके नहीं, बल्कि मेहनत करके। एक एक आदमी, बड़ा और छोटा, मद औरत और बच्चा मेहनत करेगा। हमारे लिए आराम करने का समय नहीं है। स्वराज्य आया आजादी आई तो यह न समझिए कि हमारा आपके आराम करने का समय आया है। नहीं, यह मेहनत करने का समय आया है। लेकिन पहले की उस मेहनत में और आज की इस दूसरी मेहनत में एक बड़ा फर्क है। वह मेहनत है एक गुलाम की मेहनत, यह मेहनत है निर्माण के लिए आजाद आदमी की मेहनत। हम अपने घर को बनाना है अपने देश को बनाना है और आइंदा नसला के लिए एक बड़ी मजबूत इमारत खड़ी करनी है। यह मेहनत एक शुभ मेहनत है अच्छी मेहनत है जो दिल को भाती है। और फिर इस मेहनत में एक एक इंसान और एक एक पत्थर जा हम रखते हैं, याद रखिए हम और आप गुजर जाएंगे, लेकिन वे ईंटें और पत्थर ज़ायम रहेंगे और आइंदा सड़कें घरें बाँटें वे एक यादगार होंगे और दुनिया का सामन और हमारी आइंदा नसलों के सामन इस शक्ति में होंगे कि एक जमाना आया था जब कि आजाद हिन्दुस्तान की बुनियाद इस तरह से पड़ी और जब इस तरह मेहनत में, पसीन में, खून उहाकर भारत की यह इमारत बनी।

इसमें सन्देह नहीं कि गांधीजी ने यह अच्छी तरह जानत हुए भी कि नेहरू अनेक मामलों में उनके साथ मतभेद रखते हैं, उन्हीं को अपना उत्तराधिकारी बनाया था क्योंकि कांग्रेस के सारे नेताओं में वही युग के लिए सबसे उपयोगी थे। नेहरूजी ने माशेल टीटो के साथ मिलकर जिम गूटनिरपेण आन्दोलन का प्रारम्भ किया, वह लालबहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के हाथों पलकर विश्व शांति की रक्षा में सबसे बड़ा घटक बन चुका है इसमें कोई सन्देह नहीं।

## इन्दिरा शासन की उपलब्धिया

नहरू जी के पश्चात् देश की वागडोर श्री लाल बहादुर शास्त्री के हाथ में आई, और यद्यपि भारत पात्र युद्ध में उनका नेतृत्व बहुत सफल रहा, परन्तु उनका दहात भी शीघ्र ही हो गया। उनके पश्चात् श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री बनी, जो जनता शासन के कुछ वर्षों को छोड़कर, 1984 के अंत में, सिख आतंकवादियों के द्वारा उनकी हत्या किए जाने के समय तक, इस पत्र पर बनी रही। देखा जाय तो लगभग इसी समय कांग्रेस की शताब्दी भी पूरा होती है। इन्दिरा शासन में देश ने विकास के न केवल नए कदम उठाए, अनेक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण सफलताएं अर्जित की।

**लाल बहादुर शास्त्री** —नहरू के बाद बने भारत के प्रथम मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री तब हुए स्वातंत्र्य योद्धा थे, साथ ही उच्च पदों पर योग्यता से काम कर चुके थे। वह उत्तर प्रदेश में गांधी वल्लभ पत्र के सचिव रहे थे, फिर वे द्र में रेल मंत्री रहे। यो मोरारजी देसाई प्रधान मंत्री होना चाहते थे, परन्तु कांग्रेस अध्यक्ष कामराज लाल बहादुर के पक्ष में थे। लाल बहादुर का मधुर स्वभाव के कारण कुछ लोग उनका अवमूल्यन भी करते थे, परन्तु पहली बार जब बहाल विप से बोले तो लोगों ने उन्हें सही पहचाना। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि किसी प्रकार की गलत हरकत बर्णित नहीं की जाएगी। पाकिस्तान को पटन टैंक आदि बराबर मिल रहे थे और उसकी ओर से कश्मीर का प्रश्न उठाया जा रहा था।

**कश्मीर समस्या** —शेख अब्दुल्ला ।। बप नजरबंद रहने के बाद (उन पर हर महीने 14 हजार रुपये खर्च होते थे) 8 अप्रैल, 1964 को छोड़े जा चुके थे। पहले शेख कुछ नाराज रहे पर नेहरू के हार्दिक व्यवहार से वह जन्म ही समझ गए कि पाकिस्तान में मिलना कश्मीर के लिए आत्महत्या होगी। पर वह सहसा क्रोध फसला न कर सके। वह बीच में यह भी मोचत रहे कि भारत, पाठ और काश्मीर मिलकर एक संध बना लें। पाकिस्तानी तानाशाह अयूब ने अपनी आ मक्या फ्रेडस नाट मास्टम' (एक अमरिवन पत्रकार की बलम की बरामात) में लिखा है 'शेख अब्दुल्ला मेरे पास भारत, पाठ और कश्मीर के कनफेडरेशन का बरामाती प्रस्ताव ले आया था।' परन्तु इस सम्बन्ध में पूछे जाने पर अब्दुल्ला ने कहा, 'मैंने कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं रखा था।'

**मूए मुन्ददक (पवित्र केश) कांड**—1963 के नवम्बर में नेहरूजी के जीवन काल में श्रीनगर की हजरतवल मस्जिद से पैगम्बर का पवित्र केश गायब हो गया था। इसका दुर्भाग्यवश सांस्कृतिक बमनस्य पदा किया गया, यहा तक कि कलकत्ते तक में दंग हो गए। कश्मीर में भी गडबड हुई। कश्मीर के नेता एक दूसरे पर दोष लगाते रहे। पवित्र केश का चार उमर तस्ती से पाकिस्तान भेजते हुए पकड़े गए, पर मौलवी फारुक ने यह कहकर मामल को और जटिल बना दिया कि यह असली केश नहीं है। नेहरूजी के

प्रतिनिधि के रूप में लालबहादुर शास्त्री ने इस अवसर पर बड़ी बुद्धिमानी से देश की शनाख्त कराई और इस प्रकार भारत के दुश्मनों को झगडा कराने के एक बहाने से वंचित कर दिया। इस समस्या को सफलतापूर्वक निपटाने के लिए लालबहादुर शास्त्री की बहुत सराहना हुई थी।

कुछ भी हो, नेहरूजी के देहांत से इस दिशा में प्रगति रुक सी गई।

**बच्छ में गडबड**—1965 के जनवरी अप्रैल में पाकिस्तान ने बच्छ इलाके (3500 वर्ग मील) में गडबड शुरू कर दी। शीघ्र ही यहाँ फौज भी जा गई और पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध उन अमेरिकी अस्त्रों का उपयोग किया, जिनके सम्बंध में वह कह चुका था कि ये भारत के विरुद्ध इस्तेमाल के लिए नहीं, बल्कि साम्यवादी आक्रमण रोकने के लिए हैं। विदेशी पत्रों ने इस मुठभेड़ का हमेशा की तरह बहुत गलत वर्णन प्रकाशित किया। इस झगड़े के तुरन्त बाद शास्त्री जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब राष्ट्रमंडल सम्मेलन के सिलसिले में सदन गये। ब्रिटिश प्रधान मंत्री विलसन के बीच में पड़ने के कारण 30 जून 1965 को सामयिक युद्ध विराम हो गया।

**1965 का युद्ध**—नेहरूजी का देहान्त 27 मई 1964 को हुआ और दिसंबर में निष्कासित हुए। पाकिस्तान भीतर ही भीतर कश्मीर पर आक्रमण की तैयारी कर रहा था। प्रशिक्षित घुसपैठिए कश्मीर में घुस आए। अयूब को विश्वास था कि कश्मीरी विद्रोह में उठ खड़े होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस पर पूरी लड़ाई छिड़ गई जो 1 से 23 सितम्बर 1965 तक चली। इसमें 2226 भारतीय सैनिक शहीद रहे और करीब 8 हजार घायल हुए। पाकिस्तान के 5800 सैनिक मारे गए। दोनों पक्षों ने जीत का दावा किया।

**ताशकंद संधि**—सोवियत रूस ने भारत तथा पाकिस्तान के इस युद्ध में समझौता कराने का प्रयत्न किया और ताशकंद में दोनों देशों के नेताओं का बुलावा। 10 जनवरी, 1966 को सोवियत राष्ट्रपति कोसिगिन की मध्यस्थता में शास्त्री और अयूब ने ताशकंद में संधि पर हस्ताक्षर कर दिए जिसमें शान्तिपूर्ण उपायों से झगड़े मिटाने, 25 फरवरी 1966 तक 1965 के 5 अगस्त की स्थिति में वापस जाने, युद्ध बन्नी वापस करने तथा एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार न करने के वादे किए गए।

**शान्तिदूत शास्त्री की मृत्यु**—परन्तु इस वार्ता के तुरन्त बाद 10-11 जनवरी की रात को लालबहादुर शास्त्री की तानाफा में ही एकाएक मृत्यु हो गई। अयूब तब ने माना कि शास्त्रीजी आत्मनिर्णय से शान्ति चाहते थे। परन्तु एक आत्मी इस संधि से सन्तुष्ट नहीं था और वह था भुट्टो। वह समझना था कि शास्त्रीजी ने मानवता का लोग रचकर अयूब को उबरूफ बनाया।

**इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री**—लालबहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनीं। इसने पहले वह कांग्रेस की अध्यक्षता रह चुकी थी। उस जमाने में महाराष्ट्र और गुजरात जनगण्डवने और केरल के साम्यवादी मन्त्रिमण्डल का पतन आया। या भी वह परास्तर अपने पिता की वइ तरह में सहायता करके उनसे कार्यो को रोक का कम करती रही थी। प्रधानमंत्री नेहरू की मजबूतता का काम ता वह करती ना थी। कहते हैं, इंदिराजी ने मुझ पर नी कामगज योजना में अनगनम्बेच्छा से मवानिबन लाल बहादुर की फिर में मंत्री बनाया गया था। यह भी कहा जाता है कि जब नेहरूजी को जनिम लोग पता ता इंगिजी न रवन तातयहादुर का बुलाया था। फिर बन् तात यहादुर के मन्त्रिमण्डल में सूचना और प्रचारण मंत्री बनीं। अब प्रधानमंत्री पर के विपक्ष वाक्यायदा चुनाव हुआ और कांग्रेस दल के बहुमन्यक मत के आधार पर के प्रधानमंत्री

बनी। उनके प्रतिद्वंद्वी मारारजी देसाई का 169 और स्वयं उ ह 355 मत मिले थे।

## कांग्रेस का विभाजन

**निर्जलिगप्पा कांग्रेस अध्यक्ष और जाकिर हुसैन राष्ट्रपति**—कामराज के बाद एस निर्जलिगप्पा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। जनवरी, 1968 में हैदराबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और फिर अप्रैल 1968 में हुई फरीदाबाद कांग्रेस तक यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस के कई पुराने नेता इंदिराजी के साथ नहीं चलेंगे। डाक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति चुन जा चुके थे। इसमें पहले वह उपराष्ट्रपति थे। वह महात्मा गांधी के अनुयायी थे और जामिया मिलिया के सर्वसचिव थे।

**सम्पत्ती चुनाव में कम सफलता**—1967 के चुनाव में कांग्रेस उतनी सफल नहीं रही। 510 सदस्यों की लोकसभा में उसे केवल 279 स्थान मिले। इस पर मतभेद रहा कि कांग्रेस क्या हारी, अपनी गरम नीतियों के कारण या और किसी कारण।

**विरोधी स्पष्ट**—कांग्रेस के 1969 के अधिवेशन में अध्यक्ष निर्जलिगप्पा ने अपने अध्यक्षीय भाषण में खुलकर सावजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर जबरदस्त हमला किया जिससे यह स्पष्ट हो गया कि इंदिराजी में पुराने नेताओं के मतभेद बढ़ रहे हैं। इंदिरा विरोधी समाजवादविरोधी भी थे और अब उनकी वास्तविकता सामने आ गई।

**भगडा बड़ गया**—जुलाई 1969 में बंगलूर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ जिसमें इंदिरा गांधी की चर्चा के राष्ट्रीयकरण सम्बंधी योजना के विरोध में एस० वी० पाटिल और मोरारजी देसाई खुलकर सामने आए। इस विरोध के बावजूद योजना अनुमोदित हो गई। पर यहाँ एक दूसरे मामले में विरोध और बढ़ गया। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की इस बीच असामयिक मृत्यु हो गई जिसके कारण अगला राष्ट्रपति कौन होगा, यह समस्या उठ खड़ी हुई। इंदिरा गांधी ने पहले वी० वी० गिरि, फिर जगजीवन राम का नाम रखा और कांग्रेस ससदीय बोर्ड ने सजीव रेडडी का नाम रखा। 13 जुलाई, 1969 को कांग्रेस अध्यक्ष निर्जलिगप्पा ने बाकायदा घोषणा की कि सजीव रेडडी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इसी के साथ वी० वी० गिरि ने भी घोषणा कर दी कि मैं भी उम्मीदवार हूँ।

इंदिरा गांधी ने समझ लिया कि अब लड़ाई रोकनी नहीं जा सकती। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वह वफा के राष्ट्रीयकरण की अपनी नीतियों पर डटी रहेंगी। उन्होंने कहा, एकता जरूरी है, पर एकता का कोई लक्ष्य भी होना चाहिए।

**मोरारजी अलग**—19 जुलाई 1969 को मंत्रिमण्डल की एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद वकील के राष्ट्रीयकरण की घोषणा करके एक अध्यादेश के द्वारा देश के प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इससे कांग्रेस के अंदर के समाजवाद विरोधी तत्व बहुत खुश हुए।

**गिरि की विजय**—13 अगस्त को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति के चुनाव का मामला अपने हाथ में लिया। इस बीच जनसंघ और स्वतंत्र दल ने सजीव रेडडी का और खंडित कम्युनिस्ट दलों ने गिरि का समर्थन किया। फखरुद्दीन अली अहमद और जगजीवन राम ने कहा कि जनसंघ और स्वतंत्र दल द्वारा सजीव रेडडी का समर्थन उन्हें एक विशिष्ट धर्म में खड़ा कर देता है। इंदिरा गांधी तथा समाजवादी दावे के समर्थकों ने वी० वी० गिरि को अपना समर्थन घोषित किया। यह नींव आ गई कि कांग्रेस अध्यक्ष निर्जलिगप्पा प्रधान मंत्री के विरुद्ध अनुशासन भंग की कार्रवाई की घमकी देने लगे। परंतु इंदिरा जी ने समर्थन वापस नहीं लिया और चुनाव होने पर गिरि जीत गए।

**विखड़न पूरा हुआ — 19 अक्टूबर 1969** का यशवतराव चव्हाण, फख्रुद्दीन अली जहम, जगजीवनराम तथा उमाशंकर दीक्षित के हस्ताक्षरों से यह भाग की गई कि श्री ६५ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक बसाई जाए ताकि 1960 के अंत में पूर्व कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव हो सके। निर्जलिगप्पा ने इस बीच फख्रुद्दीन जहम और सुब्रह्मण्यम का कांग्रेस की कार्यसमिति से निकाल दिया। शंकर धाप के अनुसार, 12 नवम्बर, 1969 को कांग्रेस का विभाजन उन्ही समय हो गया समझना चाहिए, जब निर्जलिगप्पा ने इंदिरा गांधी को दल से निष्कासित करना चाहा, परन्तु पूर्णहृति वर्माई कांग्रेस के दिसम्बर अधिवेशन में तब हुईं जत्र जगजीवनराम नए अध्यक्ष चुने गए। इस घटना के बाद वाक्यांश दो कांग्रेस बन गई— नई और पुरानी—और दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगी। कांग्रेस का मूल इतिहास में संस्था का यह पहला स्पष्ट विभाजन था। इससे पहले लाग कांग्रेस से अलग होकर अपनी अलग संस्था बना लेते थे परन्तु अब कांग्रेस नाम में ही 'नई' और 'पुरानी' जाड़ दिया गया। यह नेतृत्व की लड़ाई के साथ नीतियों की भी लड़ाई थी।

**सर्वोच्च अदालत में मुठभेड़**—बैंको के राष्ट्रीयकरण का मामला अदालत में ल जाया गया। फरवरी 1970 में फैसला देते हुए भारत की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि बैंको का राष्ट्रीयकरण पक्षपातमूलक है और क्षतिपूर्ति अप्रदाप्त है। इस फैसले को काटने के लिए केन्द्रीय सरकार का नए कानून बनाने पड़े। देश की अदालत प्रगति को बचावा द मकनी है और रोक भी सकती है। यह समझना भूल है कि न्यायालय में हमेशा 'याय हो होता है। इसी तरह का एक और उदाहरण यह है कि जब अमेरिका में दासप्रथा खत्म कर दी गई, तो दासप्रथा के पक्षधरों ने कहा की सर्वोच्च अदालत में मुकदमा कर दिया। तब मुख्य न्यायाधीश टनी ने दासप्रथा के समर्थन में यह कहकर फैसला दिया कि दास प्रथा बंद करना गरवानुनी है क्योंकि दास ता व्यक्ति की सम्पत्ति है और बिना उचित कानूनों कारवाई के छीने नहीं जा सकते।

**अनुष पंचवर्षीय योजना**—तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 1966 में समाप्त हो गई थी। अब चौथी योजना (1969-1974) पेश हुई जिसमें आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य 5.5 प्रतिशत रखा गया।

**राजाओं के भत्तों का प्रश्न**—मई 1970 में लोकमभा ने राजा का दिए जाने वाले भत्ते तथा दूसरी रियायतों को बंद कर दिया। परन्तु राज्य सभा में यह प्रस्ताव गिर गया। तब इंदिरा गांधी ने मध्यावधि चुनाव का यह कह कर एलान किया कि जनता से फिर एक बार आदेश लेना है कि हम किस निशा में जाएं।

**चुनाव से असली तकली का पता**—नए चुनाव में कांग्रेस के विरुद्ध कांग्रेस की लड़ाई हुई यानी नई कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस की। लोकमभा में नई कांग्रेस को 515 में से 350 स्थान मिले। पुरानी कांग्रेस के पास चुनाव से पहले 65 स्थान थे, अब केवल 15 स्थान मिले। यह भी स्पष्ट हो गया कि जनता ने असली कांग्रेस किसे माना।

**पाकिस्तान का विखड़न**—इधर कांग्रेस का जटिल यह सब हो रहा था उधर पाकिस्तान में ऐसी घटनाएँ हो रही थी जिनका भारत पर बहुत असर होता था। दिसम्बर 1970 में पाकिस्तान में वार्निंग मताधिकार पर आधारित पहला चुनाव हुआ। उसमें पूर्व के नेता शेख मुजीब तथा उनके अवाभी दल को सारे पाकिस्तान में बहुमत मिला, परन्तु सेनापति याह या खा और जुलफिकार अली भुट्टो ने 'सब परिणाम की मानने से इस कारण इनकार कर दिया क्योंकि तब मुजीब को प्रधान मंत्री बनाना पड़ता जिसके किसी भी स्थिति में नहीं चाहते थे। पाकिस्तान में पंजाबियों का ही

बोलबाला था और वे बंगाली या सिंधियों को पसंद नहीं करते थे। बंगाली मुगलमानों ने इस अंगाय में लड़ने के लिए मुक्ति वाहिनी का गठन किया।

इधर 30 जनवरी 1971 का भारतीय वायुसेना का एक जहाज हाइजैक करके लाहौर ले जाया गया और टी० बी० कैमरों के सामने उसे नष्ट कर दिया गया। भारत ने प्रत्युत्तर स्वरूप अपने देश के ऊपर से पाक हवाई जहाजों का उड़ना बंद कर दिया। फिर पाक सेना ने ईस्ट बंगाल रेजिमेंट और ईस्ट बंगाल राइफल्स पर हमला कर दिया। गण्डूद्ध घुसने लगा और पूरा बंगाल की मुक्ति वाहिनी ने जबरदस्त मोर्चा लिया। अवामी लीग ने 26 मार्च को चटगांव रडियो में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 31 मार्च को भारत की संसद ने पूरा बंगाल के लोगों के साथ अपनी सहानुभूति प्रकट की। फिर ता पूरा हो यद्ध छिड़ गया। 4 दिसम्बर तक भारतीय वायुसेना ने नये बांग्ला देश के आकाश को पाक सैनिक जहाजों में भुक्त कर दिया। 16 दिसम्बर तक पाक सेनापति नियाजों ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। उसी दिन संध्या समय इन्दिरा गांधी ने संसद में घोषणा की कि अब ढाका एक स्वतंत्र देश की राजधानी है। 90 हजार पाक सैनिक यद्ध बन्नी बनाए गए। पाक सेना ने लाखों बंगाली मारे थे और दो लाख स्त्रियों के साथ बलात्कार किया। इस प्रकार सबसे बड़ी बात जो हुई, वह यह कि दो राष्ट्र सिद्धान्त का मारे मरार के मामले में व्यवहारिक अर्थ हो गया। यह भी स्थापित हो गया कि इस्लाम राष्ट्र का आधार नहीं हो सकता।

**भारतीय सेना लौटी—**भारतीय सेना बांग्ला देश को स्वतंत्र कर 12 मार्च, 1972 को लौट आई। पाकिस्तान के युद्ध बन्दी भारत में रहे। उनके साथ जेनेवा कन वेंशन के अनुसार व्यवहार हुआ। भारत ने उन पर 36-37 करोड़ रुपये खर्च किए। मुजीब पहले कुछ युद्ध बन्धियों पर बलात्कार, हत्या के मुकदमे चलाना चाहते थे, पर अंत तक उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने 9 जून 1972 को कहा था "मुकदमे न चलाने का प्रश्न ही नहीं उठता। 30 लाख लोगों की बेरहमी से हत्या की गई, दो लाख सैनिकों के साथ पाक सैनिकों ने बलात्कार किया। एक करोड़ आदमी भारत चले गए, डेढ़ करोड़ भयप्रस्त होकर इधर से उधर भागते रहे। मसाले जाने तो कि क्या हुआ था।"

**शिमला सम्मेलन—**भारत अपने पड़ोसी पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्वक रहना चाहता था। यह था कि बाद में वहां के नए राष्ट्रपति भुट्टो और प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी में शिमला में पंचदिवसीय वार्ता के बाद एक सम्मेलन हुआ, जिसमें यह सफल किया गया कि भविष्य में सारे मतभेद और झगड़े शांतिपूर्ण तरीके से निबटारे जाएंगे। कुछ समय बाद भुट्टो की सरकार बदल गई और उन्हीं के द्वारा बनाए गए राष्ट्रपति जिया उल हक ने उन्हें 1977 में फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। तब से शिमला सम्मेलन गंदाई में पड़ गया।

**1972 की कांग्रेस—**1972 में शारदयाल शर्मा की अध्यक्षता में कांग्रेस का 74वा अधिवेशन हुआ। इसमें उन्होंने कहा कि 1972 के चुनाव में जनता ने कांग्रेस में जबरदस्त जाल्पा प्रकट की है। हम संविधान के 26वें संशोधन द्वारा राजाओं की निजी धनिया तथा गिरावट को खत्म कर चुके हैं। अन्न का उत्पादन निरंतर पर पहुँच गया है। सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। कोरिंग कोयला खानें भी अधि-गृहीत हो चुकी हैं और विदेशी व्यापार में कुछ हिस्से सरकारी नियंत्रण में आ चुके हैं। उन्होंने बगवधु मुजीबुररहमान को बधाई देते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि बांग्ला देश फने फूले।

**गुजरात विधान सभा टूटी—** कांग्रेस कुछ दमा की तथा भारत के कुछ नेताओं को, जिनकी वैयक्तिक उच्चाकांक्षाएँ लोकतान्त्रिक तरीका संपूर्ण नहीं हुई थी, बहुत अखर रही थी। 1973 तक देश में तरह-तरह के आन्दोलन चल पड़े। गुजरात में एम बहुत से लोग प्रबल हो गए और व विधायकों की घमकाने लगे। गुजरात विधान सभा बाकायदा चुने हुए लोगों की संस्था थी परंतु आन्दोलनकारी इतन आक्रामक हो गए कि विधान सभा भंग कर दी गई।

**बिहार विधान सभा को तोड़ने का क्रम—** गुजरात की स्थिति से प्रेरित होकर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में भ्रष्टाचार ने विरुद्ध जबरदस्त आन्दोलन गुरु हुआ। जनसमझ भी इसमें शरीक हो गया। जुलाई, 1974 में दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक बैठक में यह प्रस्ताव पारित हुआ "देखने में तो य आन्दोलन जनता का असन्तोष व्यक्त करने के लिए है, पर असल में इनका उद्देश्य है उत्पादन को पक्षाघातग्रस्त करके राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को विध्वस्त करना। यह फासिस्टवा" तथा उपरक्षिण पक्ष की सुपरिचित नीति है।"

**बैठक में बहस का प्रारंभ—** अक्टूबर, 1974 में देवकान्त बहस कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। उन्होंने कांग्रेसजनों से कहा कि आप जनता के बीच में जाएं और उनके दुख दर्द से परिचय प्राप्त कर उसके निवारण में लग जाएं।

**मरौरा शिविर—** नवम्बर 1974 में उत्तर प्रदेश के मरौरा शिविर में राजनैतिक और आर्थिक समस्याओं पर बातचीत हुई और तय हुआ कि ऐसे शिविर सब जिला स्तर पर हो जिससे लोगों का पता लगे कि कांग्रेस क्या कर चुकी है, क्या कर रही है और क्या करना चाहती है। बंधुआ श्रमिकों का मामला भी कांग्रेस ने सामने आया और ग्रामवासियों की कजठारी मिटाने का संकल्प किया गया।

**जयप्रकाश द्वारा विद्रोह की आवाज—** इस बीच जयप्रकाश नारायण का आन्दोलन का विस्तार हो रहा था। 3 से 5 अक्टूबर तक बिहार बंद का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जयप्रकाश नारायण ने कहा "आज से न बिहार के जरिए कोई रेल चलेगी, न बस, सरकारी दफतार, यहां तक कि सचिवालय भी खाली होंगे। एक हफ्ते तक सरकार को पक्षाघात ग्रस्त करना बिहार में सरकार का पिराने का लिए काफी होगा। हमारा युद्ध केन्द्रीय सरकार से है न कि केवल बिहार सरकार से।"

**इंदिरा की विरुद्ध अदालती निषेध—** 12 जून, 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव के विरुद्ध फैसला दिया। फसले में सर्वोच्च अदालत में अपील करने के लिए 20 दिन की मुहलत दी गई। फिर भी लोगों ने यह कहना शुरू किया कि इंदिराजी फौरन इस्तीफा दें। 24 जून को सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश ने कहा कि इंदिरा गांधी के प्रधान मंत्रित्व पर कोई रोक नहीं है, पर वह मामल के रूप में तब तक मत न दें जब तक अपील पर पक्का फैसला नहीं हो जाता। इस पर भी जनसमझ, संगठन कांग्रेस पुरानी तथा लोकदल प्रधान मंत्रियों के इस्तीफे की मांग करते रहे।

**आपातस्थिति की घोषणा—** इसी परिस्थिति में 26 जून, 1975 को देश में आपातस्थिति घोषित कर दी गई। प्रधान मंत्री ने आकाशवाणी से कहा "लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र को बालू रखने का विरोध किया जा रहा है। वध रूप से चुनी हुई सरकार को बाल नहीं करने दिया जा रहा है और कई मामलों में वध रूप से चुन हुए विधायकों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है ताकि वध विधान सभाएं रद्द हो जाएं। देश भर में गडबड मची है जो अक्सर हिंसक कार्यों में परिणत हो जाती है। कुछ लोग फौज को भी भड़का रहे हैं कि वे विद्रोह करें। मुझ पर सब तरह के दोष

रोपण किए गए हैं। यह कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। मैं प्रधान मंत्री रह या न रहूँ, यह महत्वपूर्ण नहीं है, पर प्रधान मंत्री का पद महत्वपूर्ण है और जानबूझकर राजनैतिक रूप से इसे अवमूल्यित करने का प्रयास न लोकतंत्र के हक में है न राष्ट्र के।

"हमने इन घटनाओं को बड़े घंम के साथ देर तक सहन किया। फिर भी देश के साधारण क्रियाकलाप का छिन भिन करना जारी रहा। कुछ लोग विशाल बहुसंख्या के अधिकारों पर कुठाराघात कर रहे हैं। यह स्थिति कड़ी कार्रवाई की मांग करती है। आपातस्थिति से साधारण व्यक्ति को काई भय नहीं है।"

**बीस सूत्री कार्यक्रम की घोषणा—**1 जुलाई, 1975 को इंदिरा गांधी ने एक बीस सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की जिसका उद्देश्य कमजोर वर्गों का आर्थिक उत्थान है। इसमें शहर वाले कमजोर वर्गों के जलावा गांव वालों, विशेषकर खेतिहर मजदूरों को राहत पहुंचाने की अनेक योजनाएँ घोषित की गईं।

**1975 की कांग्रेस—**31 दिसम्बर, 1975 में कोमागाटा मारु नगर (चंडीगढ़) में देवकान्त बह्मरा की अध्यक्षता में कांग्रेस का 75वाँ अधिवेशन हुआ। उन्होंने कहा कि जो लोग वध रूप से चुनी हुई विधान सभाओं को तोड़ने का पडयंत्र कर रहे हैं, वे लोकतंत्र के शत्रु और फासिस्ट हैं। बह्मरा ने आपातस्थिति की घोषणा का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने बीस सूत्री कार्यक्रम का अनुमोदन करते हुए कहा कि आर्थिक रूप से आगे बढ़ने का यही तरीका है। उन्होंने कहा कि 1976 की कांग्रेसजन 'संगठन वर्ष' के रूप में मनाए।

**मोरारजी प्रधानमंत्री—**आपातस्थिति के अन्तर्गत शासन ने जयप्रकाश नारायण सहित अनेक नेताओं को जेल में डाल दिया। 1976 के अंत में इंदिरा गांधी ने आम चुनाव की घोषणा की। 1977 के इस चुनाव में कांग्रेस हार गई। नवनिर्मित विरोधियों की जनता पार्टी की जीत में सबसे बड़ा घटक यह रहा कि कांग्रेस ने कुछ सत्तारूढ़ों के साथ परिवार नियोजन का कार्यक्रम चलाया था, जिसके कारण जनता क्षुब्ध थी। इस कार्य में इंदिरा जी के छोटे बेटे सजय गांधी ने अगुवाई की थी। जनता गुट ने इसका फायदा उठाया जिसका नतीजा यह हुआ कि गुट शक्ति आरूढ़ होने पर यह कार्यक्रम एकदम खरम सा हो गया। जनता गुट की लोकसभा में 299 स्थान मिले। मोरारजी देसाई के प्रधान मंत्रित्व में सरकार बनी, जिसमें चरण सिंह, जगजीवनराम आदि मंत्री बने। ये सब लोग भूतपूर्व कांग्रेसी थे, ये सब अपने को महात्मा गांधी के असली शिष्य मानते थे। जवाहरलाल नेहरू के सम्बंध में इनके विचार मुख्यतः द्विधाप्रस्त थे, यद्यपि ये जवाहरलाल नेहरू के प्रधान मंत्रित्व में काम कर चुके थे।

**रेडडी कांग्रेस अध्यक्ष—**चुनाव में कांग्रेस की हार के कारण दक्कान्त बह्मरा ने कांग्रेस की अखंडता से इस्तीफा दे दिया। कार्यसमिति ने स्वयंसेवकों की अस्थायी कांग्रेस अध्यक्ष चुना और ब्रह्मानंद रेडडी 6 मई 1977 को नियमित अध्यक्ष नियुक्त हुए। पर ब्रह्मानंद रेडडी संवत्प्रस्त कांग्रेस को वह नेतृत्व नहीं दे सके, जिसकी उम्मेद आवश्यकता थी। कांग्रेस के सत्ता में न रहने के कारण उमके अनेक घटक उमस अलग होने का विचार करने लगे। जनता शासन ने इंदिरा गांधी तथा उनकी सरकार के लिए एक जाच आयोग भी बैठा दिया था जिसकी कार्यवाहियों से अनेक कांग्रेसजन परेशान थे। इसी बीच एक दिन के लिए इंदिरा गांधी को गिरफ्तार भी किया गया।

**1 जनवरी 1978 का सम्मेलन—**कांग्रेस के अंदर असन्तोष बढ़ने लगा। कमला-पति त्रिपाठी, पी० वी० नरसिंह राव, श्रीमती चन्द्रशेखर, ए० पी० शर्मा, वीरेन्द्र वर्मा, बृंग सिंह आदि ने मिलकर 1 जनवरी, 1978 को एक वनवेनशन बुलाया।



इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिकांश सदस्य उपस्थित थे। इस सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्र के सामने की चुनौतियाँ का असरगार तरीके से सामना करना था। इस सम्मेलन ने सबमममति से इंदिरा गांधी की कांग्रेस की अध्यक्ष चुना।

**कांग्रेस के फिर दो टुकड़े**— कांग्रेस के फिर एक बार दो टुकड़े होने की नीबट आ गई। एक के अध्यक्ष ब्रह्मानंद रट्टी रहे दूसरे की नेता इंदिरा गांधी हो गई। एक बार फिर सड़े गले अक्ष की, जो सास ता ले रहा था परन्तु पक्षाघातग्रस्त था, शल्यक्रिया से काटकर परित्याग करने में इंदिराजी न बड़े साहस का परिचय दिया। भविष्य की घटनाओं ने यह प्रमाणित कर दिया कि कौन कांग्रेस असली है।

**इंदिरा कांग्रेस की विचारधारा**—उक्त सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित हुआ, जो संक्षेप में यों था

“भारत के आपुनिय इतिहास में अभी जा वष ममाप्त हुआ है, वह बहुत मार्क का वष था। तीन दशकों तक बराबर सत्तारुद्ध रहने के बाद कांग्रेस अब अधिकारच्युत है। भारत में इस समय राजनैतिक स्थिति दिशाहीनता से ग्रस्त और परस्पर विरुद्ध बहाव और तनाव की शिकार है। चुनाव में हारने के बाद कांग्रेस के लिए यह समय काफ़ी साव्य ही परीक्षा का भी है।

‘जब से जनता सरकार सत्ता में आई है, वह बराबर धमनिरपेक्षता और समाज शांति सम्बन्धी हमारे विरयोजित और प्रिय मूल्यों पर आघात करती जा रही है। जवाहर लाल नेहरू द्वारा आरम्भ नीतियों को प्रतिदिन परो सल कुचला जा रहा। एकाएक सांप्रदायिक दंगे उभर पड़े हैं। जनता सरकार से मिलकर स्थिर स्वाधवाला का कमजोर वर्गों पर हमला जारी है। कांग्रेस के दपतग पर हमला और कांग्रेसियों का नियंत्रित हो रहा है। देश में सुरक्षा की कमी होती जा रही है।

‘अल्पसंख्यकों के प्रति जनता पार्टी की नीति विशेष रूप से खतरनाक है। बात यह है कि यह दल जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बना है, यहाँ तक कि इतिहास लेखन को भी जनसंघी भुकाव देने का प्रयास जारी है। प्रतिक्रियावादी तत्वा को खुश करने के लिए भाषा नीति को सांप्रदायिकता के रंग में रंगने का प्रयास चालू है। वास्तविक गुटनिरपेक्षता के नाम पर भारत सरकार गुटनिरपेक्षता से हट रही है जो हमारी वदेशिक नीति की आधारशिला रही है। आत्मनिर्भरता की नीति के बजाय हम दबाव में आकर आणविक ही नहीं, हर क्षेत्र में पर निर्भरता की ओर जा रहे हैं। लाकतब की कसम खाते रहने पर भी जनता दल उपचुनावों के अवसरों पर खुलमखुला घेईमानी कर चुकी है। स्थिर स्वाधवाले शहू पाकर मनदान पेटियों का उठाकर चलते बने या उन्हें बदल दिया। इस प्रकार इस दल के कारण ममदीय लोकतंत्र की पद्धति हो खतरे में है।

“धीमते बुरी तरह बढ़ रही हैं।

“इन कारणों से कांग्रेस को उत्पन्न परिस्थिति से जूझने तथा चुनौतियों का सामना करने के लिए जाने आना चाहिए था, परन्तु कांग्रेस गगठन की तरफ से कोई पथ प्रश्न नहीं हो रहा है।

‘श्रीमती इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी से देश भर में जो स्वतः स्फूर्त उथल पुथल दृष्टिगोचर हुई उसका फायदा उठाकर देश के सामने की असली समस्याओं के समाधान की पहल की जानी चाहिए थी। पर ऐसा नहीं हुआ। 1969 का महान विखंडन ज़िम जास्था के आधार पर कार्योचित किया गया था, उस आधार से कांग्रेस विनलित होती दिखाई पड़ रही है। आम चुनाव में हार के असली कारण को लोग समझ नहीं पाए कि विदेशी और देशी प्रतिक्रियावाद के गठजोड़ से ही कांग्रेस की पराजय हुई। कुछ

कांग्रेसी नेता इस भ्रमजाल में भटक गए कि हम ज्यादा गरम थे, इस कारण हार गए। कुछ लोग भीतर ही भीतर जनता दल से अनादी सहयोग के लिए सलबन लगे। विचार-धारा को छोड़कर तोड़ जोड़ की नीति अपनाने की ओर कदम बढ़ने लगे। यह मझाड़ इस हद तक बढ़ी कि कांग्रेस का पथक अस्तित्व ही डावाबोल हो रहा है।

‘बार-बार चेतावनी देने पर भी कांग्रेस हाई कमान के कानों पर जून नहीं रेंगी। इसके विपरीत जिन लोगों ने मूलभूत मसले उठाए, उन पर पुरानी पड़ी हुई अनुशासन की लचर लाठी लपलपाई गई। हमन सुभाव दिया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक बैठक बुलाकर विचार निमेष किया जाए, परंतु सांगठनिक नेता उसे टालते चले गए। इन्हीं मजदूरियों के कागण सारी परिस्थिति पर जमर मर मर करने के लिए, नेतृत्व के दिमाग की गांठों को खोलने तथा पददलितों के लिए अपने को उत्सर्ग करने के लिए यह सम्मेलन बुलाया गया। इससे अनुशासन भंग नहीं हुआ, बल्कि किसी जीवित हल को विचार तथा कार्य के क्षेत्र में गतिशील रखने के लिए ऐसे सम्मेलन अपरिहाय हैं। इसलिए उन कांग्रेसजनों को धन्यवाद है जो इसमें शामिल हुए।”

**भावी क्रियाकलाप—**भावो नियाकलाप का एक खाका भी खींचा गया जिसमें पूरी नीति स्पष्ट करके बताई गई। कहा गया कि—

(क) लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और गृहनिर्पेक्षता का आधार को अनुष्ण रखने हुए कांग्रेस की नीतियों का पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निर्धारण हो। (ख) सांप्रदायिकता से लोहा लेने के लिए अल्पसंख्यकों को संतुष्ट रखा जाए। अतीवृद्ध विश्व-विद्यालय के मौलिक चरित्र को कायम रखने के उद्देश्य से कानून बनाया जाए। (ग) सब स्तरों पर दल के कार्यकर्ताओं को सामाजिक अधिकार परिवर्तन के प्रति सजग रहने की शिक्षा दी जाए। (घ) दल का कार्यक्रम कहा तक कार्यान्वित हो रहा है, इस पर स्वयं क्रियाशील सतक दृष्टि रखी जाए। (च) जीवन के हर क्षेत्र में बुद्धिजीवियों को स्वयं से जाड़ा जाए। (छ) शिक्षा के क्षेत्र में शहरी घनाढ्य विद्यालयों और गांव के वंचित विद्यालयों में विद्यमान अंतर को कम से कम बिया जाए। (ज) चुनावों में धन का प्रभाव घटे। (झ) असमानता को, जहां तक बन पड़े कम किया जाए क्योंकि समाजवाद की ओर यात्रा का यही तनाव है।

**सामाजिक परिवर्तन का लक्ष्य—**अंत में यह कहा गया कि जनता सरकार द्वारा पोषित स्थिर स्वायत्त के अभियान को गोका जाए और कमजोर वर्गों के स्वायत्त की रक्षा के लिए सत्याग्रह और शांतिपूर्ण आंदोलन किया जाए। नए सामाजिक परिवर्तन का हथियार बनकर काम करे, इस बात पर जार दिया गया।

**दल से निकाला—**इस सम्मेलन की प्रतिक्रियास्वरूप ब्रह्मानंद रेड्डी ने 3 जनवरी 1978 को यह फैसला किया कि जिन कांग्रेसजनों ने इन्दिरा गांधी को अभ्यक्ष माना है वे सब कांग्रेस से निकाले जाते हैं। इसके बाद तदनुसार प्रांतीय और जिला कांग्रेसों में रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाएगी।

**ब्रह्मानंद रेड्डी के साथ—**यशवतराव चव्हाण ने 27 दिसम्बर, 1977 को ब्रह्मानंद रेड्डी के साथ यह वक्तव्य दिया था—‘यह बिलकुल स्पष्ट है कि यह सम्मेलन व्यक्तिगत तथा गटीय उद्देश्य से दल का विखंडित करने का प्रयत्न है, इसलिए हम साफ कर देना चाहते हैं कि यह सम्मेलन दल विरोधी कार्यवाही समझा जाएगा।”

**इन्दिरा फिर मसदे—**इस बीच इन्दिरा गांधी समद मसदा नहीं थी। परंतु 1978 के नवम्बर में वे विश्वमयलूर में चुनकर फिर लोक सभा में आ गई। यह चुनाव बहुत भाकों का रहा और उन्होंने जनता प्रत्याशी को 80 हजार मतों से हराया। यह

घटना शासन में कांग्रेस की गणनी की पूर्वसूचना सिद्ध हुई।

जनता सरकार शिवजी की बारात—जनता दल की सरकार शुरू से ही गड़बड़ भाले में रही। कहते हैं, जनता दल के अधिवांश सास जगजीवनराम को दल का नेता बनाना चाहते थे, परन्तु जयप्रकाश जी ने मोरारजी का नाम प्रस्तावित किया और वे प्रधानमंत्री हो गए। चरणसिंह जयरदस्त महावाकावी थे और प्रधान मंत्री बनने का स्वप्न देखते थे। राजनारायण का व्यक्तित्व अपने ढंग का अनोखा था। वह रामचरणी में इंदिरा गांधी का हरावर एकाएक बड़े नेता बन चुके थे। जनता सरकार ने अपने राज्यकाल में उनमें ऐसा दुरु्यवहार किया कि जून, 1977 में उन्होंने 'मटवें रिव्यु' के भूतपूर्व सम्पादक नामन कजिस से कहा था कि 'मैं कोई मिस्त्रीपुस्तक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं अतिरजित बोलती हूँ, पर जनता सरकार ने मेरे और सजय के विरुद्ध सब तरह की झूठ गप्पें उड़ाई हैं। मैं समझती हूँ कि इसमें तो अच्छा है कि बागसा देश के नेता मुजीब की तरह मारी जाती।' मुजीब 15 अगस्त 1975 का विदेशी एजेंडा के हाथ मार गए थे।

चरणसिंह प्रधान मंत्री—जब तक जनता सरकार रही, उसने इंदिरा गांधी और कांग्रेसियों के विरुद्ध जानें कितने जांच आयोग बठाए, कुछ अंग्रेज भारतीय स्तर पर, कुछ राजकीय स्तर पर। अभी इन आयोगों का काम खरम नहीं हुआ था कि आपसी झगड़ा के कारण मोरारजी सरकार का पतन हो गया। चरणसिंह नए प्रधान मंत्री बने, परन्तु तत्पश्चात् उनका बहुमत नहीं था, इसलिए सदन की बैठक के पहले ही उन्हें इस्तीफा देकर अलग हटना पड़ा। राष्ट्रपति सजीव रेडडी ने सदन भंग करके चुनावों की घोषणा कर दी।

इंदिरा गांधी की वापसी—1980 के चुनावों में कांग्रेस फिर सत्ता में आ गई और इंदिरा जी फिर प्रधान मंत्री बन गई।

जनता सरकार के विस्मरक ही वही बर्तक हास्यास्पद बनकर टूट जाने के बाद इंदिरा गांधी के द्वितीय युग का सूत्रपात होता है। यों तो नालबहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद ही इंदिरा युग आरम्भ हो चुका था और उस युग की सबसे बड़ी उपलब्धि बांग्लादेश की स्वाधीनता में निष्ठापूर्ण भाग लेना था।

यहां आगे बढ़ने से पहले यह बात स्पष्ट कर दी जाए कि बांग्लादेश को स्वाधीनता दिलाने में इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया, वह केवल इंदिरा ही कर सकती थी। उदाहरणस्वरूप, यदि महात्मा गांधी के हाथों में उस समय बागडोर होती, तो वह अहिंसा के नाम पर वे कदम उठाने न देते जो इंदिराजी ने उठाए। इसी प्रकार यदि जवाहरलाल नेहरू के हाथों में बागडोर होती, तो वह अंतर्राष्ट्रीय कानून की उनकांनों में फसकर रह जाते। रहे नालबहादुर, वह जरूर आक्रमण का जवाब मुंह तोड़ आक्रमण से दे सकते थे जसा कि 1965 के हिन्द-पाक युद्ध के समय दम्बा गया, परन्तु वह भी शायद शत्रु की केवल अपनी भूमि में भगा कर ही रुक जाते, डाढ़ा तक उनके चरण न जान।

इंदिरा गांधी ने 1971 में जो कुछ किया उसके विचारधारागत, साथ ही पंच-वारिक परिणाम बहुत जबदस्त रहे। भारतीय उपमहादेश में सबसे खतरनाक विचार, जिसने करांडा लोगों को गुमराह किया, वह था दो राष्ट्र का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक न यह कहा कि हिंदू अलग जाति (नेशन) के हैं और मुस्लिम अलग जाति के। इतिहास का यह एक ददनाक अध्याय है (इं बरिस्टर जिना और कवि इकबाल सारे भारतीय मुसलमानों की (कुछ राष्ट्रीयतावादी मुसलमानों का छोड़कर) इस सलाह में बहाले जाने में सफल हो गए। इंदिराजी ने बंगाली मुसलमानों का इस दलदल से उद्धार

किया, जो इस बीच पाकिस्तानी जकड़ में रहकर अपने तजुबों से समझ चुके थे कि इस्लाम की आड़ में उनका औपनिवेशिक शोषण किया जा रहा है। उनके लिए यह गुलामी का दूसरा युग (1947-1971) रहा।

**व्यवहारिक लाभ**—इंदिरा जी ने उस समय जो कुछ किया, उतना ही उनके अमरत्व के लिए काफी था क्योंकि बांग्ला देश बनने में कम-से-कम पूर्व में हमारा खतरा काफी कम हो गया। यदि बांग्ला देश के राष्ट्रपिता बंगबंशु मुजीब जीवित रहते या उनकी विचारधारा के लोगो का नेतृत्व रहता, तो यह खतरा बिल्कुल ही न रहता। पर अफसोस है कि साम्राज्यवादी तथा संप्रदायवादी शक्तियों ने मुजीब की हत्या करवा दी। फिर भी वे टूटे पाकिस्तान को जुड़वा न सके।

**गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नेता** इस द्वितीय युग में इंदिरा गांधी ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। पर उनमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहा गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व कर उसे निखार देना। 1961 में बलप्रेंड में गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन हुआ था। इस आंदोलन का प्रतिपाद्य यह था कि स्थायी शांति तभी हो सकती है जब साम्राज्यवाद, तथा उपनिवेशवाद का अंत होकर सह-अस्तित्व का प हो। जवाहरलाल, माशाल टिटो और नासेर आंदोलन के प्रवर्तक नेता थे।

क्रमशः इस आंदोलन में नए स्वतंत्र देशों के आते जाने से यह आंदोलन अधिकाधिक व्यापक तथा शक्तिशाली होता गया। आंदोलन में शामिल देश सैनिक या आर्थिक दृष्टि से बड़ी शक्तियां नहीं थे, पर फल मिलाकर उनकी नैतिक शक्ति इतनी बढ़ती जा रही है कि महाशक्तियां जब उनकी अवज्ञा नहीं कर सकती। स्वाभाविक रूप से यह आंदोलन साम्राज्यवाद की आंखों में खटकने लगा है।

1983 में दिल्ली में हुए हमारे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इंदिरा जी इसकी प्रधान चुनी गई। उन्होंने सारे ससार की ओर से आणविक युद्ध को रोकने के लिए एक जबदस्त अपील की।

इंदिरा जी ने समुक्त राष्ट्र सच की शक्ति बढ़ाने पर ज़ार देते हुए कहा कि उसके आगामी 38 वें अधिवेशन (1985) को इस प्रकार सबल और मशरूफ बना दिया जाए कि उसमें देशों के बीच उठने वाली सारी उलझना को सुलझाया जा सक। इस सुझाव का उद्देश्य उस दुष्प्रवृत्ति को रोकना था, जो अमेरिका की ओर से दृष्टिगोचर हो रही थी। अमेरिका चाह रहा था कि ससार में जो कुछ भी हो, चाहे शांति हो या युद्ध, अमेरिका की अनुमति से तथा उसका लाभ देखकर हो।

समस्त दावों के बावजूद यह मिथ्य हो चुका है कि साम्राज्यवादी शक्तियां किसी भी कमजोर देश के आर्थिक उत्थान में हाथ बटाती नहीं चाहती उनका एकमात्र उद्देश्य है आर्थिक शोषण का तभी मिथ्य हो सकता है जब अविश्वसनीय देश उद्योग के क्षेत्र में पिछड़े रहें। इस कारण इंदिराजी ने दिल्ली सम्मेलन में यह नारा भी दिया कि भले ही साम्राज्यवादी हमारी महापत्ता न करें, हम एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। यह एक नया तथा नया मौलिक दृष्टिकोण है, जिससे साम्राज्यवादियों के लिए भयंकर खतरा पैदा होता है।

सम्मेलन में अमेरिकी पक्षधरों के कारण कई मामले खटाई में पड़े रह गए। हिंद महासागर में मारिशस के लिए टापू डिण्गो गारंटिया में अमेरिका कई सालों से अति प्रबल सैनिक तयारिया कर रहा है, जिससे यह सारा क्षेत्र अमेरिकी हवाई तथा समुद्री बेड़े की मार के अन्तर्गत आ गया है और यह महासागर युद्ध का क्षेत्र बन गया है। परंतु गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में इसके विरुद्ध कोई प्रस्ताव पारित न हो सका। इसी प्रकार कैरिबियन

ममुद को शांति क्षेत्र करार देना भी सम्भव नहीं हुआ।

इन सारी अड़चनों के बावजूद सम्मेलन बहुत सफल रहा और इंदिरा गांधी के नेतृत्व की सभी देशों में प्रशंसा हुई। दुनिया ने देख लिया कि भारत शांति का पोषक है। इंदिरा गांधी ने गुटनिरपेक्ष संधि को शांति आंदोलन की सबसे बड़ी सस्था बना दिया है। सबने इस सफलता की प्रशंसा की है। छठे सम्मेलन के अध्यक्ष फ्रान्सिसो ने इस कारण इंदिरा जी की सराहना की कि उनके नेतृत्व में यह सस्था शांति, राष्ट्रीय स्वाधीनता और विकास का वाहन बन गई है। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के कारण सत्तार के बुद्धिजीवियों, चिंतकों, संपादकों, लेखकों का ध्यान भारत की ओर गया।

एशियाई खेल—अपने प्रधान मंत्रित्व काल में इंदिराजी ने इसके पहले 1982 में एशियाई खेल भी कराए, जो बहुत सफल रहे और निर्विघ्न रूप से सम्पन्न हुए। उस समय भी कुछ सप्ताहों के लिए सारे एशिया की ओर बड़ी हद तक विश्व की खेल दुनिया की आँखें भारत पर टिकी रही।

राष्ट्रीय उपनधियाँ—इंदिरा-युग में कई बहुत बड़ी घटनाएँ हुई, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं—

(1) इस युग में भारत अनाज के क्षेत्र में सम्पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बन गया। इसे 'हरित क्रांति' कहते हैं और यह इसलिए सम्भव हुई कि वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग की भोपडिया से सीधा सम्बन्ध स्थापित कर दिया गया। वैज्ञानिक शोध से दैनिक आवश्यकताओं का रबत सम्बन्ध स्थापित करना इंदिरा युग की महान उपलब्धि रही।

(2) इसी युग में भारत में दूरदर्शन का आरम्भ हुआ, जो हमारे जीवन का महा तक अविच्छेद्य अंग बन चुका है कि अब लगभग 70 फीसदी जनता इसका लाभ उठा सकती है। भारतीय दूरदर्शन की एक विशेषता यह है कि इसमें आम जनता के लिए शैक्षणिक तथा विकासात्मक कार्यक्रमों को पूरा महत्व दिया गया है।

(3) इंदिरा जी के प्रधान मंत्रित्व काल में पहली बार स्वतंत्रता प्राप्ति के 25 वर्ष बाद 1972 में स्वातंत्र्य योद्धाओं को ताम्रपत्र आदि देकर उन्हें स्वीकृति प्रदान की गई और पेंशन देकर सहायता दी गई।

(4) 1971 में हिंद सोवियत मैत्री और पारस्परिक सहयोग संधि करके भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने को सुदृढ़ बना लिया।

## 1983 की कलकत्ता कांग्रेस

1983 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ते में हुआ। कलकत्ता कांग्रेस में पारित प्रस्तावों में तीन प्रकार के बिंदु तब शामिल आए—राजनितिक, आर्थिक और अन्तर्राष्ट्रीय। साम्प्रदायिकता में लोहा लेने के लिए कांग्रेसजनों का विशेष हिदायत दी गई। कहा गया कि भारत सभी प्रगति का माग पर अग्रसर हो सकता है जब मुसलमान, ईसाई, सिख सभी हर क्षेत्र में विश्वास और सम्मिलित प्रयास से बहुसंख्यकों के साथ सहयोग कर।

कांग्रेस के लिए यह दृष्टिकोण काई नया नहीं है। केवल गांधी या नेहरू युग में ही नहीं, 1919-20 के पहले में ही कांग्रेस सभी धर्मों के प्रति समदर्शिता दिखाती रही है। हम पहले ही दिखा चुके हैं कि महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के आमूलबूल परिवर्तन किए जाने में पूर्व ही कांग्रेस के कई अध्यक्ष अल्पसंख्यक सम्प्रदायों के हो चुके थे। स्वराज्य के लिए भी अनेक राष्ट्रपति, मेनाध्यक्ष आदि अल्पसंख्यकों में से बने और बन रहे हैं। 1983 के इस अधिवेशन के समय ज्ञानी जलसिंह राष्ट्रपति पद पर मुशोभित थे।

केन्द्र और राज्या के सम्बन्धों पर राजनैतिक प्रस्ताव में कहा गया कि केन्द्र का शक्तिशाली होना और रहना आवश्यक है। वाद की घटनाओं ने प्रमाणित कर दिया कि शक्तिशाली केन्द्र के बिना देश में शिथिराव की प्रक्रिया आरम्भ हो सकती है।

अंतर्राष्ट्रीय स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव में स्वतंत्र भारत की चिरन्तन गुटनिरपेक्ष नीति की पुनर्घोषणा करते हुए कहा गया कि जनता पार्टी की समदूरता वाली निर्जोष नीति कांग्रेस को स्वीकार नहीं है। कहा गया कि मध्य अमेरिका में अग्निबुड प्रज्वलित हो सकता है। यह भी स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि ग्रेनाडा में अमेरिका ने हस्तक्षेप किया है। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सभ द्वारा राजनैतिक समाधान की तलाश का समर्थन किया गया। नमिबिया का आजादी के साथ वाटरी गठव घनों की शर्तों की निंदा की गई।

आर्थिक प्रस्ताव में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (आई० एम० एफ०) की सहायता लेने से बचकर अपने पैरों पर खड़े होकर आग बढन की बात कही गई।

अकाली आतङ्कवाद—हम देखा चुके हैं कि बांग्ला देश के उभय से किस प्रकार जिना और कवि मुहम्मद इकबाल द्वारा प्रतिपादित दो राष्ट्र सिद्धान्त की धमर टूट गई और यह स्पष्ट हो गया कि धर्म के आधार पर राष्ट्र नहीं बना सकते। यदि धर्म राष्ट्र का आधार होता, तो ममार के सार मुसलमानों को एक राष्ट्र में हाना चाहिए था।

जो हा, 1971 में यह घटना भी गही की जा सकती थी कि दो राष्ट्र सिद्धान्त के मुद्दे का भूत कुछ मित्रों के सिर पर गमार होकर त्रिगुट्ट सिद्धान्त का रूप ग्रहण करेगा। 13 अप्रैल, 1978 को यह भूत सावजनिक रूप से उभर समय प्रकट हुआ, जब अमृतसर के स्वर्णमंदिर से निकलकर कुछ सिक्खों ने निरकारियों पर हमला किया। इसके दो महीने बाद रवण मंदिर की ओर से निरकारियों पर हमला करने का बाकायदा हुक्मनामा निकला। स्मरण रहे कि निरकारी सिक्ख गुरुओं को तथा गुरु ग्रंथ साहब का अर्थ मित्रों के समान ही मानते हैं परन्तु वे अहमणियों की तरह यह भी मानते हैं कि वाद में भी गुरु का सक्ता है।

इसके बाद विश्वी एजेंडा के इतिहास पर भिन्नदरवाला के नेतृत्व में सवानिबस्त सिक्ख सैनिकों के साथ साठगाठ शुरू की गई। प्रशिक्षित सैनिकों के सहयोग के कारण आतङ्कवाद के लिए परा पकड़ा माल मिला।

1977 के चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद पंजाब में अकाली दल सरकार में आ गई थी। इस सरकार ने अपनी प्रथम सरकारी विज्ञप्ति में यह कहा कि यदि भ्रष्टाचारी अधिकारी स्वर्णमंदिर में जाकर जमत गंगेवर में झुंझकी लगाने के बाद प्रार्थना के मामले यह प्रतिज्ञा करें कि वे आग भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जून, 1978 में एक हुक्मनामा जारी करके निरकारियों के नाश का आह्वान किया गया। अक्टूबर, 1978 में आनन्दपुर साहिब का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें स्पष्ट रूप से देश का तोड़कर खालिस्तान बनाने का संकल्प किया गया। जनता पार्टी के अध्यक्ष चन्द्रशेखर मंच पर आमीन थे, पर वे मौन रहे। आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव का वही महत्व और स्थान है जो 1940 के मुस्लिम लीग प्रस्ताव का था। इसमें एक बात और जोड़ दो जाय, तो स्थिति स्पष्ट होगी। वह यह कि पाकिस्तान प्रस्ताव की पृष्ठभूमि में बहुत से इलाके, यहां तक कि सिंध जैसे प्रांत थे जिनमें मुसलमानों की बहुमख्या थी, परन्तु सिक्ख बहुमत वाले जिले मुश्किल से एक या दो थे। मारे पंजाब में सिक्खों की बहुमख्या कुछ ही प्रतिशत थी। इस कारण खालिस्तानी आतङ्कवाद का शुरू से ही लक्ष्य यह था कि इतना आतङ्क फैलाया जाय कि जो लोग सिक्ख नहीं हैं, वे पंजाब से भाग खड़े हों।

सितम्बर 1983 तक स्थिति इतनी विगड़ गई कि बसों से उतारकर हिन्दू यात्रियों को गोली मारी जाने लगी। विराधी दलों ने मिलकर अकाली दल से कहा कि वे हत्याकाण्ड बंद करें, परन्तु अकाली नहीं माने। विरोधी दलों ने यह भी कहा कि निरकारियों के नाश सम्बन्धी हुक्मनामा वापस हो, पर अकाली इस भी नहीं माने। प्रसिद्ध पत्रकार बेचन बर्मन का बड़न है कि अकाली दल, गुरुद्वारा प्रपञ्चक कमटो मुख्य प्रयास सब एक धुरी के चक्कर में रहे। विरोधी दलों ने अकालियों से कहा कि निर्दोष व्यक्तियों की हत्याओं में निन्दा करते हुए एक हुक्मनामा निगाने पर अकाली नहीं माने। गहनरी ने अकाली नेताओं से कहा कि गुरुद्वारा के उपयोग के उन्मत्त अस्त्र शस्त्र प्रसारित जा रहा है ता अकाली नेता बोले 'अ' फालतू प्रश्न उठाए जा रहे हैं।

सरकार के साथ बातचीत के दौरान अकाली नेताओं का खयाल यह रहा कि जब समाधान बिलकुल करीब दिखाई देता, तो वे फौरन एक नई मांग जोड़ते। उन्होंने संविधान की धारा 25 के विरुद्ध आंदोलन में संविधान जलाना भी आरम्भ कर दिया। धारा 25 में मिक्लो के विरुद्ध कोई बात नहीं है यह चलनफहमी जान-बूझकर पनपी गई है कि हिन्दू मिक्लो को निगलना चाहते हैं, जबकि यह केवल व्याकरण और धानूनी शब्दावली का प्रश्न था। फिर भी ईश्वर सरकार ने धारा 25 को अमल में लाने का वायदा किया।

असल में अंग्रेजों के जमाने से सिक्खा का फोड़ने की चेष्टा चल रही थी। पिछे सभा के नेता नामा राज्य के काहन सिंह ने 1905 में नाया लिया था 'हम हिन्दू नहीं हैं 1911 में अंग्रेजों के एक गुप्तचर अधिकारी डी वेद्री तथा अपराधी गुप्त सूचना के निदेशक सी०एच०पैवलेड ने एक स्मरण पत्र तैयार किया था, जिसमें मिक्लो की असमत्ता का विवरण भी पहल की गई। इस प्रसंग पर गदर पार्टी (स्थापित 1913 सुदूर अमेरिका में) तथा उनके फासी जाने वाले नेताओं का विरोध प्रभाव नहीं पड़ा। भगतसिंह का साम्यवादी प्रभाव में भी ये अच्छे रहे। हा, एक बार अकारियों की आपसी पूर का पाप उठाकर साम्यवादी मन ने अपने एक उन्मीलित बार का गिरामणि गुरुदास प्रपञ्चक कमटो का अध्यास चुनवा लिया था पर उससे भी इनकी बदरता में कोई फर्क नहीं आया।

1980 के आम चुनाव में अकालियों की हार से अकाली नस्ल धीमल गया और सब से वह तेजी से आतंकवाद की ओर बढ़ने लगा। वह समझ गया कि वधानिक सभा में दावा नहीं गलेगी। पंजाब की जनसंख्या में 52 प्रतिशत मिक्लो हैं और विधान सभा के 117 स्थानों में केवल 50 गग चुनाव क्षेत्र हैं, जो गिरस बहुसंख्या क्षेत्र हैं। इस कारण बहुराज्य अकाली राजनीति का ध्येय हिन्दुओं को डराकर प्रांत में भगवत देना है। गंगा। भिंडरानाला तथा उगवा आतंकवादी गिराद गंगी राज्य को लेकर चल रहा था। गंगी विद्रोह की पंजाब में भगाए गए गंगी ता ताजिस्तान का सान्ना पूरा है। गंगी है न गंगी विधान सभा में अकालियों की निश्चित बहुसंख्या का पक्ष पूरा है। गंगी है। पर जो लोग इस प्रकार आतंकवाद में जलनस्ती बहुसंख्या प्रदान पर गुप्त गए यह भूत गए हैं 17 फीमदी गिरस पंजाब के बाहर बिखरे हैं।

निरकारियों को मिक्लो घम के डेरेतर अपना मक्क बड़ा दुश्मन मानने है बर्राफ उगवे कारण गुरुद्वारा का बड़ावा बटकर बाफी कम हा गया। इसीलिए हत्याओं में निरकारी गुरु का नंबर सबसे पहला आया। फिर पंजाब कमरी न गंगा न गंगानारायण और उनके पुत्र की हत्या का किया जा सकता है। यमा में निरकारियों हिन्दू मारे जान गए यहाँ तक कि जो निरकार नागरिकों के मांग मांगें गए। पर उनको भी नहीं छोड़ा गया। एक लोग में श्रीर गंगर न गुमीत गिर ती हत्या प्रमुख रहा। उर राणा गुररा

पह ने अमृतसर से 25 किलोमीटर दूर प्रीतनगर की स्थापना एक आदर्श ग्राम के रूप में की थी जिसमें धर्मनिरपेक्षता के स्वप्न को मृत करने की चेष्टा की गई थी। प्रगल्भ अभिनेता बलराज साहनी, लेखक नानक सिंह आदि ने इसमें सहयोग किया था। एक निका भी निकलती थी। सुमीत सिंह के हत्यारे तथा दूसरे आतंकवादी जम्मू कश्मीर तथा पाकिस्तान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। 82 साल के एक बूढ़े सिक्ख धार्मिक नेता की इस कारण हत्या की गई कि उस होन जातकवाद का साथ नहीं दिया। मकड़ा हत्याओं के अलावा बैंक लूटे गए और स्टेशनों तथा अन्य सावजनिक स्थानों पर आग लगाई गई। स्वर्ण मंदिर की आतंकवादियों का सैनिक गढ़ बना लिया गया। इसमें आधुनिकतम अस्त्र-शस्त्र तो थे ही, जयदेव विलेवदी भी की गई। यह हत्यारों के छिपाने का केन्द्र भी बन गया जहाँ तहाँ अपना काम करके यहाँ आ जाते थे। उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि 25 अप्रैल 1983 को स्वर्ण मंदिर के सामने ही डी० आई० जी० पुलिस, अटवाल की हत्या कर दी गई और हत्या के बाद हत्यारे उससे अंदर घुस गए। अटवाल स्वयं सिक्ख थे और दर्शन करके लौट रहे थे। फिर भी सरकार कायबाही करने से इसलिए हिचकिचा गई कि सिक्खों की धार्मिक भावनाओं को ठेस न लगे।

अतः तक सरकार मजबूर हो गई और जून 1984 के प्रथम सप्ताह में अच्छी तरह हिदायतें देने के बाद फौज की एक टुकड़ी स्वर्ण मंदिर में घुस गई। फौज से यह कहा गया कि किसी भी हालत में हरम-दर साहब पर गोली न चलायें। बहादुर भारतीय फौज ने, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिक्ख फौजी थे, बड़ी कुशलता से अपना काम पूरा किया। यद्यपि बहुत से बहादुर सिपाही भी आतंकवादियों की गोलियों से मारे गए परंतु उन्होंने स्वर्ण मंदिर की आतंकवादियों से भुक्कन कराने में सफलता प्राप्त की। भिड़ारावाला साधियों सहित मारा पाया गया। यदि मन्दिर की हानि न पहुँचाने की हिदायत न होती, तो सेना के लिए यह पन्द्रह मिनट का काम था और एक भी सैनिक का मरना न पड़ता।

स्वर्ण मंदिर पर सैनिक कायबाही यद्यपि तभी की गई जब उसके अनिश्चित अर्थ कोई उपाय शेष नहीं रहा, परंतु इसे सिक्खों ने अपन ढंग से लिया। विदेशों में बसे सिक्खों ने, जिनमें जगजीत सिंह का प्रमुख स्थान है, खुले तौर पर इंदिरा गांधी इत्यादि को मार डालने की धमकियाँ देना शुरू कर दिया।

**इंदिराजी की शहादत**—इंदिराजी चट्टान की तरह अविचलित प्रतिदिन भारत के किसी न किसी कोने में कभी दमकल की तरह आग बुझाती, नये नये कार्यों, उद्योगों का शुमारम्भ करती, गुमराह कांग्रेसियों को राह पर लाती, समदम विरोधी पक्ष के छक्के छुड़ाकर उन्हें उपहासस्पद बनाती आगे बढ़ती चली जा रही थी। राष्ट्रीय कार्यों के अलावा अंतराष्ट्रीय गतिधियों को सुलझाना, गुटनिरपेक्षता के नये मान स्थापित करना आदि भी चले रहा था। इंदिरा मृत्युजया थी, परंतु उन्होंने समझ लिया था कि सिर पर सतरा के बाद न मडरा रहे हैं और अकालियों का पहलवान शीघ्र ही रंग लायेगा। हत्या के एक दिन पहले 30 अक्टूबर को उड़ीसा की एक सभा में उन्होंने कहा—“यदि देश की सेवा में मेरी मृत्यु हो जाय, तो मुझे इस पर गव होगा। मुझे विश्वास है कि मेरे रक्त के प्रत्येक बिंदु से राष्ट्र के विकास में सहायता मिलेगी और राष्ट्र उससे और भी समर्थ और गतिशील होगा।”

एक विदेशी सहायतादाता ने उन्होंने कहा “नहीं, मुझे भय नहीं लगता। मुझ पर कई हमले हो चुके हैं। एक बार मुझ पर बंदूक चली गई। एक अन्य मौके पर एक व्यक्ति ने मुझ पर छुरा फेंका।”



इससे पहले सम्मेलन में यह कह चुकी थी "यदि इंदिरा मारी जाय, तो उसके रक्त से सँकड़ो इंदिरा अमुरित होगी और हजारों इन्दिराएँ देश की सेवा के लिए पैदा होंगी।"

उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अधिकारियों ने उनके अग्रदूतों में से सिक्खा को हटा दिया परंतु उन्हें जब यह मालूम हुआ तो यह बोलीं—'फिर हमारी घमनिर पेक्षा कहा जाएगी?' नतीजा यह हुआ कि सिक्ख अग्रदूत फिर बहाल कर लिये गए। इस प्रकार इंदिरा ने सेकुलरवाद के सिद्धांत के लिए जानबूझकर जान दे दी।

इसमें सदेह नहीं कि शहीद होकर वह भगल पाठों से लेकर, आजाद, भगतसिंह, गणेश शंकर विद्यार्थी और महात्मा गांधी की गौरवशाली परम्परा में सम्मिलित हो गईं। 31 अक्टूबर को प्रातः साढ़े नौ बजे वह अपने सफ़रजग रोड वाले निवासस्थान में उसी से लगे अपने अक्बर रोड वाले दफ़तर जा रही थी, तो उन्हीं के दो सिक्ख अग्रदूतों ने एकाएक उन पर हमला कर दिया। एक के पास स्टेनगन था। उसने उन पर सारी गोलियाँ खाली कर दीं। दूसरे ने भी अपनी पिस्तौल से तीन गोलियाँ चलाइ।

राजीव गांधी उस समय पूर्वी राज्यों के दौरे पर थे। सबर पाते ही वह तिली के लिए रवाना हो गए, परन्तु जब वह संध्या समय पहुँचे, तो इंदिराजी की नश्वर देह का अंत हो चुका था। सारे देश में ही नहीं, विश्व भर में शोक की लहर दौड़ गई। कई भावुक भारतीयों ने शोकसंतप्त होकर आत्महत्या कर ली।

महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को एक हिंदू धर्मांध के हाथों हुई थी। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या दो सिक्ख धर्मांधों के हाथों हुई। गहराई से देखा जाय तो दोनों के हत्यारे एक ही धर्मांध मनोबल के शिकार थे।

## शताब्दी वर्ष में राजीव युग का आरम्भ

इंदिरा गांधी की हत्या से पहले तो ऐसा लगा कि देश का भविष्य नितांत अधकारमय है, और कांग्रेस संस्था तथा शासन को भी इससे गहरी क्षति पहुंची है। पहला प्रश्न तो यही था कि संकट के इस काल में सत्ता के हस्तांतरण में क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं और क्या सहजता से नये प्रधान मंत्री का चुनाव सम्पूर्ण भी हो सकेगा। परंतु उसी शाम राष्ट्रपति के अरब देशों के दौरे से वापस आते ही यह काय जिस सरलता से सम्पन्न हो गया और श्री राजीव गांधी को निर्विरोध प्रधान मंत्री बना दिया गया, यह आश्चर्य की बात रही। इससे पूर्व इस तरह के दोना अवसरों पर, श्री नेहरू तथा श्री शास्त्री के निधन के बाद, पहले एक कायवाहक प्रधान मंत्री चुना गया था—जो संयोग-वश दोनों ही अवसरों पर श्री गुलजारीलाल नंदा रहे—फिर कुछ समय बीतने के बाद ही स्थायी प्रधान मंत्री का निर्वाचन किया गया।

दूसरी तात्कालिक समस्या इंदिराजी के निधन से उत्पन्न रोष की प्रतिक्रिया थी जिसमें राजधानी दिल्ली तथा देश के अन्य अनेक नगरों और रेलगाड़ियों इत्यादि में सिक्खों पर निंदयता से आक्रमण करना आरम्भ हो गया। इसके साथ ही उनकी सम्पत्ति भी जहा-तहा आग लगाकर नष्ट की गई। दो तीन दिन तक बबरता का यह दृश्य चलता रहा, और लगा कि इस पर काबू पाना सम्भव नहीं है। परंतु इंदिराजी की अन्त्येष्टि समाप्त होते ही—जिसमें सौ से अधिक विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया—सेना की सहायता से तुरंत स्थिति पर काबू पा लिया गया।

राजीव गांधी की स्थिति उनके कांग्रेस का प्रधान चुन लिए जाने से और भी दृढ़ हो गई। इससे पूर्व वे कांग्रेस संस्था के प्रधान मंत्री थे। उन्होंने तत्काल आम निर्वाचन की घोषणा कर दी और अपने इस निश्चित कदम में इस विषय में फैल रहे असमंजस को दूर कर दिया। चुनाव घोषणा का एक लाभ यह भी हुआ कि इसने आम जनता को विनाश की दिशा से हटाकर भविष्य के लिए सोचने और करने की ओर प्रेरित किया।

नवम्बर 1984 के अंतिम सप्ताह में चुनाव हुए और उसमें भारी बहुमत से कांग्रेस की विजय हुई। इसमें उस तीन चौथाई स्थान प्राप्त हुए। दरअसल यह भी एक रिकार्ड रहा क्योंकि स्वतंत्रता के बाद अब तक कांग्रेस को इतना बहुमत कभी प्राप्त नहीं हुआ था। न तो नेहरूजी के युग में और न इंदिराजी के युग में कांग्रेस ने यह चमत्कार किया था।

1985 कांग्रेस का शताब्दी वर्ष है और इसी वर्ष उसका एक नया युग भी आरम्भ हो गया है। यह राजीव गांधी का युग है। यह युग समस्याओं से पूर्ण है, और उनका सफल समाकलन ही युग की सफलता भी निश्चित करेगा। इस देश की मूल समस्या सेकुलरवाद और उसकी स्थापना की है। आज का प्रश्न यह है कि जिस प्रकार 1947 में पाकिस्तान बना क्या अब फिर एक नया खालिस्तान और उसके बाद अन्य

धर्मों तथा प्रदेशों के दूसरे, तीसरे, चौथे 'स्तान' बनते चले जायेंगे।

कांग्रेस संस्था तथा उसके नेताओं को भविष्य में इसी समस्या से जूझना है। परन्तु आशा का कारण मुख्यतः इसलिए विद्यमान है क्योंकि सौ वर्ष की उम्र में जहाँ व्यक्ति और संस्थाएँ प्रायः निर्जिव और नष्ट भी हो जाती हैं, वहाँ कांग्रेस संस्था की शक्ति न केवल नष्ट नहीं हुई है बरन् नई परिस्थिति तथा नये परिपेक्ष्य में वह सकल्पवान है कि एक बार फिर देश तथा समाज को कुछ महत्वपूर्ण दे सके।

आशा का दूसरा कारण पिछले कुछ वर्षों में महात्मा गांधी के विचारों और कार्यपद्धति का पुनरोदय भी है जो एटैनमरो की फिल्म 'गांधी' में तथा उसके द्वारा व्यवहृत है। आज एशिया, अफ्रीका और बाफो हूँ तक लैटिन अमेरिका की गरीबी के निराकरण का उपाय गांधी की आर्थिक विचारधारा ही लगती है। इसी तरह निरंकुश शासनो के विरुद्ध संघर्ष का उपाय भी हिंसा या आतंकवाद न होकर असहयोग ही प्रतीत होता है जिसका अनेक देशों में प्रयोग भी किया गया है। दुनिया के विचारशील लोग यह महसूस करने लगे हैं कि भविष्य का नेता इक्कीसवीं शताब्दी का नेता गांधी ही है, कि उसने स्वयं अपने जीवन में जो कुछ किया वह मात्र आरम्भिक प्रयोग ही था जो उस संघर्ष की ठीक से समझा जा सका न स्वीकृत किया जा सका—उसकी वास्तविक परिणति का समय तो अब आ रहा है। 'स्माल इज ब्यूटीफुल', 'इंटरमीजिएट तकनीकी' आदि का स्वीकार वास्तव में गांधी का ही स्वीकार है।

जहाँ तक राष्ट्रीय क्षेत्र का प्रश्न है उसमें पिछले दिनों मूल्यों का जो खोजनक हुआ है, उसके स्थान पर मानवी मूल्यों की पुनर्स्थापना तथा एक सरल, सहयोगी जीवन का विकास ही गांधीवादी जीवन की अवधारणा है जिसे हम फिर से अपनाना है।

कांग्रेस की स्थापना यद्यपि गांधी ने स्वयं नहीं की, तथापि गांधी के आगमन के बाद ही वह 'कांग्रेस' बनी, और दोनों एक दूसरे के पूरक तथा पर्याय हो गए—यहाँ तक कि गांधी के कांग्रेस छोड़ देने के बाद भी वह उनसे अलग नहीं हो सकी। आज भी यदि गांधी के विचारों का विश्व तथा भारत में प्रवर्तन होना है, तो उतना उपयुक्त तथा एकमात्र यत्र कांग्रेस संस्था ही बन सकती है।

□□

